सत्यमेव जयते

Ministry of Tourism

अतुल्य!भारत

Incredible !ndia

भारत के लिए यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए विश्व आर्थिक मंच रैंकिंग प्रणाली पर आधारित कार्य योजना के अध्ययन, विश्लेषण और विकास पर अंतिम रिपोर्ट

जून, 2019

Quality Council of India

QCI Creating an Ecosystem for Quality

अभिस्वीकृति

भारत के लिए यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (TTCI) के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंकिंग सिस्टम पर आधारित "स्टडी, एनालिसिस एंड एक्शन प्लान ऑफ़ एक्शन प्लान" का संचालन करने का अवसर देने के लिए भारत की गुणवत्ता परिषद पर्यटन मंत्रालय की आभारी है। इसलिए, हम श्री योगेंद्र त्रिपाठी, सचिव (पर्यटन), श्रीमती के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मीनाक्षी शर्मा, महानिदेशक (पर्यटन), श्री पी। सी। सारिक, अतिरिक्त महानिदेशक (बाजार अनुसंधान), श्रीमती। मिनी प्रसन्नकुमार, निदेशक (बाजार अनुसंधान), श्रीमती। अक्सा इलही, उप निदेशक (मार्केट रिसर्च), श्री एस। के। मोहनता, प्रोग्रामर (मार्केट रिसर्च) और पर्यटन मंत्रालय का पूरा मार्केट रिसर्च डिवीजन।

यह अध्ययन न केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के विभिन्न 14 क्षेत्रों के 90 प्लस संकेतकों पर अनुसंधान आधारित कार्य योजना तैयार करता है, लेकिन इसमें भारत के यात्रा और पर्यटन को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत के पेशेवरों के युवा दिमाग से नवीन कार्य योजनाएं शामिल हैं। निकट भविष्य में क्षेत्र।

पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से QCI द्वारा अध्ययन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली से हम प्रसन्न हैं। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप भारत के पर्यटन क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कई कार्ययोजनाओं के लिए एक समग्र शोध हुआ है, जो आगामी TTCI रिपोर्ट में हमारे देश की रैंकिंग की सर्वोत्तम प्रथाओं, अंतरालों और बाद के सुधार की पहचान कर सकता है। यह भारत के पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए पर्यटन मंत्रालय के जबरदस्त प्रयासों का अवलोकन करने के लिए हार्दिक था। रिपोर्ट में सफलता पर प्रकाश डाला गया है और उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां और सुधार की योजना बनाई जा सकती है और उन्हें लागू किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, संवेदीकरण कार्यशालाओं के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूरे दिल से समर्थन को देखते हुए, हमें प्राप्त समर्थन के लिए आभारी हूं और देश के लिए यात्रा और पर्यटन के मामले में बेहतर कल के लिए आशावादी महसूस करता हूं।

विषयसूची

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारी सारांश	5
2	टीटीसीआई रिपोर्ट की संरचना	13
3	136 अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी (टीटीसीआई 2017)	16
4	वर्षों से भारत की श्रेणी का स्नैपशॉट	18
5	भारत का स्कोर कार्ड - संकेतक वार	19
6	टीटीसीआई रिपोर्ट के ऐतिहासिक रुझान	21
7	क्रियाविधि	24
8	देशों की बकेटिंग	32
9	उप-सूचकांक ए: पर्यावरण को सक्षम करना	33
10	स्तंभ 1: व्यावसायिक वातावरण	35
11	स्तंभ 2: बचाव और सुरक्षा	87
12	स्तंभ 3: स्वास्थ्य और स्वच्छता	101
13	स्तंभ 4: मानव संसाधन और श्रम बाजार	123
14	स्तंभ 5: आईसीटी तत्परता	149
15	उप-सूचकांक बी: टीएंडटी नीति और सक्षम करने की शर्तें	167
16	स्तंभ 6: यात्रा और पर्यटन का प्राथमिकताकरण	169
17	स्तंभ 7: अंतर्राष्ट्रीय खुलापन	201
18	स्तंभ 8: मूल्य प्रतिस्पर्धा	215
19	स्तंभ 9: पर्यावरणीय स्थिरता	231
20	उप-सूचकांक सी: आधारिक संरचना	263
21	स्तंभ 10: हवाई परिवहन आधारिक संरचना	265
22	स्तंभ 11: जमीनी और बंदरगाह आधारिक संरचना	261
23	स्तंभ 12: पर्यटक सेवा आधारिक संरचना	299
24	उप-सूचकांक डी: प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन	313
25	स्तंभ 13: प्राकृतिक संसाधन	315
26	स्तंभ 14: सांस्कृतिक संसाधन और व्यवसाय यात्रा	331
27	डब्ल्यूइऍफ़ के लिए सिफारिशें	353
28	डब्ल्यूइऍफ़ से आवश्यक स्पष्टीकरण	355

कार्यकारी सारांश

1. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूइऍफ़) यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (टीटीसीआई) रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित करता है जो उन कारकों और नीतियों को मापता है जो देश को यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के भीतर निवेश करने के लिए एक व्यवहार्य स्थान बनाते हैं। टीटीसीआई रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में, प्रत्येक देश के पर्यटन क्षेत्र के प्रदर्शन, समग्र गुणवत्ता, भविष्य की क्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता के आधार पर उन्हें श्रेणी करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना है।

2. 2017 में, टीटीसीआई ने 136 देशों का विश्लेषण किया और प्रत्येक को चार उप-सूचकांकों : पर्यावरण को सक्षम करने, टीएंडटी नीति और स्थिति को सक्षम करने, आधारिक संरचना, और प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन के अनुसार स्कोर किया है। ये उप-सूचकांक, बदले में, 14 "स्तंभों" से बने होते हैं, जिन्हें यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा के 90 "संकेतक" में विभाजित किया जाता है।

3. इन 14 स्तंभों के स्कोर की गणना की जाती है (i) कार्यकारी राय सर्वेक्षण (इओएस) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, जो 34% संकेतक के बराबर होते हैं। भारत के लिए डब्ल्यूइऍफ़ का साझेदार संस्थान लीडकैप वेंचर्स है जो इओएस के लिए निजी क्षेत्र के प्रमुख व्यावसायिक अधिकारियों के सर्वेक्षण का संचालन करता है और 1 से 7. के मूल्य के बीच होता हैं (ii) मात्रात्मक डाटा (हार्ड डाटा) के आधार पर जो 34% संकेतकों का बना होता है। यह डाटा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पूर्व-प्रकाशित रिपोर्टों से एकत्र किया गया है, जिन्हें इओएस के परिणामों के साथ संरेखित करने के लिए 1 से 7 के पैमाने पर आगे जाकर और अधिक सामान्यीकृत किया गया था।

4. भारत उल्लेखनीय सुधार का प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रों में से एक है, जो 2013 से 25 स्थानों से बढ़कर 2017 में विश्व स्तर पर 40 वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत अपने विशाल सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों (क्रमशः 9 वें और 24 वें) और इसकी कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के फायदे (10 वां) के साथ अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह देश यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियों के माध्यम से और अधिक डिजिटल उपस्थिति के माध्यम से अपने सांस्कृतिक संसाधनों को समृद्ध करना,अधिक से अधिक सांस्कृतिक स्थलों और अमूर्त अभिव्यक्तियों की रक्षा करना जारी रखता है। अंतर्राष्ट्रीय खुलापन (55 वां, 2015 की तुलना में 14 स्थान तक), मजबूत वीज़ा

नीतियों के द्वारा जिसे ऑन अराइवल और ई-वीज़ा दोनों को लागू करके प्राप्त किया गया है, जिससे भारत को श्रेणी में ऊपर उठने में सक्षम बनाया गया है।

5. स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो रहा है, हालांकि वे अपर्याप्त (104 वें) बनी हुई हैं। इसी तरह, आईसीटी तत्परता (112 वें), सुरक्षा चिंताएं (114 वें) और मानव संसाधन (87 वें) सुधार पर हैं, लेकिन कमजोर बने हुए हैं। हालांकि इन आयामों में और अधिक सुधार की आवश्यकता है, भारत सही दिशा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। भारतीय टीएंडटी क्षेत्र महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है जिन्हें अभी तक टैप किया जाना बाकी है, विशेष रूप से पर्यटक सेवा बुनियादी ढांचे (110 वें) के प्रावधान में और अतिरिक्त आवास क्षमता, मनोरंजन सुविधाओं और संबंधित सेवाओं के द्वारा

6. पर्यटन मंत्रालय ने डब्ल्यूइऍफ़ की टीटीसीआई 2017 रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को इस अध्ययन के लिए अधिकृत किया है ताकि आने वाले वर्षों में भारत के प्रदर्शन को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ संबंधित मंत्रालयों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा सके।
7. कार्य योजना सुझाने के लिए डब्ल्यूइऍफ़ की टीटीसीआई रिपोर्ट को डिकोड करने में क्यूसीआई द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में शामिल है(i) रिपोर्ट की रूपरेखा का अध्ययन करना, (ii) कार्यप्रणाली में विकास को समझने के लिए टीटीसी रिपोर्ट के पिछले 4 संस्करणों (2011, 2013, 2015 और 2017) का विश्लेषण, (iii) वर्षों से डब्ल्यूइऍफ़ द्वारा अपनाए गए भारिता के परिवर्तन की प्रवृत्ति का विश्लेषण, (iv) ऐसे देशों की पहचान करना जो अपनी ही तरह की बेहतर श्रेणी वाले देशों द्वारा अपनाये गए नीतिगत हस्तक्षेपों और नीतियों के आधार पर भारत के लिए बेंचमार्क देशों के रूप में काम कर सकते हैं (v) भारत के प्रदर्शन की इनसे तुलना करना (ए) एशियाई साथी जो भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, (बी) संकेतक के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश, (सी) विशेष संकेतक के लिए प्रासंगिक सर्वश्रेष्ठ वैश्विक अभ्यास और (डी) संकेतक में भारत के प्रमुख प्रतियोगी।
8. प्रत्येक संकेतक के लिए, एमओटी अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा के बाद जिम्मेदार मंत्रालय / विभाग की पहचान की जाती है। 90 संकेतकों के लिए कार्य योजना विकसित की गई है, जिसमें अल्पावधि से दीर्घकालिक योजनाओं के लिए अलग-अलग नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। कार्य योजना बनाते समय संबंधित क्षेत्र के ज्ञान से परिपूर्ण विशेषज्ञों / पूर्व अधिकारियों से

सलाह ली जाती है। यदि कार्ययोजनाओं का पालन किया जाता है तो इसकी पूरी संभावना है कि आगामी टीटीसीआई रिपोर्ट में भारत की श्रेणी में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

9. 90 संकेतकों में से, क्यूसीआई 32 संकेतकों को प्राथमिकता देने की सिफारिश करता है क्योंकि ये कार्य योजनाएं, लागू किये जाने पर, सुधार की उच्च संभावना प्रदान करेंगी। प्राथमिकताकरण नीचे दिए गए तीन मानदंडों पर आधारित है:
   i. जहाँ डब्ल्यूइऍफ़ को सबसे अधिक भारिता दी गयी है (5 स्तंभ यानी स्तंभ10 से लेकर14 तक में 50% भारिता है)
   ii. वह क्षेत्र जहाँ भारत की श्रेणी गिर रही है
   iii. जहां भारत की श्रेणी पहले से ही कम है और अपेक्षाकृत कोई सुधार नहीं दिख रहा है

निम्न तालिका उन 32 प्राथमिकता वाले संकेतकों की कार्य योजना को सारांशित करती है:

स्तंभ	**सूचक**	**मंत्रालय**	**कार्य योजना**
स्तंभ 14: सांस्कृतिक संसाधन और व्यावसायिक यात्रा	14.03: बड़े खेल स्टेडियमों की संख्या	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	डब्ल्यूइऍफ़ की कार्यप्रणाली के अनुसार, 20,000 सीटों से अधिक क्षमता वाले स्टेडियमों पर विचार किया जाता है। भारत में 42 स्टेडियम हैं जिनकी बैठने की क्षमता 20,000 के बराबर है और इन्हें डब्ल्यूइऍफ़ द्वारा नहीं लिया गया है। इसलिए, इन स्टेडियमों में एक भी सीट बढ़ाने से इस सूचक में भारत की श्रेणी बढ़ जाएगी।
	14.02: मौखिक और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत	संस्कृति मंत्रालय	यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) नामांकन समिति उन तत्वों को प्राथमिकता देती है जो इनके तहत पंजीकृत हैं(i) तत्काल संरक्षित रखना (ii) सर्वश्रेष्ठ संरक्षित रखने की प्रथा और (iii) बहु-राष्ट्रीय तत्व। इसलिए, भारत को उपर्युक्त प्राथमिकताओं के तहत अधिक तत्वों को पंजीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि यह यूनेस्को की आईसीएच सूची के तहत अधिक तत्वों को सूचीबद्ध करने के हमारे मौके को बढ़ाएगा।
	14.04: अंतरराष्ट्रीय संघों की बैठकों की संख्या	पर्यटन मंत्रालय	गंतव्य विपणन संगठन (डीएमओ) और क्षेत्र स्तर के ब्यूरो, मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों (एमआईसीइ) पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक व्यावसायिक कार्यक्रम गंतव्य के रूप में देश को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। यह देश / क्षेत्र के लिए व्यावसायिक मामलेंओं को

			सुरक्षित करने में मदद करता है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और कन्वेंशन एसोसिएशन (आईसीसीए) की सदस्यता पाने के लिए डीएमओ के रूप में भारतीय कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी) की सहायता करने और शहर / क्षेत्र स्तर ब्यूरो की स्थापना करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
	14.05: सांस्कृतिक और मनोरंजन पर्यटन डिजिटल मांग		डिजिटल डिमांड की सदस्यता लें - पर्यटन की खोज के समूह तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डी 2 टूल, क्योंकि यह एक पर्यटन स्थल की लोकप्रियता, पर्यटक किसी विशेष गंतव्य पर क्या तलाश रहे है, मौसमी प्रवृत्ति और लक्षित बाजार के बारें में अंतर्दृष्टि देता है। यह उपकरण विपणन अभियान के प्रभाव को लगातार मापने में निगरानी प्रणाली के रूप में सुविधा प्रदान करेगा। इस उपकरण की ग्राहक सूची में स्वीडन, पुर्तगाल, जर्मनी, फिनलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे, यूरोपीय यात्रा आयोग आदि के राष्ट्रीय पर्यटन संगठन शामिल हैं।
स्तंभ 13: प्राकृतिक संसाधन	13.04: प्राकृतिक पर्यटन डिजिटल मांग	पर्यटन मंत्रालय	
स्तंभ 6: यात्रा और पर्यटन को प्राथमिकता	6.06: देशीय ब्रांड रणनीति मूल्यांकन		
स्तंभ 13: प्राकृतिक संसाधन	13.02: कुल ज्ञात प्रजातियाँ	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	डब्ल्यूइऍफ़ इस संकेतक के लिए आईयूसीएन के डाटा बेस पर विचार करता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई) के डाटा बेस से इसकी तुलना करने पर, आईयूसीएन के डाटा बेस में भारत की सूची से 181 प्रजातियां गायब पाई गई है। एमओईऍफ़ को उक्त असमानता के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए आईयूसीएन से संपर्क करना चाहिए।
स्तंभ 11: जमीनी और	11.05: रेलमार्ग घनत्व	रेल मंत्रालय	भारतीय रेलवे की कार्यप्रणाली के अनुसार, रेल घनत्व की गणना करते समय शहरी रेल परिवहन (मेट्रो रेल) को उसमें नहीं लिया

बंदरगाह आधारिक संरचना			गया है। इसलिए, इस गणना में बढ़ती मेट्रो रेल पटरियों को शामिल करने से इस सूचक में भारत की श्रेणी बढ़ जाएगी।
	11.06: बंदरगाह आधारिक संरचना की गुणवत्ता	पोत परिवहन मंत्रालय	एक पोत के टर्न-अराउंड-टाइम (टीएटी) को कम करने के लिए आधारिक संरचना में निवेश किया जाना चाहिए। इससे बंदरगाहों के समग्र प्रदर्शन में सुधार होगा जिससे बंदरगाहों की आधारिक संरचना गुणवत्ता में सुधार होगा।
	11.01: सड़कों की गुणवत्ता	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, एमओआरटीएच के सहयोग से क्यूसीआई ने दर निर्माण कंपनियों के लिए एक रूपरेखा विकसित की है, जिसका उपयोग भविष्य की निविदा प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। इसी तरह, राज्य राजमार्गों के लिए एक मूल्यांकन ढांचा विकसित किया जा सकता है जो भारतीय सड़कों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाएगा।
	11.07: जमीनी परिवहन दक्षता		बड़ी संख्या में बस उपयोगकर्ता प्रतिदिन एक ही प्रकार की आवागमन की यात्राएं करते हैं, लेकिन भारत के पास अंतरराज्यीय पास उपलब्ध कराने में कमी है। उदाहरण के लिए, लोगों का एक बड़ा हिस्सा प्रतिदिन चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा करता है। अंतरराज्यीय बस पास की शुरूआत से लोगों को यात्रा में आसानी होगी और दैनिक आवागमन की लागत भी कम होगी।
स्तंभ 3: स्वास्थ्य और स्वच्छता	3.01: चिकित्सक घनत्व	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अब तक, 7.73 लाख आयुष चिकित्सक हैं जिन्हें एमसीआई/एनएमसी द्वारा सामान्य चिकित्सकों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए, इन आयुष डॉक्टरों को चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में मान्यता देकर, भारत इस संकेतक में अपना कुल मूल्य 0.86 से बढ़ाकर 1.50 कर सकता है।
	3.04: अस्पताल के बेड		वर्तमान में, भारत इस संकेतक के मूल्य की गणना के लिए केवल सरकारी अस्पताल के बेड का ही डाटा बेस प्रदान कर रहा है। निजी अस्पताल के बेड की मात्रा, जो कुल सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा है, की कोई गणना नहीं की गयी है। इसलिए, सरकारी और निजी

			दोनों अस्पतालों के लिए एक केंद्रीकृत डाटा बेस विकसित किया जाना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया के मॉडल का पालन करके किया जा सकता है जहां केंद्रीय डाटा बेस प्रणाली के तहत निजी अस्पताल को पंजीकृत करना अनिवार्य है।
	3.03: उन्नत पेयजल तक पहुँच	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	भारत के अन्य राज्यों में बिहार राज्य सरकार की योजना "हर घर नल का जल" का अनुकरण करना, जो की सभी निवासियों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करते हुए भारत के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।
स्तंभ 6: यात्रा और पर्यटन का प्राथमिकताकरण	6.01: यात्रा और पर्यटन उद्योग का सरकार का प्राथमिकताकरण	पर्यटन मंत्रालय	आधिकारिक अतुल्य भारत की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन का विश्लेषण करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों को अपनी मार्केटिंग रणनीति पर तुरंत रूप से फिर से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि वे ट्रैफिक को आकर्षित करने में असमर्थ हैं। दोनों में ही बहुभाषी सुविधा की कमी है और वेबसाइट को सर्च इंजिन ऑप्टिमाइज़ेशन की तुरंत आवश्यकता है।
	6.02: T & T सरकारी खर्च		विभिन्न पर्यटन स्थलों और शहरों में सुधार के प्रमुख दायरे की पहचान करने के लिए एक तीसरे पक्ष के राष्ट्रीय पर्यटन अवसंरचना अंतराल मूल्यांकन का संचालन किया जा सकता है। इससे पर्यटन के बुनियादी ढांचे पर निवेश के प्राथमिकताकरण में मदद मिल सकती है।
स्तंभ 10: वायु परिवहन आधारिक संरचना	10.01: वायु परिवहन आधारिक संरचना की गुणवत्ता	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	भारत के भीतर एक संतुलित कराधान शासन के साथ एक केंद्रीय रूप से स्थित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग (एमआरओ) हब का गठन, जो हवाई जहाजों के रखरखाव की लागत को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है जो कि अन्यथा सिंगापुर जैसे विदेशी देशों में सेवा कर रहे हैं।
	10.02: उपलब्ध सीट किलोमीटर, घरेलू		

	10.03: उपलब्ध सीट किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय		
	10.04: विमान प्रस्थान		विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएॅफ़) को शामिल करना जो माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में एक वाहक की लागत का एक तिहाई योगदान देता है जहां एटीएॅफ़ को 28 प्रतिशत के उच्चतम जीएसटी स्लैब में वर्गीकृत किया जा सकता है जो एटीएॅफ़ पर वर्तमान के 40 प्रतिशत कर (केंद्रीय और राज्य दोनों लेवी सहित) से 12 प्रतिशत कम है। इस प्रकार, जीओआई द्वारा एक नीति हस्तक्षेप विमानन उद्योग के लिए एक उज्जवल मार्ग बना सकता है।
	10.05: हवाई अड्डे का घनत्व		
	10.06: ऑपमूल्यांकन एयरलाइंस की संख्या		
स्तंभ 4: मानव संसाधन और श्रम बाजार	4.04: ग्राहकों का उपचार	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	नई सर्किट बेंच स्थापित करके उपभोक्ता विवाद के मामलों की पेंडेंसी दर को कम किया जा सकता है क्योंकि देश में वर्तमान में केवल 7 सर्किट बेचें ही संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त, हमारे देश में ग्राहक सेवा प्रावधान में वर्तमान खामियों का विश्लेषण करने के लिए धोखाधड़ी या अनुचित सेवा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया भी ली जा सकती है।
	4.05: भर्ती करने और निकालने की प्रथा	श्रम और रोजगार मंत्रालय	विश्व स्तर पर 25 देशों के ग्लासडोर के आर्थिक अनुसंधान अध्ययन के अनुसार, भारत में औसतन 16.1 दिनों का सबसे छोटा साक्षात्कार समय रिपोर्ट किया गया है, जो भर्ती करने और निकालने की प्रथा और शिथिल श्रम बाजार के नियमों में लचीलेपन के कारण हासिल किया गया है। मंत्रालय की उपलब्धि का विज्ञापन करके विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित कार्यकारी राय सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं को संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

	4.06: कुशल कर्मचारियों को खोजने में आसानी	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	संपूर्ण कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को कौशल भारत के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कंपनियों के साथ भागीदारी करके उद्योगों की मांगों के साथ अनुसार संरेखित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनियों को कौशल भारत के तहत प्रशिक्षण हितधारकों के रूप में लिया जाना चाहिए।
स्तंभ 7: अंतर्राष्ट्रीय खुलापन	7.01: वीज़ा की आवश्यक्ताएं	गृह मंत्रालय	उन देशों / क्षेत्रों को ई-वीज़ा में सुविधा का विस्तार जो भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा / वीज़ा ऑन अराइवल / ई-वीज़ा सुविधा से छूट प्रदान कर रहे हैं। मालदीव, उत्तरी साइप्रस, रीयूनियन, स्वालबार्ड और जान मायेन, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, इथियोपिया, टोगो, नीयू, गिनी-बिसाऊ जैसे देश भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल प्रदान कर रहे हैं। हालांकि, इन देशों के पासपोर्ट धारकों को अभी भी वीज़ा प्राप्त करने की पारंपरिक पद्धति का पालन करना आवश्यक है।
स्तंभ 12: पर्यटक सेवा आधारिक संरचना	12.01: होटल के कमरे	पर्यटन मंत्रालय	डब्ल्यूइऍफ़ की कार्यप्रणाली के अनुसार, इस संकेतक का स्कोर प्रति 100 की जनसंख्या पर होटल के कमरों की संख्या पर निर्भर करता है। वर्तमान में भारत में होटलों की कुल संख्या को सत्यापित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि, प्रत्येक होटल को स्थानीय पुलिस स्टेशन में खुद को पंजीकृत करवाना होता है। इसलिए, राज्य पुलिस विभागों की मदद से एक केंद्रीय डाटा बेस डिपॉजिटरी को बनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से होटल के कमरों की वास्तविक गणना की जा सकती है।
स्तंभ 5: आईसीटी तत्परता	5.04: ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहक	संचार मंत्रालय	डब्ल्यूइऍफ़ की कार्यप्रणाली के अनुसार, इस संकेतक का स्कोर प्रति 100 की जनसंख्या पर ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करता है। परिणामस्वरूप, पर्यटक स्थलों पर वाई-फाई हॉटस्पॉट को कवर करने के उद्देश्य से एक चरण वार रणनीति अपनाकर स्थापित किया जाना चाहिए जैसे कि चरण 1 में सभी टियर -1 शहर, चरण 2 में सभी टियर -2 शहर और आगे भी इसी तरह। यह भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या में काफी महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करेगा।

	5.07: मोबाइल नेटवर्क कवरेज	संचार मंत्रालय	मोबाइल नेटवर्क कवरेज को उन निवासियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है जो मोबाइल सेलुलर सिग्नल की सीमा के भीतर हैं, चाहे वे डब्ल्यूइऍफ़ द्वारा निर्दिष्ट ग्राहक हों या नहीं। हालांकि, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में टावरों की कुल पहुंच केवल 58% है। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम टावरों के बूस्ट इंस्टॉलेशन को सरकारी परिसरों में निष्पादित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार टॉवरों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा सकती है।
स्तंभ 9: पर्यावरणीय स्थिरता	9.04: पार्टिकुलेट मैटर (2.5) सांद्रता	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर "स्वच्छ भारत अभियान" के समान तर्ज पर "स्वच्छ वायु मिशन"योजना के प्रारूपण और कार्यान्वयन की आवश्यकता है। यह स्वच्छ वायु मिशन [कैमइंडिया] योजना का उद्देश्य, बिजली, निर्माण, कृषि, ग्रामीण विकास और पर्यावरण के साथ-साथ शहर और राज्य के क्षेत्राधिकार के साथ काम करने वाले कई मंत्रालयों में वायु प्रदूषण शमन के लिए विशेष रूप से बनाई गई सरकारी नीतियों को लागू करना है।
	9.03: यात्रा और पर्यटन उद्योग के विकास की स्थिरता	पर्यटन मंत्रालय	खाद्य और कृषि संगठन (ऍफ़एओ) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत स्थलों (जीआईएएचएस) का लाभ उठाकर भारत में सतत ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिए: दार्जिलिंग सिस्टम, सिक्किम हिमालयन कृषि, जम्मू-कश्मीर में केसर विरासत, कोट्टनद केरल में समुद्री तल से नीचे खेती) आदि)। इससे एक साथ दो उद्देश्य प्राप्त होंगे: पर्यटकों को जीवनकाल तक याद किया जाने वाला एक अनुभव और यादें प्रदान करना और ग्रामीणों को अपनी आजीविका में सुधार करने के अवसर प्रदान करना।
	9.09: अपशिष्ट जल का उपचार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय	भारत में 746 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं, जिनमें से 224 एसटीपी काम में नहीं लिए जा रहे हैं या रखरखाव के अधीन हैं। भारत को तत्काल आधार पर उन 224 एसटीपी को फिर से शुरू करना चाहिए ताकि अधिक अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके।

10. रिपोर्ट में सुझाई गई कार्ययोजना के अलावा, अध्ययन में यह भी सिफारिश की गई है कि मंत्रालय डब्ल्यूइऍफ़ के साथ मिलकर नीचे दिए गए कुछ संकेतकों को संशोधित कर सकता है:

स्तंभ	सूचक	परिभाषा	सिफारिशें
स्तंभ 12: पर्यटक सेवा आधारिक संरचना	12.04: प्रति वयस्क जनसंख्या के लिए स्वचालित टेलर मशीनें	यह संकेतक प्रति 100,000 वयस्क आबादी पर स्वचालित टेलर मशीनों की संख्या को मापता है	वर्तमान में, अधिकांश देश डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए एटीएम स्थापित करने की आवश्यकता तेजी से कम हो रही है। इसलिए, स्थापित किए गए एटीएम की संख्या की गणना करने के बजाय, इस सूचक को, अधिक वैश्विक और ताज़ा हालत उपलब्ध कराने के लिए भुगतान करने के तरीके के रूप में डिजिटल नकदी का उपयोग करने वाले वयस्कों की संख्या की गणना करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
	12.03: प्रमुख कार किराए पर देने वाली कंपनियों की उपस्थिति	यह संकेतक किसी भी देश में प्रमुख कार किराए पर देने वाली नीचे दी गयी सात कंपनियों की उपस्थिति को मापता है।. 1. ऐविस 2. बजट 3. युरोपकार 4. हर्ट्ज 5. नेशनल कार रेंटल 6. सिक्सट 7. थ्रिफ्टी	इन संकेतक में जिन किराये पर कार दी जाने वाली कंपनियों को लिया गया है, वे एशियाई देशों में एक नवजात अवस्था में हैं। ये कंपनियां या तो यूरोप में स्थित है या फिर उत्तरी अमेरिका में, इसलिए इनका प्रमुख बाजार इन महाद्वीपों में हैं। इन कंपनियों के संचालन में इस तरह की असमानता एशियाई देशों के खिलाफ पक्षपात पैदा करती है। इसके अलावा, भारत और अन्य एशियाई देशों में लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए घरेलू कार किराए पर देने की सेवाएं उपलब्धहैं। इसलिए, सभी देशों को एक समान अवसर देने के लिए, इस सूचक को स्कोर देते समय घरेलू कार किराए पर देने वाली कंपनियों के बारें में भी विचार किया जाना चाहिए।
स्तंभ 1: व्यापारिक वातावरण	1.06: निर्माण परमिट से निपटने के लिए लागत	यह संकेतक किसी व्यवसाय के द्वारा गोदाम बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं से संबंधित लागत को मापता है (इसके मूल्य के संबंध में) ।	इस संकेतक के लिए किसी देश के मूल्य की गणना देश के प्रति व्यक्ति आय के 50 गुना को गोदाम के मूल्य को विभाजक लेकर उससे गुना करके की जाती है। इसलिए, कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में निर्माण परमिट के बराबर या उससे भी कम लागत होने के बावजूद, उन देशों द्वारा इन संकेतक में निम्न श्रेणी / स्कोर हासिल किया जाता है।

			इस संकेतक के डाटा सेट में देखी गई प्रवृत्ति यह है कि विकास के पहले चरण में देश निर्माण लागत की कम लागत के बावजूद स्कोर स्पेक्ट्रम के निचले हिस्से पर होते हैं। इस प्रकार, प्रति व्यक्ति आय को विभाजक में एक कारक के रूप में होने से निर्माण परमिट की लागत का सही मूल्य अस्पष्ट हो जाता है। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि या तो परमिट की सही लागत का विश्लेषण किया जाए या प्रति व्यक्ति आय को स्लैब में सामान्य किया जाए।

11. **निष्कर्ष**

i. इस अध्ययन ने विभिन्न देशों की श्रेणी के आधार पर डब्ल्यूइऍफ़ की यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक रिपोर्ट को डिकोड करने में मदद की है।

ii. इसके आधार पर, एक कार्य योजना का सुझाव दिया गया है। कार्ययोजना की अवधि छोटी अवधि से शुरू होती है और उच्चतम स्तर पर बहुत बड़ी नीतिगत हस्तक्षेप के लिए आसानी से संभव होती है।

iii. इस प्रक्रिया में, विभिन्न मंत्रालय / विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की पहचान की गई है। मंत्रालय / विभागों को सुधार की आवश्यकता वाले मापदंडों के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा और इससे भारत की विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर श्रेणी हो सकती है।

iv. अध्ययन से यह भी पता चला है कि पर्यटन मंत्रालय को डब्ल्यूइऍफ़ के साथ कुछ संकेतकों के संशोधन की आवश्यकता हो सकती है जिससे भारत की श्रेणी को फायदा होगा।

टीटीसीआई रिपोर्ट की संरचना

टीटीसीआई रिपोर्ट, जो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (टीटीसीआई) के माध्यम से विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन का विश्लेषण करती है, यह प्रत्येक उद्योग के विकास को बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश की ताकत और क्षेत्रों में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूइऍफ़) द्वारा प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में विभिन्न विषयों के साथ प्रकाशित की जाती है:

क्र.सं.	वर्ष	कवर की गयी अर्थव्यवस्थाएं	विषय
1	2011	139	मंदी से परे
2	2013	140	आर्थिक विकास में बाधाएं कम करना और रोजगार सृजन
3	2015	141	ग्रोइंग थ्रू शॉक्स
4	2017	136	अधिक स्थायी और समावेशी भविष्य के लिए रास्ता बनाना

टीटीसीआई रिपोर्ट अंतर-देशीय तुलना, बेंचमार्किंग देशों की नीति प्रगति और व्यापार और उद्योग विकास से संबंधित निवेश निर्णय लेने के लिए अनुमति देती है। रिपोर्ट न केवल देश-स्तर पर बहु-हितधारक संवाद के लिए उचित नीतियों और कार्यों को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह उद्योग के रुझानों के विश्लेषण के माध्यम से एक वैश्विक दृष्टिकोण भी लेती है और दीर्घकालिक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकार से वैश्विक नेताओं के अनूठे दृष्टिकोण प्रदान करता है।

टीटीसीआई रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा के चार व्यापक कारकों को मापती है। इन कारकों को उप-सूचकांक के रूप में जाना जाता है। इसमें चार उप-सूचकांक, 14 स्तंभ और 90 व्यक्तिगत संकेतक शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न स्तंभों के बीच बांटा गया है। प्रत्येक स्तंभ की गणना व्यक्तिगत सूचक के अभारित औसत के रूप में की गई है। उप-सूचकांकों की गणना तब शामिल स्तंभों के अभारित औसत के रूप में की जाती है। समग्र टीटीसीआई तब चार उप-सूचकांकों का अभारित औसत होता है। रिपोर्ट की संरचना नीचे उल्लिखित

की गयी है:

उप-सूचकांक	स्तंभ	संकेतक
वातावरण को सक्षम बनाना	व्यापारिक वातावरण	संपत्ति के अधिकार
		ऍफ़डीआई पर नियमों का प्रभाव
		विवादों को निपटाने में कानूनी ढांचे की क्षमता

		चुनौतीपूर्ण विनियमों में कानूनी ढांचे की क्षमता
		निर्माण परमिट से निपटने के लिए आवश्यक समय
		निर्माण परमिट से निपटने की लागत
		बाजार के वर्चस्व का विस्तार-क्षेत्र
		व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक समय
		व्यवसाय शुरू करने की लागत
		काम करने की प्रोत्साहन राशि पर कराधान का विस्तार और प्रभाव
		निवेश करने के लिए प्रोत्साहन राशि पर कराधान का विस्तार और प्रभाव
		कुल कर दर
	बचाव और सुरक्षा	अपराध और हिंसा की व्यावसायिक लागत
		पुलिस सेवाओं की विश्वसनीयता
		आतंकवाद की व्यापारिक लागत
		आतंकवादी मामलें का सूचकांक
		मानव हत्या का दर
	स्वास्थ्य और सफ़ाई	चिकित्सक घनत्व
		बेहतर स्वच्छता तक पहुंच
		बेहतर पेयजल तक पहुंच
		अस्पताल के बेड
		एचआईवी का प्रसार
		मलेरिया की मामलें
	मानव संसाधन और श्रम बाजार	प्राथमिक शिक्षा नामांकन दर
		माध्यमिक शिक्षा नामांकन दर
		स्टाफ प्रशिक्षण का विस्तार क्षेत्र
		ग्राहकों का उपचार
		भर्ती करने और निकालने की प्रथा
		कुशल कर्मचारी खोजने की आसानी

		विदेशी मज़दूर को काम पर रखने में आसानी
		वेतन और उत्पादकता
		महिला श्रम बल की भागीदारी
	आईसीटी तत्परता	व्यापार-से-व्यापार लेनदेन के लिए आईसीटी का उपयोग
		व्यापार से उपभोक्ता लेनदेन के लिए इंटरनेट का उपयोग
		इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्ति
		ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्य
		मोबाइल टेलीफोन सदस्यताएँ
		मोबाइल ब्रॉडबैंड सदस्यताएँ
		मोबाइल नेटवर्क कवरेज
		बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता
टीएंडटी नीति और शर्तों को सक्षम करना	यात्रा और पर्यटन का प्राथमिकताकरण	टीएंडटी उद्योग का सरकारी प्राथमिकताकरण
		टीएंडटी सरकारी खर्च
		पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विपणन की प्रभावशीलता
		वार्षिक टीएंडटी डाटा की व्यापकता
		मासिक / त्रैमासिक टीएंडटी डाटा प्रदान करने की समयबद्धता
		देशीय ब्रांड रणनीति मूल्यांकन
	अंतर्राष्ट्रीय खुलापन	वीज़ा आवश्यक्ताएं
		द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों का खुलापन
		प्रभाव में होने वाले क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की संख्या
	मूल्य प्रतिस्पर्धा	टिकट कर और हवाई अड्डा शुल्क
		होटल मूल्य सूचकांक
		क्रय शक्ति समता
		ईंधन का मूल्य स्तर
	पर्यावरणीय स्थिरता	पर्यावरणीय नियमों का अभाव
		पर्यावरणीय नियमों का प्रवर्तन

		यात्रा और पर्यटन उद्योग के विकास की स्थिरता
		पार्टिकुलेट मैटर (2.5) सांद्रता
		पर्यावरण संधि अनुसमर्थन की संख्या
		आधारभूत पानी का तनाव
		लुप्तप्राय प्रजातियाँ
		वन आवरण परिवर्तन
		अपशिष्ट जल उपचार
		तटीय शेल्फ पर मछली पकड़ने से पड़ने वाला दबाव
आधारिक संरचना	वायु परिवहन आधारिक संरचना	वायु परिवहन आधारिक संरचना की गुणवत्ता
		उपलब्ध सीट किलोमीटर, घरेलू
		उपलब्ध सीट किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय
		विमान प्रस्थान
		हवाई अड्डे का घनत्व
		ऑपमूल्यांकन एयरलाइंस की संख्या
	जमीनी और बंदरगाह आधारिक संरचना	सड़कों की गुणवत्ता
		सड़क का घनत्व
		पक्की सड़क का घनत्व
		रेलमार्ग आधारिक संरचना की गुणवत्ता
		रेलमार्गका घनत्व
		बंदरगाह आधारिक संरचना की गुणवत्ता
		जमीनी परिवहन दक्षता
	पर्यटक सेवा आधारिक संरचना	होटल के कमरे
		पर्यटन के आधारिक संरचना की गुणवत्ता
		प्रमुख कार किराए पर देने वाली कंपनियों की उपस्थिति
		प्रति वयस्क जनसंख्या पर स्वचालित टेलर मशीनें
प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन	प्राकृतिक संसाधन	विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थलों की संख्या
		कुल ज्ञात प्रजातियाँ
		कुल संरक्षित क्षेत्र

		प्राकृतिक पर्यटन डिजिटल मांग
		प्राकृतिक संपत्ति का आकर्षण
	सांस्कृतिक संसाधन और व्यवसाय यात्रा	विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की संख्या
		मौखिक और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अभिव्यक्तियों की संख्या
		खेल स्टेडियमों की संख्या
		अंतरराष्ट्रीय संघ की बैठकों की संख्या
		सांस्कृतिक और मनोरंजन पर्यटन डिजिटल मांग

136 अर्थव्यवस्थाओं (टीटीसीआई 2017) की श्रेणी

वर्ष 2017 में टीटीसीआर ने 14 स्तंभों के आधार पर 136 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया है जिसमें 90 संकेतक शामिल थे और उसमें 1-7 के पैमाने पर यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक / स्कोर को निकाला गया था। इन अर्थव्यवस्थाओं को फिर स्कोर के आधार पर श्रेणी दी गयी थी

प्रत्येक अर्थव्यवस्था की श्रेणी स्कोर के साथ नीचे दी गई है:

देश / अर्थव्यवस्था	श्रेणी	स्कोर
स्पेन	1	5.43
फ्रांस	2	5.32
जर्मनी	3	5.28
जापान	4	5.26
यूनाइटेड किंगडम	5	5.2
यूनाइटेड स्टेट्स	6	5.12
ऑस्ट्रेलिया	7	5.1
इटली	8	4.99
कनाडा	9	4.97
स्विट्जरलैंड	10	4.94
हांगकांग गणराज्य	11	4.86

देश / अर्थव्यवस्था	श्रेणी	स्कोर
ताइवान, चीन	30	4.47
डेनमार्क	31	4.43
क्रोएशिया	32	4.42
फिनलैंड	33	4.4
थाईलैंड	34	4.38
पनामा	35	4.37
माल्टा	36	4.25
एस्टोनिया	37	4.23
कोस्टा रिका	38	4.22
चेक गणराज्य	39	4.22
भारत	**40**	**4.18**

ऑस्ट्रिया	12	4.86
सिंगापुर	13	4.85
पुर्तगाल	14	4.74
चीन	15	4.72
न्यूजीलैंड	16	4.68
नीदरलैंड	17	4.64
नॉर्वे	18	4.64
कोरिया गणराज्य	19	4.57
स्वीडन	20	4.55
बेल्जियम	21	4.54
मेक्सिको	22	4.54
आयरलैंड	23	4.53
ग्रीस	24	4.51
आइसलैंड	25	4.5
मलेशिया	26	4.5
ब्राज़ील	27	4.49
लक्समबर्ग	28	4.49
संयुक्त अरब अमीरात	29	4.49
स्लोवाक गणराज्य	59	3.9
बहरीन	60	3.89
इजराइल	61	3.84
कोलम्बिया	62	3.83
सऊदी अरब	63	3.82
श्रीलंका	64	3.81
मोरक्को	65	3.81
ओमान	66	3.78
वियतनाम	67	3.78
रोमानिया	68	3.78

स्लोवेनिया	41	4.18
इंडोनेशिया	42	4.16
रूसी संघ	43	4.15
तुर्की	44	4.14
बुल्गारिया	45	4.14
पोलैंड	46	4.11
कतर	47	4.08
चिली	48	4.06
हंगरी	49	4.06
अर्जेंटीना	50	4.05
पेरू	51	4.04
साइप्रस	52	4.02
दक्षिण अफ्रीका	53	4.01
लातविया	54	3.97
मॉरिशस	55	3.92
लिथुआनिया	56	3.91
इक्वाडोर	57	3.91
बारबाडोस	58	3.91
रवांडा	97	3.36
अल्बानिया	98	3.35
बोलीविया	99	3.34
कुवैत	100	3.33
कंबोडिया	101	3.32
मंगोलिया	102	3.31
नेपाल	103	3.28
वेनेजुएला	104	3.28
अल साल्वाडोर	105	3.28
युगांडा	106	3.2

जमैका	69	3.71
जॉर्जिया	70	3.7
अज़रबैजान	71	3.7
मोंटेनेग्रो	72	3.68
त्रिनिदाद और टोबैगो	73	3.67
मिस्र	74	3.64
जॉर्डन	75	3.63
डोमिनिकन गणराज्य	76	3.62
उरुग्वे	77	3.61
भूटान	78	3.61
फिलीपींस	79	3.6
केन्या	80	3.59
कज़ाकस्तान	81	3.59
नामीबिया	82	3.59
केप वर्डे	83	3.55
आर्मीनिया	84	3.53
बोत्सवाना	85	3.52
ग्वाटेमाला	86	3.51
ट्यूनीशिया	87	3.5
यूक्रेन	88	3.5
मैसिडोनिया, पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य	89	3.49
होंडुरास	90	3.49
तंजानिया	91	3.45
निकारागुआ	92	3.44
ईरान, इस्लामिक गणराज्य	93	3.43
लाओ पीडीआर	94	3.4

ताजिकिस्तान	107	3.18
जाम्बिया	108	3.18
कोटे डी'वाइयर	109	3.16
पैराग्वे	110	3.15
सेनेगल	111	3.14
गाम्बिया	112	3.12
बोस्निया और हर्जेगोविना	113	3.12
जिम्बाब्वे	114	3.11
किर्गिज़ गणराज्य	115	3.1
इथियोपिया	116	3.1
माल्डोवा	117	3.09
अल्जीरिया	118	3.07
गैबॉन	119	3.06
घाना	120	3.04
मेडागास्कर	121	2.99
मोजाम्बिक	122	2.91
मलावी	123	2.91
पाकिस्तान	124	2.89
बांग्लादेश	125	2.89
कैमरून	126	2.88
बेनिन	127	2.84
लेसोथो	128	2.84
नाइजीरिया	129	2.82
माली	130	2.78
सिएरा लियोन	131	2.69
मॉरिटानिया	132	2.64

सर्बिया	95	3.38	कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य	133	2.64
लेबनान	96	3.37	बुरुंडी	134	2.57
चाड	135	2.52	यमन	136	2.44

वर्षों से भारत की श्रेणी का स्नैपशॉट

2 नए स्तंभ, अर्थात्, "व्यावसायिक वातावरण" और "अंतर्राष्ट्रीय खुलेपन" को 2015 में पेश किया गया था, जबकि स्तंभ "यात्रा और पर्यटन की आत्मीयता" और "नीति नियम और विनियम" वर्ष 2015 में भंग कर दिए गए थे

क्र. सं.	स्तंभ	2011 (139 में से)	2013 (140 में से)	2015 (141 में से)	2017 (136 में से)
1	व्यापारिक वातावरण	NA	NA	107	89
2	बचाव और सुरक्षा	78	74	129	114
3	स्वास्थ्य और सफ़ाई	112	109	106	104
4	मानव संसाधन	96	96	111	87
5	आईसीटी की तत्परता	111	111	114	112
6	यात्रा और पर्यटन का प्राथमिकताकरण	91	98	96	104*
7	अंतर्राष्ट्रीय खुलापन	NA	NA	69	55
8	टीएंडटी उद्योग में मूल्य प्रतिस्पर्धा	28	20	8	10*
9	पर्यावरणीय स्थिरता	107	107	139	134
10	वायु परिवहनआधारिक संरचना	39	39	35	32
11	जमीनी और बंदरगाह परिवहन आधारिक संरचना	43	42	50	29
12	पर्यटक सेवा आधारिक संरचना	89	95	109	110*
13	प्राकृतिक संसाधन	8	9	17	24*
14	सांस्कृतिक संसाधन और व्यापार यात्रा	24	24	10	9

15	नीति नियम और विनियम	128	125	NA	NA
16	यात्रा और पर्यटन की आत्मीयता	116	111	NA	NA
	भारत की वैश्विक श्रेणी	**68**	**65**	**52**	**40**

* भारत की श्रेणी (2015 की तुलना में) निम्नलिखित 4 स्तंभों में गिरावट आई है:

1. यात्रा और पर्यटन को प्राथमिकता
2. टीएंडटी उद्योग में मूल्य प्रतिस्पर्धा
3. पर्यटक सेवा आधारिक संरचना
4. प्राकृतिक संसाधन

भारत का स्कोर - संकेतक वार

संकेतक /स्तंभ	श्रेणी	मूल्य
व्यापारिक वातावरण	89	4.3
संपत्ति के अधिकार	99	3.9
ऍफ़डीआई पर नियमों का प्रभाव	71	4.6
विवादों को निपटाने में कानूनी ढांचे की क्षमता	32	4.6
चुनौतीपूर्ण विनियमों में कानूनी ढांचे की क्षमता	29	4.4
निर्माण परमिट से निपटने के लिए आवश्यक समय	98	190
निर्माण परमिट से निपटने की लागत (%निर्माण लागत)	134	25.9
बाजार के वर्चस्व का विस्तार-क्षेत्र	31	4.2
व्यवसाय शुरू करने के लिए समय (दिन)	110	26
व्यवसाय शुरू करने की लागत (% जीएनआई प्रति व्यक्ति)	89	13.8
काम करने की प्रोत्साहन राशि पर कराधान का प्रभाव	36	4.4
निवेश करने के लिए प्रोत्साहन राशि पर कराधान का प्रभाव	24	4.5
कुल कर दर (% लाभ)	123	60.6
बचाव और सुरक्षा	114	4.1
अपराध और हिंसा की व्यावसायिक लागत	80	4.4
पुलिस सेवाओं की विश्वसनीयता	53	4.7
आतंकवाद की व्यापारिक लागत	120	4
आतंकवादी मामलें का सूचकांक	126	1
मानव हत्या की दर (/100,000 जनसंख्या)	69	3.2
स्वास्थ्य और सफ़ाई	104	4.4
चिकित्सक घनत्व (/1,000 जनसंख्या)	94	0.7
बेहतर स्वच्छता तक पहुंच (% जनसंख्या)	119	39.6
बेहतर पेयजल तक पहुंच (%जनसंख्या)	80	94.1
अस्पताल के बेड (/10,000 जनसंख्या)	116	7
एचआईवी का प्रसार (% वयस्क जनसंख्या)	60	0.3

मलेरिया की मामलें (मामले/100,000 जनसंख्या)	109	1312.4
मानव संसाधन और श्रम बाजार	87	4.4
प्राथमिक शिक्षा नामांकन दर (कुल %)	100	90
माध्यमिक शिक्षा नामांकन दर (सकल %)	99	74.3
स्टाफ प्रशिक्षण का विस्तार क्षेत्र	30	4.6
ग्राहक अभिविन्यास की डिग्री	70	4.6
भर्ती करने और निकालने की प्रथा	15	4.8
कुशल कर्मचारी खोजने की आसानी	49	4.5
विदेशी मज़दूर को काम पर रखने में आसानी	57	4.2
वेतन और उत्पादकता	33	4.5
महिला श्रम बल की भागीदारी (पुरुषों के अनुपात में)	128	0.35
आईसीटी तत्परता	112	3.2
व्यापार-से-व्यापार लेनदेन के लिए आईसीटी का उपयोग	84	4.5
व्यापार से उपभोक्ता लेनदेन के लिए इंटरनेट का उपयोग	64	4.6
इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्ति (%जनसंख्या)	101	26
स्थायी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यताएँ (/100 जनसंख्या)	105	1.3
मोबाइल- सेलुलर टेलीफोन सदस्यताएँ (/100 जनसंख्या)	121	78.1
मोबाइल ब्रॉडबैंड सदस्यताएँ (/100 जनसंख्या)	126	9.4
मोबाइल नेटवर्क कवरेज (% जनसंख्या)	114	93.5
बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता	87	4.3
यात्रा और पर्यटन का प्राथमिकताकरण	104	3.9
टीएंडटी उद्योग का सरकारी प्राथमिकताकरण	102	4.1
टीएंडटी सरकारी खर्च (% सरकार का बजट)	125	1
पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विपणन की प्रभावशीलता	94	3.8
वार्षिक टीएंडटी डाटा की व्यापकता	114	39
मासिक / त्रैमासिक टीएंडटी डाटा प्रदान करने की समयबद्धता	3	22
देशीय ब्रांड रणनीति मूल्यांकन	81	72.6
अंतर्राष्ट्रीय खुलापन	55	3.7

वीज़ा आवश्यक्ताएं	49	37
द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों का खुलापन	28	14.6
प्रभाव में होने वाले क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की संख्या	47	20
मूल्य प्रतिस्पर्धा	10	5.8
टिकट कर और हवाई अड्डा शुल्क	25	88
होटल मूल्य सूचकांक (US$)	16	84.5
क्रय शक्ति समता (पीपीपी $)	1	0.3
ईंधन का मूल्य स्तर (US$ सेंट / लीटर)	35	91
पर्यावरणीय स्थिरता	134	3.1
पर्यावरणीय नियमों का प्रवर्तन	51	4.4
यात्रा और पर्यटन उद्योग के विकास की स्थिरता	43	4.4
पार्टिकुलेट मैटर (2.5) सांद्रता (µg/m3)	78	4.2
पर्यावरण संधि अनुसमर्थन	135	32.9
आधारभूत पानी का तनाव	31	24
लुप्तप्राय प्रजातियाँ (% कुल प्रजातियां)	106	3.7
वन आवरण परिवर्तन (%परिवर्तन)	126	13.5
अपशिष्ट जल उपचार (%)	34	0
तटीय शेल्फ पर मछली पकड़ने से पड़ने वाला दबाव (टन / किमी2)	93	2.2
पर्यावरणीय नियमों का प्रवर्तन	86	0.6
वायु परिवहन आधारिक संरचना	32	3.9
वायु परिवहन आधारिक संरचना की गुणवत्ता	63	4.5
उपलब्ध सीट किलोमीटर, घरेलू (लाखों में)	7	1763.4
उपलब्ध सीट किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय (लाखों में)	17	2013.8
विमान प्रस्थान (/1,000 जनसंख्या)	108	0.6
हवाई अड्डे का घनत्व (हवाई अड्डे/ लाख जनसंख्या)	133	0.2
ऑपमूल्यांकन एयरलाइंस की संख्या	18	89
जमीनी और बंदरगाह आधारिक संरचना	29	4.5
सड़कों की गुणवत्ता	50	4.4

सड़क का घनत्व (%कुल क्षेत्रीय क्षेत्र)	22	-
पक्की सड़क का घनत्व (%कुल क्षेत्रीय क्षेत्र)	28	-
रेलमार्ग आधारिक संरचना की गुणवत्ता	23	4.5
रेलमार्गका घनत्व (इकों / भूमि क्षेत्र का किमी)	40	2
बंदरगाह आधारिक संरचना की गुणवत्ता	48	4.5
जमीनी परिवहन दक्षता	28	4.7
पर्यटक सेवा आधारिक संरचना	110	2.7
होटल के कमरे (संख्या / 100 जनसंख्या)	133	0
पर्यटन के आधारिक संरचना की गुणवत्ता	76	4.5
प्रमुख कार किराए पर देने वाली कंपनियों की उपस्थिति	102	3
स्वचालित टेलर मशीनें (संख्या / हजार वयस्क जनसंख्या)	100	18.1
प्राकृतिक संसाधन	24	4.4
विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल (स्थलों की संख्या)	6	8
कुल ज्ञात प्रजातियाँ (प्रजातियों की संख्या)	10	1889
कुल संरक्षित क्षेत्र (%कुल क्षेत्रीय क्षेत्र)	115	5.3
प्राकृतिक पर्यटन डिजिटल मांग	45	23
प्राकृतिक संपत्ति का आकर्षण	113	4
सांस्कृतिक संसाधन और व्यवसाय यात्रा	9	5.3
विश्व धरोहर सांस्कृतिक (स्थलों की संख्या)	6	28
मौखिक और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (अभिव्यक्तियों की संख्या)	8	13
खेल स्टेडियम (बड़े स्टेडियमो की संख्या)	5	87
अंतरराष्ट्रीय संघ की बैठकों की संख्या	30	140.7
सांस्कृतिक और मनोरंजन पर्यटन डिजिटल मांग	13	51

टीटीसीआई रिपोर्ट के इतिहास की कहानी

वर्ष 2011 और 2013 में 3 उप-सूचकांक थे जो वर्ष 2015 और 2017 में 4 उप-सूचकांक में परिवर्तित हो गए। उप-सूचकांकों को समान भार दिया गया था। चूंकि 2011 और 2013 में 3 उप-सूचकांक थे, इसलिए प्रत्येक उप-सूचकांक का भार 33.33% था। 2015 और 2017 में उप-सूचकांक की संख्या की

4 उप-सूचकांक के रूप में बढ़त हो गई। इसलिए, प्रत्येक उप-सूचकांक में अब 25% का भार है। प्रत्येक स्तंभ की गणना व्यक्तिगत सूचक के अभारित औसत के रूप में की गई है। उप-सूचकांकों की गणना तब शामिल स्तंभों के अभारित औसत के रूप में की जाती है। समग्र टीटीसीआई तब चार उप-सूचकांकों का अभारित औसत होता है।

उप-सूचकांक

उप-सूचकांक में परिवर्तन

2011 - 2013		2015 - 2017	
उप-सूचकांक	अधिमान	उप-सूचकांक	अधिमान
टीएंडटी विनियामक ढांचा	33.33%	पर्यावरण को सक्षम करना	25%
टीएंडटी व्यापारिक वातावरण और आधारिक संरचना	33.33%	टीएंडटी नीतियां और सक्षम करने की शर्तें	25%
टीएंडटी मानव, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधन	33.33%	आधारिक संरचना	25%
		प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन	25%

स्तंभ

स्तंभों में भार की अवस्था में बदलाव

स्तंभ	2011-13	2015-17	भार की अवस्था में बदलाव का प्रतिशत
व्यावसायिक वातावरण		5.00%	-
बचाव और सुरक्षा	6.67%	5.00%	-25%
स्वास्थ्य और स्वच्छता	6.67%	5.00%	-25%
मानव संसाधन	8.33%	5.00%	-40%
आईसीटी तत्परता	6.67%	5.00%	-25%
यात्रा और पर्यटन की प्राथमिकताकरण	6.67%	6.25%	-6%

टीएंडटी उद्योग में मूल्य प्रतिस्पर्धा	6.67%	6.25%	-6%
अंतर्राष्ट्रीय खुलापन		6.25%	-
पर्यावरणीय स्थिरता	6.67%	6.25%	-6%
वायु परिवहन आधारिक संरचना	6.67%	8.33%	25%
जमीनी और बंदरगाह परिवहन आधारिक संरचना	6.67%	8.33%	25%
पर्यटक सेवा आधारिक संरचना	6.67%	8.33%	25%
प्राकृतिक संसाधन	8.33%	12.50%	50%
सांस्कृतिक संसाधन और व्यवसायिक यात्रा	8.33%	12.50%	50%
नीति नियम और विनियम	6.67%		-
यात्रा और पर्यटन के प्रति लगाव	8.33%		-

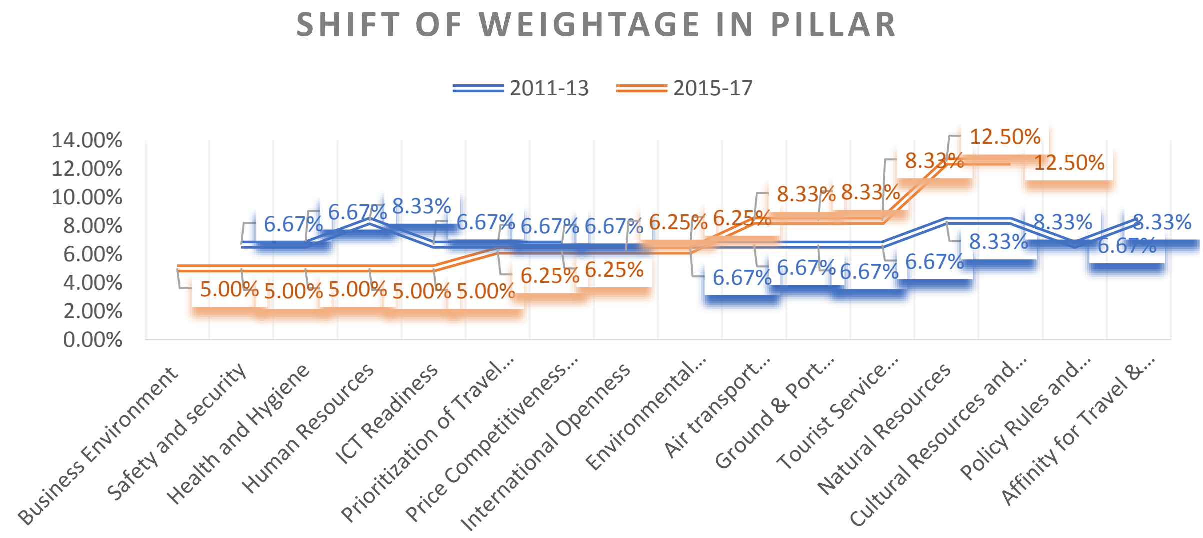

14 स्तंभों को 4 उप-सूचकांकों (जैसा कि ऊपर बताया गया है) के बीच विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तंभ को जिस उप-सूचकांक में वे शामिल होते हैं उसमें समान भार दिया जाता है। उदाहरण के लिए, पहले उप-सूचकांक में 5 स्तंभ हैं। इसलिए, पहले उप-सूचकांक का 25% 5 स्तंभों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक में 5% का भार है। प्रत्येक स्तंभ के भार में होने वाले बदलाव को ऊपर के ग्राफ में दिखाया गया है। वेभार में होने वाले बदलाव के प्रतिशत परिवर्तन को प्रत्येक स्तंभ की तालिका में दिया गया है।

संकेतक

रिपोर्ट में उपयोग किए गए डाटा को एकत्र करने के लिए डब्ल्यूइऍफ़ द्वारा दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं जिन्हें निम्नानुसार समझाया गया है:

- **कार्यकारी राय सर्वेक्षण:** इन संकेतकों की गणना एक सर्वेक्षण से की जाती है जो डब्ल्यूइऍफ़ द्वारा संचालित किया जाता है।
- **ठोस संकेतक:** इन संकेतकों को विभिन्न स्रोतों की पूर्व-प्रकाशित रिपोर्टों से लिया जाता है।.

कार्यकारी राय सर्वेक्षण (ईओएस) संकेतकों के प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। ईओएस संकेतकों के भार का प्रतिशत भी कम हो गया है (यानी) ठोस संकेतकों को अधिक भार दिया गया है जैसे की नीचे समझाया गया है -

वर्ष दर वर्ष संकेतक की संख्या

वर्ष	2011	2013	2015	2017
संकेतकों की कुल संख्या	75	79	90	90
ईओएस संकेतकों का प्रतिशत	37%	38%	34%	34%
ठोस संकेतकों का प्रतिशत	63%	62%	66%	66%
ईओएस संकेतकों के भार का प्रतिशत	40%	36%	27%	28%
ठोस संकेतकों के भार का प्रतिशत	60%	64%	73%	72%

कार्यप्रणाली

क्वालिटी कौंसिल ऑफ़ इंडिया, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट 2017 की यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (टीटीसीआई) का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर काम कर रही थी:

- स्तंभों का विस्तार से अध्ययन करने और टीटीसीआई रिपोर्ट के प्रासंगिक संकेतकों की पहचान करने के लिए
- प्रत्येक संकेतक को सौंपे गए भार का अध्ययन और पहचान करना
- सभी डाटा स्रोतों और डाटा संग्रह प्रक्रियाओं की पहचान करना
- टीटीसीआई रिपोर्ट की गणना के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पालन की जाने वाली कार्यप्रणाली का गहराई से अध्ययन

रिपोर्ट के अध्ययन के लिए क्यूसीआई द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए -

चरण 1: रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण

4 साल, 2011,2013,2015 और 2017 के लिए टीटीसीआई रिपोर्ट का विश्लेषण उद्देश्य के लिए अध्ययन किया गया था। वर्ष 2011 से 2017 तक उप-सूचकांक, स्तंभों और संकेतकों में परिवर्तन की पहचान की जाएगी।

चरण 2: भार का अनुमान लगाना

90 संकेतकों और 14 स्तंभों के लिए भार का आंकलन अभारित औसत सूत्र को लगाकर किया गया है।

चरण 3: मंत्रालय की पहचान

संकेतकों के लिए जिम्मेदार मंत्रालय की पहचान की गयी है।

चरण 4: बेंचमार्क की पहचान करना

प्रमुख बेंचमार्क देशों को विभिन्न प्रमुख संकेतकों के खिलाफ पहचाना गया है।

चरण 5: प्रत्येक संकेतक स्कोर की गणना

प्रत्येक संकेतक के स्कोर का सामान्यीकरण किया गया था और अभारित औसत सूत्र का उपयोग करके देशों के स्कोर पर पहुंचा गया था।

चरण 6: प्रवृत्ति विश्लेषण

प्रवृत्ति का विश्लेषण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऐतिहासिक सर्वेक्षणों के अध्ययन के माध्यम से कार्यप्रणाली के विकास, संकेतकों के परिवर्तन, भारांक में परिवर्तन, नमूना तकनीकों में बदलाव, स्कोर पर आने के लिए गणना आदि के साथ प्रत्येक संकेतक के लिए कार्य योजना लाने के लिए किया गया था।

चरण 7: विशेषज्ञ परामर्श

नीचे उन विशेषज्ञों की सूची दी गई है, जिनसे इस रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं के लिए परामर्श लिया गया था -

विशेषज्ञों की सूची		
क्रमांक	**नाम**	**पदनाम**
1	श्रीमती दीपाली खन्ना	• पूर्व-अतिरिक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय • पूर्व-अतिरिक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय • पूर्व-अतिरिक्त सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय • पूर्व -जॉइंट सेक्रेटरी, रक्षा मंत्रालय • अतिरिक्त सदस्य (वित्त), रेलवे
2	श्री विवेक आनंद चौरे	• महाप्रबंधक (संचालन), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
3	श्री दानिश हाशमी	• निदेशक, अर्थशास्त्र प्रमुख, व्यापार करने में आसानी, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) - कार्यकारी राय सर्वेक्षण के लिए डब्ल्यूइऍफ़ के साथ समन्वय
4	डॉ. हरीश नाडकरनी	• मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच)
5	डॉ. ऐश्वर्या राज	• वरिष्ठ निदेशक, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट
6	श्रीमती मधु अहलूवालिया	• वरिष्ठ सलाहकार, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीइटी)
7	श्री डी. के. सिंह	• संस्थापक, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल एंड टूरिज्म

चरण 8: विस्तृत और केंद्रित कार्य योजना

आगामी टीटीसीआई रिपोर्ट में भारत की श्रेणी में सुधार के उद्देश्य के साथ विस्तृत और केंद्रित कार्य योजना का संकेतक वार अध्ययन किया गया था और प्रस्तावित हस्तक्षेपों से अपेक्षित सुधार पर प्रकाश डाला गया था।

ठोस संकेतकों के लिए कार्यप्रणाली

ठोस संकेतकों की गणना विभिन्न स्रोतों की पूर्व-प्रकाशित रिपोर्टों से की जाती है। इन्हें कार्यकारी राय सर्वेक्षण के परिणामों के साथ संरेखित करने के लिए 1 से 7 के पैमाने पर सामान्यीकृत किया जाता है।

डब्ल्यूइऍफ़ द्वारा प्रत्येक ठोस डाटा संकेतक को 1 से 7 के पैमाने में बदलने के लिए माने जाने वाला मानक फॉर्मूला है $6 \times \left(\frac{\text{देश स्कोर– नमूना न्यूनतम}}{\text{नमूना अधिकतम– नमूना न्यूनतम}}\right) + 1$

नमूना न्यूनतम और नमूना अधिकतम, क्रमशः समग्र नमूने के निम्नतम और उच्चतम स्कोर हैं। उन ठोस डाटा संकेतकों के लिए जिनके लिए एक उच्च मूल्य एक खराब परिणाम (जैसे ईंधन मूल्य स्तर) को इंगित करता है, हम एक सामान्यीकरण सूत्र पर भरोसा करते हैं, जो श्रृंखला को 1 से 7 के पैमाने पर परिवर्तित करने के अलावा, इसे उलट देता है, ताकि 1 और 7 अब भी क्रमशः सबसे खराब और सर्वश्रेष्ठ के अनुरूप रहे:

$$-6 \times \left(\frac{\text{देश स्कोर– नमूना न्यूनतम}}{\text{नमूना अधिकतम– नमूना न्यूनतम}}\right) + 7$$

कुछ उदाहरणों में, डाटा में बाहरी कारकों के कारण समायोजन किए गए थे और उसी के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार परिभाषित की गई है: -

1. अपने संबंधित स्तंभ के स्कोर पर एक संकेतक के गैर-सामान्यीकृत स्कोर में परिवर्तन के प्रभाव को खोजने के लिए, रिपोर्ट में विचार किए गए सभी संकेतकों के लिए प्रत्येक 14 स्तंभों के लिए

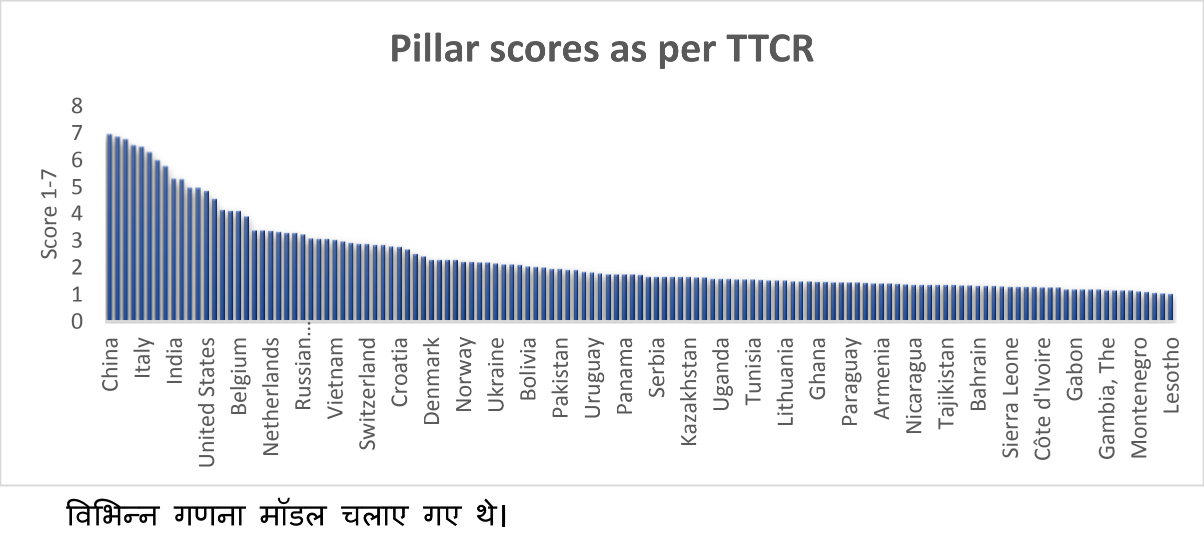

विभिन्न गणना मॉडल चलाए गए थे।

2. देशों के स्तंभ स्कोर अवरोही क्रम में तैयार किए गए थे। ये स्कोर 1-7 के पैमाने पर सामान्य होने के बाद प्रत्येक संकेतक के असतत मूल्यों का एकत्रीकरण है।

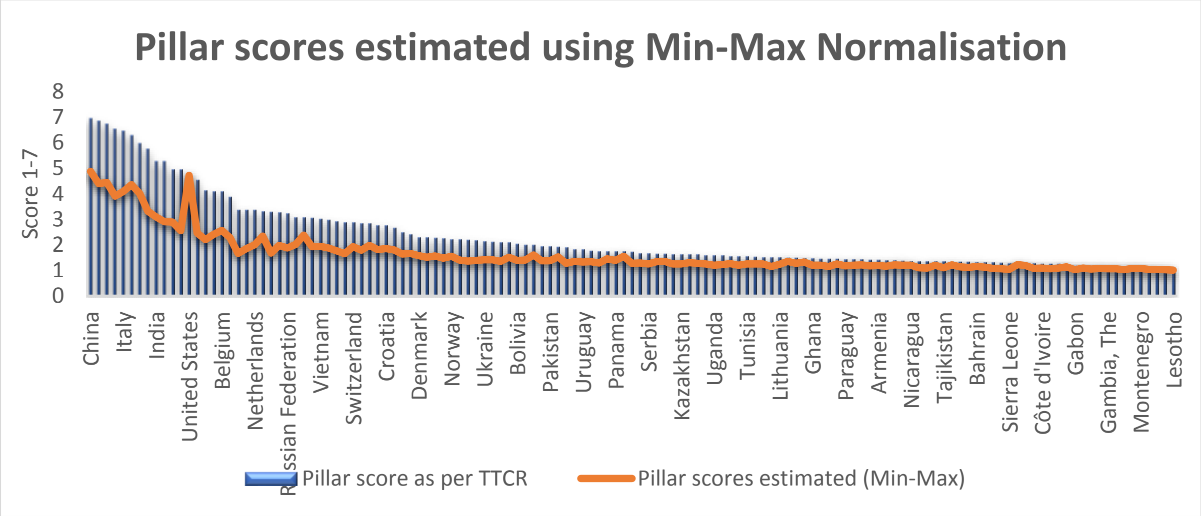

3. टीटीसीआर रिपोर्ट में दिए गए फार्मूले के अनुसार नमूने के न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों का उपयोग करके ऐसे असतत मूल्यों को सामान्यीकृत किया गया था: {6 * [(स्कोर - न्यूनतम) / (अधिकतम - न्यूनतम)] + 1}। हालांकि, वर्णित अंकों से एक महत्वपूर्ण विचलन देखा जा सकता है जो डाटा में बाहरी कारकों की मौजूदगी को दर्शाता है।

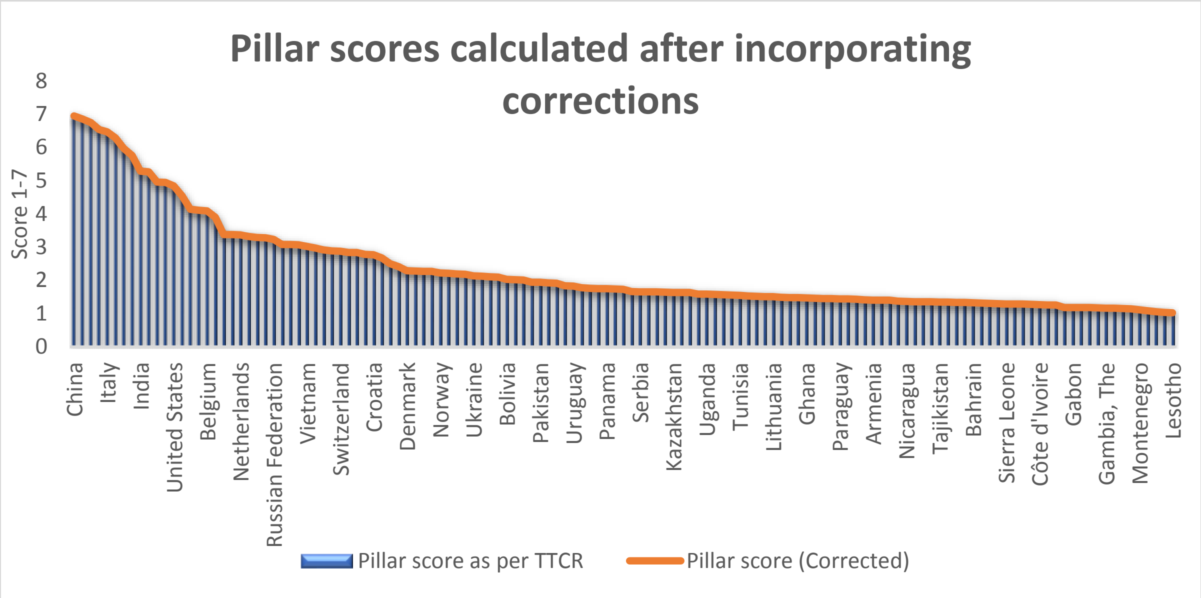

4. वैश्लेषिकी द्वारा संचालित अनुकूलन आलेख को तब सटीक फॉर्मूला-विशिष्ट मापदंडों पर पहुंचने के लिए निष्पादित किया गया था, जिसका उपयोग डब्ल्यूइऍफ़ द्वारा संकेतक के स्कोर को 1-7 के पैमाने पर सामान्य करने के लिए किया गया था।

एक बार जब संकेतक स्कोर और स्तंभ स्कोर के बीच संबंध को तर्कसंगत बना लिया जाता है, तो देश के स्कोर पर सभी दिए गए संकेतकों के स्कोर में परिवर्तन के सीधे प्रभाव की गणना की गयी थी और तदनुसार कार्य योजना विकसित की गई थी।

निम्न तालिका भारत के मूल्य के साथ-साथ सभी ठोस संकेतकों के लिए नमूना न्यूनतम और नमूना अधिकतम मूल्य दिखाती है:

ठोस संकेतकों का नमूना अधिकतम और नमूना न्यूनतम

संकेतक	संकेतक का नाम	भारत का मूल्य	नमूना न्यूनतम	नमूना अधिकतम
1.05	निर्माण परमिट से निपटने के लिए आवश्यक समय (दिन)	190	28	652
1.06	निर्माण परमिट से निपटने के लिए लागत (% निर्माण लागत)	25.9	0.1	42.4
1.08	व्यवसाय शुरू करने का समय (दिन)	26	0.5	230
1.09	व्यवसाय शुरू करने की लागत (% जीएनआई प्रति व्यक्ति)	13.8	0	159.8
1.12	कुल कर की दर (% लाभ)	60.6	11.3	106
1.12 a	श्रम और योगदान कर दर (% लाभ)	20	0	53.5
1.12 b	लाभ कर की दर (% लाभ)	20.9	0	38.9
1.12 c	मुनाफे की अन्य करों की दर (%)	15.7	0	108.1
2.04	आतंकवाद की मामलें का सूचकांक	1	1	7

2.05	मानव हत्या कादर (/ 100,000 जनसंख्या)	249.4	237.6	2325.3
3.01	चिकित्सक घनत्व (/1,000 जनसंख्या)	0.702	0.019	7.739
3.02	बेहतर स्वच्छता तक पहुंच (% जनसंख्या)	39.6	12	100
3.03	बेहतर पीने के पानी तक पहुंच (% जनसंख्या)	94.1	50.8	100
3.04	अस्पताल के बिस्तर (/10,000 जनसंख्या)	7	1	137
3.05	एचआईवी प्रसार (% व्यस्क जनसंख्या)	0.3	0.02	25.2
3.06	मलेरिया के मामले (/100,000 जनसंख्या)	1312.4	0.00	42724.9
4.01	प्राथमिक शिक्षा नामांकन (कुल %)	90.04	55.72	100
4.02	माध्यमिक शिक्षा नामांकन (सकल%)	74.28	22.4	164.81
4.09	श्रम बल में महिला की भागीदारी (पुरुषों के अनुपात में)	0.35	0.22	1.11
5.03	इंटरनेट उपयोगकर्ता (% जनसंख्या)	26	2.5	98.2
5.04	स्थाई ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता (/100 जनसंख्या)	1.3	0.00	45.1
5.05	मोबाइल-सेलुलर टेलीफोन सदस्यताएँ (/100 जनसंख्या)	78.1	37.9	231.8
5.06	मोबाइल-ब्रॉडबैंड सदस्यताएँ (/100 जनसंख्या)	9.4	1.4	144.0
5.07	मोबाइल नेटवर्क कवरेज (% जनसंख्या)	93.5	0	100
6.02	टीएंडटी सरकारी व्यय (% सरकार का बजट)	1	0.3	22
6.04	वार्षिक टीएंडटी डाटा की व्यापकता	39	8	116
6.05	मासिक / त्रैमासिक टीएंडटी डाटा प्रदान करने की समयबद्धता	22	3	22.5
6.06	देशीय ब्रांड रणनीति रेटिंग	72.7	28.9	98.8
7.01	वीज़ा की आवश्यक्ताएं	37	1	89
7.02	द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों का खुलापन	14.6	0.2	35.6
7.03	लागू क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की संख्या	20	1	53
8.01	टिकट कर और हवाई अड्डा शुल्क	88.0	3.8	100
8.02	होटल मूल्य सूचकांक (US$)	84.5	68.2	283.5

8.03	क्रय शक्ति समता (पीपीपी $)	0.3	0.3	1.3
8.04	ईंधन मूल्य स्तर (US$ सेंट / लीटर)	91	0.8	211
9.04	पार्टिकुलेट मैटर (2.5) सांद्रता (µg/m3)	32.9	0.6	47.2
9.05	पर्यावरण संधि अनुसमर्थन	24	14	30
9.06	बेसलाइन पानी का तनाव	3.7	0	5
9.07	लुप्तप्राय प्रजातियां (% कुल प्रजातियां)	13.5	1.6	37.2
9.08	वन कवर परिवर्तन (% परिवर्तन)	0.03	0.00	1.01
9.09	अपशिष्ट जल का उपचार (%)	2.2	0	100
9.10	कॉस्टल शेल्फ मछली पकड़ने का दबाव (टन /km2)	0.6	0.0	12.3
10.02	उपलब्ध सीट किलोमीटर, घरेलू (लाख)	1763.4	0.0	22812.2
10.03	उपलब्ध सीट किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय (लाख)	2013.8	0.3	12994.45
10.04	विमान प्रस्थान (/1,000 जनसंख्या)	0.6	0.0	147.1
10.05	हवाई अड्डे का घनत्व (हवाई अड्डे / करोड़ जनसंख्या)	0.2	0.1	25.7
10.06	ऑपरेटिंग एयरलाइंस की संख्या	89	1	220
11.05	लमार्ग घनत्व (सड़कों / भूमि क्षेत्र का किमी)	2.0	0.4	11.9
12.01	होटल के कमरे (संख्या / 100 जनसंख्या)	0.01	0.00	4.27
12.03	मुख्य कार किराए पर देने वाली कंपनियों की उपस्थिति	3	1.0	7.0
12.04	स्वचालित टेलर मशीनें (संख्या / हजार वयस्क जनसंख्या)	18.1	0.4	290.7

13.01	विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थलों की संख्या (स्थलों की संख्या)	7.5	0.0	14.0
13.02	कुल ज्ञात प्रजातियां (प्रजातियों की संख्या)	1889	96	3287
13.03	कुल संरक्षित क्षेत्र (% कुल क्षेत्रीय क्षेत्र)	5.3	0.2	53.9
13.04	प्राकृतिक पर्यटन डिजिटल मांग	22.5	0.2	97.3
14.01	विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की संख्या (स्थलों की संख्या)	27.5	1	47
14.02	मौखिक और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (अभिव्यक्ति की संख्या)	13	1	39
14.03	खेल स्टेडियम (बड़े स्टेडियमों की संख्या)	87	1	367
14.04	अंतरराष्ट्रीय संघ की बैठकों की संख्या	140.6	0.3	926
14.05	सांस्कृतिक और मनोरंजन पर्यटन डिजिटल मांग	50.69	0.4	91.95

सर्वेक्षण संकेतक के लिए कार्यप्रणाली

इन संकेतकों की गणना डब्ल्यूइऍफ़ द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण से की जाती है। सर्वेक्षण प्रतिस्पर्धात्मकता के महत्वपूर्ण पहलुओं का एक वार्षिक मूल्यांकन प्रदान करता है, जिसके लिए सांख्यिकीय डाटा अनुपलब्ध है क्योंकि इसे वैश्विक स्तर पर मापना असंभव या बेहद कठिन है। सर्वेक्षण का उद्देश्य वास्तविकता को यथासंभव सर्वोत्तम रूप से प्राप्त करना है, और व्यापारिक दिग्गज यकीनन इन पहलुओं का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं।

सर्वेक्षण का प्रशासन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर साझेदार संस्थानों के फोरम नेटवर्क द्वारा संचालित किया जाता है। साझेदार संस्थान आमतौर पर विश्वविद्यालय या अन्य अनुसंधान संगठन, व्यावसायिक संगठन, प्रतिस्पर्धा परिषद या सर्वेक्षण कंपनियां

हैं। इन संगठनों के पास प्रमुख व्यावसायिक अधिकारियों तक पहुंचने के लिए निजी क्षेत्र का नेटवर्क है और अपनी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता है।

साझेदार संस्थान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित टीटीसीआई रिपोर्ट के निष्कर्षों को व्यवसायिक समुदाय, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम को उजागर करने के लिए प्रेस इवेंट और कार्यशालाओं के आयोजन से प्रसारित करने में एक सक्रिय और आवश्यक भूमिका निभाते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) 2017 तक भारत के लिए साझेदार संस्थान था। 2018 से, लीडकैप नॉलेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (लीडकैप वेंचर्स) भारत के लिए भागीदार संस्थान है।

डब्ल्यूइएफ़ यादृच्छिकता सहित स्तरीकृत नमूनाकरण प्रक्रिया का उपयोग करता है। अंतिम नमूना प्रति देश न्यूनतम 80 प्रतिक्रियाओं (ब्रिक्स देशों के लिए न्यूनतम 300 प्रतिक्रियाएं प्रति देश) का बना हुआ होना चाहिए। उत्तरदाताओं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फर्म के शीर्ष पांच प्रबंधन पदों में से किसी एक स्थान पर होना चाहिए। उत्तरदाताओं के लक्षित नमूने में सरकारी एजेंसियों और / या मंत्रालयों के सार्वजनिक अधिकारी शामिल नहीं होने चाहिए।

साथी संस्थान को प्रत्येक स्ट्रेटम में लक्ष्य नमूना आकार की गणना करने के लिए पिछले वर्ष की समग्र प्रतिक्रिया दर का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पिछले वर्ष प्रतिक्रिया की दर 25% थी (यानी आपके द्वारा भेजे गए प्रत्येक चार के लिए एक सर्वेक्षण प्राप्त किया गया था), प्रत्येक स्ट्रैटम (श्रमिल-स्तर) (20) में वांछित प्रतिक्रियाओं की संख्या को 25% से विभाजित करें। अपरिवर्तनवादी होने के लिए, परिणाम को 40% तक बढ़ाएं। इसे इस प्रकार देखा जा सकता है:

वांछित प्रतिक्रियाओं की संख्या = 20 / 0.25 = 80

प्रत्येक स्ट्रैटम (श्रमिल-स्तर) में लक्षित नमूना आकार = 80 * 1.40 = 112

इसलिए, प्रत्येक स्ट्रेटम (श्रमिल-स्तर) में 112 कंपनियां, कुल 224 (मतलब 112 छोटी फर्में और 112 बड़ी फर्में) लक्षित होंगी।

नमूने को दो वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए:

1. **पुनरावृत्ति उत्तरदाताओं का नमूना अनुभाग -** पिछले वर्ष के उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण को दोहराने वाले उत्तरदाताओं के लिए 50% प्रतिक्रिया दर तक पहुंचने के समग्र लक्ष्य के साथ।
2. **यादृच्छिक उत्तरदाता नमूना अनुभाग -** संभावित नई प्रतिवादी फर्मों की लक्ष्य सूची तैयार करें।

नमूना फ्रेम को अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना को प्रतिबिंबित करना चाहिए। विशेष रूप से, प्राप्त किये गए सर्वेक्षण को कृषि, विनिर्माण उद्योग, गैर-विनिर्माण उद्योग और सेवाओं के प्रतिशत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

गतिविधि के क्षेत्र द्वारा फर्मों के नमूने को दो स्तरों में अलग किया जाना चाहिए:

1. अपने देश में 500 या अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए एक बड़ा फर्म स्ट्रैटम (भ्रमिल-स्तर) ।

2. अपने देश में 500 से कम कर्मचारियों पर 20 से अधिक कर्मचारी वाली फर्मों के लिए एक छोटा फर्म स्ट्रैटम (भ्रमिल-स्तर)। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फर्मों के प्रतिनिधि कार्यालयों या सहायक कंपनियों के लिए न्यूनतम 20 कर्मचारी मानदंडों को अनदेखा किया जा सकता है।

प्रत्येक अनुभाग का भार यानि दोहराने वाले उत्तरदाताओं (पिछले वर्ष) और यादृच्छिक उत्तरदाताओं (वर्तमान वर्ष) की गणना हर साल नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

For any given Survey question *i*, country *c*'s final score, $q_{i,c}^{2016-17}$, is given by:

$$q_{i,c}^{2016-17} = w_c^{2016} \times q_{i,c}^{2016} + w_c^{2017} \times q_{i,c}^{2017} \qquad (1)$$

where

$q_{i,c}^{t}$ is country *c*'s score on question *i* in year *t*, with t = 2016, 2017, as computed following the approach described in the text; and

w_c^t is the weight applied to country *c*'s score in year *t* (see below).

The weights for each year are determined as follows:

$$w_c^{2016} = \frac{(1-\alpha) + \dfrac{N_c^{2016}}{N_c^{2016} + N_c^{2017}}}{2} \qquad (2a) \qquad \text{and} \qquad w_c^{2017} = \frac{\alpha + \dfrac{N_c^{2017}}{N_c^{2016} + N_c^{2017}}}{2} \qquad (2b)$$

where N_c^t is the sample size (i.e., the number of respondents) for country *c* in year *t*, with t = 2016, 2017. α is a discount factor. Its value is set at 0.6. That is, the 2016 score of country *c* is given 2/3 of the weight given to the 2017 score.

Plugging Equations (2a) and (2b) into (1) and rearranging yields:

$$q_{i,c}^{2016-17} = \frac{1}{2} \times \underbrace{\left[(1-\alpha) \times q_{i,c}^{2016} + \alpha \times q_{i,c}^{2017}\right]}_{\text{discounted-past weighted average}} + \frac{1}{2} \times \underbrace{\left[\frac{N_c^{2016}}{N_c^{2016} + N_c^{2017}} \times q_{i,c}^{2016} + \frac{N_c^{2017}}{N_c^{2016} + N_c^{2017}} \times q_{i,c}^{2017}\right]}_{\text{sample-size weighted average}}. \qquad (3)$$

In Equation (3), the first component of the weighting scheme is the discounted-past weighted average. The second component is the sample-size weighted average. The two components are given half-weight each. One additional characteristic of this approach is that it prevents a country sample that is much larger in one year from overwhelming the smaller sample from the other year.

देशों की बकेटिंग

एक तालिका जो सभी देशों के प्रदर्शन का वर्णन करती है उसका संकेतकों में उल्लेख किया गया है। देशों की बकेटिंग, जिनके विरुद्ध पिछले कुछ वर्षों में भारत की श्रेणी की तुलना की जाती है, वह नीचे वर्णित की गयी हैं।

1. **शीर्ष प्रदर्शक:** इन देशों पर विचार किया जाता है क्योंकि वे अपने संबंधित संकेतकों में शीर्ष 5 देशों में से हैं
2. **एशियन साथी:** इन देशों को बेंचमार्क किया गया है क्योंकि वे समान जनसांख्यिकी होने के बावजूद भारत की तुलना में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं
3. **सर्वोत्तम प्रथाएँ:** इन देशों को उनके असाधारण प्रदर्शन के आधार पर देश में प्रचलित कुछ विशिष्ट पहल को अपनाने के कारण निर्धारित किया जाता है।
4. **प्रमुख प्रतियोगी:** इन देशों को बेंचमार्क किया गया है क्योंकि ये देश भारत के लिएतत्कालीन प्रतिस्पर्धा हैं

उप-सूचकांक -ए

वातावरण को सक्षम करना

पर्यावरण को सक्षम करने वाला उप सूचकांक, किसी देश में संचालन के लिए आवश्यक सामान्य पतिस्थिति पर कब्ज़ा करता है। इस उप-सूचकांक में स्तंभ सीधे तौर पर आर्थिक विकास से जुड़े हुए है और व्यापार विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें टीएंडटी क्षेत्र भी शामिल है पर विशेष रूप से नहीं।

इस उप-सूचकांक में 5 स्तंभ शामिल हैं:

1. व्यावसायिक वातावरण (12 संकेतक)

2. बचाव और सुरक्षा (5 संकेतक)

3. स्वास्थ्य और स्वच्छता (6 संकेतक)

4. मानव संसाधन और श्रम बाजार (9 संकेतक)

5. आईसीटी तत्परता (8 संकेतक)

स्तंभ 1: व्यावसायिक वातावरण

परिभाषा: यह स्तंभ उस हद तक कब्जा करता है, जब किसी देश के पास व्यापार करने के लिए कंपनियों के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण होता है। **स्तंभ 1** में कुल **12 संकेतक** दिए गए हैं -

1. संपत्ति पर अधिकार
2. ऍफ़डीआई पर नियमों का व्यावसायिक प्रभाव
3. विवादों को निपटाने में कानूनी ढांचे की क्षमता
4. चुनौतीपूर्ण विनियमों में कानूनी ढांचे की क्षमता
5. निर्माण परमिट से निपटने के लिए आवश्यक समय
6. निर्माण परमिट से निपटने के लिए लागत
7. बाजार के वर्चस्व का विस्तार
8. व्यवसाय शुरू करने का समय
9. व्यवसाय शुरू करने की लागत
10. काम करने के लिए प्रोत्साहन पर कराधान का प्रभाव
11. निवेश करने के लिए प्रोत्साहन पर कराधान का प्रभाव

12.. कुल कर की दर

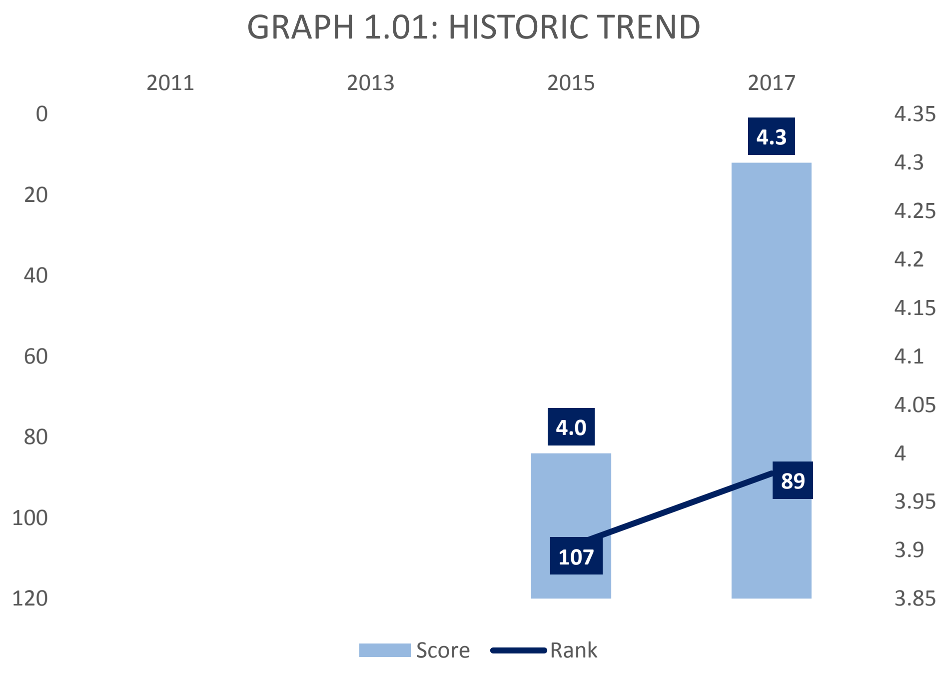

ग्राफ 1.01 भारत की श्रेणी और स्तंभ 1 में मूल्य के ऐतिहासिक रुझान को दर्शाता है। यह स्तंभ वर्ष 2015 में पेश किया गया था। भारत की श्रेणी 2015 में 107वें स्थान से बढ़कर 2017 में 89 वें स्थान पर पहुंच गई है।

भार का बदलना:

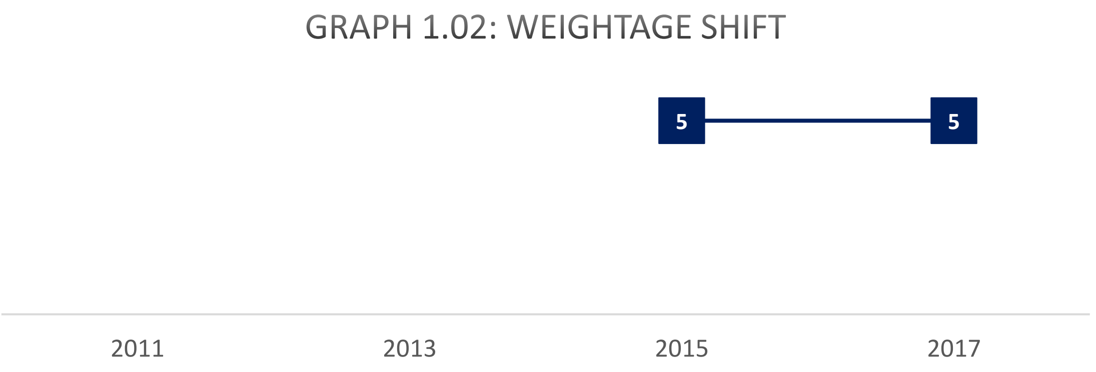

ग्राफ़ 1.02 भारत के स्कोर में स्तंभ 1 यानि व्यवसायिक वातावरण के समग्र योगदान को इंगित करता है। वर्तमान में, इस स्तंभ को 5% भार दिया जाता है।.

तालिका 1.01: संकेतक वार भार

संकेतक	2011-2013 (%)	2015-2017 (%)	भार में बदलाव (%)
संपत्ति पर अधिकार	0.74	1	35.13
ऍफ़डीआई पर नियमों का व्यावसायिक प्रभाव	0.74	1	35.13
विवाद को निपटाने में कानूनी ढांचे की क्षमता	N/A	0.12	N/A
चुनौतीपूर्ण विनियमों में कानूनी ढांचे की क्षमता	N/A	0.12	N/A
निर्माण परमिट से निपटने के लिए आवश्यक समय	N/A	0.12	N/A
निर्माण परमिट से निपटने के लिए लागत	N/A	0.12	N/A
बाजार के प्रभुत्व की अधिकता	N/A	1	N/A
व्यवसाय शुरू करने का समय	0.74	0.12	-83.78
एक व्यवसाय शुरू करने की लागत	0.74	0.12	-83.78
काम करने की प्रोत्साहन राशि पर कराधान का प्रभाव	N/A	0.12	N/A
निवेश करने के लिए प्रोत्साहन राशि पर कराधान का प्रभाव	N/A	0.12	N/A

कुल कर की दर	N/A	1	N/A

NA = लागू नहीं, उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

तालिका 1.01 उस योगदान का प्रतिशत दर्शाती है जो कि प्रत्येक संकेतक का भारत के समग्र स्कोर पर है

अस्वीकरण:

स्तंभ 1 के संबंध में, जो व्यापारिक पर्यावरण से संबंधित है, 12 संकेतक हैं जो विशेष प्रकृति के हैं और इसमें कुल कर की दर, संपत्ति के अधिकार, ऍफ़डीआईपर नियमों के व्यावसायिक प्रभाव आदि जैसे मानदण्ड शामिल हैं। ये विभिन्न सरकारी नीतिगत स्तर के हस्तक्षेपों पर आधारित हैं। और केवल वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के दायरे में आते हैं। यह भी देखा गया है कि इनमें से अधिकांश संकेतक वास्तव में 'व्यवसाय करने में आसानी' के संकेतक में आते हैं। अनुसंधान के दौरान, विशेषज्ञ स्रोतों के माध्यम से, यह पाया गया कि केपीएमजी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के लिए भारत में व्यवसाय करने में आसानी पर एक विस्तृत अध्ययन कर रहा है। यदि पर्यटन मंत्रालय इस अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम है, तो डाटा का उपयोग क्यूसीआई द्वारा स्तंभ 1 के तहत संकेतक के लिए अधिक निश्चित कार्रवाई अंक देने के लिए किया जा सकता है। इस बीच, इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए, क्यूसीआई द्वारा किए गए शोध के आधार पर कुछ सिफारिशें प्रदान करने का एक प्रयास किया गया है।

संकेतक 1.01: संपत्ति के अधिकार

परिभाषा: "अपने देश में वित्तीय संपत्ति सहित संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा कितनी मजबूत है?"

स्रोत: वर्ल्ड इकनोमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = बेहद कमजोर, 7 = अत्यंत मजबूत)

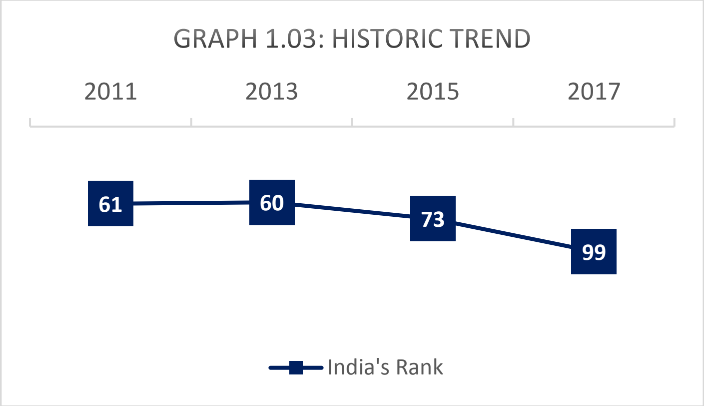

ग्राफ 1.03 संकेतक 1.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की रैंक 26 स्थान कम हो गई। इस संकेतक का देश के स्कोर में 1% का योगदान है।

तालिका 1.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
स्विट्जरलैंड	3	6.23	1	6.49	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
फिनलैंड	1	6.38	2	6.47	शीर्ष प्रदर्शक
स्वीडन	18	5.69	3	6.32	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**73**	**4.06**	**99**	**3.94**	

संपत्ति के अधिकार- संपत्ति का अधिकार सूचकांक उस सीमा को मापता है, जिस पर देश के कानून निजी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं, और वह डिग्री, जिसकी सरकार उन कानूनों को लागू करती है। वैश्विक संपत्ति गाइड संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण को एक आवासीय अचल संपत्ति निवेश की वांछनीयता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानता है। संपत्ति का अधिकार आर्थिक सफलता और राजनीतिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

सरकारी पहल

बेनामी लेनदेन अधिनियम[1]

- ○ अचल संपत्ति बाजार में काले धन के निवेश के कारण, संपत्तियों की कीमत आमतौर पर कृत्रिम रूप से उच्च बनी हुई है और इस तरह से अचल संपत्ति क्षेत्र के विकास को धीमा कर देती है। अधिशेष काला धन रखने वाले लोग इसे काल्पनिक नामों के तहत संपत्ति खरीदकर सरकार से छिपाकर रखते हैं, इस प्रकार कागज पर वे मालिक नहीं होते हैं बल्कि सभी लाभों का आनंद लेते हैं।
- ○ इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए भारत की संसद ने **बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम** लागू किया था जो की 1 नवंबर, 2016 से प्रभाव में आया है। एक बेनामी लेनदेन वह है जहां संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर होती है, लेकिन अधिग्रहण के लिए धनराशि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए, संपत्ति असली मालिक के नाम पर नहीं, बल्कि किसी और के नाम पर खरीदी जाती है है।
- ○ इस कानून का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम पर अघोषित संपत्ति हासिल करने से रोकना है। यह अधिनियम काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमले के लिए प्रमुख हथियारों में से एक है क्योंकि यह क्षेत्र में पारदर्शिता और व्यावसायिकता लाएगा और गरीबों के लिए किफायती आवास की अपनी योजना में सरकार की मदद करेगा। यह उधारदाताओं के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा जो वर्तमान में अशोध्य कर्ज से लड़ रहे हैं।

- रेरा **रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) प्राधिकरण**
  - ○ भूमि खरीदारों ने शिकायत की है कि अचल संपत्ति लेनदेन एकतर्फी और पूरी तरह से डेवलपर्स के पक्ष में थी। रेरा और सरकार का मॉडल कोड, विशेष रूप से प्राथमिक बाजार में, संपत्ति के विक्रेता और खरीदार के बीच एक अधिक न्यायसंगत और उचित लेनदेन बनाने का लक्ष्य रखता है[2]।
  - ○ अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा), घर खरीदारों के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाने का इरादा रखता है। यह देरी, कीमत, निर्माण की गुणवत्ता, शीर्षक और अन्य परिवर्तनों जैसे मुद्दों का समाधान करना चाहता है
  - ○ परियोजनाओं में देरी खरीदारों का सबसे बड़ा मुद्दा है। कारणों में अन्य परियोजनाओं के लिए धन का विभाजन, पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि जैसे अधिकारियों द्वारा

---
[1] https://www.livemint.com/Money/qS3VHjAvKWG1KzIDxH6i8N/How-new-benami-law-can-penalise-genuine-deals.html?utm_source=scroll&utm_medium=referral&utm_campaign=scroll
[2] https://indianexpress.com/article/what-is/what-is-rera-and-how-will-it-help-homebuyers-4635705/

विनियमों में परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के विकास और संचालन परिवहन में शामिल अन्य निकाय शामिल हैं। गुमराह बिल्डर्स अक्सर योजनाओं की मंजूरी के बिना, फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) में अनधिकृत वृद्धि, निर्माण की खराब गुणवत्ता, मुकदमेबाजी में फंसी परियोजनाएं आदि के बाद भीनिवेशकों को प्रोजेक्ट बेच देते हैं।

- रेरा बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर अचल संपत्ति की खरीद को सरल बना देगा। अधिनियम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपने स्वयं के नियामक और फ्रेम नियम बनाने के लिए अनिवार्य बनाता है जो नियामक 1 के कामकाज को नियंत्रित करेगा[1]।.

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय

अल्पकालिक योजना

- **डिजिटल लॉकर-** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, भारतीय नागरिकों को डिजिटल लॉकर का प्रावधान लागू किया जा रहा है। इसमें सभी कानूनी दस्तावेज को ऑनलाइन क्लाउड के व्यक्तिगत स्थान के तहत संग्रहीत किया जा सकता है जो सरकार के दायरे में होगा और आधिकारिक दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। एक बार डिजिटल लॉकर के तहत संग्रहीत संपत्ति के मालिक होने से संबंधित दस्तावेज स्वचालित रूप से दस्तावेज़ की प्रामाणिकता को सुरक्षित करेंगे और धोखाधड़ी के किसी भी अन्य मामलों में मदद करेंगे।

मध्यम अवधि की योजना

- **शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता**
  - डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में जिला अदालतों में 22 मिलियन से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 7.5 मिलियन सिविल केस हैं। बेंगलुरु स्थित एनजीओ दक्ष के एक अध्ययन के अनुसार, देश में सभी सिविल मामलों में लगभग दो-तिहाई भूमि और संपत्ति से संबंधित मामले हैं। इस प्रकार, भारत सरकार नीचे दिए गए देशों के उदाहरणों का पालन करके एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित कर सकती है:
  - सिंगापुर भूमि प्राधिकरण ने हाल ही में अपनी सेवाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए एक वेब पोर्टल पेश किया है।

- स्वीडिश लैंड और कैडस्ट्राल अथॉरिटी ने भूमि भूखंडों के नक्शे पर पहचानी गई त्रुटियों के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए एक नया तंत्र पेश किया।
- 2014 में वानुअतु ने पहली भूमि के लोकपाल को नियुक्त किया, जो सभी शिकायतों के निवारण के लिए एक अधिकारी है, जिसका कर्तव्य 30 दिनों के भीतर भूमि मंत्रालय और साथ ही ग्राहक को रिपोर्ट करना है।[3]
- **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भूमि लेनदेन पर आंकड़े एकत्र करने और प्रकाशित कर अपने साझेदारों को व्यस्त रख सकते हैं। लेन-देन के आँकड़े नियामकों के साथ-साथ रियल एस्टेट क्षेत्र को लाभान्वित कर सकते हैं, जो रियल एस्टेट बाजार की निगरानी के लिए नीति निर्माताओं के लिए डाटा विश्लेषण उपकरण के रूप में सेवारत हैं।**

दीर्घकालिक योजना

- **भूमि अधिग्रहण**
  - परियोजनाओं के लिए सरकार के अधिग्रहण का देश भर में विरोध हो रहा है। जालंधर में, 2003 में सूर्या एन्क्लेव योजना के लिए किसानों की लगभग 170 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था और उन्होंने उस समय से विभिन्न अदालतों में अधिग्रहण पुरस्कार को चुनौती दी थी। जबकि 2003 में किसानों को 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था, फिर भी उन्हें उस समायोजित राशि का इंतजार है जो 15 साल के लिए ब्याज के साथ दी जानी है। ऐसा ही एक और उदाहरण कांचीपुरम के किसानों का है, जो सरकार द्वारा कांचीपुरम बाईपास के लिए दी गई जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों को अभी भी ₹ 2.80 करोड़ रूपए से अधिक का बकाया नहीं मिला है।
  - स्विस फेडरल संविधान में तीन महत्वपूर्ण विशेषता तत्व हैं: संस्थागत गारंटी, अस्तित्व की गारंटी और संपत्ति मूल्य की गारंटी। संस्थागत गारंटी उनके अधिकारों में मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। अस्तित्व की गारंटी का कार्य राष्ट्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ स्वामित्व का आश्वासन देता है। **संपत्ति मूल्य की गारंटी यह सुनिश्चित करती है कि कब्जा-हरण पर पूरी तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए।**
  - स्विस फेडरल संविधान के लेख में दो धाराएं शामिल हैं: पहली धारा संपत्ति के मालिक होने का अधिकार प्रदान करती है और दूसरी धारा आगे परिभाषित करती है, कि प्रेषण और संपत्ति

[3] http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

प्रतिबंध, जो अनिवार्य खरीद के अनुरूप है, उसे पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। स्वामित्व की गारंटी संपत्ति कानून की चल और अचल वस्तुओं की सुरक्षा करती है।[4]

- **कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भूमि मालिकों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए स्विट्जरलैंड के समान रणनीति अपना सकते हैं।**

[4]https://knoema.com/IPRI2018/international-property-rights-index?location=1001430-switzerland

संकेतक 1.02: ऍफ़डीआई पर नियमों का प्रभाव

परिभाषा: "आपके देश में, नियम और कानून विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ऍफ़डीआई) को किस हद तक प्रोत्साहित या हतोत्साहित करते हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = दृढ़ता से ऍफ़डीआई को हतोत्साहित करें, 7 = दृढ़ता से ऍफ़डीआई को प्रोत्साहित करें)।

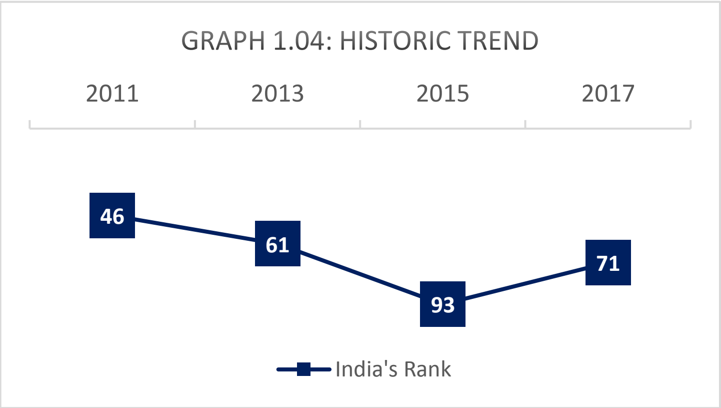

ग्राफ 1.04 संकेतक 1.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 22 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

तालिका1.03: देशों के प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
आयरलैंड	1	6.58	1	6.43	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
हांगकांग एसएआर	3	6.23	2	6.39	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	2	6.34	3	6.10	शीर्ष प्रदर्शक
स्वीडन	25	4.99	4	6.05	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**93**	**4.18**	**71**	**4.60**	

- **सरकारी पहल**

- 2017 में, भारत सरकार ने राज्यों को भारत में जापानी निवेश बढ़ाने के लिए तेजी से ट्रैक होने वाले ऍफ़डीआई अनुमोदन प्रक्रियाओं के लिए **एकल खिड़की निकासी प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।** [5].
- भारत सरकार ने आवेदन की प्राप्ति के बाद 10 सप्ताह के भीतर अनुमोदन की आवश्यकता वाले सभी प्रस्तावों को मंजूरी देकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ऍफ़डीआई) प्रस्तावों के लिए अनुमोदन तंत्र को आसान कर दिया है। [6].
- भारत सरकार मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए और उत्पन्न करने के लिए, स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ऍफ़डीआई) को मौजूदा 49 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक कम करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है[2].
- जनवरी 2018 में, भारत सरकार ने स्वचालित मार्ग से एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 100 प्रतिशत ऍफ़डीआई की अनुमति दी। [7].

अस्वीकरण: कई कारक हैं जो किसी देश में ऍफ़डीआईई प्रवाह को प्रभावित करते हैं। इसलिए, किसी भी नीति पर टिप्पणी करना संभव नहीं होगा। हालांकि, हमारे शोध के आधार पर, कुछ बिंदु जो ऍफ़डीआई प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं, वह एक कार्य योजना के रूप में दिए गए हैं।.

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **ऍफ़डीआई प्रवाह को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट कर को कम करना**
  - यह देखा गया है कि उच्च कॉर्पोरेट कर सीधे देश के ऍफ़डीआई को प्रभावित करते हैं। भारत में अत्यधिक उच्च कॉर्पोरेट कर है जो 30% से 35% के बीच है। 2009 के बाद से स्वीडन ने कॉरपोरेट कर की दर को कम कर दिया है, जो यूरोप यूनियन (ईयू) में सबसे अधिक 28% है। 22% की वर्तमान स्वीडिश कॉर्पोरेट आयकर दर 2019 में घटकर 21.4% रह जाएगी और फिर मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के माध्यम से 2021[8] में घटकर 20.6% रह जाएगी।

---

[5] http://www.fifp.gov.in/

[6] https://www.ibef.org/economy/foreign-direct-investment.aspx

[7] https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/ireland/foreign-investment

[8]https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Sweden_proposes_draft_bill_with_major_corporate_income_tax_changes/$FILE/2018G_01830-11Gbl_Sweden%20proposes%20major%20corporate%20income%20tax%20changes.pdf

तालिका 1.04: ऍफ़डीआई (अरबों डॉलर में) और देशों में कॉर्पोरेट कर दर[9] [10]

देश	कॉर्पोरेट कर दर (2018)	ऍफ़डीआई (USD अरबों में) 2016	ऍफ़डीआई (USD अरबों में) 2017
आयरलैंड	12.50%	22,300	39,104
स्वीडन	22%	11,933	18,612
भारत	**35%**	**5,048**	**11,090**

स्रोत: ओईसीडी और केपीएमजी रिपोर्ट

- **आयरलैंड** ने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कमी की है जो ऍफ़डीआई[11] के लिए आकर्षण का एक प्रमुख बिंदु है। उच्च ऍफ़डीआई में सरकार को यह लाभ है कि एकत्र किए गए कर राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता है। यह उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि एकत्र किए गए राजस्व को विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्वितरित किया जा सकता है।
- **औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के माध्यम से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और संबंधित अर्थव्यवस्थाओं पर उनके प्रभाव के आधार पर भारत में ऍफ़डीआई को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित कर सकता है।**

मध्यम अवधि की योजना

- **डाटा की पहुँच को बढ़ाने के लिए रिपोर्ट प्रकाशित करके जागरूकता बढ़ाना।**
    - आईबीएम की 2017 की ग्लोबल लोकेशन ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अमेरिका को प्रतिस्थापित करते हुए जो कि पिछले चार वर्षों से नेतृत्व कर रहा था, विदेशी निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान लिया है। ऍफ़डीआई में लगभग 25 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद

[9] https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html
[10] https://data.oecd.org/fdi/fdi-flows.htm
[11] https://www.thejournal.ie/ireland-corporate-tax-rate-davos-stealing-3817678-Jan2018/

मेक्सिको को तीसरे स्थान से सम्मानित किया गया। चीन और थाईलैंड शीर्ष पांच से बाहर हो गए।

- इमर्जिंग मार्केट प्राइवेट इक्विटी एसोसिएशन (ईएमपीईए)[12] द्वारा हाल ही में किए गए बाजार के आकर्षण सर्वेक्षण के अनुसार, भारत वर्ष 2018 के लिए वैश्विक भागीदारों (जीपी) के निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरता हुआ बाजार बन गया है।. **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय लोगों की धारणा को बेहतर बनाने के लिए ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करने में सहयोग कर सकता है।**
- विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19[13] में भारत में निजी निवेश में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो कि 7.4 प्रतिशत की निजी उपभोग वृद्धि को पीछे छोड़ देगा, और इस तरह वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि को बढ़ावा देगा। **लोगों की राय बदलने के लिए ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की जा सकती हैं।**

दीर्घकालिक योजना

भारत सरकार ने 2014 में **मेक इन इंडिया** पहल शुरू की जिसके तहत 25 क्षेत्रों के लिए ऍफ़डीआई नीति को उदार बनाया गया. ऍफ़डीआई के लिए खोले गए प्रमुख क्षेत्रों में रक्षा विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, निजी सुरक्षा एजेंसियां, रेलवे, बीमा और पेंशन और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।

- कई कारक हैं जो ऍफ़डीआई के कारण प्रभावित होते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। इसलिए, सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी ऍफ़डीआई नीति पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। हालांकि, कुछ सिफारिशें हैं कि जिसमें जिन क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग या सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% ऍफ़डीआई नहीं है, उन्हें 100% ऍफ़डीआई की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है जैसा कि तालिका 1.05 में दिया गया है।
- **सरकार को देश में ऍफ़डीआई अंतर्वाह बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए नियम बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढाँचे में 100 प्रतिशत ऍफ़डीआई की अनुमति दी है। इसी तरह, भारत सरकार ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है और स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत ऍफ़डीआई की अनुमति दे रही है।**

---

[12] https://www.empea.org/app/uploads/2017/03/EMPEA.LP_.Survey.2010.US_.web_.pdf
[13] https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/14/india-growth-story-since-1990s-remarkably-stable-resilient

- **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ सहयोग कर सकता है कि वह अज्ञात क्षेत्रों का अध्ययन कर सकता है जहाँ ऍफ़डीआई प्रत्यक्ष और प्रमुख प्रभाव डाल सकते हैं।**

तालिका 1.05: जीडीपी और ऍफ़डीआई वितरण क्षेत्रवार

क्षेत्र	जीडीपी (प्रवाह USD अरबों में)	ऍफ़डीआई (%)
संचार और दूरसंचार सेवाएं	8,809	100%
विनिर्माण	7,066	100%
खुदरा और थोक व्यापार (एकल ब्रांड)	4,478	100%
वित्तीय सेवा (बैंकिंग)	4,070	74 % निजी 20% सार्वजनिक
कंप्यूटर सेवाएं	3,173	100%
व्यापार सेवाएँ	3,005	100%
बिजली और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन	1,870	49%
निर्माण	1,281	100%
परिवहन	1,267	100%
विविध सेवाएँ	835	_
रेस्तरां और होटल	452	100%
अचल संपत्ति गतिविधियाँ	405	100%
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	347	100%
खनन	82	100%
ट्रेडिंग (मल्टी ब्रांड ट्रेडिंग)	0	51%
कृषि क्षेत्र	3,370	100%
खनन और उत्खनन	437	100%

नोट-: संकेतक 1.03 और 1.04 को एकल संकेतक के रूप में दिखाया गया है क्योंकि ये दोनों संकेतक अन्योन्याश्रित हैं और समान मानदंडों पर निर्भर करते हैं।

संकेतक 1.03: विवादों को निपटाने में कानूनी ढांचे की क्षमता

परिभाषा:: "आपके देश में, विवादों को निपटाने में निजी व्यवसाय के लिए कानूनी ढांचा कितना कुशल है।"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = अत्यंत अक्षम, 7 = अत्यंत कुशल)

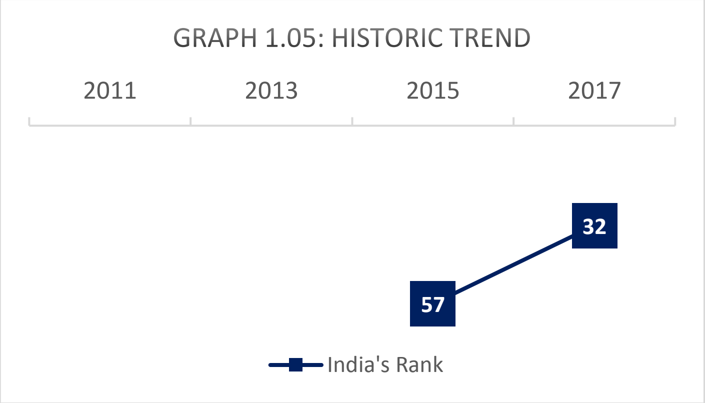

ग्राफ़ 1.05 संकेतक 1.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, वर्ष 2015 की तुलना में भारत की श्रेणी में 25 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.125% का योगदान देता है।

तालिका 1.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
सिंगापुर	1	6.16	1	6.23	एशियाई साथी
हांगकांग	3	5.93	2	5.99	एशियाई साथी
स्विट्जरलैंड	8	5.55	3	5.75	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**57**	**3.84**	**32**	**4.59**	

संकेतक 1.04: चुनौतीपूर्ण नियमों में कानूनी ढांचे की क्षमता

परिभाषा: "आपके देश में, निजी व्यवसायों के लिए सरकारी कार्यों और / या कानूनी प्रणाली के माध्यम से नियमों को चुनौती देना कितना आसान है?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = अत्यंत कठिनाई, 7 = अत्यंत आसान)

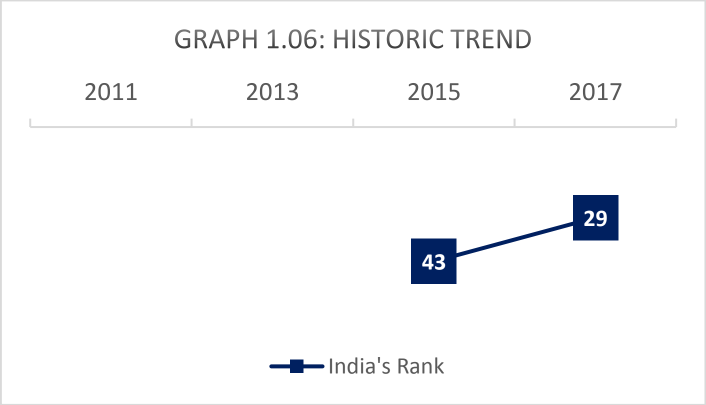

ग्राफ़ 1.06 संकेतक 1.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, वर्ष 2015 की तुलना में भारत की श्रेणी में 14 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.125% का योगदान देता है।

तालिका 1.07: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
स्विट्जरलैंड	8	4.93	1	5.84	शीर्ष प्रदर्शक
फिनलैंड	1	5.56	2	5.76	शीर्ष प्रदर्शक
हांगकांग	3	5.39	3	5.55	एशियाई साथी
यूएई	15	4.70	20	4.72	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**43**	**3.76**	**29**	**4.43**	

सरकारी पहल

- **मध्यस्थता को आसान बनाना**

  भारत ने मध्यस्थता से संदर्भित विवादों की संख्या में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि देखी है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां संस्थागत मार्ग पर तदर्थ मध्यस्थता पसंद करती हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 2015 वाणिज्यिक विवादों की बढ़ती संख्या और जटिलता को संबोधित करता है जो पिछले पांच वर्षों में बढ़ गया। नया कानून मध्यस्थ प्रणाली के साथ सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को संबोधित करता है यानी पुरस्कारों के निपटान में देरी। पुराने कानून के तहत, यदि मध्यस्थता की कार्यवाही में देरी करना किसी पार्टी के हित में होता था तो, वह पार्टी पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को नियोजित करने में सक्षम था, जो पूरी प्रक्रिया को वर्षों तक खींच सकती थी, लेकिन 12 महीने की समय-सीमा को लागू करके, सरकार को उम्मीद है कि व्यवसायों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया को सरल और तेज किया जाएगा।[14].

- **वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना:**

  उच्च न्यायालयों के अधिनियम, 2015 के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग, भारतीय उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभागों और जिला स्तर पर विशेष वाणिज्यिक न्यायालयों के निर्माण को अधिकृत करके मध्यस्थताऔर सुलह अधिनियम के माध्यम से किए गए सुधारों का विस्तार करते हैं। इसका उद्देश्य उच्च मूल्य "वाणिज्यिक विवादों" के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है, और मध्यस्थता कानून की तरह, वाणिज्यिक विवादों के सुचारू और शीघ्र समाधान की सुविधा प्रदान करना है।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय

मध्यम अवधि की योजना

  - **भारत में मध्यस्थता और उसके प्रवर्तन को मजबूत करने की आवश्यकता**

[14] https://www.india-briefing.com/news/government-passes-bills-improve-dispute-resolution-ease-business-11591.html/

- निति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में विवाद समाधान के लिए 1,420 दिन और दावा मूल्य का 39.6% है। नीचे दी गई तालिका अन्य देशों के लिए विवादों को हल करने के लिए समय और लागत दोनों पर तुलनात्मक डाटा दिखाती है।[15]

तालिका 1.09: भारत में एक वाणिज्यिक विवाद को समाप्त करने के लिए लगने वाले दिनों की संख्या और लागत

देश	समय (दिन)	लागत (दावे का %)
बांग्लादेश	1442	66.08
भारत	**1420**	**39.06**
क्षेत्रीय औसत दक्षिण एशियाई देश	1077	30.05
ओईसीडी	538.03	27.01
चीन	452.08	16.02
रूस	307	16.05

- भारत में मध्यस्थता उच्च लागत और अत्यधिक देरी से ग्रस्त है, जो मध्यस्थता को आम नागरिक की पहुंच से दूर रखता है। बड़े निगम दुबई और सिंगापुर जैसे क्षेत्राधिकार में अपनी मध्यस्थता लेना पसंद करते हैं और उपर्युक्त कारणों से भारत को पसंद नहीं करते हैं। सिंगापुर या यूएस जैसे देशों की तुलना में, जहां एक सप्ताह या अधिकतम कुछ महीनों में एक अनुबंध लागू किया जा सकता है, दुबई, सिंगापुर और हांगकांग जैसे न्यायालयों में अधिकतम, एक बड़ी मध्यस्थता को एक ही दिन में पूरा किया जा सकता है। प्रवर्तन का खतरा लोगों को अवसरवादी रूप से टूटने वाले अनुबंधों से रोकता है, इस प्रकार व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को विश्वसनीय और भरोसेमंद रखता है।[16]
- **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सहयोग से कानून और न्याय मंत्रालय को विश्वसनीय, स्वतंत्र, कुशल और पारदर्शी मध्यस्थ संस्था के लिए एक स्थिर और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना चाहिए। और तो और, इसे शारीरिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे के अलावा, गुणात्मक मध्यस्थता के लिए पुस्तकालय, अच्छी तरह से प्रशिक्षित सहायक कर्मचारियों के साथ मजबूत किया जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया अभियान के साथ सिस्टम को जोड़ा जाए ताकि ई-फाइलिंग, ई-ऑफिस, ई-लॉकर, मामलों के डाटाबेस का निर्माण, बड़े डाटा एनालिटिक्स, ऑनलाइन विवाद**

[15] https://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Arbitration.pdf
[16] https://thewire.in/business/how-does-india-plan-on-solving-its-crippling-contract-enforcement-problem

समाधान आदि जैसे प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को शुरू करने से मध्यस्थता की प्रक्रिया की लागत कम हो जाएगी क्योंकि इससे कॉर्पोरेट विवादों के समाधान की प्रक्रिया तेज होगी।

दीर्घकालिक योजना

- **भारत में विवाद समाधान पर न्यायाधीशों की पृष्ठभूमि और भविष्य की आवश्यकता**[17]
  - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार भारत में विभिन्न अदालतों में 3.3 करोड़ मामले लंबित हैं। सभी लंबित मामलों में से, 60% दो साल से अधिक पुराने हैं, जबकि 40% पांच साल से अधिक पुराने हैं। सुप्रीम कोर्ट में, 30% से अधिक लंबित मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं। सबसे ज्यादा लंबमानता देने वाले पांच राज्य उत्तर प्रदेश (61.58 लाख), महाराष्ट्र (33.22 लाख), पश्चिम बंगाल (17.59 लाख), बिहार (16.58 लाख) और गुजरात (16.45 लाख) हैं।

तालिका 1.08: लंबित मामलों की संख्या

कोर्ट	लंबित मामलों की संख्या
सुप्रीम कोर्ट	57,987
उच्च न्यायालय	43 लाख
अधीनस्थ न्यायालय	2.84 करोड़

[17] https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/3-3-crore-cases-pending-indian-courts-pendency-figure-highest-cji-dipak-misra/story/279664.html

- देश भर की अदालतों में वाणिज्यिक विवादों की लंबमानता 2015 की तुलना में 2017 में 123% से अधिक हो गई है। कानून मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2015 में 17,539 मामलों में अदालतों में वाणिज्यिक विवादों की स्थिति बढ़ गई है। 2017 में 39,141।
- दिल्ली शीर्ष श्रेणी पर होने वाले राज्य के रूप में उभरा है, जिसमें सबसे अधिक संख्या वाणिज्यिक विवादों की है, 2017 में 16,267 केस नामित अदालतों में लंबित है, जो 2015 के लंबित केस में 152% की वृद्धि है। देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य यूपी 11,796 वाणिज्यिक विवादों के साथ दूसरे स्थान पर है और जम्मू और कश्मीर वर्ष 2017 के अंत में लंबमानता 6,200 से अधिक वाणिज्यिक केस के साथ है, जो लंबमानता सूची में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से अधिक है। [18]

JUDICIAL VACANCIES

In some states, the current strength and rate of disposal is enough to dispose of all cases more than two years old within the next three years, whereas in others, the sanctioned strength of judges needs to be increased dramatically.

		Judges required		
	Current strength (as on 1 Jan 2016)	to clear cases older than two years	to clear all pending cases	as per CJI/Law Commission
Bihar	**1,067**	2,896	**3,581**	5,190
Uttar Pradesh	**1,825**	2,489	**2,936**	9,964
Maharashtra	**1,917**	1,989	**2,531**	5,619
Gujarat	**1,170**	1,548	**1,795**	3,019
Madhya Pradesh	**1,215**	1,405	**1,622**	3,630
West Bengal and Andaman and Nicobar	**868**	1,167	**1,493**	4,567
Andhra Pradesh and Telangana	**786**	983	**1,253**	4,234
Rajasthan	**985**	949	**1,094**	3,431
Tamil Nadu	**969**	945	**1,041**	3,607
Karnataka	**820**	921	**1,095**	3,057
Odisha	**598**	878	**1,093**	2,097
Jharkhand	**466**	664	**810**	1,648
Delhi	**490**	525	**1,019**	838
Haryana	**474**	479	**577**	1,268
Punjab	**490**	469	**552**	1,385
Kerala	**442**	468	**575**	1,669
Chhattisgarh	**341**	372	**446**	1,277
Assam	**319**	289	**340**	1,558
Jammu and Kashmir	**220**	213	**233**	627
Uttarakhand	**206**	196	**224**	506
Himachal Pradesh	**134**	138	**150**	343
Tripura	**68**	79	**93**	184
Goa	**48**	50	**63**	73
Mizoram	**30**	33	**37**	55
Manipur	**34**	32	**34**	136
Meghalaya	**30**	30	**32**	148
Nagaland	**25**	27	**32**	99
Chandigarh	**30**	22	**24**	53
Arunachal Pradesh	**15**	19	**24**	69
Puducherry	**14**	13	**15**	62
Sikkim	**14**	12	**14**	30
Daman and Diu	**6**	6	**8**	29
Lakshadweep	**3**	3	**4**	3

- भारत सरकार के पास कानून मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औसतन प्रति 10 लाख लोगों पर 19 न्यायाधीश हैं, जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका को 6,000 से अधिक न्यायाधीशों की संयुक्त कमी का सामना करना पड़ता है, जिसमें से 5,000 से अधिक तो निचली अदालतों में शामिल हैं। आंकड़ों, संसद में चर्चा के लिए मार्च, 2018 में तैयार किए गए एक दस्तावेज के हिस्से के अनुसार, जज-जनसंख्या अनुपात 19.49 प्रति मिलियन (10 लाख) लोग हैं।[19]

---

[18] https://timesofindia.indiatimes.com/india/number-of-pending-commercial-disputes-has-arisen-by-123-in-2017/articleshow/65168645.cms
[19] https://www.thehindubusinessline.com/news/india-has-19-judges-per-10-lakh-people-data/article25030009.ece

- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर (सीजेआई) / विधि आयोग के अनुसार जनवरी 2016 तक 16,119 न्यायाधीश हैं और 2 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को निपटाने के लिए 20,312 न्यायाधीशों की आवश्यकता है, सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए 24,839 न्यायाधीशों की आवश्यकता है और सीजेआई / विधि आयोग के अनुसार 60,476 न्यायाधीशों की आवश्यकता है। उपरोक्त आँकड़े स्पष्ट रूप से **"न्यायिक रिक्तियों"** में उल्लिखित विभिन्न राज्यों में रिक्तियों को भरने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं।[20]

इसलिए, समस्या से छुटकारा पाने और स्थिति से निपटने के लिए तत्काल उपाय लागू करने की आवश्यकता है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सहयोग से कानून और न्याय मंत्रालय को इस विशाल अंतर को भरने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो न केवल रिक्तियों को कम करेगा, बल्कि भारत में विवाद सुलझाने की दर को अधिक गति से बढ़ाएगा।

[20] https://www.livemint.com/Politics/OdHaDzBHLpvG8M2Wj4pAoJ/Narendra-Modi-assures-CJI-Thakur-of-govt-support-in-increasi.html

नोट - संकेतक 1.05 और 1.06 का विलय किया गया है क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं और दोनों ही निर्माण परमिट से निपटने के लिए समय और लागत पर निर्भर करते हैं।

संकेतक 1.05: निर्माण परमिट से निपटने के लिए समय आवश्यकता

परिभाषा: यह सूचक गोदाम बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं से निपटने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या को संदर्भित करता है। यह मध्य अवधि (दिनों की संख्या में) को मापता है जो एक व्यवसाय के लिए गोदाम बनाने के लिए स्थानीय विशेषज्ञों को संकेत देता है। अवधि निम्नलिखित प्रक्रियाओं को ध्यान में रखती है:

- सभी प्रासंगिक परियोजना-विशिष्ट दस्तावेजों को प्राप्त करना और अधिकारियों को जमा कराना।
- बाहरी तृतीय-पक्ष पर्यवेक्षकों, इंजीनियरों या निरीक्षक को काम पर रखना
- सभी आवश्यक मंजूरी, लाइसेंस, परमिट और प्रमाण पत्र प्राप्त करना
- सभी आवश्यक सूचनाएं जमा करना
- पानी और सीवरेज के लिए कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक निरीक्षणों के साथ-साथ सभी प्रक्रियाओं का अनुरोध करना और उन्हें प्राप्त करना

स्रोत: वर्ल्ड बैंक / इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डूइंग बिजनेस 2017 इक्वल ऑपर्चुनिटी फॉर ऑल

देश का मूल्य = गोदाम बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं से निपटने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या

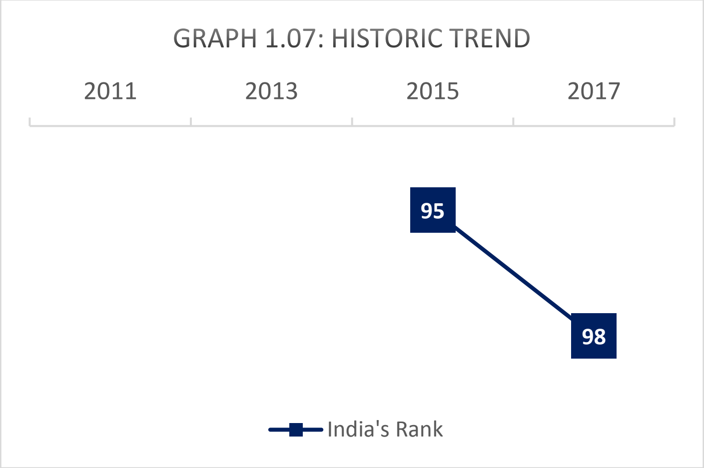

ग्राफ 1.07 संकेतक 1.05 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 3 पदों में कमी आई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.125% का योगदान देता है।

तालिका 1.10: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण

कोरिया गणराज्य	2	29	1	28	एशियाई साथी
जॉर्जिया	11	68.5	2	48	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	1	26	2	48	एशियाई साथी
भारत	**95**	**185.9**	**98**	**190**	

संकेतक 1.06: निर्माण परमिट से निपटने के लिए लागत

परिभाषा: यह संकेतक उस लागत को संदर्भित करता है जिसे गोदाम मूल्य के प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया है। यह व्यवसाय के लिए एक गोदाम बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं से जुड़ी लागत को मापता है (इसके मूल्य के संबंध में)

यह लागत निम्नलिखित प्रक्रियाओं से संबंधित है:

- सभी प्रासंगिक परियोजना-विशिष्ट दस्तावेजों (उदाहरण के लिए, योजनाओं का निर्माण, साइट मानचित्र और शहरीकरण के प्रमाण पत्र) को प्राप्त करना और अधिकारियों को जमा कराना।
- बाहरी तृतीय-पक्ष पर्यवेक्षकों, इंजीनियरों या निरीक्षकों को काम पर रखना
- सभी आवश्यक मंजूरी, लाइसेंस, परमिट और प्रमाण पत्र प्राप्त करना
- सभी आवश्यक सूचनाएं जमा करना; तथा
- पानी और सीवरेज के लिए कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक निरीक्षणों के साथ-साथ सभी प्रक्रियाओं का अनुरोध करना और उन्हें प्राप्त करना।

स्रोत: वर्ल्ड बैंक / इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डूइंग बिजनेस

देश का मूल्य = लागत गोदाम मूल्य के प्रतिशत के रूप में दर्ज की जाती है

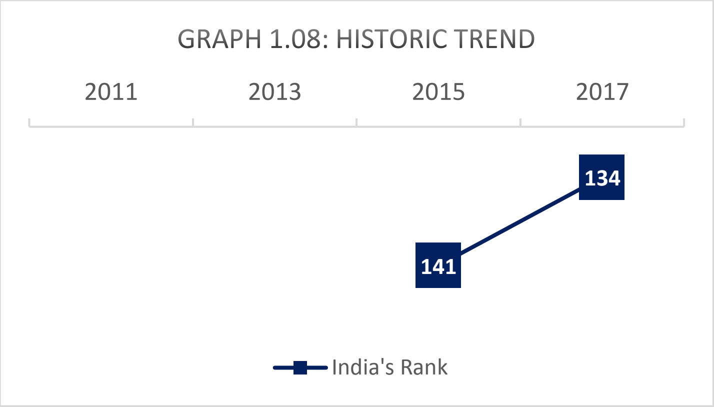

ग्राफ 1.08 संकेतक 1.06 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 7 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.125% का योगदान देता है।

तालिका 1.11: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
थाईलैंड	3	0.1	1	0.1	एशियाई साथी
हंगरी	6	0.2	5	0.2	शीर्ष प्रदर्शक
चेक गणराज्य	11	0.3	9	0.3	शीर्ष प्रदर्शक
ऑस्ट्रेलिया	25	0.5	18	0.5	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
बुरुंडी	130	10.1	124	10.4	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**141**	**28.2**	**134**	**25.9**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

अल्पकालीन योजना

तालिका 1.12: दिल्ली और मुंबई के लिए निर्माण परमिट मूल्य

अर्थव्यवस्था	वर्ष	प्रक्रियायों की संख्या	समय (दिन)	प्रक्रियाओं की लागत लाखों में (वेयरहाउस मूल्य का %)
दिल्ली	2016	24	213	27.5
मुंबई	2016	42	164	25.3
दिल्ली	2017	29	213	26.2
मुंबई	2017	42	164	25
दिल्ली	**2018**	**24**	**157.5**	**23.9**
मुंबई	**2018**	**37**	**128.5**	**22.5**

परमिट के निर्माण के लिए प्रक्रियाओं और दिनों की संख्या वर्ष 2016 में 56 दिनों से बढ़कर वर्ष 2018 में 144 दिन हो गई है। इसके अलावा, प्रक्रियाओं की संख्या वर्ष 2015 में 36 से बढ़कर वर्ष 2017 में 38.8 हो गई है।

- **एकल खिड़की लाइसेंसिंग**
  - टीएमएफ ग्लोबल रिसर्च ग्रुप के अनुसार[21], भारत को 2017 में वर्ल्ड बैंक द्वारा सर्वेक्षण के लिए आवेदन करने के बाद निर्माण परमिट प्राप्त करने में लगने वाले समय में 190 देशों में

[21] https://www.tmf-group.com/en/news-insights/articles/top-challenges/doing-business-in-india/

185 वें स्थान पर रखा गया था। पहले, मुंबई में एक निर्माण परमिट प्राप्त करने में 164 दिन और 42 प्रक्रियाएं लगा करती थी, और दिल्ली में 213 दिन और 29 प्रक्रियाएं लगा करती थी[1]। सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक से चार महीने के बीच लग सकते हैं, फीस और ऐड-ऑन लागत के साथ जो पंजीकृत व्यवसाय के आकार और प्रकार पर निर्भर करती हैं।

- थाईलैंड में, नए निर्माण के लिये और मौजूदा निर्माण को जोड़ने / संशोधित करने के लिए एक एकल निर्माण परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता होती है। निर्माण परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया में 45 दिन (अधिकतम 135 दिन) लगते हैं। नए निर्माण / उपयोग में परिवर्तन के लिए सरकारी शुल्क के रूप में इसकी कीमत केवल 20 थाई भाट (लगभग 50 रुपए) है। निर्माण[22] की सादगी या जटिलता या अधिकार क्षेत्र के आधार पर किस प्राधिकरण के बारे में प्रक्रिया और विवरण स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- सभी परमिटों को एक मंच पर लागू किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग सिस्टम के माध्यम से परियोजनाओं के लिए एक एकल खिड़की अनुमोदन को लागू किया गया है ताकि दस्तावेजों (उदाहरण के लिए, योजनाओं का निर्माण, साइट मानचित्र और शहरीवाद के प्रमाण पत्र) को एकीकृत किया जा सके और परियोजनाओं को एक सप्ताह के भीतर ही मंजूरी दी जा सके।
- **इसलिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आवास और शहरी कार्य मंत्रालय थाईलैंड के समान पदचिन्हों पर चलते हुए भारत में एकल खिड़की लाइसेंसिंग को लागू करने पर विचार कर सकता है।**

मध्यम अवधि की योजना

- **निर्माण परमिट की लागत को कम करना**
  - विश्व बैंक समूह[23], द्वारा प्रकाशित डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण परमिट की लागत से निपटने के लिए भारत सबसे खराब मूल्यांकन वाले देशों में से है। निर्माण अनुमति से निपटने के लिए औसत रूप से 23.2 लाख रुपये लगते हैं, जैसा कि तालिका 1.13 में बताया गया है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 1,631% है। बुरुंडी में, निर्माण परमिट से निपटने के लिए लगभग बीआईएफ़ 29,87,000 (लगभग 1,17,000 रुपये) लगते हैं।

[22] http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/thailand/THA.pdf
[23] http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB12-Chapters/Dealing-with-construction-permits.pdf

- ○ **बुरुंडी** ने भू-तकनीकी अध्ययन के लिए शुल्क संरचना में बदलाव किया, प्रति व्यक्ति आय[24] के 1,968% द्वारा निर्माण परमिट से निपटने की लागत को कम कर दिया है।
- ○ **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उन प्रक्रियाओं के लिए शुल्क संरचना को बदलने पर विचार कर सकता है जो निर्माण परमिट की लागत से निपटने के लिए बुरुंडी के समान हैं।**

तालिका 1.13: निर्माण परमिट की लागत

देश	श्रेणी (2017)	लागत (रु. लाख में)	प्रक्रियाओं की संख्या
थाईलैंड	1	0.1	18
हंगरी	5	0.6	20
0ऑस्ट्रेलिया	18	0.9	11
बुरुंडी	126	1	15
भारत	**134**	**23.2**	**30**

दीर्घकालिक योजना

- **परमिट प्रक्रिया के बारें में उचित जागरूकता**
  - ○ टीएमएफ समूह के अनुसार निर्माण परमिट भी एक महंगा काम है, जिसमें 34 प्रक्रियाएं शामिल हैं और 196 दिन लगते हैं। भवन प्रस्ताव कार्यालय से अस्वीकृति की सूचना प्राप्त करने और शुल्क का भुगतान करने में लगभग एक महीने का समय लगता है, और पेड़ प्राधिकरण, तूफान जल और नाली विभाग, सीवरेज विभाग, इलेक्ट्रिक विभाग, पर्यावरण विभाग, यातायात और समन्वय विभाग और सीएफओ से एनओसी प्राप्त कर ली जानी चाहिए।
  - ○ दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया भी अधिकांश निर्माणों के लिए एक बहुत ही संरचित दृष्टिकोण से गुजरा है। उनकी विवरण पुस्तिका स्पष्ट निर्देशों के साथ प्री-परमिट-से-पोस्ट-परमिट के चरणों से प्रक्रिया और जिम्मेदारी मैट्रिक्स का पूरा प्रवाह साझा करती है। हमारा देश ऑस्ट्रेलिया के बिल्डिंग कोड (बीसीए) नामक एक सामान्य मानक का पालन करता है, जिसका प्रत्येक बिल्डर को पालन करना होगा, इस प्रकार ग्रे क्षेत्रों[25] को हटा देना चाहिए। प्राधिकरण ने प्रमाणित अनुप्रयोगों के लिए 10 कार्यदिवसों की समय-सीमा निर्धारित की है जबकि अप्रमाणित आवेदनों

[24] http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB12-Chapters/Dealing-with-construction-permits.pdf
[25] https://hia.com.au/business-information/standards-regulations/building-standards

को 25 कार्यदिवसों की समय-सीमा दी गई है। किसी भी परियोजना के लिए बिल्डिंग परमिट लगभग $ 600[26] से शुरू होता है।

- **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत में एक बिल्डिंग कोड विकसित कर सकता है जो नागरिकों को निर्माण परमिट से निपटने की विस्तृत प्रक्रिया से अवगत कराएगा।**

[26] https://ablis.business.gov.au/service/wa/building-permit/23126

संकेतक 1.07: बाजार के प्रभुत्व का विस्तार

परिभाषा: "अपने देश में, आप कॉर्पोरेट गतिविधि को कैसे चित्रित करेंगे?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = कुछ व्यावसायिक समूहों का प्रभुत्व, 7 = कई फर्मों के बीच फैला हुआ)

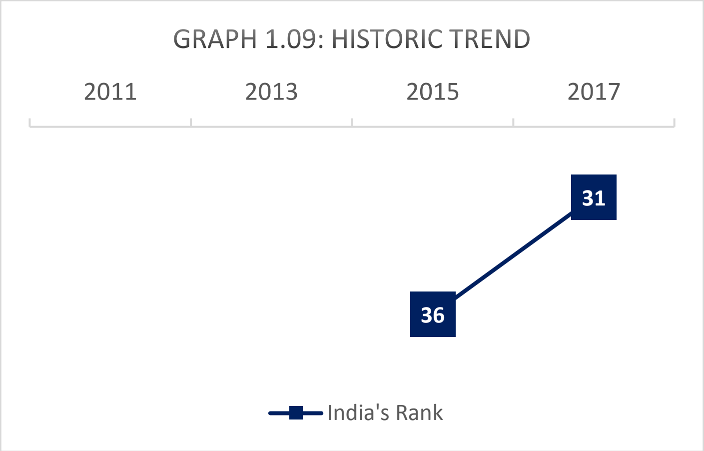

ग्राफ 1.09 संकेतक 1.07 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, वर्ष 2015 की तुलना में भारत की श्रेणी में 5 स्थान की वृद्धि हुई थी। यह संकेतक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

तालिका 1.14: देश का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
जापान	2	5.73	1	5.89	एशियाई साथी
स्विट्जरलैंड	1	5.97	2	5.84	शीर्ष प्रदर्शक
जर्मनी	3	5.65	3	5.29	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	36	4.22	31	4.21	

- **भारत में क्षेत्र वार बाजार का प्रभुत्व:**
  - भारत में तीन सेक्टर हैं:
    - कृषि क्षेत्र (प्राथमिक)
    - औद्योगिक क्षेत्र (द्वितीयक)

- सेवा क्षेत्र (तृतीयक)

  - बाजार में सेवा क्षेत्र का प्रमुख वर्चस्व है, जिसमें वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से जुड़ी सेवाएँ शामिल हैं और इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में भी जाना जाता है और भारतीय जीडीपी[27] में लगभग 53.66% का योगदान देता है।

मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, एमएसएमई जैसी राष्ट्रीय योजनाएं सीबीटी के माध्यम से मजबूत हो रही हैं और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जैसे कार्यक्रमों के साथ आसानी से उपलब्ध वित्तीय मदद बाजार में ठोस आधार स्थापित करने में नई / छोटी फर्मों की मदद कर रही हैं। ये पहल भारत में कई कंपनियों के बीच बाजार के वर्चस्व को बनाए रखने में मदद करेंगी और चूंकि ये पहल लंबे समय तक प्रभावी रहेंगी, इसलिए भारत स्थायी रूप से इस संकेतक में अपनी श्रेणी को बनाए रखने और विकसित करने में सक्षम होगा।.

- **सेवा क्षेत्र का बाजार में योगदान:**
  - **पर्यटन और आतिथ्य उद्योग**
    - **भारतीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग सेवा क्षेत्र के विकास के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में उभरा है। जनवरी-सितंबर 2018 के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जक (एफईई) सालाना 12.1% बढ़कर 17.09 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। इसी अवधि में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) वर्ष दर वर्ष 6.70% बढ़कर 7.47 मिलियन हो गया था। चिकित्सा प्रयोजन के लिए विदेशी पर्यटकों की आवक 2016 में 427,014 से बढ़कर 2017 में 495,056 हो गई थी। जनवरी-सितंबर 2018 के दौरान ई-वीज़ा के माध्यम से आगमन 47.90% प्रति वर्ष बढ़कर 1.58 मिलियन[28] हो गया था।**
  - **पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में बाज़ार का प्रभुत्व**
    - भारतीय होटल उद्योग में लगभग 210,000 कमरों[29] की आपूर्ति है। 22,000 से अधिक कमरों के साथ मैरियट ने कमरे की सूची के मामले में स्थानीय साथियों ताज, ओबेरॉय, आईटीसी और द लीला को पीछे छोड़ते हुए भारत में शीर्ष स्थान ले लिया है 14,400 कमरों वाला ताज, पहले से ही बहुत दूर जाकर दूसरे स्थान[30] पर है।

[27] http://statisticstimes.com/economy/sectorwise-gdp-contribution-of-india.php
[28] https://www.ibef.org/industry/indian-tourism-and-hospitality-industry-analysis-presentation
[29] https://www.ibef.org/download/Tourism-and-Hospitality-January-2018.pdf
[30] https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/hotels-/-restaurants/with-global-hospitality-firms-scaling-up-in-india-will-homegrown-hotels-survive-the-chain-effect/articleshow/63980838.cms

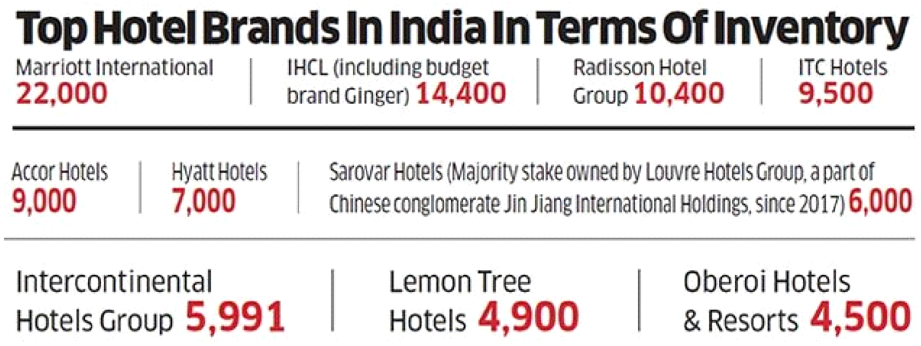

- अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाएं भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं, क्योंकि यह 2020 तक भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में लगभग 47% और 2022[3] तक 50% हो जाएगा।
- 2002 में, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों में भारत के 25,000 ब्रांडेड कमरों का 20% का हिस्सा लिया गया था। 2018 में, अंतरराष्ट्रीय चेन 1,23,000 ब्रांडेड कमरों की वर्तमान आपूर्ति का लगभग 50% हिस्सा है और 2020 तक, वे 76% आपूर्ति[3] देंगे।
- कुल मिलाकर, कमरे की सूची के संदर्भ में भारत के आठ सबसे बड़े होटल ब्रांडों में से पांच वैश्विक ब्रांड हैं। घरेलू ब्रांडों द्वारा 4,781 चाबियों की तुलना में 2016 में अंतर्राष्ट्रीय होटल ब्रांडों ने 11,831 चाबियां जारी की है। 2017 में, घरेलू ब्रांडों द्वारा 7,152 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों ने 8,868 कमरे जारी किए है।

- **विमान सेवा क्षेत्र में बाज़ार का प्रभुत्व**
  - **इंडिगो** घरेलू उड़ानों पर ले जाए जाने वाले यात्री पर आधारित 39% बाजार के हिस्से (2017) के साथ विमान सेवा क्षेत्र पर हावी है, जिसके बाद जेट एयरवेज का हिस्सा बाजार में इंडिगो के आधे से कम हिस्से के साथ यानी 15.4%[5] है।.

तालिका 1.15: विमान सेवा का बाजार में हिस्सा[31]

विमान सेवा	बाजार में हिस्सा (%)
इंडिगो	39%
जेट एयरवेज	15.4%
एयर इंडिया	13%
स्पाइसजेट	13.2%

[31] https://www.statista.com/statistics/575207/air-carrier-india-domestic-market-share/

गो एयर	8.5%
एयर एशिया	3.7%
विस्तारा एयरलाइंस	3.5%
जेट लाइट	2.4%
ट्रूजेट	0.4%
एयर कोस्टा	0.1%

- घरेलू यात्रा बाजार में हवाई यात्रा का सबसे बड़ा योगदान है और इसके 15% से $ 30 बिलियन[32] तक बढ़ने की उम्मीद है।

- **आईटी-बीपीएम (सूचना प्रौद्योगिकी-व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन) क्षेत्र में बाजार का प्रभुत्व.**
    - भारत में कई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियां हैं। सूची में टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल जैसे दिग्गज शामिल हैं। टीसीएस उच्चतम बाजार पूंजीकरण[33] के साथ सूची में सबसे ऊपर है।

तालिका 1.16: कंपनियों[7] की बाज़ार पूंजी

कंपनी	बाजार पूंजीकरण (करोड़ में)
टीसीएस	4,87,919
इंफोसिस	2,21,528
विप्रो	1,32,380
एचसीएल टेक्नोलॉजीज	1,29,933
टेक महिंद्रा	58,621
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज	29,538
माइंडट्री	11,148
एमफैसिस	8,132

- **खुदरा क्षेत्र में बाजार का प्रभुत्व**

[32] https://www.thehindubusinessline.com/economy/logistics/indias-travel-market-to-reach-48-billion-by-2020-google-bcg/article9745424.ece
[33] https://www.trendrr.net/1942/top-10-best-largest-companies-in-india-by-market-capital-famous/

- भारतीय खुदरा उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले में से एक है। भारत में खुदरा उद्योग के 2017[34] में US $ 680 बिलियन से 2020 तक US $ 1.2 ट्रिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
- तालिका 1.17 से पता चलता है कि वर्ष 2018[8] में अर्जित आय के मामले में रिलायंस समूह बाजार में हावी है।

तालिका 1.17: कंपनियों द्वारा उत्पन्न राजस्व

कंपनी	राजस्व (अरब $)
रिलायंस रिटेल	7
फ्यूचर ग्रुप	3.5
ट्रेंट	2.5
आदित्य बिड़ला रिटेल	2
टाइटन	1.8
शॉपर्स स्टॉप	0.3
द रेमंड ग्रुप	3
एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड	1.9

- **दूरसंचार उद्योग में बाज़ार का प्रभुत्व**
  - जून 2018 तक 1.17 बिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की मजबूत नीति का समर्थन महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2018 में दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। एयरटेल 24.85% हिस्सेदारी[35] के साथ दूरसंचार बाजार पर हावी है। फ्री वॉयस कॉल[9] देने में सबसे बड़े समूह रिलायंस द्वारा किए गए निवेश के कारण आइडिया और वोडाफोन जैसे बड़े खिलाड़ियों ने विलय का फैसला किया था।

[34] https://www.ibef.org/industry/retail-india.aspx
[35] https://www.ibef.org/industry/telecommunications.aspx

तालिका 1.18: मुख्य दूरसंचार कंपनियां और उनकी बाजार में हिस्सेदारी[36]

कंपनी	ग्राहक आधार (मिलियन में)	राजस्व (अरब डॉलर $ में)	बाजार की हिस्सेदारी (%)	स्वामित्व
एयरटेल	303	15	24.85%	भारती एंटरप्राइजेज (64%) और सिंग टेल (36%
आइडिया	200	5.5	16.83%	आदित्य बिड़ला ग्रुप और अक्सीआटा
वोडाफोन	208	6.6	18.23%	वोडाफोन ग्रुप पीएलसी
जिओ	186	0.8	13.71%	रिलायंस इंडस्ट्रीज
टाटा टेलीसर्विसेस	86	0.49	2.1%	टाटा ग्रुप
टेलीनॉर	40	0.18	5.1%	भारती एयरटेल
रिलायंस कम्युनिकेशंस	12	3.5	0.06%	रिलायंस एडीएजी (90%) और एसएसटीएल (10%)
बीएसएनएल	100	5.1	9.24%	भारत सरकार
एमटीएनएल	4	0.5	0.5%	भारत सरकार

- **बाजार में कृषि क्षेत्र का योगदान:**
  - भारत की लगभग 58% आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने का सकल मूल्य वित्त वर्ष 18 में अनुमानित रूप से 17.67 ट्रिलियन (यूएस $ 274.23 बिलियन) है। यह तालिका 1.19 में देखा जा सकता है कि **यूपीएल लिमिटेड की भारतीय उर्वरकों, कीटनाशकों के बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी है**, यह अकेले 40% से अधिक की

[36] https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/airtel-leads-telecom-market-with-25-85-share-rjio-sees-highest-growth-in-wireless-subs-trai-dec-data/62947738

बाजार हिस्सेदारी का आनंद उठाती है। हालांकि, अन्य कंपनियों[37] ने भी बाजार में कुछ हिस्सेदारी हासिल करने में कामयाबी हासिल की है।

तालिका 1.19: मुख्य कृषि-रसायन कंपनियां और उनकी बिक्री

कंपनियां	2017-18 बिक्री (mn INR)	2016-17 बिक्री (mn INR)	2015-16 बिक्री (mn INR)
यूपीएल लिमिटेड	1,50,060.00	144610	126768
घारडा ग्रुप	23,363.00	19650	17070
इंडोफिल इंडस्ट्रीज	17,490.00	16683	13525
भारत ग्रुप	15,678.00	14200	10850
क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन	13,649.00	12,856	12000
कोरोमंडल इंटरनेशनल	15,060.00	13,980	12040
रैलिस भारत	12,117.00	12,302	11232
शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड	14,881.00	11,988	10265
पीआई इंडस्ट्रीज़	12,050.00	11,400	10,326
कृषि रसायन ग्रुप	12780	11,170	9546

- **बाजार के लिए विनिर्माण क्षेत्र का योगदान**
    - **ऑटोमोबाइल क्षेत्र**
        - भारतीय ऑटो उद्योग 2017 में बिक्री में 9.5% सालाना-दर-वर्ष 4.02 मिलियन यूनिट (दो पहिया वाहनों को छोड़कर) के साथ दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बन गया था। यह 2017[38] में वाणिज्यिक वाहनों का 7 वां सबसे बड़ा निर्माता

[37] https://www.ibef.org/industry/agriculture-india.aspx
[38] https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/india-pips-germany-ranks-4th-largest-auto-market-now/articleshow/63438236.cms

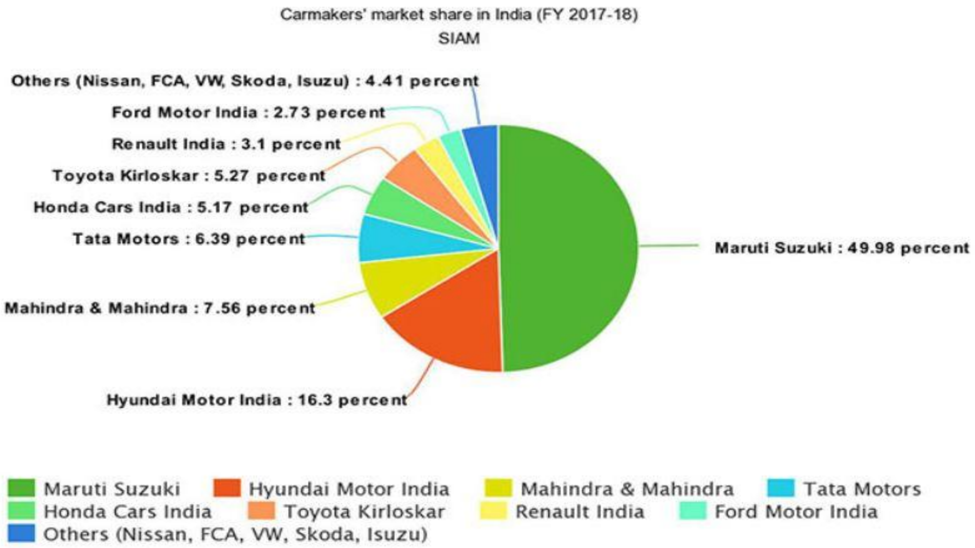

- मारुति सुजुकी 49.98% के साथ बाजार में हावी है। भारत एक प्रमुख ऑटो निर्यातक भी है और निकट भविष्य में इसके निर्यात में मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। अप्रैल-जुलाई 2018[39] के दौरान ऑटोमोबाइल निर्यात 26.56% बढ़ा था।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

[39] https://www.ibef.org/industry/india-automobiles.aspx

- **उत्पादों और सेवाओं पर यादृच्छिक चेक**
  - घटिया उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाली फर्मों के बाजार प्रभुत्व को हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को दावा किए गए विनिर्देशों का पालन किये जाने की यादृच्छिक आधार पर जाँच की जानी चाहिए।

मध्यम अवधि की योजना

- **हर क्षेत्र के लिए एक नियामक संस्था की आवश्यकता**
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, कृषि क्षेत्र आदि के लिए एक नियामक संस्था लाने के लिए आदेश देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, उदाहरण के लिए आईआरडीए (बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) और ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण)। साथ ही, वर्तमान नियामक निकायों को अनैतिक प्रथाओं द्वारा बाजार पर प्रभुत्व में प्रमुख कॉर्पोरेट फर्मों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के लिए और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए।

दीर्घकालिक योजना

- **स्टार्ट-अप और एमएसएमइ (माइक्रो स्माल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज) को बढ़ावा देना**
  - सरकार / विनियमन निकाय को स्टार्ट-अप और एमएसएमइ (माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज) को बढ़ावा देने के लिए तेज़ प्रयास करने चाहिए ताकि वे अपने मौजूदा व्यवसायों को अच्छी तरह से स्थापित बाजार के खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार कर सकें।

ध्यान दें - संकेतक 1.08 और 1.09 को एकल संकेतक के रूप में दिखाया जा रहा है क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं और समान मानदंडों पर निर्भर करते हैं।

संकेतक 1.08: व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक समय

परिभाषा: यह संकेत व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को संदर्भित करता है। यह मध्यस्थता अवधि को मापता है जिनके लिए निगमन वकील इंगित करते हैं कि सरकारी एजेंसियों के साथ न्यूनतम अनुवर्ती प्रक्रिया के साथ पूरा करना आवश्यक है और कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं है।

स्रोत: वर्ल्ड बैंक / इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डूइंग बिजनेस 2017

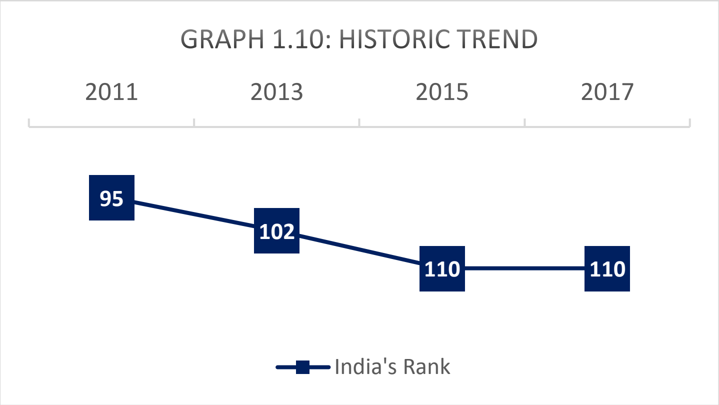

देश का मूल्य: व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या।

श्रेणी 1.10 संकेतक 1.08 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत का रैंक 110 वें स्थान पर रहा। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.12% का योगदान देता है।

तालिका1.20: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
न्यूजीलैंड	1	0.5	1	0.5	शीर्ष प्रदर्शक
हांगकांग	4	2.5	2	1.5	एशियाई साथी
मैसेडोनिया	2	2	4	2	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	4	2.5	5	2.5	एशियाई साथी
यूनाइटेड किंगडम	27	6	20	4.5	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**110**	**28.4**	**110**	**26**	

संकेतक 1.09: व्यवसाय शुरू करने के लिए लागत

परिभाषा: प्रति व्यक्ति अर्थव्यवस्था की आय (जीएनआई) के प्रतिशत के रूप में व्यवसाय शुरू करने के लिए लागत को संदर्भित करता है। यदि ऐसी सेवाएं कानून द्वारा आवश्यक है तो यह कानूनी या पेशेवर सेवाओं के लिए सभी आधिकारिक शुल्क को मापता है।

स्रोत: विश्व बैंक / अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, डूइंग बिज़नेस 2018 इक्वल ओपोर्तुनिटी फॉर ऑल।

$$\text{देश का मूल्य} = \frac{\text{व्यवसाय शुरू करने की लागत} \times 100}{\text{अर्थव्यवस्था की आय प्रति व्यक्ति (GNI)}}$$

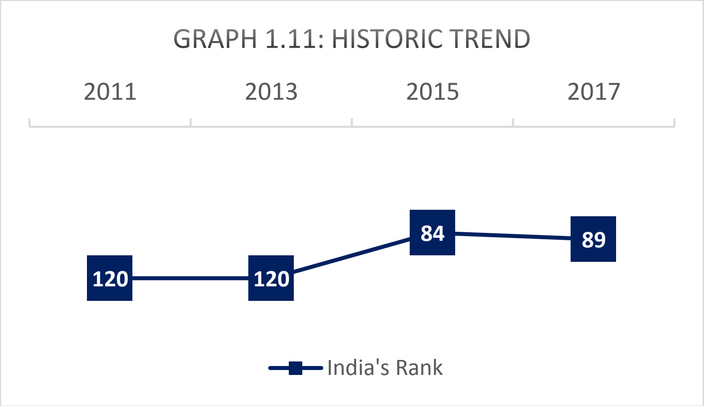

ग्राफ 1.11 संकेतक 1.09 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी 5 स्थान कम हुई है। यह सूचक देश के स्कोर में 0.125% का योगदान देता है।

तालिका 1.21: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
स्लोवेनिया	1	0	1	0	शीर्ष प्रदर्शक
यूनाइटेड किंगडम	3	0.3	2	0.1	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
साउथ अफ्रीका	3	0.3	4	0.2	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**84**	**12.2**	**89**	**13.8**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय दीर्घकालिक योजना

- टीएमएफ समूह के अनुसार, भारत में व्यवसाय शुरू करने की लागत खगोलीय है, और इसमें शामिल प्रक्रियाएं स्थानीय ज्ञान के बिना चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। 13 प्रक्रियाएँ हैं जिन्हें किसी को भी शुरू में व्यवसाय को स्थापित करने की लिए आवश्यकता होती है जैसा कि तालिका 1.22 में दिखाया गया है। औसतन सभी कार्यों को पूरा करने में लगभग एक महीने (27 दिन) लगते हैं, जो कि 12 दिनों[40] के औसत आर्थिक सहयोग संगठन (ओईसीडी) से ऊपर है।
- भारत के भीतर, दिल्ली जैसे महानगरीय शहर में प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 38 दिन लगते हैं, जैसा कि तालिका 1.24 में दिया गया है और मुंबई को तालिका 1.23 में दिए गए अनुसार लगभग 40 दिन लगते हैं। यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर की तुलना में यह संख्या बहुत अधिक प्रतीत होती है, जहां किसी को किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में केवल 3-6 दिन लगते हैं (तालिका 1.25 और 1.26 में दिया गया है)। **इस प्रकार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इन देशों से उदाहरण ले सकता है और भारत[41] में व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को और आसान बना सकता है।**
- **एकल खिड़की निकासी (एसडब्ल्यूसी)**
  - कुछ प्रक्रियाएं जैसे कि निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करना और कंपनी के नाम का आरक्षण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और पूरा होने में केवल 1-2 दिन लगते हैं, पर कर खाता संख्या प्राप्त करने जैसी कई अन्य प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें पूरा करने कुछ विशिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता होने के कारण एक सप्ताह से अधिक का समय लगता है।
  - **इसलिए, वित्त मंत्रालय की मदद से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** पैन और टैन जैसी चीजों के लिए अनंतिम डाटा प्रदान कर सकता है ताकि व्यक्ति पैन प्राप्त करने के लिए 10 दिनों तक इंतजार किए बिना अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके अलावा, अगर एकल खिड़की निकासी प्रणाली लागू की जाती है, तो यह महत्वपूर्ण तरीके से समय और लागत को कम कर सकती है।

तालिका 1.22: भारत में शुरू होने वाले कारोबार में शामिल किए गए चरण

क्र.सं.	प्रक्रिया	पूरा होने में लगने वाला समय	पूरा होने में लगने वाली लागत

[40] https://www.tmf-group.com/en/news-insights/business-culture/top-challenges-india/
[41] http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

1	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (राष्ट्रीय) से ऑनलाइन प्राप्त करें	1 दिन	INR 100
2	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (राष्ट्रीय) द्वारा अधिकृत निजी एजेंसी से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करें	3 दिन	INR 1,500
3	कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) (नेशनल) के साथ नाम ऑनलाइन आरक्षित करें	2 दिन	INR 500
4	कंपनी के दस्तावेजों को राज्य राजकोष (राज्य) या अधिकृत बैंक (निजी) में स्टाम्प कराये	1 दिन	INR 1,300 (एमओए के लिए INR 200 + INR 1,000 एओए के लिए प्रत्येक शेयर पूंजी के 500,000 या भाग के लिए + घोषणा पत्र 1 के लिए स्टांप पेपर के लिए INR 100)
5	कंपनियों के रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (राष्ट्रीय) से निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करें	5 दिन	INR 14,133 (टिप्पणियां देखें)
6	मुहर बनाएं (निजी)	1 दिन	INR 350 (लागत आवश्यक मुहरों की संख्या और वितरण के लिए समय अवधि पर निर्भर करती है)
7	आयकर विभाग (राष्ट्रीय) द्वारा आउटसोर्स किये गए अनुसार नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) इनवेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड द्वारा नियुक्त एक अधिकृत मताधिकार या एजेंट से एक स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करें।	7 दिन	INR 67 (INR 60 आवेदन शुल्क + 12.36% सेवा कर + आवेदन पत्र के लिए INR 5, यदि डाउनलोड नहीं किया गया है)
8	मुंबई आयकर विभाग में मूल्यांकन कार्यालय से स्रोत पर काटे गए आयकर के	7 दिन	INR 57 (INR 50 आवेदन शुल्क + 12.36% सेवा कर)

	लिए एक कर खाता संख्या (टैन) प्राप्त करें		
9	इंस्पेक्टर के कार्यालय, दुकानें और स्थापना अधिनियम (राज्य / नगर निगम) के साथ रजिस्टर करें	2 दिन	INR 6,500 (INR 2000 + व्यापार से इनकार शुल्क के लिए 3 गुना पंजीकरण शुल्क)
10	वाणिज्यिक कर कार्यालय (राज्य) में मूल्य-वर्धित कर (वैट) के लिए रजिस्टर करें	12 दिन	INR 5,100 (पंजीकरण शुल्क INR 5000 + स्टैम्प ड्यूटी INR 100)
11	व्यवसाय कर कार्यालय (राज्य) में व्यवसाय कर के लिए रजिस्टर करें	2 दिन	कोई लागत नहीं
12	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (राष्ट्रीय) के साथ रजिस्टर करें	12 दिन	कोई लागत नहीं
13	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (राष्ट्रीय) के क्षेत्रीय कार्यालय में चिकित्सा बीमा के लिए रजिस्टर करें	9 दिन	कोई लागत नहीं

भारत के दो प्रमुख शहरों पर ध्यान दें

दिल्ली और मुंबई दो ऐसे शहर हैं जिन्हें डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में प्राथमिक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है और इस प्रकार एक व्यवसाय शुरू करने के लिए दोनों राज्यों द्वारा आवश्यक कुछ चरणों को शामिल किया गया है:

तालिका 1.23: मुंबई में शुरू होने वाले व्यापार में शामिल किए गए चरण

क्र.सं.	प्रक्रिया	पूरा करने का समय	संबद्ध लागत
1	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (राष्ट्रीय) द्वारा अधिकृत निजी एजेंसी से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करें **एजेंसी: प्रमाणित निजी एजेंसियां**	1 दिन	INR 700 से INR 2,500 प्रति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
2	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से ऑनलाइन निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करें	1 दिन	INR 500 प्रति डिन

	एजेंसी: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय		
3	कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ कंपनी का नाम ऑनलाइन आरक्षित करें	1-3 दिन	INR 1,000
4	स्टाम्प शुल्क का भुगतान करें, स्पाइस फॉर्म दाखिल करें और निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करें **एजेंसी: रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी)**	5 दिन	1,000,000 के बीच भुगतान की गई शेयर पूंजी की एक छोटी कंपनी के लिए शुल्क अनुसूची: - मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (इ एमओए) की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग: INR 4,800 (1,000,000 राशि तक) निर्धारित है हर 10,000 या उसके भाग के लिए 2,000+ 200 INR) - आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुल्क (इएओए): INR 400 (500,000 से 2,499,999 के बीच) - फॉर्म INC32 (एसपीआईसीइ फॉर्म) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुल्क: INR 500 - स्टाम्प ड्यूटी: INR 10 - आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के लिए स्टाम्प शुल्क: INR 3,000 - मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए स्टाम्प शुल्क: INR 200
5	कंपनी की मोहर बनाएं: **एजेंसी: अधिकृत विक्रेता (निजी)**	1 दिन, समकालिक	INR 350-500

6 (i)	जमा करें और (i) स्थायी खाता संख्या (पैन) और कार्ड और एक कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन) प्राप्त करें **एजेंसी: रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज (आरओसी)**	10 दिन	INR 350 (लागत आवश्यक मुहरों की संख्या और वितरण के लिए समय अवधि पर निर्भर करती है)
6 (ii)	आयकर विभाग द्वारा आउटसोर्स के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (युटीआई) इंवेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड द्वारा नियुक्त एक अधिकृत फ्रैंचाइज़ी या एजेंट से एक स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करें।	7 दिन	INR 67 (INR 60 आवेदन शुल्क + 12.36% सेवा कर + आवेदन पत्र के लिए INR 5, यदि डाउनलोड नहीं किया गया है)
7	एक बैंक खाता खोलें **एजेंसी: बैंक खाता**	2 दिन	कोई शुल्क नहीं
8	वैट और व्यवसाय कर के लिए पंजीकरण करें **एजेंसी: बिक्री कर विभाग** वैट ऑनलाइन पंजीकरण www.mahavat.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आयोजित किया जाता है।	7-10 दिन	INR 500 (पंजीकरण शुल्क) + INR 25 (स्टाम्प ड्यूटी) अनिवार्य वैट पंजीकरण के लिए
9	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ रजिस्टर करें	1 दिन, समकालिक	कोई शुल्क नहीं

	एजेंसी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (संघीय)		
10	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआईसी) के साथ रजिस्टर करें **एजेंसी: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (संघीय)**	1 दिन	कोई शुल्क नहीं
11	कार्यालय निरीक्षक, मुंबई दुकानें और स्थापना अधिनियम के साथ रजिस्टर करें **एजेंसी: नगर निगम ग्रेटर मुंबई**	7 दिन, समकालिक	INR 1,200 (पंजीकरण शुल्क) + ट्रेड रेफ्यूज़ चार्जेज के लिए 3 गुना पंजीकरण शुल्क (INR 3,600)

तालिका 1.24: दिल्ली में कारोबार शुरू करने में शामिल किए गए चरण

क्रमांक	प्रक्रिया	पूरा करने का समय	संबद्ध लागत
1	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (राष्ट्रीय) द्वारा अधिकृत निजी एजेंसी से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करें **एजेंसी: प्रमाणित निजी एजेंसियां**	1 दिन	INR 700 से INR 2,500 प्रति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
2	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के मंत्रालय से ऑनलाइन निदेशक पहचान संख्या (डिन) प्राप्त करें **एजेंसी: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय**	1 दिन	INR 500 प्रति डिन
3	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ कंपनी का नाम ऑनलाइन आरक्षित करें **एजेंसी: रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी)**	1-3 दिन	INR 1,000
4	स्टाम्प शुल्क का भुगतान करें, स्पाइस फॉर्म दाखिल करें और निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करें **एजेंसी: रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी)**	5 दिन	INR 500,000 और INR 1,000,000 के बीच भुगतान की गई शेयर पूंजी की एक छोटी कंपनी के लिए 5 दिनों की फीस अनुसूची: - मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (इएमओए) की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग: INR 4,800 (1,000,000 राशि तक निर्धारित है, हर 10,000 या उसके हिस्से के लिए 2,000+ 200 INR) - आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (इएओए) दाखिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुल्क: INR 400

			- फॉर्म आईएनसी-32 एसपीआईसीइ के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुल्क: INR 500 - स्टाम्प ड्यूटी: INR 10 - आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के लिए स्टाम्प शुल्क: INR 1,703 - मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए स्टाम्प शुल्क: INR 200
5	कंपनी की मोहर बनाएं **अधिकृत विक्रेता (निजी)**	1 दिन, **समकालिक**	INR 500-1,000
6 (i)	जमा करें और (i) स्थायी खाता संख्या (पैन) और कार्ड और एक कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन) प्राप्त करें **एजेंसी: रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ (आरओसी)**	10 दिन	INR 350 (लागत आवश्यक मुहरों की संख्या और वितरण की समय अवधि पर निर्भर करती है)
6 (ii)	आयकर विभाग (राष्ट्रीय) द्वारा आउटसोर्स के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (युटीआई) इंवेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड द्वारा नियुक्त एक अधिकृत फ्रैंचाइज़ी या एजेंट से एक स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करें।	7 दिन	INR 67 (INR 60 आवेदन शुल्क + 12.36% सेवा कर + आवेदन पत्र के लिए INR 5, यदि डाउनलोड नहीं किया गया है)

7	एक बैंक खाता खोलें **एजेंसी: बैंक खाता**	2 दिन	कोई शुल्क नहीं
8	दिल्ली और राज्य के एनसीटी के व्यापार और कर विभाग में मूल्य वर्धित कर (वैट) के लिए रजिस्टर करें **एजेंसी: व्यापार और कर विभाग, दिल्ली एनसीटी की सरकार**	9 दिन	INR 500 पंजीकरण शुल्क + INR 25 अनिवार्य वैट पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क
9	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ रजिस्टर करें **एजेंसी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (संघीय)**	1 दिन, **समकालिक**	कोई शुल्क नहीं
10	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआईसी) के साथ रजिस्टर करें **एजेंसी: कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय**	1 दिन	कोई शुल्क नहीं
11	दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करें **एजेंसी: श्रम विभाग - दिल्ली की एनसीटी सरकार**	एक दिन से कम (ऑनलाइन प्रक्रिया), **समकालिक**	कोई शुल्क नहीं

- **व्यवसाय शुरू करने के लिए समय को कम करने के लिए मुख्य रूप से विभिन्न देशों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है:**

सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स इस बात के प्रमुख उदाहरण हैं कि किसी व्यवसाय को शुरू करने की प्रक्रिया को कितनी कुशलता से कम किया जा सकता है

तालिका 1.25: यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू होने वाले व्यापार में शामिल किए गए चरण

क्र.सं.	प्रक्रिया	पूरा करने में लगने वाला समय	संबद्ध लागत
1	**अद्वितीय कंपनी के नाम की उपलब्धता की जाँच करें, आवेदन फार्म IN01 पूरा करें, और कंपनी हाउस के साथ पंजीकरण के लिए फ़ाइल करें** *एजेंसी: कंपनीज हाउस* कंपनी संस्थापकों के पास अद्वितीय कंपनी के नाम की जाँच करने और खुद को पंजीकरण के लिए फ़ाइल करने या ऐसा करने के लिए निगमन पेशेवरों को बनाए रखने का विकल्प है। पंजीकरण पूरा करने का विकल्प कागज के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से है। यदि कंपनी ऑनलाइन निगमन के लिए फाइल करने का विकल्प चुनती है, तो निगमन और कंपनी ज्ञापन के मॉडल लेख पंजीकरण वेबसाइट www.gov.uk/register-a-company-online द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त रूपों के अलावा, सभी कंपनियों को संबंधित कंपनियों के रजिस्ट्रार (यानी इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड या उत्तरी आयरलैंड के लिए) को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी चाहिए: • 2006 कंपनी अधिनियम की सभी आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण; • आवेदन फार्म IN01, जिसमें शामिल हैं:	एक दिन से कम (ऑनलाइन प्रक्रिया)	GBP 12 ऑनलाइन पंजीकरण के लिए

	o प्रस्तावित कंपनी का नाम; o पंजीकरण कार्यालय का देश (जैसे इंग्लैंड और वेल्स (या वेल्स), स्कॉटलैंड या उत्तरी आयरलैंड); o क्या सदस्यों का दायित्व सीमित होना है और यदि ऐसा है तो क्या शेयरों से होगा या गारंटी से; तथा; o कंपनी सार्वजनिक है या निजी; • शेयर पूंजी के साथ एक कंपनी के मामले में, आवेदन में ग्राहक के नाम और पते सहित पूंजी और प्रारंभिक शेयरधारिता का विवरण भी शामिल होना चाहिए। • प्रस्तावित अधिकारियों का एक स्टेटमेंट, पहले निदेशक और कंपनी सचिव होने के नाते (जब तक कि एक निजी कंपनी के मामले में, जहां कंपनी सचिव की नियुक्ति वैकल्पिक है); • इच्छित पंजीकृत कार्यालय पते का विवरण। ऑनलाइन फॉर्म पूरा करने पर अगर कंपनी के नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वेबसाइट आपको इस बारे में सचेत करेगी और आपके पास दूसरा नाम चुनने का विकल्प होगा। निगमन दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए शुल्क इस प्रकार हैं: वेब निगमित निगमन के लिए GBP 12 और पेपर फाइलरों के लिए GBP 40 (या उसी दिन की सेवा के लिए GBP 100)। तीसरी टीं एजेंट के माध्यम से मानक डिजिटल पंजीकरण शुल्क GBP 13 (या एक ही दिन की सेवा के लिए GBP 30) है। किसी कंपनी के लिए किसी तीसरे पक्ष के एजेंट का उपयोग करने की		

	कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड पार्टी एजेंट अतिरिक्त शुल्क के साथ-साथ मानक पंजीकरण शुल्क भी ले सकते हैं। यदि कंपनी पंजीकरण के लिए निगमन एजेंटों को बनाए रखने का विकल्प चुनती है, तो उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा, आवेदन फ़ाइल में एजेंटों का नाम और पता भी शामिल होना चाहिए। ध्यान दें कि यदि कंपनी संघ या कंपनी के ज्ञापन के मॉडल लेखों में संशोधन करना चाहती है तो वह www.gov.uk/register-a-company-online के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण के लिए फाइल नहीं कर सकती है। इसके बजाय, कंपनी को निगमन दस्तावेज़ों की रचना करने के लिए पेशेवरों का उपयोग करना चाहिए और उन्हें विशेष सॉफ़्टवेयर के माध्यम से कंपनी हाउस में जमा करना चाहिए। पंजीकरण आमतौर पर कुछ घंटों के भीतर पूरा हो जाता है।		
2	**एचएमआरसी से संपर्क करें और वैट के लिए पंजीकरण करें** *एजेंसी: एचएमआरसी* एक व्यवसाय को वैट के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा यदि पिछले 12 महीनों के लिए ब्रिटेन के भीतर आपूर्ति की जाने वाली कर योग्य वस्तुएं और सेवाएं £ 83,000 की वर्तमान पंजीकरण सीमा से अधिक हैं (अप्रैल 2016 तक) या व्यवसाय यह अपेक्षा करता है कि यह उस आंकड़े से अधिक हो जाएगा अगले 30 दिनों में, इसे वैट के लिए पंजीकृत होना चाहिए। हालाँकि, व्यवसाय स्वेच्छा से वैट के लिए पंजीकरण का चयन कर सकता है यदि उसका वैट कर योग्य माल £ 83,000 सीमा के अंतर्गत आता है।	एक दिन से कम (ऑनलाइन प्रक्रिया)	कोई शुल्क नहीं

	लिमिटेड कंपनियों सहित अधिकांश व्यवसाय, वैट खाते के लिए यहाँ ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं: https://online.hmrc.gov.uk/registration या पोस्ट के माध्यम से कागज़ी प्रपत्र भेज सकते हैं। वैट पंजीकरण के लिए अधिकांश आवेदन ऑनलाइन ही पूरे किए जा सकते हैं लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां किसी व्यवसाय को डाक से आवेदन करना होता है। वैट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण या अन्य वैट ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए, एक व्यवसाय को पहले एचएमआरसी ऑनलाइन सेवाओं या सरकारी गेटवे के लिए साइन अप करना होगा।		
3	**एचएमआरसी से संपर्क करें और पीएवायई के लिए पंजीकरण करें** *एजेंसी: एचएमआरसी* कंपनी को राष्ट्रीय बीमा और पे-ऐज़-यू-अर्न (पीएवायई) कर के लिए एक योगदान योजना स्थापित करने के लिए एचएमआरसी से संपर्क करना चाहिए, जो कर्मचारी की मज़दूरी या वेतन से कर घटाता है। कंपनी को 5 कार्य दिवसों के भीतर - आमतौर पर कम - एक सक्रियण पिन जारी किया जाएगा और उसे 28 दिनों के भीतर इस पिन को सक्रिय करना होगा (या फिर नए पिन का अनुरोध करें)। कंपनी ऑनलाइन पंजीकरण और नामांकन के लिए पिन का उपयोग करेगी। सुरक्षा कारणों से, प्रदान किए गए डाटा पर एक चेक चलाया जाता है। सुरक्षा जांच में विफल रहने वाले पंजीकरण का एक छोटा प्रतिशत अधिक समय ले सकता है अन्यथा, सक्रियण तत्काल है।	3 दिन, पिछली प्रक्रिया के साथ समकालिक	कोई शुल्क नहीं

	6 अप्रैल 2013 से, कंपनियों को वास्तविक समय में अपने पीएवायई को रिपोर्ट करना होगा। इसका मतलब यह है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए हर बार ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा या अपने एकाउंटेंट को रिपोर्ट जमा करनी होगी।		
4	**नियोक्ता के देयता बीमा के लिए साइन अप करें** *एजेंसी: बीमा कंपनी* 1969 के नियोक्ता दायित्व (अनिवार्य बीमा) अधिनियम को यूनाइटेड किंगडम में सभी नियोक्ताओं को एक अनुमोदित बीमा कंपनी से नियोक्ता के देयता बीमा को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नियोक्ताओं के देयता बीमा के लिए न्यूनतम कानूनी आवश्यकता GBP 5,000,000 की क्षतिपूर्ति की सीमा है। इसके अलावा, यदि नियोक्ता के देयता बीमा को निकाला नहीं जाता है तो प्रति दिन GBP 2,500 का जुर्माना लगाया जा सकता है। 1969 के नियोक्ता देयता (अनिवार्य बीमा) अधिनियम के लिए आवश्यक है कि कार्यस्थल पर बीमा का प्रमाण पोस्ट किया जाए। 1 अक्टूबर, 2008 से, यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित करना संभव है, हालांकि ऐसा करने वाली एक कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि उसके कर्मचारियों को पता है कि प्रमाण पत्र कैसे और कहां से प्राप्त करना है और इसके लिए उचित पहुंच है।	1 दिन	कोई शुल्क नहीं

- **सिंगापुर** - सभी के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की संख्या, चाहे वह शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी हो, एक साझेदारी या एक संयुक्त उद्यम है, केवल तीन ही होती है, जिसे एक दिन के भीतर पूरा

किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सभी पूर्व अनुमोदन संबंधित सरकारी अधिकारियों से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे उदाहरण जिनमें निवेशकों को तत्काल मंजूरी नहीं मिल सकती है, वे भी आमतौर पर आसानी से हल हो जाते हैं। वास्तुकला और चिकित्सा जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए, पेशेवरों को कंपनी को शामिल करने से पहले संबंधित वैधानिक बोर्डों या मंत्रालयों के प्रभारी से पेशेवर या व्यावसायिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि अधिकांश प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है, एक कंपनी के लिए निगमन प्रक्रिया अपेक्षाकृत परेशानी मुक्त होती है। निगमन के बाद, एक कंपनी अपने व्यवसाय के संचालन को तुरंत शुरू कर सकती है।

तालिका 1.26: सिंगापुर में बिजनेस शुरू करने में शामिल होने वाले चरण

क्रमांक	प्रक्रियाएं	प्रक्रिया के पूरे होने का समय	संबद्ध लागत
1	कंपनी के नाम खोज और कंपनी निगमन और कर संख्या (जीएसटी) सहित एसीआरए के साथ ऑन-लाइन पंजीकरण) एजेंसी: एसीआरए लेखा और कॉर्पोरेट नियामक प्राधिकरण (एसीआरए) सिंगापुर में व्यवसायों और सार्वजनिक लेखाकारों का राष्ट्रीय नियामक है। निगमन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम बिज़फाइल के माध्यम से किया जाता है। कंपनी के नाम के अनुमोदन और आरक्षण के लिए एक आवेदन बिज़फाइल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना होता है। 2007 से, बिज़फ़ाइल पंजीकरण के बिंदु पर ग्राहकों को वन-स्टॉप व्यापार सुविधा सेवाएँ प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं में डोमेन नाम, माल और सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण, संबंधित ई-न्यूज़लेटर की सदस्यता लेना और नवीनतम सरकारी खरीद अवसरों पर ई-सेवा अलर्ट के लिए पंजीकरण करना, सीमा शुल्क खाते को सक्रिय करना और कॉर्पोरेट बैंक खाते के लिए आवेदन शामिल हैं। प्रत्येक स्वीकृत कंपनी के नाम के लिए एसजीडी 15 का एक आवेदन	एक दिन से कम (ऑनलाइन प्रक्रिया)	एसजीडी 315

	शुल्क देय होता है। यह आम तौर पर ऑनलाइन भुगतान के बाद एक घंटे के भीतर पूरा किया जा सकता है। एक बार नाम स्वीकृत हो जाने के बाद, इसे 60 दिनों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। आरक्षण अवधि के विस्तार के लिए समाप्ति की तारीख से पहले 60 दिनों तक एक बार आवेदन किया जा सकता है। एक नया व्यवसाय पंजीकृत करने वाले उद्यमी, पंजीकरण प्रपत्रों को भरते समय पंजीकरण के एक ही समय में लाइन पर व्यवसाय प्रोफ़ाइल खरीद सकते हैं। सभी दस्तावेजों और सभी सूचनाओं के सफल जमा होने के समय से प्रसंस्करण का समय लगभग 15 मिनट है, और देय पंजीकरण शुल्क एसजीडी 300 है। एसीआरए कानून फर्म या पेशेवर फर्म कंपनी के पंजीकरण संख्या के साथ कंपनी के सफल निगमन पर निगमन के उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से निगमन की सूचना जारी करेगा। जब (क) इसका वार्षिक कर योग्य टर्नओवर एसजीडी 1 मिलियन से अधिक हो जाता है तो माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए सिंगापुर के अंतर्देशीय राजस्व प्राधिकरण (आईआरएएस) के साथ पंजीकरण उसी ऑनलाइन रूपों का उपयोग करके किया जा सकता है।		

2	एक कंपनी सील बनाएं एजेंसी: सील निर्माता कंपनी की सील अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह अभी भी उद्यमियों के लिए एक आम बात है। यह आमतौर पर कंपनी सील निर्माताओं से प्राप्त की जाती है। यदि सील को 3 दिन के भीतर एकत्र किया जाना है तो आमतौर पर पर एसजीडी 40 की बाजार दर वसूल की जाती है यदि सील को 1 दिन के भीतर एकत्र किया जाना हो तो एसजीडी 70 वसूली जाती है।	1 दिन	एसजीडी 70
3	एक बीमा एजेंसी में कर्मचारी मुआवजा बीमा के लिए साइन अप करें एजेंसी: बीमा एजेंसी सिंगापुर के कार्य चोट क्षतिपूर्ति अधिनियम (डब्ल्यूआईसीए), अध्याय 354 की धारा 23 (1) के तहत, प्रत्येक नियोक्ता सभी देयताओं जो कंपनी के प्रावधानों के तहत हो सकती है, उनके खिलाफ बीमा कंपनी के साथ एक या अधिक स्वीकृत नीतियों के तहत बीमा करेगा और उसे बनाए रखेगा। कंपनी द्वारा नियोजित किसी भी कर्मचारी के संबंध में यह अधिनियम, जब तक कि मंत्री, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी नियोक्ता के संबंध में इस तरह की बीमा की आवश्यकता को माफ नहीं करता है। समय और लागत कंपनी और बीमा एजेंसी के बीच की व्यवस्था पर निर्भर हो सकते हैं।	1 दिन	कोई शुल्क नहीं

ध्यान दें - संकेतक 1.10 और 1.11 का विलय कर दिया गया हैं क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं और दोनों कराधान की सीमा और प्रभाव पर निर्भर हैं।

संकेतक 1.10: काम करने के लिए प्रोत्साहन पर कराधान का विस्तार और प्रभाव

परिभाषा: "आपके देश में, कर किस हद तक कर काम करने के लिए प्रोत्साहन को कम करते हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = काम करने के प्रोत्साहन को काफी कम कर देता है, 7 = काम करने के प्रोत्साहन को कम नहीं करता है)

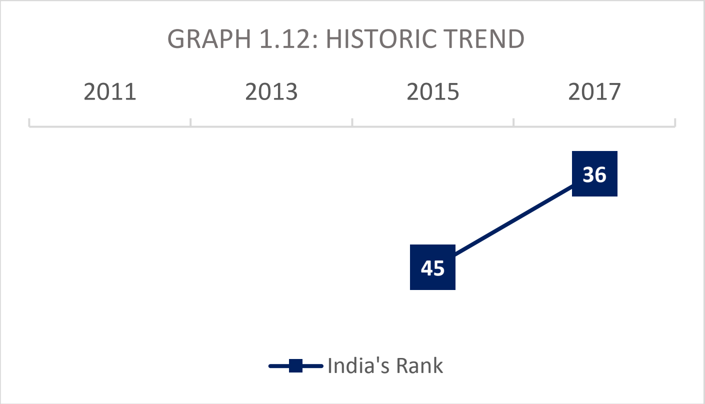

ग्राफ 1.12 संकेतक 1.10 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में 2015 की तुलना में 9 पदों की वृद्धि हुई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.125% का योगदान देता है।

तालिका1.27: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
कतर	2	6.26	1	6.33	शीर्ष प्रदर्शक
संयुक्त अरब अमीरात	3	6.22	2	6.21	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	4	5.99	3	6.14	एशियाई साथी
भारत	**45**	**3.91**	**36**	**4.36**	

संकेतक 1.11: निवेश करने के लिए प्रोत्साहन पर कराधान का विस्तार और प्रभाव

परिभाषा: "आपके देश में, कर किस हद तक कर निवेश करने के प्रोत्साहन को कम करता हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = निवेश करने के लिए प्रोत्साहन को काफी कम करता है, 7 = निवेश करने के लिए प्रोत्साहन को कम नहीं करता है)

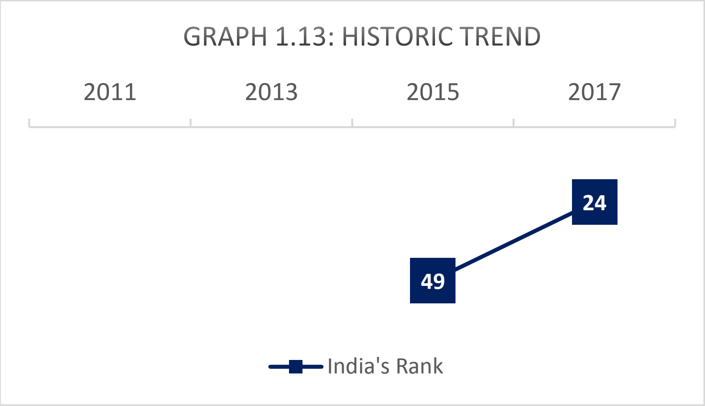

ग्राफ 1.13 संकेतक 1.11 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, 2015 की तुलना में भारत की श्रेणी 25 पदों की वृद्धि हुई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.125% का योगदान देता है।

तालिका 1.28: 1.28: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
संयुक्त अरब अमीरात	2	6.33	1	6.22	शीर्ष प्रदर्शक
बहरीन	1	6.49	2	6.07	शीर्ष प्रदर्शक
हांगकांग एसएआर	6	5.68	3	6.03	एशियाई साथी
भारत	**49**	**3.92**	**24**	**4.5**	

संकेतक का इतिहास: वर्ष 2011 और 2013 में, इस सूचक को 'कराधान का विस्तार और प्रभाव' नाम दिया गया था (कार्य और निवेश दोनों के लिए संयुक्त) । 2015 तक भारत की श्रेणी कम हो रही थी, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार की नीतियों में बदलाव के कारण 24 के एक अच्छे आंकड़ा पर आ गयी थी।

सरकारी पहल

- **कौशल विकास एक जिम्मेदारी के रूप में** - भारत को विश्व मानचित्र पर वापस लाने के लिए कौशल विकास क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सरकार,क्षेत्र के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कर लाभ की उम्मीद कर रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि कौशल विकास में शामिल सभी कंपनियों को आयकर या सेवा कर से छूट दी जाएगी। सेगमेंट पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सीएसआर पर पैसा खर्च करने वाली कंपनियों को 200% कर लाभ दिया जाना चाहिए। यदि सभी बड़े उद्योगों को कौशल प्रशिक्षण[42] पर पारदर्शी रूप से खर्च करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो कौशल खंड देश की बढ़ती कौशल आवश्यकताओं को आगे बढ़ा सकता है और पूरा कर सकता है।

- **भारत में निवेश की धारणा पर जीएसटी का प्रभाव। (माल और सेवा कर)**
    - भारत में कर संरचना को सरल बनाने के उद्देश्य से, जीएसटी व्यापार के लिए भौगोलिक बाधाओं को दूर करने और पूरे राष्ट्र को एक आम बाज़ार में बदलने का प्रस्ताव करता है। 'इससे पहले, अलग-अलग उदग्रहण के लिए अलग-अलग कानून थे। मसलन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, संबंधित राज्य वैट कानून आदि। जीएसटी शासन के साथ, केवल एक ऐसा कानून होगा, क्योंकि जीएसटी विभिन्न अप्रत्यक्ष करों[43] को कम कर देगा।.
    - पिछले कर शासन की अलग-अलग दरें थीं, जैसे कि, आबकारी @ 12.36% और सेवा कर @ 14%। जीएसटी के साथ, सभी राज्यों में केवल एक सीजीएसटी दर और एसजीएसटी की एक समान दर है।.
    - प्री-जीएसटी, समान विषय कर मामले पर केंद्र और राज्य दोनों को ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। जीएसटी के साथ, केंद्र और राज्य दोनों को सामान और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने के लिए समवर्ती शक्ति के साथ निहित किया जाता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 246ए में प्रस्तावित है। राज्यान्तरिक व्यापार अब केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
    - पहले, कर अनुपालन कानूनों की बहुलता और उनके प्रावधानों का पालन करने के कारण जटिल था। जीएसटी के साथ, कर अनुपालन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि केवल एक कानून के अनुसार अन्य करों का पालन करना होगा।

---

[42] https://www.businessinsider.in/Budget2016-Give-tax-incentives-to-India-Inc-for-skill-development-as-CSR/articleshow/51057269.cms

[43] https://www.greengst.com/difference-between-current-tax-structure-and-gst/

- इससे पहले, कर व्यापक रूप से उत्पादन और खपत में दो चरणों में लगाया जाता था, यानी, जब उत्पाद कारखाने से बाहर निकलता है तब और खुदरा आउटलेट पर भी। जीएसटी केवल उपभोग के अंतिम स्थान पर लगाया जाना है न कि विभिन्न बिंदुओं पर। यह अधिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त कर प्रशासन लाता है।
- इसके द्वारा कई कराधान शासनों को हटाने और कर प्रभाव को कम करने के लिए प्रेरित किया गया है। करों के कम बोझ के कारण, उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत में भी कमी आई है। यह भी धीरे-धीरे अंत उपभोक्ता पर बोझ को कम कर रहा है। काले धन, धोखाधड़ी प्रथाओं और कर चोरी में कमी आई है, खासकर ई-वे बिल जैसे सुधार अधिक नियंत्रण और पारदर्शिता में लाते हैं। नतीजतन, विस्तारित कर आधार के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई है; इसने एक स्वस्थ आर्थिक दृष्टिकोण को जन्म दिया है।
- जीएसटी का देश की जीडीपी वृद्धि, व्यापार करने में आसानी, व्यापार और उद्योग का विस्तार और 'मेक इन इंडिया' पहल पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ईमानदार व्यावसायिक प्रथाओं को स्थापित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होगा, जो भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति[44] बनने की ओर अग्रसर करेगा।

जीएसटी की शुरूआत का प्रभाव निवेशकों की सकारात्मक रूप से परिवर्तित धारणा और भारतीय बाजार में निवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि से दिखाई देता है। यह कराधान में शामिल पहले की थकाऊ और समय लेने वाली प्रक्रियाओं से काफी आसान होने के कारण है।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **जीएसटी के क्षेत्रवार प्रभाव का आकलन**

  करदाताओं के साथ-साथ क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक क्षेत्र वार प्रभाव आकलन अध्ययन से मौजूदा संरचना में सुधार और खामियों को दूर करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप को लागू करने में मदद मिलेगी।.

[44] https://qrius.com/the-future-of-gst-what-will-be-the-long-term-impact-on-the-indian-economy/

दीर्घकालिक योजना

- **अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संरचना को बढ़ाना**
    - सिंगापुर[45] में की गई आर एंड डी के लिए किए गए खर्च में 250% की कटौती प्रदान की गई है।
    - ये कटौती विभिन्न चरणों में पेश की गई है, पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (आईपी) रजिस्टर करने के लिए पहले 1,00,000 (सिंगापुर डॉलर) क्वालीफाइंग खर्च पर 200% की कटौती दी गई है, और क्वालिफाइंग आईपी लाइसेंस के लिए पहले SGD 1,00,000 के खर्च पर 200% की कटौती दी गई है।
    - व्यवसाय से संबंधित अनुसंधान एवं विकास पर किसी भी पूंजीगत व्यय (भूमि और भवन को छोड़कर) के लिए भारतीय कंपनियों / संस्थाओं को 100% कटौती उपलब्ध है। एक अनुमोदित इन-हाउस आर एंड डी सुविधा पर वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय करने वाली भारतीय कंपनियां पूंजी और राजस्व व्यय (भूमि और भवनों की लागत को छोड़कर) के 150% के भारित कटौती के हकदार हैं।
    - **भारत में बढ़ते अनुसंधान और विकास के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय को आगे भी इस तरह की छूट देने की आवश्यकता है।**

[45] http://taxsummaries.pwc.com/ID/Singapore-Corporate-Tax-credits-and-incentives

संकेतक 1.12: कुल कर दर

परिभाषा: यह संकेतक लाभ कर (लाभ के %), श्रम कर और योगदान (लाभ के %) और अन्य करों (लाभ के%) के संयोजन को संदर्भित करता है। कुल कर की दर एक मध्यम आकार की कंपनी द्वारा देय कर की राशि और अनिवार्य योगदान को मापती है, जो वाणिज्यिक लाभ के हिस्से के रूप में व्यक्त की जाती है। करों की कुल राशि में कटौती और छूट के लिए लेखांकन के बाद देय पांच अलग-अलग प्रकार के कर और योगदान का योग है: लाभ या कॉर्पोरेट आयकर, सामाजिक योगदान और श्रम कर नियोक्ता, संपत्ति कर, कारोबार कर और अन्य छोटे करों द्वारा भुगतान।

स्रोत: विश्व बैंक / अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, डूइंग बिज़नेस 2017 इक्वल ऑपर्चुनिटी फॉर ऑल

देश का मूल्य: लाभ कर (लाभ के %) + श्रम कर और योगदान (लाभ के %) + अन्य कर (लाभ के %)

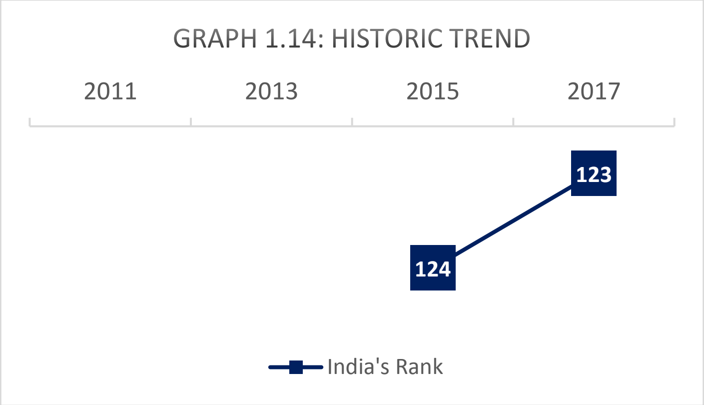

ग्राफ 1.14 संकेतक 1.12 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत कीश्रेणी वर्ष 2015 की तुलना में 1 स्थान की वृद्धि हुई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.99% का योगदान देता है।

तालिका 1.29: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
कतर	2	11.3	1	11.3	शीर्ष प्रदर्शक
कुवैत	3	12.8	2	13	शीर्ष प्रदर्शक
बहरीन	4	13.5	4	13.5	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	124	61.7	123	60.6	

- **सरकारी पहल**

- केंद्रीय बजट 2018 के तहत, सरकार ने 2 साल की अवधि में कॉर्पोरेट कर की दर को 30% से घटाकर 25% करने की घोषणा की है, जो 2016-2017 के दौरान 250 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू होगी ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मदद मिल सके। यह भी अनुमान है कि इस कदम के कारण जो राजस्व बलिदान किया गया है, वह महान आर्थिक सुधार लाएगा जो समग्र कर प्रणाली को बढ़ाएगा।
- नया माल और सेवा कर (जीएसटी) एक समान कर व्यवस्था है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर अलग-अलग करों की वर्तमान जटिल प्रणाली को बदल देगा, और अचल संपत्ति[46] सहित विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की संभावना है। इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के अनुसार, माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से कर अनुपालन में वृद्धि होगी और कर पारदर्शिता के कारण क्षेत्रों में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होंगे। जीएसटी कार्यान्वयन के कुछ अन्य प्रमुख लाभों में, कम रसद लागत, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता, बाजारों की बेहतर पहुंच और निर्यात प्रभावशीलता[47] शामिल हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

दीर्घकालिक योजना

- **कर को कम करना:**

तालिका 1.30: प्रकार के अनुसार कर

प्रकार के अनुसार कर	भारत		चीन	
	दिल्ली	मुंबई	शंघाई	बीजिंग
लाभ कर	21.70%	21.70%	10.60%	12.70%
श्रम कर	20.30%	20.30%	49.10%	40.80%
अन्य कर	10.10%	10.10%	8%	7.90%

स्रोत: डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2018

46 https://www.abode2.com/indias-biggest-tax-reform-will-boost-the-real-estate-industry/
47 https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/implementation-of-gst

- जैसा कि तालिका 1.30 में दिखाया गया है, भारत में व्यवसायों के मुनाफे पर लगभग 22% के लाभ कर की उच्च दर है। चीन के संशोधित व्यक्तिगत आयकर कानून जो अक्टूबर (2018) में लागू हुए, ने बच्चों की शिक्षा, सतत शिक्षा, गंभीर बीमारियों के उपचार, बुजुर्गों की देखभाल, साथ ही आवास ऋण के ब्याज और कर योग्य आय से किराए[48] में अतिरिक्त कटौती की है।
- अस्थायी कटौती के नियम निष्पक्ष और उचित होने के सिद्धांतों के तहत बनाए गए थे और एक ही समय में इसे सरल रखते हुए लोगों पर बोझ को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू करना आसान हो सके ताकि उनके जीवन में सुधार हो सके[1]।
- चीन ने अक्टूबर (2018) से व्यक्तिगत आयकर के लिए एक नया मानक लागू करना शुरू किया। व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 3,500 युआन से बढ़ाकर 5,000 युआन प्रति माह कर दी गई। नवीनतम योजना में कर से बचाव के नए उपाय[1]भी शामिल हैं, जो चीन में रहने वाले लोगों के लिए काफी तैक्ष्ण है।
- इन उपायों का उद्देश्य अचल संपत्ति कर संग्रह को मजबूत करना है, अपतटीय टैक्स हैवन्स के उपयोग को रोकना और करों[3] से बचने के लिए डिज़ाइन की गई "अनुचित वाणिज्यिक व्यवस्था" पर दरार डालना है।.
- मूल्य वर्धित कर चीनी कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक है, जिसमें पिछले साल 39 प्रतिशत कर संग्रह शामिल थे। कॉरपोरेट आय करों का 22 प्रतिशत[48] का योगदान है।
- चीन एक संपत्ति होल्डिंग टैक्स लगाने की योजना के साथ भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह ऐसी प्रक्रिया जो काफी विवादास्पद है, उसे कई और साल लगने की उम्मीद है।

---

[48] http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/20/c_137547189.htm

<u>स्तंभ 2: बचाव और सुरक्षा</u>

परिभाषा: यह स्तंभ इस बात को मापता है कि एक देश पर्यटकों और व्यवसायों को सुरक्षा जोखिमों के लिए किस हद तक मुख्य रूप से लोगों (हिंसा और आतंकवाद) से गंभीर नुकसान पहुंचाता है, तुच्छ अपराध को ध्यान में नहीं रखा जाता है। **स्तंभ 2 में कुल 5 संकेतक दिए गए हैं --**

1. अपराध और हिंसा की व्यावसायिक लागत
2. पुलिस सेवाओं की विश्वसनीयता
3. आतंकवाद की व्यावसायिक लागत
4. आतंकवाद की मामलें का सूचकांक
5. मानव हत्या दर

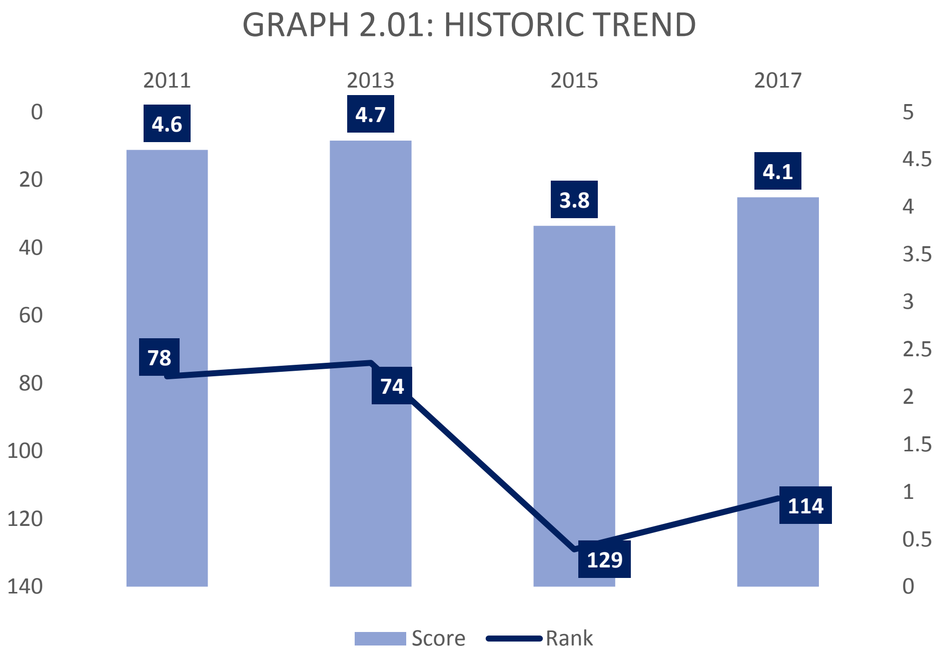

ग्राफ 2.01 भारत की श्रेणी और स्तंभ में मूल्य की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को इंगित करता है। भारत की श्रेणी 2011 में 78 वें स्थान से घटकर 2017 में 114 वें स्थान पर पहुंच गई है।

भार की अवस्था में बदलाव:

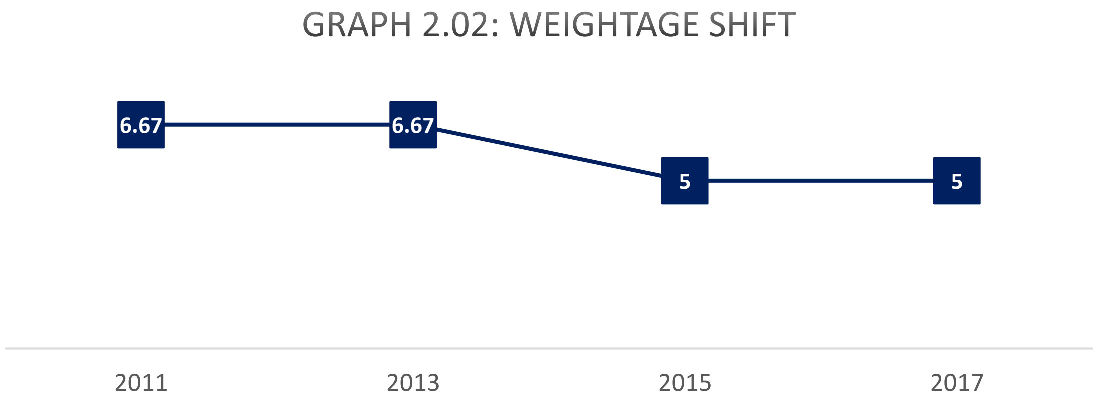

ग्राफ 2.02 भारत के स्कोर में स्तंभ 2 यानी बचाव और सुरक्षा के समग्र योगदान को इंगित करता है। वर्तमान में, इस स्तंभ को 5% भार दिया जाता है। इस स्तंभ का भार वर्ष 2015 में 25% कम हो गया है।

तालिका 2.01: भार की अवस्था में संकेत वार बदलाव

संकेतक	2011-2013 (%)	2015-2017 (%)	भार में बदलाव (%)
अपराध और हिंसा की व्यावसायिक लागत	1.67	1	-40.12
पुलिस सेवाओं की विश्वसनीयता	1.67	1	-40.12
आतंकवाद की व्यावसायिक लागत	1.67	1	-40.12
आतंकवाद की मामलें का सूचकांक	NA	1	NA
मानवहत्या दर	NA	1	NA

NA = लागू नहीं, उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

तालिका 2.01 उस योगदान का प्रतिशत दर्शाती है कि जो कि प्रत्येक संकेतक का भारत के समग्र स्कोर पर है।

अस्वीकरण- यह स्तंभ राष्ट्रीय सुरक्षा के मापदंडों और सरकार द्वारा उन मुद्दों पर अंकुश लगाने के लिए की गई कार्रवाई से संबंधित है। ये क्रियाएं और वर्गीकृत जानकारी आम लोगों के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए, खंभे से संबंधित मौजूदा उपायों या स्थितियों पर टिप्पणी करना अनुचित होगा।

हमारे अनुसंधान और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, स्तंभ के समग्र सुधार के लिए सकारात्मक प्रकाश में संबंधित संकेतकों के लिए सुझाव प्रदान किए गए हैं।

ध्यान दें: संकेतक 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 और 2.05 एक एकल संकेतक के रूप में दिखाए जा रहे हैं क्योंकि वे अंतर-संबंधित हैं और उनकी एक आम कार्य योजना हो सकती है क्योंकि बचाव और सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से एक आम रणनीति इन सभी संकेतकों पर वांछित प्रभाव डाल सकती है।

संकेतक 2.01: अपराध और हिंसा की व्यावसायिक लागत

परिभाषा: "आपके देश में, अपराध और हिंसा की मामलें किस हद तक व्यवसायों पर लागत प्रभाव डालती हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = काफी हद तक; 7 = बिल्कुल नहीं)

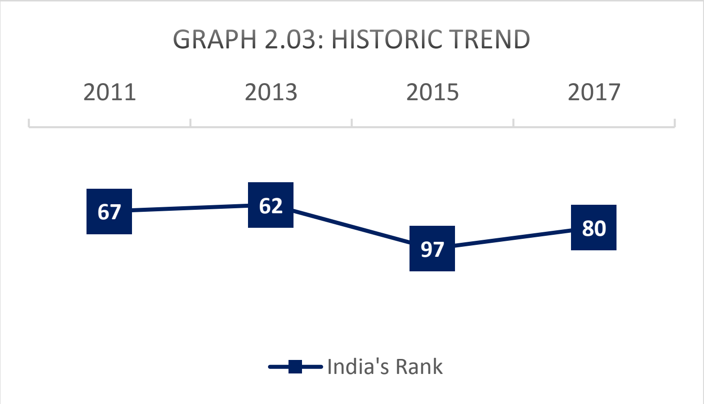

ग्राफ 2.03 संकेतक 2.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 17 स्थान की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

तालिका 2.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
संयुक्त अरब अमीरात	2	6.51	1	6.43	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
सिंगापुर	4	6.17	7	6.15	एशियाई साथी
नॉर्वे	20	5.60	11	5.82	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**97**	**3.84**	**80**	**4.36**	

संकेतक 2.02: पुलिस सेवाओं की विश्वसनीयता

परिभाषा: "एक देश में, कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए पुलिस सेवाओं पर किस हद तक निर्भर किया जा सकता है?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

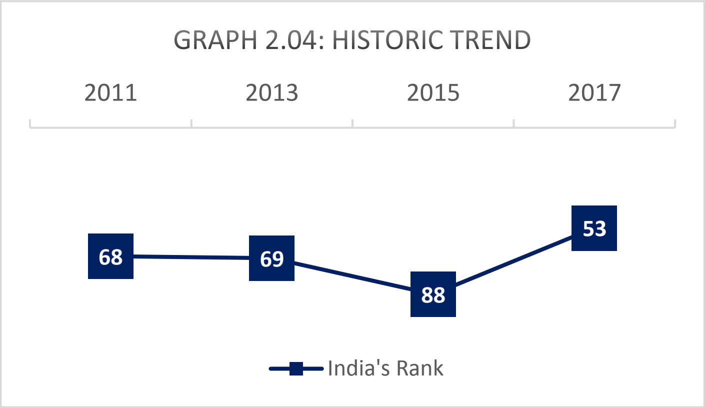

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = बिलकुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, 7 = पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है)

ग्राफ 2.04 संकेतक 2.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 35 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

तालिका 2.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
फिनलैंड	1	6.73	1	6.78	शीर्ष प्रदर्शक
न्यूज़ीलैंड	2	6.48	2	6.61	शीर्ष प्रदर्शक
स्विट्जरलैंड	5	6.22	3	6.56	शीर्ष प्रदर्शक
यूनाइटेड स्टेट्स	22	5.73	23	5.97	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**88**	**3.82**	**53**	**4.73**	

संकेतक 2.03: आतंकवाद की व्यावसायिक लागत

परिभाषा: "आपके देश में, आतंकवाद का खतरा किस हद तक व्यवसायों पर लागत का बोझ डालता है?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = काफी हद तक, 7 = बिल्कुल नहीं)

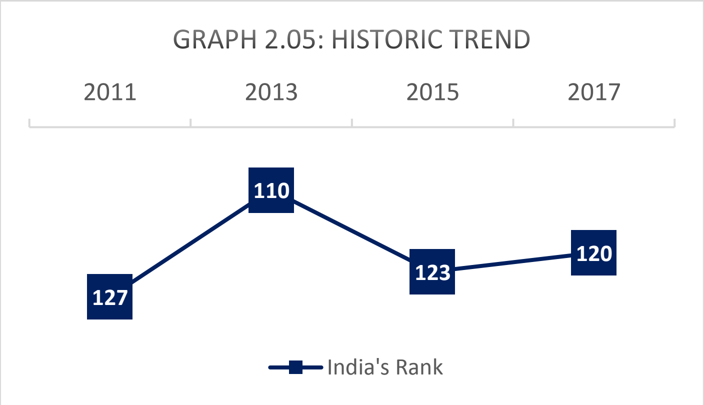

ग्राफ 2.05 संकेतक 2.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 3 पदों की वृद्धि हुई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

तालिका 2.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
लेसोथो	76	5.19	1	6.71	शीर्ष प्रदर्शक
उरुग्वे	4	6.52	2	6.52	शीर्ष प्रदर्शक
फिनलैंड	1	6.68	3	6.43	शीर्ष प्रदर्शक
इंडोनेशिया	104	4.61	113	4.21	एशियाई साथी
भारत	**123**	**3.96**	**120**	**4.00**	

संकेतक 2.04: आतंकवाद संबंधी मामलेंओं का सूचकांक

परिभाषा: यह सूचक आतंकवाद संबंधी कार्यवाहियों की संख्या और आतंकवादी हमलों की संख्या के एक साधारण औसत को संदर्भित करता है, प्रत्येक को 1 से 7 के पैमाने पर सामान्यीकृत किया जाता है जहां न्यूनतम अधिकतम सूत्र का उपयोग किया जाता है जहां 1 सबसे अधिक हमले / जनहानि होता है और 7 कोई हमला नहीं / जनहानि की संख्या होता है।

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आतंकवाद के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय संघ और आतंकवाद का जवाब, वैश्विक आतंकवाद डाटाबेस

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{कुल आतंकवादी हमलों की संख्या + आतंकवाद के कारण होनेवाली कुल जनहानि की संख्या}}{2}$$

जहां दोनों, आतंकवादी हमलों की कुल संख्या और आतंकवाद के कारण होने वाली जनहानि की कुल संख्या 1 से 7 के पैमाने पर सामान्य कर दी गई है।.

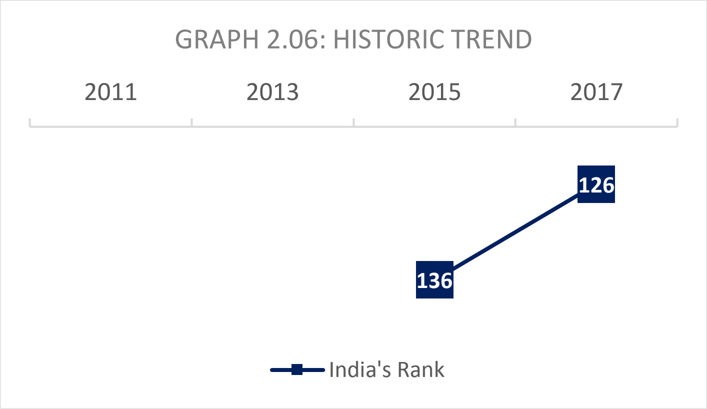

ग्राफ 2.06 संकेतक 2.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 10 पदों की वृद्धि हुई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

तालिका 2.05: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
वियतनाम	1	7	1	7	एशियाई साथी
सिंगापुर	1	7	1	7	एशियाई साथी
हांगकांग	1	7	1	7	एशियाई साथी
नॉर्वे	107	6.74	1	7	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

फ्रांस	120	6.15	110	5.48	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**136**	**1**	**126**	**1**	

इस संकेतक में 6 देशों की पहली श्रेणी है क्योंकि उन सभी का मूल्य समान है।

संकेतक 2.05: मानवहत्या दर

परिभाषा: यह संकेतक प्रति 100000 जनसंख्या पर मानवहत्या दर मामलों की संख्या को संदर्भित करता है

स्रोत: ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, भारत का राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो

देश का मूल्य = $\frac{\text{कुल मानवहत्या मामलों की संख्या} \times 100000}{\text{देश की जनसंख्या}}$

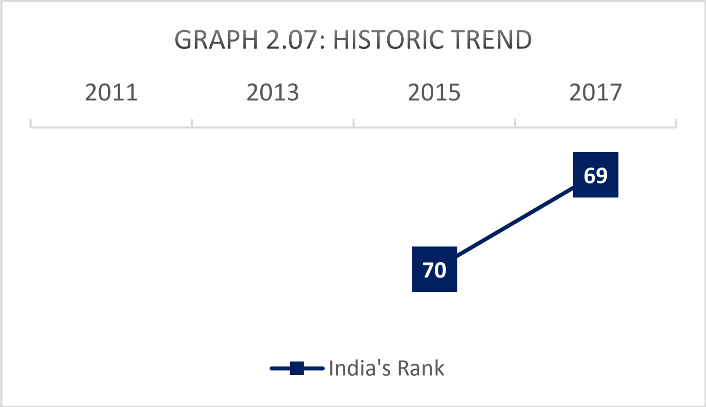

ग्राफ 2.07 सूचक 2.05 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 1 स्थान की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

तालिका 2.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
साइप्रस	50	2	1	0.1	शीर्ष प्रदर्शक
ग्रीस	42	2	1	0.1	शीर्ष प्रदर्शक
आइसलैंड	2	0	3	0.3	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	70	4	69	3.2	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **सामुदायिक जागरूकता और शैक्षिक गतिविधियाँ कार्यक्रम**

  पुलिस सेवाओं में नए प्रावधानों की शुरुआत, झूठी सूचना के प्रसार और हिंसक अतिवाद के खतरों के बारे में भारत में काफी कम जन जागरूकता है। एक अध्ययन के अनुसार, यह कहा गया है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग पाँचवाँ हिस्सा (लगभग 21%) जानता है कि "पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन" पूरे भारत में मौजूद हैं और लगभग 16% लोग चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर[49] की शुरुआत के बारे में जानते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की एक रिपोर्ट में गलत जानकारी और उल्लेखों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बताया गया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में और वृद्धि की आशंका को रोकने के लिए लगभग 16,315 घंटे के इंटरनेट बंद किया गया था। कई मामलों में, सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वाले या भड़काऊ मैसेजिंग ने 2012 से 2017 के बीच इंटरनेट शटडाउन का फैसला करने के लिए निर्णय लिया था, जिससे देश में अनुमानित $ 3.04 बिलियन[50] की लागत आयी थी। इस प्रकार, उपर्युक्त मुद्दों पर अंकुश लगाने के लिए, भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों के निम्नलिखित उदाहरणों का अनुसरण किया जा सकता है:

  - **"एसजीसिक्योर" सिंगापुर[51] में जन जागरूकता अभियान** आपातकालीन तैयारी को बेहतर बनाने, सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने और एसजीसिक्योर मोबाइल एप्लिकेशन के लॉन्च के द्वारा राष्ट्रीय पुनरुत्थान का निर्माण करने के लिए शुरू किया गया था, जहां नागरिक प्रमुख आपात स्थितियों के दौरान अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अधिकारियों को जानकारी प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने एक एसजीसिक्योर वेबसाइट भी शुरू की, जो बढ़ते खतरों, ई-लर्निंग मॉड्यूल के बारे में तथ्य प्रदान करती है और इसे निम्नानुसार तीन क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाता है:

[49] http://commoncause.in/pdf/SPIR-2018-c-v.pdf
[50] http://commoncause.in/pdf/SPIR-2018-c-v.pdf
[51] http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf

- **सचेत रहें (सामुदायिक सतर्कता):** किसी भी सुरक्षा खतरे की सूचना दें और हमले के बाद सतर्क रहें।
- **एकजुट रहे (सामुदायिक सामंजस्य):** मजबूत सामुदायिक संबंधों का निर्माण करें और सिंगापुर की नस्लीय और धार्मिक सद्भाव की रक्षा करें और शांति के समय और हमले के बाद एक साथ खड़े रहे।
- **मजबूत रहें (सामुदायिक लचीलापन):** जानें कि किसी हमले में फंसने पर खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे बचाया जाए और किसी भी मामलें के बाद एक-दूसरे को जल्दी से उबारने में मदद करें।.

○ **ऑस्टिन सिटी (यूएसए)** एकमात्र शहर है जिसके पास अपने पुलिस विभाग का इंस्टाग्राम खाता है। वे लोगों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा युक्तियों और सामान्य जागरूकता के बारे में वीडियो अपलोड करते हैं। इससे उन्हें जनता के बीच अपनी छवि सुधारने में मदद मिली है। प्रचार और सूचना संबंधी गतिविधियों जैसे सोशल मीडिया दृश्यता, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो शो आदि ने जागरूकता फैलाने के साथ-साथ नागरिकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद की है।

विभिन्न राज्यों में पुलिस विभागों की मदद से गृह मंत्रालय भारत भर में सामुदायिक जागरूकता और शैक्षिक गतिविधियों के कार्यक्रम को लागू कर सकता है (बिहार, पंजाब और मिजोरम जैसे राज्यों में ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए) जो हिंसक अतिवाद के खतरों के साथ सुरक्षा के सभी प्रावधानों के बारे में अवगत कराता है और आपातकालीन तैयारी में सुधार करके राष्ट्रीय लचीलापन बनाने का उद्देश्य रखता है। अखबारों और विज्ञापनों का उपयोग लोगों को झूठी जानकारी के प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है और यह उसी के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में पहला कदम होना चाहिए। **सोशल मीडिया पर इस तरह की झूठी खबरों को रोकने के लिए विभिन्न राज्य विभागों द्वारा स्वतंत्र तथ्य-चेकर्स भी लगाए जा सकते हैं।**

मध्यम अवधि की योजना

- **अधिकारियों और नागरिकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (सीबीटी) कार्यक्रम**

  आत्मरक्षा, सैन्य अभ्यास, और आपातकालीन स्थितियों के बारे में जागरूकता की गुणवत्ता शिक्षा अधिकतर सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक और निजी फर्मों में ठीक से शामिल नहीं की गयी है। इसके अलावा, पुलिस थानों में लैंगिक अनुकूल माहौल की कमी, दुर्व्यवहार और भारत में पुलिस कर्मियों

की जबरन वसूली वाली प्रकृति महिलाओं को पुलिस थानों[52] में जाने से रोकती है। परिणामस्वरूप यह पुलिस के साथ लोगों की बातचीत को कम करता है और इसके बाद विश्वास के स्तर को कम करता है। उपरोक्त चुनौतियों को निम्नलिखित विधियों द्वारा संबोधित किया जा सकता है:

- **अधिकारियों के लिए सीबीटी:** उपरोक्त कौशल को व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम प्रदान करके दूर किया जा सकता है जहां पुलिसकर्मियों को प्रबंधन और संचार कौशल के साथ-साथ "व्यावहारिक कौशल" में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसे टेलीफोन कॉल का जवाब देना, आगंतुकों से बात करना आदि। प्रशिक्षण को तीसरे पक्ष को आउटसोर्स भी किया जा सकता है जहां विशेषज्ञ महीने में एक या दो बार पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही, पीड़ितों और गवाहों के साक्षात्कार और संदिग्धों[53] और अभियुक्तों के वैज्ञानिक पूछताछ में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: 2013 में, पर्यावरण और अपेक्षाओं को बदलने में पुलिस विभाग की, जिम्मेदारी पर 2-दिवसीय कार्यशाला और जनता के साथ पुलिस के महत्व पर जोर देना "पुलिस और गैर-सरकारी संगठनों[54] की मदद से आयोजित किया गया था। **इसलिए, पुलिस विभाग, गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थाओं के सहयोग से गृह मंत्रालय को पुलिस कर्मियों के लिए व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए और लिंग, एससी / एसटी, अल्पसंख्यक, बच्चों, शारीरिक रूप से अक्षम और अन्य कमजोर वर्गों के मुद्दों के प्रति एक बार संवेदनशीलता कार्यशालाओं का म्हणे में एक बार संचालन करना चाहिए। यह न केवल पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि पुलिस के साथ लोगों के संपर्क स्तर को भी बढ़ाएगा।**
- **नागरिकों के लिए सीबीटी:** सरकार की सेवा प्रावधान क्षमता में सुधार करके, लड़कियों के लिए शैक्षिक पहुंच को लक्षित करने और स्कूलों में आत्म-रक्षा प्रशिक्षण प्रदान करके सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है। स्कूलों में प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए। हाशिए के युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों को स्थापित करने में मदद और समुदाय आधारित स्कूलों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में, यूएसएआईडी (यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) कार्यक्रमों ने 154,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में मदद

---

[52]http://www.bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/201808160350402786762PeopleFriendlyReportsenttostates.pdf
[53]http://www.bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/201808160350402786762PeopleFriendlyReportsenttostates.pdf
[54]http://www.bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/201808160350402786762PeopleFriendlyReportsenttostates.pdf

की, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण में 54,000 से अधिक महिला शिक्षक भी शामिल थी। इससे प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की उपलब्धता और महिला छात्रों की नामांकन दर में भी सुधार हुआ क्योंकि अफगानिस्तान में सांस्कृतिक मानदंड एक ऐसी सीमा तक सीमित हैं जिससे कि पुरुष शिक्षक महिला छात्रों.[55] को नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए, **गृह मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण के उद्देश्य से विशेष रूप से काम पर रखे गए सैन्य अधिकारियों की मदद से यूएसएआईडी या इसी प्रकार के गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर सकता है।**

- **एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (काला धन शोधन विरोधी) कानून**
  - मनी लॉन्ड्रिंग को आपराधिक गतिविधियों का गुणक माना जा सकता है क्योंकि यह अपराधियों को आर्थिक शक्ति देता है। अपराधियों की कार्यवाही का उपयोग करने के लिए अपराधियों को अनुमति देने से लॉन्ड्रिंग अपराध को सार्थक बनाता है, जो बदले में आपराधिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है।
  - वित्तीय कार्रवाई कार्य बल द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नॉर्वे और फ्रांस सहित अधिकांश यूरोपीय देशों में विभिन्न मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण के उपाय किए गए। देशों को उन व्यक्तियों की यात्रा का वित्तपोषण करने की आवश्यकता होती है जो अपने राज्य के निवास या राष्ट्रीयता के अलावा किसी अन्य राज्य की यात्रा करते हैं, जो अपराधी के कार्य, नियोजन या तैयारी, या आतंकवादी गतिविधियों को प्रदान करने या आतांकवादी प्रशिक्षण[56] प्राप्त करते या देते हैं।
  - भारत सरकार ने 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के निवारण के लिए उसमें संशोधन किया है जिससे आतंकवादी संगठनों द्वारा प्राप्त धन और धन के प्रवाह पर सतर्कता बढ़ी है।
  - भारत को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने और वैश्विक मानदंडों के अनुरूप धन शोधन कानून की रोकथाम के मद्देनजर मनी लॉन्ड्रिंग (संशोधन) विधेयक 2011 को जरूरी करार दिया गया था। उक्त विधेयक अभी भी संसद में मंजूरी के लिए लंबित है। **इसलिए, गृह मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के लिए एक अल्पकालिक योजना संसद में बिल पारित करने के लिए कार्रवाई करना है।**

[55] http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf
[56] http://www.fatf-gafi.org/home/

दीर्घकालिक योजना

- **क़ानून और कानून प्रवर्तन**
  - अमेरिकी विभाग द्वारा आतंकवाद 2016 पर देश रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के आतंकवाद निरोधक कानूनों में बड़े बदलाव आवश्यक हैं। भारत ने अपने मौजूदा लेकिन इतने प्रभावी क़ानूनों के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को संबोधित करना जारी रखा है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) (1967), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए आतंकवाद के दमन अधिनियम (1993) और विभिन्न राज्य स्तरीय[57]. कानून शामिल हैं। इसलिए, सरकार की शक्ति का सही दिशा में उपयोग करने के लिए उचित उपायों की आवश्यकता है ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण मौजूदा कानूनों को बेहतर तरीके से आकार दे सके और अधिक स्थिरता प्रदान करने में मदद कर सके।
  - विकेंद्रीकरण को किसी एक हिस्से को दूसरे के विकल्प के लिए सक्षम करने के रूप में परिभाषित किया गया है। जब प्रणाली का एक हिस्सा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, तो एक या कई अन्य हिस्सों को संभाल सकता है। एक देश जो आतंकवादी हमलों का संभावित लक्ष्य है, विकेंद्रीकरण[58] के विभिन्न रूपों को लागू करके इसकी भेद्यता को कम कर सकता है।
  - इंडोनेशिया ने 2000 में, एक झटके में केंद्रीयकृत सरकार की पिछली प्रणाली और विकास योजना को विकेंद्रीकरण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ बदल दिया। सुधारों ने अधिक अधिकार, राजनीतिक शक्ति, और वित्तीय संसाधनों को सीधे रीजेंसी और नगर पालिकाओं को दिया, प्रांतों को पारित करके। हस्तांतरित शक्तियों में स्वास्थ्य, प्राथमिक और मध्यम स्तर की शिक्षा, सार्वजनिक कार्यों, पर्यावरण, संचार, परिवहन, कृषि, विनिर्माण और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के क्षेत्रों में जिम्मेदारियों की एक विस्तृत श्रृंखला को निष्पादित करना शामिल है। उसी समय, सरकार ने आधुनिक वित्त-प्रवेश लेखांकन प्रणाली के साथ सार्वजनिक वित्त की प्राचीन नकदी-आधारित, एकल-प्रवेश प्रणाली को बदल दिया, जो एकल कोषागार खाते का उपयोग करती है; प्रदर्शन आधारित है; और सार्वजनिक संकेतक के पारदर्शी प्रबंधन, तंग व्यय और प्रदर्शन संकेतकों के साथ वित्तीय नियंत्रण, कम्प्यूटरीकृत रिपोर्टिंग और एक तंग अनुसूचित लेखा प्रणाली[59] है। **इस प्रकार, कानून और न्याय मंत्रालय, इसी तरह की तर्ज पर, भारत में विकेंद्रीकृत बिजली व्यवस्था को लागू करने के लिए एक तंत्र के बारे में सोच सकते है।**

---

[57] https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/
[58] https://d-nb.info/1026857384/34
[59] https://www.adb.org/sites/default/files/publication/201116/adbi-wp601.pdf

- **काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म (CVE) को बढ़ाना**
    - सीवीई हिंसात्मक उग्रवादियों द्वारा हिंसा के लिए अनुयायियों को कट्टरपंथी बनाने, भर्ती करने और भड़काने के लिए किए गए प्रयासों का मुकाबला करने के लिए सक्रिय गतिविधियों को संदर्भित करता है। सीवीई कार्रवाइयाँ विशिष्ट कारकों को संबोधित करने का इरादा रखती हैं जो हिंसक चरमपंथी भर्ती और हिंसा को कट्टरपंथी बनाती हैं। भारत में हिंसात्मक अतिवाद का मुकाबला करना एक सबसे कम सक्रिय पहल है और देश में सीवीई को लागू करने के लिए एक गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए। यह नीचे उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करके किया जा सकता है, जो कि यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) द्वारा भी लागू किया गया है:
    - आतंकवादी कट्टरपंथीकरण और भर्ती के उत्प्रेरकों को बेहतर ढंग से समझने और प्रभावी हस्तक्षेपों को जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक इच्छाशक्ति, साझेदारी और विशेषज्ञता का विस्तार करें।
    - हिंसक चरमपंथ के प्रसार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए साझेदार सरकारों को और अधिक प्रभावी नीतियों और दृष्टिकोणों को अपनाने और प्रोत्साहित करने में सहायता करें, जिसमें जहाँ आवश्यक हो वहां परिवर्तनशील प्रथाओं को शामिल करना होता है।
    - विकास सहित विदेशी सहायता उपकरण और दृष्टिकोणों को कार्य में लाएं, विशिष्ट कारकों को कम करने के लिए जो पहचान योग्य क्षेत्रों में हिंसक चरमपंथ के लिए समुदाय के समर्थन में योगदान करते हैं या आबादी के विशेष क्षेत्रों को उच्च जोखिम में डालते हैं।
    - सशक्त और स्थानीय रूप से विश्वसनीय आवाज़ों को बढ़ाये जो प्रमुख जनसांख्यिकीय खंडों के बीच हिंसक चरमपंथी समूहों और उनकी विचारधारा की धारणा को बदल सकते हैं।
    - सरकारी और गैर-सरकारी कारकों की क्षमताओं को अलग-थलग करने, हस्तक्षेप करने और हिंसा[60] के लिए कट्टरता के चक्र में पकड़े गए व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्बलन को बढ़ावा दे।
  - **पाकिस्तान संक्रमण पहल (2007-वर्तमान):** कराची और दक्षिणी पंजाब में अपने कार्यक्रमों के साथ यूएसएआईडी के संक्रमण पहल कार्यालय पाकिस्तान में संघर्ष-ग्रस्त समुदायों में राजनीतिक और सामाजिक विकास की नींव बनाने के लिए हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करना चाहता है।

[60] https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/

संबंधित मंत्रालयों, स्थानीय सरकारों, सामुदायिक समूहों और निजी क्षेत्र के साथ काम करते हुए, यूएसएआईडी निवासियों को कौशल विकसित करने, सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान के मूल्यों को सुदृढ़ करने और प्रति-कथन विकसित करने के लिए सकारात्मक अवसर प्रदान करता है। अलग-अलग, पाकिस्तान के ऍफ़ऐटीऐ / केपी क्षेत्र में, यू एसएआईडी स्थानीय रूप से संचालित परियोजनाओं[61] के माध्यम से समुदाय-सरकार के संबंधों को मजबूत करके चरमपंथियों के लिए समुदायों को लचीला बनाने के पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है।

- **इसलिए, गृह मंत्रालय हाल ही के वर्षों में आतंकवाद की गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों (मुंबई, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदि) में भारत में सीइवी कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएसएआईडी की समान नीतियों को अपना सकता है।**

- **कौशल और आधारिक संरचना विकास**
  - उचित आधारिक संरचना और सुविधाओं जैसे वाहनों, फोन या वायरलेस संचार उपकरणों की कमी से किसी भी कार्रवाई के लिए प्रतिक्रिया समय में वृद्धि होती है, जिससे भारत में पुलिस सेवाओं की सार्वजनिक छवि बिगड़ती है। मानव-शक्ति की कमी एक और कारक है जो इस स्थिति को और खराब करता है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 22.8 लाख की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 5.6 लाख पुलिस कर्मियों की कमी थी और भारत[62] में महिला पुलिस बल की संख्या केवल 7.28% ही थी। साथ ही, ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के डाटा से पता चलता है कि 2013 में, प्रति लाख जनसंख्या में 138 पुलिस कर्मियों का अनुपात 71 देशों में जिनका अध्ययन[63] किया गया था वह पांचवें निम्नतम स्थान पर था।
  - पुलिस बल के जीवन पर विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि कानून और व्यवस्था को संभालने में काम के दबाव और जटिलताएं जबर्दस्त गति से बढ़ी हैं, जनशक्ति की वृद्धि कम नहीं हुई है। रिक्तियों और पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं[64] की कमी के बीच एक कड़ी है। उत्तरार्द्ध ही इसका एक कारण हो सकता है जो कि राज्य पुलिस बलों को जल्दी से पदों को भरने से रोक रहा है। इसे संबोधित करने के लिए, विभिन्न विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि कुछ प्रशिक्षित

[61] https://www.usaid.gov/countering-violent-extremism
[62] https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/just-7-28-per-cent-women-in-police-forces-government-data/articleshow/63068249.cms
[63] https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/indias-ratio-of-138-police-personnel-per-lakh-of-population-fifth-lowest-among-71-countries/articleshow/48264737.cms
[64] http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Strengthening-Police-Force.pdf

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को राज्यों में तैनात किया जा सकता है और साथ ही, इन भावी प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण को एक आकर्षक विकल्प बनाया जाना चाहिए।

- एक अन्य सुधार जनशक्ति के पूरक के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
  - यूएई, **एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)** क्राइम डिटेक्शन का उपयोग करके[65]अपने अपराधों को कम कर रहा है: वास्तविक समय की जानकारी के स्रोतों वाले शहर, पारंपरिक सुरक्षा कैमरों से लेकर स्मार्ट लैंप तक, जिसका उपयोग वे अपराधों का पता लगाने के लिए कर सकते हैं जैसा ही वे होते हैं। यूके ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की भी मदद ली है, एकत्र किए गए डाटा का उपयोग गोलाबारी और उस बिंदु का पता लगाने के लिए किया गया है जहां[66] से बंदूक की गोली आई थी।
  - **यूनाइटेड स्टेट्स में, कैमरे और निगरानी प्रणाली** चेहरे की पहचान, लाइसेंस प्लेट रीडिंग और अप्राप्य सामान का पता लगाने जैसे कार्यों को करने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। कैमरों के भीतर प्रसंस्करण करने से, प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाती है। यह महत्वपूर्ण बैंडविड्थ का उपयोग करने की आवश्यकता को भी कम कर सकता है क्योंकि केवल प्रासंगिक जानकारी को प्रेषित[67] करने की आवश्यकता होती है।
- **सिंगापुर के द्वीपों में पुलिस कैमरों का नेटवर्क** उनके घरेलू अपराध से लड़ने में मददगार रहा है। उन्होंने 10,000 हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड (एचडीबी) ब्लॉक और मल्टी स्टोरी कार पार्क (एमएससीपी) में 62,000 से अधिक कैमरे स्थापित किए हैं, जिन्हें पोलकैम 1.0 के रूप में जाना जाता है। पोलकैम पुलिस कैमरों के एक बड़े नेटवर्क के उपयोग के माध्यम से पड़ोस और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बहु-वर्षीय सार्वजनिक पहल है। अपने पोलकैम 1.0 कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के बाद, वे अपने पोलकैम 2.0 कार्यक्रम[68] के तहत द्वीप पर 2,500 स्थानों पर कुछ वर्षों में 11,000 अधिक कैमरे लगाने की योजना बना रहे है।
- **इस प्रकार, इसी तरह की तर्ज पर, गृह मंत्रालय पुलिस बलों की आधारिक संरचना और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उपर्युक्त उन्नत तकनीकों को लागू करने के लिए सभी राज्य पुलिस विभागों के साथ सहयोग कर सकता है।**

---

[65] https://www.thenational.ae/uae/robocops-and-predicting-crime-dubai-police-plan-an-artificial-intelligence-future-1.698034

[66] https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2018/04/21/can-ai-help-us-predict-and-prevent-crimes-in-the-future/#620245055d9a

[67] https://www.wscpa.net/uploads/1/1/9/8/119821114/smr18nl.pdf

[68] https://www.straitstimes.com/singapore/installation-of-62000-police-cameras-in-10000-hdb-blocks-multi-storey-carparks-complete

- **यूएनओडीसी (ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) के साथ साइनिंग कंट्री प्रोग्राम**
    - A यूएनओडीसी द्वारा वर्ष 2001 में "नेशनल सर्वे ऑन एक्स्टेंट, पैटर्न एंड ट्रेंड्स ऑफ ड्रग एब्यूज" नाम का एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 12-60[69] वर्ष की आयु के लोगों में नशीली दवाओं के उपयोग में 3.2% की मासिक प्रसार दर है। भारत फार्मास्युटिकल व्यापार के लिए लाइसेंस अफीम और केटामाइन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन अफीम की एक अनिर्धारित मात्रा को अंतरराष्ट्रीय दवा बाजारों में बदल दिया जाता है। भारत हवाला[70] प्रणाली के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मादक पदार्थों की भी चपेट में है।
    - **वियतनाम ने ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ एक देश कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए,** जो यूएनओडीसी और वियतनामी सरकार के बीच सहयोग प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। कार्यक्रम उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन की वकालत और समर्थन करता है, जिनके लिए यूएनओडीसी दुनिया भर में संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इसने वियतनामी कानूनी प्रणाली के भीतर संबंधित कानून को अपनाने में भी मदद की। समर्पित कार्यक्रम घटक उन प्रथाओं और सामग्रियों की शुरूआत में मदद कर रहे हैं जो दवा नियंत्रण और आपराधिक न्याय में आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं। देश कार्यक्रम नीचे दिए गए पांच अंतर-संबंधित उप कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न चुनौतियों का जवाब देता है:
        - अपराधिक संगठित अपराध और अवैध तस्करी;
        - भ्रष्टाचार विरोधी और धन शोधन;
        - आतंकवाद की रोकथाम;
        - आपराधिक न्याय; तथा
        - दवा की मांग में कमी और एचआईवी / एड्स

    इसलिए, कानून और न्याय मंत्रालय, वियतनाम के समान तर्ज पर, ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ एक देश कार्यक्रम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय के साथ भी सहयोग कर सकता है।

---

[69] https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/2.0_Drug_statistics_and_Trends.pdf
[70] https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Illicit-drugs

<u>स्तंभ 3: स्वास्थ्य और स्वच्छता</u>

परिभाषा: यह स्तंभ स्वास्थ्य संसाधनों की उपलब्धता जैसे कि चिकित्सक घनत्व, बुनियादी सफाई संसाधन तक पहुंच, बेहतर पेयजल तक पहुंच को मापता है जो यात्रियों के आराम और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी मामलें में कि जहाँ पर्यटक बीमार हो जाते हैं, देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को यह सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए कि उनकी ठीक से देखभाल की जा रही हैं। स्तंभ 3 के नीचे कुल 6 संकेतक हैं -

1.चिकित्सक घनत्व

2. बेहतर सफाई संसाधन तक पहुंच

3. बेहतर पेयजल तक पहुंच

4. अस्पताल के बिस्तर

5. एचआईवी का प्रसार

6. मलेरिया की मामलें

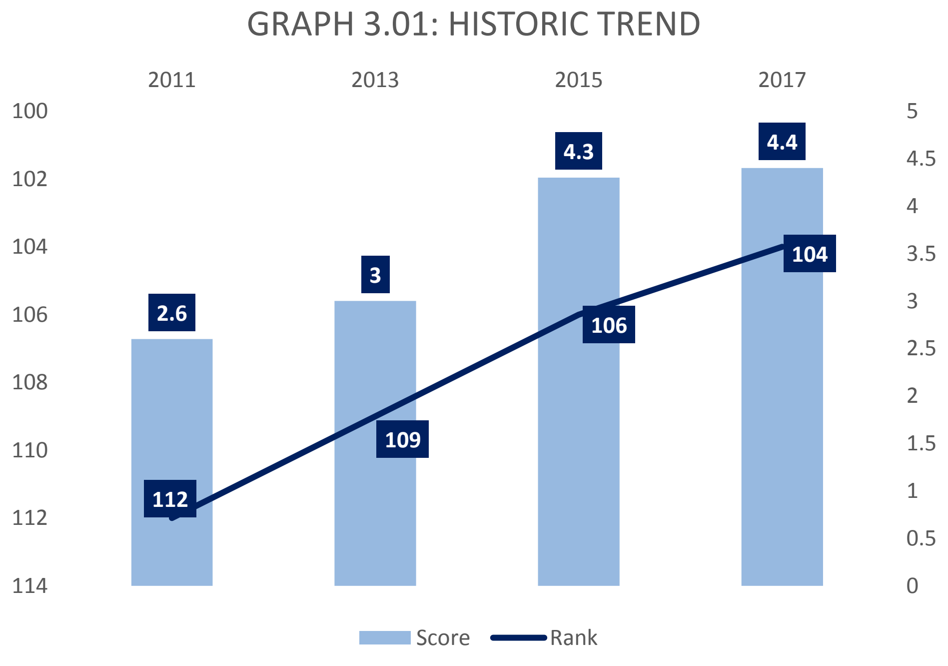

ग्राफ 3.01 में भारत की श्रेणी और स्तंभ में मूल्य का संकेत दिया गया है। भारत की श्रेणी 2011 में 112 वें स्थान से बढ़कर 2017 में 104 वें स्थान पर पहुंच गई है।

भार की स्थिति में बदलाव:

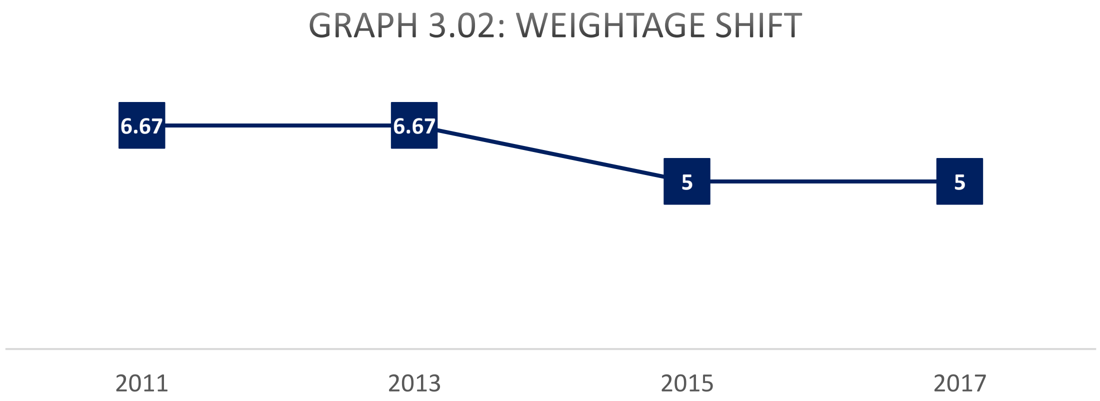

ग्राफ 3.02 भारत के स्कोर में स्तंभ 3 यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता के समग्र योगदान को इंगित करता है। वर्तमान में, इस स्तंभ को 5% भार दिया जाता है। वर्ष 2015 में इस स्तंभ के भार में 25% की कमी आई है।

तालिका 3.01: संकेतक वार भार की स्थिति में बदलाव

संकेतक	2011-2013 (%)	2015-2017 (%)	भार की स्थिति में बदलाव (%)
चिकित्सक घनत्व	1.67	1	-40.12
बेहतर सफाई संसाधन तक पहुंच	1.67	0.5	-70.06
बेहतर पेयजल तक पहुंच	1.67	0.5	-70.06
अस्पताल के बिस्तर	1.67	1	-40.12
एचआईवी का प्रसार	0.83	1	20.48
मलेरिया की मामलें	NA	1	NA

NA = लागू नहीं, उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

2013 तक, एचआईवी प्रसार मानव संसाधन के स्तंभ के तहत था। टीटीसीआई रिपोर्ट 2015 संस्करण में, एचआईवी प्रसार स्तंभ 3 का एक हिस्सा बन गया और एक नया संकेतक (मलेरिया की मामलें) भी पेश किया गया है।

तालिका 3.01 योगदान का वह प्रतिशत दर्शाती है जो कि प्रत्येक संकेतक भारत के समग्र स्कोर पर है।

संकेतक 3.01: चिकित्सक घनत्व

परिभाषा: यह संकेतक देश में प्रति 1,000 की जनसंख्या पर चिकित्सकों की संख्या को संदर्भित करता है।

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक स्वास्थ्य वेधशाला रिपोजिटरी

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{चिकित्सकों की संख्या} \times 1000}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

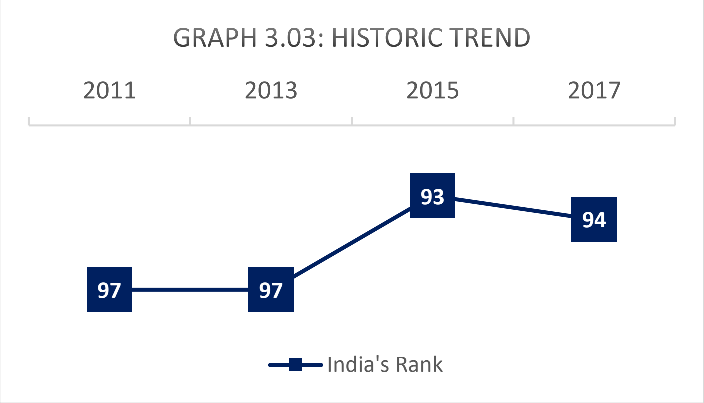

ग्राफ 3.03 सूचक 3.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 1 स्थान की कमी आई है। यह सूचक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

भारत में डाटा स्रोत: डब्ल्यूएचओ वैश्विक स्वास्थ्य वेधशाला रिपॉजिटरी (जीएचओआर) के डाटा को प्रत्येक देश के संबंधित काउंसिल डाटाबेस से संकलित करता है। इसलिए, भारत के मामले में, भारतीय मेडिकल काउंसिल डब्ल्यूएचओ को यह डाटाबेस प्रदान करता है।

तालिका 3.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
कतर	1	7.74	1	7.74	शीर्ष प्रदर्शक
स्पेन	13	3.7	2	4.95	शीर्ष प्रदर्शक
ग्रीस	3	4.38	3	4.38	शीर्ष प्रदर्शक
	38	2.79	40	2.8	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**93**	**0.7**	**94**	**0.7**	

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय प्रगतिशील रणनीतियाँ**
    - डब्ल्यूएचओ के मानकों (1: 1000) के अनुसार, भारत को 10 गुना अधिक एलोपैथिक डॉक्टरों की आवश्यकता है, जो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में वर्णित संख्या से कम से कम 6 लाख अतिरिक्त सरकारी डॉक्टरों के बराबर हैं। इस प्रकार, इस कमी को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ रणनीतिक उपाय निम्नलिखित हैं:
        - एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम सेवन क्षमता में 150 से 250 की वृद्धि।
        - भूमि, संकाय, कर्मचारियों, बिस्तर / बिस्तर की तादाद और अन्य आधारिक संरचना की आवश्यकता के संदर्भ में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के मानदंडों में छूट।
        - पीजी सीटों के नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम / वृद्धि शुरू करने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण / उन्नयन।
        - मौजूदा जिला / रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।
        - छात्रों के लिए शिक्षकों का अनुपात 1: 1 से 1: 2 या अधिकतम 1: 3 से संशोधित किया गया है और 65-70 साल से संकाय की नियुक्ति के लिए आयु सीमा में वृद्धि की गयी है।
        - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उपर्युक्त रणनीतियों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा कर सकता है और यदि परिदृश्य में भिन्नता के आधार पर किसी और सुधार की आवश्यकता होती है, तो उचित बदलाव शुरू किए जाने चाहिए जो देश के चिकित्सक घनत्व को लंबे समय तक सुधारने में मदद करेगा।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (पहले भारतीय चिकित्सा परिषद के रूप में जाना जाता था।)

ध्यान दें: भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), 2018 अध्यादेश के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है

अल्पकालीन योजना

- **एमसीआई/एनएमसी द्वारा आयुष डॉक्टरों को मान्यता:**
  - आयुष: आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) का गठन आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान के विकास पर ध्यान देने के साथ किया गया था।
  - ओस्टियोपैथी: ऑस्टियोपैथी के चिकित्सकों को ओस्टियोपैथ कहा जाता है। ऑस्टियोपैथी एक प्रकार की वैकल्पिक दवाई है जो मैनुअल समायोजन, मायोफेशियल रिलीज और मांसपेशियों के ऊतकों और हड्डियों के अन्य शारीरिक हेरफेर पर जोर देती है।
  - यूनाइटेड किंगडम ने "ओस्टियोपैथी एक्ट 1993" नामक एक अधिनियम पारित किया, जिसमें यूके के जनरल मेडिकल काउंसिल (जीएमसी) ने जीएनआई को ऑस्टियोपैथिक चिकित्सकों को चिकित्सा चिकित्सकों के रूप में मान्यता दी है। इसी तरह, भारत में, 7.73 लाख आयुष[71] चिकित्सक हैं, लेकिन उन्हें सामान्य चिकित्सकों के रूप में एमसीआई/एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। **इस प्रकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपील कर सकता है कि वे इन आयुष डॉक्टरों को मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में मान्यता दे सकें। इससे चिकित्सक का घनत्व 0.86 से बढ़कर 1.50 हो जाएगा।.**
  - यह मानकर कि अन्य देशों के चिकित्सक घनत्व में कोई बदलाव नहीं है, आयुष डॉक्टरों को मान्यता देकर, भारत की श्रेणी 18 स्थानों पर उछल कर इस संकेतक में अपनी श्रेणी को 76 पर पंहुचा सकती है।

तालिका 3.03: चिकित्सक घनत्व प्रति 1000 लोगों पर आयुष चिकित्सक को शामिल करके

डॉक्टरों के प्रकार	एमसीआई के तहत पंजीकृत चिकित्सक	चिकित्सक घनत्व प्रति हजार लोगों पर
एलोपैथी डॉक्टर	1041395	0.86/1000
आयुष चिकित्सक	773668	0.64/1000
कुल (आयुष + एलोपैथी)	**1815063**	**1.50/1000**

[71] Ministry of AYUSH

दीर्घकालिक योजना

- **विदेशों में पलायन करने वाले डॉक्टरों पर जुर्माना लगाना**
    - भारत दुनिया में मेडिकल डॉक्टरों के सबसे बड़े "निर्यातकों" में से एक है। 2004 तक, 71,290[72] भारतीय चिकित्सा चिकित्सकों ने पलायन किया है (नवीनतम डाटा उपलब्ध नहीं है)। यह 14-वर्षीय डाटा उन 7% डॉक्टरों के लिए है जो वर्तमान में भारत में मौजूद है।
    - ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (बीएपीआईओ) के अनुसार, यूके में 40,000 भारतीय डॉक्टर हैं, जबकि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन (बीएपीआईओ) यूएस में 50,000 भारतीय डॉक्टर दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले लगभग 20% डॉक्टरों ने भारत[73] में अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त की है।
    - इसी तरह की समस्या से निपटने के लिए, यूनाइटेड किंगडम अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई के 4 साल के भीतर विदेश जाने वाले डॉक्टरों पर £ 220m का जुर्माना लगाने की सोच रहा है। यह देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के प्रति अधिक निष्ठा सुनिश्चित करेगा। क्योंकि भारत दुनिया में चिकित्सकों के पलायन का सबसे बड़ा स्रोत है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसी तरह से ब्रिटेन की तर्ज़ पर अपने डॉक्टरों पर जुर्माना लगाना शुरू कर सकते हैं जो विदेश जाने की योजना बना रहे हैं जो देश में प्रतिभा पलायन की समस्या को हल करने में भी मदद करेगा।

[72] The World Bank: Physician Brain Drain
[73] Economic Times: Indian Healthcare: Stop the brain drain of doctors

संकेतक 3.02: बेहतर सफाई संसाधन तक पहुंच

परिभाषा: यह संकेतक उत्सर्जन की कम से कम पर्याप्त सुविधाओं के साथ आबादी के प्रतिशत को संदर्भित करता है जो उत्सर्जन के साथ मानव, पशु और कीट के संपर्क को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं।

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक स्वास्थ्य वेधशाला डाटा रिपॉजिटरी

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{पर्याप्त स्वच्छता का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या x 100}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

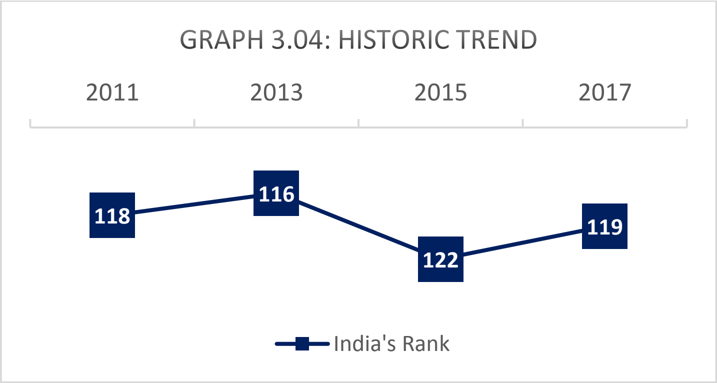

ग्राफ 3.04 संकेतक 3.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 3 स्थान की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.5% का योगदान देता है।

तालिका 3.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
जापान	1	100	1	100	एशियाई साथी
यूनाइटेड स्टेट्स	1	100	1	100	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**122**	**36**	**119**	**39.6**	

इस संकेतक में 13 देशों की पहली श्रेणी है क्योंकि इन सभी का मूल्य समान है।.

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) / स्वच्छ भारत मिशन: एसबीएम एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसे 2 अक्टूबर 2014 को अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 तक, केवल 38.70% ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त थे। एसबीएम

के प्रक्षेपण के 4 साल बाद, 96.17% ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच मुक्त हैं। अब तक एसबीएम अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है और इस दर पर भारत को 2019 तक ओडीएफ घोषित किया जाएगा। इससे भारत की श्रेणी को 2021 तक पहली श्रेणी तक ले जाने में काफी सुधार होगा।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पेयजल मंत्रालय और स्वच्छता (एमडीडब्ल्यूएस)

अल्पकालीन योजना

- **बचाव, सुरक्षा और स्वच्छता:**
  - सितंबर 2017 तक, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के आंकड़ों[74] का दावा है कि 12,526 सामुदायिक शौचालय (सीटी) बनाए गए हैं। हालांकि, उत्तरी भारत के एक ग्रामीण गांव में एसक्यूयूएटी[75] (स्वच्छता गुणवत्ता, उपयोग, पहुंच और रुझान) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में एक प्रमुख मुद्दा प्रकाश में आया कि महिलाएं रात में सामुदायिक शौचालय (सीटीएस) में जाना सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इसके अलावा, अपर्याप्त डिजाइन, आंशिक रूप से निर्मित शौचालय, खराब रखरखाव, अनुचित प्रकाश व्यवस्था, खराब पहुंच और पानी की अनियमित उपलब्धता सार्वजनिक शौचालय / सामुदायिक शौचालयों की कुछ अन्य समस्याएं हैं जो महिलाओं को उनका उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करती हैं।
  - **इसलिए, पेयजल और स्वछता मंत्रालय को लिंग अनुकूल सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों, इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान और अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के लिए पानी की आपूर्ति और साबुन की उपलब्धता के लिए क्यूबिकल्स में डस्टबिन का प्रावधान कर सकते हैं। उनका मुख्य ध्यान सीटी के लिए कार्यवाहक / सुरक्षा गार्ड नियुक्त करके महिलाओं के बचाव और**

[74] http://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/index.htm
[75]http://riceinstitute.org/news_post/why-community-toilets-wont-reduce-open-defecation-in-rural-india

सुरक्षा पर होना चाहिए। सीटी के लिए सुरक्षा गार्ड को समुदाय के भीतर से ही भर्ती किया जा सकता है ताकि एक जाना माना चेहरा होने के नाते, यह महिलाओं को रात में भी सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे।

मध्यम अवधि की योजना

- **पिछड़ रहे राज्यों पर ध्यान दें**

तालिका 3.05: न्यूनतम खुले में शौच से मुक्त (ओडीऍफ़) कवरेज के साथ वाले राज्य

राज्य	ओडीऍफ़ कवरेज
गोवा	5.87%
ओडिशा	36.56%
बिहार	42.35%
त्रिपुरा	56.54%
तेलंगाना	62.51%

- भारत के भीतर गोवा[76] जैसे राज्य हैं जो न्यूनतम 5.87% ग्रामीण खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि ओडिशा के लिए यह आंकड़ा 36.56% है। भारत को इन राज्यों पर ध्यान देने और उन्हें शौचालयों के अनिवार्य उपयोग[77] के माध्यम से ग्रामीण ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) बनाने की आवश्यकता है जैसे कि हरियाणा जैसे राज्यों में (शौचालय उपयोग के मामले में एक मॉडल राज्य), उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कुछ अन्य राज्यों में किया गया है वहां विधेयक पारित किया गया है कि एक विधेयक पंचायत चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए घर में एक कार्यात्मक शौचालय होना अनिवार्य बना दिया है। कई जिला समस्या को हल करने के लिए नवीन दृष्टिकोण अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, खुले में शौच करने वाले लोगों पर सीटी बजाना, गाँव के होर्डिंग पर उनकी तस्वीरें प्रकाशित करना, उनके राशन कार्ड रद्द करना, या अन्य सरकारी लाभ वापस ले लेना। इन प्रथाओं के अलावा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे शौचालय का उपयोग करने के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करें और यह आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) कार्यक्रमों जैसे

[76] https://sbm.gov.in/sbmdashboard/ODF.aspx
[77] http://www.rediff.com/news/report/how-to-make-the-eople-use-toilets/20170818.html

कि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से और शौचालयों के अनिवार्य उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान के द्वारा किया जा सकता है।

दीर्घकालिक योजना

- **सामुदायिक द्वारा संचालित पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) मॉडल को अपनाना**

○ **सामुदायिक द्वारा संचालित पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस)** मॉडल को अपनाना

- ○ हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक स्तर पर परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी पाया गया है क्योंकि यह स्वच्छता की ओर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को संबोधित करता है और महिलाओं को बदलाव के एजेंट के रूप में शामिल करता है। सीएलटीएस में, वे घर के मुखिया को शिक्षित करते हैं और एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) की भागीदारी के माध्यम से शौचालय का उपयोग करने के लाभों से अवगत कराते हैं, आईईसी कार्यक्रमों के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक समूह बनाते हैं।
- ○ **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय सीएलटीएस मॉडल का गहनता से अध्ययन कर सकता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रथा कैप्चरिंग और उनके पीछे के कारण पर ध्यान केंद्रित करने पर किया जाएगा। अध्ययन के बाद, एमडीडब्ल्यूएस, मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से उन राज्यों में लागू कर सकता है जहां ओडीएफ प्रथाएं न्यूनतम स्तर पर है।**

संकेतक 3.03: बेहतर पेयजल तक पहुंच

परिभाषा: यह संकेतक आबादी के उस प्रतिशत को संदर्भित करता है, जिसमें एक बेहतर स्रोत से पर्याप्त मात्रा में पानी तक पहुंच प्राप्त होती है, जैसे कि घरेलू कनेक्शन, सार्वजनिक स्टैंडपाइप, बोरहोल, संरक्षित कुएं या सोते और वर्षा जल संग्रह।

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक स्वास्थ्य वेधशाला डाटा रिपॉजिटरी

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{बेहतर स्रोत से पानी की पर्याप्त मात्रा के साथ कुल जनसंख्या} \times 100}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

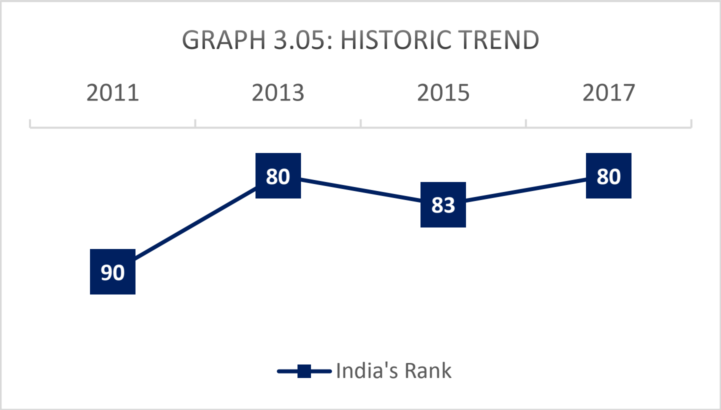

ग्राफ 3.05 संकेतक 3.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 3 स्थान की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.5% का योगदान देता है।

तालिका 3.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
भूटान	55	98	1	100	एशियाई साथी
जॉर्जिया	43	99	1	100	शीर्ष प्रदर्शक

हांगकांग	1	100	1	100	एशियाई साथी
सिंगापुर	1	100	1	100	एशियाई साथी
भारत	**83**	**93**	**80**	**94.1**	

इस सूचक में 35 देशों की पहली श्रेणी है क्योंकि उन सभी का मूल्य एक समान है।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पेयजल मंत्रालय और स्वच्छता

अल्पकालीन योजना

- **वर्षा जल संचयन प्रथा**
  - 2001 में, तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक घर के लिए वर्षा जल संचयन आधारिक संरचना का होना अनिवार्य कर दिया, जो 5 वर्षों के भीतर समग्र जल गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। इसी तरह का एक प्रयोग बंगलौर और पुणे शहरों में किया गया था, जहां हाउसिंग सोसाइटियों को वर्षा के पानी का संचयन करना था। इन कुछ उदाहरणों के अलावा, वर्षा जल संचयन के लिए कोई पैन इंडिया आधारिक संरचना या योजना नहीं है। इस प्रमुख क्षेत्र को पिछले कई वर्षों से यूहीं छोड़ दिया गया है, जिसे इस तथ्य के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि पेयजल और स्वच्छता (एमडीडब्ल्यूएस) ने वर्षा जल संचयन पर अपने मैनुअल को आखिरी बार 2004 में अपडेट किया था। तब से मंत्रालय द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए कोई संशोधित सामग्री प्रकाशित नहीं हुई है।
  - बड़े पैमाने पर प्रभाव / अंतर बनाने के लिए देशव्यापी वर्षा जल संचयन अभियान शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। इस प्रकार, पेयजल और स्वच्छता को एनजीओ जैसे वर्षा-जल, केएफपी आदि के साथ या सीएसआर पहल के तहत विभिन्न निगमों के साथ मिलकर एक गाँव / खेत को गोद लेने की नीति तैयार करनी चाहिए और इसे स्थायी रूप से पानी को लेकर सुरक्षित बनाना चाहिए। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से सीखते हुए, एमडीडब्ल्यूएस विशाल नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं और स्व-सहायता समूहों से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर वर्षा जल संचयन के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं।

मध्यम अवधि की योजना

- **अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग**
  - एशियाई विकास बैंक की भविष्यवाणी के अनुसार, भारत में वर्ष 2030 तक पानी की 50% तक की कमी होगी। पानी की कमी में पानी का तनाव, पानी की कमी और पानी का संकट शामिल है। मुख्य कारक जो इसमें योगदान देते हैं वे हैं कृषि के लिए पानी का अकुशल उपयोग,

पारंपरिक जल रिचार्जिंग क्षेत्रों की संख्या में कमी, पारंपरिक जल निकायों में सीवेज और अपशिष्ट जल की निकासी और कुशल जल प्रबंधन और वितरण की कमी।

- तालिका 3.07 में 50% से अधिक शहरी आबादी वाले राज्यों[78] की सूची है जिसमें पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं है।

तालिका 3.07: पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के बिना वाली शहरी आबादी का प्रतिशत

राज्य	पेयजल आपूर्ति के बिना की शहरी जनसंख्या का %
झारखंड	55.12
राजस्थान	62.24
बिहार	80.09
नागालैंड	76.8
असम	80.39

- सिंगापुर को भी पानी की कमी की ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा जहाँ उसे मलेशिया से आयातित पानी पर निर्भर रहना पड़ा। सिंगापुर सरकार ने देश को टिकाऊ पानी की आपूर्ति प्रदान करने की इस चुनौती को संभालने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसके लिए उसने "एनई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट" विकसित किया, जिसे 2003 में पेश किया गया था। इस उपचार के एक हिस्से के रूप में, उन्नत तकनीकें पानी को उपचारित करती हैं और इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाती हैं। परिणामी उपचारित पानी की गुणवत्ता इतनी अधिक होते है कि इसका उपयोग पीने के पानी के स्थान पर किया जाता है। वर्तमान में पांच एनई जल उपचार संयंत्र हैं, जो देश की पानी की 30% मांग को पूरा करते हैं।

[78] Niti Aayog WTR Ranking

- **इसी तरह से, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को तालिका 3.07 में वर्णित राज्यों के लिए कम से कम, सिंगापुर की अपशिष्ट जल उपचार रणनीति को अपनाना चाहिए। इसे जल संसाधन मंत्रालय और संबंधित राज्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर ऐसे राज्यों में अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लागू किया जा सकता है, ताकि अपशिष्ट जल को पीने के पानी के रूप में परिवर्तित करके स्थायी जल आपूर्ति को बनाए रखा जा सके।**

दीर्घकालिक योजना

- **पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)**
  - सुलभ इंटरनेशनल, एक संगठन जिसने बिहार में दशकों पहले 'सुलभ शौचालय' की अवधारणा को पेश किया था, ने एक अभिनव परियोजना के लिए एक आधारशिला रखी है जो दुनिया में केवल 50 पैसे प्रति लीटर की लागत से सस्ता पेयजल प्रदान करती है। यह दूषित तालाब के पानी को सुरक्षित पेयजल में परिवर्तित करके किया जाएगा। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन (एसआईएसएसओ) ने दक्षिण परगना जिले[79] के मधुसूदन कांति गांव में 20 लाख रुपये के तालाब आधारित जल उपचार संयंत्र स्थापित किये है।.
  - 2017 में, बिहार सरकार ने 2020 के अंत तक सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के मकसद से "हर घर नल का जल" योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, बिहार का सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) पानी गंगा की जमीन से स्रोत करने के बजाय पाइप लाइन के द्वारा गंगा की सतह से प्रदान करेगा। गंगा के पानी को शुद्ध करने के लिए, पीएचईडी ने सुलभ इंटरनेशनल के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक निर्मित किए गए लोगों के समानांतर ही जल उपचार संयंत्र का निर्माण किया है।
  - नीति अयोग[80] ने उपर्युक्त पहल की सराहना की और कहा कि अन्य राज्यों को समान मॉडल का अनुकरण करना चाहिए। **एमडीडब्ल्यूएस विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के साथ मिलकर इस अभिनव अवधारणा का विस्तार करने के लिए ऐसी कंपनियों के साथ सहयोग कर सकता है ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सभी पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता हो, वहां सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके।**

---
[79] http://www.sulabhinternational.org/bihar-to-get-worlds-cheapest-clean-drinking-water/
[80] http://www.sulabhinternational.org/arsenic-free-water-across-bihar-by-2020-phed-minister/

○ तालिका 3.08 उन राज्यों[81] को दिखाती है जिनके पास पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के बिना वाली 50% से अधिक की ग्रामीण आबादी है। इन राज्यों की ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से तत्काल ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

तालिका 3.08: अतिरिक्त पेय जल आपूर्ति के बिना ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत

राज्य	पेयजल आपूर्ति के बिना की ग्रामीण जनसंख्या का %
नागालैंड	54.31
राजस्थान	55.58
सिक्किम	64.64
कर्नाटक	67.01
केरल	77.95
मेघालय	83.25

[81] Niti Aayog WTR Ranking

संकेतक 3.04: अस्पताल के बिस्तर

परिभाषा: यह संकेतक प्रति 10,000 लोगों पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या को संदर्भित करता है। अस्पताल के बेड में सार्वजनिक, निजी, सामान्य, और विशिष्ट अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में उपलब्ध आंतरिक रोगी बिस्तर शामिल हैं। ज्यादातर मामलों में, तीव्र और स्थायी देखभाल दोनों के लिए बिस्तर शामिल हैं।

स्रोत: द वर्ल्ड बैंक, विश्व विकास संकेतक

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{अस्पताल के बिस्तरों की संख्या} \times 10000}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

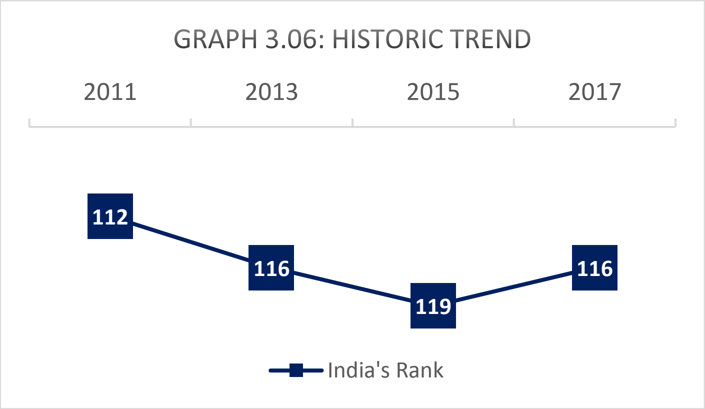

ग्राफ 3.06 संकेतक 3.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 3 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

तालिका 3.09: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
जापान	1	137	1	137	एशियाई साथी
कोरिया, गणराज्य	2	103	2	103	एशियाई साथी
रूसी संघ	3	97	3	97	शीर्ष प्रदर्शक
हांगकांग	38	45	30	52.4	एशियाई साथी
ऑस्ट्रेलिया	41	39	42	39	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

भारत	119	7	116	7	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **निजी और आयुष अस्पताल के बिस्तर का समावेश**
    - कनाडा, लिथुआनिया, चिली, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में उनके देश में उपलब्ध अस्पताल के बेड की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जो की इस संकेतक की की परिभाषा भी है उसमें सार्वजनिक, निजी, सामान्य, और विशिष्ट अस्पतालों और पुनर्सुधार केंद्रों में उपलब्ध उनके दाखिल किये गए रोगियों के बिस्तर शामिल हैं।.
    - दूसरी ओर, भारत में केवल अपने सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध अस्पताल के बिस्तरों की संख्या शामिल है, जो की इसके इस संकेतक में खराब श्रेणी में आने का एक कारण भी है। **यदि भारत निजी अस्पतालों में उपलब्ध अपने दाखिल किये हुए रोगियों के बिस्तर के साथ-साथ अपने 3601 आयुष अस्पतालों (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) को भी शामिल करता है, तो आने वाले वर्षों में भारत की श्रेणी में 116 वें स्थान से सुधार हो सकता है। इसलिए, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अस्पतालके बिस्तर के लिए एक केंद्रीकृत डाटाबेस को बनाए रखना भारत की श्रेणी में सुधार कर सकता है।**

मध्यम अवधि की योजना

- **अस्पताल के बिस्तरों के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस बनाए रखना**
    - केंद्र सरकार ने सभी चिकित्सीय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और नियमन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कानून लागू किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सुविधाओं और सेवाओं के लिए बुनियादी न्यूनतम मानकों के अनुरूप हों। वर्तमान में, यह भारत के कई राज्यों में लागू है, लेकिन असम, गोवा, गुजरात, केरल, और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, निजी अस्पतालों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानून का अभाव है अर्थात सरकार[82] से प्रमुख लाइसेंस प्राप्त किए बिना अस्पतालों की स्थापना की जा सकती है।

[82] PWC, 2017-Healthcare Infrastructure

- ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधित राज्य या क्षेत्र के स्वास्थ्य विभागों के साथ एक निजी अस्पताल को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया था, तभी वह अपना कामकाज शुरू कर सकता है और अपने रोगियों का उपचार/इलाज कर सकता है। इस पंजीकरण प्रक्रिया ने स्वास्थ्य देखभाल की आधारिक संरचना[83] के लिए एक केंद्रीकृत डाटा बेस को बनाए रखने में ऑस्ट्रेलिया की मदद की है। इसी तरह, **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सभी निजी अस्पतालों के लिए नैदानिक स्थापना अधिनियम को अनिवार्य बनाने के लिए राज्य और क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह एक केंद्रीकृत डाटाबेस प्रदान करेगा, जो देश भर में स्वास्थ्य सेवा के आधारिक संरचना से संबंधित नीतिगत निर्णयों में सुधार करेगा।**

[83] Australian government: Department of Health

दीर्घकालिक योजना

- **स्वास्थ्य देखभाल आधारिक संरचना पर खर्च में वृद्धि करें**
  - भारत चिकित्सा पर्यटन के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक है, जिसका तात्पर्य है कि हमारे कुछ अस्पताल अपेक्षाकृत कम लागत पर विश्व स्तरीय उपचार प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे अस्पताल भी हैं, जिनके लिए कोई सुविधा नहीं है, अपर्याप्त सुविधाएं हैं, मरीज के लिए कोई बिस्तर या एम्बुलेंस नहीं है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण भारत कुल आबादी की 75% है, लेकिन देश के अस्पतालों, अस्पताल के बिस्तर और डॉक्टरों केवल 30% है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए 100 किमी से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है।
  - गरीबों को माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की, जिसे आयुष्मान भारत के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को शामिल करने की योजना है और यह देश की जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सशक्त करेगा। लेकिन इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल के लाभों के प्रावधान के लिए एक विशाल आधारभूत संरचना और प्रणाली का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसके लिए देश भर में डॉक्टरों, क्लीनिकों और अस्पतालों समान रूप से वितरित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाले परिवार की पहुंच में आ सकें।
  - सरकार की विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ने बढ़ती स्वास्थ्य सेवा की मांग को पूरा करने और मौजूदा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आने वाले 10 वर्षीय अस्पताल विकास योजना (एचडीपी) को लागू करने के लिए HK $ 200 बिलियन का एक समर्पित कोष अलग से रखा है। 10-वर्षीय एचडीपी में शामिल हैं:
    - विकास क्षेत्र में नए एक्यूट अस्पताल का निर्माण, नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नए सहायक सेवा केंद्र और मौजूदा अस्पतालों के पुनर्विकास / विस्तार का लक्ष्य देश में वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है।
  - इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्तमान स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना की स्थिति को सुधारने के लिए, हम हांगकांग की ही तर्ज पर, 10 वर्षीय अस्पताल विकास योजना भी शुरू कर सकते हैं, जो उन्हें देश भर में दूरस्थ क्षेत्रों में

अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या बढ़ाने में सक्षम बनाएगी।

संकेतक 3.05: एचआईवी का प्रसार

परिभाषा: एचआईवी प्रसार 15-49 आयु वर्ग के लोगों के प्रतिशत को संदर्भित करता है जो समय के साथ एक विशेष बिंदु पर एचआईवी से संक्रमित होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है की संक्रमण कब हुआ है।

स्रोत: द वर्ल्ड बैंक, विश्व विकास संकेतक डाटाबेस, यूएनएड्स

देश का मूल्य = $\frac{((15-49) \text{ आयु वर्ग में एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या} \times 100)}{(\text{देश की } (15-49) \text{ कुल जनसंख्या})}$

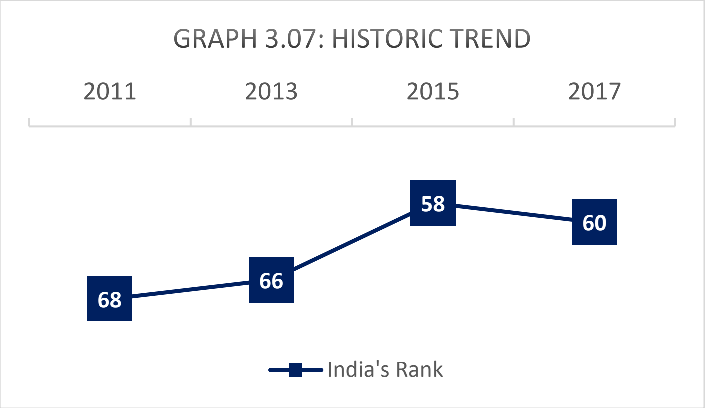

ग्राफ 3.07 संकेतक 3.05 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 2 स्थान की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

तालिका 3.10: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
अल्बानिया	1	<0.2	1	<0.1	शीर्ष प्रदर्शक
चीन	1	<0.1	1	<0.1	एशियाई साथी
नेपाल	58	0.3	1	0.2	एशियाई साथी
भारत	**58**	**0.3**	**60**	**0.3**	
मेडागास्कर	87	0.5	60	0.3	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

इस संकेतक में 58 देशों की पहली श्रेणी है क्योंकि यह सभी 0.2 मूल्य से कम या बराबर है

- **भारत की एचआईवी प्रसार दर में कमी**

  2017 के यूएनएड्स रिपोर्ट के अनुसार, 2017 के अंत में, भारत ने अपनी एचआईवी प्रसार दर को 0.3% से घटाकर 0.2% कर दिया है, जो कि भारत की श्रेणी में 1 स्थान यानी 59 वीं श्रेणी में वृद्धि करेगा, अगर हम यह मान लें कि अन्य देशों के एचआईवी संक्रमण दर में कोई बदलाव नहीं होगा।

तालिका 3.11: भारत की एचआईवी की प्रसार दर और नए संक्रमण की मामलें

वर्ष	2016	2017
एचआईवी प्रसार दर	0.3	0.2
नए संक्रमण की मामलें	80000	88000

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय सामरिक योजना:** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) ने एचआईवी / एड्स और यौन संचारित संक्रमणों पर सात वर्षीय राष्ट्रीय सामरिक योजना का प्रस्ताव किया है, (2017-2024) जो दो अलग-अलग चरणों में विभाजित है, जिसे नीचे समझाया गया है: -
  - **चरण 1-** 2020 तक एचआईवी के 75% नए मामलों को कम करें और 90-90-90 योजना को लागू करें अर्थात 90% एचआईवी पीड़ित लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें एचआईवी है, 90% लोग जानते हैं कि उन्हें एचआईवी का इलाज किया जाना चाहिए और 90% उपचार पर उन लोगों को प्रभावी वायरल लोड दमन को अनुभव करना चाहिए।
  - **चरण 2- -** 2024 तक, आगे की उपलब्धियों की योजना 80% नए एचआईवी संक्रमणों को कम करने और 90-90-90 की योजना को 95-95-95 तक बढ़ाने की है। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो भारत की एचआईवी व्यापकता दर 2024 तक 0.2 % से घटकर 0.1% हो जाएगी, जिससे भारत की स्थिति पहले स्थान पर आ जाएगी।

एचआईवी / एड्स का मुकाबला करने के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के अलावा, कुछ सुझाव हैं जिन्हें राष्ट्रीय योजना के साथ अपनाया जा सकता है:

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफ़डब्ल्यू), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)

अल्पकालीन योजना

- **प्रवासियों को ट्रैक करना**
  - नेपाल 2015 में 58 वें स्थान से उछलकर 2017 में पहले स्थान पर पहुंच गया है। देश में एचआईवी / एड्स के प्रसार को खत्म करने के लिए नेपाल की प्रमुख रणनीतियों में से एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य / एड्स स्ट्रैटेजी 2011 - 2016 को लागू करना था और काम के लिए कहीं ओर जाने वाले प्रवासी लोग और विशेष रूप से भारत जाने वाले। नेपाल ने शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से पुरुषों (एमएसएम) के साथ यौन संबंध रखने वाले समलैंगिक पुरुषों और पुरुषों की कवरेज बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई हैं।
  - This इस रणनीति ने नेपाल के लिए काम किया, जिसने देश में अपनी एचआईवी प्रसार दर में 2011 में 0.4% से 2017 में 0.2% तक का सुधार देखा। नेपाल के नक्शेकदम पर चलते हुए, भारत विशेष रूप से पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों की मोबाइल और प्रवासी आबादी की भी कड़ी निगरानी रख सकता है जहाँ एचआईवी का प्रचलन अधिक है। इस तरह की रणनीति को लागू करने के लिए, **राज्य विभागों की मदद से एमएचएफ़डब्ल्यू को बांग्लादेश और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे उच्च प्रवास बिंदुओं पर शिविर लगाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए एमएचएफ़डब्ल्यू को संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय के साथ काम करने की भी आवश्यकता होगी ताकि इसेआसानी से लागू किया जा सकें।**

मध्यम अवधि की योजना

- **मोबाइल क्लीनिक के माध्यम से जागरूकता और परामर्श**

- **मेडागास्कर**[84] ने 2008 में एक आर्थिक और सामाजिक विकास रणनीति शुरू की जो पूरे देश में महिलाओं और पुरुषों को कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्प (कंडोम, गोलियां, आईयूडी) प्रदान करने के लिए सामुदायिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं दोनों के साथ काम करती है। उन्होंने एचआईवी मुद्दों पर उचित परामर्श प्रदान करके सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है।
- उन्होंने **"मोबाइल क्लीनिक"** की एक क्रांतिकारी पद्धति की शुरुआत की, जो देश के चारों ओर घूमते हुए, पहले से अगम्य क्षेत्रों में प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के ज्ञान को उजागर करता है। इस रणनीति ने 2015 में मेडागास्कर की श्रेणी को 87 वें स्थान से 2017 में 60 वें स्थान पर सुधार दिया है। इसलिए, इसी तरह की तर्ज पर, राज्य के स्वास्थ्य विभागों की मदद से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मोबाइल क्लीनिक स्थापित कर सकता है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों का पता लगाने के लिए मणिपुर जैसे उच्च एचआईवी प्रसार दर वाले राज्य को पायलट राज्य के रूप में चुना जा सकता है।

दीर्घकालिक योजना

- **आईईसी (सूचना, शिक्षा, संचार) रणनीतियाँ**
  - जैसा कि तालिका 3.12 में देखा गया है, एचआईवी की व्यापकता की दर उन राज्यों में अधिक है जहां साक्षरता का स्तर अच्छा नहीं है जैसे की मणिपुर, नागालैंड आदि, जबकि ऐसे राज्य जहां साक्षरता का स्तर ऊँचा है जैसे की केरल, लक्षद्वीप आदि, वहाँ एचआईवी प्रसार की दर कम है।

तालिका 3.12[85]: राज्य वार एचआईवी प्रसार दर और साक्षरता दर

States	एचआईवी प्रसार दर (%)	साक्षरता दर (%)
मणिपुर	1.15%	79.85%
नागालैंड	0.80%	80.11%
अरुणाचल प्रदेश	0.66%	66.95%
तेलंगाना	0.66%	66.50%
कर्नाटक	0.45%	75.60%

[84] (Source: USAIDS Madagascar)
[85] https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/asia-pacific/india

केरल	0.13%	93.91%
लक्षद्वीप	<0.04%	92.28%
त्रिपुरा	0.06%	87.75%

- एचआईवी प्रसार दर और साक्षरता दर के बीच के सह - संबंध से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उन राज्यों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जहां साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इसलिए, एमएचएफडब्ल्यू एड्स जागरूकता पर राज्य के विशिष्ट आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) रणनीति जैसे नुक्कड़ नाटक को विकसित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ रणनीति बना सकता है। **स्थानीय ब्रांड एंबेसडर जो अपने राज्यों में लोकप्रिय हैं, उन्हें भी अभियान के लिए लिया जा सकता हैं और क्षेत्र विशेष के विज्ञापन अभियानों की भी योजना बनाई जा सकती है।**

संकेतक 3.06: मलेरिया मलेरिया के मामलें

परिभाषा: यह संकेतक प्रति 100,000 जनसंख्या पर अर्थव्यवस्था में मलेरिया के नए मामलों की अनुमानित संख्या को संदर्भित करता है

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मलेरिया रिपोर्ट

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{मलेरिया मामलों की संख्या} \times 100000}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

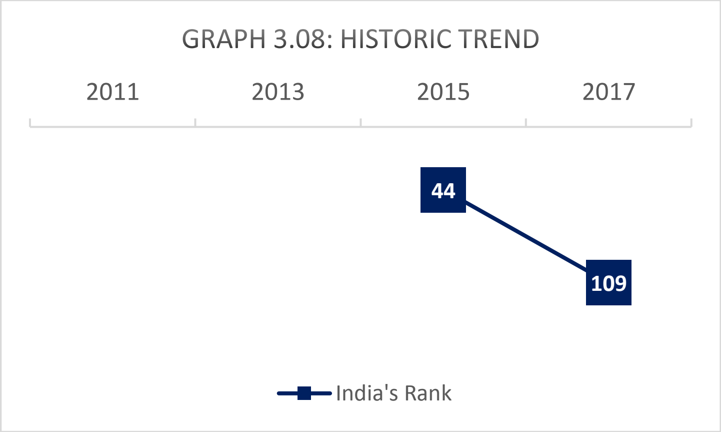

ग्राफ 3.08 संकेतक 3.06 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 65 पदों की कमी आई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 1% का योगदान देता है।

तालिका 3.13: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
अज़रबैजान	8	0.04	1	0	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
श्रीलंका	14	0.38	1	0	एशियाई साथी
बांग्लादेश	41	394	106	810	एशियाई साथी
पाकिस्तान	47	1953	108	440	एशियाई साथी
भारत	**44**	**1536**	**109**	**1312**	

इस संकेतक में 74 देशों की पहली श्रेणी है क्योंकि उन सभी को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है

इस संकेतक में 2015 और 2017 के मूल्य के अनुसार भारत के प्रदर्शन में वृद्धि के बावजूद, इस श्रेणी में 65 स्थानों की कमी, 75 (2015 में) से लेकर 136 (2015 में) तक इससंकेतक इस श्रेणी के देशों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है।

सरकारी पहल

राष्ट्रीय सामरिक योजना: मलेरिया उन्मूलन के लिए 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन (एनएफएमई) का राष्ट्रीय ढांचा शुरू किया गया है और इसके तहत एक दृष्टि के साथ मलेरिया उन्मूलन (2017-2022) के लिए 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करते हुए सार्वभौमिक हस्तक्षेप पैकेज प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) विकसित की गई है।
मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के अलावा, कुछ सुझाव हैं जिन्हें राष्ट्रीय योजना के साथ अपनाया जा सकता है:

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **मच्छर मछली (अज़रबैजान)[86] का उपयोग**
  - One मच्छर नियंत्रण में सबसे सुरक्षित और दिलचस्प तरीकों में से एक जैविक एजेंटों का उपयोग है जो लार्वा को खाते हैं या नष्ट करते हैं। मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए इको-फ्रेंडली लार्विसोलस मछली जैसे कि शीर्ष जल मिन्कोव या मच्छर मछली (गंबुसिया एफिनिस) या आम गप्पी (पोसीलिया रेटिकुलेट) का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। इन मछलियों को कुओं, टैंकों, तालाबों और झीलों जैसे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में मीठे पानी वाले निकायों में पानी के संग्रह में पेश किया जा सकता है। **एनवीबीडीसीपी को सफाई और स्वच्छता गतिविधियों में शामिल विभिन्न हितधारकों (यूएलबी,**

[86] http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/vector-borne-and-parasitic-diseases/malaria/country-work/azerbaijan

ग्राम पंचायत, आदि) को मच्छर मछली वितरित करने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के साथ काम करने की आवश्यकता है जो देश में मलेरिया के मामलों की संख्या को कम करने में मदद करेगा।

मध्यम अवधि की योजना

- **संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग (श्रीलंका)**[87]

  2011 में, श्रीलंका ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें मलेरिया के प्रत्येक मामले को मलेरिया नियंत्रण मुख्यालय को सूचित किया गया था। परिषद तब परिवार के सदस्यों और उन लोगों का परीक्षण और स्क्रीन करती है जो संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में थे। हर उस व्यक्ति की स्क्रीनिंग करके, जो संभवतः वायरस की चपेट में आ गया था, अधिकारियों ने शुरू होने से पहले इस प्रकोप को रोक दिया था। 2015 में, श्रीलंका की श्रेणी 14 वें स्थान पर थी, जो कि 2017 में बेहतर हो गई है। एनवीबीडीसीपी की राष्ट्रीय सामरिक योजना में, एक निगरानी प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की स्क्रीन करने की कोई भी प्रक्रिया अनुपस्थित है, जो की जरुरी है क्योंकि यह सभी संभावित खतरों को खत्म करने का एक तरीका है । **इसलिए, एनवीबीडीसीपी इसके प्रभावी उपयोग के लिए श्रीलंका के समान अपनी वर्तमान निगरानी प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग शामिल कर सकता है।**

दीर्घकालिक योजना

- **आईईसी गतिविधियों में जनजातीय कार्य मंत्रालय का समावेश**
  - 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनजातीय जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% है। मध्यप्रदेश और ओडिशा में सबसे बड़ी आदिवासी आबादी[88] है क्रमशः 14.7% और 9.2% है। देश के मलेरिया के कुल मामलों[89] में मध्य प्रदेश का हिस्सा 30% ओडिशा का 25% और छत्तीसगढ़ 13% पर और पश्चिम बंगाल 11% पर है, जैसा कि तालिका 3.14 में दिखाया गया है।

तालिका 3.14: राज्य वार मलेरिया के मामलें (% में)

---

[87] World Health Organization: Malaria Free Sri Lanka
[88] Ministry of Tribal Affairs Statistical Division
[89] National Vector Borne Disease Control Programme Statistical Division

राज्य	आदिवासी जनसंख्या (%)	मलेरिया के मामलें (%)
मध्य प्रदेश	14.7%	30%
ओडिशा	9.2%	25%
छत्तीसगढ़	7.5%	13%
पश्चिम बंगाल	5.1%	11%

- हम उपरोक्त तालिका से अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में आदिवासी आबादी मलेरिया की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित है। इसलिए, आदिवासी आबादी पर प्रमुखता से ध्यान देने की आवश्यकता है। **इसलिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को जनजातीय कार्य मंत्रालय, क्षेत्र विशेष के गैर-सरकारी संगठनों या समुदाय-आधारित संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करके बीमारी के बारे में और अधिक जागरूक बनाने के उद्देश्य से दूरस्थ ओर संघर्षरत क्षेत्रों पर पहुंच कर, आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) अभियानों के माध्यम से इस पर अंकुश लगाता है और इस बीमारी के रोकथाम के लिए इन्हें उचित आवश्यक दवा की आपूर्ति करता है।**

<u>स्तंभ 4: स्तंभ 4: मानव संसाधन और श्रम बाजार</u>

परिभाषा: यह स्तंभ गुणवत्ता मानव की उपलब्धता और मानव संसाधन को उनके सबसे कुशल उपयोग में कैसे कुशलता से आवंटित किया जाता है इसे मापता है। स्तंभ 4 में कुल 9 संकेतक हैं जिन्हें नीचे बताया गया है-

1. प्राथमिक शिक्षा नामांकन दर
2. माध्यमिक शिक्षा नामांकन दर
3. स्टाफ प्रशिक्षण की अधिकता
4. ग्राहकों का उपचार
5. भर्ती करने और निकालने की प्रथा
6. कुशल कर्मचारियों को खोजने में आसानी
7. विदेशी श्रम बल को भर्ती करने में आसानी
8. वेतन और उत्पादकता
9. महिला श्रम बल की भागीदारी

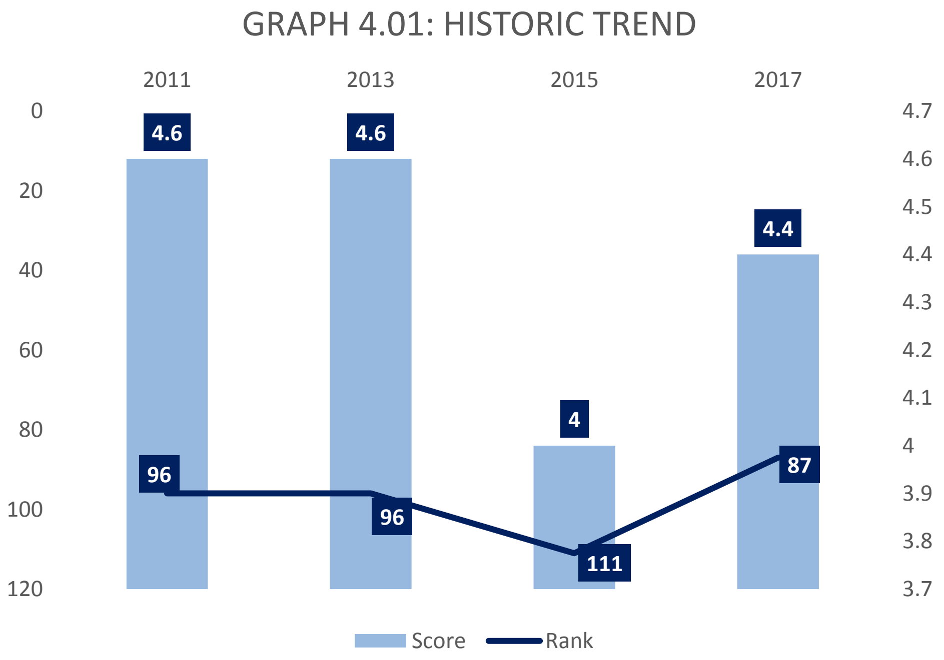

ग्राफ 4.01 भारत की श्रेणी और स्तंभ में मूल्य की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को इंगित करता है। भारत की श्रेणी 2015 में 111 वें स्थान से बढ़कर 2017 में 87 वें स्थान पर पहुंच गई है।

GRAPH 4.02: WEIGHTAGE SHIFT

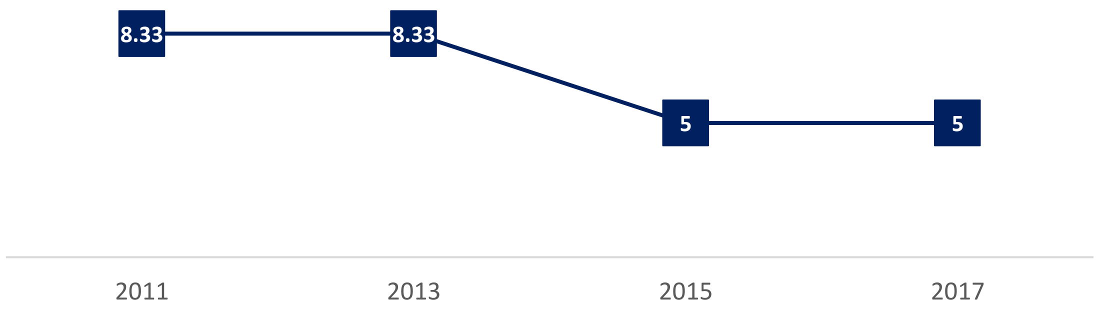

भार की स्थिति में बदलाव:

ग्राफ़ 4.02 भारत के स्कोर में स्तंभ 4 यानी मानव संसाधन और श्रम बाजार के समग्र योगदान को इंगित करता है। वर्तमान में, इस स्तंभ को 5% भार दिया जाता है। वर्ष 2015 में इस स्तंभ का भार 40% तक कम हो गया है।

तालिका 4.01: भार की स्थिति में संकेतक वार बदलाव

संकेतक	2011 (%)	2013 (%)	2015 (%)	2017 (%)	भार की स्थिति में बदलाव (%)
प्राथमिक शिक्षा नामांकन दर	0.83	0.83	0.625	0.625	-24.70
माध्यमिक शिक्षा नामांकन दर	0.83	0.83	0.625	0.625	-24.70
स्टाफ प्रशिक्षण की अधिकता	0.83	0.83	0.625	0.625	-24.70
ग्राहकों का उपचार	NA	2.08	0.625	0.625	-69.95
भर्ती करने और निकालने की प्रथा	0.83	0.83	0.5	0.5	-39.76
कुशल कर्मचारियों को खोजने में आसानी	NA	NA	0.5	0.5	NA
विदेशी श्रम बल को भर्ती करने में आसानी	0.83	0.83	0.5	0.5	-39.76
वेतन और उत्पादकता	NA	NA	0.5	0.5	NA
महिला श्रम बल की भागीदारी	NA	NA	0.5	0.5	NA

NA = लागू नहीं, उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

टीटीसीआई रिपोर्ट 2013 में, ग्राहकों के उपचार के नाम से 1 नया संकेतक पेश किया गया था। टीटीसीआई रिपोर्ट 2015 में, कुशल कर्मचारियों को खोजने में आसानी, वेतन और उत्पादकता और महिला श्रम बल की भागीदारी जैसे 3 नए संकेतक पेश किए गए थे।.

तालिका 4.01 उस योगदान का प्रतिशत दर्शाती है जो प्रत्येक संकेतक का भारत के समग्र स्कोर पर है।

ध्यान दें - संकेतक 4.01 और 4.02 को एकल संकेतक के रूप में दिखाया जा रहा है क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं और समान मानदंडों का पालन करते हैं।

संकेतक 4.01: प्राथमिक शिक्षा नामांकन दर

परिभाषा: यह संकेतक कुल प्राथमिक शिक्षा नामांकन दर को संदर्भित करता है। रिपोर्ट किया गया मूल्य आधिकारिक स्कूल आयु के बच्चों (राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली द्वारा परिभाषित) के अनुपात से मेल खाता है, जो स्कूल में इसी आधिकारिक स्कूल की उम्र के लोगों के लिए नामांकित हैं।

स्रोत: यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टेटिस्टिक्स, डाटा सेंटर, आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन, शिक्षा एक नज़र में, यूनिसेफ।

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{प्राथमिक शिक्षा में दाखिल की हुई कुल जनसंख्या (आयु } 6-11) \text{ x } 100)}{\text{समान आयु वर्ग में कुल जनसंख्या (आयु } 6-11 \text{ वर्ष)}}$$

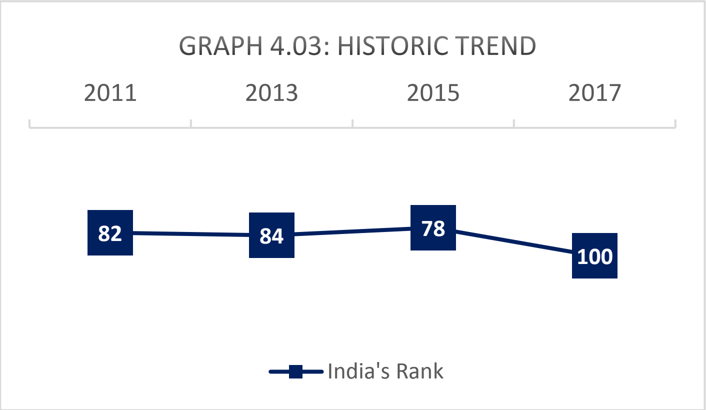

ग्राफ 4.03 सूचक 4.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 22 पदों की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.62% का योगदान देता है।

तालिका 4.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
चीन	4	99.9	1	100	एशियाई साथी
सिंगापुर	1	100	1	100	एशियाई साथी
जापान	3	99.91	3	99.95	एशियाई साथी
भारत	**78**	**93.34**	**100**	**90.04**	

संकेतक 4.02: माध्यमिक शिक्षा नामांकन दर.

परिभाषा: यह संकेतक सकल माध्यमिक शिक्षा नामांकन दर को संदर्भित करता है। रिपोर्ट किया गया मूल्य आयु वर्ग (11-17 वर्ष) से कुल माध्यमिक नामांकन के अनुपात से मेल खाता है, जो आयु वर्ग की आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर माध्यमिक शिक्षा स्तर से मेल खाता है।

स्रोत: यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टेटिस्टिक्स, डाटा सेंटर, आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन, शिक्षा एक नज़र में, यूनिसेफ, एनसीईआरटी।

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{माध्यमिक शिक्षा में नामांकित कुल जनसंख्या (आयु } 11-17 \text{ वर्ष)} \times 100}{\text{समान आयु वर्ग में कुल जनसंख्या (आयु } 11-17 \text{ वर्ष)}}$$

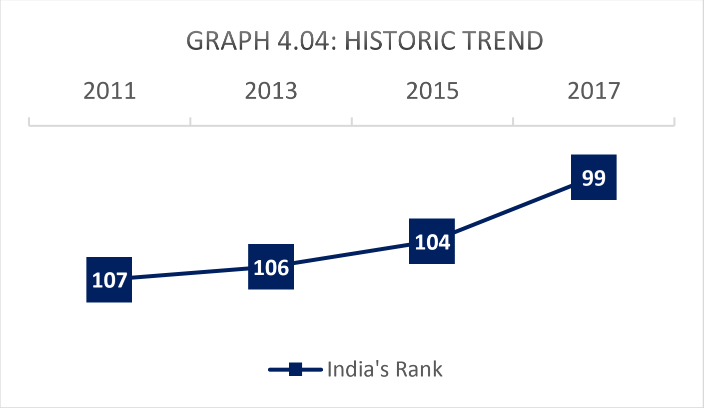

ग्राफ 4.04 संकेतक 4.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2017 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 5 स्थानों की वृद्धि हुई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.62% का योगदान देता है।

तालिका 4.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)*	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
बेल्जियम	15	107.26	1	164.81	शीर्ष प्रदर्शक
फिनलैंड	14	107.67	2	149.46	शीर्ष प्रदर्शक
ऑस्ट्रेलिया	1	135.53	3	137.56	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**104**	**68.5**	**99**	**74.28**	

* तालिका 4.03 में अधिक उम्र के और कम उम्र के विद्यार्थियों / छात्रों को जल्दी या देर से प्रवेश करने, और ग्रेड पुनरावृत्ति को शामिल किये जाने के कारण मूल्य 100 वर्ष से ऊपर हो सकता है।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नामांकन के लिए सरकारी पहल

- **प्राथमिक शिक्षा नामांकन**
  - भारत सरकार ने छात्रों की आधार आईडी का उपयोग करके ड्रॉप-आउट दरों पर नज़र रखने की एक नई प्रणाली शुरू की है, ताकि उन्हें स्कूल वापस लाने के लिए शुरुआती हस्तक्षेप किया जा सके। आईडी-आधारित ट्रैकिंग प्रणाली के पीछे का विचार देश के 15 लाख स्कूलों में कक्षा I-XII में नामांकित प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत डाटा को लॉग इन करना है ताकि नीति निर्माता किसी विशेष स्कूल से बाहर निकलने वाले विशिष्ट छात्र को इंगित कर सकें। यूनिक आईडी नंबर (आधार) को हर साल ट्रैक किया जाएगा। यदि कोई छात्र किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित हो गया है, तो उसका आईडी नंबर उसी को दर्शाएगा। यदि वह बाहर हो गया है, तो आईडी नंबर उस स्कूल के ड्रॉपआउट बॉक्स में दिखाया जाना चाहिए।डाटा को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए) द्वारा शिक्षा के लिए एकीकृत-जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई)[90] नामक योजना के तहत बनाए रखा जाएगा।

- **माध्यमिक शिक्षा नामांकन**
  - उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) ने 2015-16 में 24.5% से 2016-17 में 25.2% की वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए 2020 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
  - "द मॉडल स्कूल स्कीम" को अपनाना जिसका उद्देश्य प्रतिभावान ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जो कि 6,000 मॉडल स्कूलों को प्रति ब्लॉक एक स्कूल की दर से उत्कृष्टता के मानक के रूप में स्थापित करता है।
  - फरवरी 2017 में, एचआरडी मंत्रालय ने राज्य सरकार[91] की मदद से तेलंगाना में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन का एक पैनल बनाया है।

प्रस्तावित कार्य योजना

[90]https://www.telegraphindia.com/india/dropout-pill-aadhaar-tabs-on-all-students/cid/1513969
[91]https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-02/need-faster-growth-spend-more-on-educating-india-s-children

मंत्रालय: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) अल्पकालीन योजना

- **दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल**[92] **का अनुकरण करना**

स्कूलों में सुविधा	दिल्ली (%)	समस्त भारत(%)
कंप्यूटर जो काम करने की स्थिति में है	67.53	14.11
खेल के मैदान की सुविधा	87.42	61.98
पुस्तकालय की सुविधा	97.92	82.96
बिजली कनेक्शन	99.91	60.81

  - भारत में लगभग आधे स्कूलों में यू-डीआईएसई (शिक्षा के लिए एकीकृत-जिला सूचना प्रणाली) के अनुसार उचित धोने की सुविधाएं (कार्यात्मक शौचालय, पेयजल और हाथ धोने की सुविधा) नहीं है। खराब आधारिक संरचना जैसे लीक करते टॉयलेट, बदबूदार कैफेटेरिया, टूटा हुआ फर्नीचर, कक्षाओं में अत्यधिक तापमान, फफूंदीयुक्त दीवारें और छत से गिरने वाले प्लास्टर छात्रों को निरुत्साहित और निराशाजनक बना देते हैं जिससे स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि होती है।
  - विद्यालय के वातावरण की यह नकारात्मक धारणा उच्च अनुपस्थिति, कम परीक्षा स्कोर और खराब शैक्षणिक उपलब्धि में योगदान करती है।
  - 2016-17 में आधारिक संरचना की समस्या को दूर करने के लिए, राज्य के बजटों के आरबीआई अध्ययन के अनुसार, दिल्ली सरकार ने अपने कुल बजट का 22.8%, शिक्षा को आवंटित किया है, जो भारत में किसी भी राज्य के लिए उच्चतम और 15.6% के समस्त भारतीय औसत से ऊपर है। दिल्ली सरकार ने स्कूल आधारिक संरचना में सुधार लाने, पाठ्यक्रम को बदलने और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में बजट का उपयोग किया है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारहवीं कक्षा के छात्रों ने 90.68 उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज करके अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, और 20 वर्षों में पहली बार सरकारी स्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 90% के मानदंड को पार कर गया है।

[92]https://medium.com/@SaaksharOrganisation/primary-education-in-india-progress-and-challenges-c318b5c41d9e

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को छात्रों के स्कुल छोड़ने की उच्च दर से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल शिक्षकों की मदद से नियमित अंतराल पर शिक्षा के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इसके अलावा एमएचआरडी द्वारा इस
- मॉडल की अन्य राज्यों को भी सिफारिश की जानी चाहिए क्योंकि सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नामांकन दर में वृद्धि के लिए उन छात्रों को भी आकर्षित करेगा जो पहले स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक थे।

मध्यम अवधि की योजना

- **प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में शिक्षकों की कमी**

तालिका 4.04- स्कूल छोड़ने की उच्चतम दर वाले राज्य (प्राथमिक स्तर)

राज्य	स्कूल छोड़ने की दर
नागालैंड	31.51%
मणिपुर	31.30%
अरुणाचल प्रदेश	27.91%
मिजोरम	21.43%
मिजोरम	18.71%
गोवा	15.66%

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जहां ड्रॉप आउट बहुत अधिक हैं, जैसा कि तालिका[93] 4.04 में सूचीबद्ध है। एएसईआर (वार्षिक राज्यों की शिक्षा रिपोर्ट) 2016 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि 11 से 14 वर्ष की आयु के 1.1% बच्चों ने कभी स्कूलों में दाखिला नहीं लिया था और 3.5% ड्रॉपआउट[94] थे। इसका कारण है:
  - गरीबी, पलायन, बाल विवाह, पीने के पानी और स्वच्छता जैसी स्कूल आधारिक संरचना की कमी, बाल श्रम और माता-पिता की ओर से बच्चों को स्कूल भेजने के लाभों पर जागरूकता की कमी।

[93] U-DISE: Flash Statistics on School Education 2016-17
[94]https://www.firstpost.com/india/indias-great-education-challenge-low-attendance-high-rate-of-dropouts-plague-rural-schools-3378802.html

- **मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को छात्रों के उच्च ड्रॉपआउट दर से निपटने के लिए** ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल शिक्षकों की मदद से नियमित अंतराल पर शिक्षा के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

दीर्घकालिक योजना

- **प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में शिक्षकों की कमी**
  - हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमएचआरडी द्वारा लोकसभा में डाटा तालिका के अनुसार, भारत में सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 18% पद और 15% पद माध्यमिक विद्यालय खाली हैं। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 9,00,000 शिक्षण रिक्तियां है और माध्यमिक विद्यालयों में 100,000 - कुल मिलाकर एक लाख पद रिक्त हैं। देश के एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या में भी भारी कमी का पता चलता है जो कुल प्राथमिक विद्यालयों[95] का 11 प्रतिशत है। प्यूपिल शिक्षक अनुपात (पीटीआर) प्राथमिक स्कूलों में 30: 1 होना चाहिए, हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश में, पीटीआर अनुपात 60 से ऊपर है, जो आवश्यक मानकों[96] से बहुत दूर है।
  - **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** को शिक्षकों की नियमित भर्ती पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण स्कूलों को आवंटित शिक्षक हमेशा शहरी पोस्टिंग की तलाश में रहते हैं और वहां रहने के लिए उनके पास कोई प्रेरणा नहीं होती है। राज्य सरकार और एमएचआरडी को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन आधारित योजना विकसित करनी चाहिए।

[95] http://www.idreameducation.org/blog/lack-teachers-govt-schools-impacting-students-learning-outcomes/
[96] https://www.tribuneindia.com/news/nation/india-improves-student-classroom-pupil-teacher-ratios-survey/535524.html

ध्यान दें -संकेतक 4.03 और 4.06 को एकल संकेतक के रूप में दिखाया जा रहा है क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं और समान मानदंडों का पालन करते हैं।

संकेतक 4.03: स्टाफ प्रशिक्षण की अधिकता

परिभाषा: "आपके देश में, कंपनियां प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास में किस हद तक निवेश करती हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

देश का मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = बिल्कुल नहीं, 7 = काफी हद तक)

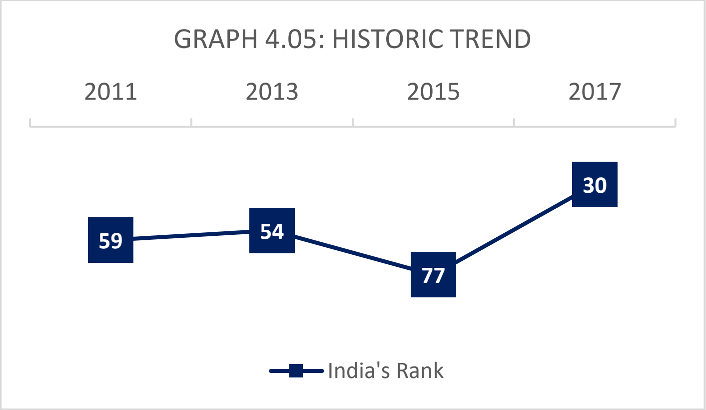

ग्राफ 4.05 संकेतक 4.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 47 पदों की वृद्धि हुई है। यह सूचक देश के स्कोर में 0.62% का योगदान देता है।

तालिका 4.05: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
स्विट्जरलैंड	1	5.68	1	5.71	शीर्ष प्रदर्शक
नॉर्वे	8	5.16	2	5.54	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	7	5.25	3	5.51	एशियाई साथी
भारत	**77**	**3.94**	**30**	**4.59**	

संकेतक 4.06: कुशल कर्मचारियों को खोजने में आसानी Employees

परिभाषा: "आपके देश में, कंपनियां अपने रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कौशल वाले लोगों को किस हद तक ढूंढ पाती हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = बिल्कुल नहीं, 7 = काफी हद तक)

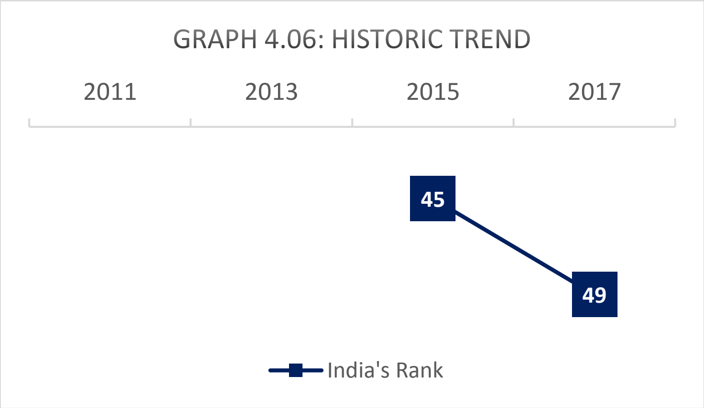

ग्राफ 4.06 संकेतक 4.06 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में भारत की श्रेणी में 4 स्थानों की कमी आई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.5% का योगदान देता है

तालिका 4.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
नॉर्वे	21	4.77	1	5.76	शीर्ष प्रदर्शक
फिनलैंड	1	5.61	2	5.72	शीर्ष प्रदर्शक
आइसलैंड	13	4.93	3	5.53	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	22	4.76	19	5.09	एशियाई साथी
भारत	**45**	**4.26**	**49**	**4.52**	

सरकारी पहल[97]

- कौशल विकास और उद्‌यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने कौशल भारत (2015) की स्थापना के बाद से कई लघु और दीर्घकालिक कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न कौशल में 1.17 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत 20 लाख से अधिक नागरिकों को प्रशिक्षित किया गया है। लगभग 356 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) 24 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए गए हैं और ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए 124 अतिरिक्त स्थलों पर काम चल रहा है।

[97]http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=164440

- **स्किल इंडिया मिशन ऑपरेशन (एसआईएमओ) परियोजना**[98]
    - देश के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, विश्व बैंक ने स्किल इंडिया मिशन ऑपरेशन (एसआईएमओ) को यूएस $ 250 मिलियन की सहायता प्रदान की है, जिससे भारत के बढ़ते युवा कार्यबल को बाज़ार के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी जॉब मार्केट में आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह अभियान भारत सरकार के स्किल इंडिया पहल का समर्थन करेगा और प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार के लिए अग्रणी गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने की दोहरी चुनौती को संबोधित करने का प्रयास करेगा।
    - यह अनुमान है कि 2023 तक, जब यह परियोजना समाप्त हो जाएगी, तो लगभग 8.8 मिलियन युवाओं को कुछ बाजार-प्रासंगिक प्रशिक्षण प्राप्त होंगे जो बदले में हर समय बदलते रोजगार के बाजार में उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर खोलेंगे।
    - भारत सरकार के पास भारत को महत्वाकांक्षी, उच्च-विकास और उच्च उत्पादकता वाले देश में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना है। 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, 2022[99] तक देश भर में लगभग 300 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखता है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं, सीमांत समुदायों, आदिवासियों और विकलांग लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा ताकि उन्हें भविष्य के श्रम बाजार[100] में आवश्यक कौशल हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

मध्यम अवधि की योजना

मैनपावर ग्रुप द्वारा 2018 प्रतिभा की कमी के सर्वेक्षण के अनुसार, 56% नियोक्ताओं को आवश्यक कौशल वाले श्रमिकों को खोजने में कठिनाई होती है। यह पाया गया कि 26% आवेदक में कठिन कौशल, 25% में अनुभव की कमी है और 15% को पेश किये गए वेतन से उच्च वेतन की उम्मीद है। जिन मुख्य भूमिकाओं में कौशल की कमी देखी गई है, वे हैं:

---

[98]http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/06/23/skilling-india
[99] https://www.msde.gov.in/assets/images/Mission%20booklet.pdf
[100] http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/06/23/skilling-india

नियोक्ताओं द्वारा खोजी जाने वाले सबसे कठिन कौशल

बिक्री प्रतिनिधि (बी 2 बी, बी 2 सी, संपर्क केंद्र)

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, नेटवर्क प्रशासक

केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर

परियोजना प्रबंधक, वकील, शोधकर्ता

प्रमाणित लेखाकार, लेखा परीक्षक, वित्तीय विश्लेषक

प्रबंधन / कार्यकारी

कुशल बिजली मिस्त्री, वेल्डर, मैकेनिक

- **4.06 के साथ संकेतक 4.03 पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की अवधारणा का परिचय**
  - इस अवधारणा की योजना कौशल क्षेत्र को बाजार की माँगों से जोड़ने की है। संपूर्ण कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को कंपनियों की व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर कौशल भारत के तहत प्रशिक्षण हितधारकों में परिवर्तित करके उद्योगों की मांग के साथ जोड़ा जा सकता है और अंत में उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सकता है।
  - यह कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कंपनियों के निवेश को बढ़ाने के साथ-साथ, सेक्टर या उद्योगों की उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ बाजार आधारित कौशल प्रशिक्षण की सुविधा देगा। सरकार एक सुविधा देने वाले के रूप में या उसी के लिए कार्य कर सकती है और कंपनियां अभिभावक कौशल प्रदाता बन जाएंगी और विस्थापित संस्थानों की जगह ले लेंगी।
  - **ध्यान दें -** राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के एक भाग के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोजगार के तहत कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम के माध्यम से एक समान अभ्यास प्रदान किया जा रहा है।

दीर्घकालिक योजना

- **मांग-आपूर्ति अंतराल विश्लेषण के साथ संशोधित कौशल अंतर विश्लेषण:**
  - पिछला कौशल अंतर विश्लेषण 2011 में आयोजित किया गया था और तब से संशोधित नहीं किया गया है। डिजिटलकरण और अवधारणाओं की ओर बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में, जहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर में आती है, अर्थव्यवस्था की बदलती मांगों के आधार पर कौशल बाजार का विश्लेषण करने की अत्यधिक आवश्यकता है।
  - संशोधित कौशल अंतर विश्लेषण को एक मांग और आपूर्ति अंतर विश्लेषण के साथ किया जाना चाहिए ताकि बाज़ार की जरूरतों को सतत रूप से शामिल किया जा सके।
  - **ध्यान दें -** यह एक अध्ययन के माध्यम से देखा गया था कि वर्तमान में विशेषज्ञों की कमी है जो भारत में जीआईएस मैपिंग प्रदान कर सकते हैं। आरएपीडीआरपी योजना के तहत, विद्युत मंत्रालय ने जीआईएस के माध्यम से देश के पूरे विद्युत नेटवर्क का मानचित्रण करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी के कारण अभी तक इसे हासिल नहीं किया गया है। यह उदाहरण उपर्युक्त बिंदु को दोहराता है।

संकेतक 4.04: ग्राहकों का उपचार

परिभाषा: "आपके देश में, कंपनियां ग्राहकों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण.

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = ग्राहकों की संतुष्टि के प्रति उदासीन, 7 = ग्राहकों के लिए अत्यधिक उत्तरदायी और ग्राहक प्रतिधारण देखती है)

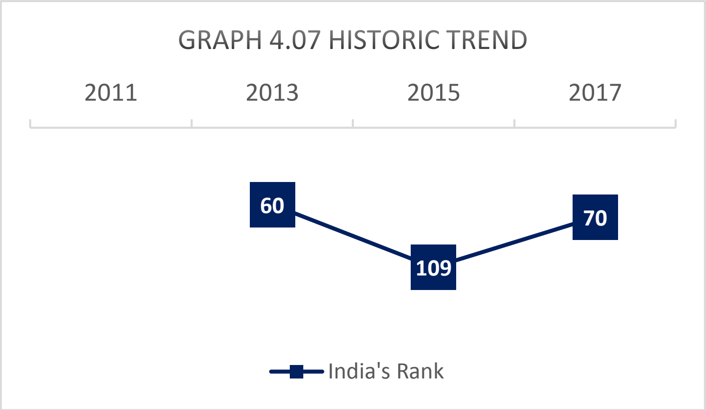

ग्राफ 4.07 संकेतक 4.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2013 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 39 पदों की वृद्धि हुई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.62% का योगदान देता है।

तालिका 4.07 - देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
जापान	1	6.26	1	6.23	एशियाई साथी
स्वीडन	18	5.37	2	6	शीर्ष प्रदर्शक
स्विट्जरलैंड	2	6.02	3	5.95	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**109**	**4.04**	**70**	**4.6**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और प्रकाशन मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य विभाग

अल्पकालीन योजना

- **लंबमानता दर[101] को कम करना**
    - उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए मामलों की लंबमानता एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 13.74% मामले राष्ट्रीय आयोग में, 14.32% मामले राज्य आयोगों में और 7.56% मामले जिला उपभोक्ता फ़ोरम में लंबित हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिला उपभोक्ता फ़ोरम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक हैं जबकि राज्य आयोग सबसे खराब प्रदर्शक हैं।
    - लंबमानता दर को कम करने के लिए, नए सर्किट बेंच स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में देश में केवल 7 सर्किट बेंच काम कर रही हैं। सर्किट बेंचों के अलावा, मध्यस्थता का उपयोग उपभोक्ता विवादों के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि यह हाल ही में विभिन्न प्रकार के विवादों में एक प्रभावी निवारण उपकरण बन गया है।
    - **उपभोक्ता कार्य विभाग और राज्य सरकारों को हमारे देश में ग्राहक सेवा प्रावधान में वर्तमान** खामियों का विश्लेषण करने के लिए जो नीतिगत बदलावों को लागू करने में बेहद फायदेमंद है उनके लिए उन उपभोक्ताओं से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए जो धोखाधड़ी या अनुचित सेवा प्राप्त कर करने के शिकार हो चुके है।

दीर्घकालिक योजना

- **अचल संपत्ति क्षेत्रों[102] में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार की पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना:**

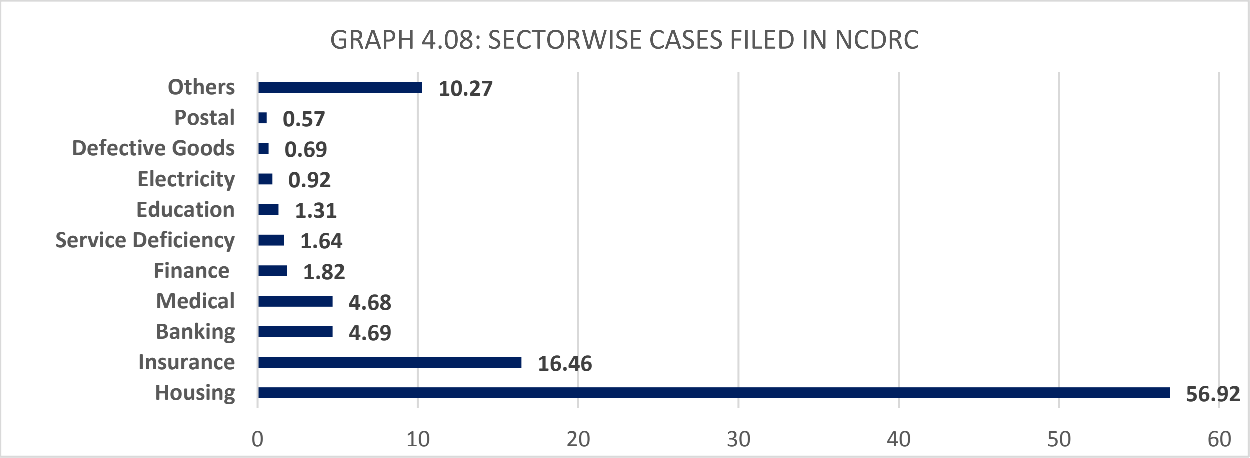

[101] ISOR JBM: Performance Evaluation of Consumer Disputes Redressal Agencies in India
[102] http://cms.nic.in/ncdrcusersWeb/dashboard.do?method=loadDashBoardPub

- कन्फॉनेट डैशबोर्ड के अनुसार, हाउसिंग सेक्टर के तहत सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में 56.92%। अधिकांश मामलें घरों पर कब्जे में देरी से संबंधित थे, जबकि कुछ मामलों में देरी लगभग छह साल या उससे अधिक होने पर भी कब्जे की कोई गुंजाईश नज़र नहीं आ रही थी।
- 2016 में, भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर अनियमित अचल संपत्ति क्षेत्र को विनियमित करने के लिए रेरा या रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम पारित किया है। इसका उद्देश्य नियमित कानूनी ढांचे के अलावा एक निवारण तंत्र प्रदान करना है।
- भले ही, अधिनियम 2 वर्ष पहले लागू किया गया था, यह अभी भी अपने प्रारंभिक अवस्था में ही है। प्रवर्तन निदेशालय स्थिति अभी भी 8 राज्यों में पिछड़ रही है जैसा कि तालिका[103] 4.08 में वर्णित है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूऐ) को संबंधित राज्यों से प्रगति रिपोर्ट मांगनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि रेरा को जल्द से जल्द पूरे देश में लागू किया जाए।
- **राज्य सरकारें और एक हद तक एमओएचयूऐ भी यह सुनिश्चित कर सकती है कि नागरिकों को पत्र और भावना दोनों** में इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाए। इसलिए, एक मजबूत जागरूकता अभियान बनाने की जरूरत है ताकि रेरा का लाभ लक्षित **दर्शकों तक पहुंचे जिसके लिए एमओएचयूऐ को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ सहयोग किया जाना चाहिए।**

तालिका 4.08 भारत के विभिन्न राज्यों में रेरा की स्थिति

राज्य	स्थिति
पश्चिम बंगाल	ड्राफ्ट में है
सिक्किम	प्रगति में है
मणिपुर	प्रगति में है
मिजोरम	प्रगति में है
मिजोरम	प्रगति में है
नागालैंड	प्रगति में है

[103]https://getmeroof.com/blog/2018/02/a-guide-to-understanding-rera-and-its-impact-on-indian-real-estate/

गोवा	ड्राफ्ट में है
अरुणाचल प्रदेश	प्रगति में है

संकेतक 4.05: भर्ती करने और निकालने की प्रथा

परिभाषा: " आपके देश में, आप श्रमिकों को काम पर रखने और निकालने को को कैसे समझायेंगे?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = नियमों द्वारा पूरी तरह से लगाया गया, 7 = अत्यंत लचीला)

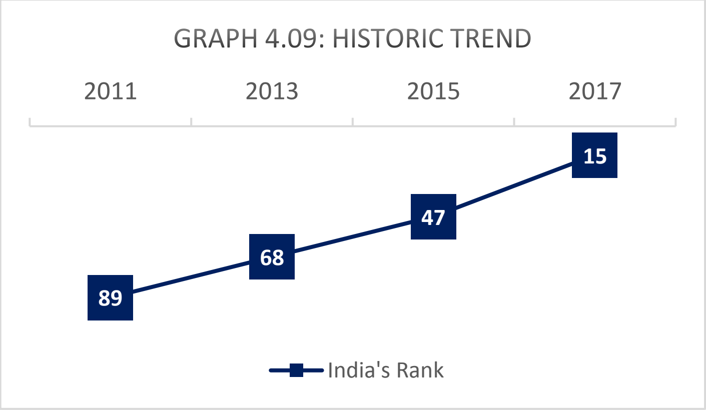

ग्राफ 4.09 संकेतक 4.05 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2017 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 32 पदों की वृद्धि हुई है। यह सूचक देश के स्कोर में 0.5% का योगदान देता है।

तालिका 4.09 देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
स्विट्जरलैंड	2	5.69	1	5.79	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
हांगकांग SAR	1	5.72	2	5.73	एशियाई साथी
सिंगापुर	3	5.4	3	5.56	एशियाई साथी
भारत	**47**	**4.13**	**15**	**4.75**	

सरकारी पहल

- वर्तमान सरकार ने सभी उद्योगों में निश्चित कार्यकाल या अनुबंध की नौकरियों को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम नियमों (2016 में पहले कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए पेश किए गए श्रम अनुबंध नियमों को विस्तारित) को संशोधित किया है, जो रोजगार सृजन की रणनीति में नौकरी की सुरक्षा से लेकर नौकरी सृजन तक को इंगित करता है।
- नए नियम कंपनियों को एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंधित श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देते हैं। नियमों के अनुसार, किसी भी समाप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही श्रमिकों को एक महीने, सप्ताह या किसी विशिष्ट परियोजना की अवधि के लिए अनुबंधित किया गया हो। इस कदम का उद्देश्य श्रम की नीतियों को उदार बनाने के उद्देश्य से हायर-एंड-फायर नीति की सुविधा देना है, जिसमें कंपनी की जरूरत के अनुसार सख्त छंटनी की स्थितियों को कम करना और देश के पुरातन श्रम कानूनों[104] से छुटकारा पाने में मदद करना है।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **भारत की उपलब्धियों के बारें में छापना**
  - दुनिया भर के 25 देशों के ग्लासडोर आर्थिक अनुसंधान अध्ययन के अनुसार, भारत में 16.1 दिन का सबसे कम समय का साक्षात्कार समय है, जो काम पर रखने और अभ्यास करने और लचीले श्रम बाजार नियमों में लचीलेपन के कारण हासिल किया गया है।
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित कार्यकारी राय सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण में लगे अधिकांश उत्तरदाता विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष व्यवसायिक अधिकारी हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) को उत्तरदाताओं को संवेदनशील बनाने के लिए अपनी उपलब्धि का विज्ञापन करना चाहिए। संवेदीकरण की प्रक्रिया में, एमओएलई भारत के उद्योग (सीआईआई) के परिसंघ के साथ सहयोग कर सकता है क्योंकि वे 2016 तक भारत में डब्ल्यूइऍफ़'के सर्वेक्षण के लिए भागीदार थे। इस अभ्यास से उत्तरदाताओं की धारणा बदल जाएगी और वे आगामी सर्वेक्षणों में भारत को उच्चतर आंकेंगे।

[104] https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/ease-of-doing-biz-cos-may-get-flexibility-to-hire-and-fire/articleshow/62657759.cms

तालिका 4.10: देश के द्वारा औसत भर्ती में लगने वाला समय

देश	साक्षात्कार प्रक्रिया की औसत लंबाई (दिन)
भारत	16.1
इज़राइल	16.9
रोमानिया	19.2
सिंगापुर	25.4
स्पेन	31.7
स्विट्जरलैंड	37.6

दीर्घकालिक योजना

- **फीडबैक तंत्र**
    - **श्रम और रोजगार मंत्रालय** को मुख्य आधार पर हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक फीडबैक लूप सिस्टम शुरू करना चाहिए जहां हितधारकों को समिति के सामने अपनी चिंताओं और विचारों को उठाने का मौका मिल सकता है। यह नीति निर्माताओं और उनके लाभार्थियों के बीच एक सीधा संबंध पैदा करेगा, ओर इससे हितधारक खुदको सिस्टम में अधिक शामिल महसूस करेंगे।

संकेतक 4.07: विदेशी श्रम बल को भर्ती करने में आसानी

परिभाषा: "आपके देश में विदेशी श्रम की भर्ती से संबंधित नियम कितने प्रतिबंधित हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = अत्यधिक प्रतिबंधित, 7 = बिलकुल प्रतिबंधित नहीं)

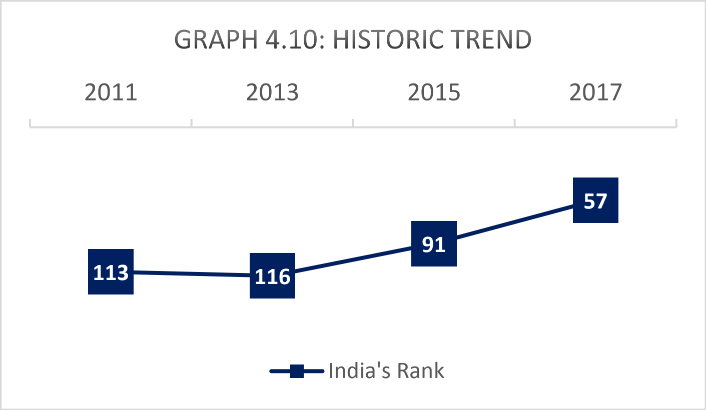

ग्राफ 4.10 संकेतक 4.07 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2017 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 34 स्थानों की वृद्धि हुई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.5% का योगदान देता है।

तालिका 4.11: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
अल्बानिया	6	5.26	1	5.64	शीर्ष प्रदर्शक
लक्समबर्ग	5	5.28	2	5.51	शीर्ष प्रदर्शक
संयुक्त अरब अमीरात	1	5.57	3	5.41	शीर्ष प्रदर्शक
चीन	20	4.58	39	4.35	एशियाई साथी
भारत	**91**	**3.82**	**57**	**4.15**	

सरकारी पहल

- **भारत में विदेशी श्रम के लिए विनियम और आवश्यकताएँ**
    - **रोजगार वीज़ा:**
        - एक विदेशी नागरिक आम तौर पर अपने निवास स्थान के भारतीय दूतावास / उच्चायोग में भारतीय रोजगार वीज़ा के लिए आवेदन करता है।
        - रोजगार वीज़ा विदेशी मूल के देश से जारी किया जाना चाहिए, या विदेशी राष्ट्रीय अधिवास के देश से, बशर्ते आवेदक की उस विशेष देश में स्थायी निवास की अवधि दो साल से अधिक हो।
        - यदि भारत में 180 दिनों से अधिक समय तक निवास रहेगा, तो रोजगार वीज़ा धारक को आगमन के 14 दिनों के भीतर विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (ऍफ़आरआरओ) या विदेशियों के पंजीकरण कार्यालयों (ऍफ़आरओ) के साथ पंजीकरण करना होगा। विदेशी नागरिक के पास एक वैध यात्रा दस्तावेज और एक पुन: प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए (यदि संबंधित देश के कानून के तहत आवश्यक हो)। एक रोजगार वीज़ा को अधिकतम पांच वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
        - विस्तार के लिए एक आवेदन अग्रिम में 30 से 90 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। रोजगार वीज़ा के लिए प्रायोजित होने वाले विदेशी नागरिक को 25,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष (कुछ क्षेत्रों में रोजगार को छोड़कर) से अधिक वेतन प्राप्त करना चाहिए।
        - न्यूनतम वेतन सीमा US $14,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास होगी, जो विदेशी नागरिकों के लिए लगभग (INR 0.91 मिलियन प्रति वर्ष) होगी, जो भारत के एन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयूएस), नेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे निर्दिष्ट प्रीमियर भारत के शिक्षण संस्थानों में शिक्षण संकाय के रूप में कार्यरत हैं। नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एनआईटी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर).
        - रोजगार वीज़ा या ई-वीज़ा एक वर्ष या भारत में अनुबंध की अवधि (5 वर्ष तक) के लिए दिया जाता है।
        - अमेरिकी नागरिक को 5 साल या 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है।
    - **लागत:** एक रोजगार वीज़ा का शुल्क US $ 15 और US $ 1,000 के बीच है और सरकार द्वारा आवधिक संशोधनों के अधीन है।
    - **समय सीमा:** एक सटीक समय सीमा देना मुश्किल है क्योंकि प्रक्रिया संबंधित देशों में भारत के दूतावास / उच्चायोग के विवेक पर है।

- **प्रतिबंध:** यदि वीज़ा नहीं दिया जाता है, तो प्रवासी भारत की यात्रा नहीं कर सकता है। यदि वीज़ा किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है और प्रवासी उस उद्देश्य का पालन नहीं करता है, तो प्रवासी का वीज़ा रद्द कर दिया जाना चाहिए और उसे निर्वासित कर दिया जाएगा। वह कारावास और / या जुर्माना के प्रतिबंधों को भी आकर्षित करेगा।
- **वर्क परमिट:** रोजगार वीज़ा को छोड़कर, आप्रवासन के नजरिए से किसी अन्य परमिट की आवश्यकता नहीं है।
- **राष्ट्रीयता प्रतिबंध:** दूरसंचार और प्रसारण उद्योग पर कुछ विशिष्ट प्रतिबंध लागू होते हैं। इन उद्योगों में काम करने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्यों में भारतीय देश शामिल हों। रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्य भारतीय निवासी हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय और विदेश मंत्रालय (एमईए)।

मध्यम अवधि की योजना

- **रोजगार वीज़ा विनियमों में आसानी**
  - भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा $25,000 प्रति वर्ष निर्धारित कर रखी है। हालाँकि, यह शर्त एथनिक रसोइयों , भारत के शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी, स्टाफ, संबंधित दूतावास / भारत के उच्चायोग के लिए काम करने वाले शिक्षकों पर लागू नहीं होती है।
  - न्यूनतम आय सीमा अधिक होने के कारण कई विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार वीज़ा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने अपने कई नियमों में ढील दी है और मेक इन इंडिया पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ऍफ़डीआई) की अनुमति दी है।
  - ऍफ़डीआई के माध्यम से भारत में विदेशी कंपनियों को निवेश करने और काम करने की अनुमति देने से न केवल धन को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि कुशल विदेशी श्रम के लिए भारत के बाजार भी खुलेंगे। इसलिए, वाणिज्य मंत्रालय के साथ परामर्श से विदेश मंत्रालय इस दिशा में काम कर सकता है ताकि विदेशी श्रम के प्रवेश के लिए निर्धारित विनियमन को आसान बनाया जा सके।

दीर्घकालिक योजना

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए स्थायी निवास नीति का पुनर्मूल्यांकन**
  - भारत में लगभग किसी भी अन्य प्रमुख देश की तुलना में इसकी आवश्यकताओं के सापेक्ष में कुशल श्रमिकों की कमी है। हाल ही की मैनपावर टैलेंट शॉर्टेज सर्वे ने बताया कि आधे से अधिक भारतीय नियोक्ताओं ने सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया की उन्होंने आवश्यक कौशल वाले श्रमिकों को खोजने में कठिनाइयों का अनुभव किया है।
  - चीन ने मोबाइल प्रतिभाओं के महत्व को पहचाना और 2008 में 1000 प्रतिभाओं के कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें दुनिया भर के अत्यधिक प्रतिभाशाली अनुसंधान वैज्ञानिकों और उद्यमियों

को बुलाया गया। उन्होंने चीन ग्रीन कार्ड भी लॉन्च किया है, जो कुशल विदेशियों के कुछ समूहों के लिए स्थायी निवास की अनुमति देता है।

- भारत को अपनी कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियों को बनाने और विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने वाली संस्थाओं का निर्माण करने की भी आवश्यकता है, इसलिए भारत को इस दौड़ में शामिल होना चाहिए और कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए आसान निवास की पेशकश करनी चाहिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय एक व्यापक कौशल अंतराल और बाजार की मांग का विश्लेषण कर सकते हैं जिसके माध्यम से वे कौशल के उस समूह की पहचान कर सकते हैं जिसकी बाजार में कमी हैं। पहचाने गए अंतर को कुशल विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने के द्वारा कवर किया जा सकता है, जिसके लिए एमईए को अपनी आप्रवासन नीति में एक स्थायी निवास प्रावधान प्रदान करना चाहिए।

संकेतक 4.08: वेतन और उत्पादकता

परिभाषा: "आपके देश में श्रमिक उत्पादकता से भुगतान किस सीमा तक संबंधित है?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = श्रमिक उत्पादकता से संबंधित नहीं है, 7 = कोई प्रतिबंध नहीं है)

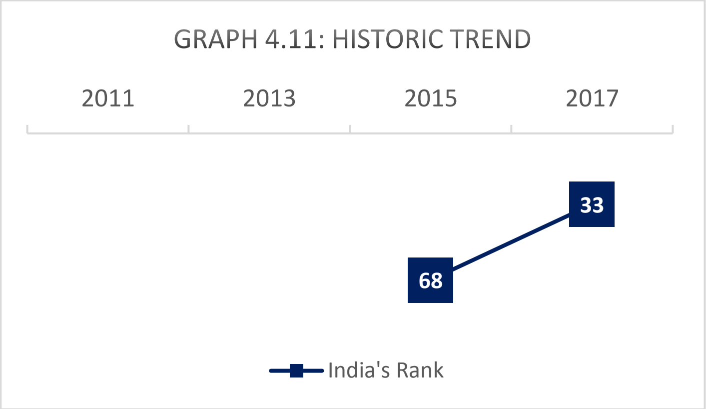

ग्राफ 4.11 संकेतक 4.08 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 35 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.5% का योगदान देता है।

तालिका 4.12: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
स्विट्जरलैंड	5	5.25	1	5.62	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	4	5.33	2	5.5	एशियाई साथी
हांगकांग SAR	1	5.52	3	5.49	एशियाई साथी
भारत	**68**	**3.95**	**33**	**4.54**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **एक नियमित आधार पर डाटा का संग्रह और विश्लेषण**
    - भारत में रोजगार, मजदूरी, उत्पादकता और किये गए कार्य के घंटों के अच्छे और विश्वसनीय राष्ट्रीय आंकड़ों को नियमित आधार पर एकत्र नहीं किया जाता है। जैसा कि नीति निर्माताओं द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारण, सामूहिक सौदेबाजी और पर्याप्त श्रम बाजार के विकास के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए इन डाटा बिंदुओं की आवश्यकता होती है, उसी के संग्रह को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
    - **श्रम और रोजगार मंत्रालय** को **भारत सरकार के श्रम ब्यूरो** को डाटा संग्रह का काम सौंपना चाहिए, जो पहले से ही ग्रामीण श्रम पूछताछ (ग्रामीण और कृषि मजदूरी इकट्ठा करना) और व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (गैर-कृषि क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए मजदूरी डाटा को कैप्चर करना) दोनों का संचालन करता है इस तरह से सभी क्षेत्रों को कवर करता हैं। इसके अलावा, व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण में व्यवसायों की सूची को संशोधित करने की आवश्यकता है, जो लगभग चार दशक पहले तैयार की गई थी।

मध्यम अवधि की योजना

- **अनौपचारिक क्षेत्र का गठन**
    - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भारतीय मज़दूरी रिपोर्ट में सुझाई गई सिफारिशों के अनुसार, भारत को औपचारिक रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया के माध्यम से श्रमिकों को कानून में और व्यवहारिक रूप से न्यूनतम मजदूरी सुरक्षा का विस्तार करना चाहिए। यह सिफारिशें औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों और आर्थिक इकाइयों के संक्रमण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने की सुविधा देती हैं, जबकि संक्रमण के दौरान मौजूदा आजीविका के संरक्षण और सुधार को सुनिश्चित करती हैं। यह प्रोत्साहन, अनुपालन और प्रवर्तन उपायों के संयोजन के लिए कहता है, जिसमें उदाहरण के लिए, व्यापार सेवाओं या वित्त की पहुंच में सुधार, संक्रमण के कारण, सरलीकृत कर और योगदान शासन के माध्यम से सूक्ष्म और लघु आर्थिक इकाइयों के लिए अनुपालन लागत को कम करना, साथ ही साथ अधिक व्यापक है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम निरीक्षण का अच्छी तरह से कवरेज प्रदान करता है।

दीर्घकालिक योजना

- **समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना**
    - अनौपचारिक और औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के बीच वेतन की अंतर को प्रभावी कानूनों, नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से कम किया जा सकता है जो टीएईएल को औपचारिक अर्थव्यवस्था से अनौपचारिक रूप से संक्रमण को बदल देगा। इस संबंध में, एक व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून, जैसे कि भेदभाव-रोधी और समानता विधेयक (2016), यदि इसे इस तरह की विधानों में लागू किया जाता है, तो भेदभावपूर्ण प्रथाओं में से कुछ को संबोधित करने में मदद मिल सकती है।

संकेतक 4.09: महिला श्रम बल की भागीदारी

परिभाषा: यह संकेतक 15-64 आयु वर्ग की श्रम बल में भाग लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत है, जो श्रम बल में भाग लेने वाले 15-64 आयु वर्ग के पुरुषों द्वारा विभाजित किया जाता हैं।

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

देश का मूल्य = $\frac{\text{श्रम बल में महिला का \% (आयु 15−64)}}{\text{श्रम बल में पुरुष का \% (आयु 15−64 वर्ष)}}$

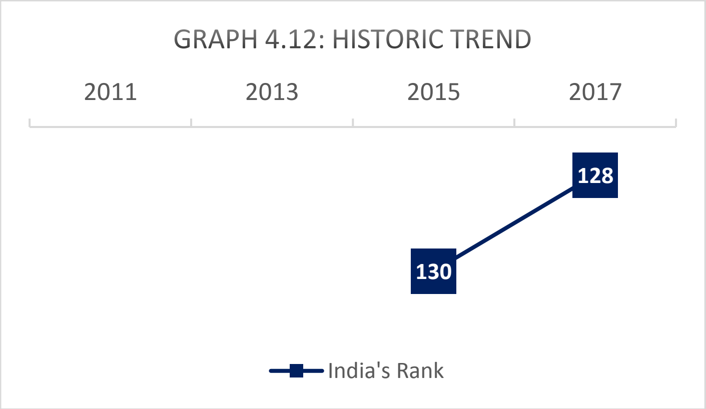

ग्राफ 4.12 सूचक 4.09 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 2 पदों की वृद्धि हुई है। यह सूचक देश के स्कोर में 0.5% का योगदान देता है।

तालिका 4.13 देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
मोज़ाम्बिक	2	1.04	1	1.1	शीर्ष प्रदर्शक
रवांडा	3	1.02	2	1.05	शीर्ष प्रदर्शक
लाओ पीडीआर	5	0.98	3	1.02	एशियाई साथी
भारत	**130**	**0.36**	**128**	**0.34**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमएलइ)

अल्पकालीन योजना

- **कौशल विकास**
    - वर्तमान में, महिलाएं देश की जीडीपी में मात्र 17% का योगदान देती हैं, जो कि वैश्विक औसत 37% से कम है। महिलाओं की श्रम शक्ति में 10 प्रतिशत की वृद्धि से 2025 तक भारत की जीडीपी में $ 700 बिलियन (या 1.4% की वृद्धि) जुड़ सकती है। ज्यादातर महिलाएं, जो काम करने की इच्छुक हैं, कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं पाती हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
    - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना स्व-रोजगार और ग्रामीण गरीबों के संगठन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के पीछे मूल विचार गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय को एक मार्केटिंग टीम बनानी चाहिए जो एनआरएलएम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे उपायों को बढ़ावा दे सके, ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों को इन योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूक करेगी।

मध्यम अवधि की योजना

- **संसद में आरक्षण**[105]
    - संसद में 50% से अधिक महिला सदस्यों के साथ रवांडा दुनिया का पहला देश था। 86% पर, रवांडा [106] में दुनिया में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी की उच्चतम दर है। ऑक्सफैम इंडिया के एक शोध में बताया गया है कि संसद में महिलाओं की संख्या अधिक होने से महिला सशक्तीकरण और घरेलू हिंसा पर अधिक सवाल उठते हैं। वर्तमान में, भारत में लोकसभा में केवल 11.6% महिलाएँ और राज्य सभा में 11% महिलाएँ हैं।

---

[105] https://www.oxfamindia.org/blog/women-representation-political-decision-making-catalyst-achieving-gender-equality

[106] http://www.lmis.gov.rw/scripts/publication/reports/Fourth%20Rwanda%20Population%20and%20Housing%20Census_labour_Force.pdf

- ○ महिला आरक्षण विधेयक, भारत की संसद में व्यपगत हो गया है जिसने भारत के संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को विधेयक पारित किया था। हालांकि, लोकसभा ने कभी भी विधेयक पर मतदान नहीं किया। 2014 में 15 वें लोकसभा सत्र के विघटन के बाद यह बिल समाप्त हो गया। इसलिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय को लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण बिल को वापस लाने और सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाकर इसे पारित करने की योजना बनानी चाहिए। यह महिलाओं को सशक्त करेगा और भारत में नीति निर्माण के उच्चतम स्तर पर अपनी राय को अधिकाधिक रूप से रखने का अवसर प्रदान करेगा।

दीर्घकालिक योजना

- **लिंग वेतन अंतर कम करें**
  - ○ जेंडर, 2017 पर मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों के लिए औसत सकल प्रति घंटा वेतन रु 345.8 और महिलाओं के लिए रु 259.8 था। 2016 में औसतन लिंग का अंतर 25% था। यह आंकड़ा हर उद्योग में भिन्न होता है जैसा कि 4.14 तालिका में दिखाया गया है। भारत में महिलाएं पुरुषों से कम कमाती हैं भले ही उनकी शैक्षणिक योग्यता समान हो।
  - ○ इसके लिए, कंपनियों को कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से निवेश करने की आवश्यकता है जो लिंग के अंतर के मुद्दे पर लोगों को संवेदनशील बना सकते हैं। नेतृत्व पदों पर महिलाओं को नियुक्त करने के लिए सक्रिय विचार दिया जाना चाहिए। यह महिलाओं के लिए सलाह योजनाओं और नेतृत्व कार्यशालाओं को शुरू करने से प्रभावित हो सकता है। लिंग वेतन अंतर को कम किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

तालिका 4.14: क्षेत्र वार औसत लिंग वेतन अंतर

क्षेत्र	औसत लिंग वेतन अंतर (%)
विनिर्माण	29.90%
आईटी	38.20%
निर्माण और तकनीकी परामर्श	18.10%

वित्तीय सेवाएँ, बैंकिंग और बीमा	21.50%
शिक्षा और अनुसंधान	14.70%
हेल्थकेयर, देखभाल सेवाएँ और सामाजिक कार्य	22.60%
परिवहन, रसद और संचार	7.70%
कानूनी और बाजार परामर्श और व्यावसायिक गतिविधियाँ	27.50%

- **शी-बॉक्स के बारे में जागरूकता**
  - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 80 के दशक से भारत में महिलाओं के आंदोलन की प्रमुख चिंताओं में से एक रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), बैंकिंग और वित्त और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में सबसे अधिक मामले सामने आए। बाजार मूल्यांकन[107] द्वारा भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष में यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या वित्त वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष से 5.81% बढ़ कर 601 मामले तक हो गयी है।
  - 2013 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के पंजीकरण के लिए कामकाजी महिलाओं को एकल खिड़की की सुविधा प्रदान करने के लिए एक यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) की स्थापना की है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। शी-बॉक्स कार्यस्थल[108] पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले भंडार के रूप में भी काम करता है।
  - इस कदम के बारे में अभी भी बहुत से लोग अनजान हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर इस पहल को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हर महिला न्याय के लिए अपनी आवाज उठा सके।

[107] https://www.livemint.com/Companies/sZR4sQ2lNON3IcecgE6UUP/Government-workplaces-lag-in-setting-up-sexual-harassment-me.html?utm_source=scroll&utm_medium=referral&utm_campaign=scroll
[108] http://www.shebox.nic.in/user/termsConditions

<u>स्तंभ 5: आईसीटी तत्परता</u>

परिभाषा: यह स्तंभ यह मापता है कि किसी देश में आईसीटी आधारिक संरचना कितनी विकसित है और साथ ही साथ इसका उपयोग देश में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा कैसे किया जा सकता है। स्तंभ 5 में कुल 8 संकेतक हैं जिन्हें नीचे बताया गया है -

1. व्यापार-से-व्यापार लेनदेन के लिए आईसीटी का उपयोग
2. व्यापार से उपभोक्ता लेनदेन के लिए इंटरनेट का उपयोग
3. इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्ति
4. ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहक
5. मोबाइल टेलीफोन सदस्य
6. मोबाइल ब्रॉडबैंड सदस्यताएँ
7. मोबाइल नेटवर्क कवरेज
8. बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता

GRAPH 5.01: HISTORIC TREND

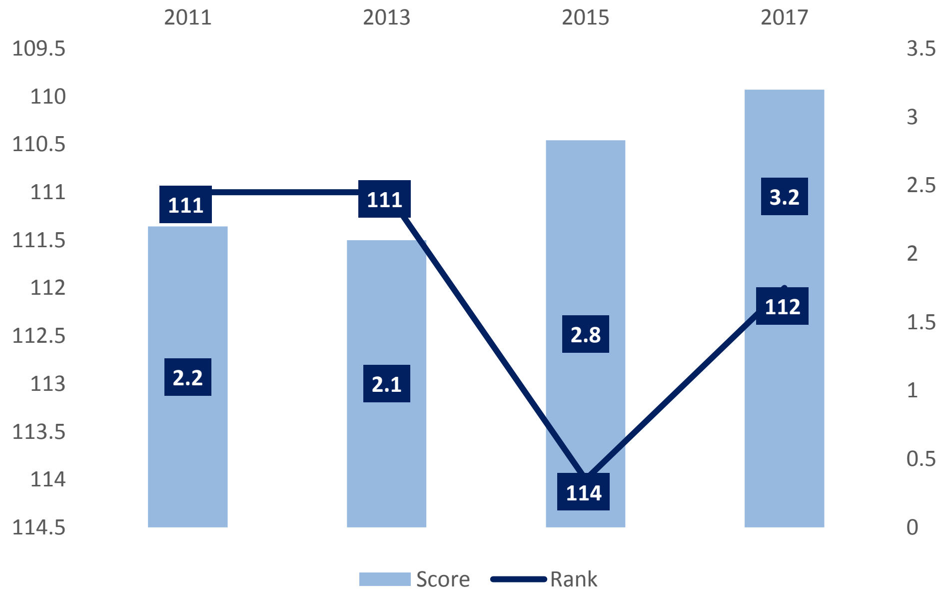

ग्राफ 5.01 में भारत की श्रेणी और स्तंभ 5 में ऐतिहासिक प्रवृत्ति का संकेत देता है। भारत की श्रेणी 2011 में 111 वें स्थान से घटकर 2017 में 112 वें स्थान पर आ गई है।

भार की स्थिति में बदलाव:

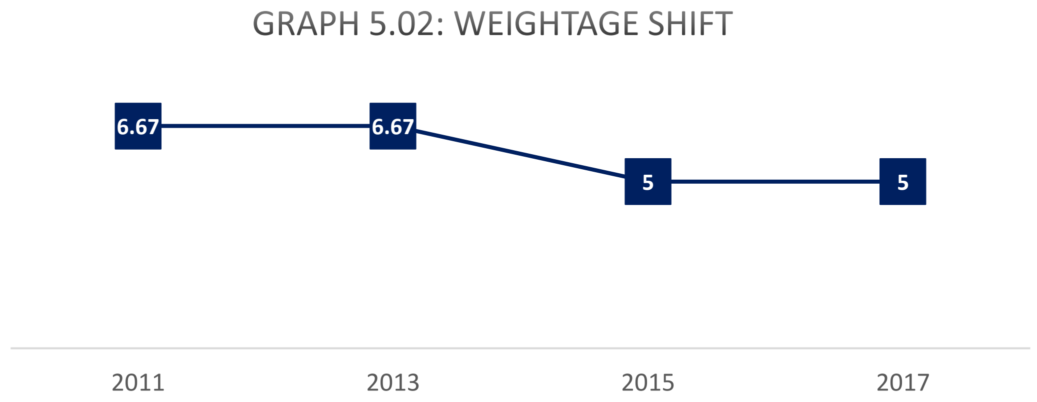

ग्राफ़ 5.02 भारत के स्कोर में स्तंभ 5 यानी आईसीटी तत्परता के समग्र योगदान को इंगित करता है। वर्तमान में, इस स्तंभ को 5% भार दिया गया है। वर्ष 2015 में इस स्तंभ का भार 25% तक कम हो गया है।

तालिका 5.01: संकेतक वार भार की स्थिति में बदलाव

संकेतक	2011 (%)	2013 (%)	2015 (%)	2017 (%)	भार की स्थिति में बदलाव(%)***
व्यापार-से-व्यापार लेनदेन के लिए आईसीटी का उपयोग*	NA	0.55	0.35	0.35	-36.36
व्यापार-से-उपभोक्ता लेनदेन के लिए इंटरनेट का उपयोग*	NA	0.55	0.35	0.35	-36.36
इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्ति	1.33	1.11	0.71	0.71	-36.04
ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहक	1.33	1.11	0.71	0.71	-36.04
मोबाइल टेलीफोन सदस्यता	1.33	1.11	0.71	0.71	-36.04
मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन*	NA	1.11	0.71	0.71	-36.04
मोबाइल नेटवर्क कवरेज**	NA	NA	0.71	0.71	NA
बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता**	NA	NA	0.71	0.71	NA

NA = लागू नहीं, उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

*** 3 नए संकेतक यानी व्यवसाय से व्यापार लेनदेन के लिए आईसीटी उपयोग, व्यवसाय से उपभोक्ता लेनदेन के लिए इंटरनेट का उपयोग और मोबाइल ब्रॉडबैंड सदस्यता 2013 में पेश किए गए थे।**

**** 2 नए संकेतक यानी मोबाइल नेटवर्क कवरेज और बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता 2015 में शुरू किये गए थे**

***** भार की स्थिति में बदलाव वर्ष 2013 की तुलना में दिखाया गया है**

तालिका 5.01 भारत के समग्र स्कोर पर प्रत्येक संकेतक के योगदान का प्रतिशत दर्शाती है।

ध्यान दें: संकेतक 5.01 और 5.02 को एक एकल संकेतक के रूप में दिखाया जा रहा है क्योंकि दोनों संकेतक ई-कॉमर्स की छतरी के नीचे आते हैं। इसलिए, ई-कॉमर्स के उद्देश्य से एक आम रणनीति दोनों संकेतकों पर वांछित प्रभाव डाल सकती है।

संकेतक 5.01: व्यापार-से-व्यापार लेनदेन का आईसीटी उपयोग

परिभाषा: "आपके देश में, व्यवसाय किस सीमा तक अन्य व्यवसायों के साथ लेनदेन के लिए आईसीटी का उपयोग करते हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर(1 = बिल्कुल नहीं, 7 = काफी हद तक)

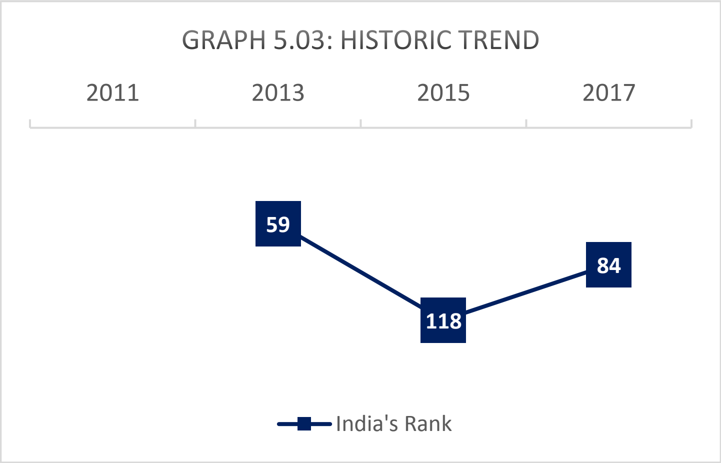

ग्राफ 5.03 संकेतक 5.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2013 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 34 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.35% का योगदान देता है।

तालिका 5.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
नॉर्वे	8	5.95	1	6.11	शीर्ष प्रदर्शक
स्विट्जरलैंड	6	6.02	2	6.09	शीर्ष प्रदर्शक
यूनाइटेड किंगडम	3	6.08	3	6.04	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**118**	**4.01**	**84**	**4.47**	

संकेतक 5.02: व्यापार से उपभोक्ता लेनदेन के लिए इंटरनेट का उपयोग

परिभाषा: "आपके देश में, उपभोक्ता अपने माल और सेवाओं को उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किस हद तक इंटरनेट का उपयोग करते हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = बिल्कुल नहीं, 7 = काफी हद तक)

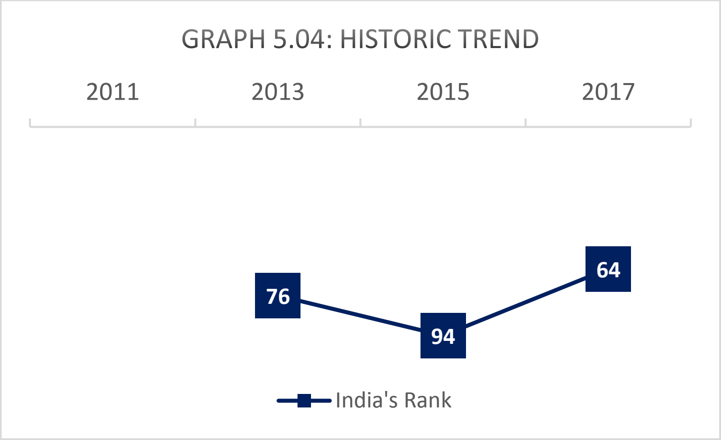

ग्राफ 5.04 संकेतक 5.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2013 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 30 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.35% का योगदान देता है।

तालिका 5.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
यूनाइटेड किंगडम	1	6.3	1	6.4	शीर्ष प्रदर्शक
यूनाइटेड स्टेट्स	2	6.26	2	6.38	शीर्ष प्रदर्शक
स्वीडन	5	6.03	3	6.17	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**94**	**4.08**	**64**	**4.57**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **कौशल विकास और प्रशिक्षण**
  - ई-कॉमर्स ने भारत में ब्लू-कॉलर और व्हाइट-कॉलर दोनों तरह के रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इसके अलावा, रसद, विश्लेषण, मूल्य निर्धारण, सूची प्रबंधन, परिवहन, लास्ट-माइल डिलीवरी आदि गतिविधियां अनूठी हैं और उच्च विशेषज्ञता की मांग करती हैं। इन क्षेत्रों में कुशल श्रमशक्ति की कमी ई-कॉमर्स उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक है।
  - ई-कॉमर्स ऑनलाइन उत्पादों को खरीदने और बेचने से कही ज्यादा है। इसमें उत्पादों और सेवाओं के विकास, विपणन, बिक्री, वितरण, सेवा और भुगतान की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया शामिल है। ऑनलाइन विक्रेताओं के द्वारा जब वे अपने व्यवसाय को बिना तैयारी के लॉन्च करते हैं तो उनसे महंगी गलतियां होने की संभावना होती है क्योंकि वे सफल होने के लिए पर्याप्त डिजिटल ज्ञान से लैस नहीं होते हैं।
  - इस समस्या को दूर करने के लिए, निजी और सरकारी क्षेत्र के संयुक्त कार्यक्रम ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षित करने में सहायक होंगे जो इस उद्योग द्वारा अनुभव किए गए गतिशील विकास के चरणों को जल्दी से अनुकूलित करने की क्षमता रखते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच रणनीतिक संरेखण इस प्रतिभा विकास पहल को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिए, ई-**कॉमर्स निजी खिलाड़ी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की भारत सरकार की पहल के साथ मिलकर इसे अधिक उद्योग के लिए प्रासंगिक बना सकते हैं जबकि राज्य सरकारों की मदद से एमएसडीई को संभावित प्रतिभाओं के समूह की पहचान करनी चाहिए जो उनके क्षेत्र में मौजूद है जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता हैं। (स्रोत:** डेलोइट के "ई-कॉमर्स इन इंडिया ए गेम चेंजर इन इकॉनमी" भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से)

मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और संचार मंत्रालय

मध्यम अवधि की योजना

- **सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच सहज एकीकरण**

- भारत में ई-कॉमर्स विकास पर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश हितधारकों ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे कि आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग और कंपनियों के रजिस्ट्रार के बीच एकीकरण और समन्वय की कमी के बारे में चिंता जताई है, जो कार्य के धीमी गति से पूरा होने, कम दक्षता और पारदर्शिता की कमी का कारण बनता है।
- उपरोक्त चुनौतियों से उबरने के लिए, एक ऑनलाइन सीमा शुल्क निकासी प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए, जहां सरकार के सभी संबंधित विभाग, जैसे डाक विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), आरबीआई और विभिन्न अन्य हितधारकों को कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज (ईडीआई) के मंच के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्रक्रिया को आसान बनाने वाले विभिन्न विभागों के बीच डाटा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके।

दीर्घकालिक योजना

- **स्कोरिंग डाटाबेस**
  - वर्तमान में ई-कॉमर्स साइटों पर विक्रेताओं या उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए ग्राहक के पास एक भरोसेमंद तंत्र अनुपस्थिति है, क्योंकि ऐसी कोई प्रमाणीकरण रेटिंग तंत्र नहीं है जो सरकार द्वारा प्रमाणित है। इसलिए, ग्राहकों को साथी ग्राहकों द्वारा दी गई विक्रेता रेटिंग (या कई मामलों में नकली या भुगतान किए गए समीक्षकों) के आधार पर चुनाव करने के लिए छोड़ दिया जाता है।
  - इसलिए, ऐसे ई-कॉमर्स संस्थाओं में विश्वसनीयता लाने के हित में, सरकार द्वारा मान्यता और / या रेटिंग प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। एक परामर्श पूर्ण दृष्टिकोण को उपयोग में लिया जाना चाहिए जिसे ई-कॉमर्स उद्योग में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ विकसित किया जा सकता है। उद्देश्य केवल एक ऐसे डाटाबेस विकसित करना होना चाहिए जिसमें खरीदारों और विक्रेताओं के पिछले ऑनलाइन शॉपिंग व्यवहार के आधार पर स्कोरिंग के लिए मुख्य मापदंडों को निर्धारित करके पहले दोनों ग्राहकों की रेटिंग शामिल हो।
  - इसी तरह, व्यापारियों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर स्कोरिंग सौंपी जा सकती है। स्कोरिंग तंत्र देश में खरीदारों और विक्रेताओं में उम्मीदों के अनुरूप प्रक्रियाओं के मानकीकरण, सेवा वितरण में गुणवत्ता और समग्र समरूपता लाकर उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास निर्माण

को प्रोत्साहित करके दोनों खरीदारों और विक्रेताओं से दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी के उदाहरणों को हतोत्साहित करेगा।

- **उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए वांछित मानकीकरण प्राप्त करने के लिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक नामित सुविधा देने वाली और हैंड होल्डिंग एजेंसी बनाने की आवश्यकता है जो एक मानक मॉडल के पालन को सक्षम करने के लिए उचित अगले और पिछले संपर्कों के साथ ई-कॉमर्स के लिए मानक मॉडल कोड के साथ एक ऑनलाइन-सिस्टम बनाएगी।**

ध्यान दें: संकेतक 5.03, 5.05, 5.06 और 5.07 को एकल संकेतक के रूप में दिखाया गया है क्योंकि सभी अन्योन्याश्रित हैं और समान मानदंडों का पालन करते हैं।

संकेतक 5.03: इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्ति

परिभाषा: यह संकेतक इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत को संदर्भित करता है। यहां, इंटरनेट उपयोगकर्ता पिछले 12 महीनों में किसी भी डिवाइस (मोबाइल फोन सहित) से इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग हैं। डाटा आमतौर पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं या इंटरनेट सदस्यता की संख्या के आधार पर अनुमानित होते हैं।

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व दूरसंचार संकेतक

देश का मूल्य = $\frac{\text{इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्ति} \times 100}{\text{कुल जनसंख्या}}$

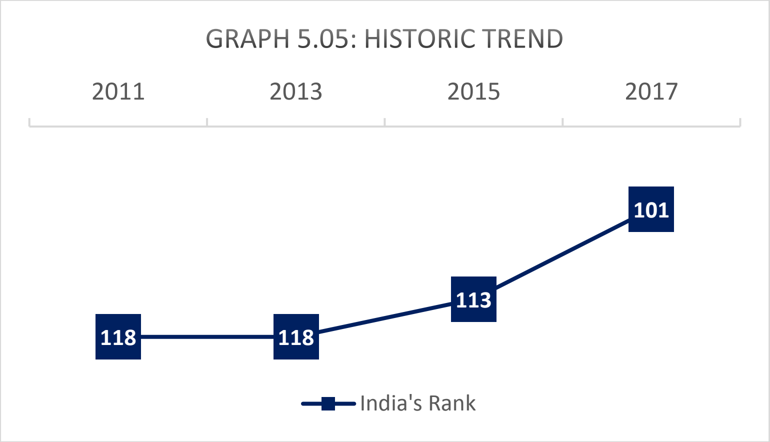

ग्राफ 5.05 संकेतक 5.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 12 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.71% का योगदान देता है।

तालिका 5.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
आइसलैंड	1	96.55	1	98.2	शीर्ष प्रदर्शक
लक्समबर्ग	6	93.78	2	97.33	शीर्ष प्रदर्शक
नॉर्वे	2	95.05	3	96.81	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**113**	**15.1**	**101**	**26**	

संकेतक 5.05: मोबाइल-सेलुलर टेलीफोन सदस्यता

परिभाषा: यह संकेतक प्रति 100 जनसंख्या पर मोबाइल टेलीफोन सदस्यता की संख्या को संदर्भित करता है। एक मोबाइल टेलीफोन सदस्यता एक सार्वजनिक मोबाइल टेलीफोन सेवा की सदस्यता को संदर्भित करती है जो पिछले 3 महीनों के दौरान सक्रिय प्री-पेड सिम कार्डों की संख्या सहित सेल्युलर तकनीक का उपयोग करके सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) तक पहुँच प्रदान करती है। इसमें एनालॉग और डिजिटल सेल्युलर सिस्टम (आईएमटी -2000, थर्ड जेनरेशन, 3G) और 4G सब्सक्रिप्शन शामिल हैं, लेकिन डाटा कार्ड या यूएसबी मोडेम के माध्यम से मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन को शामिल नहीं करता है। सार्वजनिक मोबाइल डाटा सेवाओं, निजी ट्रंक किए गए मोबाइल रेडियो, टेली पॉइंट या रेडियो पेजिंग और टेलीमेट्री सेवाओं की सदस्यता को भी बाहर रखा गया है। इसमें सभी मोबाइल सेलुलर सब्सक्रिप्शन शामिल हैं जो ध्वनि संचार प्रदान करते हैं।

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व दूरसंचार संकेतक

देश का मूल्य = $\frac{\text{मोबाइल टेलीफोन सदस्यता संख्या} \times 100}{\text{कुल जनसंख्या}}$

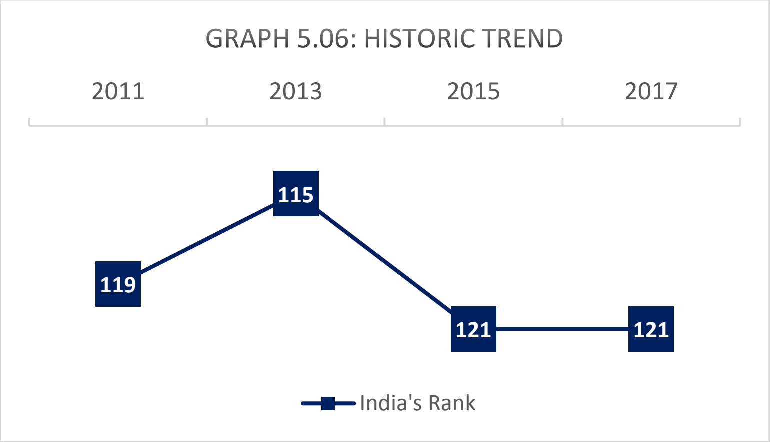

ग्राफ 5.06 संकेतक 5.05 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी 121 वें स्थान पर बनी हुई थी। यह सूचक देश के स्कोर में 0.71% का योगदान देता है।

तालिका-5.05: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण

कुवैत	4	190.29	1	231.76	शीर्ष प्रदर्शक
हांगकांग गणराज्य	1	237.35	2	228.68	एशियाई साथी
यूनाइटेड अरब	7	171.87	3	187.35	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**121**	**70.78**	**121**	**78.06**	

संकेतक 5.06: मोबाइल ब्रॉडबैंड सदस्यता

परिभाषा: यह संकेतक प्रति 100 जनसंख्या पर मोबाइल ब्रॉडबैंड सदस्यता को संदर्भित करता है। मोबाइल ब्रॉडबैंड सदस्यता का तात्पर्य सक्रिय सिम कार्ड से है या सीडीएमए नेटवर्क पर, 512 kb/s से अधिक ब्रॉडबैंड की गति से इंटरनेट तक पहुँचने वाले कनेक्शन, जिसमें सेलुलर तकनीक जैसे एचएसएसपीए, ईवी-डीओ और ऊपर के शामिल हैं। इसमें किसी भी प्रकार के डिवाइस में उपयोग किये जा रहे कनेक्शन को शामिल किया जाता है, जिसमें मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें स्मार्टफोन, यूएसबी मॉडेम, मोबाइल हॉटस्पॉट और अन्य मोबाइल-ब्रॉडबैंड कनेक्टेड डिवाइस शामिल हैं।

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व दूरसंचार संकेतक

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{मोबाइल ब्रॉडबैंड सदस्यता} \times 100}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

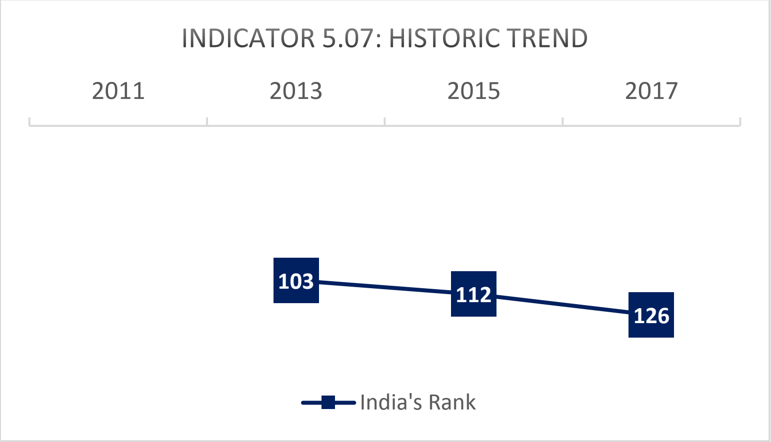

ग्राफ 5.07 संकेतक 5.06 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2013 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 14 पदों की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.71% का योगदान देता है।

तालिका 5.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
फिनलैंड	2	123.14	1	143.99	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	1	149.33	2	143.23	एशियाई साथी
कुवैत	NA	NA	3	140.2	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**112**	**3.22**	**126**	**9.36**	

संकेतक 5.07: Mobile network coverage

परिभाषा: यह संकेतक उन निवासियों के प्रतिशत को संदर्भित करता है जो मोबाइल सेलुलर सिग्नल की सीमा के भीतर हैं, भले ही वे ग्राहक हों या न हों।

स्रोत: तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व दूरसंचार संकेतक

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{मोबाइल सेलुलर सिग्नल की एक सीमा के भीतर रहने वालों की संख्या} \times 100}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

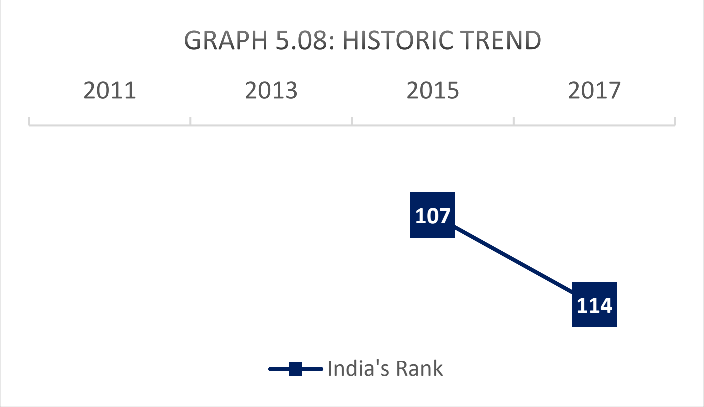

ग्राफ 5.08 संकेतक 5.07 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 7 पदों की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.71% का योगदान देता है।

तालिका 5.07: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
आर्मेनिया	1	100	1	100	शीर्ष प्रदर्शक
अज़रबैजान	1	100	1	100	शीर्ष प्रदर्शक
बुल्गारिया	34	99.99	30	99.99	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**107**	**93.46**	**114**	**93.46**	

तालिका 5.07 में इस संकेतक में पहली श्रेणी में 29 देश हैं

सरकारी पहल[109]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2018 में नई दूरसंचार नीति (राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 2022 तक भारत में निवेश के रूप में $ 100 बिलियन को आकर्षित करना और 4 मिलियन नौकरियों का निर्माण करना है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति का उद्देश्य निम्नलिखित रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना है:

- सभी के लिए ब्रॉडबैंड का प्रावधान
- डिजिटल संचार क्षेत्र में 4 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों का सृजन
- 2017 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 6% से 8% तक बढ़ाना
- 2017 में आईटीयू के आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष 50 राष्ट्रों में भारत को ऊपर बढ़ाना
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के योगदान को बढ़ाना
- डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना

इस राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति को निम्नलिखित तीन मिशनों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिन्हें 2022 तक पूरा किया जाना है:

- **कनेक्ट इंडिया: एक मजबूत डिजिटल संचार आधारिक संरचना बनाना**

    - प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस पर यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करें
    - भारत की सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps उपलब्ध कराएं
    - सभी प्रमुख विकास संस्थानों के लिए 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सक्षम करें; सभी शैक्षिक संस्थानों सहित
    - 2020 तक 55 और 2022 तक 65 'अद्वितीय मोबाइल ग्राहक घनत्व' प्राप्त करें

- **प्रोपेल इंडिया: निवेश, नवाचार, स्वदेशी विनिर्माण और आईपीआर पीढ़ी के माध्यम से अगली पीढ़ी की तकनीकों और सेवाओं को सक्षम करना**

    - वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के योगदान को बढ़ाएं

[109] National Digital Communication Policy 2018

- डिजिटल संचार क्षेत्र में नवाचार द्वारा नेतृत्व किये गए स्टार्ट-अप का सृजन
- भारत में वैश्विक रूप से जानी गयी आईपीआर का निर्माण
- डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) का विकास
- नए कौशल के निर्माण के लिए 1 मिलियन जनशक्ति को ट्रेन / री स्किल करना
- 5 बिलियन जुड़े उपकरणों के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करें
- उद्योग 4.0 में बदलाव को तेज करना

- **सुरक्षित भारत: डिजिटल संप्रभुता, सुरक्षा और डिजिटल संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करना**

  - डिजिटल संचार के लिए एक व्यापक डाटा सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना, जो निजता, स्वायत्तता और व्यक्तियों की पसंद की रक्षा करे और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
  - सुनिश्चित करें कि अगली पीढ़ी के उपयोग की तकनीकों सहित शुद्ध तटस्थता सिद्धांतों को सेवा की आवश्यकताओं, बैंडविड्थ की उपलब्धता और नेटवर्क क्षमताओं के साथ बरकरार रखा गया है।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग

अल्पकालीन योजना

- **फीडबैक समिति[110] का गठन**
  - राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति का उद्देश्य 2017 में 134 वें स्थान से यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) के आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष 50 देशों में भारत को आगे बढ़ाना है। इसलिए, विभिन्न हितधारकों के साथ गठबंधन में संचार मंत्रालय को गहराई से अध्ययन करना चाहिए। आईटीयू के आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में टेलीकॉम सेक्टर में खामियों का पता लगाने की जरूरत है, जिस पर ध्यान दिया

[110] https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/08/Accelerating-growth.PDF

जाना चाहिए, जिसके बाद वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करके हल किया जा सकता है और जो शीर्ष देशों में भारत की श्रेणी को आगे बढ़ाएगा।

- **औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की श्रेणी में सुधार के लिए फीडबैक प्रणाली के एक मॉडल का पालन किया, जिसने अंतिम रिपोर्ट में भारत की श्रेणी में 23 पदों की वृद्धि की थी। दूरसंचार विभाग द्वारा एक समान मॉडल का पालन किया जा सकता है, जहां वे एक फीडबैक समिति बना सकते हैं, जिसमें हितधारक शामिल होंगे जो दूरसंचार उद्योग में जमीन के मुद्दों को हल करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करेंगे।**

मध्यम अवधि की योजना

- **मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय
- **डिजिटल साक्षरता**
    - तकनीकी निरक्षरता भारत की ग्रामीण आबादी के बीच मोबाइल फोन के उपयोग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान (पीएमजीदिशा), सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, जो इसके लक्ष्य[111] से काफी पीछे है। यह भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाय) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से सत्यापित किया जा सकता है, जिन्होंने 31 मार्च, 2018 तक ग्रामीण आबादी के 3 करोड़ को डिजिटल साक्षर बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन इस योजना की उपलब्धि केवल 57 लाख है यानी 19% ही है।
    - **इसलिए, समय पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एमईआईटीवाय को ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्व-सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय में डिजिटल साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आउटरीच को बढ़ाना और उन्हें मोबाइल प्रौद्योगिकी के बारे में अधिक जागरूक बनाना है। यह अंततः भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करेगा।**

[111] https://indianexpress.com/article/india/aiming-to-cover-3-crore-people-digital-literacy-scheme-covers-57-lakh-pm-modi-5208856/

दीर्घकालिक योजना

- **साइट अधिग्रहण प्रक्रिया**
    - साइट अधिग्रहण टॉवर प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रमुख परिचालन चुनौतियों में से एक है। साइट के अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टॉवर प्रदाताओं को सरकारी साइटों पर टेलीकॉम टॉवर स्थापित करने की अनुमति है क्योंकि ये साइट देश के महत्वपूर्ण स्थानों में अच्छी तरह से फैली हुई हैं, और वे कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मोबाइल फोन उपयोगकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
    - हालांकि, अब तक केवल 3 राज्यों अर्थात्; केरल, आंध्र प्रदेश और असम ने टॉवर लगाने के लिए सरकारी परिसरों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। इसलिए, संचार मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकारों को इस पहल के अनुप्रयोग को तेज करने के लिए धक्का देना चाहिए ताकि पूरे भारत में सरकारी साइटों पर अधिक टॉवर लगाए जा सकें। यदि योजना सफलतापूर्वक लागू की जाती है, तो इससे मोबाइल नेटवर्क कवरेज में सुधार होगा।

- **टेलीकॉम टावर्स की स्थापना को बूस्ट करना**
    - 2018 तक देश में, 1.18 बिलियन के ग्राहक आधार के लिए लगभग 461,000 मोबाइल टॉवर हैं। टावर एंड बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (टीआईपीए) का कहना है कि भारत को अभी भी बढ़ते डाटा और वॉइस जरूरतों का ख्याल रखने के लिए कम से कम 100,000 से अधिक टावरों की जरूरत है।।
    - ग्रामीण बाजार एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है जहां विकास की संभावनाएं अधिक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल दूरसंचार प्रवेश सिर्फ 58% है। कई टेलीकॉम दिग्गज मोबाइल टावर केवल शहरों में लगाते हैं, लेकिन मोबाइल टावर लगाने के दौरान होने वाले भारी खर्च के कारण ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए, इस मुद्दे को हल करने के लिए और नेटवर्क कवरेज को बढ़ावा देने और मोबाइल ग्राहकों को बढ़ाने के लिए, **दूरसंचार विभाग को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को सब्सिडी या कोई अन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार टॉवरों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।**

संकेतक 5.04: ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता

परिभाषा: यह संकेतक प्रति 100 जनसंख्या पर निश्चित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता को संदर्भित करता है। यह कुल स्थायी (वायर्ड) ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता (यानी, सार्वजनिक इंटरनेट पर उच्च गति की सदस्यता के लिए - टीसीपी / आईपी कनेक्शन - डाउनस्ट्रीम गति के बराबर या 256 केबीपीएस से अधिक) को संदर्भित करता है।

स्रोत: तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व दूरसंचार संकेतक

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सदस्यता} \times 100}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

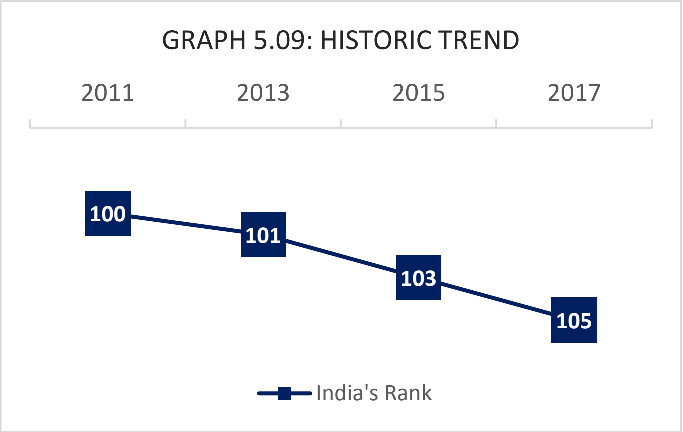

ग्राफ 5.09 संकेतक 5.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2017 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 2 पदों की कमी आई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.71% का योगदान देता है।

तालिका 5.08: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
स्विट्जरलैंड	1	42.52	1	45.11	शीर्ष प्रदर्शक
डेनमार्क	2	40.16	2	42.51	शीर्ष प्रदर्शक
नीदरलैंड	3	40.08	3	41.73	शीर्ष प्रदर्शक
जापान	19	28.90	20	30.66	एशियाई साथी
ऑस्ट्रेलिया	26	25.01	25	28.54	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

इटली	34	22.30	37	24.37	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**103**	**1.16**	**105**	**1.32**	

स्थायी ब्रॉडबैंड किसी भी हाई-स्पीड डाटा ट्रांसमिशन को निवास या व्यवसाय - अर्थात् एक निश्चित स्थान - जिसमें केबल, डीएसएल, फाइबर ऑप्टिक्स, और वायरलेस भी शामिल है, यह इन सहित विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। अनिवार्य रूप से, यह उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्शनों को संदर्भित करता है जो निश्चित स्थानों पर "हमेशा चालू" होते हैं।

सरकारी पहल

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड पहुंच को सुरक्षित करने के लिए **राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन - राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान** 'की स्थापना करके भारत की डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था की पहुंच को पूरा करना है। रणनीति के मुख्य उद्देश्य हैं:

- **भारत नेट** - ग्राम पंचायतों को 1 जीबीपीएस प्रदान करना जो 10 जीबीपीएस तक अपग्रेड हो सकता है
- **ग्राम नेट -** 10 एमबीपीएस के साथ सभी प्रमुख ग्रामीण विकास संस्थानों को 100 एमबीपीएस में अपग्रेड करने योग्य
- **नगर नेट -** शहरी क्षेत्रों में 1 मिलियन सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना
- **जन वाई-फाई** - ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मिलियन वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना
- टियर I, II और III कस्बों में ग्रामीण, उद्यमों और प्रमुख विकास संस्थानों के लिए और राज्य, स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र की मदद से ग्रामीण समूहों को फाइबर लेने के लिए एक पहले 'फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव' को लागू करना।
- राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक ब्रॉडबैंड तत्परता इंडेक्स बनाना ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके और सही तरीके से चुनौतियों का सामना किया जा सके
- राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से ब्रॉडबैंड आधारिक संरचना में निवेश को प्रोत्साहित करना, जिसमें त्वरित मूल्यह्रास और कर प्रोत्साहन; और फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित करना शामिल हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

अल्पकालीन योजना

- फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवा के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 105 वें स्थान पर है। इस प्रकार, वाई-फाई नेटवर्क की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है जो इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक सस्ती, बहुमुखी और लचीली विधि की पेशकश करते हैं। देश भर में वाई-फाई हॉटस्पॉट के विकास में बाधा बन रही बड़ी चुनौती देश में राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियम है।
    - **पूरे देश में राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियमों का एकरूप और निर्बाध कार्यान्वयन**

- राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) एक ढांचा है जो समय-सीमा में अनुमोदन प्रदान करता है और विवादों का निपटारा करता है, साथ ही कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार करता है।
- देश के नुक्कड़ों और कोनों में वाई-फाई कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए फाइबर डालना आवश्यक है। हालांकि, कई आरओडब्ल्यू चुनौतियां हैं जैसे कि साइटों का अधिग्रहण, अत्यधिक शुल्क शुल्क इत्यादि, जो फाइबर को बिछाने और वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने में देरी का कारण बनते हैं। कई दस्तावेजों और एनओसी की आवश्यकता होती है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं। चुनौती केवल अनुमतियाँ प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आरओडब्ल्यू को प्राप्त करने के लिए शुल्क के भुगतान में भी है।
- **इसलिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) को दूरसंचार आधारिक संरचना की स्थापना के लिए राज्यों में आरओडब्ल्यू नियमों में एकरूपता और मानकीकरण लाना होगा। नीति निर्माण के दौरान, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे भूमिगत या ओवर टेलिकॉम आधारभूत संरचना को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।**

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संचार मंत्रालय

दीर्घकालिक योजना

- **सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना**
    - 2016 में, जापान ने पर्यटकों के लिए ट्रैवल जापान वाई-फाई नामक एक मुफ्त वाई-फाई कनेक्शन ऐप पेश किया। यह पूरे देश में कम से कम 2,00,000 हॉटस्पॉट[112] का कनेक्शन प्रदान करता है। ऐप स्वचालित रूप से प्रमुख रेल परिवाहनो, पर्यटन स्थलों, लोकप्रिय दुकानों, रेस्तरां और कैफे में मौजूद हॉटस्पॉट से जुड़ता है। यात्रा जापान वाई-फाई ऐप कई भाषाओं में उपलब्ध है और पास की दुकानों और दर्शनीय स्थलों के बारे में यात्रियों को मार्गदर्शन देकर एक निजी सहायक के रूप में कार्य करता है। सिंगापुर, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अपने पर्यटक को मुफ्त वाई-फाई हॉटस्पॉट की यह सेवा प्रदान करते हैं जो उनकी यात्रा को आसान बनाने में मदद करता है।

[112] https://japanfreewifi.com/

- वर्तमान में, भारत में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट केवल 31,518[113] हैं जो कि आवश्यकता से बहुत कम है और इस संख्या को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। **पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) को टेली-संचार मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के साथ एक चरण-वार रणनीति को स्पष्ट करना चाहिए (क्योंकि प्रमुख साइट संस्कृति मंत्रालय के दायरे में आती हैं) जिसमें पर्यटक स्थलों पर वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। 1 चरण में सभी टियर -1 शहरों को, दूसरे चरण में सभी टियर -2 शहरों को कवर करने का लक्ष्य है। यह न केवल पर्यटकों के अनुभवों को बढ़ाएगा, बल्कि निश्चित ब्रॉडबैंड सदस्यता की संख्या भी बढ़ाएगा।**
- **इस बीच, एमओटी जापान के समान एक ऐप विकसित कर सकता है, जहां सभी सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट सूचीबद्ध किए जाएंगे ताकि यह आगंतुकों को पास में उपलब्ध वाई-फाई कनेक्शन को अधिक आसानी से उपयोग करने की अनुमति देगा।**

[113] https://www.trai.gov.in/sites/default/files/201608260444111068778TAIPA.pdf

संकेतक 5.08: बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता

परिभाषा: "आपके देश में, बिजली की आपूर्ति (रुकावट की कमी और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की कमी) कितनी विश्वसनीय है?"

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = बेहद अविश्वसनीय, 7 = अत्यंत विश्वसनीय).

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

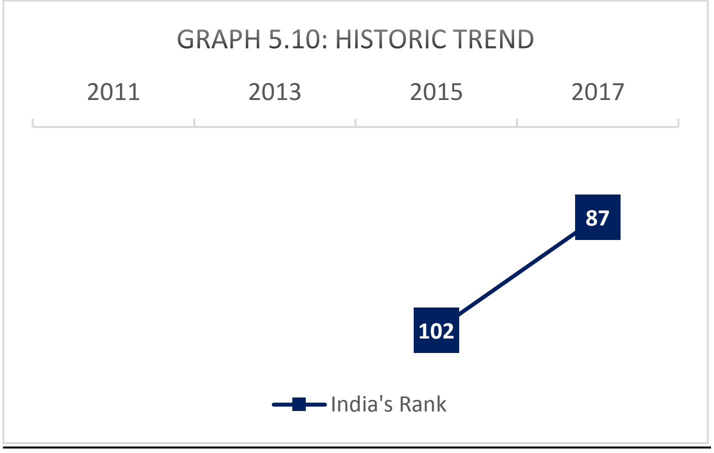

ग्राफ 5.10 संकेतक 5.08 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 15 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.71% का योगदान देता है।

तालिका 5.09: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
स्विट्जरलैंड	1	6.78	1	6.89	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	6	6.68	2	6.81	एशियाई साथी
हांगकांग SAR	2	6.76	3	6.79	एशियाई साथी
भारत	**102**	**3.43**	**87**	**4.28**	

सरकारी पहल

- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना-** यह योजना फीडर सेपरेशन (ग्रामीण घरों और कृषि) और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पैमाइश सहित उप-पारेषण और वितरण आधारिक संरचना को

मजबूत करने पर केंद्रित है। इससे ग्रामीण परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

- **सौभाग्य-** प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, 25 सितंबर 2017 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एक नई योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों (एपीएल और गरीब परिवारों दोनों) और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
- **एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)** विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। आईपीडीएस का उद्देश्य उप-पारेषण नेटवर्क को मजबूत करना है, और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग एक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम (आरएपीडीआरपी) के जीओआई एनजी कार्यों पर पैमाइश, आईटी एप्लीकेशन, कस्टमर केयर सर्विसेस, सोलर पैनल की व्यवस्था और चल रहे कार्यों को पूरा करना भी शामिल है।
- भारत में स्मार्ट ग्रिड के लाभों को पुनः प्राप्त करने और स्मार्ट ग्रिड तैनाती में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के **ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन** की स्थापना की गई है**।** एनएसजीएम एक समर्पित टीम के साथ जनवरी 2016 से चालू है। एनएसजीएम के पास देश में स्मार्ट ग्रिड से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने के मुख्य उद्देश्य के साथ अपने स्वयं के संसाधन, प्राधिकरण, कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता है।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **वितरण कंपनी के चयन के लिए विकल्प**
  - सिंगापुर में, ओपन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट मॉडल (ओईएम) ने सिंगापुर के आसपास केउपभोक्ताओं को किसी भी रिटेलर से कीमत और गुणवत्ता के आधार पर बिजली खरीदने का विकल्प दिया है जो उनकी जरूरतों को पूरा करता है। जबकि प्रतिस्पर्धा कीमत में कमी ला रही है,साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक वितरक उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम गुणवत्ता की आपूर्ति प्रदान करे।
  - **इसलिए, इसी तर्ज पर विद्युत मंत्रालय भारत में ऐसे मॉडल को अपना सकता है क्योंकि इससे वितरकों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा।**

दीर्घकालिक योजना

- **पूरे देश में पावर क्वालिटी पैरामीटर्स का मानकीकरण**
  - राज्य आयोगों के विनियमों में, या तो कोई भी या कुछ[114] विद्युत गुणवत्ता पैरामीटर निर्दिष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, मापदंडों के लिए निर्धारित सीमाएं, जो निर्दिष्ट हैं, विभिन्न राज्यों में भिन्न हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्य नियामकों द्वारा निर्दिष्ट मानक दक्षता के विभिन्न स्तर प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, स्पष्ट रूप से परिभाषित ढांचे के साथ प्रोत्साहन / विघटनकारी तंत्र को व्यापक रूप से कवर नहीं किया गया है।
  - उपर्युक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए, पावर क्वालिटी पर एक मॉडल विनियमन को अपनाया जाना चाहिए जहां बिजली की गुणवत्ता सूचकांकों, विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, मानकों / सीमाओं का पालन किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन / विघटनकारी तंत्र और निगरानी, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए प्रक्रिया, बिजली की गुणवत्ता के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। **राज्य विद्युत विनियमन आयोगों (एसईआरसी) की सहायता से विद्युत मंत्रालय को विद्युत गुणवत्ता पर इस मॉडल विनियमन को लागू करना चाहिए ताकि देश भर में बिजली की गुणवत्ता पर एक समान और सुसंगत मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।**

उप-सूचकांक बी

टीएंडटी नीति और शर्तों को सक्षम करना

टीएंडटी नीति और शर्तों को सक्षम करना उप-सूचकांक, विशिष्ट नीतियों या रणनीतिक पहलुओं को पकड़ती हैं जो टीएंडटी उद्योग को अधिक सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। इस उप-सूचकांक में दिए गए स्तंभ यह इंगित करते हैं कि किस हद तक प्राकृतिक पूंजी-जिस पर पर्यटन उद्योग का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता है, उसका संरक्षण किया जा रहा है।

[114] Report on Power Quality of Electricity Supply to the Consumers: Central Electricity Regulatory Commission

इस उप-सूचकांक में 4 स्तंभ शामिल हैं:

1. यात्रा और पर्यटन का प्राथमिकताकरण (6 संकेतक)

2. अंतर्राष्ट्रीय खुलापन (3 संकेतक)

3. मूल्य प्रतिस्पर्धा (4 संकेतक)

4. पर्यावरणीय स्थिरता (10 संकेतक)

स्तंभ 6: यात्रा और पर्यटन का प्राथमिकताकरण

परिभाषा: यह स्तंभ उस सीमा को मापता है जिससे सरकार सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है और टीएंडटी क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाती है। स्तंभ 6 के नीचे कुल 6 संकेतक हैं -

1. यात्रा और पर्यटन उद्योग को सरकार की प्राथमिकता
2. टीएंडटी सरकारी खर्च
3. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विपणन और ब्रांडिंग की प्रभावशीलता
4. वार्षिक टीएंडटी डाटा की व्यापकता
5. मासिक / त्रैमासिक टीएंडटी डाटा प्रदान करने की समयबद्धता
6. देशीय ब्रांड रणनीति श्रेणी

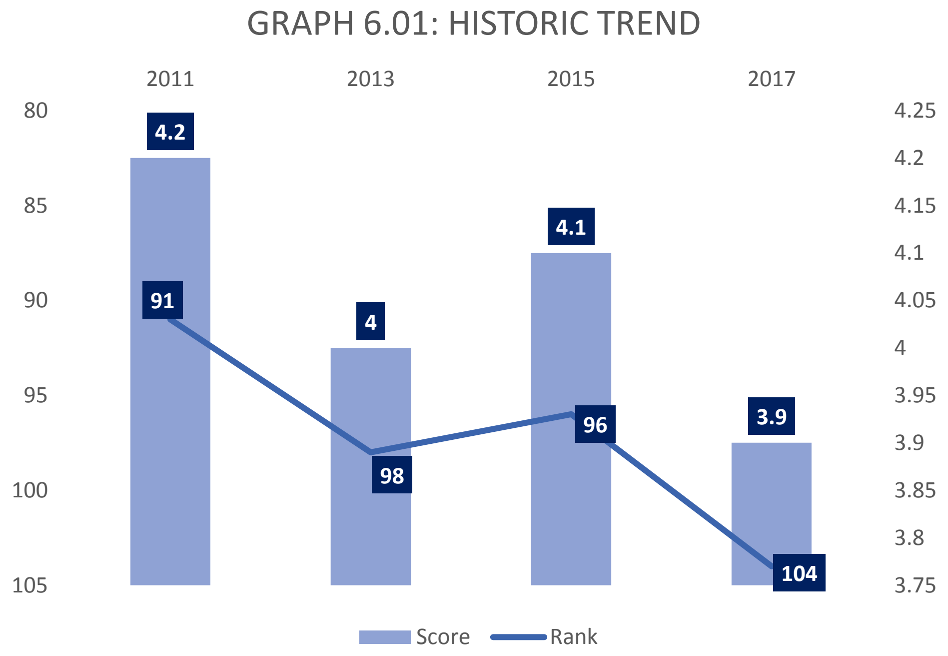

ग्राफ 6.01 भारत की श्रेणी और स्तंभ 6 में मूल्य की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को इंगित करता है। भारत की श्रेणी 2011 में 91 वें स्थान से घटकर 2017 में 104 वें स्थान पर आ गई थी।

भार की स्थिति में बदलाव:

GRAPH 6.02: WEIGHTAGE SHIFT

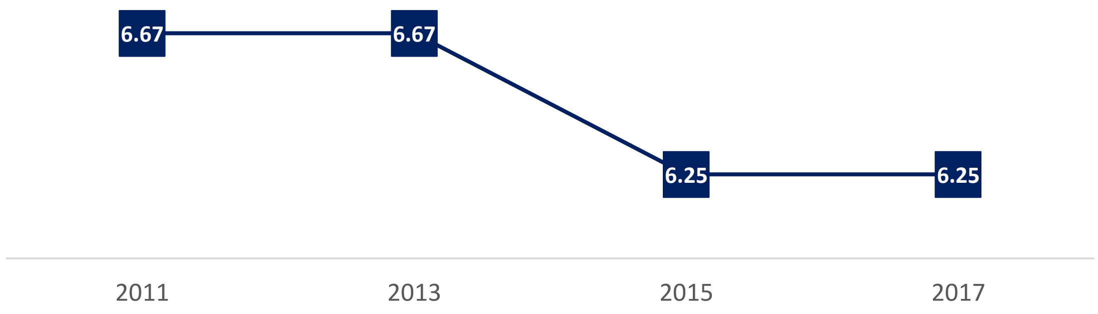

ग्राफ़ 6.02 भारत के स्कोर में स्तंभ 6 यानी यात्रा और पर्यटन के प्राथमिकताकरण के समग्र योगदान को इंगित करता है। वर्तमान में 6.25% भार इस स्तंभ को दिया जाता है। इस स्तंभ का भार वर्ष 2015 में 6.30% कम हो गया है।

तालिका 6.01: संकेतक वार भार की स्थिति में बदलाव

संकेतक	2011-2013 (%)	2015-2017 (%)	भार की स्थिति में बदलाव (%)
यात्रा और पर्यटन उद्योग की सरकारी प्राथमिकता	1.67	1.25	-25.15
टीएंडटी सरकारी व्यय	1.67	1.25	-25.15
पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विपणन और ब्रांडिंग की प्रभावशीलता	1.67	1.25	-25.15
वार्षिक टीएंडटी डाटा की व्यापकता*	0.83	0.625	-24.70
मासिक / त्रैमासिक टीएंडटी डाटा प्रदान करने की समयबद्धता*	0.83	0.625	-24.70
देशीय ब्रांड रणनीति श्रेणी	NA	1.25	NA

NA = लागू नहीं, संकेतक उस वर्ष में पेश नहीं किया गया था।

*** इन संकेतकों को एक एकल संकेतक बनाने के लिए एक सरल औसत एकत्रीकरण लागू किया जाता है। नतीजतन, वे 0.5 के कारक के द्वारा स्पष्ट रूप से भारित होते हैं।**

तालिका 6.01 योगदान का प्रतिशत दर्शाती है कि प्रत्येक संकेतक का भारत के समग्र स्कोर पर है।

यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल जो चल रही हैं

- **उड़ें देश का आम नागरिक (उड़ान)**[115]
  - उड़ान क्षेत्रीय विकास बाजार को विकसित करने के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। यह एक बाजार-आधारित तंत्र है जिसमें विमान सेवाएं सीट सब्सिडी के लिए बोली लगाती हैं। यह अपनी तरह की पहली योजना क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य और फायदें की उड़ानें बनाएगी ताकि छोटे शहरों में रहने वाले आम आदमी के लिए भी उड़ान सस्ती हो जाए।
- **स्वदेश दर्शन योजना**
  - यह योजना देश में थीम आधारित पर्यटन को विकसित करने के लिए कैबिनेट मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
  - स्वदेश दर्शन योजना में पर्यटक अनुभव बढ़ाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों को समन्वित करके उच्च पर्यटन मूल्य, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता के सिद्धांतों पर थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए एक सोच है।
  - इस योजना के तहत विकास के लिए पंद्रह विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है, जैसे: उत्तर-पूर्व भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालयन सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्डलाइफ सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिट सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और सूफी सर्किट।
- **तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत वृद्धि ड्राइव (प्रसाद)**
  - पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, वृद्धि ड्राइव' (प्रसाद) का शुभारंभ किया गया है, जिसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रा और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटकों की सुविधा के लिए सुव्यवस्थित पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुलभ, सुरक्षा, स्वच्छता, अनुभव और एकीकृत, समावेशी और टिकाऊ विकास के माध्यम से तीर्थ / विरासत शहर की आत्मा को पुनर्जीवित / संरक्षित करना जो स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
  - वर्तमान में इस योजना के तहत विकास के लिए पहचाने जाने वाले स्थलों की कुल संख्या 25 राज्यों में 41 है। वे अमरावती और श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश), कामाख्या (असम), परशुराम कुंड

[115]http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=151850

(लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश), पटना और गया (बिहार), बालमेश्वरी देवी मंदिर (राजनांदगांव, छत्तीसगढ़), द्वारका और सोमनाथ (गुजरात), गुरुद्वारा नाडा साहेब, पंचकुला (हरियाणा), मां चिंतपूर्णी (ऊना, हिमाचल प्रदेश), हजरतबल और कटरा (जम्मू और कश्मीर), देवगढ़ और पारसनाथ (झारखंड)), चामुंडेश्वरी देवी, मैसूरु (कर्नाटक), गुरुवायूर, सेंट थॉमस इंटरनेशनल श्राइन, (मलयाट्टूर), चेरामन जुमा मस्जिद (त्रिशूर, केरल), ओंकारेश्वर और अमरकंटक (मध्य प्रदेश, बाबेदरा, पश्चिम जयंतिया हिल्स और सोहरा (मेघालय) आइजवाल (मिजोरम), कोहिमा और मोकोकचुंग डिस्ट्रक्ट आईसीटी (नागालैंड), त्र्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र), पुरी (ओडिशा), अमृतसर (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), कांचीपुरम और वेल्लनकनी (तमिलनाडु), त्रिपुरा सुंदरी (त्रिपुरा), वाराणसी, और वाराणसी मथुरा (उत्तर प राधेश), बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री (उत्तराखंड) और बेलूर (पश्चिम बंगाल) हैं।

- **अतुल्य भारत 2.0**[116]
  - पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न गंतव्यों और पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया है, जिसमें विदेशों में महत्वपूर्ण और संभावित स्रोत बाजारों में आध्यात्मिक, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन शामिल हैं।
  - मंत्रालय, अपनी चल रही गतिविधियों के तहत, सालाना, 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत, देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियानों को, सांस्कृतिक विरासत सहित जारी करता है। प्रचार मंत्रालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों के माध्यम से भी किए जाते हैं।
  - भारत सरकार द्वारा कई ब्रांडिंग और विपणन पहल की शुरुआत जैसे अतुल्य भारत! और अतिथि देवो भव विकास के लिए एक केंद्रित गति प्रदान करता है।
- **चलो कुंभ चलो**[117]
  - पर्यटन मंत्रालय ने एक पहल की है जो कुंभ 2019 के लिए 49 दिनों के कुंभ मेले को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 'चलो कुंभ चलो' अभियान की शुरुआत है, जो देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विज्ञापनों के माध्यम से, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया हैं ओर साथ ही, कुंभ मेले में जाने वाले 192 देशों के लिए झंडा फहराने के लिए

[116] http://www.incredibleindia.com/
[117] https://www.traveltrendstoday.in/news/india-tourism/item/6236-govt-to-promote-kumbh-mela-to-attract-foreign-tourists

जो कुंभ 2019 का दौरा करेंगे और वाराणसी में 'प्रवासी भारतीय दिवस', 2019 के आयोजन के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र का विकास किया गया हैं 'प्रवासी भारतीय प्रतिनिधि' को आकर्षित करने के लिए।

- **आदर्श स्मारक**
  - **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)** ने मॉडल स्मारकों के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 स्मारकों की पहचान की है। इन स्मारकों को वाई-फाई, सुरक्षा, साइनेज, अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र, व्याख्या केंद्रों सहित आवश्यक पर्यटक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो स्मारकों के महत्व के बारे में लघु फिल्में दिखाती हैं।
- **साहसिक पर्यटन**
  - साहसिक पर्यटन में सुदूर, विदेशी क्षेत्रों की खोज या यात्रा शामिल है। कोई भी रचनात्मक गतिविधि जो एक व्यक्ति और उसके उपकरण दोनों के धीरज का परीक्षण चरम सीमा तक करती है, इसे साहसिक कहा जाता है। जैसे-जैसे एक पर्यटक विभिन्न प्रकार की छुट्टियों की तलाश करता है वैसे ही साहसिक पर्यटन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।
  - पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स की मंजूरी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो सभी स्वैच्छिक एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के लिए खुली एक स्वैच्छिक योजना है।
  - पर्यटन मंत्रालय ने 2012 में साहसिक पर्यटन पर सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंड पर साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए बेसिक न्यूनतम मानक के रूप में कई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और संशोधित दिशा-निर्देश 'भारतीय साहसिक पर्यटन दिशा-निर्देश' (संस्करण 2) को 31 मई 2018 को लॉन्च किया गया है, जिसमें साहसिक पर्यटन गतिविधियों के संबंध में भूमि, वायु और पानी से जुड़े 31 वर्टिकल शामिल हैं। ये दिशानिर्देश पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अनुपालन के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भी भेजा गया है। केंद्रीय वित्तीय सहायता को विभिन्न राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित किया जा रहा है
  - साहसिक पर्यटन स्थलों सहित स्थलों में पर्यटन के आधारिक संरचना के विकास के लिए व्यवस्थापन।
  - अंतर्देशीय जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा आवश्यक आधारिक संरचना सुविधाएं प्रदान करके विशेष प्रयास किए जाते हैं। डबल हल नौकाओं, जेटी का गठन, क्रूज पोत, नाव आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाया गया है।

- अक्टूबर 2016 में एडवेंचर टूरिज्म पर एक टास्क फोर्स का गठन सचिव (पर्यटन) के साथ अध्यक्ष के रूप में किया गया है, जो देश में एडवेंचर टूरिज्म के विकास और संवर्धन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। टास्क फोर्स की पहली बैठक 21 दिसंबर 2016 को आयोजित की गई थी। साहसिक पर्यटन टास्क फोर्स की अंतिम बैठक 11.08.2017 को आयोजित की गई थी।

- **खेल पर्यटन**[118]
  - देश भर में खेलों को प्रोत्साहित करने के मकसद से खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और देश में खेल उत्कृष्टता हासिल करने के लिए, खेलो भारत योजना को फिर से शुरू किया गया है और समुदाय, स्कूल और विश्वविद्यालय स्तरों पर खेल के विकास के लिए विशिष्ट ऊर्ध्वाधर के साथ 262 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट परिव्यय के साथ फिर से लाया गया है।

[118] http://ficci.in/spdocument/22996/Tourism-Report-2018.pdf

संकेतक 6.01: यात्रा और पर्यटन उद्योग का सरकारी प्राथमिकताकरण

परिभाषा: "हमारे देश की सरकार के लिए यात्रा और पर्यटन उद्योग का विकास कितनी प्राथमिकता पर है?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

देश का मूल्य: देश का मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = कोई प्राथमिकता नहीं, 7 = सर्वोच्च प्राथमिकता)

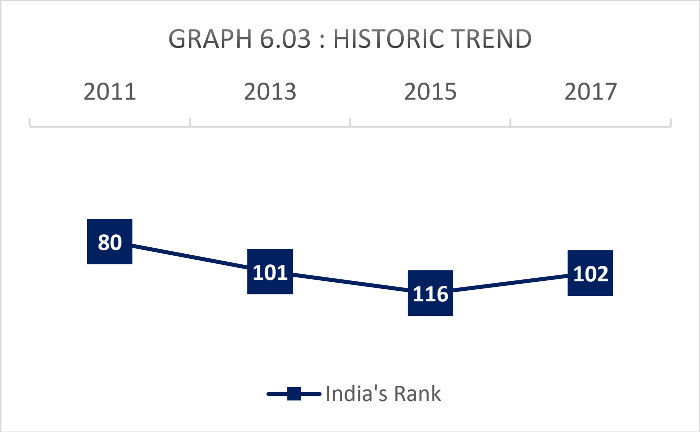

ग्राफ 6.03 संकेतक 6.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 14 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 1.25% का योगदान देता है।

तालिका 6.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
संयुक्त अरब अमीरात	1	6.71	1	6.62	शीर्ष प्रदर्शक
न्यूज़ीलैंड	2	6.68	2	6.49	शीर्ष प्रदर्शक
लेसोथो	62	5.32	3	6.47	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
फ्रांस	34	5.84	36	5.45	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**116**	**4.34**	**102**	**4.07**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न गंतव्यों और पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अतुल्य भारत 2.0 अभियान नामक एक फ्लैगशिप योजना शुरू की है, जिसमें महत्वपूर्ण और संभावित स्रोत बाजारों में आध्यात्मिक, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न आला उत्पादों पर विषयगत क्रिएटिव के साथ विशिष्ट प्रचार योजनाओं और सामग्री निर्माण के लिए दुनिया भर में किए जाने वाले सामान्य प्रमोशन से एक बदलाव लाना है।
    - **सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम**
        - अतुल्य भारत 2.0 को अभी भी एक परिवर्तित और आधुनिक भारत का प्रदर्शन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। इस उद्देश्य को तेजी से हासिल करने के लिए, भारत को न केवल पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाने के लिए अपनी मूल्य श्रृंखला को ठीक करना चाहिए, बल्कि उस अनुभव की गारंटी भी देनी चाहिए, जो वे फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियान और कहानियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। **एक सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम की स्थापना करके, जिसका मुख्य फोकस विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल, पर्यटन मंत्रालय पर होने वाले कार्यक्रमों की ऑनलाइन मार्केटिंग पर होगा, अपने निम्नलिखित का विस्तार करने और अंतर्राष्ट्रीय अपील प्राप्त करने के लिए अभियान चला सकता है।**
        - अतुल्य भारत ऐप में एंड्रॉइड पर लगभग 10,000+ डाउनलोड हैं। आवेदन के उचित प्रचार / विपणन द्वारा इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। **उपयोगकर्ताओं को अतुल्य भारत ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश की जा सकती है जैसे पंजीकृत होटल, पर्यटन पैकेज, घटनाओं के लिए टिकट बुक करना, जैसे अन्य कि अन्य एप्लिकेशन द्वारा किये जाते हैं जैसे makemytrip.com, goibibo, आदि द्वारा किया जाता है।**
        - अतुल्य भारत ऐप की पुन: गतिशीलता को बढ़ाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक अधिक प्रमुख तरीका अपनाया जा सकता है। वे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंच सकते हैं, विशेष रूप से अपनी वेबसाइट पर इंक्रेडिबल इंडिया योजना के प्रचार के लिए यात्रा और पर्यटन जैसे makemytrip.com, goibibo, आदि से संबंधित हैं। यह उन

अधिकारियों की धारणा को भी प्रभावित करेगा जो रिपोर्ट के 30% सर्वेक्षण प्रश्नों के लिए जिम्मेदार हैं।

- **अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन को मजबूत बनाना:**
    - अध्ययन के दौरान, यह देखा गया कि वर्तमान संस्करण **वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन** में सुधार की गुंजाइश है जैसा कि नीचे बताया गया है:
        - एप्लिकेशन केवल एकल भाषा यानी अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन इसमें हिंदी भाषा के विकल्प का अभाव है **जो घरेलू उपयोगकर्ताओं को ऐप[119] का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित कर सकता है।**
        - वेबसाइट के वर्तमान संस्करण में एक अच्छे खोज इंजन अनुकूलन का अभाव है। अतुल्य भारत की आधिकारिक वेबसाइट गूगल के माध्यम से खोजे जाने के दौरान 4 की स्थिति दिखाती है। अतुल्य भारत की वेबसाइट पर भी, मोबाइल एप्लिकेशन या उसके डाउनलोड लिंक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
    - ऐसी कमजोरियां वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए पर्यटकों के हित को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। इसलिए, इसकी कार्यक्षमता के साथ-साथ वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन विकास का फिर से विश्लेषण करने की तत्काल आवश्यकता है। यह, एप्लिकेशन के उचित और प्रभावी प्रचार के साथ युग्मित होने से ऐप डाउनलोड की संख्या में वृद्धि हो सकती है जिससे देश में संभावित पर्यटन बढ़ सकता है।

- विदेशों में प्रचार की कमी, पुरानी ब्रांड छवि, भारत में पर्यटन के प्रबंधन कार्यालयों की कमी, नकारात्मक प्रचार का सामना करने के लिए खराब पीआर प्रयास, उच्च मूल्य और राष्ट्रीय स्मारकों की आधारिक संरचना कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत में पर्यटन में निकट भविष्य में गिरावट आयी हैं। **इन कारणों को समाप्त करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित तरीके अपना सकता है:**[120]
    - रोकथाम के लिए एक जनसंपर्क सलाहकार / कंपनी की नियुक्ति और कमीशनिंग करना, जो भारतीय पर्यटन के लिए एक पीआर (पब्लिक रिलेशन) रणनीति तैयार करने के लिए है, जो

[119] https://itunes.apple.com/in/app/incredible-ndia/id1398253039?mt=8
[120] http://www.iato.in/uploads/newsletter/Newsletter_Feb2015March201612.pdf

रोकथाम, बुरे प्रचार के लिए शीघ्र हस्तक्षेप और संकट की स्थितियों[121] के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया पर आधारित है।

- किसी भी क्षेत्र में होटल की संख्या, आधारिक संरचना विकास, मोबाइल नेटवर्क कवरेज, परिवहन सुविधा और पहुंच, सुरक्षा उपायों आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर नज़र रखने के लिए पर्यटक स्थलों पर एक तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण किया जा सकता है, इससे मंत्रालय को मदद मिलेगी। पर्यटन स्थलों पर नज़र रखने के लिए पर्यटन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

- **मध्यम अवधि की योजना**
  - 1 सितंबर 2003 को लॉन्च किया गया लेसोथो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एलटीडीसी) [122], एक लेसोथो सरकार की पहल है जो लेसोथो देश के पर्यटन स्थल के रूप में विपणन और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। एलटीडीसी की एक मजबूत और जीवंत पर्यटन उद्योग के विकास में नेतृत्व है जो स्थायी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देता है। यह रणनीतिक विपणन, अनुसंधान, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सेवा वितरण और मानव संसाधन विकास में निजी क्षेत्र और समुदाय के साथ प्रभावी साझेदारी के माध्यम से किया जाता है। इसलिए, पर्यटन मंत्रालय एलटीडीसी जैसा एक निगम भी स्थापित कर सकता है जो पर्यटन विपणन की देखरेख कर सकता है। निगम के मुख्य उद्देश्य में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:
  - इस तरह से पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत का प्रचार करना और बढ़ावा देना, जो अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उत्पादन, भुगतान में सुधार और रोजगार के सृजन में योगदान देगा।
  - भारत के अनूठे बिक्री बिंदुओं जैसे कुम्भ मेला, जयपुर साहित्य उत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल, पुष्कर इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल को बढ़ावा देने के लिए उचित विपणन रणनीति अपनाकर पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए, विरासत, पारंपरिक और सांस्कृतिक आयोजनों और जिम्मेदारियों की सराहना पर विशेष ध्यान देने के साथ पर्यावरण का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करना है।

---
[121]http://www.wttcii.org/pdf/India_Tourism_Plan.pdf
[122]https://www.lesothotradeportal.org.ls/kcfinder/upload/files/MINISTRY%20OF%20TOURISM.pdf

- वे इंडाबा जैसा कार्यक्रम भी ला सकते हैं और अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे लेसोथो अपने प्रसिद्ध इंडबा कार्यक्रम (डरबन[123] में सालाना आयोजित होने वाला अफ्रीका का शीर्ष कार्यक्रम) में अपने पर्यटन को बढ़ावा देता है।

दीर्घकालिक योजना

- फ्रांस को वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी का केंद्र भी कहा जाता है। फ्रांसीसी व्यंजनों के पर्व उत्सव ने संदेश को रेखांकित किया कि फ्रांस का उद्देश्य उन आगंतुकों को पूरा करना है जो विशेष रूप से अपने भोजन के लिए देश की यात्रा करते हैं। इसी तरह की तर्ज पर, पर्यटन मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और / या राज्य सरकारों के साथ मिलकर नियमित अंतराल पर फूड फेस्टिवल के माध्यम से इसे बढ़ावा देकर गैस्ट्रोनॉमी पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, क्योंकि भारत अपनी पुरानी और अनूठी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है जो असंख्य अद्वितीय व्यंजन पेश करता है। यह न केवल भारतीय व्यंजनों को अधिक से अधिक तस्वीर में लाएगा, बल्कि अद्वितीय भारतीय संस्कृति[124] पर आधारित उत्पादों और सेवाओं के लिए मूल्यों को जोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

[123] https://maliba-lodge.com/blanketwrap/tag/ltdc/, http://fortuneofafrica.com/lesotho/tourism-in-lesotho/
[124] https://www.campusfrance.org/en/culinary-specialties-French-gastronomy

संकेतक 6.02: टीएंडटी सरकारी व्यय

परिभाषा: यह सूचक कुल सरकारी बजट के प्रतिशत के रूप में कुल टीएंडटी सरकारी व्यय को संदर्भित करता है। इसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा टीएंडटी सेवाएं जैसे कि सांस्कृतिक (जैसे कला संग्रहालय), मनोरंजन (जैसे राष्ट्रीय उद्यान), निकासी (उदाहरण के लिए आव्रजन / सीमा शुल्क) और आगंतुकों को प्रदान करने के लिए किए गए व्यय (ट्रांसफर या सब्सिडी) शामिल हैं।

स्रोत: विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, पर्यटन उपग्रह खाता अनुसंधान

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{टीएंडटी पर सरकार द्वारा कुल प्रत्यक्ष निवेश} \times 100}{\text{कुल सरकारी बजट}}$$

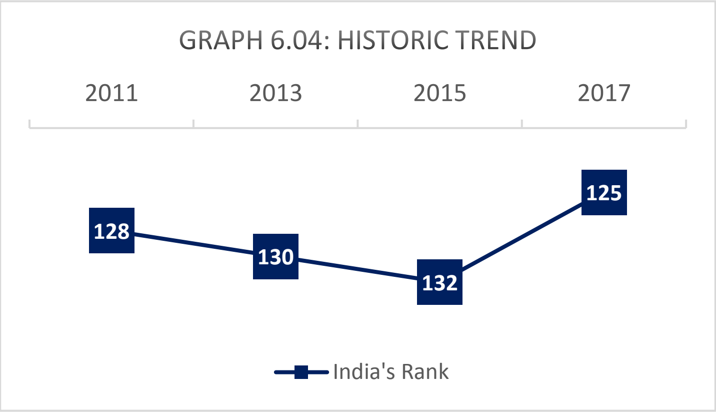

ग्राफ 6.04 संकेतक 6.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 7 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 1.25% का योगदान देता है।

तालिका 6.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
डोमिनिक गणराज्य	2	21.77	1	22	शीर्ष प्रदर्शक
जमैका	3	17.05	2	17.1	शीर्ष प्रदर्शक
मॉरीशस	4	16.44	3	16.6	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**132**	**0.98**	**125**	**1**	

पर्यटन आधारिक संरचना

- **आतिथ्य विश्लेषण**
    - भारतीय आतिथ्य उद्योग सेवा क्षेत्र के विकास को चलाने वाले प्रमुख उद्योगों में से एक के रूप में उभरा है और इसी प्रकार से, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय होटल बाजार का 2020 तक लगभग 13 बिलियन USD तक बढ़ने का अनुमान है।

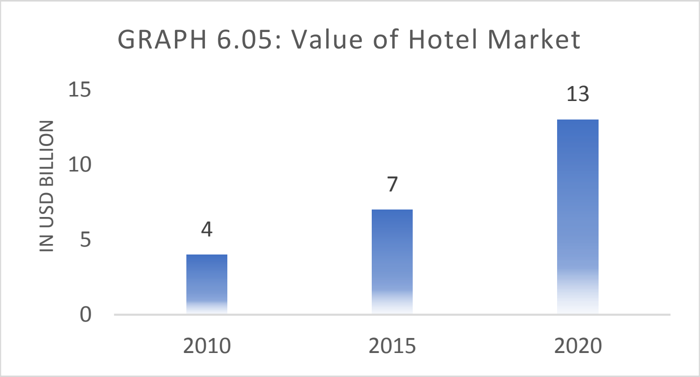

    - निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि के बावजूद, भारतीय होटल उद्योग ने 2016-17 में औसत कमरे की दर और कमरे में रहने की स्थिति में गिरावट देखी हैं, जिसका श्रेय भारत में फाइव-स्टार डीलक्स और फाइव-स्टार श्रेणियों में होटल की कम भागीदारी को दिया जाता है। आतिथ्य के अनुसार, आतिथ्य परामर्शदाता फर्म, भारत में होटलों की अधिभोग और औसत दरें निम्नलिखित हैं। होटलीवेट[125], के अनुसार, आतिथ्य परामर्शदाता फर्म, भारत में होटलों की अधिभोग और औसत दरें निम्नलिखित हैं।

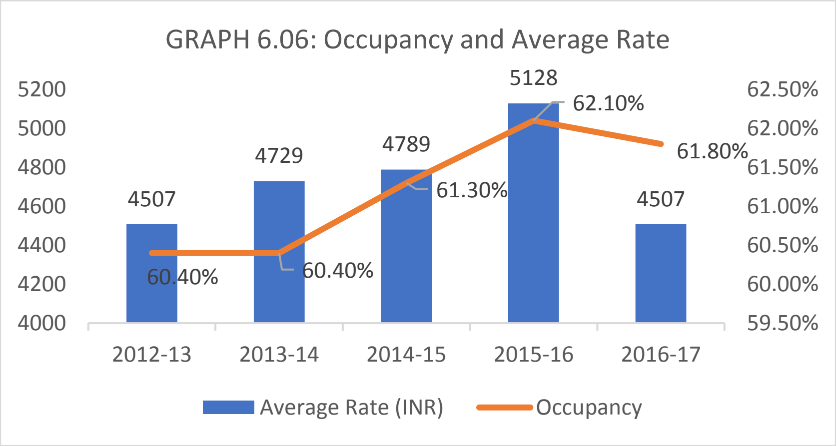

प्रस्तावित कार्य योजना

[125] https://hotelivate.com/hotel-finance/indian-hotel-industry-survey-2016-2017/

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

- भारतीय सरकार की यात्रा और पर्यटन सेवाओं जैसे कि सांस्कृतिक (जैसे कला संग्रहालय), मनोरंजन (जैसे राष्ट्रीय उद्यान), आगंतुकों के लिए निकासी (उदाहरण / आप्रवासन / सीमा शुल्क) पर व्यय सरकार के कुल बजट का 1% है। भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा सुझाए गए अनुमानों के अनुसार, पूँजी निवेश में यात्रा और पर्यटन का योगदान 2016-2026 के दौरान 6.3% प्रतिवर्ष तक बढ़ने की उम्मीद है, जो 4.5% प्रतिवर्ष[126] वैश्विक औसत से अधिक है, **इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय को दुनिया में अपनी मांग को बढ़ावा देने के लिए यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।**

अल्पकालीन योजना

- **विपणन और विज्ञापन**
  - स्कॉटलैंड ने कमीशन-प्राप्त संगीत, टीवी पर विज्ञापनों की एक श्रृंखला के माध्यम से या टैक्सी में या लोकप्रिय समाचार वेबसाइटों और सोशल मीडिया और अन्य प्रचार प्रयासों के माध्यम से कमीशन-प्राप्त संगीत पर लगभग $ 5.6 मिलियन खर्च किए है।[127] विपणन अभियानों पर लाखों खर्च करने से कई देशों के लिए समझ में आता है, जो अपने जीडीपी के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए पर्यटकों पर निर्भर हैं। हालांकि, मामूली निवेश से भी ठोस रिटर्न मिल सकता है। डब्ल्यूटीटीसी की रिपोर्ट[128] के अनुसार, विजिट डेनमार्क अभियान ने प्रत्येक डॉलर के लिए राजस्व में $16 के रिटर्न रिपोर्ट किया हैं, जबकि टूरिज्म आयरलैंड ने अपने टेलीविजन और ऑनलाइन विज्ञापन के लिए 10% का रिटर्न पाया हैं।
  - इसी प्रकार, असम टूरिज्म ने अपने ब्रांड एंबेसडर प्रियंका चोपड़ा के साथ अपना नया मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया है। साढ़े तीन मिनट के यूट्यूब वीडियो संस्करण को जारी किए जाने पर काफी हद तक ध्यान बटोरा है। इस वीडियो के कारण, यह उम्मीद की जाती है कि भारत का पर्यटन बढ़ेगा और यह ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे जापान, सिंगापुर, चीन, थाईलैंड, आदि और असम का दौरा करने के लिए दुनियाभर के प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करेगा। **इसलिए, पर्यटन मंत्रालय ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए**

[126]https://www.ibef.org/download/Tourism-and-Hospitality-January-2018.pdf
[127] https://www.cnbc.com/2016/09/29/tourism-how-much-do-countries-spend-to-attract-tourists.html
[128] https://www.wttc.org/-/media/files/reports/benchmark-reports/the_comparative_economic_impact_of_travel__tourism.pdf

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और / या मनोरंजन और उत्पादन मंत्रालय के साथ मिल कर एक ब्रांड एंबेसडर की मदद से ऐसे विज्ञापन ओर वीडियो से पर्यटन को बढ़ावा दे सकता हैं।

दीर्घकालिक योजना

- **यात्रा और पर्यटन के लिए पर्याप्त आपूर्ति बनाना**
  - जबकि भारत में पर्यटन स्थल के रूप में भारत की मांग को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए, इसे पर्याप्त आपूर्ति के माध्यम से भी पूरक होना चाहिए। बैन एंड कंपनी ने अनुमान लगाया कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय आवक में 20 मिलियन की वृद्धि के साथ, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से वृद्धिशील पर्यटन प्राप्तियों में लगभग 19.9 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी होगी और लगभग 1 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों का निर्माण होगा। भारत दुनिया के पांच सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है, 2030 तक इस वृद्धि को जारी रखते हुए सबसे बड़ा बाजार बनने की योजना है, जिसमें 2026 तक यात्री संख्या 278 मिलियन और 2030 तक 442 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हालांकि, भारत के वर्तमान निवेश के बावजूद, अनुमानित मांग[129] को पूरा करने के लिए आने वाले दशक में अनुमानित $ 1.5 ट्रिलियन के आधारिक संरचना निवेश की आवश्यकता होगी।
  - इस स्तर पर, आधारिक संरचना में निवेश करना सबसे आवश्यक है। हवाई अड्डों से लेकर सड़कों और होटलों से लेकर पर्यटक सेवा आधारिक संरचना तक, आधारिक संरचना विकास आवश्यक है। इसके अलावा, प्रगतिशील कानून को लागू करने और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल आधारिक संरचना सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। **इस प्रकार, पर्यटन मंत्रालय पर्यटन स्थलों (पर्यटक सर्वेक्षण के माध्यम से) की पहचान करने के लिए राज्य विभाग के साथ मिल कर काम कर सकता है, जिसके लिए उनकी विभिन्न सेवाओं में वृद्धि की आवश्यकता है और फिर उन पर्यटन स्थानों के विकास में निवेश कर सकते हैं।**

[129]http://www3.weforum.org/docs/White_Paper_Incredible_India_2_0_final_.pdf

संकेतक 6.03: पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विपणन और ब्रांडिंग की प्रभावशीलता

परिभाषा: पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आपके देश की विपणन और ब्रांडिंग कितनी प्रभावशील है?

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = बिलकुल प्रभावी नहीं हैं, 7 = अत्यंत प्रभावी है)

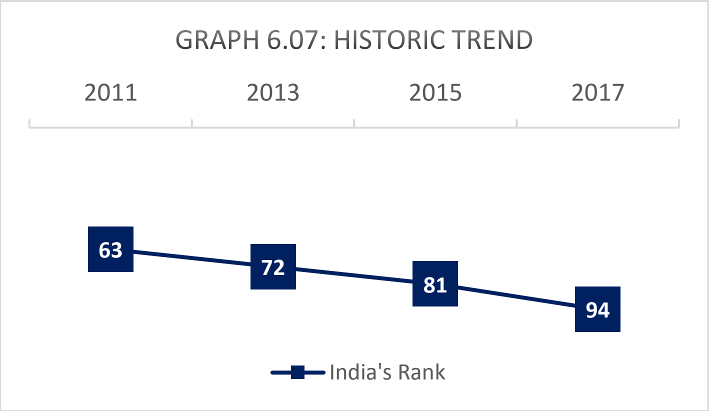

ग्राफ 6.07 संकेतक 6.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 13 स्थान की कमी आई है। यह सूचक देश के स्कोर में 1.25% का योगदान देता है।

तालिका 6.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
संयुक्त अरब अमीरात	1	6.59	1	6.63	शीर्ष प्रदर्शक
न्यूज़ीलैंड	2	6.22	2	6.23	शीर्ष प्रदर्शक
आयरलैंड	5	5.98	3	6.19	शीर्ष प्रदर्शक
ऑस्ट्रेलिया	40	5.09	18	5.37	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
चीन	53	4.84	36	4.92	एशियाई साथी
जर्मनी	76	4.39	61	4.49	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**81**	**4.23**	**94**	**3.78**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- चीन के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग महत्वपूर्ण है, और वीचेट और वीबो महत्वपूर्ण प्लेटफार्म हैं जो इसे गंतव्य पर्यटन उपस्थिति बनाने और संभावित आगंतुकों के साथ जुड़ने में मदद करते हैं। वीचेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जहाँ वे हमारी आईडी को स्कैन कर सकते हैं और वीचेट के माध्यम से हमारे साथ संवाद कर सकते हैं, जबकि दूसरी ओर वीबो मार्केटिंग का एक बेहतरीन मंच है जहाँ बहुत सारे ब्लॉगर, मीडिया संगठन, सरकारी विभाग और उपयोगकर्ता अपने विचारों को साझा करते हैं। इसलिए, भारत की पर्यटन मंत्रालय इसी तरह की तर्ज पर, इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग पर्यटकों को उनकी यात्रा निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए कर सकती है और जहां ट्रैवल ब्रांड उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं, टिप्पणियों और संदेशों का जवाब दे सकते हैं, अच्छी सामग्री साझा कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं की शुरुआत कर सकते हैं। और लक्षित विज्ञापन अभियान वितरित कर सकते है। इसलिए, पहला कदम सही सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एक आधिकारिक खाता स्थापित करना होगा, और फिर विशेषज्ञ रूप से तैयार की गई सामग्री, चित्र, वीडियो, समीक्षा और अन्य लुभावने दृष्टिकोणों को साझा करना शुरू करना होगा।[130]

मध्यम अवधि की योजना

- **विरासत निर्माण के लिए कॉर्पोरेट प्रायोजन की अनुमति दें:** भारतीय पर्यटन के सबसे बड़े आकर्षण में से एक इसकी वास्तुकला और ऐतिहासिक स्मारकों की संपत्ति है, लेकिन इसका नियमित रखरखाव एक अनसुलझी समस्या बनी हुई है। एक जर्मन आधारित कंपनी, कारचर, उनके सांस्कृतिक प्रायोजन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, ऐतिहासिक स्मारकों और इमारतों के संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल है।[131] इसलिए, **उपर्युक्त मुद्दे के लिए एक प्रभावी समाधान स्मारक पर कुछ ब्रांडिंग अवसर के बदले में कारचर जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों को विरासत स्मारक के रखरखाव और बाहरी प्रकाश व्यवस्था को आउटसोर्स करना होगा।**

---

[130] https://www.marketmechina.com/7-tips-for-china-outbound-tourism-success-how-to-market-your-destination-to-chinese-tourists/

[131] https://www.kaercher.com/in/inside-kaercher/sponsoring/cultural-sponsorship.html

दीर्घकालिक योजना

- पर्यटन ऑस्ट्रेलिया टीएंडटी उद्योग और ऑस्ट्रेलिया में सरकार के सभी स्तरों के साथ काम करता है ताकि ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन के आर्थिक योगदान को अधिकतम किया जा सके। उद्योग ने 2009 में $ 69 बिलियन से $ 115 बिलियन और $ 2020 में $ 140 बिलियन के बीच रातोंरात पर्यटन व्यय में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। इसे प्राप्त करने के लिए, पर्यटन ऑस्ट्रेलिया आउट-ऑफ-द-रीजनल ट्रेवल डेस्टिनेशन (जो लक्षित ग्राहकों के तत्काल भौगोलिक क्षेत्र से परे हैं), के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर केंद्रित है। पर्यटन ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, पर्यटन मंत्रालय उन स्थानों की पहचान करने के लिए राज्य विभाग के साथ सहयोग कर सकता है जो सर्वेक्षण के माध्यम से ग्राहकों के लक्ष्य से परे हैं और उन स्थानों को बढ़ावा देते हैं।[132] भारत में कुछ सबसे कम ज्ञात पर्यटक आकर्षण हैं:
    - **जागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड:** जागेश्वर मंदिर परिसर में लगभग 200 मंदिर हैं, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक एचआईवी महादेव के सम्मान में निर्मित हैं। शिव को समर्पित नागेश ज्योतिर्लिंग को भारत में 8 वां द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है।
    - **ऐतिहासिक सिरपुर, छत्तीसगढ़:** सिरपुर शहर महानदी नदी के तट पर स्थित है और यह बौद्ध, जैन और हिंदू का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सिरपुर ऐतिहासिक स्थल के प्रसिद्ध आकर्षणों में लक्ष्मण मंदिर, गंधेश्वर मंदिर और बुद्ध विहार शामिल हैं।
    - **जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश:** जीरो वैली पूरे भारत में सबसे सुंदर परिदृश्यों में से एक है, अरुणाचल प्रदेश के दुर्जेय पर्वतों की पहाड़ियों में स्थित हैं और यह कई पहाड़ियों के साथ भरा हुआ है।
    - **ओरछा, मध्य प्रदेश:** ओरछा एक समय में शक्तिशाली बुंदेलखंड साम्राज्य की राजधानी थी। बुंदेला सरदार, रुद्र प्रताप द्वारा 16 वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, यह स्थान बेतला नदी के तट पर किले के लिए प्रसिद्ध है। अद्भुत वास्तुकला, सुंदर महल और आकर्षक मंदिर एक ऐसा स्थल हैं जिसकी यात्रा करनी ही चाहिए।

[132] http://www.tourism.australia.com/content/dam/assets/document/1/6/w/u/3/2002107.pdf

संकेतक 6.04: वार्षिक टीएंडटी डाटा की व्यापकता.

परिभाषा: इस संकेतक का तात्पर्य है कि यूएनडब्ल्यूटीओ के पर्यटन आंकड़े के संग्रह के सिद्धांतों से 30 विभिन्न अवधारणाओं पर राष्ट्रीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वार्षिक आंकड़ों में से कितने उपलब्ध हैं।

स्रोत: विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)

देश का मूल्य = उपलब्ध आंकड़ों की संख्या (0 = कोई डाटा नहीं, 120 = सभी चयनित संकेतक उपलब्ध हैं)

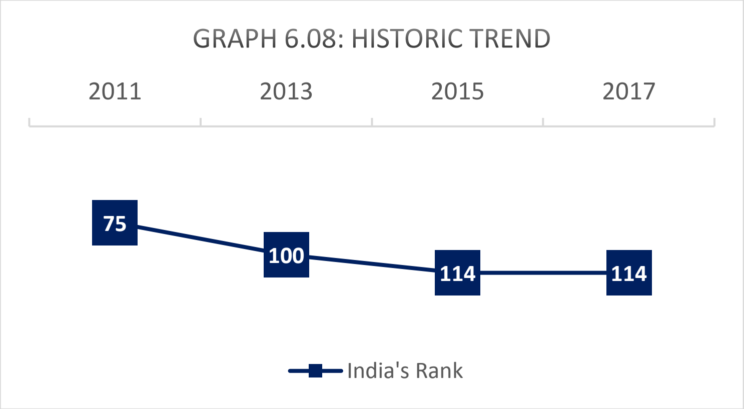

ग्राफ 6.08 संकेतक 6.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी ने अपना 114 वां स्थान बरकरार रखा है। यह सूचक देश के स्कोर में 0.625% का योगदान देता है।

तालिका 6.05: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
सऊदी अरब	1	120	1	116	शीर्ष प्रदर्शक
लिथुआनिया	2	116	2	113	शीर्ष प्रदर्शक
स्पेन	2	116	2	113	शीर्ष प्रदर्शक
मलेशिया	82	61	95	53	एशियाई साथी
भारत	**114**	**43**	**114**	**39**	

स्कोरिंग मानदंड

यूएनडब्ल्यूटीओ के पर्यटन आंकड़े के संग्रह से 30 विभिन्न अवधारणाओं पर राष्ट्रीय प्रशासन द्वारा कितने वार्षिक डाटा प्रदान किए जाते हैं। यह 2012 से 2016 तक प्रदान किए गए डाटा को शामिल करता है। स्कोर न्यूनतम 0 से अधिकतम 120 तक होता है, जहां 120 को एक देश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो कि ध्यान में रखे गए सभी चार वर्षों में सभी 30 अवधारणाओं के लिए डाटा प्रदान करता है। (0 = कोई डाटा नहीं हैं, 120 = सभी चयनित संकेतक उपलब्ध हैं)

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- पिछले कुछ वर्षों से, पर्यटन मंत्रालय आवास विवरण, उसी दिन के पर्यटक, उनकी यात्रा का उद्देश्य, उनके द्वारा अपनाए गए परिवहन के तरीके और प्रति दिन उनके औसत व्यय के लिए डाटा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। **इसलिए, उपरोक्त आंकड़ों पर कब्जा करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए एक केंद्रीकृत ऐप विकसित कर सकता है जो इस डाटा को एकत्र कर सकता है और पर्यटकों को डाटा भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए होटलों में छूट जैसे कुछ प्रचार लाभ प्रदान कर सकता है।**

मध्यम अवधि की योजना

- पर्यटन मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों के बारे में डाटा एकत्र करने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न सर्वेक्षण आयोजित करता है और इसे पर्यटन के आर्थिक प्रभाव को मापने 'पर एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है: पर्यटक मांग को मापने के लिए पर्यटन उपग्रह उपयोग में लिया जाता हैं। भारत का पर्यटन नीचे उल्लिखित तीन सर्वेक्षणों का भी अनुसरण कर सकता है जिनका कि मलेशिया उपयोग करता था।
    - **प्रस्थान आगंतुक सर्वेक्षण (डीवीएस):** पर्यटक व्यय और जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल की गणना के लिए चुनिंदा निकास बिंदुओं पर विदेशी पर्यटकों पर एक सर्वेक्षण।
    - **भ्रमणकर्ता सर्वेक्षण: भ्रमणकर्ता** एक दिन के सैलानी होते हैं जो 24 घंटे से कम समय बिताते हैं। यह सर्वेक्षण चुनिंदा सीमावर्ती शहरों में किया जाता है।
    - **डोमेस्टिक पर्यटन सर्वेक्षण:** यह सर्वेक्षण डेमोग्राफिक प्रोफाइल, उद्देश्य, व्यय आदि पर केंद्रित घरेलू पर्यटन के बारे में डाटा एकत्र करने के लिए है।

इन सर्वेक्षणों के माध्यम से, निम्नलिखित डाटा समस्याओं को हल किया जा सकता है:

- खर्च के बारे में डाटा
- आगंतुकों की संख्या
- ट्रिप्स और अवधि की संख्या
- यात्रा पैटर्न

- जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल[133]

दीर्घकालिक योजना

- **पैन इंडिया होटल और ट्रैवल एजेंसी सर्वेक्षण**
    - हाल ही में, आगरा और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों के नगर निगम ने सर्वेक्षण किया और शहर में अवैध रूप से संचालित होटलों, लॉज, पीजी और गेस्ट हाउस की पहचान की। **इसी तरह की तर्ज पर, पर्यटन मंत्रालय भी उचित डाटा संग्रह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीसरे पक्ष की मदद से होटल और ट्रैवल एजेंसियों के लिए पैन इंडिया सर्वेक्षण कर सकता है, जिससे प्रशासन को डिफॉल्टरों पर नकेल कसने में मदद मिल सके।** एक तीसरे पक्ष द्वारा आयोजित पैन इंडिया होटल सर्वेक्षण न केवल अपंजीकृत होटल और ट्रैवल एजेंसियों के बारे में डाटा प्रदान करेगा, बल्कि मालिकों द्वारा पंजीकरण न कराने के कारण को ट्रैक करने में भी मदद कर सकता है। सर्वेक्षण में निम्नलिखित कुछ प्रश्न शामिल होने चाहिए:
        - उद्घाटन का वर्ष
        - बुकिंग की संख्या
        - कमरों की संख्या
        - सुविधाएं
        - होटल / ट्रैवल एजेंसी को पंजीकृत नहीं कराने का कारण
        - अनुमानित आय
        - क्षेत्र आदि

संदर्भ तालिका

निम्न तालिका वार्षिक आंकड़ों को दर्शाती है जिसे सरकार को यूएनडब्ल्यूटीओ को प्रदान करना होता है।

क्रमांक	आंकड़ों कि लिए यूएनडब्ल्यूटीओ के लिए प्रदान की गयी अवधारणा	यूएनडब्ल्यूटी को दिया गया डाटा
1.	**आंतरिक पर्यटन**	
	डाटा	

[133] http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/item_9_malaysia.pdf

	आगमन	
1.1	कुल	
1.2	◆ ओवरनाइट आगंतुक (पर्यटक)	हां
1.3	◆ उसी दिन के आगंतुक (भ्रमणकर्ता)	नहीं
1.4	* जिनमें से, क्रूज यात्री	
	क्षेत्र द्वारा आगमन	
1.5	कुल	हां
1.6	◆ अफ्रीका	हां
1.7	◆ अमेरिका	हां
1.8	◆ पूर्वी एशिया और प्रशांत	हां
1.9	◆ यूरोप	हां
1.10	◆ मध्य पूर्व	हां
1.11	◆ दक्षिण एशिया	हां
1.12	◆ अन्य वर्गीकृत नहीं	हां
1.13	* इनमे से, विदेश में रहने वाले नागरिक	हां
	मुख्य उद्देश्य से आगमन	
1.14	कुल	हां
1.15	◆ व्यक्तिगत	हां
1.16	* छुट्टियां, अवकाश और मनोरंजन	हां
1.17	* अन्य व्यक्तिगत उद्देश्य	हां
1.18	◆ व्यापार और पेशेवर	हां
	परिवहन के माध्यम से आगमन	

1.19	कुल	हां
1.20	◆ वायु	हां
1.21	◆ पानी	हां
1.22	◆ भूमि	हां
1.23	* रेलवे	हां
1.24	* सड़क	हां
1.25	* अन्य	भारत के मामले में लागू नहीं हैं
	यात्रा के संगठन के रूप में आगमन	
1.26	कुल	हां
1.27	◆ पैकेज टूर	हां
1.28	◆ अन्य रूप	हां
	आवास	
	कुल	नहीं
1.29	◆ मेहमान	नहीं
1.30	◆ ओवरनाइट्स	नहीं
	होटल और इसी तरह के प्रतिष्ठान	नहीं
1.31	◆ मेहमान	नहीं
1.32	◆ ओवरनाइट्स	नहीं
	व्यय	
1.33	कुल	हां
1.34	◆ यात्रा	हां

1.35	◆ यात्री परिवहन	हां
	यात्रा के मुख्य उद्देश्य से व्यय	
1.36	कुल	हां
1.37	◆ व्यक्तिगत	हां
1.38	◆ व्यापार और पेशेवर	हां
	संकेतक	
1.39	यात्रा पार्टी का औसत आकार	हां
	रहने की औसत लंबाई	हां
1.40	कुल	
1.41	◆ सभी वाणिज्यिक आवास सेवाओं के लिए	नहीं
1.42	* इनमें से किस, "होटल और समान प्रतिष्ठान"	नहीं
1.43	◆ गैर-वाणिज्यिक आवास सेवाओं के लिए	
1.44	प्रति दिन औसत व्यय	हां

2. घरेलू पर्यटन

	डाटा	
	यात्राएं	
2.1	कुल	नहीं
2.2	◆ ओवरनाइट आगंतुक (पर्यटक)	हां
2.3	◆ उसी दिन के आगंतुक (भ्रमणकर्ता)	नहीं
	मुख्य उद्देश्य से यात्राएं	
2.4	कुल	

2.5	◆ व्यक्तिगत	नहीं
2.6	* छुट्टियां, अवकाश और मनोरंजन	नहीं
2.7	* अन्य व्यक्तिगत उद्देश्य	नहीं
2.8	◆ व्यापार और पेशेवर	नहीं
	परिवहन के मोड द्वारा यात्राएं	
2.9	कुल	
2.10	◆ वायु	नहीं
2.11	◆ पानी	नहीं
2.12	◆ भूमि	नहीं
2.13	* रेलवे	नहीं
2.14	* सड़क	नहीं
2.15	* अन्य	नहीं
	संगठन के रूप में यात्राएं	
2.16	कुल	
2.17	◆ पैकेज टूर	नहीं
2.18	◆ अन्य प्रकार	नहीं
	आवास	
	कुल	
2.19	◆ मेहमान	नहीं
2.20	◆ ओवरनाइट्स	नहीं
	होटल और इसी तरह के प्रतिष्ठान	नहीं
2.21	◆ मेहमान	नहीं

2.22	◆ ओवरनाइट्स	नहीं
	संकेतक	
2.23	यात्रा दल का औसत आकार	नहीं
	रहने की औसत लंबाई	नहीं
2.24	कुल	नहीं
2.25	◆ सभी वाणिज्यिक आवास सेवाओं के लिए	नहीं
2.26	* जिनमें से, "होटल और समान प्रतिष्ठान"	नहीं
2.27	◆ गैर-वाणिज्यिक आवास सेवाओं के लिए	नहीं
2.28	औसत व्यय प्रति दिन	नहीं
3.	**आउटबाउंड पर्यटन**	
	डाटा	
	प्रस्थान	
3.1	कुल	
3.2	◆ ओवरनाइट आगंतुक (पर्यटक)	हां
3.3	◆ उसी दिन के आगंतुक (भ्रमणकर्ता)	नहीं
	व्यय	
3.4	कुल	हां
3.5	◆ यात्रा	हां
3.6	◆ यात्री परिवहन	हां
	यात्रा के मुख्य उद्देश्य से व्यय	
3.7	कुल	हां

3.8	◆ व्यक्तिगत	हां
3.9	◆ व्यापार और पेशेवर	हां
	संकेतक	
3.10	रहने की औसत लंबाई	
3.11	प्रति दिन औसत व्यय	
4.	**पर्यटन उद्योग**	
	डाटा	
	प्रतिष्ठानों की संख्या	
4.1	कुल	
4.2	◆ आगंतुकों के लिए आवास	नहीं
4.3	* जिनमें से, "होटल और समान प्रतिष्ठान "	हां
4.4	◆ खाद्य और पेय पदार्थ सेवारत गतिविधियाँ	नहीं
4.5	◆ पैसेंजर परिवहन	नहीं
4.6	◆ यात्रा एजेंसियां और अन्य आरक्षण सेवा गतिविधियाँ	नहीं
4.7	◆ अन्य पर्यटन उद्योग	नहीं
	होटल और इसी तरह के प्रतिष्ठानों में आगंतुकों के लिए आवास	
	मौद्रिक डाटा	नहीं
4.8	◆ आउटपुट	नहीं
4.9	◆ मध्यवर्ती खपत	नहीं
4.10	◆ सकल मूल्य जोड़ा गया हैं	नहीं
4.11	◆ कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति	नहीं

4.12	◆ सकल निश्चित पूंजी निर्माण	नहीं
	गैर-मौद्रिक डाटा	
4.13	◆ प्रतिष्ठानों की संख्या	हां
4.14	◆ कमरों की संख्या	हां
4.15	◆ बिस्तर-स्थानों की संख्या	हां
	संकेतक	
4.16	अधिग्रहण दर / कमरे	नहीं
4.17	अधिग्रहण दर / बिस्तर-स्थान	नहीं
4.18	रहने की औसत लंबाई	नहीं
4.19	उपलब्ध क्षमता (प्रति 1000 निवासियों पर बिस्तर-स्थान)	हां
	ट्रैवल एजेंसियां और अन्य आरक्षण सेवा गतिविधियां	
	मौद्रिक डाटा	
4.20	◆ आउटपुट	नहीं
4.21	◆ मध्यवर्ती खपत	नहीं
4.22	◆ सकल जोड़ा गया मूल्य	नहीं
4.23	◆ कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति	नहीं
4.24	◆ सकल निश्चित पूंजी निर्माण	नहीं
	गैर-मौद्रिक डाटा	
	◆ घरेलू यात्राएँ	
4.25	* पैकेज टूर के साथ	
4.26	* बिना पैकेज टूर के	
	◆ इनबाउंड यात्राएँ	

4.27	⁎ पैकेज टूर के साथ	
4.28	⁎ बिना पैकेज टूर के	
	◆ आउटबाउंड यात्राएं	
4.29	⁎ पैकेज टूर के साथ	
4.30	⁎ पैकेज टूर के बिना	
5.	**रोजगार**	
	डाटा	
	पर्यटन उद्योगों द्वारा कर्मचारियों की संख्या	
5.1	कुल	
	◆ आगंतुकों (होटल और इसी तरह के प्रतिष्ठानों) के लिए	
5.2	आवास सेवाएं	हां
5.3	◆ अन्य आवास सेवाएँ	हां
5.4	खाद्य और पेय पदार्थ परोसने वाली गतिविधियाँ	हां
5.5	◆ पैसेंजर परिवहन	हां
5.6	◆ ट्रैवल एजेंसियां और अन्य आरक्षण सेवाओं की गतिविधियाँ	हां
5.7	◆ अन्य पर्यटन उद्योग	हां
	रोजगार में स्थिति द्वारा नौकरियों की संख्या	
5.8	कुल	
5.9	◆ कर्मचारी	हां
5.10	◆ स्वरोजगार	हां
	संकेतक	

	रोजगार में स्थिति द्वारा पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों की संख्या	
5.11	कुल	हां
5.12	◆ कर्मचारी	हां
5.13	* पुरुष	हां
5.14	* महिला	हां
5.15	◆ स्वरोजगार	हां
5.16	* पुरुष	हां
5.17	* महिला	हां
6.	**पूरक संकेतक**	
	मांग	
6.1	सकल यात्रा प्रवृत्ति	हां
6.2	(1.2 इनबाउंड पर्यटक + 2.2 घरेलू पर्यटक) / जनसंख्या	हां
	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से संबंधित मैक्रोइकॉनोमिक संकेतक	
6.3	जीडीपी पर इनबाउंड पर्यटन व्यय	हां
6.4	जीडीपी पर आउटबाउंड पर्यटन व्यय	हां
6.5	जीडीपी से अधिक जीडीपी पर 6.5 पर्यटन संतुलन (इनबाउंड - आउटबाउंड पर्यटन व्यय)	हां
6.6	जीडीपी से अधिक जीएसटी पर पर्यटन का खुलापन (इनबाउंड + आउटबाउंड पर्यटन व्यय)	हां
6.7	पर्यटन कवरेज (इनबाउंड पर आउटबाउंड पर्यटन व्यय)	हां
6.8	वस्तुओं के निर्यात पर इनबाउंड पर्यटन व्यय	हां
6.9	वाओं के निर्यात पर इनबाउंड पर्यटन व्यय	हां

6.10	माल और सेवाओं के निर्यात पर इनबाउंड पर्यटन व्यय	हां
6.11	चालू खाता क्रेडिट पर इनबाउंड पर्यटन व्यय	हां
6.12	माल के आयात पर आउटबाउंड पर्यटन व्यय	हां
6.13	सेवाओं के आयात पर आउटबाउंड पर्यटन व्यय	हां
6.14	वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर आउटबाउंड पर्यटन व्यय	हां
6.15	आउटबाउंड पर्यटन व्यय पर चालू खाता डेबिट	हां

संकेतक 6.05: मासिक / त्रैमासिक टीएंडटी डाटा प्रदान करने की समयबद्धता

परिभाषा: यह संकेतक मासिक या तिमाही आधार पर दो प्रमुख टीएंडटी संकेतकों (अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन और पर्यटन प्राप्तियां) की उपलब्धता को संदर्भित करता है।

स्रोत: विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)

देश का मूल्य = उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों की संख्या (0 = कोई डाटा नहीं, 22.5 = मानी गयी सभी अवधियों के लिए रिपोर्ट किया गया डाटा)

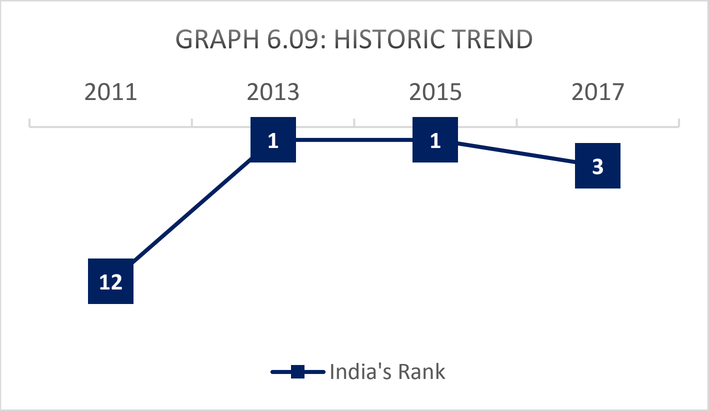

ग्राफ 6.09 संकेतक 6.05 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 2 पदों की कमी हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.625% का योगदान देता है।

तालिका 6.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
उरुग्वे	1	21	1	22.5	शीर्ष प्रदर्शक
वियतनाम	86	14	1	22.5	एशियाई साथी
भारत	**1**	**21**	**3**	**22**	

विश्व पर्यटन बैरोमीटर: स्कोरिंग मानदंड

- यूएनडब्ल्यूटीओ विश्व पर्यटन बैरोमीटर[134] विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) का एक प्रकाशन है जो वैश्विक पर्यटन हितधारकों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पर ताजा विश्लेषण प्रदान करने के लिए नियमित आधार पर अल्पकालिक पर्यटन रुझानों की निगरानी करता है।
- यूएनडब्ल्यूटीओ प्रत्येक सरकार को एक ईमेल भेजकर विभिन्न देशों की सरकार से डाटा एकत्र करता है जहां उन्हें पर्यटन से संबंधित डाटा भरने के लिए कहा जाता है। विशेष रूप से, इस सूचक के लिए डब्ल्यूईएफ़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक रसीद के लिए डाटा जमा करने के लिए सरकार के नियामक के आधार पर अंक देता है।
- यूएनडब्ल्यूटीओ ने प्रत्येक उपलब्ध देश के स्कोर की गणना नवीनतम उपलब्ध यूएनडब्ल्यूटीओ विश्व पर्यटन बैरोमीटर में शामिल महीनों के आंकड़ों के आधार पर की है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन पर डाटा महीनों की संख्या के लिए उपलब्ध है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों पर डाटा उपलब्ध हैं। आधा भार दो अंकों के निचले हिस्से पर लागू किया गया है, इसलिए स्कोर न्यूनतम 0 से अधिकतम 22.5 तक है।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

मध्यम अवधि की योजना

- भारत समय के आधार पर यूएनडब्ल्यूटीओ को डाटा प्रदान करता है जिसने भारत को दुनिया में तीसरा स्थान प्राप्त करने में मदद की है। भारत अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आधार पर डाटा प्रदान कर रहा है, लेकिन उसी दिन के पर्यटकों के लिए डाटा प्रदान करने में कमी है, जिसके कारण भारत ने 22.5 में से 22 अंक बनाए हैं। उसी दिन के पर्यटक की डाटा की इस समस्या को नीचे बताई गई विधि के माध्यम से हल किया जा सकता है:

भारत आने वाले पर्यटकों के लिए डाटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत ऐप का विकास:

  - विदेशी पर्यटकों के लिए एक केंद्रीकृत ऐप का विकास, यात्रा के स्थान, यात्रा विवरण, परिवहन का तरीका, अनुमानित बजट आदि के लिए डाटा प्राप्त करना, जो भारत आने वाले पर्यटकों के लिए डाटा को ट्रैक करेगा।
  - विदेशी पर्यटकों को उनकी सुरक्षा और सटीक डाटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए ऐप पर डाटा अपलोड करना अनिवार्य किया जा सकता है। यह क्रूजर और दैनिक यात्रियों से संबंधित डाटा सुनिश्चित करेगा।

[134]http://www2.unwto.org/ca/node/50680

- पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक विदेशी पासपोर्ट के खिलाफ चिह्नित आगमन और प्रस्थान के डाटा के माध्यम से उसी दिन के पर्यटकों का डाटा प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय / आप्रवासन मंत्रालय के साथ सहयोग कर सकता है।

संकेतक 6.06: देशीय ब्रांड रणनीति श्रेणी

परिभाषा: यह संकेतक राष्ट्रीय पर्यटन संगठनों (एनटीओ) की रणनीति की सटीकता का मूल्यांकन एक सूत्र द्वारा करता है जो एक विशिष्ट देश के लिए सबसे लोकप्रिय ब्रांड टैग्स (जैसा कि मालिकाना डिजिटल डिमांड डी 2 टूल द्वारा मापा जाता है) की तुलना में ब्रांड टैगों द्वारा सबसे अधिक प्रचारित किया जाता है। उस देश का एनटीओ अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों से उच्चतम मांग (कुल ऑनलाइन खोजों द्वारा मापा जाता है) के साथ पर्यटन से संबंधित ब्रांड टैग पर अपनी रणनीतिक और प्रचार स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है, तो एक उच्च रेटिंग प्राप्त करता है। एक खराब रेटिंग एनटीओ द्वारा या तो कम से कम लोकप्रिय ब्रांड टैग (कुल ऑनलाइन खोजों द्वारा मापा गया) के अनुचित प्रचार का सुझाव दे सकती है या उच्चतम मांग में ब्रांड टैग पर ध्यान देने की कमी है।

स्रोत: ब्लूम परामर्श देशीय ब्रांड श्रेणी आईएनजी, पर्यटन संस्करण

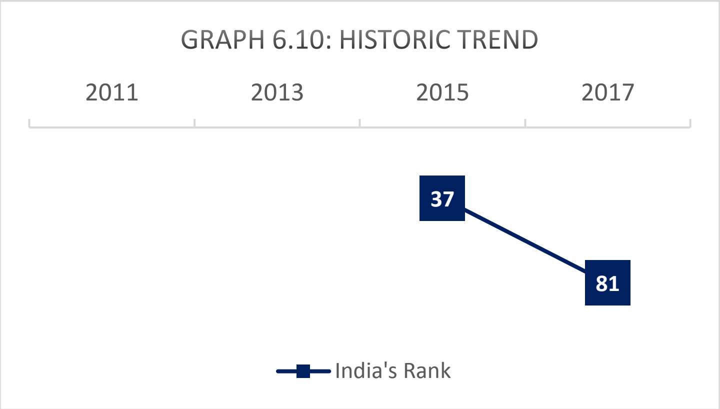

ग्राफ 6.10 सूचक 6.06 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 44 पदों की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 1.25% का योगदान देता है।

तालिका 6.07: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	सीबीएस श्रेणी *	कारण
पैराग्वे	3	97.6	1	98.8	एएए	शीर्ष प्रदर्शक
जर्मनी	1	100	2	95.55	एए	शीर्ष प्रदर्शक
लक्समबर्ग g	5	93.6	3	94.43	एएए	शीर्ष प्रदर्शक
ऑस्ट्रेलिया	81	65	71	74.04	ए	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

भारत	37	77.3	81	72.55	बीबीबी	

देशीय ब्रांड रणनीति (सीबीएस) श्रेणी: बहुत मजबूत - एएए, मजबूत - एए, थोड़ा मजबूत - ए, बहुत अच्छा - बीबीबी, अच्छा - बीबी, थोड़ा अच्छा - बी[135]

[135]https://www.bloom-consulting.com/pdf/rankings/Bloom_Consulting_Country_Brand_Ranking_Tourism.pdf

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **पर्यटन मंत्रालय को बड़े पैमाने पर विपणन के बजाय तेजी से केंद्रित विपणन अभियानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।** यह भारत के विपणन खर्च की दक्षता में सुधार करेगा, एक मजबूत ब्रांड उपस्थिति को बनाए रखने में मदद करेगा और मौसमी कारक को संबोधित करेगा। पर्यटन मंत्रालय को तेजी से केंद्रित विपणन योजनाओं को विकसित करने के लिए पीआर फर्मों और / या विपणन एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए जो नए बाजारों को खोजने की उम्मीद में कम-ज्ञात ब्रांड टैग को उजागर करने में सहायक होंगे। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष रूप से विपणन किया जा सकता है:
    - **ग्रामीण पर्यटन:** भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास की संभावना अधिक है क्योंकि इसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यह स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ पहुंचा सकता है, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच पारस्परिक रूप से समृद्ध अनुभव के लिए बातचीत कर सके।
    - **पर्यावरणीय पर्यटन:** भारत को अक्सर जैव-विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है और यह प्राकृतिक विरासत कई मायनों में अविश्वसनीय है। इस तरह के मूल्यवान संसाधन आधार वैकल्पिक पर्यटन रूपों की विविधता के अभ्यास के लिए प्रेरणा देते हैं और जिनमें से कई पहले से ही अस्तित्व में हैं। उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जीवमंडल भंडार[136]।

मध्यम अवधि की योजना

- **D2 उपकरण की सदस्यता लें**[137]
    - D2© एक बिग डाटा कंपनी है जो देशों, क्षेत्रों और शहरों के बारे में विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। उनका मालिकाना सॉफ्टवेयर देशों, क्षेत्रों और शहरों की ओर वैश्विक स्तर पर की गई सभी खोजों को इकट्ठा करता है और इसकी अपील को प्रकट करता है। हर साल, डिजिटल देश और डिजिटल सिटी इंडेक्स को पर्यटन, निवेश, निर्यात, प्रतिभा और

[136] https://www.ibef.org/download/Tourism-and-Hospitality-January-2018.pdf
[137]https://www.weforum.org/agenda/2017/10/india-tourism/

राष्ट्रीय प्रमुखता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रुचि और देशों के प्रदर्शन और शहरों के आधार पर मापा जाता है।

- पर्यटन उपकरणों के लिए D2- टूल को स्वीडन, पुर्तगाल, जर्मनी, जर्मनी, कोस्टा रिका, यूरोपीय यात्रा आयोग आदि के पर्यटन संगठनों द्वारा सदस्यता ली गई है, **पर्यटन मंत्रालय भी इस उपकरण की सदस्यता ले सकता है ताकि विभिन्न लक्षित बाजार अवलोकन के लिए विश्लेषण से जानकारी प्राप्त की जा सके।**

दीर्घकालिक योजना

- Australia.com अब फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय गंतव्य पृष्ठों में से एक है, जिसके छह मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं। उन्होंने कई दिलचस्प तकनीकों को अपनाया है जिन्होंने अपनी अपील को बढ़ाया है और दुनिया भर से लाखों फॉलोवर्स को आकर्षित किया है। भारत भी निम्नलिखित तरीकों से अपनी सीबीएस रेटिंग बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग रणनीतियों को अपना सकता है:
  - **एक उत्कृष्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम को हायर करें**
    पर्यटन मंत्रालय australia.com जैसी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम को काम पर रख सकता है जो प्रवीण, भावुक और रचनात्मक होनी चाहिए, जब यह उनके फॉलोवर्स तक पहुंच सके। यह मंत्रालय को व्यापक रूप से इसके अनुसरण में विस्तार करने और अंतर्राष्ट्रीय अपील प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
  - **सामग्री के लिए अनुयायियों पर भरोसा करें**
    एक अन्य रणनीति का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है जहां भारत किसी भी स्थान पर आने वाले विभिन्न पर्यटकों द्वारा भेजे गए फ़ोटो को प्रकाशित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर सकता है। फिर, मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सबसे अच्छी छवियां प्रकाशित की जाएंगी। इस पद्धति के माध्यम से, मंत्रालय स्वचालित रूप से पर्यटक को ब्रांड के साथ भारी रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।[138]. इसी तरह की पहल ऑस्ट्रेलिया ने अपने australia.com के प्लेटफार्म के साथ भी की है।

---

[138]https://www.8ways.ch/en/digital-news/3-social-media-marketing-lessons-tourism-australia/

- राष्ट्रीय प्रमुखता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रुचि और देशों के प्रदर्शन और शहरों के आधार पर मापा जाता है।
- पर्यटन उपकरणों के लिए D2- टूल को स्वीडन, पुर्तगाल, जर्मनी, कोस्टा रिका, यूरोपीय यात्रा आयोग आदि के पर्यटन संगठनों द्वारा सदस्यता ली गई है, **पर्यटन मंत्रालय भी इस उपकरण की सदस्यता ले सकता है ताकि विभिन्न लक्षित बाजार अवलोकन के लिए विश्लेषण से जानकारी प्राप्त की जा सके।**

दीर्घकालिक योजना

- Australia.com अब फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय गंतव्य पृष्ठों में से एक है, जिसके छह मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं। उन्होंने कई दिलचस्प तकनीकों को अपनाया है जिन्होंने अपनी अपील को बढ़ाया है और दुनिया भर से लाखों फॉलोवर्स को आकर्षित किया है। भारत भी निम्नलिखित तरीकों से अपनी सीबीएस रेटिंग बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग रणनीतियों को अपना सकता है:
    - **एक उत्कृष्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम को हायर करें**
      पर्यटन मंत्रालय australia.com जैसी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम को काम पर रख सकता है जो प्रवीण, भावुक और रचनात्मक होनी चाहिए, जब यह उनके फॉलोवर्स तक पहुंचc सके। यह मंत्रालय को व्यापक रूप से इसके अनुसरण में विस्तार करने और अंतर्राष्ट्रीय अपील प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
    - **सामग्री के लिए अनुयायियों पर भरोसा करें**
      एक अन्य रणनीति का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है जहां भारत किसी भी स्थान पर आने वाले विभिन्न पर्यटकों द्वारा भेजे गए फ़ोटो को प्रकाशित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर सकता है। फिर, मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सबसे अच्छी छवियां प्रकाशित की जाएंगी। इस पद्धति के माध्यम से, मंत्रालय स्वचालित रूप से पर्यटक को ब्रांड के साथ भारी रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।[139]. इसी तरह की पहल ऑस्ट्रेलिया ने अपने australia.com के प्लेटफार्म के साथ भी की है।

[139]https://www.8ways.ch/en/digital-news/3-social-media-marketing-lessons-tourism-australia/

<u>स्तंभ 7: अंतर्राष्ट्रीय खुलापन</u>

परिभाषा: यह स्तंभ मापता है कि किसी देश में यात्रा और सेवाओं के लिए कोई देश कितना खुला है। स्तंभ 7 के नीचे कुल 3 संकेतक हैं --

1. वीज़ा की आवश्यक्ताएं
2. द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों का खुलापन
3. बल में क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की संख्या

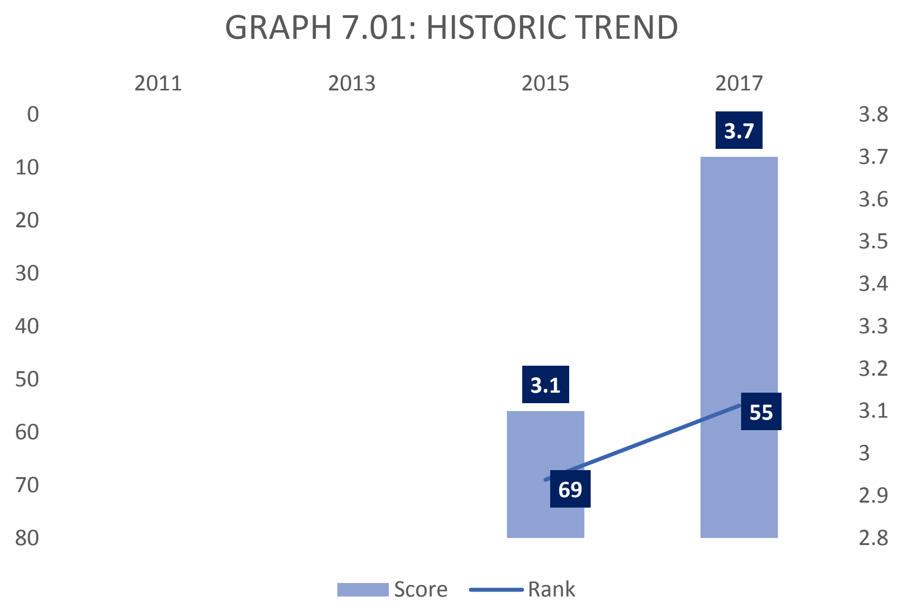

ग्राफ 7.01 स्तंभ 7. में भारत की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह स्तंभ 2015 में पेश किया गया था। भारत की श्रेणी 2015 में 69 वें स्थान से बढ़कर 2017 में 55 वें स्थान पर पहुंच गई है।

भार की स्थिति में बदलाव:

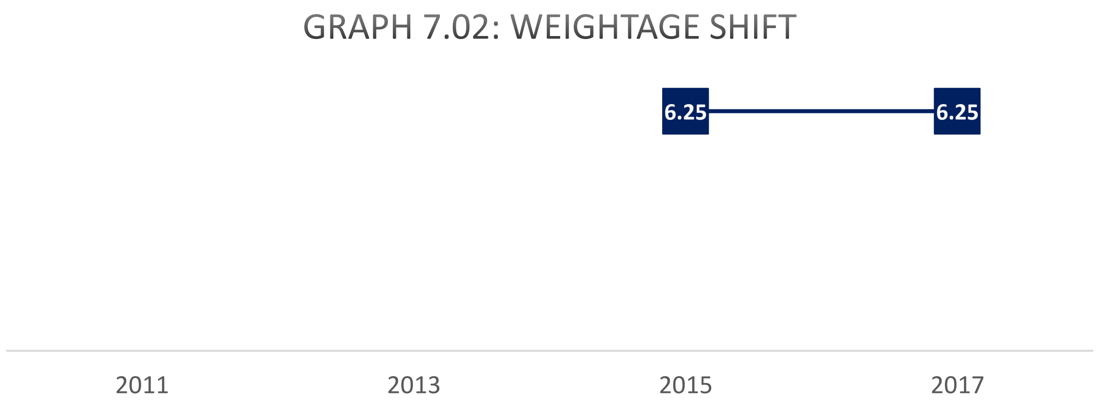

ग्राफ 7.02 स्तंभ 7 के समग्र योगदान को इंगित करता है यानी भारत के स्कोर में अंतर्राष्ट्रीय खुलापन। वर्तमान में, इस स्तंभ को 2017 में भारत के समग्र स्कोर में 6.25% भार दिया गया है।

तालिका 7.01: संकेतक वार भार की स्थिति में बदलाव

संकेतक	2011-2013 (%)	2015-2017 (%)	भार की स्थिति में बदलाव (%)
वीज़ा आवश्यकताएं	0.74	2.08	181
द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों का खुलापन	0.74	2.08	181
बल में क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की संख्या	NA	2.08	NA

NA लागू नहीं है क्योंकि उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

ये संकेतक 2013 तक स्तंभ 1 (नीति नियम और विनियम) में मौजूद थे, लेकिन वर्ष 2015 में, स्तंभ "नीति नियम और विनियम" को भंग कर दिया गया था और "अंतर्राष्ट्रीय खुलेपन" नाम से एक नया स्तंभ बनाया गया था, जहां इन 3 संकेतकों को पेश किया गया था।

तालिका 7.01 उस योगदान का प्रतिशत दर्शाती है कि प्रत्येक संकेतक का भारत के समग्र स्कोर पर है।

संकेतक 7.01: वीज़ा आवश्यकताएं

परिभाषा: यह संकेतक दुनिया भर के स्रोत बाजारों से आगंतुकों के लिए सीमित अवधि की पर्यटन यात्रा के लिए गंतव्य देश में प्रवेश के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को मापता है। यह इस बात को ध्यान में रखता है कि गंतव्य देश अपनी वीज़ा नीति के माध्यम से गंतव्य इनबाउंड पर्यटन के सुविधा देता है, यह देखते हुए कि क्या देश में बिना वीज़ा के यात्रा की जा सकती है, आगमन पर वीज़ा प्राप्त किया जा सकता है या एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा उपलब्ध है।

मूल्य =

$$\frac{(\text{वीज़ा से PoC की छूट X 1}) + (\text{PoC ने आगमन पर वीज़ा दिया} \times 0.7) + (\text{PoC जिसमें ई–वीज़ा का उपयोग होता है} \times 0.5)\ x\ 100}{\text{कुल विश्व जनसंख्या द्वारा स्रोत देश का दौरा}}$$

**PoC का मतलब होता है पॉपुलेशन ऑफ़ सोर्स कंट्रीज़*

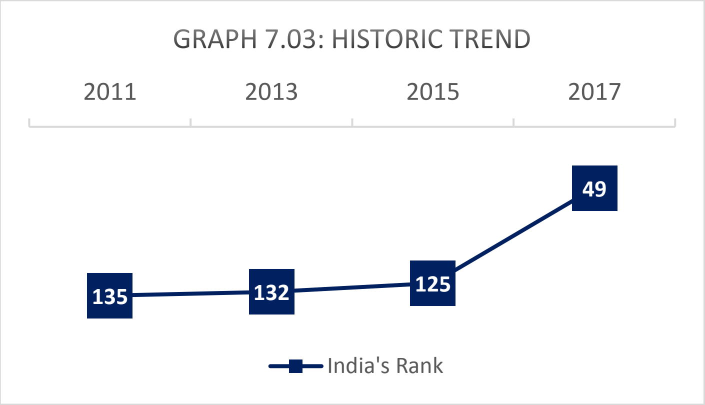

ग्राफ 7.03 सूचक 7.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 76 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 2.08% का योगदान देता है।

तालिका 7.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य(2017)	कारण
इक्वाडोर	NA	NA	1	89	शीर्ष प्रदर्शक
इंडोनेशिया	28	53	2	86	एशियाई साथी
हांगकांग SAR	3	80	3	80	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**125**	**9**	**49**	**37**	

गणना में बदलाव

2013 तक, इस संकेतक की गणना विभिन्न वीज़ा आवश्यकताओं वाले देशों की कुल संख्या के रूप में की गई थी, लेकिन 2015 के बाद से इसे वीज़ा आवश्यकताओं के साथ जनसंख्या के प्रतिशत में बदल दिया गया है।

सरकारी पहल

- भारत सरकार ने 27.11.2014 को 43 देशों के लिए ऑनलाइन ई-टूरिस्ट वीज़ा पेश किया था। इसके अलावा, भारत में वीज़ा व्यवस्था के उदारीकरण और सरलीकरण के तहत, पर्यटक, व्यवसाय और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ई-वीज़ा योजना को लागू किया गया है।
- 2018 तक, भारत सरकार की वीज़ा नीतियां तीन श्रेणियों के बीच बांटा जाता हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:
    - **वीज़ा से छूट**
        - भारत 2 देशों जैसे नेपाल और भूटान के नागरिकों को बिना वीज़ा के प्रवेश की अनुमति दे रहा है।
    - **आगमन पर वीज़ा**
        - वीज़ा ऑन अराइवल 2 देशों के नागरिकों के लिए प्रदान किया जाता है, जैसे कि जापान और दक्षिण कोरिया, वह भी केवल छह नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात् बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में।
    - **इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा**
        - ई-वीज़ा रखने वाले व्यक्तियों को केवल 26 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 5 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की अनुमति है, जबकि ई-वीज़ा रखने वाले ऐसे व्यक्ति भारत[140] में किसी भी अधिकृत आवासन चेक पोस्ट से प्रस्थान कर सकते हैं।
        - पात्र देशों / क्षेत्रों के आवेदक 120 देशों की खिड़की के साथ आगमन की तारीख से न्यूनतम 4 दिन पहले ऑनलाइन लागू कर सकते हैं। ई-वीज़ा के तहत भारत में रहने की अवधि भारत में आगमन के दिन से अधिकतम 60 दिन है। ई-वीज़ा का लाभ एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार लिया जा सकता है यानी जनवरी से दिसंबर के बीच।

[140] https://mha.gov.in/PDF_Other/AnnexIII_01022018.pdf

- ई-मेडिकल वीज़ा के मामले में, संबंधित विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (ऍफ़आरआरओ) / विदेशियों के पंजीकरण अधिकारी (ऍफ़आरओ) द्वारा प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर 6 महीने तक के लिए विस्तार दिया जा सकता है।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: गृह मंत्रालय | आप्रवासन ब्यूरो

दीर्घकालिक योजना

- **इंवीज़ा की छूट के लिए इंडोनेशिया की नीति**
    - 2018 तक, इंडोनेशिया 140 देशों के नागरिकों को एक क्लॉज के साथ वीज़ा की छूट प्रदान कर रहा है कि यात्रा का उद्देश्य पर्यटन हो सकता है और यात्रा केवल 30 दिन की अधिकतम समय अवधि के लिए हो सकती है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हालाँकि, आगमन पर वीज़ा 60 देशों के नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जहां पर्यटक 60 दिनों से अधिक तक नहीं रह सकते हैं।[141]
    - इसी प्रकार, विदेश और गृह मंत्रालय अपने वीज़ा का विस्तार अधिक देशों में, कम से कम उन देशों / क्षेत्रों में कर सकते हैं, जो भारतीय पासपोर्ट धारकों को आगमन पर वीज़ा / वीज़ा से छूट प्रदान कर रहे हैं।
    - भारत देश के अन्य प्राथमिक पर्यटन स्थलों में से गोवा, वाराणसी, बोधगया और जयपुर के हवाई अड्डों पर आने के लिए वीज़ा की नीति का विस्तार भी कर सकता है। इससे भारत में देश के पर्यटन बाजार को बढ़ावा देने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।.
- नीचे उन देशों / क्षेत्रों की सूची दी गई है जो भारत के एन पासपोर्ट धारकों के लिए आगमन / ई-वीज़ा सुविधा पर वीज़ा / वीज़ा से छूट प्रदान कर रहे हैं। हालांकि, इन देशों के पासपोर्ट धारकों को अभी भी भारत में ई-वीज़ा सुविधा प्रदान नहीं करने वाले वीज़ा प्राप्त करने की पारंपरिक पद्धति का पालन करना आवश्यक है। इसलिए, विदेश मंत्रालय और भारत के गृह मंत्रालय इन देशों / क्षेत्रों के नागरिकों को इस ई-वीज़ा सुविधा का विस्तार कर सकते हैं।

[141] https://www.bali.com/visa-indonesia-entry-requirements-bali.html

तालिका 7.03: देश[142]

देश / क्षेत्र (10)	
उत्तरी साइप्रस	मालदीव
रीयूनियन	इथियोपिया
स्वालबार्ड और जेन मेयन	टोगो
ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड	गिनी-बिसाऊ
पिटकेर्न द्वीप	नीयू

[142] https://www.makemytrip.com/blog/visa-on-arrival-for-indians, https://www.bankbazaar.com/visa/list-of-visa-free-countries-for-india.html?ck=Y%2BziX71XnZjIM9ZwEflsyDYlRL7gaN4W0xhuJSr9Iq7aMYwRm2IPACTQB2XBBtGG&rc=1

संकेतक 7.02: द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों का खुलापन

परिभाषा: सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा संपन्न सभी द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों के भारित औसत खुलेपन को मापता है जैसा कि आईसीएओ की विश्व सेवा समझौते डाटा बेस में पंजीकृत है।

- भार प्रत्येक वायु सेवा समझौते के तहत होने वाला द्विपक्षीय अनुसूचित यात्री यातायात है।
- विनियामक डाटा आईसीएओ की डब्ल्यूएएसए डाटा बेस से आता है और ट्रैफ़िक डाटा आईएटीए से प्राप्त किया जाता है।

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

मूल्य = हवाई सेवा समझौतों के औसत खुलेपन को मापने वाला सूचकांक (0 = सबसे अधिक प्रतिबंधित, 38 = सबसे उदार)

ध्यान दें: एक द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता दो अनुबंधित देशों के बीच संपन्न होता है और उन देशों के बीच वाणिज्यिक नागरिक विमानन सेवाओं का उदारीकरण करता है। द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते उन देशों की नामित एयरलाइनों को वाणिज्यिक उड़ानों को संचालित करने की अनुमति देते हैं जो दो देशों के बीच यात्रियों और कार्गो के परिवहन को कवर करते हैं। इसके अलावा, वे सामान्य रूप से देशों, मूल्य निर्धारण और अन्य वाणिज्यिक पहलुओं के बीच वायु सेवाओं की आवृत्ति और क्षमता को विनियमित करते हैं।

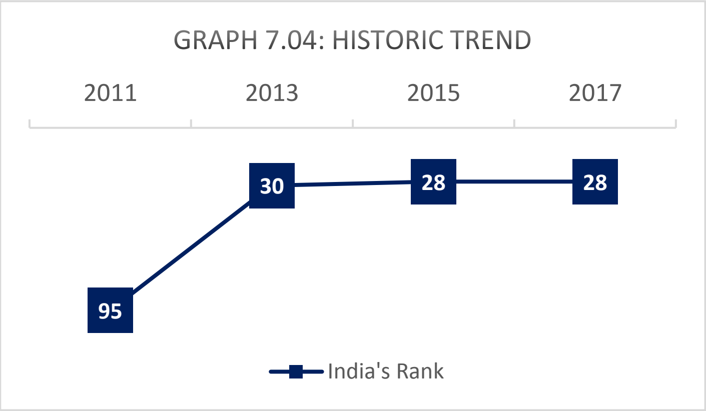

इस सूचक में ग्राफ 7.04 भारत की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2013 की तुलना में 2 पदों की वृद्धि हुई है। यह सूचक देश के स्कोर में 2.08% का योगदान देता है।

तालिका 7.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी 2015	मूल्य 2015	श्रेणी 2017	मूल्य 2017	कारण
न्यूज़ीलैंड	1	35.59	1	35.59	शीर्ष प्रदर्शक
अल सल्वाडोर	2	27.77	2	27.77	शीर्ष प्रदर्शक
ताइवान, चीन	3	27.5	3	27.5	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**28**	**14.57**	**28**	**14.57**	

सरकारी पहल

- भारत ने 17 देशों के साथ बातचीत की और 12 देशों के साथ एक "समझौता ज्ञापन" पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी 2016) के निर्देशों के अनुसार इन वार्ताओं में हल किए गए प्रमुख मुद्दे हैं:[143]
    - **नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी (एनसीएपी 2016) के अनुसार ओपन स्काईज समझौता:** यह समझौता छह महानगरों के छह मेट्रो हवाई अड्डों, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई को असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति देता हैं, इसे छः देशों जैसे की जमैका, गुयाना, चेक गणराज्य, अटलांटा, स्पेन और श्रीलंका के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। नई व्यवस्था से भारत और इन देशों के बीच संपर्क और यात्री यात्रा को बढ़ावा मिलेगा।
- नीचे दी गई तालिका में भारत और विभिन्न देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए वर्ष के साथ समझौतों को दिखाया गया है।

तालिका 7.05: सबसे हाल ही में वायु सेवा समझौते

देशों के बीच **समझौता**	**समझौता वर्ष**
भारत और न्यूज़ीलैंड[144]	2016
भारत और ग्रीस [145]	2017
भारत और मोरक्को [146]	2018
भारत और सर्बिया [147]	2018

- 2016 तक, भारत में 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौते (एएसए) हैं, जो उड़ानों, सीटों, लैंडिंग बिंदुओं और कोड-शेयर की संख्या से संबंधित पहलुओं को कवर करते हैं।
- नई नागरिक उड्डयन नीति (2016) के तहत, कोई नया उड़ान अधिकार, जिसे द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता भी कहा जाता है, तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि भारतीय वाहक अपनी क्षमता के कम से कम 80% का उपयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए दुबई के साथ द्विपक्षीय पात्रता, जहां दोनों पक्षों के वाहक ने मौजूदा कोटा का 90% से अधिक का उपयोग किया है, भारतीय

[143] http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155471
[144] https://www.mea.gov.in/Images/attach/ASA_English_version.pdf
[145] https://currentaffairs.gktoday.in/india-greece-sign-air-services-agreement-11201750322.html
[146] http://www.dgca.nic.in/
[147] http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=183613

सरकार दुबई के साथ बढ़ते उड़ान अधिकारों पर सहमत नहीं हुई, क्योंकि दुबई अधिकारी भारत सरकार की मांगों के अनुसार दुबई हवाई अड्डे पर वांछित स्लॉट प्रदान करने से सहमत नहीं थे।

- केवल अमेरिका के साथ एएसए क्षमता, मार्ग या मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध के बिना एक ओपन स्काय समझौता है। हालांकि ओपन स्काय नहीं हैं, यूके के साथ एएसए को भी 2004 में काफी उदारीकृत किया गया था। यह ध्यान देना चाहिए कि डीएएस को आमतौर पर एएसए की शर्तों पर बातचीत करते समय पारस्परिकता की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह संभव है कि एक एएसए के भीतर प्रतिबन्ध भारत सरकार की नीतियों के कारण नहीं बल्कि विपरीत देश की नीतियों के कारण हैं। देश.

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय

दीर्घकालिक योजना

- टीटीसीआर की पिछले वर्षों की रिपोर्टों से देखे गए रुझान बताते हैं कि इस संकेतक के लिए माना जाने वाला डाटा आधार हर 6 साल में अद्यतित किया जाता है। टीटीसीआर 2007, 2009 और 2011 के लिए माना जाने वाला डाटा बेस 2005 का था और 2013, 2015, 2017 का डाटा बेस 2011 का है। इस प्रवृत्ति के अनुसार, टीटीसीआर 2019, 2021, 2023 में इस संकेतक के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा को 2017 में प्रस्तुत किया गया है।
- डाटा बेस में अगला अपडेट अब 2023 में टीटीसीआर2025, 2027, 2029 के लिए किया जाएगा। एक दीर्घकालिक योजना के रूप में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नियमित रूप से यूएनडब्ल्यूटीओ को अपडेट करना चाहिए जैसे ही एक हवाई सेवा समझौते के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं ताकि वहां जब डाटा बेस परिवर्तन के लिए वर्ष माना जाता है तो लंबित अध्यतन के कोई मामले नहीं हैं।

संकेतक 7.03: बल में क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की संख्या

परिभाषा: यह संकेतक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के लिए क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) की संख्या और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अग्रीमेंट (ईआईए) की संख्या द्वारा मापा गया है, जैसा कि विदेशी वस्तुओं और सेवा के लिए किसी देश के खुलेपन के स्तर का आकलन करता है। आरटीए में प्रवेश करने वाले सदस्यों को डब्ल्यूटीओ के लिए आरटीए को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, या तो टैरिफ और व्यापार (जीएटीटी) 1994 के सामान्य समझौते के अनुच्छेद XXIV के तहत या सक्षम क्लॉज (माल में व्यापार को कवर करने वाले आरटीए के लिए), या सामान्य समझौते के अनुच्छेद वी के तहत। व्यापार और सेवा (जीएटीएस) (सेवाओं में व्यापार को कवर करने वाले आरटीए के लिए)। माल और सेवाओं दोनों को कवर करने वाले एक आरटीए के मामले में, दो निक्षेपों की आवश्यकता नहीं होती है। आरटीए के अनुसमर्थन के बाद और पक्षकारों के बीच अधिमान्य उपचार के आवेदन से पहले नहीं किया जाना चाहिए।

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ); क्षेत्रीय व्यापार समझौते सूचना प्रणाली (आरटीए-आईएस)

मूल्य = विश्व व्यापार संगठन के लिए क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) की संख्या और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अग्रीमेंट (ईआईए) की संख्या का योग।

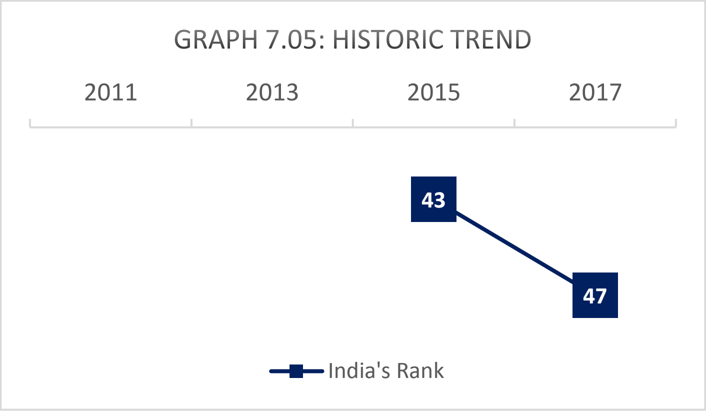

इस संकेतक में ग्राफ 7.05 भारत की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 4 पदों की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 2.08% का योगदान देता है।

तालिका 7.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
जर्मनी	1	46	1	53	शीर्ष प्रदर्शक

फ्रांस	1	46	1	53	शीर्ष प्रदर्शक
नीदरलैंड	1	46	1	53	शीर्ष प्रदर्शक
पुर्तगाल	1	46	1	53	शीर्ष प्रदर्शक
बुल्गारिया	1	46	1	53	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**43**	**19**	**47**	**20**	

इस संकेतक में 28 देशों की पहली श्रेणी है क्योंकि इन सभी का मूल्य समान है।

विश्व व्यापार संगठन के तहत क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) के लिए प्रक्रिया:

- **चरण 1: प्रारंभिक घोषणा**

  आरटीए के समापन के उद्देश्य से नई बातचीत में भाग लेने वाले सदस्यों को डब्ल्यूटीओ सचिवालय को इस तरह की वार्ताओं के बारे में सूचित करना चाहिए। जो सदस्य एक नए हस्ताक्षरित आरटीए के पक्षकार हैं, उन्हें आरटीए पर सूचना आरटीए के आधिकारिक नाम, कार्यक्षेत्र, हस्ताक्षर की तिथि, किसी भी पूर्वाभास समय सारणी में बल या अनंतिम आवेदन, प्रासंगिक संपर्क बिंदुओं और / वेबसाइट पते, किसी भी अन्य प्रासंगिक अप्रतिबंधित जानकारीऔर सहित के लिए सचिवालय को सूचना भेजनी चाहिए।

- **चरण 2: अधिसूचना**

  सदस्यों द्वारा आरटीए की अधिसूचना को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए, सामान्य तौर पर बाद में पार्टियों के आरटीए के अनुसमर्थन या किसी समझौते के प्रासंगिक भागों के आवेदन पर किसी भी पार्टी के निर्णय से पहले और पार्टियों के बीच उसके अधिमान्य उपचार के आवेदन से पहले। पार्टियों को निर्दिष्ट करना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ समझौतों के किस प्रावधान के तहत आरटीए को अधिसूचित किया गया है और डब्ल्यूटीओ की आधिकारिक भाषाओं में से एक में पूर्ण टेक्स्ट और किसी भी संबंधित कार्यक्रम, एनेक्सिस और प्रोटोकॉल प्रदान करते हैं।

- **चरण 3: पारदर्शिता बढ़ाने की प्रक्रिया**

  अधिसूचित आरटीए के सदस्यों द्वारा विचार सामान्य रूप से अधिसूचना की तारीख के बाद एक वर्ष के भीतर समाप्त किया जाएगा। डब्ल्यूटीओ सचिवालय अधिसूचना के समय पार्टियों के साथ परामर्श करके आरटीए के विचार के लिए एक सटीक समय सारणी तैयार करेगा। समझौते की अधिसूचना की तिथि के बाद आरटीए की पार्टियां सामान्य रूप से सचिवालय को दस सप्ताह (या केवल विकासशील देशों को शामिल करने वाले आरटीए के मामले में 20 सप्ताह) के भीतर डाटा उपलब्ध कराएंगी।

  एक नियम के रूप में, एक एकल औपचारिक बैठक प्रत्येक अधिसूचित आरटीए के विचार के लिए समर्पित होगी; सूचना का कोई भी अतिरिक्त आदान-प्रदान लिखित रूप में होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ सचिवालय के तथ्यात्मक निर्धारित प्रस्तुति, साथ ही पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किसी भी अतिरिक्त जानकारी को सभी डब्ल्यूटीओ की आधिकारिक भाषाओं में परिचालित किया जाना चाहिए, जो संबंधित क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (सीआरटीए) की बैठक से पहले आठ सप्ताह से कम नहीं है। विचाराधीन आरटीए पर सदस्यों के लिखित प्रश्न या टिप्पणियां सीआरटीए की बैठक से कम से

कम चार सप्ताह पहले सचिवालय के माध्यम से पार्टियों को प्रेषित की जानी हैं और सभी सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम तीन कार्यदिवस में उत्तर के साथ वितरित किए जाएंगे।

चरण 4: बाद की अधिसूचना और रिपोर्टिंग

आरटीए के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले या पहले से लागू आरटीए के संचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी परिवर्तन को डब्ल्यूटीओ को सूचित किया जाना चाहिए जैसे ही वे परिवर्तन होते हैं आरटीए के कार्यान्वयन की अवधि के अंत में, पार्टियां मूल रूप से अधिसूचित आरटीए में उदारीकरण प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति पर डब्ल्यूटीओ को एक छोटी-लिखित रिपोर्ट सौंपेंगी।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

अल्पकालीन योजना

- डब्ल्यूटीओ के आंकड़ें / आरटीए की गिनती "बल में" आरटीए की संख्या पर आधारित होती है, जिन्हें डाटा बेस में मौजूद आरटीए के बजाय डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित किया गया है जो केवल "बल में" हैं, लेकिन अधिसूचित नहीं हैं। भारत में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और प्रभावी रूप से तालिका 7.07 और तालिका 7.08 में दिए गए हैं। 12 क्षेत्रीय समझौते प्रस्तावित हैं और परामर्श के तहत हैं। चूंकि डब्ल्यूटीओ बल की तारीख के बजाय आरटीए की अधिसूचना तिथि को ध्यान में रखता है, इसलिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को आरटीए के लागू होते ही डब्ल्यूटीओ को सूचित करना चाहिए ताकि आरटीए का बल वर्ष और वर्ष अधिसूचना एक ही रहे।
- **दोहरे समझौते में रूपांतरण-** विदेश मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मौजूदा समझौतों पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित कर सकता है जो या तो माल समझौते या सेवा समझौते हैं जो उन्हें दोहरे समझौतों में परिवर्तित करने के लिए हैं, जो कि सामान और सेवा समझौते दोनों ही हैं मूल्य गणना में उनकी गिनती बढ़ाने के लिए।

दीर्घकालिक योजना

- भारत में डब्ल्यूटीओ के तहत तालिका 7.07 और तालिका 7.08 में दी गई 14 आरटीए वार्ताएं हैं। इसलिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इन वार्ताओं को सुधार सकता है और उन्हें लागू कर सकता है और इन आरटीए के बारे में डब्ल्यूटीओ को सूचित कर सकता है।
- डब्ल्यूटीओ आरटीए की गणना नीचे दिए गए श्रेणी के तहत करता है: -
    - माल आरटीए - आरटीए की संख्या को 1 के रूप में गिना जाता है
    - सेवा आरटीए - आरटीए की संख्या को 1 के रूप में गिना जाता है
    - माल और सेवाएं आरटीए - आरटीए की संख्या को 2 के रूप में गिना जाता है

चूंकि माल और सेवाओं के अंतर्गत आरटीए को डब्ल्यूटीओ द्वारा दो बार गिना जाता है, इसलिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अधिक आरटीए हस्ताक्षर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

तालिका 7.07: समझौतों की स्थिति और संख्या

स्थिति	समझौतों की संख्या	माल	सेवाएं	माल और सेवाएं
हस्ताक्षरित और प्रभाव में	17	12	-	5
वार्ता का शुभारंभ	14	2	-	-
Proposed/Under प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	12	-	-	-
(एफए) हस्ताक्षर किए गए	1	-	-	-

तालिका 7.07 में वर्ष 2017 तक हस्ताक्षरित और प्रभाव में 'क्षेत्रीय व्यापार समझौते शामिल हैं, लेकिन टीआईएसआर 2017 के लिए उत्पन्न मूल्य की गणना वर्ष 2015 तक व्यापार समझौतों का उपयोग करके की गई है।

तालिका 7.08: समझौतों की सूची[148]

समझौते	स्थिति	वर्ष	अधिसूचना वर्ष	कवरेज
आसियान- भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2010	2010	माल और सेवाएँ
भारत- अफगानिस्तान अधिमान्य व्यापार समझौता	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2003	2010	माल
भारत- भूटान व्यापार समझौता	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2006	2008	माल
भारत-चिली अधिमान्य व्यापार समझौता	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2007	2009	माल

[148] https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm

भारत- मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2009	2010	माल
भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2005	2007	माल और सेवाएँ
भारत- श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2001	2002	माल
भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार क्षेत्र	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2014	2017	माल
भारत-[गणराज्य] कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2010	2010	माल और सेवाएँ
भारत-नेपाल व्यापार समझौता	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2002	2010	माल
जापान-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2011	2011	माल और सेवाएँ
मलेशिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2011	2011	माल और सेवाएँ
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2006	2008	माल

एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट (एपीटीए) -चीन	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2004	2004	माल
दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौता (एसएपीटीए)	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	1997	1997	माल
विकासशील देशों के बीच व्यापार वरीयता की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	1989	1989	माल
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता- अफगानिस्तान तक पहुंच	हस्ताक्षर किए गए और प्रभाव में	2016	2016	माल
पूर्वी एशिया के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी (सीईपीईए / आसियान + 6)	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2005	-	
भारत- कोलम्बिया अधिमान्य व्यापार व्यवस्था	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2004	-	
भारत - इक्वाडोर एफटीए	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2017	-	
भारत- जॉर्जिया एफटीए	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2017	-	

भारत- ईरान मुक्त व्यापार समझौता	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2015	-	
भारत- रूसी महासंघ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2006	-	
भारत- तुर्की मुक्त व्यापार समझौता	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2009	-	
भारत- यूनाइटेड किंगडम ऍफ़टीए	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2017	-	
भारत- उरुग्वे अधिमानी व्यापार व्यवस्था	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2004	-	
भारत- वेनेजुएला अधिमान्य ट्रेडिंग व्यवस्था	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2004	-	
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना- भारत क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2003	-	

ताइपे, चीन- भारत एफटीए	प्रस्तावित / परामर्श और अध्ययन के तहत	2014	-	
बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल (बिम्सटेक) मुक्त व्यापार क्षेत्र	वार्ता का शुभारंभ	2014	-	माल
भारत - यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन	वार्ता का शुभारंभ	2015	-	
भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता	वार्ता का शुभारंभ	2011	-	
भारत- कनाडा आर्थिक भागीदारी समझौता	वार्ता का शुभारंभ	2010	-	
भारत- मिस्र अधिमान्य व्यापार समझौता	वार्ता का शुभारंभ	2002	-	
भारत- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ मुक्त व्यापार समझौता	वार्ता का शुभारंभ	2008	-	
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता	वार्ता का शुभारंभ	2007	-	
भारत-इंडोनेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग व्यवस्था	वार्ता का शुभारंभ	2011	-	
भारत- इज़राइल मुक्त व्यापार समझौता	वार्ता का शुभारंभ	2006	-	
भारत- मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता	वार्ता का शुभारंभ	2005	-	
भारत - दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ अधिमान्य व्यापार समझौता	वार्ता का शुभारंभ	2007	-	माल
न्यूजीलैंड-भारत मुक्त व्यापार समझौता	वार्ता का शुभारंभ	2010	-	

पेरू- भारत मुक्त व्यापार समझौता	वार्ता का शुभारंभ	2016	-	
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी	वार्ता का शुभारंभ	2013	-	
भारत- खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार क्षेत्र	(एफए) पर हस्ताक्षर किए गए	2006	-	

स्तंभ 8: मूल्य प्रतिस्पर्धा

परिभाषा: यह स्तंभ मापता है कि किसी देश में यात्रा करना या निवेश करना कितना महंगा है। स्तंभ 8 के नीचे कुल 4 संकेतक हैं-

1. टिकट कर और हवाई अड्डा शुल्क
2. होटल मूल्य सूचकांक
3. क्रय शक्ति समता
4. ईंधन मूल्य स्तर

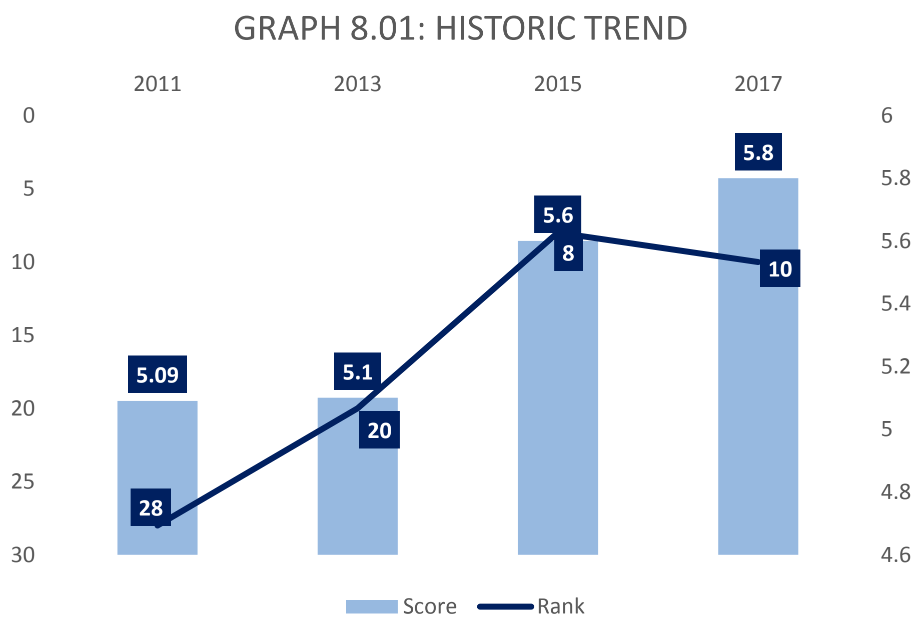

ग्राफ 8.01 भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति स्तंभ 8 में अंकित है। भारत की श्रेणी 2011 में 28 वें स्थान से बढ़कर 2017 में 10 वें स्थान पर पहुंच गई है।

भार की स्थिति में बदलाव:

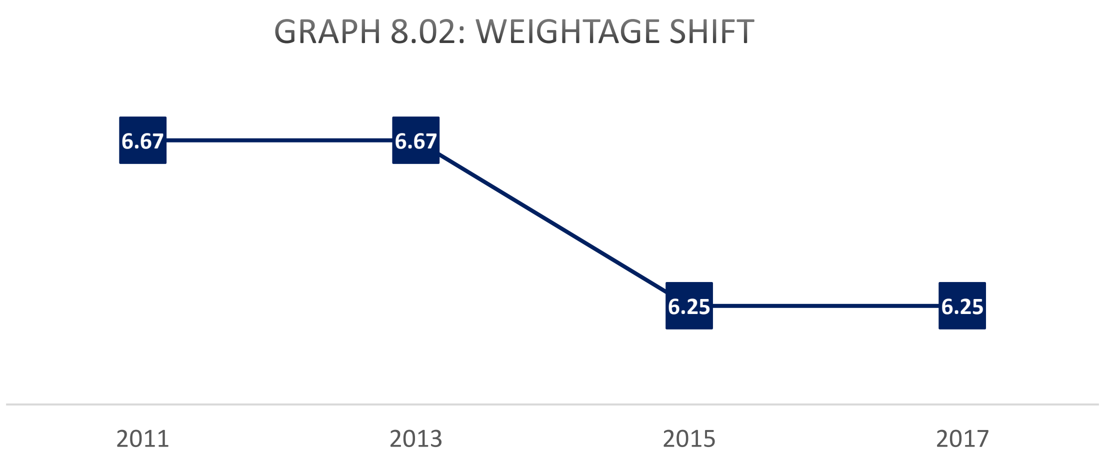

ग्राफ़ 8.02 भारत के स्कोर में स्तंभ 8 के मूल्य प्रतिस्पर्धा को इंगित करता है। वर्तमान में, 6.25% भार इस स्तंभ को दिया जाता है। इस स्तंभ का भार वर्ष 2015 में 6.30% कम हो गया है।

तालिका 8.01: भार की स्थिति में संकेतक वार बदलाव

संकेतक	2011-2013 (%)	2015-2017 (%)	भार की स्थिति में बदलाव (%)
टिकट कर और हवाई अड्डा शुल्क	1.33	1.56	17.29
होटल का मूल्य सूचकांक	1.33	1.56	17.29
क्रय शक्ति समता	1.33	1.56	17.29
ईंधन का मूल्य स्तर	1.33	1.56	17.29

तालिका 8.01 योगदान का प्रतिशत दर्शाती है जो कि प्रत्येक संकेतक का भारत के समग्र स्कोर पर है।

संकेतक 8.01: टिकट कर और हवाई अड्डा शुल्क

परिभाषा: यह सूचकांक हवाई अड्डे के शुल्क, यात्री टिकट करों और मूल्य वर्धित कराधान के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन सेवाओं तक पहुँच की सापेक्ष लागत को मापता है। यह प्रत्येक देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक संकीर्ण-शरीर और चौड़े शरीर वाले यात्री विमान के आगमन और प्रस्थान से जुड़ी लागत को दर्शाता है।

स्रोत: इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एसआरएस एनालाइजर

देश का मूल्य: एक एसआरएस विश्लेषक उपकरण का उपयोग उस मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है जहां लैंडिंग, टर्मिनल नेविगेशन, यात्री शुल्क, सुरक्षा शुल्क, टिकट कर और हवाई अड्डे के शुल्क की गणना अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जाती है। प्रत्येक प्रकार के विमान के विशिष्ट बैठने के विन्यास में 75% लोड फैक्टर लागू करके प्रति-यात्री शुल्क की गणना की जाती है। मूल्यवर्धित करों (वैट) की गणना प्रत्येक देश के औसत टिकट मूल्य के आधार पर की जाती है, जो प्रस्थान करने वाले यात्रियों के आधी संख्या पर लागू होता है, क्योंकि वैट सामान्य रूप से संबंधित देश में उत्पन्न होने वाली आईटीनीरी पर लगाया जाता है। एक उच्च स्कोर निम्न स्तर के शुल्कों और करों को इंगित करता है।

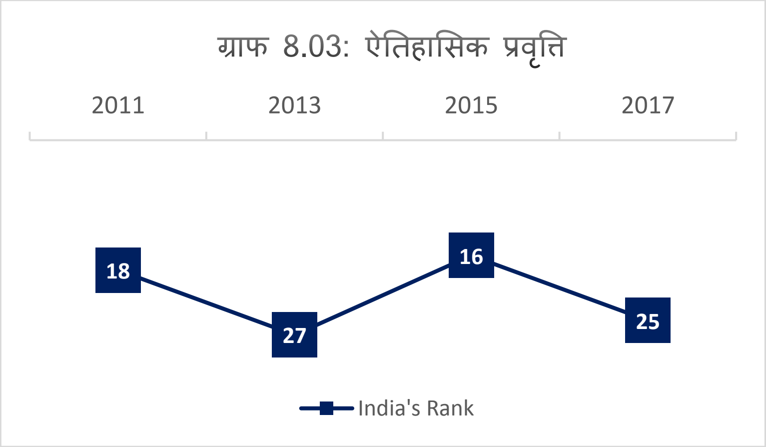

ग्राफ 8.03 सूचक 8.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 9 पदों की कमी आई। यह सूचक देश के स्कोर में 1.56% का योगदान देता है।

तालिका 8.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
लेबनान	65	80.46	1	100	शीर्ष प्रदर्शक
बोत्सवाना	4	96.09	2	98.51	शीर्ष प्रदर्शक
तंजानिया	95	72.86	5	95.34	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
कजाखस्तान	53	82.89	24	90.01	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**16**	**91.1**	**25**	**88.01**	
फ्रांस	114	61.78	51	80.15	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

प्रमुख शब्दावली:

- नीचे दिए गए सभी शुल्क टिकट कर को छोड़कर हवाई अड्डा सेवा शुल्क के अंतर्गत आते हैं
    - **लैंडिंग चार्ज** एक विमान द्वारा किसी विशेष हवाई अड्डे पर उतरने के लिए किसी विमान कंपनी द्वारा दिया जाने वाला शुल्क है। इसकी गणना अधिकतम स्वीकार्य ले-ऑफ भार को निकटतम टन तक राउंड ऑफ करके की जाती है।
    - **सुरक्षा शुल्क** किसी भी हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाले सभी विमानों पर लगाया जाता है।
    - **पार्किंग शुल्क** एक हवाई अड्डे पर एक विमान को पार्किंग से संबंधित शुल्क है। ये शुल्क आम तौर पर उस समय के आधार पर लगाए जाते हैं जिसके लिए एक विमान पार्क किया जाता है, लेकिन विमान के आकार या भार से संबंधित भी हो सकता है।
    - **यात्री शुल्क:** ये वे शुल्क हैं जो हवाई अड्डे द्वारा प्रति ऑन-बोर्ड यात्री से लिए जाते हैं। ये शुल्क सामान्य रूप से एयरलाइन को बिल किये जाते हैं, जो बाद में इसका भार यात्री पर डाल देते हैं।
    - **टिकट कर:** वे कर जो टिकट बिक्री के समय एकत्र किए जाते हैं और जो टिकट के कर बॉक्स में दिखाई देते हैं या जिन्हें कभी-कभी टिकट की कीमत में शामिल किया जाता है। कर, आम तौर पर प्रति यात्री आधार पर, राज्य द्वारा और अक्सर पूरे राज्य में लगाए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी एक हवाई अड्डे के स्तर पर भी लगाए जाते हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: नागरिक उड्डयन मंत्रालय

अस्वीकरण: टिकट कर और हवाई अड्डा शुल्क कई जटिल कारकों पर निर्भर हैं जैसे ईंधन की कीमतें, हवाई अड्डा सेवा खर्च, राजस्व उत्पन्न, वगैरह। टिकट कर और हवाई अड्डा शुल्क को अंतिम रूप देने का निर्णय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बाजार के गहन बाजार मूल्यांकन के बाद लिया जाता है। इसलिए, हम सुझाव दे सकते हैं, एक ठोस कार्ययोजना के स्थान पर, उसी के बदले किसी भी कार्य योजना को प्रस्तावित करने की स्थिति में नहीं हैं, हम कुछ नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव दे रहे हैं जो हवाई अड्डा सेवा शुल्क को कम कर सकते हैं।

मध्यम अवधि की योजना

- **परामर्श की आवश्यकता**
    - **नागरिक उड्डयन मंत्रालय,** नीतियों और नागरिक उड्डयन की रणनीतियों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ उनके मुख्य सलाहकार के रूप परामर्श के लिए खुली वार्ता कर सकता है। एक आदर्श संगठन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) हो सकता है क्योंकि वे इस क्षेत्र में अग्रणी हैं और भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और भारत सरकार के साथ काम करने की उनकी इच्छा को संबोधित किया है। उनकी ग्राहक सूची में **ऑस्ट्रिया सरकार, स्कॉटलैंड, ब्राजील, जापान, दक्षिण अफ्रीका आदि शामिल हैं।**

दीर्घकालिक योजना

- **कर और कर्तव्यों में कमी**
  - **फ्रेंच एयरपोर्ट टैक्स:** फ्रांस ने एक नया तरीका अपनाया है, जहां वे उन हवाई अड्डों पर एयरलाइन से वसूली नहीं कर रहे हैं, जिनकी वार्षिक औसत हवाई यातायात 5000 यूनिट (1 यूनिट = 1 यात्री या 100 किलोग्राम माल ढुलाई) से कम है। इसके अलावा, उन्होंने हवाई यातायात की मात्रा के आधार पर समूहों में हवाई अड्डों को वर्गीकृत किया है और इस वर्गीकरण के आधार पर करों को चार्ज कर रहे हैं। **नागरिक उड्डयन मंत्रालय दूरदराज के क्षेत्रों में अपने हवाई अड्डों के लिए एक समान नीति अपना सकता है क्योंकि इससे दूरदराज के हवाई अड्डों को उच्च हवाई यातायात आकर्षित होगा।**
  - **यूके की 16 साल से कम उम्र वालों को एयर पैसेंजर ड्यूटी (एपीडी) में दी जाने वाली छूट:** यूनाइटेड किंगडम ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एयर पैसेंजर ड्यूटी से छूट दी है, जिससे ग्राहकों और एयरलाइंस दोनों के लिए पैसा बचता है। जबकि भारत 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक छूट एपीडी प्रदान कर रहा है। **यह आयु सीमा जो कि ब्रिटेन के सामान पदचिन्हों पर जाकर16 साल तक बढ़ाई जा सकती है। यह हवाई किराए को कम करने में मदद कर सकता है और जिससे हवाई यात्रियों में वृद्धि हो सकती है।**
  - **कम किए गए टिकट कर:** तंजानिया और कजाकिस्तान जैसे देश हवाई टिकट पर 2% वैट लगा रहे हैं, जबकि भारत क्रमशः आर्थिक वर्ग और बिजनेस क्लास के टिकट पर 5% से 12% जीएसटीटी वसूल रहा है। **नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ान टिकटों पर लगाए गए जीएसटी को कम करने पर भी ध्यान दे सकता है क्योंकि यह ग्राहकों को आवश्यक मूल्य छूट प्रदान करेगा और यात्रियों की संख्या में वृद्धि करेगा।**

संसंकेतक 8.02: होटल मूल्य सूचकांक

परिभाषा: परिभाषा: यह सूचकांक प्रत्येक देश में प्रथम श्रेणी के होटल आवास की औसत कीमत (यूएसडी) को मापता है। सूचकांक की गणना प्रत्येक देश में 12 महीने की अवधि में प्रथम श्रेणी के होटलों* द्वारा प्राप्त औसत कमरे की दर का उपयोग करके की जाती है।

* प्रथम श्रेणी के होटलों में पाँच सितारा होटल शामिल हैं।

स्रोत: डेलोइट-एसटीआर ग्लोबल और स्मिथ ट्रैवल रिसर्च इंक।

देश का मूल्य = 12 महीने की अवधि में प्रथम श्रेणी के होटलों की औसत कमरे की दर ($ में)

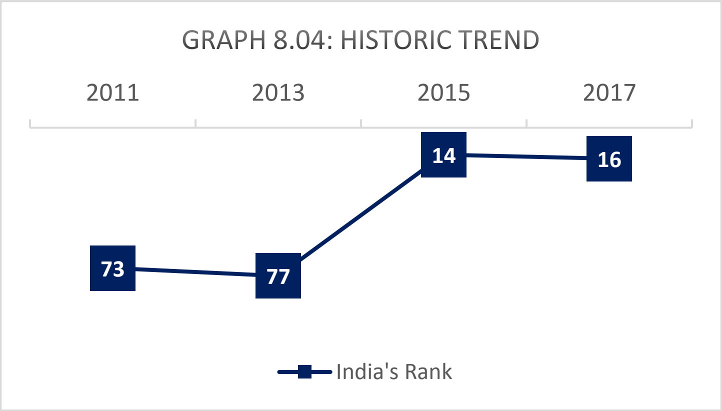

ग्राफ़ 8.04 संकेतक 8.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में भारत की श्रेणी में 2 पदों की कमी आई है। यह सूचक देश के स्कोर में 1.56% का योगदान देता है।

तालिका 8.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
लिथुआनिया	1	70.49	1	68.24	शीर्ष प्रदर्शक
पोलैंड	4	79.89	2	69.17	शीर्ष प्रदर्शक
नामीबिया	6	83.64	3	71.54	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**14**	**93**	**16**	**84.54**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **नई होटल परियोजनाओं के अनुदान के लिए एकल खिड़की निकासी**
  - भारत में एक होटल खोलने के लिए वर्तमान समय में कई लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे समय, प्रयास और धन की हानि होती है। इसके अलावा, अनुमोदन / लाइसेंस जारी करने वाले विभिन्न निकाय स्वतंत्र सिलोस में काम करते हैं, और इन अनुमोदन / लाइसेंस प्राप्त करने के समन्वय को आवेदक के ऊपर छोड़ देते हैं। वर्तमान में, एक होटल को एक ही परिसर के भीतर विभिन्न स्थानों के लिए राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत एक से अधिक लाइसेंस लेने होते हैं जैसे कि बिल्डिंग परमिट, फायर सेफ्टी परमिट, पुलिस लाइसेंस, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस, व्यापार पंजीकरण, बार लाइसेंस, एफएसएसएआई खाद्य व्यवसाय लाइसेंस, सेवा कर लाइसेंस, वैट पंजीकरण आदि।
  - भारत सरकार द्वारा खनिज ब्लॉकों के आवंटन में जहां पर्यावरण और अन्य मंजूरी प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की निकासी प्रणाली रखी गई है, उसी तर्ज पर पर्यटन मंत्रालय भी होटल उद्योग[149] के लिए सभी लाइसेंस देने के लिए ऐसी एकल खिड़की निकासी प्रणाली को अपना सकता है।

मध्यम अवधि की योजना

- **निवेश रणनीतियाँ तैयार करना**
  - भारत में, आतिथ्य क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआईआई) की अनुमति है। कार्लसन, हैम्पटन, हिल्टन गार्डन इन, कोनराड, हिल्टन होटल्स समूह जैसे अंतर्राष्ट्रीय होटल ब्रांड भारत[150] में अपने होटलों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल टूरिज्म डिमांड कॉर्पोरेशन (डब्ल्यूबीटीडीसी) ने पूरे राज्य में ब्रांडेड होटल आवास की उपलब्धता बढ़ाकर इच्छुक निवेशकों का लाभ उठाने के लिए एक निवेश रणनीति शुरू की है।
  - इसी अवसर का फायदा उठाते हुए समान मॉडल और ब्रांडेड होटलों की मांगों को पूरा करने के लिए, एमओटी को उन राज्यों के राज्य पर्यटन विकास निगमों (एसटीडीसी) को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनके पास पर्यटकों की अधिक संख्या है, लेकिन सीमित संख्या में 5- सितारा होटल हैं। ऐसे राज्यों को नीचे दी गई तालिका 8.04 में सूचीबद्ध किया गया है। एमओटी को इन

---

[149] http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol16-issue9/Version-1/J016916973.pdf
[150] https://www.rediff.com/business/report/hilton-100-hotels-in-india-very-soon/20180623.htm

एसटीडीसी के लिए निवेश रणनीति तैयार करने में सहायता करनी चाहिए और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुनिया भर में पर्यटन क्षेत्र में उन निवेश योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए।

- ब्रांडेड होटलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के अलावा, यह होटल के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को विकसित करने की सुविधा भी देगा, जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कमी आएगी।

तालिका 8.04: राज्य वार पर्यटक अन्तर्वाह पांच सितारा होटलों के प्रतिशत के साथ[151]

राज्य	पांच सितारा होटलों का प्रतिशत	घरेलू और विदेशी पर्यटकों के दौरे की हिस्सेदारी का प्रतिशत
मणिपुर	0	26.12
आंध्र प्रदेश	2	10.87
पश्चिम बंगाल	4	10.80
तमिलनाडु	6	40.42
उत्तर प्रदेश	6	25.90

[151] Indian Tourism Statistics 2017: Market Research Division Ministry of Tourism

दीर्घकालिक योजना

- **पांच सितारा होटलों पर जीएसटी को कम करना**
  - भारत में पाँच सितारा होटल 28% के जीएसटी टैक्स स्लैब के तहत हैं जो देश का अधिकतम टैक्स स्लैब है। हालांकि, चार और तीन सितारा होटल 18% के टैक्स स्लैब के तहत हैं। पाँच सितारा और चार सितारा होटलों में टैक्स स्लैब के बीच का जो यह अंतर है यह होटल की कीमत बढ़ा देता है। इस क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने और आकर्षित करने के लिए, लगाए गए कर को कम करने की तत्काल आवश्यकता है।
  - **राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को नए विकास के लिए सेवा कर में छूट और नए होटलों और रिसॉर्ट्स के लिए एक लम्बी कर छुट्टी प्रदान करनी चाहिए**, क्योंकि यह उद्योग में निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा।

संकेतक 8.03: क्रय शक्ति समानता

परिभाषा: विश्व बैंक क्रय शक्ति समता (पीपीपी) रूपांतरण कारक को परिभाषित करता है, क्योंकि घरेलू बाजार में समान मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स में खरीदेगा। आधिकारिक विनिमय दर राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर या कानूनी रूप से स्वीकृत विनिमय बाजार में निर्धारित दर को संदर्भित करता है। इसकी गणना मासिक औसत (अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष स्थानीय मुद्रा इकाइयों) के आधार पर वार्षिक औसत के रूप में की जाती है।

स्रोत: विश्व बैंक, विश्व विकास संकेतक

देश का मूल्य = S और S = $\frac{P_1}{P_2}$

जहाँ

S, मुद्रा 1 से मुद्रा 2 की विनिमय दर का प्रतिनिधित्व करता है

P1 मुद्रा 1 में अच्छे X की लागत का प्रतिनिधित्व करता है

P2 मुद्रा 2 में अच्छे X की लागत का प्रतिनिधित्व करता है

उदाहरण के लिए: मान लीजिए कि 1 यूएसडी = 100 INR। यूनाइटेड स्टेट्स में ब्रेड $ 1 की हैं जबकि भारत में ब्रेड, वे इसे 30 रूपए में बेचते हैं, जिसका अर्थ है कि यूएसए में ब्रेड पर खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए, उसी मात्रा और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए 30 रूपए भारत में खर्च करने होंगे - या, अन्य शब्द में, ब्रेड की- वही मात्रा। और अगर माने कि मार्केट एक्सचेंज रेट $ 1 जो कि 100 INR हैं। इसलिए, पीपीपी पर देश का मूल्य 30 (पीपीपी रूपांतरण कारक) ÷ 100 (बाजार विनिमय दर) = 0.3 है

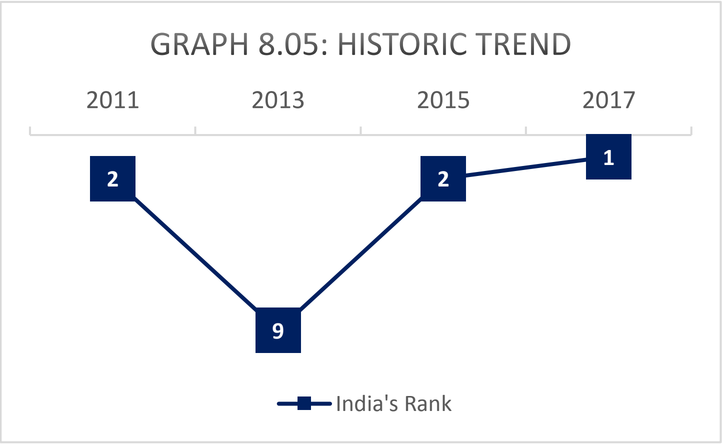

ग्राफ 8.05 संकेतक 8.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 1 स्थान की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 1.56% का योगदान देता है।

तालिका 8.05: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
भारत	**2**	**0.277**	**1**	**0.261**	
यूक्रेन	NA	NA	2	0.266	शीर्ष प्रदर्शक
मेडागास्कर	12	0.337	3	0.274	शीर्ष प्रदर्शक

संकेतक 8.03 यानी, क्रय शक्ति समता, बहुत विशिष्ट है और विशुद्ध रूप से विभिन्न सरकारी नीति स्तर के हस्तक्षेपों पर आधारित है। यह सूचक वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में है। ये निकाय पहले से ही किसी भी नीति या कानून को लागू करने की बाधाओं से परिचित हैं और प्रत्येक कार्यान्वयन में कई नतीजे हैं।

क्रय शक्ति समानता- वह सिद्धांत जो दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर में परिवर्तन को दर्शाता है, दोनों देशों के सामान्य मूल्य स्तरों के अनुपात में परिवर्तन के समानुपाती होता है।

इस सिद्धांत के दो दृष्टिकोण हैं:

- **निरपेक्ष पीपीपी**
  - निरपेक्ष क्रय-शक्ति समता सिद्धांत बताता है कि दो मुद्राओं के बीच संतुलन विनिमय दर दो राष्ट्रों में मूल्य स्तरों के अनुपात के बराबर है। विशेष रूप से:

    $$R = P/ P_*$$

    जहां R, विनिमय दर या स्पॉट रेट है और P और P_* क्रमशः, घरेलू राष्ट्र में और विदेशी राष्ट्र में सामान्य मूल्य स्तर है।
- **सापेक्ष पीपीपी**
  - अधिक परिष्कृत रिश्तेदार क्रय-शक्ति समता सिद्धांत यह बताता है कि समय की अवधि में विनिमय दर में परिवर्तन समान समय अवधि में दो राष्ट्रों में मूल्य स्तरों में सापेक्ष परिवर्तन के लिए आनुपातिक होना चाहिए।
  - $R1 = (P_1/P_0) \,/\, (P^*_1/P^*_0) \cdot R0$

- सबस्क्रिप्ट 0 बेस पीरियड और एक बाद की अवधि के लिए सबस्क्रिप्ट 1 को संदर्भित करता है, जहां क्रमशः R1 और R0 क्रमश: बेस पीरियड में विनिमय दरें हैं।

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय, एसांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

क्रय शक्ति समता को प्रभावित और प्रभावित करने वाले कारक नीचे सूचीबद्ध हैं

- **आय**
  - बालासा-सैमुअलसन प्रभाव यह बताता है कि समृद्ध देश गैर-व्यापार वाले सेवा क्षेत्रों की तुलना में व्यापार के सामान क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पूर्व खरीदे गए इनपुट के लिए बाजारों पर अधिक भरोसा करते हैं और इस तरह के लेनदेन-गहन क्षेत्र उच्च आय, बेहतर-प्रबंधित देशों में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। इसका प्रभाव गैर-व्यापार और व्यापार दोनों क्षेत्रों में मजदूरी में वृद्धि और गैर-व्यापार वाले सामानों के सापेक्ष मूल्यों में वृद्धि के रूप में होता है।
  - गरीब देशों में जीडीपी के स्तर को कम आंकने से कम आय के स्तर पर "फ्लैट टेल" में योगदान करके पीपीपी संबंधों के आकार पर प्रभाव पड़ेगा।

- **सब्सिडी और कर**
    - आय के सापेक्ष रखने वाले, सभी उच्च आय वाले राज्य जो उच्च पीपीपी मूल्य स्तर के साथ होते हैं वे ईंधन की खपत पर बड़ी सब्सिडी बनाए रखते हैं, जैसा कि अपेक्षित लागत स्तर के साथ निम्न और मध्यम आय वाले राज्य करते हैं। ऊर्जा सब्सिडी की बड़ी अर्थव्यवस्था-व्यापक कीमत और लागत प्रभाव पड़ने की संभावना है, ताकि जो देश सब्सिडी पर अधिक खर्च करते हैं, उनके आय स्तर के लिए अपेक्षाकृत कम पीपीपी मूल्य स्तर हो सकते हैं। जब सरकारी बिक्री कर, जैसे मूल्य-वर्धित कर (वैट), एक देश में दूसरे के सापेक्ष उच्च होते हैं, इसका मतलब है कि माल उच्च-कर वाले देश में अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर बिकेगा।.

- **कीमतें**
    - मुद्रास्फीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में कीमतें धीरे-धीरे बढ़ती हैं, प्रभावी रूप से अचल संपत्तियों और वर्तमान आय स्तरों की क्रय शक्ति को कम करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का उपयोग आमतौर पर खरीदे गए सामानों के लिए मूल्य परिवर्तन पर नज़र रखने के द्वारा क्रय शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। जिस दर पर वस्तुओं की कीमत (या वस्तुओं की टोकरी) बदल रही है वह उन देशों की मुद्राओं के मूल्य का संकेत दे सकती है। ऐसे सापेक्ष पीपीपी निरपेक्ष पीपीपी का परीक्षण करते समय माल के एक जैसे होने की आवश्यकता को ख़त्म करते हैं।.

- **बाज़ार की प्रतिस्पर्धा**
    - माल को जानबूझकर किसी देश में अधिक कीमत दिया जा सकता है क्योंकि कंपनी को अन्य विक्रेताओं पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, या फिर इसलिये क्योंकि इसका एकाधिकार है या कीमतों में हेरफेर करने वाली कंपनियों के उत्पादक संघ का हिस्सा है।

- **गैर-व्यापार सेवाएँ**
    - कुछ ऐसी सेवाएँ हैं जिनका व्यापार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उन लागतों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समता होने की संभावना नहीं है। इन लागतों में स्टोरफ्रंट, बीमा, उपयोगिता व्यय और श्रम की लागत शामिल हो सकती है। पीपीपी के अनुसार, उन देशों में जहां गैर-व्यापार सेवा लागत अपेक्षाकृत अधिक है, माल अपेक्षाकृत महंगा होगा, जिससे ऐसे देशों की

मुद्राएं गैर-व्यापार सेवाओं की कम लागत वाले देशों में मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य से अधिक हो जाएंगी।

- **सरकारी हस्तक्षेप**
  - आयातित टैरिफ आयातित वस्तुओं की कीमत में इजाफा करता है। जहां इनका उपयोग प्रतिबंधितआपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण माल की कीमत भी बढ़ जाती है। जिन देशों में समान मान है वह अप्रतिबंधित हैं और प्रचुर मात्रा में है, इसकी कीमत कम होगी। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकारों को आयात करने वाले देशों में एक माल की कीमत में वृद्धि देखने को मिलेगी और उन देशों में निर्यात में कमी आएगी जहां इसकी आपूर्ति बढ़ रही है।

- **विनिमय दर**
  - एक पीपीपी विनिमय दर को दो देशों में अंतिम माल और सेवाओं की एक प्रतिनिधि बास्केट के लिए कीमतों के अनुपात के रूप में दो राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यक्त की गई कीमतों के साथ परिभाषित किया गया है। इस विनिमय दर पर, विभिन्न मुद्राओं की क्रय शक्ति सामान या सेवाओं के विशिष्ट बंडल की विशिष्ट गुणवत्ता के संदर्भ में समान होती है जिसे खरीदा जा सकता है। क्योंकि ये पीपीपी विनिमय दरें गैर-व्यापार और व्यापार वाले सामान दोनों की राष्ट्रीय कीमतों में अंतर को दर्शाती हैं, वे जीवन स्तर के अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए उपयोगी हैं। पीपीपी विनिमय दर का निर्माण भले ही सीधा-साधा प्रतीत हो, लेकिन व्यवहार में यह कठिन है।

- **मुद्रा विचार**
  - विनिमय दर में उतार-चढ़ाव अन्य मुद्राओं के संबंध में क्रय शक्ति को प्रभावित करता है। जैसा कि एक देश की मुद्रा दूसरे के खिलाफ अवमूल्यन करती है, दूसरे देश में माल पहले देश की मुद्रा में अधिक होगा। यह तथ्य अपने आप में घरेलू खरीद के लिए क्रय शक्ति को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन दूसरे देश में आपूर्तिकर्ताओं पर भरोसा करने वाले व्यवसाय आयातित वस्तुओं पर नाटकीय कीमत में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। ये व्यवसाय उपभोक्ताओं को उच्च लागत, मुद्रास्फीति में योगदान और घरेलू क्रय शक्ति को कम कर सकते हैं।

- **ब्याज दर समता**
    - यह बताता है कि दो देशों में ब्याज दर के बीच का अंतर आगे की दर और उन दोनों देशों की हाजिर दर के बीच के अंतर के बराबर है। यह समानता हमेशा मौजूद नहीं होती है, और इस तरह से व्यापारियों को जोखिम रहित रिटर्न अर्जित करने के लिए विकल्प पदों पर मध्यस्थता करने की अनुमति मिलती है। ब्याज दर समानता तब मौजूद होती है जब घरेलू और विदेशी संपत्ति दोनों के लिए अपेक्षित नाममात्र दरें समान होती हैं। कोई भी अंतर विदेशी या घरेलू मुद्राओं में अपेक्षित प्रशंसा या गिरावट के कारण होता है।

संकेतक 8.04: ईंधन मूल्य स्तर

परिभाषा: यह सूचक सबसे अधिक बिकने वाली श्रेणी के डीजल ईंधन के पंप की कीमतों को संदर्भित करता है।

स्रोत: विश्व बैंक, विश्व विकास संकेतक

देश का मूल्य: खुदरा डीजल ईंधन की कीमतें प्रति लीटर अमेरिकी सेंट के रूप में व्यक्त की जाती हैं।

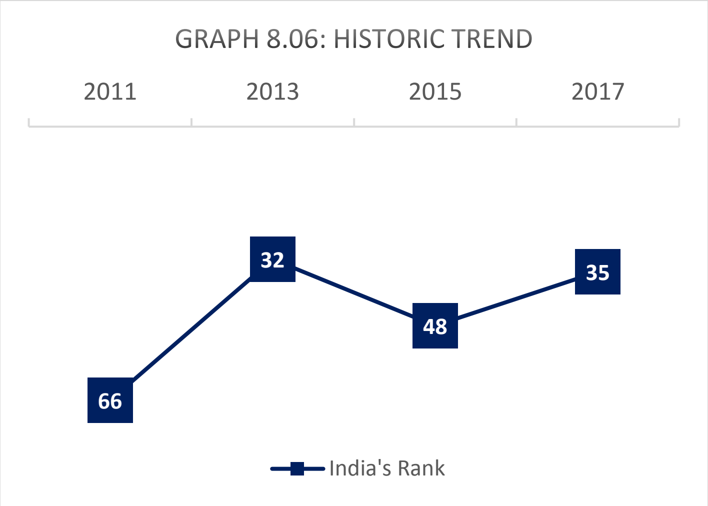

ग्राफ 8.06 संकेतक 8.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 13 स्थान की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 1.56% का योगदान देता है।

तालिका 8.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
वेनेजुएला	1	2.3	1	0.8	शीर्ष प्रदर्शक
सऊदी अरब	2	16	2	7	शीर्ष प्रदर्शक
अल्जीरिया	6	29	3	16	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**48**	**125**	**35**	**91**	
यूनाइटेड स्टेट्स	27	97	38	97	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

नीति में हस्तक्षेप

भारत में, वर्तमान में ईंधन के लिए बाजार अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और विक्रेताओं के लिए खुला है, जो ईंधन की कीमतों को काफी प्रभावित कर रहा है और अगर यह जारी रहता है, तो हमारे देश की श्रेणी आने वाली रिपोर्टों में गिर सकती है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई कारकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं जैसे:

- रिफाइनरियों द्वारा खरीदे गए कच्चे तेल की लागत
- लागत और मुनाफे को परिष्कृत करना
- वितरण, विपणन, और खुदरा स्टेशन लागत और मुनाफा
- कर (संघीय, राज्य, काउंटी और स्थानीय सरकार)

2017 में भारत की औसत मासिक डीजल खपत 6.6 मिलियन टन या प्रति दिन लगभग 1.6 मिलियन बैरल (बीपीडी) थी। 2016 से यह लगभग 3.1% प्रतिशत थी, जब औसत मासिक खपत 6.4 मिलियन टन थी। भारत के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित ईंधन पर जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तेल आयात बिल और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा अपनाया जा सकता है:

- **इलेक्ट्रिक वाहन (इवी)**
  - भारत में उपलब्ध होने वाली कुछ इलेक्ट्रिक कारें हैं - एड्डी करंट कंट्रोल्स लवबर्ड, महिंद्रा इ2ओ प्लस , महिंद्रा इ-वेरिटो, टाटा टीगोर इलेक्ट्रिक, महिंद्रा इ-केयूवी 100, और टाटा टियागो इलेक्ट्रिक।
  - शुरुआती अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम वांछनीय है। भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ईवी कार के ऋण पर ब्याज सबवेंशन या ईवी के आधार मूल्य पर सब्सिडी प्रदान करके कार खरीद पर एकमुश्त प्रोत्साहन के माध्यम से इसे लक्षित कर सकते हैं। अन्य उपायों में सड़क करों की छूट और अन्य स्थानीय शुल्क और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे पसंदीदा पहुंच और पार्किंग लाभ शामिल हैं।
  - पांच साल के लिए सालाना 1,00,000 चार-पहिया वाहनों का समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम के लिए 2000 करोड़ रुपए वार्षिक अनुदान की आवश्यकता होगी (वाहन लागत का 20%

सब्सिडाइज्ड है यह अनुमान लगाते हुए) जबकि 5% के ब्याज सबवेंशन के लिए INR 720 प्रति वर्ष की धुन के लिए धन की आवश्यकता होगी प्रति वर्ष करोड़।[152]

- **जैव-ईंधन**
  - जीवाश्म ईंधन के विपरीत, जैव ईंधन एक अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, क्योंकि वे उन फसलों से प्राप्त होते हैं जिन्हें वार्षिक रूप से काटा जा सकता है, या शैवाल, मासिक के मामले में। इसलिए, जैव ईंधन सैद्धांतिक रूप से असीमित हैं।[153].
  - छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ देश में जैव ईंधन उत्पादन के लिए एक उपन्यास राज्य बन सकता है क्योंकि राज्य में कृषि क्षेत्र की अत्यधिक वृद्धि दर है। छत्तीसगढ़ में जटरोफा संयंत्र से उत्पादित जैव ईंधन का उपयोग पहली जैव ईंधन से संचालित उड़ान में किया गया था जो हाल ही में देहरादून से उड़ान भरकर दिल्ली में उतरा था।[154].
  - यूनाइटेड स्टेट्स में, मकई से इथेनॉल बनाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में उत्पादित सबसे बड़ी फसल में, मोटे तौर पर 72,700,000 एकड़ भूमि में मक्का उगाई जाती है। राष्ट्रीय मकई की लगभग 7% उपज 2001 में इथेनॉल बनाने में चली गई और 2010 में लगभग 39% तक बढ़ गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने चाहिए जहां धान के पुआल, गेहूं के भूसे, गन्ना, मकई से ईंधन का उत्पादन किया जा सके। और बायो-फ्यूल के उपयोग के कारण नगर निगम का कचरा देश में डीजल की मांग में कमी लाएगा।
- **सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना**
  - ईंधन की मांग और ईंधन की कीमत के बीच सीधा संबंध है। सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने से हमें इस स्थिति पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि मेट्रो संरचना का एक निरंतर और उच्च स्तर पर विस्तार पहले से ही चल रहा है, यह नेटवर्क स्थिति को कम करने के लिए एक उत्कृष्ट उपाय के रूप में कार्य कर सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और उसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उपाय हैं:

---

[152] https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/11/Electric-Vehicles.pdf
[153] http://biofuel.org.uk/advantages-of-biofuels.html
[154] https://www.financialexpress.com/auto/car-news/chhattisgarh-can-become-bio-fuel-production-hub-nitin-gadkari/1309334/

- परिवहन की कम आवृत्ति वाले क्षेत्रों के लिए, आने-जाने के लिए फीडर सेवाएं प्रदान करना, जैसे कि मिनीवैन।
- यात्रियों को हर सौ यात्राओं के लिए एक मुफ्त सवारी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रियायतें और यात्रियों के लिए अन्य लाभ जैसे ऑफ़र प्रदान करने चाहिए। दिल्ली और अन्य राज्य के महानगर इस तरह के प्रोत्साहन दे सकते हैं।
- बसों के मामले में अधिक ड्राइवर और कंडक्टरों को नियुक्त करना चाहिए। यह मौजूदा श्रमिकों पर दबाव को कम करता है, जिन्हें कई बार अतिरिक्त शिफ्ट करनी पड़ती है। इससे अधिक संख्या में यात्राएं भी सक्षम हो सकती हैं, भले ही बसों की संख्या में वृद्धि न हो। इसके अलावा, यात्रियों की एक बड़ी शिकायत ड्राइवरों और कंडक्टरों का अभद्र व्यवहार है। संचार कौशल और ग्राहक संपर्क को बेहतर बनाने पर नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। कुछ सार्वजनिक परिवहन संगठनों के पास पहले से ही अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं।
- ऑटो चालकों को सार्वजनिक परिवहन कार्यबल में आत्मसात करके सड़क पर ऑटो को कम करने का प्रयास।

स्तंभ 9: पर्यावरणीय स्थिरता

परिभाषा: यह स्तंभ उस हद तक मापता है कि पर्यावरण संरक्षण उन पहलुओं तक सीमित है जो पर्यटकों को सीधे प्रभावित करते हैं। स्तंभ 9 के नीचे कुल 10 संकेतक हैं -

1. पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन
2. पर्यावरणीय नियमों का प्रवर्तन
3. यात्रा और पर्यटन उद्योग के विकास की स्थिरता
4. पार्टिकुलेट मैटर (2.5) सांद्रता
5. पर्यावरण संधि अनुसमर्थन
6. बेसलाइन पानी का तनाव
7. लुप्तप्राय प्रजातियां
8. वन कवरेज में परिवर्तन
9. अपशिष्ट जल उपचार
10. कॉस्टल शेल्फ में मछली पकड़ने का दबाव

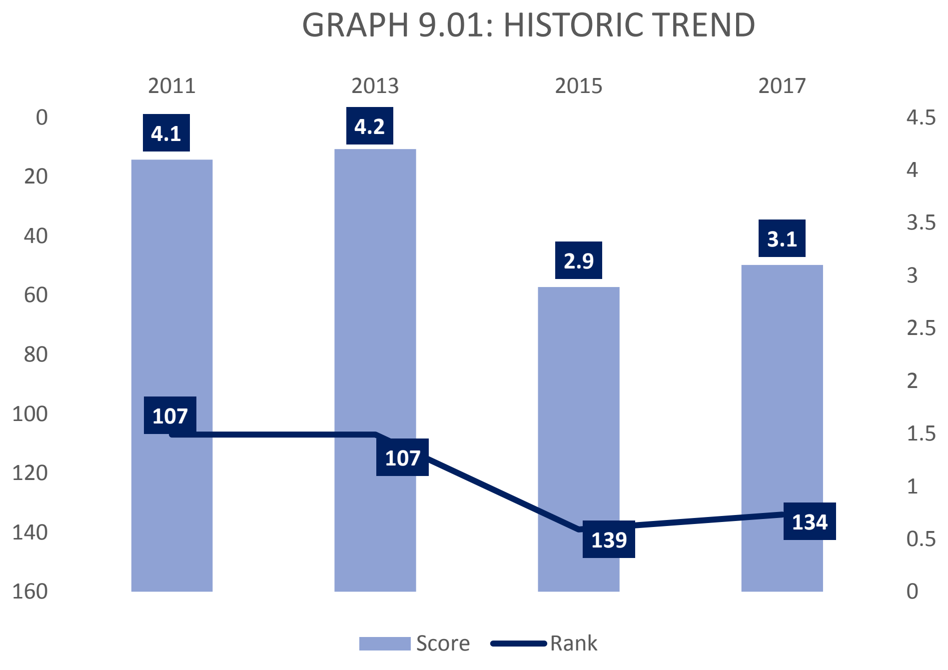

ग्राफ 9.01 भारत की श्रेणी और स्तंभ में मूल्य 9. की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को इंगित करता है। भारत की श्रेणी वर्ष 2015 में 139 वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2017 में 134 वें स्थान पर पहुंच गई।

भार की स्थिति में बदलाव:

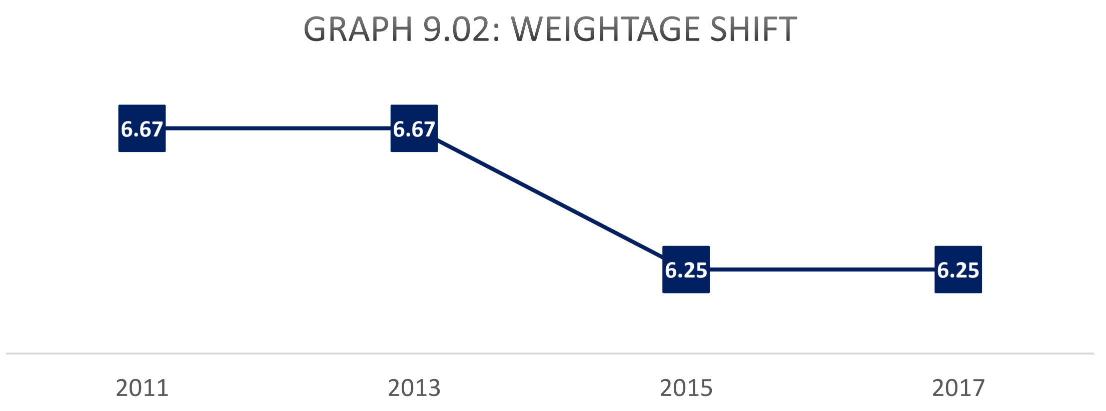

ग्राफ 9.02, स्तंभ 9 के समग्र योगदान को इंगित करता है यानी भारत के स्कोर में पर्यावरणीय स्थिरता। वर्तमान में 6.25% भार इस स्तंभ को दिया जाता है। 2013 की तुलना में इस स्तंभ का भार 6.30% कम हो गया है।

तालिका 9.01: संकेतक वार भार की स्थिति में बदलाव

संकेतक	2011-2013 (%)	2015-2017 (%)	भार की स्थिति में बदलाव (%)
पर्यावरणीय नियमों का अभाव*	0.95	0.34	-64.21
पर्यावरणीय नियमों का प्रवर्तन*	0.95	0.34	-64.21
यात्रा और पर्यटन उद्योग के विकास की स्थिरता	0.95	0.69	-27.37
पार्टिकुलेट मैटर (2.5) सांद्रता	0.95	0.69	-27.37
पर्यावरण संधि अनुसमर्थन	0.95	0.69	-27.37
बेसलाइन पानी का तनाव	N/A	0.69	N/A
लुप्तप्राय प्रजातियां	0.95	0.69	-27.37
वन कवरेज में परिवर्तन	N/A	0.69	N/A

अपशिष्ट जल उपचार	N/A	0.69	N/A
कॉस्टल शेल्फ में मछली पकड़ने का दबाव	N/A	0.69	N/A

NA = लागू नहीं, उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

*** इन संकेतकों को एक एकल संकेतक बनाने के लिए एक सरल औसत एकत्रीकरण लागू किया जाता है। नतीजतन, वे 0.5 के एक कारक द्वारा स्पष्ट रूप से भारित होते हैं।**

तालिका 9.01 उस योगदान का प्रतिशत दर्शाता है जो की प्रत्येक संकेतक का भारत के समग्र स्कोर पर है।

ध्यान दें: संकेतक 9.01 और 9.02 को एक एकल संकेतक के रूप में दिखाया जा रहा है क्योंकि वे अंतर-संबंधित हैं और भारत की पर्यावरण नीति का आकलन करने के लिए एक सामान्य कार्य योजना होगी।

संकेतक 9.01- पर्यावरण विनियमों का उल्लंघन

परिभाषा: "आप अपने देश के पर्यावरण नियमों की कठोरता का आकलन कैसे करेंगे?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = बहुत ढीला, दुनिया में सबसे खराब; 7 = दुनिया के सबसे कठोर में)

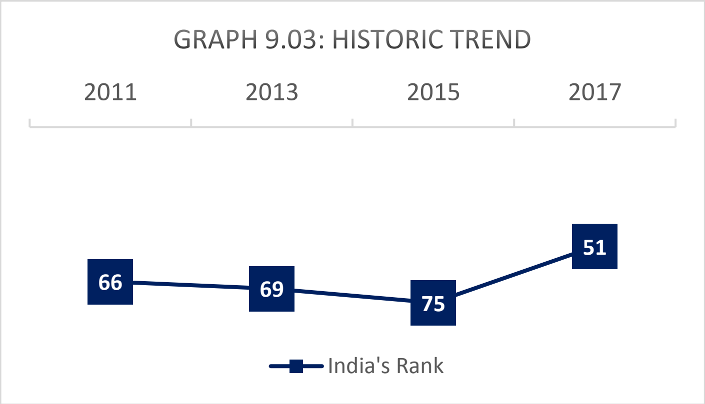

ग्राफ 9.03 संकेतक 9.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 24 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.34% का योगदान देता है।

तालिका 9.02 देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
स्विट्जरलैंड	2	6.33	1	6.24	शीर्ष प्रदर्शक
स्वीडन	11	5.87	2	6.22	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
फिनलैंड	3	6.23	3	6.21	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**75**	**3.95**	**51**	**4.42**	

संकेतक 9.02: पर्यावरणीय नियमों का प्रवर्तन

परिभाषा: "आपके देश में, आप पर्यावरण नियमों के प्रवर्तन का आकलन कैसे करेंगे?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (दुनिया में सबसे खराब, दुनिया में सबसे खराब; 7 = दुनिया में सबसे कड़ा)

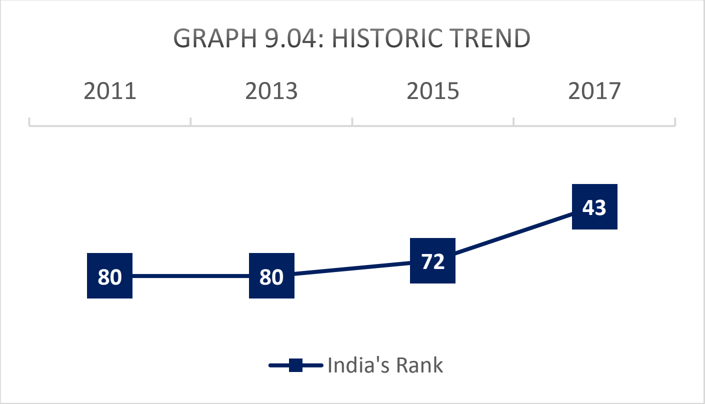

9.04 संकेतक 9.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 29 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.34% का योगदान देता है।

तालिका 9.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
फिनलैंड	1	6.26	1	6.21	शीर्ष प्रदर्शक
स्विट्जरलैंड	3	6.17	2	6.17	शीर्ष प्रदर्शक
ऑस्ट्रिया	7	5.99	3	6.08	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**72**	**3.77**	**43**	**4.36**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अल्पकालीन योजना

- **उद्योगों के लिए तीसरे पक्ष का मूल्यांकन**
    - सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए एक तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, गुजरात ने राज्य[155] में कार्यरत विभिन्न उद्योगों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों के प्रदर्शन का पता लगाने के उद्देश्य से एक **पर्यावरण लेखा परीक्षा**[6] योजना पेश की है। यह एक प्रबंधन उपकरण है जिसमें एक व्यवस्थित, समय-समय पर प्रलेखित और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली कितनी अच्छी तरह प्रदर्शन कर रही है, इसका उद्देश्य मूल्यांकन शामिल है। नीचे उल्लिखित उपकरण के प्राथमिक उद्देश्य हैं:
        - अपशिष्ट की रोकथाम और कमी
        - नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन का आकलन करना
        - एक कंपनी प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रथाओं के नियंत्रण की सुविधा
        - सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में पर्यावरण की जानकारी रखना

इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसी तरह की तर्ज पर गुजरात सरकार द्वारा अपनाए गए मॉडल को अपना सकते हैं और इसे देशव्यापी रूप में लागू कर सकते हैं।nationwide.

मध्यम अवधि की योजना

- **पर्यावरण कानूनों का सख्त कार्यान्वयन:**
    - काउंटरव्यू संगठन[156] के अनुसार, भारत के पर्यावरण नियम विश्व मानक के हैं, लेकिन उनका **प्रवर्तन बहुत कमजोर है।**[157]
    - हालांकि, हमारे पड़ोसी देश चीन के पास पर्यावरण कानूनों का बहुत ही सख्त प्रवर्तन है। अधिकृत पर्यावरण पर्यवेक्षण संस्थान, जो सभी स्तरों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशासनिक विभागों के अधीनस्थ हैं, प्रदूषण फैलाने वाले उद्यमों में साइट पर निरीक्षण कर सकते हैं।.
    - देश स्तर पर या उससे ऊपर के पर्यावरणीय प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न प्रवर्तन उपाय कर सकते हैं, जैसे कि साइट पर निरीक्षण, प्रदूषण फैलाने वाली सुविधाओं और उपकरणों को जब्त करना और लगाना इत्यादि।
    - इसके बाद, पर्यावरण कानूनों के क्रियान्वयन में चीन की मजबूती के परिणाम सामने आ रहे हैं। 2017 में प्रदूषण करने वाली कंपनियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। 2017 में, पर्यावरण

[155] https://www.gpcb.gov.in/images/environment-audit-scheme.pdf
[156] https://counterview.org/2017/08/28/indias-environmental-regulations-are-of-world-standard-but-their-enforcement-is-very-weak/
[157] https://counterview.org/2017/08/28/indias-environmental-regulations-are-of-world-standard-but-their-enforcement-is-very-weak/

कानून और नियमों के उल्लंघन के 3,416 नए मामले देशव्यापी दर्ज किए गए और साल-दर-साल 92% की वृद्धि देखी गई है।[158]

- **चीन के समान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत भर में कानूनों का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए।**

दीर्घकालिक योजना

- **पर्यावरण नीति के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र नियामक संस्था**
  - लाइव लॉ के एक लेख के अनुसार "प्रवर्तन में कमी का एक मुख्य कारण पर्यावरणीय शासन के लिए स्वतंत्र नियामक संस्था का अभाव है"। वर्तमान में, इसकी देखभाल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईऍफ़सीसी) द्वारा की जाती है। मंत्रालय के कामकाज में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण, भारत में पर्यावरण कानून का खराब कार्यान्वयन है। उदाहरणों में से एक भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना का कार्यान्वयन है। 'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006' में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं की मंजूरी के लिए पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और उसी पर अंतिम प्राधिकरण एमओईऍफ़सीसी का है। चूंकि एमओईऍफ़सीसी पूरी तरह से सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियंत्रित है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मानदंडों में लगातार छूट दी गई है और इसलिए, परियोजनाओं के लिए कई मनमानी मंजूरी प्रदान की जा रही है। इस प्रक्रिया में, सत्तारूढ़ सरकार का निहित स्वार्थ पर्यावरणीय निर्णय लेने को प्रभावित करता है।[159]
  - इसके अलावा, जैसा कि सरसंविस[160], इसके अलावा, जैसा कि सरसंविस द्वारा पर्यावरण नियामक निकायों पर रिपोर्ट में कहा गया है, बेहतर पर्यावरण शासन के लिए नियामक संस्थानों को बनाने और पुनर्गठन करने की तत्काल आवश्यकता है। स्वतंत्र पर्यावरण नियामक प्रभावी पर्यावरण शासन की दिशा में योगदान दे सकता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के अति प्रयोग और दुरुपयोग को रोकने में मदद कर सकता है और साथ ही सीमांत समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेगा। यह परियोजना की निगरानी की प्रक्रिया में भी मदद कर सकता है जिनकी अतीत में उनकी अप्रभावीता के लिए अक्सर आलोचना की गई है। पर्यावरण शासन में संस्थागत पुनर्गठन भी सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में योगदान देगा। नए नियामक के आदेश निम्नानुसार हो सकते हैं:

---

[158] http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-09/05/content_31602351.htm
[159] https://www.livelaw.in/taking-environmental-law-seriously-indian-perspective/
[160] http://cercenvis.nic.in/PDF/Reg_Bodies_National.pdf

- नियामक के पास पर्यावरणीय मंज़ूरी के लिए औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करने की शक्तियां होंगी
- नियामक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के प्रत्याशित मान्यता की प्रक्रिया की देखरेख करेगा
- नियामक पर्यावरण मंज़ूरी में निर्धारित शर्तों को लागू करना सुनिश्चित करेगा
- घोषणा पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमणियन के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के विपरीत है।
- समिति ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण को मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की शक्तियों को लेने का सुझाव दिया था।

○ बिजनेस स्टैंडर्ड्स के एक लेख के अनुसार, भारत ने कई नियामकों को स्थापित किया है। हालाँकि, प्रत्येक नियामक या तो किसी कानून में शामिल होता है या उसके पास एक मूल विभाग होता है जो सत्ताधारी सरकार द्वारा संभाला जाता है। स्वीडन में, सरकार ने एक स्वतंत्र जलवायु नीति परिषद बनाई है, जो इस बात का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करेगी कि सरकार द्वारा प्रस्तुत समग्र नीति, जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल कैसे है। परिषद इस बात का मूल्यांकन करता है कि विभिन्न नीति क्षेत्रों की दिशा जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना को कैसे बढ़ाएगी या कम करेगी। इस प्रक्रिया में, सरकार को इस बात की स्पष्ट रिपोर्ट देनी होगी कि किस तरह से कार्य प्रगति पर है जिसकी समीक्षा स्वतंत्र जलवायु **नीति परिषद द्वारा की जाएगी।**[161] **इस प्रकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समान तर्ज पर एक स्वतंत्र नियामक निकाय बना सकते हैं जो प्रभावी पर्यावरण शासन की दिशा में योगदान देगा।**

---

[161] https://www.government.se/495f60/contentassets/883ae8e123bc4e42aa8d59296ebe0478/the-swedish-climate-policy-framework.pdf

संकेतक 9.03: यात्रा और पर्यटन उद्योग के विकास की स्थिरता

परिभाषा: "आपकी सरकार के प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रभावी हैं कि यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को स्थायी रूप से विकसित किया जा रहा है?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = बहुत अप्रभावी, क्षेत्र का विकास पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित मुद्दों को ध्यान में नहीं रखता है; 7 = बहुत प्रभावी, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित मुद्दे सरकार की रणनीति के लिए मुख्य हैं) ।

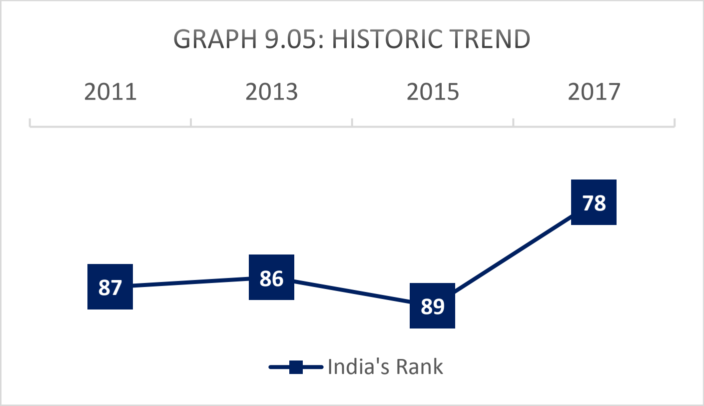

ग्राफ 9.05 संकेतक 9.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 11 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.69% का योगदान देता है।

तालिका 9.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारणs
संयुक्त अरब अमीरात	1	6.49	1	6.27	शीर्ष प्रदर्शक
न्यूज़ीलैंड	4	5.87	2	5.85	शीर्ष प्रदर्शक
रवांडा	3	5.92	3	5.84	शीर्ष प्रदर्शक
स्लोवेनिया	103	3.82	46	4.66	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
चीन	58	4.6	63	4.41	एशियाई साथी
भारत	**89**	**4.08**	**78**	**4.17**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **ग्रामीण भारत में स्थायी / प्रभाव पर्यटन**
    - पर्यटन मंत्रालय ने आतिथि देवो भव 'पहल के तहत सामाजिक जागरूकता अभियान पर ध्यान कैंद्रित करने के साथ सतत पर्यटन पर 12 वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर निरंतर सफाई अभियान चलाने के लिए स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संघों आदि का समावेश किया गया है।[162] हालांकि, ग्रामीण भारत में स्थायी पर्यटन की कमी है, जहां देखा गया हैं कि, ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा मितव्ययी कृषि पर जीवम यापन कर रहा है।
    - इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव पर्यटन को अपनाया जा सकता है। यह एक सामुदायिक और पर्यटन-कैंद्रित दृष्टिकोण है, जिसमें पर्यटन को स्थायी सामुदायिक आधारिक संरचना में मदद करने और वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डब्ल्यूईएफ़एफ के लेख के अनुसार, गाँव-आधारित प्रभाव पर्यटन मॉडल 15 मिलियन अतिरिक्त पर्यटकों को अकेले गाँवों में लाकर भारत की पर्यटन को 25 बिलियन डॉलर तक बढ़ा सकता है, और साथ ही इस प्रक्रिया[163] में 100,000 गाँव-स्तरीय उद्यमी बना सकता है।
    - उदाहरण के लिए, भारत में, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा कृषि विरासत की सरलता और विशिष्टता पर आधारित 13 ग्लोबली महत्वपूर्ण कृषि विरासत स्थल (जीआईएएच) (जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है) हैं, जिनका लाभ प्रभाव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा सकता है। इन साइटों मेंआय और आजीविका सुरक्षा बनाने की उच्च क्षमता है, अगर इसे आला दर्ज़े की कृषि और टिकाऊ पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रबंधित किया जाता है।[164]
    - **इसलिए, पर्यटन मंत्रालय स्थानीय राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर सकता है जो सामाजिक संगठनों के साथ हाथ से काम कर सकते हैं, विभिन्न गांवों में प्रमुख विकास स्थलों और प्रणालियों की पहचान कर सकते हैं, और फिर इन स्थलों को विकसित करके पर्यटन स्थलों के रूप में इन स्थलों को विकसित करने में मदद करने के लिए प्रभाव पर्यटन मॉडल का उपयोग**

[162] http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=137882
[163] https://www.weforum.org/agenda/2017/10/secret-india-tourism/
[164] http://www.mssrf.org/content/biodiversity-and-sustainable-tourism-development

कर सकते हैं। इसके द्वारा दो उद्देश्य एक साथ प्राप्त होंगें: पर्यटकों को जीवन भर के लिए एक अनुभव और यादें प्रदान करना और ग्रामीणों को अपनी आजीविका में सुधार करने के अवसर प्रदान करना।

विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत स्थल (जीआईएएच) - प्रमाणित, समीक्षा और अनंतिम के तहत

गतिविधि	राज्य
कोरापुट पारंपरिक कृषि प्रणाली (आदिवासी कृषि)	ओडिशा
कुट्टनाड समुद्र तल से नीचे खेती प्रणाली (समुद्र तल से नीचे चावल की खेती)	केरल
सेफ्रन हेरिटेज (केसर की खेती में पारिवारिक खेती)	जम्मू और कश्मीर
ग्रैंड एनीकट (कल्लनई) खेती प्रणाली	तमिलनाडु
कटमरैन फिशिंग सिस्टम	तमिलनाडु
कोरांगनडु सिल्वो-देहाती प्रणाली	तमिलनाडु
सोपिना बेटस सिस्टम	पश्चिमी घाट
सेथमघाट की जनजातीय कृषि प्रणाली	आंध्र प्रदेश
अपातानी राइस फिश कल्चर सिस्टम	अरुणाचल प्रदेश

स्रोत: खाद्य और कृषि संगठन

मध्यम अवधि की योजना

- **स्मार्ट पर्यटन के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)**
    - भारत की वर्तमान आईसीटी प्रणाली में पर्यटकों को उचित गंतव्य सूचनाओं से जोड़ने में कमी है और कुछ निश्चित रुकावटें भी हैं। उदाहरण के लिए, इंटरनेट और www के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना एक बुद्धिमान भरा साधन है, लेकिन कई बार, किसी को भी मिलने वाली जानकारी बहुत अधिक तोड़-मरोड़ की हुयी होती है। कोई भी केवल एक बुद्धिमान नेविगेशन के बाद ही प्रासंगिक सामग्री पाता है, जो काफी समय लेती है। कभी-कभी, वेब पर जानकारी की प्रस्तुति पर्याप्त आकर्षक नहीं होती हैं।[165]
    - उपरोक्त मुद्दे को दूर करने के लिए, चीन सरकार ने 2011 में नानजिंग शहर में अपनी "स्मार्ट टूरिज्म" पहल शुरू की। उन्होंने आईसीटी- एकीकृत पर्यटन मंच विकसित किया हैं, जो विभिन्न पर्यटन सूचना स्रोतों को एकीकृत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इसने

[165] https://pdfs.semanticscholar.org/111e/eabb4c758252fc3a507969ec74ec9b53300d.pdf

नवीन मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर पर्यटकों को स्पष्ट जानकारी और संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया हैं। स्थानीय सरकार (यानी, नानजिंग पर्यटन समिति) और पर्यटन व्यवसायों के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी से निम्नलिखित पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हुई है:

- एक स्मार्ट पर्यटन केंद्रीय प्रबंधन मंच की स्थापना की है, जो पर्यटन सूचना को अधिक प्रभावी ढंग से संभालता है।
- एक स्मार्ट पर्यटन एपीपी विकसित किया गया है जो शहर के दर्शनीय स्थलों, होटल, रेस्तरां, परिवहन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
- एक ग्रामीण स्मार्ट पर्यटन विपणन मंच का निर्माण, और उपनगरीय क्षेत्रों में पर्यटन संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्र करना, साथ ही स्थानीय आतिथ्य सुविधाओं और संस्कृति से संबंधित जानकारी।
- नानजिंग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पायलट परियोजनाओं का संचालन करना।
- नानजिंग में हर पर्यटक आकर्षण में 42 इंच के टच-स्क्रीन डिस्प्ले से पर्यटन से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले इंटरैक्टिव अनुभव टर्मिनलों का निर्माण।[166]

  - **इसलिए, पर्यटन मंत्रालय चीन के समान मॉडल को अपना सकता है और भारत में स्मार्ट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निजी संगठनों के साथ सहयोग कर सकता है जो भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए नए भविष्य की स्थापना में मदद करेगा।**

दीर्घकालिक योजना

- **हरित नीति कार्यक्रम का कार्यान्वयन**
  - स्लोवेनिया में, प्रत्येक गंतव्य जो स्लोवेनिया ग्रीन लेबल प्राप्त करना चाहता है, उसे आधिकारिक प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में एक हरित विकास नीति पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है और जागरूकता बढ़ाने, गंतव्य प्रोफ़ाइल बनाने, और सांख्यिकी डाटा के संग्रहण सहित 7-चरण की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। एक बार प्रमाणित होने के बाद, गंतव्य समन्वयकों को हर दो से तीन वर्षों में पुनर्मूल्यांकन चरण में प्रवेश करने के लिए वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। स्थिरता के स्तर के अनुसार जो बनाए रखा गया है, उनके प्रमाणन में

[166] http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/global_report_public_private_partnerships_v8.pdf

गंतव्य कांस्य से प्लैटिनम तक बढ़ सकते हैं। स्लोवेनिया ग्रीन प्रमाणपत्र के लिए अर्हता प्राप्त करने से पहले होटलों को ग्रीन ग्लोब, यात्रा जीवन या यूरोपीय संघ इकोलेबेल जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन पहलों ने स्लोवेनिया में पर्यटकों की आमद में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है।[167]

- दूसरी तरफ, भारत में स्थायी पर्यटन के लिए स्थानीय पर्यटन स्थल के बीच प्रतिस्पर्धा की कमी एक प्रमुख मुद्दा है। इसलिए, इसे सुधारने के लिए, पर्यटन मंत्रालय एक समग्र प्रमाणन योजना भी स्थापित कर सकता है। **प्रत्येक गंतव्य को हरित प्रमाणन के साथ मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने के लिए, अंततः उन्हें एक हरित विकास नीति पर हस्ताक्षर करना होगा।**

[167] https://www.slovenia.info/en

संकेतक 9.04: पार्टिकुलेट मैटर (2.5) सांद्रता

परिभाषा: यह संकेतक PM2.5 के लिए जनसंख्या-भारित जोखिम (माइक्रो-ग्राम (10^{-6}) प्रति घन मीटर) को संदर्भित करता है

स्रोत: येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक

देश का मूल्य = औसत एक्सपोज़र की गणना पीएम 2.5 की सांद्रता को आबादी द्वारा गुणा करके की जाती है।

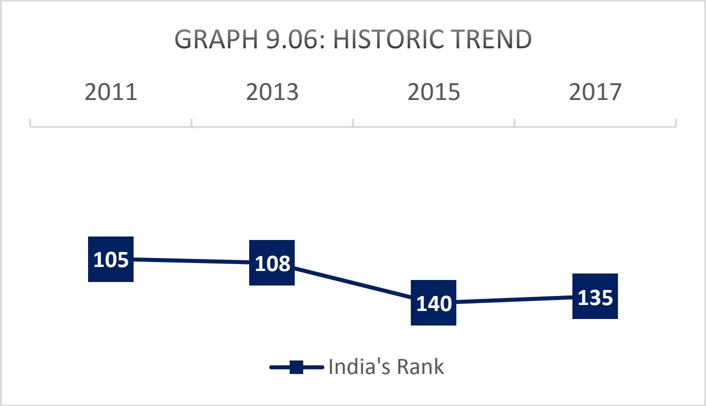

ग्राफ 9.06 संकेतक 9.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 5 स्थान की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.69% का योगदान देता है

तालिका 9.05: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
मॉरीशस	2	1.46	1	0.6	एशियाई साथी
न्यूज़ीलैंड	3	2.14	2	1.2	शीर्ष प्रदर्शक
बारबाडोस	9	3.02	3	1.4	शीर्ष प्रदर्शक
यूएसए	65	7.47	58	6.8	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**140**	**31.98**	**135**	**32.9**	
चीन	141	48	136	47.2	एशियाई साथी

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **शीर्ष 5 प्रदूषित शहरों में एयर प्यूरीफायर की स्थापना**[168]
    - 2018 में, 7 भारतीय शहरों का दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है, जहां PM 2.5 सामग्री 144-175ug/ m^3 के बीच है।
    - चीन भी प्रदूषण की एक समान स्थिति का सामना कर रहा है और इस मुद्दे को दूर करने के लिए, चीन के पृथ्वी पर्यावरण संस्थान ने दुनिया के सबसे प्रदूषित उत्तरी शहर जियान में दुनिया के सबसे बड़े वायु शोधक का निर्माण किया है। प्रयोगात्मक स्मॉग-चूसने वाला टॉवर 100 मीटर से अधिक लंबा है और इसे शहर में हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ हवा 70-75% साफ़ पाई जाती है। प्रणाली में टॉवर के आधार पर स्थित विशेष रूप से अनुकूलित ग्रीनहाउस की एक श्रृंखला शामिल है, जो प्रदूषित हवा को चूसते हैं और इसे सौर ऊर्जा से गर्म करते हैं। वायु फिर वायुमंडल में छोड़े जाने से पहले सफाई फिल्टर की परतों के माध्यम से उठती है। आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण की निगरानी करने वाले स्टेशन ने पाया कि एक सामान्य दिन में औसत स्तर की तुलना में भारी प्रदूषण के समय पीएम 2.5 का स्तर 15% गिर गया है।
    - **इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत के प्रमुख शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए समान तकनीकी प्रगति को अपना सकता है।**

मध्यम अवधि की योजना

- भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत ईंधन और बायोमास जलाना, ईंधन में मिलावट और वाहन उत्सर्जन हैं। शरद ऋतु और सर्दियों के महीनों में, कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फसल अवशेषों को जलाना (मैकेनिकल टिल्लिंग का एक कम लागत वाला विकल्प) धुएं, धुंध और कण प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। हालाँकि, भारत में ग्रीनहाउस गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है, लेकिन

[168] https://www.weforum.org/agenda/2018/02/china-has-built-the-world-s-largest-air-purifier-to-battle-smog/

पूरे देश में चीन और यूनाइटेड स्टेट्स[169] के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इसलिए, इस मुद्दे से निपटने के लिए, स्वच्छ वायु मिशन भारत अभियान की शुरुआत और प्रचार भारत में किया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

[169] http://documents.worldbank.org/curated/en/223591468164352248/pdf/multi0page.pdf

- **स्वच्छ वायु मिशन भारत**[170]
  - स्वच्छ भारत (स्वच्छ भारत) मिशन की तर्ज पर, भारत सरकार को भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्वच्छ वायु मिशन शुरू करना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर की रणनीतियों का मसौदा तैयार करने और कार्यान्वित करने के द्वारा किया जा सकता है।
  - मिशन का उद्देश्य निर्धारित समय सीमा में देश के सभी स्थानों पर निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होना चाहिए।
  - यह स्वच्छ वायु मिशन [सीएएम भारत] परिवहन, बिजली, निर्माण, कृषि, ग्रामीण विकास और पर्यावरण के साथ-साथ शहर और राज्य क्षेत्राधिकार के साथ काम करने वाले कई मंत्रालयों में वायु प्रदूषण शमन के लिए विशेष रूप से बनाई गई सरकारी नीतियों को लागू करने का लक्ष्य रख सकता है।
  - स्वच्छ वायु मिशन भारत के प्रस्तावित घटक हैं::
    - **वायु की गुणवत्ता की निगरानी और स्रोतों का मूल्यांकन:** निगरानी, उत्सर्जन सूची और क्षेत्रीय स्रोत अनुप्रयोग
    - **लक्षित वायु गुणवत्ता प्रबंधन:** नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय रणनीति
    - **बहु-स्तरीय और क्रॉस-सेक्टोरल समन्वय:** केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों के बीच समन्वय
    - **क्षमता निर्माण:** सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) और एसपीसीबी (राज्य प्रदूषण बोर्ड) की संस्थागत मजबूती

      जन जागरूकता और भागीदारी

दीर्घकालिक योजना

- **उद्योगों में उत्सर्जन व्यापार योजना का प्रवर्तन**[171]
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान की है, जो निलंबित कण पदार्थ, गैसों और अपशिष्टों के संदर्भ में पर्यावरण में भारी योगदान देते हैं।[172] इस बात की व्यापक स्वीकार्यता है कि जलवायु परिवर्तन की समस्याओं में भारत का बड़ा योगदान है। एक उत्सर्जन व्यापार योजना को स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि भारत को भी अपने लिए उत्सर्जन कैप पर सहमत होना होगा।[173] औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़े उद्योगों के लिए **उत्सर्जन व्यापार योजनाएं**

[170] http://www.teriin.org/sites/default/files/2018-03/policy-brief-air-pollution-in-urban-centres-of-India.pdf
[171] http://www.teriin.org/sites/default/files/2018-03/policy-brief-air-pollution-in-urban-centres-of-India.pdf
[172] https://www.downtoearth.org.in/tag/industry
[173] https://www.lawctopus.com/academike/emission-trading-scheme-overview-indian-perspective/

(ईटीएस) विकसित और लागू की जाती हैं। यह कार्बन कार्बन ट्रेडिंग योजनाएं जिसमें उत्सर्जन पर एक कैप एक क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाता है और प्रत्येक योगदान देने वाले उद्योग के लिए आवंटित किया जाता है। यह कार्बन उत्सर्जन और वायुमंडलीय प्रदूषण के अन्य रूपों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली है जिसके द्वारा उत्सर्जन राशि पर एक ऊपरी सीमा निर्धारित की जाती है जो किसी भी व्यवसाय या अन्य संगठन का उत्पादन कर सकती है। यह उन अन्य संगठनों से भी खरीदे जाने की क्षमता प्रदान करता है जिन्होंने अपने पूर्ण भत्ते का उपयोग नहीं किया है। इसी तरह के कार्यक्रम यूएसए में सल्फर डाइऑक्साइड के कैप और व्यापार तंत्र के रूप में पेश किए गए हैं।[174]

- **इसलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सहयोग से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) उत्सर्जन व्यापार योजना को लागू कर सकते हैं,** जिसके माध्यम से वे क्षेत्र के लिए वांछित प्रदूषक सांद्रता और उत्सर्जन परमिट के आधार पर उद्योगों के लिए कैप निर्धारित कर सकते हैं। ऊपरी सीमा फिर इन उद्योगों के लिए निर्धारित की जा सकती है, जो या तो अपने कैप का अनुपालन कर सकते हैं या बाजार से क्रेडिट खरीद सकते हैं। यह कार्यक्रम लागत प्रभावी साबित होगा और नवाचार को भी बढ़ावा देगा।

- **अवशेष जलाने को हटाने के लिए सतत मॉडल का विकास**[175]

कृषि गतिविधियाँ धूल पैदा करती हैं और वायु प्रदूषण की समस्या को और अधिक बढ़ाती हैं। इन अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने की आवश्यकता है, जो नीचे दिए गए दिशानिर्देशों पर इस अवशेषों के संग्रह, परिवहन और प्रबंधन के लिए एक व्यवसाय मॉडल के विकास और गोद लेने के द्वारा किया जा सकता है:

  - प्रोत्साहन और सजा के माध्यम से खेत में फसल अवशेषों के जलने की रोकथाम और निगरानी पर उचित कानून का विकास और कार्यान्वयन।
  - उन किसानों को लाभान्वित करने के लिए सी-क्रेडिट योजनाओं का परिचय देना जो कार्बन अनुक्रम और जीएचजी शमन के लिए कृषि संरक्षण का पालन करते हैं।
  - फसल अवशेषों की अवधारण / जल की उचित निगरानी और मृदा स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड में संरक्षण कृषि के घटक को शामिल करना।

---

[174] https://environmentallaw.uslegal.com/federal-laws/clean-air-act/
[175] http://www.teriin.org/sites/default/files/2018-03/policy-brief-air-pollution-in-urban-centres-of-India.pdf

- फसल अवशेषों को संशोधन (जैसे चूना या जिप्सम) के रूप में वर्गीकृत करना और कृषि में उनका उपयोग किसी भी अन्य खनिज उर्वरक या संशोधन की तरह की सब्सिडी को आकर्षित कर सकता है।[176]

किसानों से कृषि-अवशेष खरीद के लिए एक राज्य / राष्ट्रीय स्तर की खरीद एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, इसमें बायोमास सामग्री के संग्रह, भंडारण और आपूर्ति के लिए ग्राम स्तर के संस्थान और स्थानीय उद्यमी शामिल होंगे। इसे मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम) और पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) से भी जोड़ा जा सकता है। इसके माध्यम से, सीज़न और ऑफ-सीज़न अवधि के दौरान बायोमास सामग्री की कीमतों के जंगली उतार-चढ़ाव को बायोमास भूखंड सुविधाओं को स्थापित करके भी संबोधित किया जा सकता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में जलते अवशेषों को नष्ट करने में स्थायी मॉडल प्राप्त करने के लिए उपरोक्त रणनीतियों को लागू कर सकता है।

[176] http://www.iari.res.in/files/Important_Publications-2012-13.pdf

संकेतक 9.05: पर्यावरणीय संधि अनुसमर्थन

परिभाषा: यह संकेतक 27 के सेट से कुल अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संदर्भित करता है जिसमें एक राज्य भागीदार होता है। एक राज्य, एक भागीदार के रूप में स्वीकार किया जाता है, जब उसकी स्थिति प्रत्येक संधि के लिए, अनुममर्थन, परिग्रहण या कार्यान्वित के रूप में प्रकट होती है।

स्रोत: प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूआईएसएनएन), पर्यावरण कानून केंद्र ईएलआईएस संधि डाटा बेस।

देश का मूल्य = कुल पर्यावरणीय संधियों की संख्या (0-32 पैमाने, जहाँ 32 सर्वश्रेष्ठ है)

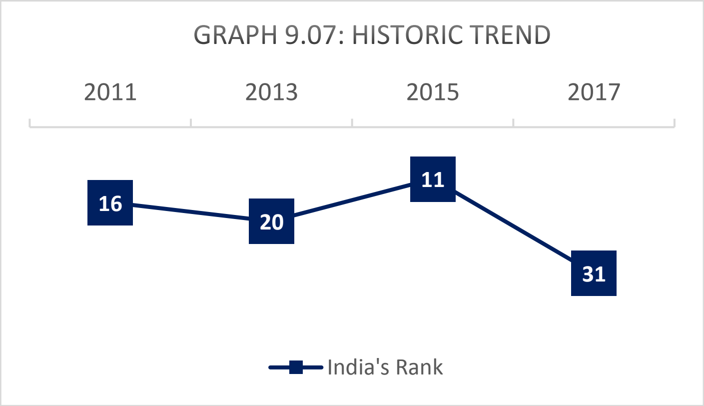

ग्राफ 9.07 संकेतक 9.05 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 20 पदों की कमी आई हैं। यह सूचक देश के स्कोर में 0.69% का योगदान देता है।

तालिका 9.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
डेनमार्क	1	25	1	30	शीर्ष प्रदर्शक
नीदरलैंड	4	24	7	29	शीर्ष प्रदर्शक
बुल्गारिया	11	23	10	28	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**11**	**23**	**31**	**24**	

इस संकेतक में 6 देशों की पहली श्रेणी है क्योंकि इन सभी का समान मूल्य 30 है

2017 टीटीसीआई रिपोर्ट के लिए, संधियों पर हस्ताक्षर किए गए और वह संधियां जो वर्ष 2015 तक लागू हुई केवल उन्हीं को गिना गया हैं। भारत ने 2015 तक जिन 27 संधियों पर हस्ताक्षर किए, उन्हें नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 9.07: अंतर्राष्ट्रीय संधियों की स्थिति की सूची (भारत)[177]

क्रमांक	संधियां	परिग्रहण	अनुममर्थन	कार्यान्वित
1	लिंग के विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1948 वाशिंगटन	9-मार्च-81		9-मार्च-81
2	1962 और 1969, 1954 लंदन में संशोधन के अनुसार तेल, 1954 द्वारा समुद्र के प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन		4-मार्च-74	4- जून - 74
3	अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर सम्मेलन विशेष रूप से वाटरफाउल हैबिटेट, 1971 रामसर	2- दिसंबर -77		2- अप्रैल - 78
4	विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के बारे में कन्वेंशन, 1972 पेरिस		19- दिसंबर -95	19- मार्च - 96
5	वन्य जीवों और वनस्पतियों, लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1973 वाशिंगटन		20- जुलाई -76	18- अक्टूबर-76
6	1978, लंदन के प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित शिल्स (एमएआरपीओएल) से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	25- जून - 85		25- सितंबर - 85
7	वन्य जीवों के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर कन्वेंशन, 1979 बॉन	12- जुलाई -83		1- नवंबर- 83
8	संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, 1982 मोंटेगो बे		29- जून - 95	29- जुलाई -95
9	ओजोन परत के संरक्षण पर कन्वेंशन, 1985 वियना	18- मार्च - 91		16- जून - 91

[177] https://www.ecolex.org/

10	उन पदार्थों पर प्रोटोकॉल जो ओजोन परत को श्रीण करते है, 1987 मॉन्ट्रियल	19- जून - 92		17- सितंबर - 92
11	खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान, ट्रांसबाउन्ड्री आंदोलनों के नियंत्रण पर कन्वेंशन, 1989 बेसल		24- जून - 92	23- सितंबर - 92
12	तेल प्रदूषण की तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन , 1990 लंदन		21- जून - 93	13- मई- 95
13	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 1992 न्यूयॉर्क		1- नवंबर- 93	21-मार्च- 94
14	जैव विविधता पर कन्वेंशन, 1992 रियो डी जनेरियो		18-फरवरी -94	19- मई- 94
15	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उन देशों में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए, गंभीर सूखे और / या रेगिस्तान का अनुभव कर रहे हैं, विशेष रूप से अफ्रीका, 1994 पेरिस		17- दिसंबर -96	26- दिसंबर - 96
16	संयुक्त राष्ट्र के भाग XI के कार्यान्वयन से संबंधित समझौता 10 दिसंबर 1982 के सागर के कानून पर कन्वेंशन, 1994 न्यूयॉर्क		29- जून - 95	28- जुलाई -96
17	स्ट्रैडलिंग फिश स्टॉक्स और अत्यधिक प्रवासी मछली स्टॉक्स के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रावधानों से संबंधित समझौता, 1995 न्यूयॉर्क	19-अगस्त-03		18- सितंबर - 03
18	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मलेन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो 1997	26-अगस्त-02		16-फरवरी -05
19	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998 रॉटरडैम	24- मई-05		24-अगस्त-05

20	जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसैफिटी, 2000 मॉन्ट्रियल		17- जनवरी -03	11- सितंबर - 03
21	जिद्दी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मलेन, 2001 स्टॉकहोम		13- जनवरी -06	13-अप्रैल-06
22	खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, 2001 रोम	4-मार्च-04		29- जून - 04
23	इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर कमिशन, 2006 जिनेवा		25- जुलाई -08	7- दिसंबर -11
24	जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के लिए देयता और निवारण पर पूरक प्रोटोकॉल, 2010 नागोया - कुआलालंपुर		19-दिसंबर -14	5-मार्च-18
25	आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके निष्पक्ष और न्यायसंगत विविधता पर उनके उपयोग से होने वाले लाभ को साझा करने का प्रोटोकॉल, जैविक विविधता पर सम्मलेन, नागोया 2010		9- अक्टूबर -12	12- अक्टूबर-14
26	बुध पर सम्मेलन, मिनामाता, 2013		18- जून - 18	16- सितंबर - 18
27	पेरिस समझौता 2015		2- अक्टूबर-16	4- नवंबर-16

स्रोत: इकोलेक्स

भारत की भावी स्थिति

- भारत सरकार ने वर्ष 2016 और 2018 में तीन नई संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसा कि तालिका 9.08 में दिखाया गया है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि यदि प्रत्येक देश वर्ष 2019 की तरह ही प्रदर्शन करता है, तो आगामी 2019 टीटीसीआई रिपोर्ट में भारत की श्रेणी बढ़ जाएगी।.

तालिका 9.08: अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सूची (हस्ताक्षरित लेकिन शामिल नहीं, भारत)

संधियां	परिग्रहण	अनुममर्थन	कार्यान्वित
जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के लिए देयता और निवारण पर पूरक प्रोटोकॉल, 2010 नागोया - कुआलालंपुर		19- दिसंबर-14	5- मार्च-18
बुध पर सम्मेलन, मिनामाता, 2013		18- जून-18	16-सितंबर18
पेरिस समझौता 2015		2- अक्टूबर-16	4- नवंबर -16

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

दीर्घकालिक योजना

- भारत सरकार ने किसी भी श्रेणी के तहत छह संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जैसे कि परिग्रहण, अनुसमर्थन या कार्यान्वित जैसा कि नीचे तालिका 9.09 में दिखाया गया है। इसलिए, भारत सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दीर्घकालिक योजना को इन संधियों पर हस्ताक्षर करने का विचार बना रहे है।

तालिका 9.09: अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सूची (हस्ताक्षरित नहीं, भारत)

संधियां	परिग्रहण	अनुममर्थन	कार्यान्वित
कचरे और अन्य पदार्थ के डंपिंग द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर सम्मलेन, 1972 लंदन, मैक्सिको सिटी, मास्को, वाशिंगटन	–	–	–
ट्रांसबाउन्ड्री जलस्रोतों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मलेन, 1992	–	–	–
अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों के गैर-नेविगेशनल उपयोगों के कानून पर सम्मेलन, 1997	–	–	–

पर्यावरण संबंधी मामलों में सूचना, सार्वजनिक भागीदारी में निर्णय लेने और पर्यावरण संबंधी मामलों में न्याय तक पहुंच के लिए सम्मेलन, 1998	_	_	_
खतरनाक और विषाक्त पदार्थों द्वारा प्रदूषण की घटनाओं के लिए तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग पर प्रोटोकॉल, 2000 लंदन	_	_	_
प्रदूषक रिलीज और स्थानांतरण रजिस्टर पर प्रोटोकॉल 2003	_	_	_

स्रोत: इकोलेक्स

ध्यान दें - संकेतक 9.06 और 9.09 को एक एकल संकेतक के रूप में दिखाया जा रहा है क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं और पानी के तनाव को मिटाने के लिए जल प्रबंधन के समान मानदंडों पर निर्भर करता है।

संकेतक 9.06: बेसलाइन जल तनाव

परिभाषा: यह संकेतक अनुमानित भविष्य के देश-स्तर के पानी के तनाव को एक व्यवसाय के तहत 2020 के लिए वार्षिक जल निकासी डाटा पर आधारित सामान्य (बीएयू) परिदृश्य के रूप में संदर्भित करता है।

स्रोत: वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एक्वाडक्ट

$$\textbf{देश का मूल्य}* = \frac{\text{कुल वार्षिक जल निकासी} \times 100}{\text{कुल वार्षिक उपलब्ध सतही जल}}$$

*** गणना के बाद (0-5) के पैमाने पर देश के मूल्य को सामान्यीकृत किया जाता है।**

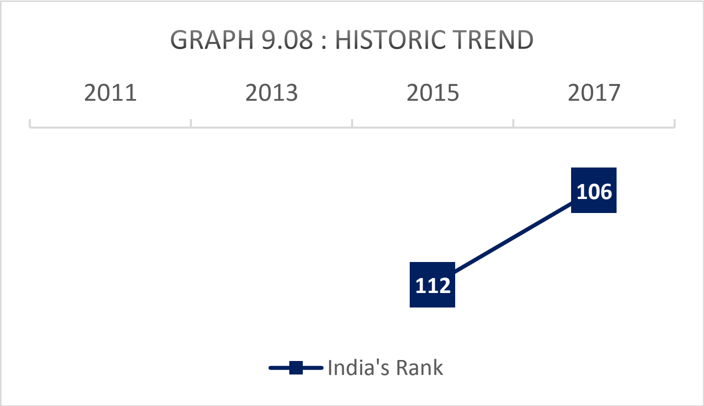

ग्राफ 9.08 संकेतक 9.06 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 6 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.69% का योगदान देता है।

तालिका 9.10: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
भूटान	32	0.45	1	0	एशियाई साथी
बुरुंडी	1	0	1	0	शीर्ष प्रदर्शक
रवांडा	1	0	1	0	शीर्ष प्रदर्शक
ज़ाम्बिया	12	0.07	1	0	शीर्ष प्रदर्शक
मलावी	14	0.1	1	0	शीर्ष प्रदर्शक
जापान	93	3.06	78	2.31	एशियाई साथी
भारत	**112**	**3.58**	**106**	**3.69**	

इस संकेतक में 7 देशों की पहली श्रेणी है, क्योंकि उन सभी का मूल्य 0 है।

संकेतक की पृष्ठभूमि: पानी का तनाव कुल वार्षिक जल निकासी (नगरपालिका, औद्योगिक और कृषि) को मापता है जो कुल वार्षिक जल ताजा पानी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उच्चतर मूल्य उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा का संकेत देते हैं। पानी का तनाव 0-5 पैमाने से मापा जाता है, जहां [0-1] कम है (<10%) और [4-5] अत्यंत उच्च (> 80%) हैं

संकेतक 9.09: अपशिष्ट जल उपचार

परिभाषा: यह संकेतक अपशिष्ट जल के प्रतिशत को संदर्भित करता है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में वापस जारी होने से पहले इलाज किया जाता है।

स्रोत: येल सेंटर फ़ॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी (वाईसीईएलपी) और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क (सीआईईएसआईएन) का सेंटर, पर्यावरण प्रदर्शन

$$\text{देश का मूल्य} = \frac{\text{कुल उपचार किया गयाअपशिष्ट जल} \times 100}{\text{कुल एकत्र किया गया अपशिष्ट जल}}$$

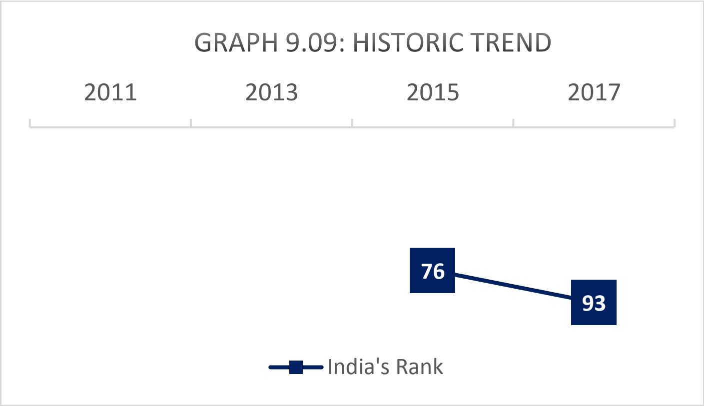

ग्राफ 9.09 संकेतक 9.09 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 17 पदों की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.69% का योगदान देता है।

तालिका 9.11: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
सिंगापुर	1	99.65	1	100	एशियाई साथी
नीदरलैंड	2	98.81	2	99.27	शीर्ष प्रदर्शक

लक्समबर्ग	6	95	3	96.84	शीर्ष प्रदर्शक
जापान	25	71.26	36	56.53	एशियाई साथी
भारत	**76**	**10.48**	**93**	**2.24**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **सुलभ जल पहल**
  - पिछले वर्षों में, बिहार के कई हिस्सों में भूजल आर्सेनिक और अन्य रासायनिक प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लंबे समय तक पीने के पानी में आर्सेनिक के अधिक उपयोग से लोगों के जीवन पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रभाव पड़े हैं। मिट्टी की उर्वरता में कमी, उत्पादकता और खाद्य श्रृंखला के विघटन के कारण कृषि गतिविधि भी बाधित हो रही है। इसलिए, पीने के पानी की कमी का सामना करने के लिए, सुलभ इंटरनेशनल ने 2018 में बिहार में प्रोजेक्ट सुलभ जल पेश किया है, जिसका उद्देश्य दूषित तालाब के पानी को सुरक्षित पेयजल में बदलना है।
  - परियोजना की स्थापना लागत रुपये 20 लाख के आसपास है और इसमें प्रति दिन 8,000 लीटर पीने के पानी का उत्पादन करने की क्षमता होगी जो कि 50 पैसे प्रति लीटर की बोतल[178] पर बेचा जा रहा है।
  - घटती पुनर्भरण दर और तेजी से बढ़ती निष्कर्षण गति के साथ, भूजल की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भूजल संदूषण की समस्या स्थिति को और खराब करती है। भारत में, 19 राज्यों ने फ्लोराइड से पानी के दूषित होने और कम से कम 10 राज्यों में आर्सेनिक से दूषित होने की सूचना दी है। **इसलिए, जल संसाधन मंत्रालय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह भारत भर में सुलभ जल जैसी अभिनव प्रथाओं को लागू करने के लिए खरीदने की क्षमता और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे।**

मध्यम अवधि की योजना

- **सीवेज उपचार संयंत्र की क्षमता बढ़ाना (एसटीपी)**
  - वर्तमान में 22649 मिलियन लीटर प्रतिदिन की कुल क्षमता वाले कुल 746 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भारत में मौजूद हैं जिनमें से केवल 522 ही चालू हैं। 224 सीवेज उपचार संयंत्र या तो

[178] http://www.sulabhinternational.org/sulabh-jal-innovation-approach-to-provide-cheapest-drinking-water-in-bihars-darbhanga/

निर्माणाधीन हैं या वर्तमान में गैर-परिचालन में हैं। सरकार द्वारा 70 नए सीवेज उपचार संयंत्र प्रस्तावित किए गए हैं। 522 काम में लिए जाने वाले एसटीपी की क्षमता 18883.2 मिलियन लीटर प्रतिदिन[179] है जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 9.12: SटीएटीUS OF एसटीपीs

स्थिति	एसटीपी की संख्या	क्षमता [एमएलडी]
परिचालन	522	18883.2
गैर परिचालन	79	1237.16
निर्माणाधीन	145	2528.36
प्रस्तावित	70	628.64
कुल	**816**	**23277.36**

- हालांकि, देश में सीवेज उपचार संयंत्रों का एक असमान वितरण है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छतीसगढ़, मणिपुर, और नागालैंड जैसे राज्यों में अपने क्षेत्र में कोई सीवेज उपचार संयंत्र नहीं है, जिसे तालिका 9.13 के माध्यम से भी देखा जा सकता है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पैदा होने वाले सीवेज के कचरे का लगभग 78% अनुपचारित[180] रहता है। इसलिए, उपचार और अनुपचारित अपशिष्ट जल के बीच की खाई को पाटने के लिए प्रभावी कदमों की तत्काल आवश्यकता है। यह तालिका 9.13 में उल्लिखित राज्यों में नए एसटीपी के निर्माण द्वारा किया जा सकता है या सभी 746 एसटीपी के कार्यात्मक को चालू करके हल किया जा सकता है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। वर्तमान एसटीपी की क्षमता में वृद्धि करना एक तरीका हो सकता है। **इसलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को**

[179]https://nrcd.nic.in/writereaddata/FileUpload/NewItem_210_Inventorization_of_Sewage-Treatment_Plant.pdf

[180] https://www.downtoearth.org.in/news/waste/-78-of-sewage-generated-in-india-remains-untreated--53444

सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सहयोग करना चाहिए और उसी के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

तालिका 9.13: बिना किसी जल निकासी संयंत्र (एसटीपी) के संचालन वाले राज्य

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	शहरी क्षेत्रों में सीवेज उत्पादन, (मिलियन लीटर प्रति दिन)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22
अरुणाचल प्रदेश	50
छत्तीसगढ़	951
दादरा और नागर हवेली	26
दामन और दियू	29
लक्षद्वीप	8
मणिपुर	132
नागालैंड	92
कुल	**1,310**

दीर्घकालिक योजना

- **प्रभावी प्रौद्योगिकी को अपनाना**
    - पहले से ही भारत की 60% से अधिक आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां वर्तमान पानी की आपूर्ति भविष्य की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। यदि पानी का विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता है, तो आज देखे जाने वाला संकट कल का प्रलय बन जाएगा[181]। इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपर्युक्त मुद्दे पर काबू पाने के लिए प्रभावी तकनीकों को अपनाना चाहिए।
    - **जापान द्वारा विलवणीकरण परियोजना:** कई वर्षों के लिए, फुकुओका शहर (जापान) पानी की कमी के कारण लंबे समय तक जलापूर्ति प्रतिबंध से ग्रस्त था। इसलिए, फुकुओका जिला वाटर एजेंसी ने 2005 में समुद्री जल विलवणीकरण सुविधा शुरू की जो वर्तमान में जापान में सबसे बड़ी विलवणीकरण सुविधाओं में से एक है। फुकुओका में अपनाई गई अलवणीकरण की विधि एक रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्ली विधि (आरओ) है। हाल के वर्षों में, कई देशों ने इसकी कम स्थापना के कारण इस पद्धति को अपनाया है। यह 10,000 m3 / दिन क्षमता की प्रत्येक पंक्ति के साथ पांच लाइनों से बना है[182]। यह 60% मीठे पानी की वसूली अनुपात (समुद्री जल से बरामद मीठे पानी की मात्रा) को प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है।
    - **इसी तर्ज पर, जल संसाधन मंत्रालय आईआईटी और एनआईटी जैसे शीर्ष तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर खारे पानी के रूपांतरण और सीवेज जल के पुनर्चक्रण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर सकता है ताकि मीठे पानी के संसाधन पर निर्भरता कम की जा सके।**

- **स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से भूजल प्रतिकृति मॉडल को अपनाना**
    - तरुण भारत सिंह के एनजीओ द्वारा स्थानीय जल चक्रों और जल संसाधनों की बहाली का राजस्थान में व्यापक प्रभाव पड़ा हैं। यह भूजल संसाधनों के पुनर्भरण में सुधार के लिए, छोटे पैमाने पर जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और वनों और मिट्टी के उत्थान के साथ, विशेष रूप से ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में इसे जोड़ने पर आधारित था।
    - इसके माध्यम से होने वाले प्रभाव महत्वपूर्ण है और राज्य भर के 1,000 गांवों में पानी वापस लाया गया है। पांच नदियां जो वार्षिक मानसून के मौसम के बाद सूखी रहतीथीं, अब फिर से

[181] http://wateraidindia.in/publication/water-gap-state-worlds-water-2018/
[182] https://www.niph.go.jp/soshiki/suido/pdf/h21JPUS/abstract/r9-2.pdf

स्थापित होकर मत्स्य पालन के साथ बह रही हैं। भूजल का स्तर अनुमानित छह मीटर तक बढ़ गया है और उत्पादक खेत 20% से बढ़कर 80% हो गए हैं। **इसलिए, जल संसाधन मंत्रालय ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर के काम कर सकता है और पूरे भारत में इस प्रकार के मॉडल को लागू कर सकता है ताकि भूजल पुनःपूर्ति और भूजल संसाधनों के पुनर्जनन को सुनिश्चित किया जा सके।**

संकेतक 9.07: लुप्तप्राय प्रजातियां

परिभाषा: यह संकेतक स्तनधारियों (एम), पक्षियों (बी) और उभयचर (ए) के लिए कुल ज्ञात प्रजातियों के प्रतिशत के रूप में गंभीर रूप से **लुप्तप्राय (सीआर), लुप्तप्राय (ईएन) और कमजोर (वीयू)** प्रजातियों की कुल संख्या को संदर्भित करता है।

स्रोत: द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूआईएसएनएन), रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{(\text{सीआर प्रजातियों की कुल संख्या} + \text{इएन प्रजातियों की कुल संख्या} + \text{वीयू प्रजातियों की कुल संख्या}) \times 100}{\text{कुल ज्ञात प्रजातियां}}$$

जहां इन प्रजातियों में स्तनधारी, पक्षी और उभयचर शामिल हैं

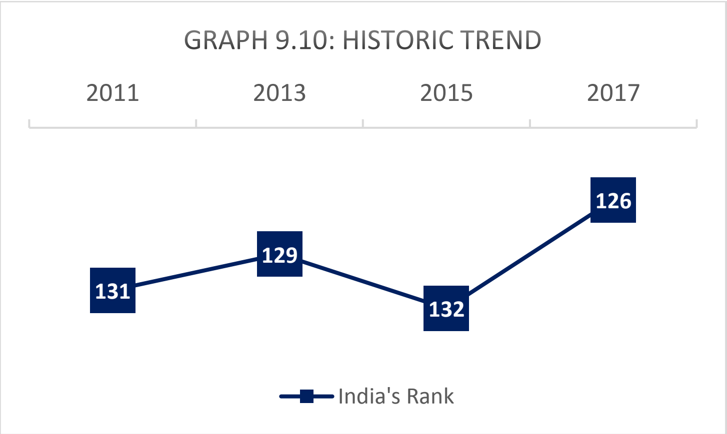

ग्राफ 9.10 संकेतक 9.0 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 6 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.69% का योगदान देता है।

तालिका 9.14: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
लक्समबर्ग	1	0.39	1	1.56	शीर्ष प्रदर्शक
बारबाडोस	10	2.1	2	2.52	शीर्ष प्रदर्शक
त्रिनिदाद और टोबैगो	17	2.67	3	2.88	शीर्ष प्रदर्शक
नेपाल	98	6.64	79	6.44	एशियाई साथी
चीन	125	11.54	120	11.74	एशियाई साथी
भारत	**132**	**13.55**	**126**	**13.49**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए तत्काल कार्य योजना**
  - आईयूसीएन स्पीशीज़ कमिशन के साथ काम करने वाला आईयूसीएन स्पीशीज़ सर्वाइवल प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सरकारों और राष्ट्रों को लेखक आधिकारिक जानकारी और सलाह प्रदान करता है। आईयूसीएन स्पीशीज़ सर्वाइवल कमिशन (एसएससी), विशेषज्ञ समूहों और साझेदार संगठनों के काम का उपयोग करते हुए आईयूसीएन स्पीशीज़ प्रोग्राम विभिन्न सरकारों के वैज्ञानिक अधिकारियों, फ़ौना और फ्लोरा (सीआईटीईएस) के लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन और जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) सलाह प्रदान करता है।
  - नीति के विकास में सहायता के लिए, आईयूसीएन एसएससी ने स्तनधारियों, उभयचरों और पक्षियों के लिए एक विशिष्ट विशेषज्ञ समूह का निर्माण किया है जो नीचे उल्लिखित है:
    - **स्तनपायी:** आईयूसीएन एसएससी स्तनधारी विशेषज्ञ समूह प्रजातियों के बेहतर अस्तित्व में योगदान करने के लिए दुनिया भर से विभिन्न विशेषज्ञ प्रदान करते हैं।[183]
    - **एम्फ़िबियन:** आईयूसीएन एसएससी एम्फ़िबियन स्पेशलिस्ट ग्रुप और एम्फ़िबियन सर्वाइवल एलायंस नए ज्ञान को इकट्ठा करने और उभयचरों के लिए प्रभावी संरक्षण कार्रवाई को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। [184]
    - **पक्षी (एवेस):** आईयूसीएन एसएससी पक्षी विशेषज्ञ समूह प्रजातियों के बेहतर अस्तित्व में योगदान करने के लिए दुनिया भर से विभिन्न विशेषज्ञ प्रदान करते हैं।[185]
  - **इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को स्तनधारियों, उभयचरों और पक्षियों के लिए प्रत्येक विशेषज्ञ समूह से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए क्षेत्रीय संरक्षण नीति तैयार करने के लिए सलाह लेने के लिए आईयूसीएन प्रजाति कार्यक्रम के साथ सहयोग करना चाहिए।**

मध्यम अवधि की योजना

- **कैप्टिव प्रजनन और लुप्तप्राय प्रजातियों का प्रजनन**

---

[183]https://www.iucn.org/ssc-groups/mammals, https://globalmammal.org/
184 http://www.iucnredlist.org/initiatives/amphibians, http://www.amphibians.org/redlist/
185 https://www.iucn.org/ssc-groups/birds, http://www.birdlife.org/worldwide/partnership/about-birdlife

- ○ भारत दुनिया के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ एक बहुत ही विविध देश है, जिसमें सभी रिकॉर्ड की गयी प्रजातियों के 7-8% खाते हैं, जिसमें 45,000 से अधिक प्रजातियां और 91,000 जानवरों की प्रजातियां शामिल हैं।[186] हालांकि, चूंकि विलुप्त होने की दर ऊपर के और जाती जा रही हैं, इसलिए इस बात का पुर्वनुमान लगाया जाता है कि दुनिया की 20-50% प्रजातियां अगले कुछ दशकों[187] में विलुप्त हो जाएंगी। भारत में भी, कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं। भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय जानवरों में से चार हैं: हंगुल, ग्रेट इंडिया एन बस्टर्ड, संगाई और डुगॉन्ग।
- ○ **पुन: उत्पादन:** कुछ प्रजातियां जो जंगल में विलुप्त होने के खतरे में हैं, उन्हें आसन्न विलुप्त होने से बचाने और कैप्टिव प्रजनन और संभोग के माध्यम से जनसंख्या संख्या बढ़ाने के लिए कैद में लाया जा रहा है। हालांकि, चिड़ियाघर में जंगली जानवरों के बीच इस तरह की प्रथाओं को भारत में सक्रिय रूप से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है और इस मुद्दे[188] पर किसी भी विशेषज्ञ द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।
- ○ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-पांडा अभियान चीन में शुरू किया गया था, जहां प्रजाति की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान जैसे नए सिरे से एकत्र किए गए या जमे हुए और पिघले हुए शुक्राणु के साथ मिलान किया गया था। यह प्रक्रिया अब चीन और अन्य देशों के साथ-साथ पांडा प्रजनन केंद्रों में भी नियमित रूप से की जा रही है।[189] [190]
- ○ **इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के साथ सहयोग करना चाहिए - समान रणनीति विकसित करने के लिए प्रकृति ताकि वे अत्यधिक गंभीर रूप से लुप्तप्राय, लुप्तप्राय और कमजोर प्रजातियों का संरक्षण कर सकें।**

दीर्घकालिक योजना

- **ज़ीरो पोचिंग नीति को अपनाना**
  - ○ Wildlife वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया (डब्ल्यूपीएसआई), एक वन्यजीव संरक्षण संगठन ने 20,000 से अधिक वन्यजीव अपराध मामलों को दर्ज किया है। भारत में सबसे अधिक खतरा वन्यजीवों की प्रजातियों में बाघों, हाथियों, तेंदुओं और गैंडों में हैं। डब्ल्यूपीएसआई

[186] *https://www.iucn.org/asia/countries/india*
[187] https://link.springer.com/article/10.1007/BF00114044
[188] https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/breeding-in-captivity-or-celibacy/articleshow/59814858.cms
[189] https://gizmodo.com/giant-panda-breeding-efforts-have-actually-been-really-1614308529
[190] http://science.sciencemag.org/content/330/6010/1503

के आंकड़ों के अनुसार, एजेंसी ने वर्ष 2014 में 120 से अधिक हाथियों की हानि और 66 बाघों की मौत दर्ज की है।[191]

- **नेपाल में नवाचार:** नेपाल में, 400 सामुदायिक इकाइयां पूरे देश में काम कर रही हैं और वन्यजीव गलियारों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं ताकि अवैध गतिविधि पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। देश मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसी प्रौद्योगिकियों का एक प्रारंभिक अपनाने वालों में से था, जिसके माध्यम से उन्होंने संरक्षित क्षेत्रों में अवैध शिकार विरोधी अभियानों में सुधार किया। इसने स्थानिक निगरानी और रिपोर्टिंग उपकरण (स्मार्ट) को भी अपनाया है, जो साइट-आधारित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग संरक्षण प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी और सुधार के लिए किया जाता है। अवैध शिकार विरोधी गश्ती दलों में पार्क कर्मचारियों और नेपाल सेना की सहायता के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में विशेष रूप से प्रशिक्षित स्निफर डॉग तैनात किए जा रहे हैं।
- **इस प्रकार, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन इसी तरह की तर्ज पर, जंगलों के आसपास रहने वाले विभिन्न स्थानीय छोटे समुदायों के सहयोग से भारत के विभिन्न हिस्सों में अवांछित बढ़े हुए अवैध शिकार को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं।**[192]

[191] https://www.downtoearth.org.in/news/over-20000-wildlife-crimes-recorded-in-india--48209

[192] *wwf.panda.org › Knowledge Hub › Publications & Resources*

संकेतक 9.08: वन आवरण परिवर्तन

परिभाषा: यह सूचक 2000 और 2014 के बीच 30% से अधिक वृक्षों के आवरण वाले क्षेत्रों में वार्षिक वृक्ष आच्छादन के योग में होने वाली हानि को दर्शाता है, जिसे 2000 वन सीमा से विभाजित किया जाता है।

स्रोत: येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{(\text{वर्ष } \mathbf{2001} \text{ में टीसीएल}) + (\text{वर्ष } \mathbf{2002} \text{ में टीसीए}) + \ldots + (\text{वर्ष } \mathbf{2014} \text{ में टीसीएल})}{\text{वर्ष } \mathbf{2000} \text{ में कुल वन क्षेत्र (हेक्टेयर)}}$$

जहां टीसीएल वृक्षों के आवरण की हानि को दर्शाता है

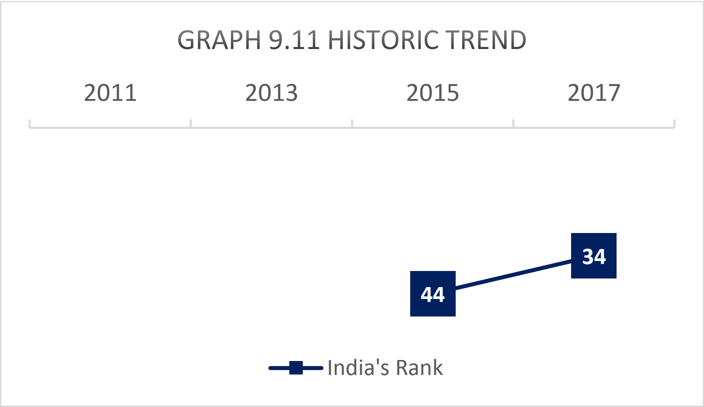

ग्राफ 9.11 संकेतक 9.08 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 10 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.69% का योगदान देता है।

तालिका 9.16: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
ईरान, इस्लामिक गणराज्य	15	-0.1	1	0.002018	शीर्ष प्रदर्शक

जॉर्डन*	N/A	N/A	2	0.002357	शीर्ष प्रदर्शक
जॉर्जिया	15	-0.1	3	0.002836	शीर्ष प्रदर्शक
नेपाल	21	-0.4	10	0.007461	एशियाई साथी
भारत	**44**	**-1.6**	**34**	**0.026641**	

*** 2015 श्रेणी और जॉर्डन के लिए मूल्य टीटीसीआई 2105 रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं था।**

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **बॉन चैलेंज के लिए लगातार प्रयास**
  - बॉन चैलेंज 2020 तक दुनिया की वनों की कटाई और खराब हुई भूमि को 150 मिलियन हेक्टेयर और कुल 350 मिलियन हेक्टेयर में लाने का एक वैश्विक प्रयास है।
  - भारत उन 56 देशों में से है, जो 2030 तक वन हेक्टेयर बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। भारत ने कुल 21 मिलियन हेक्टेयर की अवक्रमित भूमि यानी 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर भूमि और 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि 2030 तक बहाल करने की प्रतिबद्धता जताई है।
  - **इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए अल्पकालीन योजना एक समिति की स्थापना करने के लिए होगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि बॉन चुनौती के लिए निर्धारित लक्ष्य को ठीक से पूरा किया जा रहा है।**

मध्यम अवधि की योजना

- **वानिकी क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान को अपनाना**[193]
  - दशकों से, भारत अपने भौगोलिक क्षेत्र के 33% को वन आवरण के तहत रखने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टेट ऑफ़ फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह अभी भी 22% मूल्य[194] से ऊपर जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रस्तावित राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन मिशन के तहत लोगों के अधिकार, संरक्षण और प्रबंधन भूमिकाओं के विभाजन के लिए कोई रूपरेखा तैयार नहीं करते हैं। यह मिशन थोड़ा गलत तरीके से और खराब नियोजित लगता है, क्योंकि 2006 के वन अधिकार अधिनियम के अधिनियमन के 10 साल बाद भी, सामुदायिक वन अधिकारों के तीन प्रतिशत से कम ने भारत में मान्यता प्राप्त की हैं।[195]
  - नेपाल ने 1989 में वानिकी क्षेत्र के लिए 25 साल की नीति और योजना की रूपरेखा तैयार की थी। योजना का उद्देश्य निरंतर आधार पर वन उत्पादों के लिए लोगों की जरूरतों को पूरा

---

[193]https://theredddesk.org/countries/plans/master-plan-forestry-sector-nepal
[194] http://fsi.nic.in/isfr2017/isfr-forest-cover-2017.pdf
[195] https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/india-forests-threat-180425104442969.html

करना, पारिस्थितिक तंत्र और आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करना, पारिस्थितिक असंतुलन के प्रभाव और अन्य प्रभावों के खिलाफ भूमि की रक्षा करना और स्थानीय और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान करना है।[196]

- इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नेपाल के समान तर्ज पर, वानिकी क्षेत्र के लिए ऐसे मास्टर प्लान को लागू कर सकते हैं जो छोटे समुदाय की जरूरतों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस तरह की मास्टर प्लान के उद्देश्य में राष्ट्रीय वनों का प्रबंधन, रोपाई का वितरण, ईंधन-कुशल स्टोव के उपयोग को बढ़ावा देना, कानून को अद्यतन करना, वानिकी संगठनों को मजबूत करना, वानिकी पेशेवरों का प्रशिक्षण और प्रबंधन के लिए अनुसंधान और जंगलों के विकास प्रबंधन का कार्य और एक प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना करना शामिल हो सकता हैं।

दीर्घकालिक योजना

- **ग्लोबल फ़ॉरेस्ट फ़ाइनेंसिंग फैसिलिटेटिंग नेटवर्क (जीएॅफ़एॅफ़एॅफ़एन)** जीएॅफ़एॅफ़एॅफ़एन एक ऐसा मंच है, जहां भारत जैसे देशों को वनों की सुरक्षा के साथ-साथ नीति निर्माण में मार्गदर्शन के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है। जीएॅफ़एॅफ़एॅफ़एन की 3 प्रमुख भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:
- स्थायी वन प्रबंधन (एसएफएम) के लिए संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय वन वित्तपोषण रणनीतियों के डिजाइन को बढ़ावा देना
- ग्लोबल पर्यावरण सुविधा और ग्रीन क्लाइमेट फंड सहित मौजूदा और उभरते वित्तपोषण तंत्रों तक पहुंच की सुविधा देना
- मौजूदा, नए और उभरते वित्तपोषण अवसरों पर एक समाशोधन गृह के रूप में सेवा करें और सफल परियोजनाओं से सीखा सबक साझा करने के लिए एक उपकरण के रूप में सेवा करें।[197]
- 2015 में अपनी स्थापना के बाद से, जीएॅफ़एॅफ़एॅफ़एन ने विभिन्न संसाधनों को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके, विभिन्न देशों को सुविधा प्रदान की है, जिसका उपयोग एसएॅफ़एम लागू करने के लिए किया जाता है।.
    - राष्ट्रीय स्तर पर, नेटवर्क ने 13 देशों को विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाने में मदद की है: कैमरून, इक्वाडोर, फिजी, गिनी, ईरान, मेडागास्कर, नाइजर, नाइजीरिया, पापुआ न्यू गिनी, सेनेगल, युगांडा, यूक्रेन और जिम्बाब्वे।

---

[196]https://www.globalforestwatch.org/
[197]http://www.un.org/esa/forests/forum/capacity-development/forest-financing/index.html

- क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय स्तर पर, नेटवर्क ने बहुपक्षीय वित्तपोषण तंत्र से धन तक पहुंचने पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया है। ये क्षेत्र ईसीओ क्षेत्र (मध्य एशिया), एसएडीसी क्षेत्र (दक्षिणी अफ्रीका), दक्षिण पूर्व एशिया, एसपीसी क्षेत्र (प्रशांत) और अफ्रीकी संघ हैं। केवल दो वर्षों में, नेटवर्क ने स्थायी वन प्रबंधन पर परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए 300 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि, सिविल सोसायटी और शिक्षाविदों को प्रशिक्षित किया है।
- जीएॅफ़एॅफ़एॅफ़एन संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सहयोग कर रहा है, जिसमें वनविभाग, सीपीईएॅफ़, आईयूसीएनएन, यूएनसीसीडी और यू एनडीपी और साथ ही अन्य भागीदारों, जैसे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकी वन फोरम और संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय।

○ **इस प्रकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी जीएॅफ़एॅफ़एॅफ़एन के साथ सहयोग कर सकते हैं क्योंकि यह न केवल वनों की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता देगा बल्कि नीति निर्माण के लिए उचित मार्गदर्शन भी देगा।**

संकेतक 9.10: तटीय शेल्फ मछली पकड़ने का दबाव

परिभाषा: यह संकेतक अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) प्रति ट्रैपिंग कैच को संदर्भित करता है। यह प्रत्येक देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के कुल क्षेत्र द्वारा विभाजित ट्रावलिंग और ड्रेजिंग उपकरणों से कुल पकड़ का आकलन करता है।

स्रोत: येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी (वाईसीईएलपी) और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क (सी आईईएसआईएन), पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2014।

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{ट्रॉलिंग कैच (टन)}}{\text{एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (ईईजेड) (वर्ग किलोमीटर)}}$$

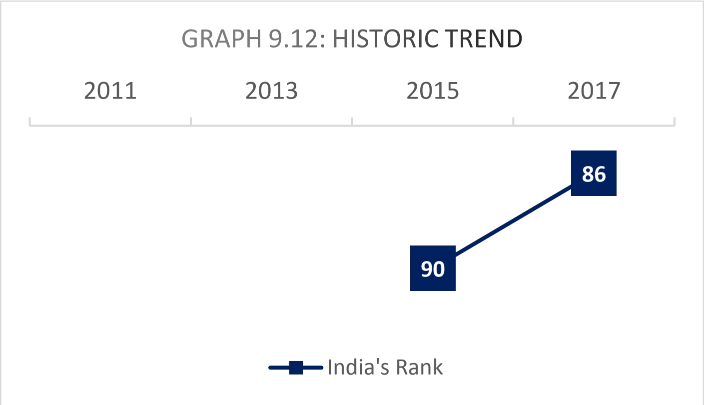

ग्राफ 9.12 इस सूचक 9.10 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 4 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.69% का योगदान देता है।

तालिका 9.17: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
बारबाडोस	1	0.000015	1	0.000015	शीर्ष प्रदर्शक
मॉरीशस	3	0.000034	2	0.000034	एशियाई साथी
जॉर्जिया	4	0.000045	3	0.000045	शीर्ष प्रदर्शक
श्रीलंका	7	0.000438	6	0.000438	एशियाई साथी
भारत	**90**	**0.62**	**86**	**0.62**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मध्यम अवधि की योजना

- **विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विस्तार (ईईजेड)**
    - **राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र (ऐबीएनजे) से परे का क्षेत्र** जिसे आमतौर पर उच्च समुद्र कहा जाता है, वे महासागर के वे क्षेत्र हैं जिनके लिए किसी एक राष्ट्र के पास प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी नहीं है। सभी में, ये ग्रह की सतह का 40% हिस्सा बनाते हैं, जिसमें महासागरों की सतह का 64% और इसकी मात्रा का लगभग 95% है।[198]
    - मछली पकड़ने के लिए वर्तमान अनुमति क्षेत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है और भारत अभी भी एबीएनजे की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत के चरण में है। इस प्रकार, यदि इस संधि की पुष्टि हो जाती है, तो भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) पर दबाव काफी कम हो जाएगा क्योंकि तब एबीएनजे या उच्च समुद्र क्षेत्रों में मछली पकड़ने की अनुमति होगी।
    - भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को भारत के लिए ईईजेड के अपने वर्तमान क्षेत्र को दोगुना करने के अपने दावे को स्वीकार करने के लिए याचिका दायर कर रही है। चूंकि भारत में ईईजेड की भू-वैज्ञानिक मानचित्रण नहीं है, इसलिए भारत में ईईजेड का कोई निर्दिष्ट क्षेत्र नहीं है। कई अन्य देशों ने अपने ईईजेड के व्यवस्थित मानचित्रण और अन्वेषण कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जो ईईजेड सहित समुद्र में स्थायी प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
    - **इस प्रकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भी ईईजेड के भू-वैज्ञानिक मानचित्रण शुरू कर सकता है ताकि ईईजेड के अपने क्षेत्र को निर्दिष्ट किया जा सके।[199]**

दीर्घकालिक योजना

- **नियमों और विनियमों में अधिक कड़ापन**
    - निचला ट्रवलिंग एक पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी अभ्यास है। इस अभ्यास में समुद्र तल के साथ भारित जाल को खींचने वाले ट्रॉलर शामिल होते हैं, जिससे जलीय संसाधनों की भारी कमी होती है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बनता है। [200]

[198] https://www.thegef.org/topics/areas-beyond-national-jurisdiction
[199] https://www.geographyandyou.com/economy/development/exclusive-economic-zone-seas-around-india/
[200] https://www.2thepoint.in/bottom-trawling/

तमिलनाडु और केरल की नावें जो विभिन्न बंदरगाहों से संचालित होती हैं, पेयर बॉटम ट्रवलिंग और पेयर पेलागिक ट्रवलिंग मछली पकड़ने जैसी विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाओं का पालन कर रही हैं।[201]

- श्रीलंका ने अपने पानी में बॉटम ट्रवलिंग मछली पकड़ने के विनाशकारी अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया है।[202] श्रीलंका ने अपने मत्स्य और जलीय संसाधन अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके अनुसार उल्लंघन अब दो साल की जेल की सजा और रुपये 50,000 के जुर्माना को आकर्षित करेगा। हालांकि भारत सरकार ने निचले स्तर पर चल रही तबाही को खत्म करने के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन ये प्रयास केवल लंबे समय में पर्याप्त प्रभाव दिखाएंगे।[203]
- **इसलिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को बॉटम ट्रवलिंग की पारंपरिक विधि पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो अभी भी इसका अभ्यास करते हैं।**

[201] http://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2018/aug/05/tn-boats-fishing-practices-harm-marine-environment-1853379.html
[202] https://thewire.in/external-affairs/bottom-trawling-india-sri-lanka
[203] https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/sri-lankas-bottom-trawling-ban-indias-deep-sea-fishing-all-you-need-to-know/article19396217.ece

उप-सूचकांक सी

आधारिक संरचना

आधारिक संरचना उप-सूचकांक, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की भौतिक आधारिक संरचना की उपलब्धता और गुणवत्ता को दर्शाता है। कनेक्टिविटी और आतिथ्य आधारिक संरचना यात्रा और पर्यटन के स्पष्ट रूप से विशिष्ट चालक हैं, यह उप-सूचकांक उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से मूल्यांकन करने की अनुमति देता है, जब उन्हें नीतिगत ध्यान की आवश्यकता होती है।

इस उप-सूचकांक में 3 स्तंभ शामिल हैं:

1. वायु परिवहन आधारिक संरचना (6 संकेतक)

2. जमीनी और बंदरगाह आधारिक संरचना (7 संकेतक)

3. पर्यटक सेवा आधारिक संरचना (4 संकेतक)

स्तंभ 10: वायु परिवहन आधारिक संरचना

परिभाषा: यह स्तंभ उस सीमा तक मापता है कि कोई देश किस हद तक यात्रियों की पहुँच और देशों के साथ-साथ कई देशों में आवाजाही के लिए पर्याप्त हवाई संपर्क प्रदान करता है। स्तंभ 10 में कुल 6 संकेतक हैं जो नीचे दिए गए हैं -

1. वायु परिवहन आधारिक संरचना की गुणवत्ता
2. उपलब्ध सीट किलोमीटर, घरेलू
3. उपलब्ध सीट किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय
4. विमान प्रस्थान
5. हवाई अड्डे का घनत्व
6. परिचालन एयरलाइनों की संख्या

GRAPH 10.01: HISTORIC TREND

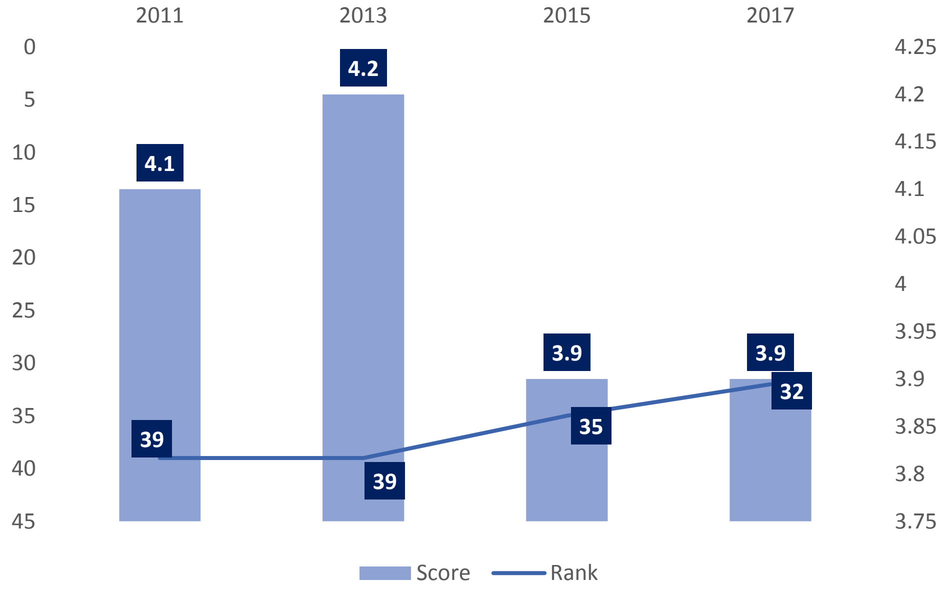

ग्राफ 10.01 स्तंभ 10 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति और मूल्य दर्शाता है। भारत की श्रेणी 2011 में 39 वें स्थान से बढ़कर 2017 में 32 वें स्थान पर पहुंच गई है।

भार की स्थिति में बदलाव:

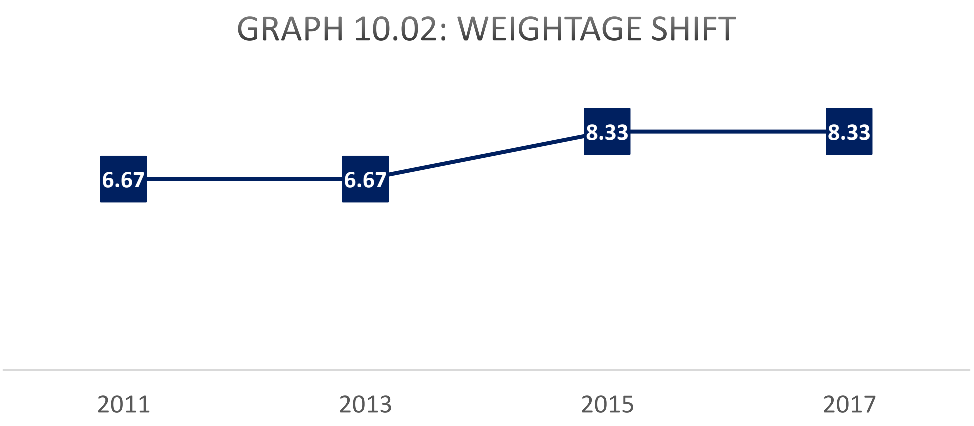

ग्राफ 10.02, भारत के स्कोर में स्तंभ 10 यानी वायु परिवहन आधारिक संरचना के समग्र योगदान को इंगित करता है। वर्तमान में, इस स्तंभ को 8.33% भार दिया जाता है। इस स्तंभ का भार वर्ष 2015 में 25% से बढ़ गया है।

तालिका 10.01: भार के स्थिति में संकेतक वार बदलाव

संकेतक	2011-2013 (%)	2015-2017 (%)	भार के स्थिति में बदलाव (%)
वायु परिवहन आधारिक संरचना की गुणवत्ता	1.11	1.66	49.55
उपलब्ध सीट किलोमीटर, घरेलू	0.55	0.83	50.91
उपलब्ध सीट किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय	0.55	0.83	50.91
विमान प्रस्थान	1.11	1.66	49.55
हवाई अड्डे का घनत्व	1.11	1.66	49.55
परिचालन एयरलाइनों की संख्या	1.11	1.66	49.55

तालिका 10.01 योगदान का प्रतिशत दर्शाती है जो कि प्रत्येक संकेतक का भारत के समग्र स्कोर पर है।

ध्यान दें: संकेतक 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 और 10.06 को एकल संकेतक के रूप में दिखाया जा रहा है क्योंकि वे अंतर-संबंधित हैं और उनकी एक सामान्य कार्य योजना होगी। हवाई परिवहन आधारिक संरचना में सुधार के उद्देश्य से एक आम रणनीति सभी संकेतकों पर वांछित प्रभाव डाल सकती है।

संकेतक 10.01: वायु परिवहन आधारिक संरचना की गुणवत्ता

परिभाषा: "आप अपने देश में वायु परिवहन आधारिक संरचना की गुणवत्ता का आंकलन कैसे करेंगे?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = अत्यंत अविकसित, दुनिया में सबसे खराब; 7 = व्यापक और कुशल, दुनिया में सबसे अच्छा)।

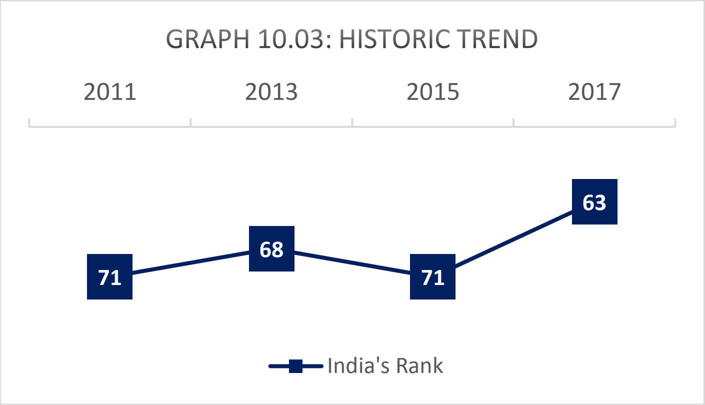

ग्राफ 10.03 सूचक 10.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 8 स्थान की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 1.66% का योगदान देता है।

तालिका 10.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
सिंगापुर	1	6.75	1	6.85	एशियाई साथी
संयुक्त अरब अमीरात	2	6.71	2	6.74	शीर्ष प्रदर्शक
हांगकांग गणराज्य	3	6.63	3	6.61	शीर्ष प्रदर्शक

भारत	71	4.27	63	4.49	

संकेतक 10.02: उपलब्ध सीट किलोमीटर, घरेलू

परिभाषा: यह संकेतक एयरलाइन की यात्री-वहन क्षमता को दर्शाता है। यह किलोमीटर में उड़ान दूरी से गुणा की गई प्रत्येक घरेलू उड़ान पर उपलब्ध सीटों की संख्या से बना है। अंतिम मूल्य एयरलाइन कंपनियों द्वारा पहले से निर्धारित उड़ानों को ध्यान में रखते हुए, साल (जनवरी-दिसंबर) के लिए साप्ताहिक औसत का प्रतिनिधित्व करता है।

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण, एसआरएस विश्लेषक

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{प्रत्येक घरेलू उड़ान पर उपलब्ध सीटों की संख्या x उड़ान दूरी}}{52}$$

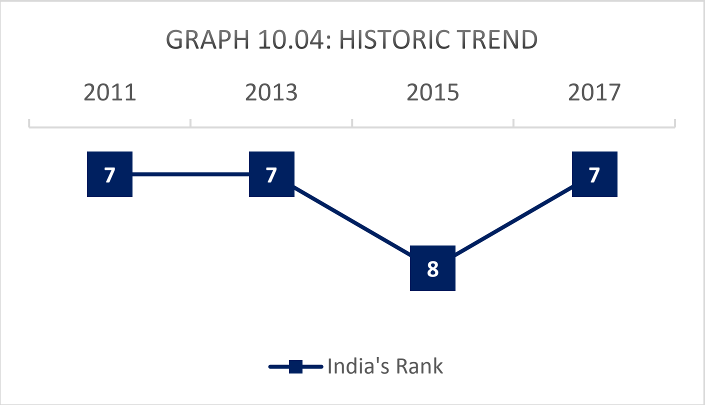

ग्राफ 10.04 संकेतक 10.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 1 स्थान की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.83% का योगदान देता है।

तालिका 10.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
यूनाइटेड स्टेट्स	1	21884.84	1	22812.24	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
चीन	2	10264.49	2	11208.56	एशियाई साथी
ब्राज़ील	3	2282.38	3	2257.42	शीर्ष प्रदर्शक

भारत	8	1612.12	7	1763.42	

संकेतक 10.03: उपलब्ध सीट किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय

परिभाषा: यह संकेतक एयरलाइन की यात्री-वहन क्षमता को मापता है। यह प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर उपलब्ध सीटों की संख्या को किलोमीटर में उड़ान की दूरी से गुणा करके बना है। अंतिम मूल्य एयरलाइन कंपनियों द्वारा पहले से निर्धारित उड़ानों को ध्यान में रखते हुए, साल (जनवरी-दिसंबर) के लिए साप्ताहिक औसत का प्रतिनिधित्व करता है।

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण, एसआरएस विश्लेषक

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर उपलब्ध सीटों की संख्या X फ्लाइट दूरी}}{52}$$

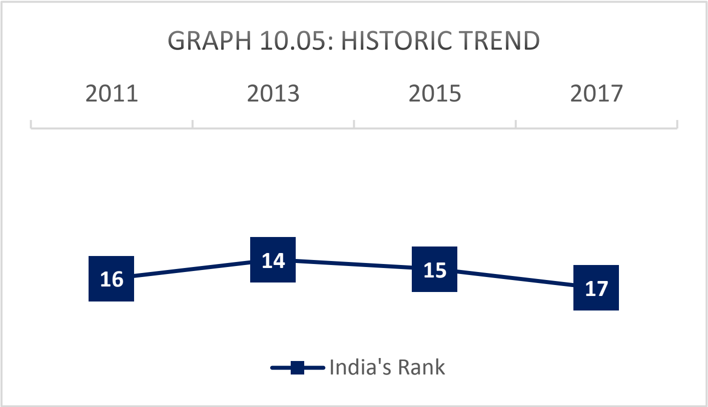

ग्राफ 10.05 संकेतक 10.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 2 स्थान की कमी आई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.83% का योगदान देता है।

तालिका 10.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
यूनाइटेड स्टेट्स	1	12182.49	1	12994.45	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
यूनाइटेड किंगडम	2	6418.57	2	6195.12	शीर्ष प्रदर्शक
संयुक्त अरब अमीरात	3	4849.48	3	5461.64	शीर्ष प्रदर्शक
चीन	5	3926.255	5	4489.14	एशियाई साथी

भारत	15	1907.39	17	2013.8	

संकेतक 10.04: विमान प्रस्थान

परिभाषा: यह संकेतक देश में पंजीकृत एयर कैरियर की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टेक-ऑफ की संख्या को संदर्भित करता है। इसकी गणना प्रति 1000 जनसंख्या पर विमान प्रस्थान की संख्या के रूप में की जाती है।.

स्रोत: विश्व बैंक, विश्व विकास संकेतक

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{विमान प्रस्थान की कुल संख्या x 1000}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

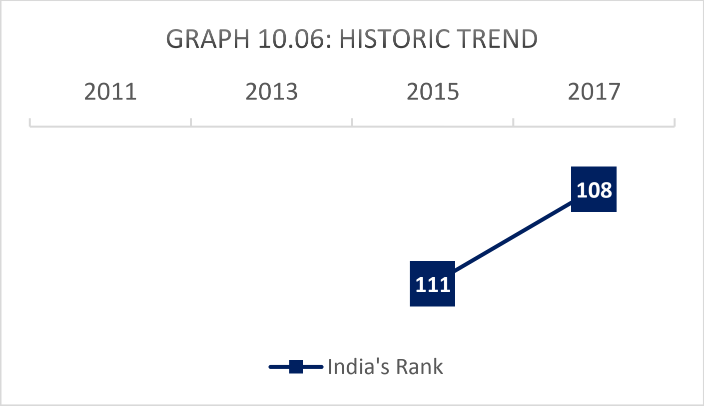

ग्राफ 10.06 संकेतक 10.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में, 2017 में, 3 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 1.67% का योगदान देता है।

तालिका 10.05: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
आयरलैंड	2	145.7	1	147.1	शीर्ष प्रदर्शक
आइसलैंड	3	83.4	2	93.4	शीर्ष प्रदर्शक
लक्समबर्ग	4	72.3	3	85.3	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**111**	**0.5**	**108**	**0.6**	

संकेतक 10.05: एयरपोर्ट घनत्व

परिभाषा: यह संकेतक कम से कम एक निर्धारित उड़ान प्रति मिलियन शहरी आबादी के साथ हवाई अड्डों की संख्या को संदर्भित करता है। शहरी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संदर्भित करती है जैसा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों द्वारा परिभाषित किया गया है। इसकी गणना विश्व बैंक के प्रदूषण अनुमानों और संयुक्त राष्ट्र विश्व शहरीकरण की संभावनाओं से शहरी अनुपात का उपयोग करके की जाती है।

देश का मूल्य = शहरी आबादी के प्रति कम से कम एक निर्धारित उड़ान के साथ हवाई अड्डों की संख्या

*** श्रेणी प्रति मिलियन आबादी वाली कम से कम एक निर्धारित उड़ान के साथ कार्यात्मक हवाई अड्डों की कुल संख्या को ध्यान में रखने से ली गई है।**

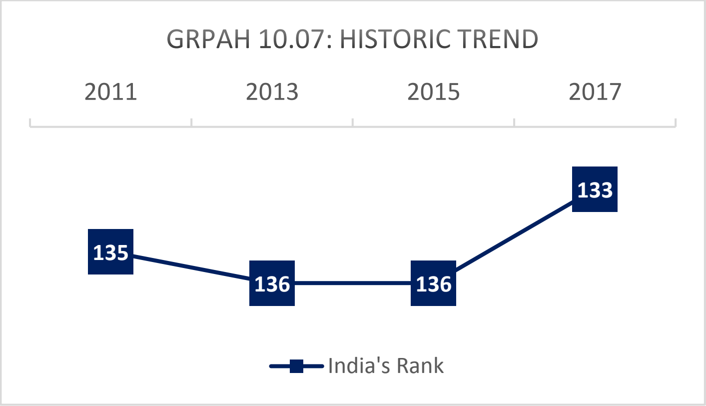

ग्राफ 10.07, संकेतक 10.05 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 3 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 1.67% का योगदान देता है।

तालिका 10.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
आइसलैंड	2	26.36	1	25.68	शीर्ष प्रदर्शक
केप वर्डे	3	21.87	2	20.52	शीर्ष प्रदर्शक
त्रिनिदाद और टोबैगो	4	17.20	3	17.41	शीर्ष प्रदर्शक

यूनाइटेड स्टेट्स	29	2.50	26	2.49	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
भारत	**136**	**0.18**	**133**	**0.17**	

संकेतक 10.06: परिचालन एयरलाइंस की संख्या

परिभाषा: यह संकेतक देश में उत्पन्न होने वाली निर्धारित उड़ानों की संख्या को दर्शाता है।

स्रोत: इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एसआरएस विश्लेषक

देश का मूल्य: देश में होने वाली निर्धारित उड़ानों के साथ एयरलाइंस की संख्या

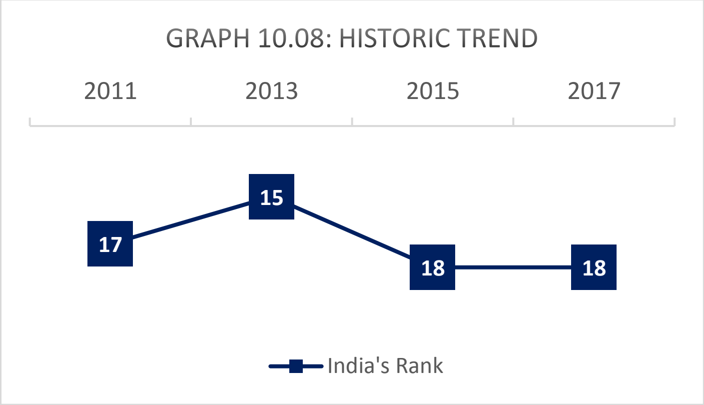

ग्राफ 10.08, संकेतक 10.06 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। भारत की श्रेणी 2017 और 2015 में 18 वें स्थान पर बनी रही। यह संकेतक देश के स्कोर में 1.67% का योगदान देता है।

तालिका 10.07: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
यूनाइटेड स्टेट्स	1	223	1	220	सर्वश्रेष्ठ प्रथा
फ्रांस	2	195	2	183	शीर्ष प्रदर्शक
जर्मनी	3	181	3	172	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**18**	**90**	**18**	**89**	

- **सरकारी पहल**
  - नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बजट का आबंटन केंद्रीय बजट 2018-19[204] के तहत 6,602.86 करोड़ (US $ 1,019.9 मिलियन) कर दिया गया है।

[204] https://www.ibef.org/industry/indian-aviation.aspx

- उड़ान (हवाई यात्रा सस्ती और विस्तारित नेटवर्क बनाना) "उड़े-देश-का-आम-नागरिक" एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और कनेक्टिविटी योजना है। यह योजना दो व्यापक विषयों पर लक्षित है:
    - देश में विमानन आधारिक संरचना का विकास और विस्तार। इसमें मौजूदा हवाईअड्डों, क्षेत्रीय हवाई अड्डों और अनछुई और अछूती जगहों पर नए हवाई अड्डों का विकास।
    - "वायबिलिटी गैप फ़ंडिंग" (वीजीऍफ़) का उपयोग करके बड़े शहरों में छोटे शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में 100 से अधिक अनछुए और अछूते हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए कई सौ आर्थिक रूप से व्यवहार्य कैप्ड-एयरफ़ेयर नए क्षेत्रीय उड़ान मार्गों को जोड़ना जहां भी जरूरत हो
- भारत सरकार ने 15 ग्रीनफील्ड पीपीपी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनसे भारत में हवाई यातायात बढ़ने की उम्मीद है।
- सितंबर 2018 में, ओडिशा में झारसुगुड़ा हवाई अड्डे और सिक्किम में प्योंगॉन्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम का पहला हवाई अड्डा और एएआई का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण है।[205]
- 5/20 नियम के संबंध में नीतिगत सुधार भी हुए हैं, जिसमें घरेलू वाणिज्यिक कैरियर के लिए ऐतिहासिक रूप से पांच साल के परिचालन अनुभव और विदेशों में उड़ान भरने के लिए कम से कम 20 विमानों के बेड़े की आवश्यकता होती है। यह नीति हाल ही में 0/20 तक सीमित थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए केवल 20 घरेलू विमान सेवा की आवश्यकता थी।.[4]
- सरकार ने क्षेत्रीय रूटों पर 2,500 रुपये ($ 37) प्रति घंटे की दर से यात्रा की, जो कि दिल्ली से मुंबई जैसे सबसे लोकप्रिय मार्गों को छोड़कर, अनछुए गंतव्यों तक, यात्रा करने की सुविधा देता हैं।[206]

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)

अल्पकालीन योजना

[205] https://www.ibef.org/industry/indian-aviation.aspx
[206] http://www3.weforum.org/docs/White_Paper_Incredible_India_2_0_final_.pdf

- **यात्रियों का सर्वेक्षण करना**
    - उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एयरलाइंस के विभिन्न वर्गों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में खामियों की पहचान करने के लिए एक एकीकृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यह सर्वेक्षण विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विमान में चढ़ते समय यात्रियों को फॉर्म प्रदान किए जा सकते हैं और डी-बोर्डिंग के समय एकत्र किए जा सकते हैं। वेटिंग एरिया में बैठे लोगों से फीडबैक लेना भी एक और विकल्प हो सकता है। यह भारतीय उड्डयन उद्योग के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करेगा।
    - कुछ एयरलाइनें हैं जो लगातार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइनों के अंतर्गत अपनी श्रेणी की प्रभावशीलता को बनाए रखती हैं। इन एयरलाइनों के व्यवसाय मॉडल का अध्ययन किया जा सकता है और भारतीय उड्डयन उद्योग के सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इनकी अंतर्दृष्टि का उपयोग किया जा सकता है।

मध्यम अवधि की योजना

- **परामर्श की आवश्यकता**
  - इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) की पूर्व रिपोर्ट ने भारत द्वारा 2025 तक ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बनने से आगे निकलने का अनुमान लगाया हैं। इसके अलावा, 2036 तक, भारत में 478 मिलियन एयरलाइन यात्री होंगे, जो की जापान और जर्मनी से अधिक हैं। दुर्भाग्य से, उड़ान में इस उछाल के आने से कई अप्रत्याशित कई घटनाएं घट सकती हैं, अगर उनका निवारण सही से नहीं किया जाता हैं तो यह उनके लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकता हैं। पिछले कुछ वर्षों में विमानन क्षेत्र की उपभोक्ता शिकायतों में वृद्धि हुई है। जबकि 30.5% यात्रियों ने ग्राहक सेवा को दोषी ठहराया, 16% ने अचानक रद्द होने और देरी जैसी उड़ान की समस्याओं पर उंगली उठाई हैं, 22% ने अपने सामान के साथ समस्याएँ और 7.5% ने कर्मचारियों के व्यवहार को पसंद नहीं किया है।[207]
  - नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय संगठनों को ग्राहक सेवा से संबंधित ऐसे मुद्दों के लिए अपने प्रमुख सलाहकार के रूप में काम पर रखने पर विचार कर सकता है। एक आदर्श संगठन आईऐटीऐ (इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन) हो सकता है क्योंकि वे इस क्षेत्र में अग्रणी हैं और भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और भारत सरकार के साथ काम करने की उनकी इच्छा के बारे में खुलकर संबोधित किया है। उनकी ग्राहक सूची में पहले से ही ऑस्ट्रिया सरकार, स्कॉटलैंड, ब्राजील, जापान, दक्षिण अफ्रीका आदि शामिल हैं।

- **रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग (एमआरओ) चुनौती**
  - एमआरओ को भारत में 9,000-10,000 करोड़ का हब माना जाता हैं। कराधान के मुद्दों और एमआरओ सेवाओं को रखने के लिए बड़े हवाई अड्डों पर समर्पित हैंगर की कमी के कारण को जिम्मेदार ठहराया गया है एमआरओ सेवाओं के लिए विदेशों में हवाई जहाज भेजना विमान के उपयोग को प्रभावित करता है और भारत से एमआरओ गंतव्य देश के लिए रसद की एक अतिरिक्त लागत पर जोर देता है। वर्तमान में, एमआरओ सेवाओं पर 18% की जीएसटी दर लागू है। घरेलू विनिर्माण के साथ देश में पुर्जों और महत्वपूर्ण हिस्सों को आयात किया जाता है, जो केवल कम मूल्य के उत्पादों तक सीमित हैं। इसलिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को संतुलित कराधान शासन के साथ एक केंद्रीय रूप से स्थित एमआरओ हब विकसित करना

[207] https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/airlines-/-aviation/a-blowback-in-indias-booming-aviation-industry-surge-in-consumer-complaints/articleshow/61705471.cms

चाहिए जो हवाई जहाजों के रखरखाव की लागत को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है जिनकी अन्यथा सिंगापुर जैसे विदेशी देशों में सर्विस कराई जाती हैं।[208]

[208] http://www.careratings.com/upload/NewsFiles/Studies/Airlines%20and%20Airports.pdf

दीर्घकालिक योजना

- **हवाई जहाज को फिर से डिज़ाइन करना:**

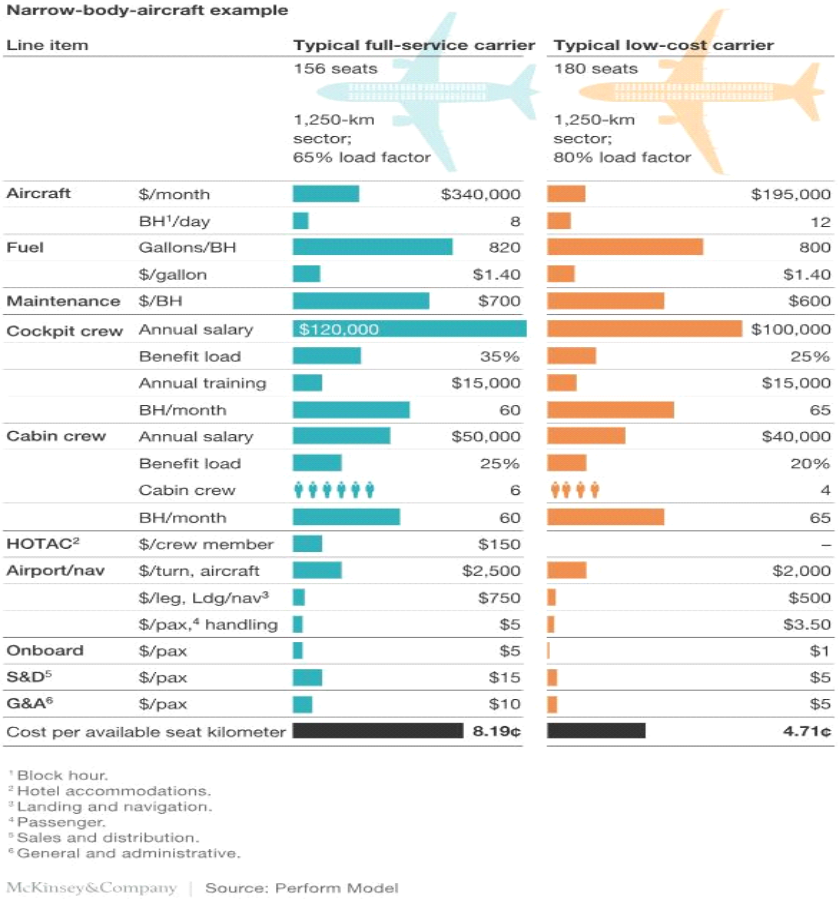

(स्रोत: मैकिन्से एंड कंपनी)

- कम लागत वाले कैरियर की तुलना में एक सामान्य पूर्ण-सेवा वाहक के पास केवल 156 सीटें होती हैं, जिसमें सिर्फ 24 सीटें ज्यादा होती हैं यानी 180 सीटें। संकेतक 10.02 और 10.03 में देश के मूल्य की गणना करते समय यह प्रमुख कारकों में से एक है। लो-कॉस्ट कैरियर में लोड फैक्टर भी 65% से बढ़कर 80% हो जाता है।
- पूर्ण-वाहक सेवा की तुलना में कम लागत वाले वाहक का रखरखाव भी 16% सस्ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं की, कम लागत वाली वाहक सेवा में प्रति सीट उपलब्ध किलोमीटर की लागत लगभग 73% सस्ती है।[209]
- जेट एयरवेज, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस जैसे प्रमुख खिलाड़ी कम लागत के वाहक विमान नहीं उड़ाते हैं। इसलिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रमुख खिलाड़ियों के बीच लो-

[209] https://www.mckinsey.com/industries/travel-transport-and-logistics/our-insights/a-better-approach-to-airline-costs

कॉस्ट कैरियर (एलसीसी) के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह उपलब्ध सीट किलोमीटर में वृद्धि करेगा और आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी होगा।

- सीटों की बढ़ती संख्या: यूएसए की यूनाइटेड एयरलाइन ने बोइंग 777-200 पर 21 अतिरिक्त सीटों को जोड़ने के लिए अपने नवीनतम वाहक की सीटिंग को फिर से व्यवस्थित किया है। अतिरिक्त सीटों को फिट करने के लिए, इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस सीटों को नौ की बजाय 10 पार की पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाएगा। अमेरिकन एयरलाइंस ने पहले ही अपने बोइंग 777-200 में से कुछ को 289 यात्रियों को फिट करने के लिए दस सीटों के साथ कॉन्फ़िगर किया है, जो कि पिछले लेआउट के मुकाबले 42 अधिक है।
- निजी विमानन कंपनियों के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी सीटों पर जोड़ने के लिए हवाई जहाज के पुनर्गठन की इस रणनीति को अपना सकता है। एयर इंडिया के पास लगभग 25 बोइंग 777 हैं। इन विमानों में अतिरिक्त सीटें लगाने की इस रणनीति से कुल सीटों में लगभग 400 की वृद्धि होगी।[210]

- **आवागमन और भीड़ में संशोधन:**
  - सटीक समय में हवाई अड्डे की भीड़ यातायात के भीतर और बाहर की लहरों की बैठक के कारण होती है, जो एयरलाइन संचालन और चोटियों (या, वैकल्पिक रूप से, हवाई अड्डे के आधारभूत संरचना के बेकार अतिप्रवाह) के बीच हवाई अड्डे की परिसंपत्तियों के अभाव के कारण महंगा हो जाता है। सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन के अनुसार, मार्च 2019[211] में समाप्त होने वाले वर्ष में भारत का घरेलू हवाई यातायात 18-20% बढ़ने और 150 मिलियन को छूने का अनुमान है। इस प्रकार, भीड़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपायों को लागू किया जा सकता है:
  - एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तेजी से चेक-इन, इमिग्रेशन, पोर्टर कर्तव्यों और हवाई अड्डे के संचालन और सुरक्षा के इर्द-गिर्द पूरी तरह से प्रबंधन करता है। उदाहरण के लिए, एक सेल्फ-सर्विस बैगेज रोबोट यात्रियों के बैग को चेक-इन कर सकता है और जब वे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो उन्हें उड़ानों के लिए तेजी से संसाधित किया जा सकता हैं।

---
[210] https://www.latimes.com/business/la-fi-travel-briefcase-united-boeing-20171021-story.html
[211] https://www.bloombergquint.com/business/indias-congested-airports-slowing-down-air-traffic-growth#gs.pGtj8RM

- यूएसए की यूनाइटेड एयरलाइंस ने ग्राहकों को उनकी उड़ानों के बारे में जानने और जानने में मदद करने के लिए अमेज़न एलेक्सा के साथ करार किया है। डेल्टा एयर लाइन्स स्वयं सेवा कियोस्क का उपयोग कर रही है जो पासपोर्ट फोटो के लिए ग्राहक चेहरे का मिलान करके ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने के लिए चेहरे को पहचानने की तकनीक का उपयोग करते हैं।[212]

इसलिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी भारत के सभी हवाई अड्डों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि बैंगलोर हवाई अड्डे पर किया जाता है।

- **स्थायी विमानन की ओर बढ़ना**
  - विमान के इंजन में आमतौर पर ईंधन का दहन कुशलता से होता है, और जेट निकास में बहुत कम धुआं उत्सर्जन होता है। हालांकि, विमान के आंदोलनों के साथ जमीनी स्तर पर विमान से प्रदूषक उत्सर्जन बढ़ रहा है। इसके अलावा, हवाई अड्डों के आसपास वायु प्रदूषण की एक बड़ी मात्रा भी सतह के यातायात से उत्पन्न होती है।[213]
  - **स्थायी विमानन ईंधन** अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विमानन के लिए एक विशाल अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। ये ईंधन पारंपरिक जीवाश्म-आधारित ईंधन के रासायनिक रूप से लगभग समान हैं और उनके जीवन चक्र पर 80% तक कम कार्बन-सघन हो सकते हैं। उन्हें कई स्थायी, नवीकरणीय फीडस्टॉक्स जैसे कि खाना पकाने के तेल, वानिकी अवशेष या नगरपालिका के कचरे का उपयोग करके संश्लेषित किया जा सकता है।
  - 2016 में, दो प्रमुख टिकाऊ वैकल्पिक ईंधन पहल की घोषणा की गई थी, ओस्लो हवाई अड्डे के साथ नॉर्वे की राजधानी और यूनाइटेड एयरलाइंस को रवाना करने वाली सभी एयरलाइनों को ईंधन की पेशकश करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हब बन गया है, जो अपने बेस से बाहर, लॉस एंजिल्स से इस ईंधन का उपयोग कर सभी उड़ानों को संचालित करने वाली पहली एयर लाइन बन गयी है। [214]

---

[212] https://emerj.com/ai-sector-overviews/airlines-use-artificial-intelligence/
[213] https://www.environmental-protection.org.uk/policy-areas/air-quality/air-pollution-and-transport/aviation-pollution/
[214] https://www.atag.org/our-activities/sustainable-aviation-fuels.html

इस प्रकार, निजी कंपनियों के सहयोग से नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ सकता है जो इन वैकल्पिक ईंधनों के व्यावसायीकरण की अनुमति देगा जो की उद्योग के दीर्घकालिक उत्सर्जन में कमी वाले लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

- **ईंधन की कीमतें जीएसटी के तहत शामिल करें:**
  - भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण मई, 2018 के दौरान 16.53% की धीमी वृद्धि दर्ज की गई जिसके कारण किरायों में वृद्धि हुई है।
  - एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएॅफ़ उद्योग के महत्वपूर्ण वर्गों में से एक है। भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के अनुपात में जेट ईंधन की कीमतों को कम नहीं करती है, जबकि जब कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होती है, तो ईंधन की कीमत बढ़ जाती है जो अंततः एयरलाइनों की परिचालन लागत को बढ़ाती है। इसके अलावा, यह एयरलाइनों को परिचालन की बढ़ी हुई लागत की भरपाई करने के लिए एक बेहतर किराया संशोधन के लिए मजबूर करती है। जेट ईंधन में एयरलाइन की परिचालन लागत का 45% हिस्सा होता है। वर्ष 2018 के लिए, एटीएफ़एफ मूल्य में पिछले छह महीनों (2018) में लगभग 30% और लगभग 25% की वृद्धि देखी गई है।

इसलिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक नई नीति पहल के रूप में जीएसटी के तहत ईंधन की कीमतों को शामिल करने पर विचार कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत सरकार ने विमान ईंधन पर जीएसटी की शुरुआत की, तो वह 10,353 करोड़ रुपये कमा सकती है, जो कि वह जो अभी कमाती है, उससे 7% अधिक है, और एयरलाइंस Rs.5,220 करोड़ का संयुक्त वार्षिक इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकते हैं।[215] निम्नलिखित वह ईंधन कर हैं जो अन्य देशों में लागू होते हैं।

तालिका 10.08: ईंधन कर

देश	ईंधन पर कर (%)
यूनाइटेड स्टेट्स	18.40%
चीन	20%
रूस	20%

[215] https://www.businesstoday.in/sectors/aviation/gst-jet-fuel-could-earn-airlines-rs-5220-crore-input-tax-credit-7-percent-more-tax-revenue-govt/story/277350.html

भारत	40%-50%

स्रोत: द हिंदू

स्तंभ 11: जमीनी और बंदरगाह आधारिक संरचना

परिभाषा: यह स्तंभ प्रमुख व्यापारिक केंद्रों और पर्यटकों के आकर्षण के लिए कुशल और सुलभ परिवहन की उपलब्धता को मापता है। स्तंभ 11 के नीचे कुल 7 संकेतक हैं-

1. सड़कों की गुणवत्ता
2. सड़क घनत्व
3. पक्की सड़क घनत्व
4. रेलमार्ग आधारिक संरचना की गुणवत्ता
5. रेलमार्ग घनत्व
6. बंदरगाह आधारिक संरचना की गुणवत्ता

7.जमीने परिवहन दक्षता

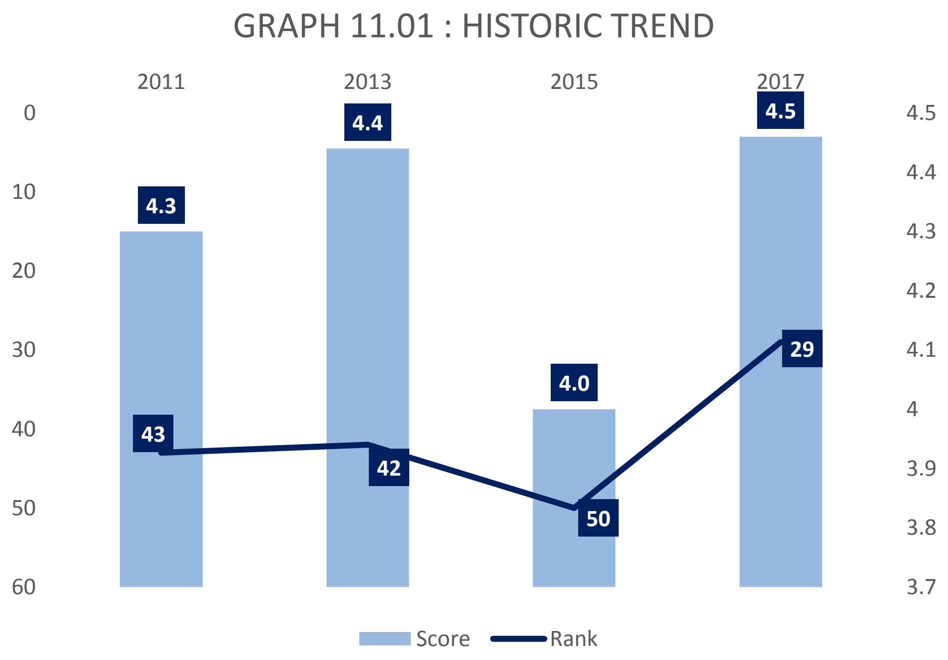

ग्राफ 11.01 भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति और स्तंभ 11 में अंकित मूल्य का संकेत देता है। भारत ने 2015 में अपनी श्रेणी को 50 वें स्थान से बढ़ाकर 2017 में 29 वें स्थान पर कर दिया है।

भार की स्थिति में बदलाव:

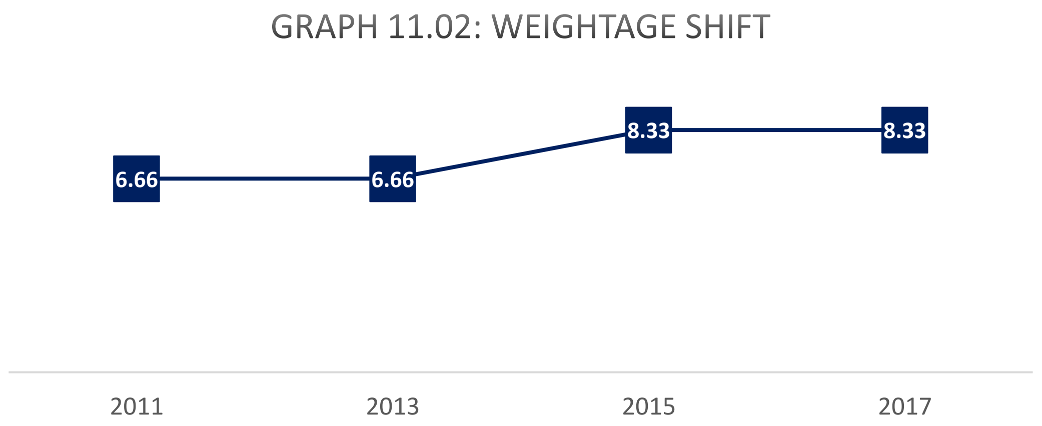

ग्राफ 11.02 स्तंभ 11 के समग्र योगदान को दर्शाता है यानी जमीनी और बंदरगाह आधारिक संरचना भारत के स्कोर में। वर्तमान में स्तंभ को 8.33% भार दिया जाता है। इस स्तंभ का भार वर्ष 2015 और 2017 में बरकरार रहा है।

भार की स्थिति में संकेतक-वार बदलाव:

तालिका 11.01: भार की स्थिति में संकेतक-वार बदलाव:

संकेतक	2011-2013(%)	2015(%)	2017(%)	भार की स्थिति में बदलाव (%)*
सड़कों की गुणवत्ता	1.33	1.39	2.08	49.64
सड़क घनत्व	1.33	0.69	0.52	-24.64
पक्की सड़क घनत्व	NA	0.69	0.52	-24.64
रेलमार्ग आधारिक संरचना की गुणवत्ता	1.33	1.39	0.52	-62.59
रेलमार्ग घनत्व	NA	1.39	0.52	-62.59
बंदरगाह आधारिक संरचना की गुणवत्ता	1.33	1.39	2.08	49.64
जमीनी परिवहन दक्षता	1.33	1.39	2.08	49.64

NA = लागू नहीं, उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

2015 में इस स्तंभ में दो नए संकेतक यानी पक्के सड़क घनत्व और रेलरोड घनत्व को जोड़ा गया था।

*** भार की स्थिति में बदलाव 2015 की तुलना में दिखाया गया है**

तालिका 11.01 में भारत के समग्र स्कोर पर प्रत्येक संकेतक के योगदान का प्रतिशत दिखाया गया है।

संकेतक 11.01: सड़कों की गुणवत्ता।

परिभाषा: "आप अपने देश में सड़कों की गुणवत्ता का आंकलन कैसे करेंगे?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण.

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = अत्यंत अविकसित, दुनिया के सबसे बुरे में; 7 = व्यापक और कुशल, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से)

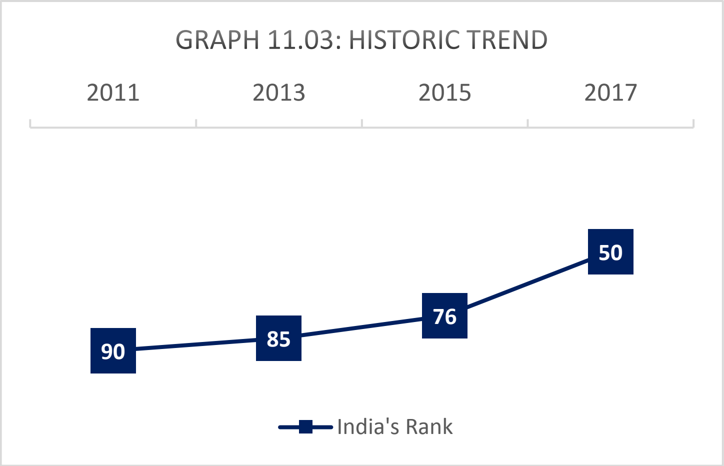

ग्राफ 11.03 संकेतक 11.0 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 26 स्थान की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 2.08% का योगदान देता है।

तालिका 11.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
यूनाइटेड अरब अमीरात	1	6.6	1	6.5	शीर्ष प्रदर्शक

सिंगापुर	6	6.05	2	6.28	एशियाई साथी
हांगकांग	7	6.04	3	6.15	एशियाई साथी
जापान	10	5.91	5	6.12	एशियाई साथी
भारत	**76**	**3.79**	**50**	**4.42**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)

मध्यम अवधि की योजना

- **सड़क की गुणवत्ता में सुधार करना**
    - **उपयोग की गई सामग्री की घटिया गुणवत्ता, पुरानी तकनीक और समय पर रखरखाव की कमी से सड़कों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में, अधिकांश मामलों में, पुराने डामर को हटाया नहीं जाता है और एक नई परत जोड़ी जाती है जो सड़क की गुणवत्ता को खराब करती है।**
    - **सड़कों की खराब गुणवत्ता उनके जीवन को कम करती है और गड्ढों जैसे मुद्दों का कारण बनती है। 2017 में, गड्ढों ने घातक नुकसान किया हैं, जिसमें 3,597 लोगों की मौत हुई, 2016 में मौतों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई हैं। केंद्र के साथ राज्यों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में 987 कार्यवाहियों के साथ यूपी, 726 के साथ महाराष्ट्र , 522 के साथ हरियाणा और 228 कारणों के साथ गुजरात शामिल है।**
    - **हालांकि, जापान में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को अपनाकर भारत की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। वहां डामर बिछाने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जब तक कि सड़क को सौ मीटर की दूरी पर डामर के साथ समतल किया जाता है, एक बार में सपाट और तंग रूप में डाली जाती है। इस अभ्यास ने जापान को पूरी तरह से समतल सड़कों के निर्माण में मदद की है। इसलिए, सड़कें लंबे समय तक चलती हैं और उन्हें बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और विभिन्न राज्य विभागों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि विनियमन को लागू किया जा सके जिससे कि उपर्युक्त मुद्दों को सुधारा जा सके।**

- **जापान में कार्यान्वित विधियों का परीक्षण करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की जा सकती है ताकि पायलट परियोजनाओं से एकत्रित किए गए डाटा से प्राप्त विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि के आधार पर टिकाऊ आधारिक संरचना के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके।**

दीर्घकालिक योजना

- **सड़क की गुणवत्ता का आंकलन**
  - **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के साथ मिलकर एक ढांचा तैयार किया है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और डिज़ाइन कर इसमें शामिल विभिन्न दलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा।** विकसित ढांचे के आधार पर इन कंपनियों को एक श्रेणी प्रदान की जाएगी। इसके बाद कमजोर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को अलग करने के लिए भविष्य की निविदा प्रक्रिया के लिए इस रेटिंग का उपयोग किया जाएगा। अच्छी रेटिंग बनाए रखने के लिए, कंपनियां अंततः बेहतर निर्माण गुणवत्ता की दिशा में प्रयास करेंगी। **लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) और विभिन्न राज्य विभागों जैसे झारखंड के पथ निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, पश्चिम बंगाल राजमार्ग विकास निगम लिमिटेड और अन्य की मदद से एमओओआरटीएच राज्य राजमार्गों और स्थानीय सड़कों में गुणवत्ता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए समान रूपरेखा विकसित कर सकते हैं।**

ध्यान दें: संकेतक 11.02 और 11.03 को एकल संकेतक के रूप में दिखाया जा रहा है क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं और समान मानदंडों का पालन करते हैं।

संकेतक 11.02: सड़क घनत्व

परिभाषा: सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भूमि पर सड़क का किलोमीटर है। इसकी गणना देश के भूमि क्षेत्र के देश के कुल सड़क नेटवर्क की लंबाई के अनुपात के रूप में की जाती है। सड़क नेटवर्क में देश की सभी सड़कें शामिल हैं: मोटरवे, राजमार्ग, मुख्य या राष्ट्रीय सड़कें, माध्यमिक या क्षेत्रीय सड़कें और अन्य शहरी और ग्रामीण सड़कें।

स्रोत: आईआरएफ जेनेवा, वर्ल्ड रोड सांख्यिकी डब्ल्यूआरएस।

देश का मूल्य = $\frac{\text{Lदेश की कुल सड़क की लंबाई (किलोमीटर)} \times 100}{\text{देश का कुल भूमि क्षेत्र}}$

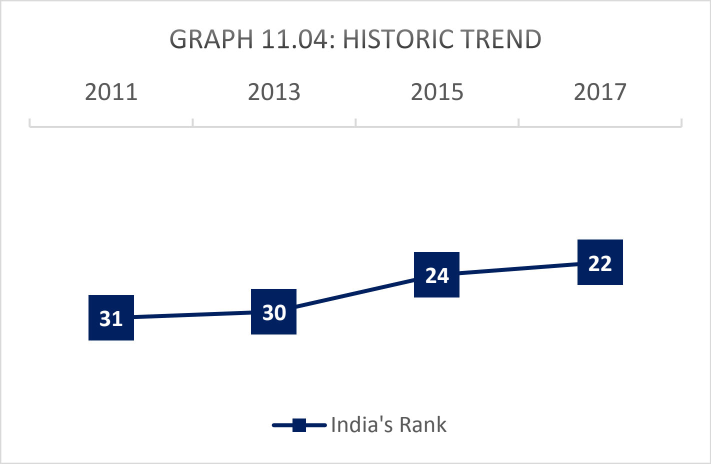

ग्राफ 11.04 संकेतक 11.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 2 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.52% का योगदान देता है।

तालिका 11.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	श्रेणी (2017)	कारण
सिंगापुर	4	4	एशियाई साथी
नीदरलैंड	6	6	शीर्ष प्रदर्शक
हांगकांग गणराज्य	13	11	एशियाई साथी
भारत	**24**	**22**	
ऑस्ट्रेलिया	112	93	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

इन संकेतकों के लिए मूल्य डब्ल्यूईवाईएफ रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रदर्शन तालिका में शामिल नहीं है।

संकेतक 11.03: पक्की सड़क घनत्व

परिभाषा: पक्की सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भूमि में पक्की सड़क का किलोमीटर है। इसकी गणना देश की कुल पक्की सड़क नेटवर्क की देश के भूमि क्षेत्र की लंबाई के अनुपात के रूप में की जाती है। पक्की सड़कें वह हैं जो क्रश्ड पत्थर (मैकाडैम) और हाइड्रोकार्बन बाइंडर या बिटुमिनिज्ड एजेंटों के साथ, कंक्रीट के साथ या कोब्लैस्टोन के साथ सभी देश की सड़कों के प्रतिशत के रूप में सामने आती हैं, जिसे लंबाई में मापा जाता है।

स्रोत: आईआरएफ जेनेवा, वर्ल्ड रोड सांख्यिकी डब्ल्यूआरएस।

$$\text{देश का मूल्य} = \frac{\text{देश की कुल पक्की सड़क कीलंबाई (किलोमीटर)} \times 100}{\text{देश का कुल भूमि क्षेत्र}}$$

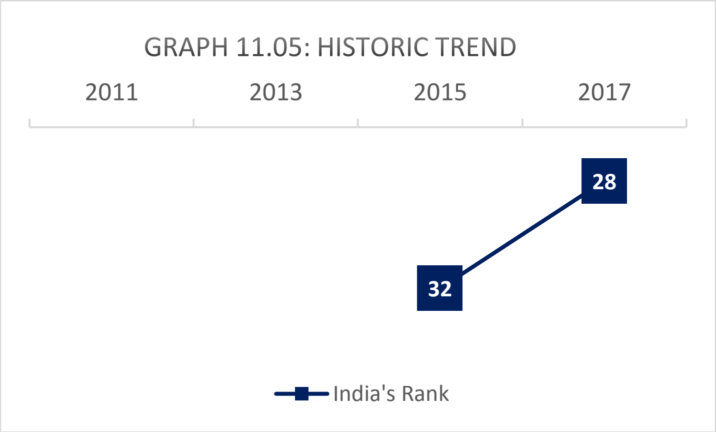

ग्राफ 11.05 संकेतक 11.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। वर्ष 2015 की तुलना में भारत की श्रेणी में 4 पदों की वृद्धि हुई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.52% का योगदान देता है।

तालिका 11.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	श्रेणी (2017)	कारण
सिंगापुर	2	2	एशियाई साथी
नीदरलैंड	7	6	शीर्ष प्रदर्शक

हांगकांग गणराज्य	10	9	एशियाई साथी
भारत	**32**	**28**	
ऑस्ट्रेलिया	112	96	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

इन संकेतकों के लिए मूल्य डब्ल्यूईवाईएफ रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रदर्शन तालिका में शामिल नहीं किया गया है।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)

मध्यम अवधि की योजना

- **प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया में सुधार**
  - ऑस्ट्रेलिया की जीआरटी (ग्लोबल रोड टेक्नोलॉजी) अद्वितीय, विशेष रूप से तैयार किए गए बहुलक उत्पादों का उपयोग करती है, जो चरम मौसम की स्थिति का सामना कर सकते हैं और कम रखरखाव के साथ वर्ष भर उपयोग करने योग्य होते हैं। जीआरटी का उपयोग त्वरित आधारिक संरचना बनाने और इन-सीटू सामग्री का उपयोग करके सड़कों का निर्माण करने के लिए किया जाता है जो कि 3 गुना तेज है और पारंपरिक तरीकों की तुलना में 37% सस्ता है।[216]
  - कंपनी व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर तीन सेटों पर काम कर रही है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिहार के औरंगाबाद तक यातायात की उच्च मात्रा को देखता है। जीआरटी कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकताओं में शामिल होने के कारण उप-अनुबंध के आधार पर भारत में मौजूद है। **इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर एक एकल खिड़की का गठन करके कानूनी कार्य की मात्रा को कम करना चाहिए, जहां सभी कानूनी औपचारिकताओं को समाप्त किया जा सकता है ताकि भारत में बड़े पैमाने पर जीआरटी के लाभ फिर से मिल सके।.**
  - **दीर्घावधि में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष तकनीकी संस्थानों जैसे आईआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) और एनआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) जीआरटी** जैसी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए साझेदारी कर सकता है, जो विदेशी प्रौद्योगिकी पर भारत की निर्भरता को कम करेगा।

दीर्घकालिक योजना

- **पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) परियोजनाओं का प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन:**

[216] https://www.globalroadtechnology.com/global-road-technology-officially-opens-headquarters/

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई है कि लगभग 85% परियोजनाओं को पीपीपी मोड पर विकसित करने की आवश्यकता है। लेकिन वैश्विक वित्तीय मेल्ट-डाउन, भूमि अनुमोदन में देरी, अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करना और सामग्री की कम गुणवत्ता का उपयोग जैसे कारक पीपीपी परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ बाधाएं हैं। इसके अलावा, लागत का गलत मूल्यांकन और बोली कुप्रबंधन पीपीपी में आने वाली अन्य बाधाएं हैं। एनएचएआई के अनुसार, टीएईटी ने एक वास्तविकता और आधारिक संरचना लिमिटेड (टीआरआईएल) ने राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद खंड के लिए दो परियोजनाओं के निर्माण अनुबंध जीतने के बाद अपनी बोलियां वापस ले लीं, यह कह कर कि इसकी लागत की जानता गलत कर ली गयी थी। यह इस बात का उदाहरण है कि वैश्विक कंपनियां कैसे परियोजना में त्रुटियों और देरी का कारण बन रही हैं।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पहले ही क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के साथ मिलकर एक ढांचा विकसित कर रहा है, जो पूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं पर विभिन्न दलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। इसी तर्ज पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ सहयोग कर सकते हैं ताकि चालू पीपीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों पर प्रकाश डाला जा सके। परियोजना के दौरान गुणवत्ता का काम, कार्यान्वयन में देरी, अनुमोदन में देरी आदि की पहचान की जा सकती है।

संकेतक 11.04: रेलमार्ग आधारिक संरचना की गुणवत्ता

परिभाषा: "आप अपने देश में रेलवे की आधारिक संरचना की गुणवत्ता का आकलन कैसे करेंगे?" **स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण**

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर 1 = अत्यंत अविकसित, दुनिया के सबसे बुरे में; 7 = व्यापक और कुशल, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से)

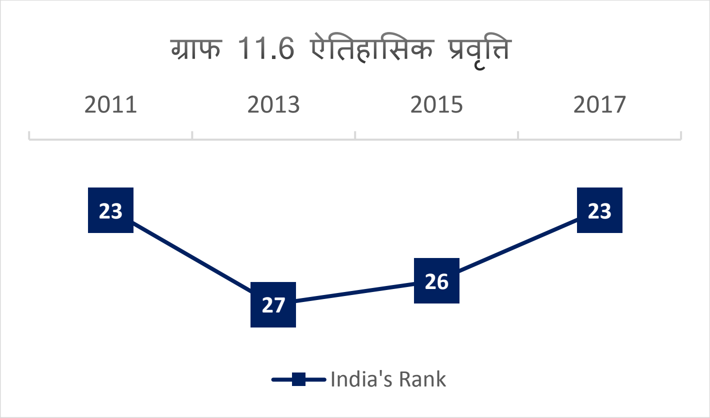

ग्राफ 11.06 इस संकेतक में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 3 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 0.52% का योगदान देता है।

तालिका 11.05: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
जापान	1	6.69	1	6.66	एशियाई साथी
स्विट्जरलैंड	2	6.6	2	6.56	शीर्ष प्रदर्शक
हांगकांग	3	6.33	3	6.36	एशियाई साथी
भारत	**26**	**4.24**	**23**	**4.47**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: रेल मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **रैपिड एक्शन टीम**
    - जापानी बुलेट ट्रेनें 50 से अधिक वर्षों से बिना किसी घातक दुर्घटना के चल रही हैं। उनके पास एक रैपिड एक्शन टीम है जो क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरती है ताकि बिना किसी देरी के दुर्घटनाओं के समय पर तैनात किया जा सके। दूसरी ओर, भारत में 70 रेल दुर्घटनाएँ केवल 2017-18 के बीच हुई हैं। इसलिए, रेल मंत्रालय देश के प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों को मिलाकर एक त्वरित कार्रवाई दल बनाने के लिए जोनल रेलवे विभागों का सहयोग कर सकता है, जो दुर्घटनाओं के दौरान यात्रियों की देखभाल कर सकता है। रैपिड एक्शन टीम द्वारा प्रदान की गई समय पर मदद भी हताहतों की संख्या को कम करेगी।[217]

मध्यम अवधि की योजना

- **आधारभूत संरचना का अभाव**
    - सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें 11 स्टेशन (पटना, मुगलसराय, नई दिल्ली, हावड़ा, भोपाल, इटारसी, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, चेन्नई, नागपुर) की जांच की गई, यह पाया गया कि बाहरी सिग्नलों या पास के स्टेशनों पर से बस कुछ दूरी पहले गाड़ियों को रोकना एक 'विचारणीय' अवधि के लिए ट्रैक को कब्जे में कर लेती है। चूंकि मार्गों में एकल-ट्रैक प्रावधान है, इसलिए समय पर चलने वाली अधिकांश ट्रेनों को मध्यवर्ती स्टेशनों पर पार करने के लिए प्रतीक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा, जिन ट्रेनों में पास के स्टेशनों में निर्धारित ठहराव नहीं होता है, उन्हें भी रास्ते की चाह के कारण रोक लिया जाता है, जिससे ट्रेनों में विलंब होता है। हालांकि, विभिन्न मार्ग में डबल ट्रैक प्रदान करके इन देरी से बचा जा सकता है।
    - **इसलिए, जोनल रेलवे विभागों की मदद से रेल मंत्रालय को बाहरी सिग्नल / पास के स्टेशनों / मार्ग पर ट्रेनों को रोकने के तरीके खोजने चाहिए और अन्य बाधाओं जैसे रूट रिले इंटरिंग, यार्ड रीमॉडेलिंग इत्यादि को देखना चाहिए।** ट्रैक की लंबाई को दोगुना करने की प्रक्रिया ताकि ट्रेन के आगमन में समय की देरी हो, जो कि रेलवे आधार संरचना की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करती है, उनसे बचा जा सकता है।

दीर्घकालिक योजना

- **आधुनिकीकरण और आधारिक संरचना का विकास**

[217] https://www.japanstation.com/shinkansen-high-speed-train-network-in-japan/

- हाल ही में, रेल मंत्रालय ने 90 रेलवे स्टेशनों को फिर से विकसित करने और बदलने का फैसला किया है। इस कदम से रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, इसलिए यह विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करता है। पुनर्विकास योजना में कई प्रमुख रेलवे स्टेशन शामिल होंगे, जो सीसीटीवी कैमरों, वाई-फाई, पुनर्निर्मित स्टेशन भवनों, वाटर एटीएम, एलईडी लाइट्स, एस्केलेटर, स्टेनलेस स्टील बेंच, आदि सुविधाओं के साथ प्रदान किए जाएंगे, इन सुविधाओं के अलावा, वेटिंग हॉल, वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, और वर्ष 2019 के अंत तक स्टेशनों के वॉश रूम में भी सुधार किया जाएगा।
- हालांकि, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2012 की तुलना में मार्च 2017 में प्रति दिन चलने वाली / समाप्त होने वाली ट्रेनों की संख्या में 13% (94 ट्रेनों) की वृद्धि हुई, पर उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक आधारिक संरचना तदनुसार नहीं बढ़ी है। इन स्टेशनों पर प्लेटफ़ॉर्म, वाशिंग पिट लाइन्स और स्टैबलिंग लाइन्स को ट्रेनों की संख्या के अनुसार संवर्धित नहीं किया गया हैं। इस अवधि के दौरान केवल दो पिट लाइनें जोड़ी गईं हैं, जिससे वाशिंग पिट लाइनों की संख्या 59 से 61 हो गई हैं, जबकि स्टेबलिंग लाइनों की संख्या समान ही रही हैं।
- **इसलिए, जोनल रेलवे विभागों की मदद से रेल मंत्रालय अधिक रेलवे स्टेशनों की पहचान कर सकता है, जिन्हें तत्काल संशोधनों की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें विश्व स्तर के मानकों के लिए विकसित किया जा सके। इसके अलावा, जहां भी आवश्यकता हो, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और पिट लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए। जगहकी कमी के मामले में, वैकल्पिक टर्मिनलों के विकास पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए और मौजूदा स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक स्टेशनों का विकास करना चाहिए।**

संकेतक 11.05: रेलमार्ग घनत्व

परिभाषा: लमार्ग घनत्व रेल का किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भूमि है। इसकी गणना देश के कुल रेल नेटवर्क की देश के भूमि क्षेत्र की लंबाई के अनुपात के रूप में की जाती है। रेल लाइनें रेल सेवा की लंबाई हैं, जो रेल सेवा के लिए उपलब्ध हैं, चाहे समानांतर पटरियों की संख्या कितनी भी हो।

स्रोत: विश्व बैंक, विश्व विकास संकेतक

देश का मूल्य = $\frac{\text{देश के कुल रेल नेटवर्क की लंबाई (किलोमीटर)} \times 100}{\text{देश की कुल भूमि क्षेत्र)}}$

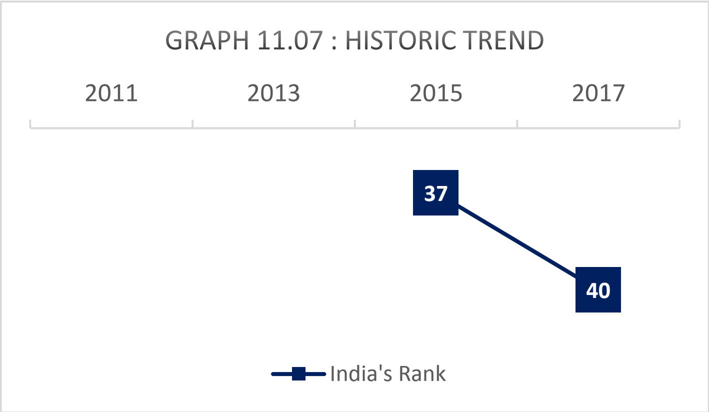

इस संकेतक में ग्राफ 11.07 भारत की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में 2015 की तुलना में 3 पदों की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 0.52% का योगदान देता है।

तालिका 11.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
चेक गणतंत्र	1	12	1	11.98	शीर्ष प्रदर्शक
बेल्जियम	2	11.71	2	11.72	शीर्ष प्रदर्शक
लक्समबर्ग	3	10.61	3	10.61	शीर्ष प्रदर्शक
यूनाइटेड किंगडम	9	6.74	9	6.07	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

भारत	37	1.96	40	2	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: रेल मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **रेलमार्ग घनत्व के तहत मेट्रो पटरियों पर विचार:**
    - भारतीय रेलवे अपने रेल घनत्व की गणना करते समय शहरी रेल पारगमन पर विचार नहीं करता हैं जबकि यूनाइटेड किंगडम (यूके) जैसे अन्य देशों में उनकी भूमिगत ट्यूब, ओवर ग्राउंड, टीएफएल (लंदन के लिए परिवहन) रेल, डीएलआर (डॉकलैंड्स लाइट रेलवे), राष्ट्रीय रेल और ट्राम उनके रेल घनत्व के तहत शामिल हैं। सितंबर 2018 तक, भारत में 515 किलोमीटर (320 मील) परिचालन मेट्रो लाइनें और 381 स्टेशन **हैं। आगे 500+ किमी लंबी लाइनें निर्माणाधीन है। इस प्रकार, यह सलाह दी जाती है कि रेल मंत्रालय को विश्व विकास संकेतकों के लिए अपने डाटा की रिपोर्ट करते समय कुल रेल घनत्व में मेट्रो रेल लाइन की लंबाई को भी जोड़ना चाहिए।**

तालिका 11.07: रेलवे घनत्व के मूल्य में वृद्धि

ट्रेन नेटवर्क	कवरेज (किलोमीटर)	रेलमार्ग घनत्व
रेलवे	65740	2
मेट्रो	425	0.0129
कुल (रेलवे + मेट्रो)	**66,165**	**2.0129**

- चूँकि मेट्रो रेल कुछ ऐसा है जिसे अधिकांश शहर अपना रहे हैं और नोएडा, लखनऊ, मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों में काम चल रहा है, यह आगे चलकर रेल घनत्व बढ़ाने के लिए एक सतत प्रक्रिया के रूप में कार्य करने वाले विभिन्न शहरों में फैल जाएगा जो भारत के लिए अपनी श्रेणी बढ़ाने के लिए फायदेमंद होगा।

दीर्घकालिक योजना

- **समर्पित माल गलियारों को लागू करना**
    - वर्षों तक, मालगाड़ियों को एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में द्वितीय श्रेणी के उपचार का सामना करना पड़ा और अन्य यात्री ट्रेनों को पटरियों का उपयोग करने के लिए प्राथमिकता मिली। जैसा कि सभी ट्रेनें समान पटरियों का उपयोग करती हैं, मालगाड़ियां जो माल ले जाती हैं, समय पर अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचती हैं। इससे रेलवे द्वारा 1950-51 में 86% से 36% तक

माल ढुलाई के शेयर में तीव्र गिरावट आई, जबकि कुल माल यातायात में तेजी से वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में, कई देशों में, लगभग 50 प्रतिशत माल की धुलाई रेलवे नेटवर्क के माध्यम से होती है।

- मई 2018 में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से को वेस्ट कोस्ट से जोड़ने के लिए पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन (पीसीईटी) का संचालन शुरू किया है।
- **इसी तरह, देश के अन्य हिस्सों में जहाँ संभव हो, माल ढुलाई के लिए एक अलग रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए। इससे यात्री की ट्रेन में परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने के लिए मौजूदा लाइन को बढ़ावा मिलेगा और मालवाहक ट्रेनों के लिए नए ट्रैक का इस्तेमाल किया जा सकता है जो वाणिज्यिक लाभ को काफी बढ़ाएगा।**

संकेतक 11.06: बंदरगाह आधारिक संरचना की गुणवत्ता

परिभाषा: "आप अपने देश में बंदरगाह आधार संरचना की गुणवत्ता का आंकलन कैसे करेंगे?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 तक के पैमाने पर (1 = अत्यंत अविकसित, दुनिया के सबसे बुरे में; 7 = व्यापक और कुशल, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से)

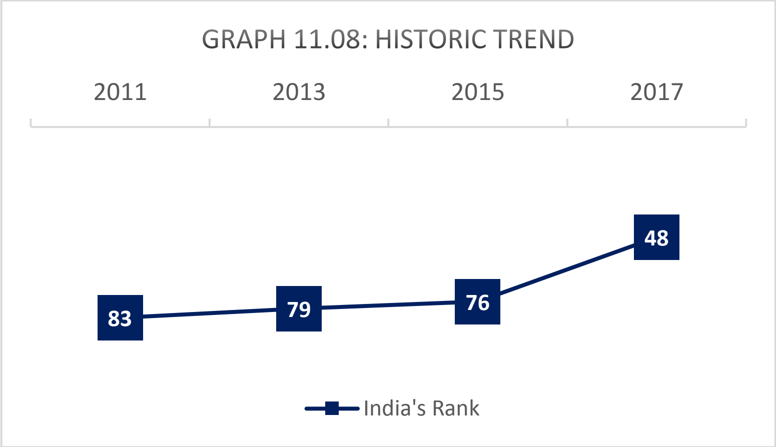

इस संकेतक में ग्राफ 11.08 भारत की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 28 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 2.08% का योगदान देता है।

तालिका 11.08: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
नीदरलैंड	1	6.8	1	6.8	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	2	6.7	2	6.7	एशियाई साथी
यूनाइटेड अरब अमीरात	3	6.5	3	6.4	शीर्ष प्रदर्शक
भारत	**76**	**4**	**48**	**4.5**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पोत परिवहन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **टर्न-अराउंड समय को कम करना**
  - टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) रिपोर्टिंग स्टेशनों से उसके प्रस्थान तक रिपोर्टिंग स्टेशनों पर आगमन पर बंदरगाह पर एक पोत द्वारा खर्च किया गया कुल समय है। औसत टीएटी कई कारकों से प्रभावित होता है जैसे कि कार्गो के प्रकार, पार्सल आकार और प्रवेश चैनल। पिछले कुछ वर्षों में, औसत टीएटी वित्त वर्ष 2016 में 2.04 दिन, वित्त वर्ष 2015[218] में 4.01 दिन से सुधरा है। लेकिन भारत अभी भी सिंगापुर जैसे विभिन्न देशों से पीछे है जहाँ टीएटी एक दिन[219] से भी कम है। इस प्रकार, पोत परिवहन मंत्रालय को अपनी अपर्याप्त बंदरगाह आधारिक संरचना में सुधार के लिए उचित उपाय करना चाहिए ताकि औसत टीएटी को कम किया जा सके।

मध्यम अवधि की योजना

- **बंदरगाहों को वित्तीय सहायता**
  - पोर्ट आधारिक संरचना की गुणवत्ता उस राजस्व पर अत्यधिक निर्भर करती है जो बंदरगाह उत्पन्न कर रहा है, जो उस बंदरगाह पर व्यापार किए जाने वाले सामानों से सीधे प्रभावित होता है। यह कुछ बंदरगाहों के आधारिक संरचना विकास में कमी पैदा करता है जो उन वस्तुओं का व्यापार नहीं करते हैं जो भारी मुनाफा कमाते हैं। इसलिए, पोत परिवहन मंत्रालय को हस्तक्षेप करने और इन दोनों प्रकार के बंदरगाहों के बीच एक संतुलन विकसित करना आवश्यक है ताकि अंत में, सभी बंदरगाहों को विश्व स्तर के आधारिक संरचना से बनाया जा सके जो सर्वोत्तम सेवा प्रावधान सुनिश्चित करता है।

दीर्घकालिक योजना

- **कनेक्टिविटी में सुधार**
  - बंदरगाह उत्पादकता और दक्षता सड़क और रेल कनेक्टिविटी, पर्याप्त भंडारण और हैंडलिंग सुविधाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करती है। प्रमुख बंदरगाहों के साथ-साथ औद्योगिक समूहों और उच्च ईंधन लागत के बीच एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी की कमी से हंटरलैंड परिवहन अक्षम और धीमा हो जाते हैं। पोत परिवहन मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सभी प्रमुख बंदरगाहों और औद्योगिक

---

218 https://www.ibef.org/download/Ports-March-2017.pdf
219 https://www.india-briefing.com/news/ports-india-incentives-investment-14354.html/

समूह स्थानों को एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइनों के साथ जोड़ने के लिए क्रमशः विभिन्न संस्थाओं के बीच माल की एक सुव्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित कर सकता है। [220]

[220] http://blogs.worldbank.org/transport/what-are-some-critical-innovations-improving-port-hinterland-connectivity

संकेतक 11.07: जमीने परिवहन दक्षता

परिभाषा: “आपके देश में, निम्नलिखित परिवहन सेवाएँ कितनी कुशल (यानी आवृत्ति, समय की पाबंदी, गति, मूल्य) है?

A. जमीनी परिवहन (बसें, सबवे, टैक्सियाँ)

B. ट्रेन सेवाएं ”

दोनों मापदंडों, जमीनी परिवहन और ट्रेन सेवाओं को इओएस के माध्यम से 1 से 7 पैमाने पर (1 = अत्यंत अक्षम, दुनिया में सबसे खराब; 7 = अत्यंत कुशल, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में) के माध्यम से स्कोर किया जाता है;

मूल्य: जमीनी परिवहन और इओएस से ट्रेन सेवाओं के स्कोर का औसत

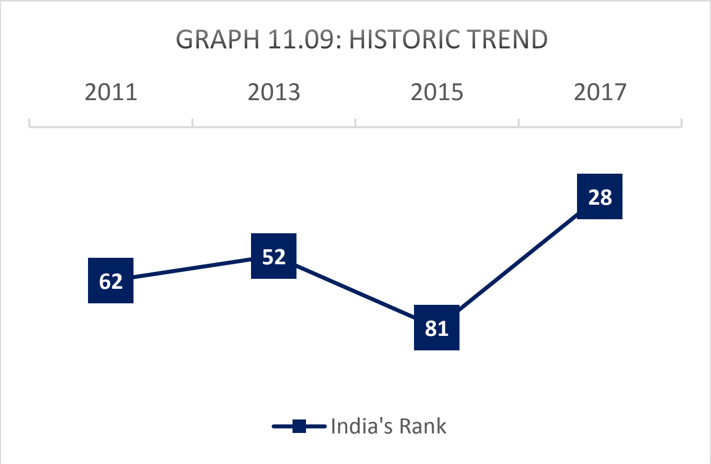

ग्राफ 11.09 संकेतक 11.07 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 53 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 2.08% का योगदान देता है।

तालिका 11.09: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
जापान	3	6.40	1	6.60	एशियाई साथी
स्विट्जरलैंड	1	6.48	2	6.38	शीर्ष प्रदर्शक
हांगकांग गणराज्य	2	6.43	3	6.14	एशियाई साथी
सिंगापुर	8	6.0	4	5.94	एशियाई साथी
भारत	**81**	**4.13**	**28**	**4.73**	
ऑस्ट्रेलिया	39	4.95	32	4.46	सर्वश्रेष्ठ प्रथा

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **सार्वजनिक परिवहन की दक्षता में सुधार**

  भारत के परिवहन क्षेत्र में विकास में बड़ी कमी है क्योंकि सड़कें घटिया स्तर की हैं और कम लेन क्षमता वाली हैं। यद्यपि ग्रामीण सड़क नेटवर्क व्यापक है, भारत के लगभग 33% गांवों में सभी मौसम वाली सड़कों तक पहुंच नहीं है और मानसून सीजन 1 के दौरान उनका संपर्क टूट जाता हैं। भारत का परिवहन क्षेत्र बड़ा और विविध है; यह 1.3 बिलियन लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संबंधित राज्य विभागों की मदद से उपर्युक्त कमियों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं: - [221]

  - **परिवहन सेवाओं के लिए इष्टतम मूल्य निर्धारण रणनीतियों को अपनाना:** परिवहन का मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे ठीक से संबोधित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य निर्धारण नीति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

    - सरकार को सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लगाए गए वार्षिक मोटर वाहन कर और यात्री कर को समाप्त करके सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए, सरकारी बस संचालक अपनी संपत्ति और संचालन पर 13 विभिन्न करों के लिए उत्तरदायी हैं। मोटर वाहन कर, यात्री कर और अन्य कर परिचालन लागत[222] का 20% के करीब योगदान करते हैं। इस भारी कराधान नीति को हटाने का प्रयास होना चाहिए।
    - अंतर मूल्य निर्धारण तंत्र जैसे पीक पीरियड, ऑफ-पीक पीरियड, पीक-दिशा, ऑफ-पीक दिशा, आदि आधारित मूल्य निर्धारण रणनीति को मेट्रो और कैब में अपनाया गया है, लेकिन बसों और तीन पहिया वाहनों में भी अपनाया जा सकता है।

  - **इंटरस्टेट बस पास का उपयोग:** बस उपयोगकर्ताओं के विशाल बहुमत हर दिन एक ही प्रकार की आवागमन यात्राएं करते हैं। विभिन्न शहरों ने भारत में बस पास की शुरुआत की है, लेकिन इंटरस्टेट पास प्रदान करने में कमी है। उदाहरण के लिए, लोगों का एक बड़ा हिस्सा चंडीगढ़ से दिल्ली, हरियाणा से दिल्ली आदि की दैनिक यात्रा करता है। इंटरस्टेट बस पास की शुरूआत न

---

[221] http://web.worldbank.org/archive/website01291/WEB/0__CO-21.HTM

[222] https://www.hindustantimes.com/delhi-news/taxation-policy-killing-bus-systems-in-cities-across-india/story-gxe7wPIX8N2BUROnZA3VfN.html

केवल लोगों की यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगी, बल्कि दो शहरों के बीच परिवहन की आवृत्ति के आधार पर दैनिक यात्रियों के लिए कुछ प्रोत्साहन को भी बढ़ावा देगी।

- **समर्पित बस लेन, और सिग्नल प्राथमिकता के साथ बस की गति बढ़ाएँ:** समर्पित बस लेन, जो बसों को यातायात से बच कर चलने दें, विभिन्न रूपों में मौजूद हैं। अमेरिकी शहर जो बस गलियां डालते हैं, उन्हें आमतौर पर सड़क के कर्ब साइड में, पार्किंग लेन के ठीक बगल में रखा जाता है, जिससे बसों के लिए सामान्य बस स्टॉप से यात्रियों को उठाना आसान हो जाता है। चौराहों पर, बसों में सिग्नल प्राथमिकता हो सकती है। इसका मतलब यह है कि चौराहे ऐसे सेंसर से लैस हैं जो एक बस की उपस्थिति का पता लगाते हैं, और इसके पास पहुंचते ही इसकी रोशनी को हरे रंग में बदल देते हैं। बस की गति पर पड़ने वाला प्रभाव महत्वपूर्ण हैं: न्यूयॉर्क में, सिग्नल प्राथमिकता प्राप्त करने वाली बसों को लगभग 10% की गति मिलती हैं।

मध्यम अवधि की योजना

- **सार्वजनिक परिवहन के लिए ऑनलाइन बस टिकट प्रणाली**
  - सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार,[223] भारत में सार्वजनिक परिवहन का एक विशाल नेटवर्क है, जिसके पास लगभग 140.5 हजार बसें हैं, जिनका स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के पास है, जो सड़क पर कुल वाहनों का 7.13% है, लेकिन बस सेवा की इंटरसिटी ऑनलाइन प्रणाली के संचालन में कमी है। जैसा कि भारत एक कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदल रहा है, सार्वजनिक परिवहन (जैसे डीटीसी बसों) के लिए इंटरसिटी ऑनलाइन बस टिकट प्रणाली की आवश्यकता है जहां बसों के लिए टिकट ऑनलाइन उत्पन्न किया जा सकता है।
  - सिंगापुर के पास 'माय सिंगापुर' 'नाम की एक वेबसाइट है जो एक शहर में रेल, बसों और टैक्सी सेवाओं के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। सिंगापुर में बस सेवा की एक विशेष ऑनलाइन प्रणाली है जो ऑनलाइन टिकट उत्पन्न करती है, बसों के आगमन और प्रस्थान के समय के बारे में बताती है और संक्षिप्त मार्ग मानचित्र प्रदान करती है।[224][225]
  - भारत में सड़क परिवहन, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बस परिवहन क्षेत्र द्वारा एक समान तकनीक अपनाई जा सकती है।

दीर्घकालिक योजना

- **परिवहन समन्वय प्राधिकरण का गठन**

[223] https://community.data.gov.in/buses-owned-by-the-public-sector-in-india-from-2001-to-2015/
[224] https://www.mytransport.sg/content/mytransport/home/commuting/busservices.html
[225] https://community.data.gov.in/buses-owned-by-the-public-sector-in-india-from-2001-to-2015/#

- हमें एक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है जो कि सभी मोड में मूल रूप से एकीकृत है। मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन सहित सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न तरीकों को मिलकर काम करना है। वर्तमान में, विभिन्न एजेंसियां, एक दूसरे से स्वतंत्र, भारत के शहरों में विभिन्न सेवाओं पर काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है, उत्तर रेलवे द्वारा उप-शहरी रेल सेवा, दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बस परिवहन सेवा, और निजी ऑपरेटरों द्वारा टैक्सी और ऑटो-रिक्शा। इन एजेंसियों में समन्वय की कमी है।
- पर्याप्त और कुशल परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए, विभिन्न मोडों के संचालन को समन्वित करने के लिए एक समन्वित प्राधिकारी की आवश्यकता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अमेरिका में एक सफल प्रणाली ने सार्वजनिक परिवहन संगठन के गठन से सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता में बहुत सुधार किया है जो सभी मार्गों, सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन और महानगरीय क्षेत्र[226] के सभी हिस्सों के लिए किराए और सेवाओं का समन्वय करता है।
- यह समन्वयन प्राधिकरण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और इसमें निजी टैक्सी ऑपरेटरों, बस ऑपरेटरों, रेलवे, राज्य सरकार, आदि[3] जैसे विभिन्न हितधारकों से प्रतिनिधियों की पुनःपूर्ति हो सकती है।

- **सार्वजनिक परिवहन में किराया एकीकरण**
  - सभी सार्वजनिक परिवहन साधनों पर एक एकल प्रयोग करने योग्य किराया कार्ड होता है, जो एकीकृत परिवहन को बहुत ही सुविधाजनक बनाता है। ऐसी प्रणाली के प्रभाव दक्षता लाभ और परिचालन लागत में कमी हैं। एकल किराया कार्ड के साथ, इंटरमॉडल ट्रांसफर के लिए छूट प्रदान करके सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी आसान है। भारत में किसी भी सार्वजनिक परिवहन के बीच कोई एकीकरण नहीं है। इसलिए, कई यात्रियों को परिवहन के विभिन्न तरीकों के लिए बार-बार टिकट लेना पड़ता है जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। एक समान किराया एकीकरण कार्ड का उपयोग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है, जहां सार्वजनिक परिवहन जैसे सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो और कैब के साथ दिन-प्रतिदिन यात्रा के लिए आंतरिक छूट के साथ यात्रा करने वाले एक एकल पारगमन लिंक कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।

[226] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0967070X9500022I

- मायकी ऑस्ट्रेलिया का एक यात्रा कार्ड है जो ऑस्ट्रेलिया, (मेलबोर्न, सिडनी आदि) के कई हिस्सों में ट्रेनों, ट्रामों और बसों के लिए उपयोग किया जाता है। यह कार्ड 7- एलेवेंस (डिपार्टमेंटल स्टोर्स) सहित 800 दुकानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यात्रा के ऑफ पीक आवर्स के दौरान कुछ मामलों में उपयोगकर्ताओं को 35% तक छूट के साथ 10-20% की छूट भी दी जाती है।[227]
- भारत में एक समान रणनीति अपनाई जा सकती है, जहां महानगरीय शहरों के सभी सार्वजनिक परिवहन में एकल ट्रांजिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। एक एकल कार्ड जो दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और बेंगलुरु आदि में किसी भी सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बस, टैक्सी) में इस्तेमाल किया जा सकता है।

[227] https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/myki/manage-your-myki-online

स्तंभ 12: पर्यटक सेवा आधारिक संरचना

परिभाषा: यह स्तंभ प्रमुख पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता और गुणवत्ता जैसे आवास और कार किराए पर लेने की गुणवत्ता को मापता है। स्तंभ 12 के नीचे कुल 4 संकेतक हैं -

1. होटल के कमरे
2. पर्यटन आधारिक संरचना की गुणवत्ता
3. प्रमुख कार किराए पर देने वाली कंपनियों की उपस्थिति
4. स्वचालित वयस्क जनसंख्या प्रति टेलर मशीन

GRAPH 12.01: HISTORIC TREND

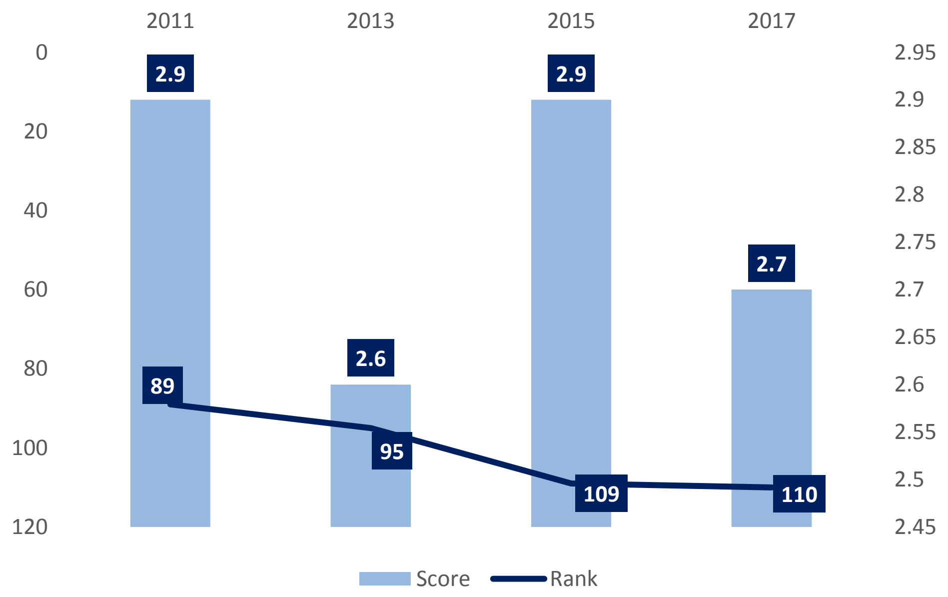

ग्राफ 12.01 भारत की श्रेणी और स्तंभ 12 में मूल्य के ऐतिहासिक रुझान को इंगित करता है। भारत की श्रेणी 2011 में 89 वें स्थान से घटकर 2017 में 110 वें स्थान पर आ गई है।

भार की स्थिति में बदलाव:

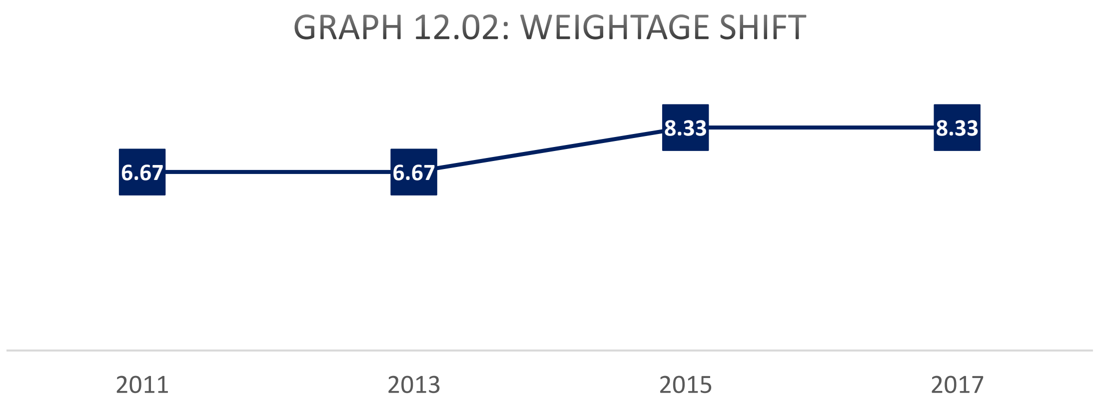

ग्राफ 12.02, स्तंभ 12 के समग्र योगदान को दर्शाता है, जो कि भारत के स्कोर में पर्यटक सेवा आधारिक संरचना है। वर्तमान में इस स्तंभ को 8.33% भार दिया जाता है। इस स्तंभ का भार वर्ष 2015 में 25% बढ़ गया है।

तालिका 12.01: भार के स्थिति में संकेतक वार बदलाव

संकेतक	2011-2013 (%)	2015-2017 (%)	भार के स्थिति में बदलाव (%)
होटल के कमरे	2.22	2.08	-6.31
पर्यटन आधारिक संरचना की गुणवत्ता	NA	2.08	NA
प्रमुख कार किराए पर देने वाली कंपनियों की उपस्थिति	2.22	2.08	-6.31
स्वचालित टेलर मशीनों की संख्या	2.22	2.08	-6.31

NA = लागू नहीं, उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

तालिका 12.01 योगदान का प्रतिशत दर्शाती है कि प्रत्येक संकेतक द्वारा भारत के समग्र स्कोर पर होता है।

संकेतक 12.01: होटल के कमरे

परिभाषा: यह संकेतक प्रति 100 जनसंख्या वाले देश में होटल के कमरों की संख्या को संदर्भित करता है।

विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)

देश का मूल्य = $\frac{\text{देश में होटल के कमरों की संख्या} \times 100}{\text{देश की कुल जनसंख्या}}$

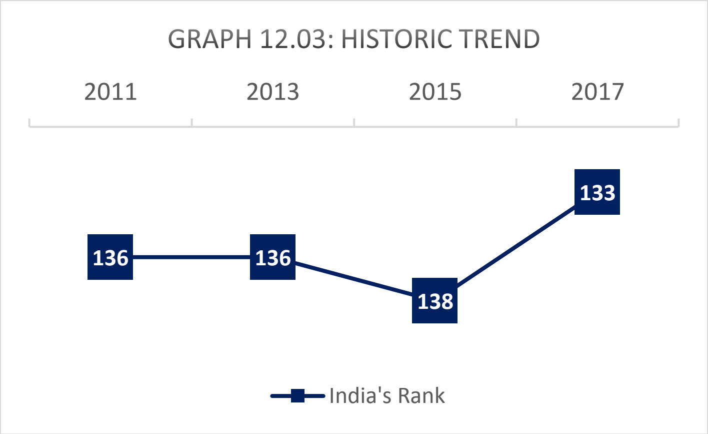

ग्राफ 12.03 संकेतक में भारत की श्रेणी के ऐतिहासिक रुझान को इंगित करता है 12.01। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 5 स्थान की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 2.08% का योगदान देता है।

तालिका 12.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
माल्टा	1	4.35	1	4.268	शीर्ष प्रदर्शक
आइसलैंड	5	3.53	2	4.077	शीर्ष प्रदर्शक
ग्रीस	2	3.63	3	3.752	शीर्ष प्रदर्शक
जापान	27	1.12	27	1.118	एशियाई साथी
चीन	112	0.11	116	0.106	एशियाई साथी
भारत	**138**	**0.006018**	**133**	**0.0061**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **नई होटल परियोजनाओं के अनुदान के लिए एकल खिड़की प्रणाली**
    - भवन अनुज्ञा, अग्नि सुरक्षा अनुज्ञा, पुलिस लाइसेंस, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस, व्यापार पंजीकरण, बार लाइसेंस, एफएसएसएआई खाद्य व्यापार लाइसेंस, सेवा कर लाइसेंस, वैट पंजीकरण (कुछ राज्यों में 100 से अधिक तक जोड़ सकते हैं) जैसे कई लाइसेंस और अनुमोदन हैं जिनकी भारत में एक होटल खोलने के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता है जो समय, प्रयास और धन की भारी हानि की ओर जाता है।
    - इसके अलावा, अनुमोदन / जारी करने वाले लाइसेंस देने वाले विभिन्न निकाय स्वतंत्र सिलोस में काम करते हैं, जिससे सबकुछ आवेदक पर छोड़ दिया जाता है। जैसा कि खनिज ब्लॉकों के आवंटन में भारत सरकार द्वारा किया गया है, जहां पर्यावरण और अन्य मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक एकल खिड़की निकासी प्रणाली रखी गई है, पर्यटन मंत्रालय इसी तरह से एक ही क्षेत्र के तहत होटल उद्योगों के लिए सभी लाइसेंस देने के लिए एकल मंच के तहत एकल खिड़की निकासी प्रणाली को अपना सकता है।[228]

मध्यम अवधि की योजना

- **भारत में केंद्रीकृत डाटा बेस का रखरखाव:** भारत में केंद्रीकृत डाटा बेस का रखरखाव: भारत में वर्तमान में होटल डाटा का एक केंद्रीकृत पूल का अभाव है जो किसी भी राज्य में बिस्तर और होटल के कमरों की कुल संख्या जैसी विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार, होटल जाने वाले पर्यटकों की पहचान भी सरकार के लिए अज्ञात रहती है जो सुरक्षा के मुद्दों को आगे बढ़ाती है। इस वजह से, बड़ी मात्रा में मौद्रिक डाटा सरकार के पास बिना ट्रेस करे ही रहता है। इसके अलावा, डाटा की कमी के कारण, सेवित (जैसे होटल) और गैर-सेवित (जैसे किराए पर) दोनों के लिए मांग और आपूर्ति का प्रक्षेपण, भविष्य के लिए, ठीक से नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक ही स्थान पर होटल के डाटा को इकठ्ठा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

---

[228] http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol16-issue9/Version-1/J016916973.pdf

- **थर्ड-पार्टी पैन इंडिया सर्वेक्षण:** फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के साथ सहयोग करके पर्यटन मंत्रालय पैन इंडिया स्तर पर एक थर्ड-पार्टी सर्वे कर सकता है जो अपंजीकृत होटलों के बारे में सार्थक जानकारी दे सकता है। इससे होटल के कमरों का अपंजीकृत खंड मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा।
- **पुलिस विभाग का सहयोग:** भारत में प्रत्येक होटल अपने शहर में स्थानीय पुलिस के साथ खुद को पंजीकृत करता है। इसलिए, राज्य पुलिस विभागों के साथ सहयोग करने से होटलों के डाटा को एक स्थान पर समेटने में मदद मिल सकती है।

पर्यटन मंत्रालय वर्तमान नियम में संशोधन कर सकता है ताकि कंपनियों की सभी वेबसाइट जैसे मेक माई ट्रिप, गोइबीबो, ट्रिवैगो, फैबहोटल, ट्रीबो आदि केवल बुकिंग और अन्य सुविधाओं के

- लिए केंद्रीय रूप से पंजीकृत होटल प्राप्त कर सकें। यह आगे चलकर होटलों को केंद्रीकृत डाटा बेस के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।दीर्घकालिक योजना

- **जापान में पर्यटकों के लिए निजी घरों में किराए के कमरे पर लेने के लिए कानून**

जापान में होटल और इन्स अधिनियम में उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो पर्यटकों को होटल और इन्स अधिनियम के तहत आने के लिए निजी घरों को किराए पर देता है। इन निजी घरों को भी सरकार से परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है और साथ ही (होटल एंड इन्स एक्ट, 1948 के अधिनियम संख्या 138, 2016 के अधिनियम संख्या 47 द्वारा संशोधित, art.3, ई-गोव) (जापान में)[229]. इसके अलावा, अधिनियम के तहत राज्यपाल की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है, जहां घर-साझा करने वाले व्यवसाय संचालकों को समय-समय पर उन मेहमानों की संख्या की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिनके लिए अतिथि रुके थे, प्रत्येक संपत्ति को घर-साझाकरण व्यवसाय के रूप में रिपोर्ट करते हैं। यदि कोई व्यवसाय उल्लंघन करता है, तो राज्यपाल एक वर्ष तक के व्यवसाय के संचालन को निलंबित कर सकता है।

- **भारत में कानून को अपनाना:** पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में एक समान कानून अपनाया जा सकता है, जहां एयरबीएनबी के तहत निजी घरों को अपंजीकृत किया जाता है या पर्यटकों के ठहरने के उद्देश्य से उपयोग किए जा रहे किसी भी निजी घरों को भारत सरकार के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य किया जा सकता है क्योंकि यह होटल / होटल के कमरों की संख्या के

[229] http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/japan-law-on-renting-rooms-in-private-homes-to- tourists/

लिए एक डाटा बेस के रखरखाव में मदद करेगा। साथ ही, सरकार और घर के मालिकों के बीच एक पारस्परिक संबंध की योजना बनाई जा सकती है, जहां बुनियादी सुविधाएं और आधारभूत संरचना सरकार द्वारा प्रदान की जा सकती है और बदले में, उत्पन्न राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत सरकार के साथ साझा किया जा सकता है।

संकेतक 12.02: पर्यटन आधारिक संरचना की गुणवत्ता

परिभाषा: आपके देश में, आप पर्यटन आधारिक संरचना (जैसे होटल, रिसॉर्ट, मनोरंजन सुविधाओं) की गुणवत्ता का आंकलन कैसे करते हैं। "

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = बहुत खराब, दुनिया में सबसे खराब, 7 = उत्कृष्ट, दुनिया के लोगों

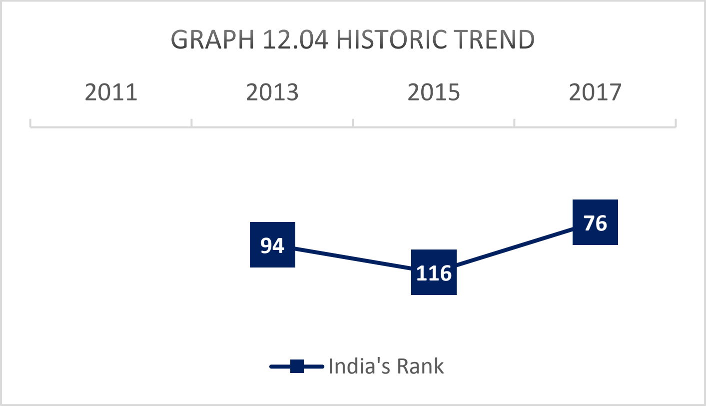

के बाच में सबसे अच्छा)

ग्राफ 12.04 संकेतक 12.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक 2013 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 40 पदों की वृद्धि हुई। यह संकेतक देश के स्कोर में 2.08% का योगदान देता है।

तालिका 12.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
संयुक्त अरब अमीरात	2	6.391	1	6.691	शीर्ष प्रदर्शक
सिंगापुर	51	5.584	2	6.384	एशियाई साथी
ऑस्ट्रिया	6	6.311	3	6.187	शीर्ष प्रदर्शक
चीन	110	4.639	72	4.553	एशियाई साथी
भारत	**116**	**4.545**	**76**	**4.516**	

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **पर्यटन के लिए मांग का निर्माण कारण :** चुनौती रही है। आर्थिक और सामाजिक आधारिक संरचना की खराब गुणवत्ता होटल, कनेक्टिविटी, मानव संसाधन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि में परिलक्षित होती है। सुरक्षा और सुरक्षा भी पर्यटन विकास के लिए एक प्रमुख मार्ग है।[230] वं में भी भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचना की कमी एक बड़ी मूल्य प्रस्तावों की उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एक पर्यटक-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना और पर्यटन और संवर्धन के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा "खोजा जाना चाहिए" गंतव्य के रूप में ब्रांडिंग करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए, नीचे दिए गए भविष्य में सुधार के कुछ उपाय दिए गए हैं:
    - **ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना:** पर्यटन मंत्रालय भारत में 600,000 गाँवों का लाभ उठा सकता है जिनकी अपनी संस्कृतियाँ और विरासत हैं और वे यात्रियों के लिए अद्वितीय अनुभव बनाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। **इसलिए, पर्यटन मंत्रालय ऐसे गांवों और कस्बों की पहचान करने के लिए राज्य के पर्यटन विभागों के साथ सहयोग कर सकता है।**
    - **उदाहरण:** सुमाडा चेनमो भारत के लद्दाख क्षेत्र का एक सुदूरवर्ती गाँव है, जो गाँव में पाए जाने वाले लकड़ी के बुद्ध प्रतिमाओं के युगों के आधार पर 1,000 साल पहले का है। 2016 में, ग्रामीणों ने 100 से अधिक पर्यटकों को खानपान देकर 2,000 डॉलर से अधिक की कमाई की हैं।
    - **होटलों की गुणवत्ता के लिए केंद्रीकृत प्रणाली:** होटल मंत्रालय और रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मदद से पर्यटन मंत्रालय द्वारा होटलों की गुणवत्ता की जाँच के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली बनाई जा सकती है। कमरे की सेवाओं, आतिथ्य और होटल सुविधाओं के आधार पर गुणवत्ता की जाँच की जा सकती है। पर्यटन मंत्रालय, होटलों के उचित निरीक्षण के बाद उन्हें गुणवत्ता अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है। यह प्रक्रिया एमओटी द्वारा बनाए गए एक केंद्रीकृत डाटा बेस का उपयोग करके सभी होटलों के लिए किया जा सकता है जैसा कि संकेतक 12.01 में उल्लेख किया गया है।
    - **रोजगार सृजन:** भारत में कौशल उद्योग का लाभ उठाते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत चलाए जा रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय

[230] https://www.onlinejournal.in/IJIRV3I10/031.pdf

शहरी आजीविका मिशन, कौशल भारत आदि। देश में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सहयोग कर सकता है जैसे आतिथ्य प्रबंधन, खाद्य पदार्थ, उत्पादन और सेवा, होटल संचालन, अवकाश यात्रा और पर्यटन, रेस्तरां प्रबंधन आदि।

मध्यम अवधि की योजना

- **"सुरक्षित और यात्रा पहल" को अपनाना:** पर्यटन मंत्रालय द्वारा यूएनडीपी भारत के साथ सहयोग करके एक "सुरक्षित और यात्रा पहल" को अपनाया जा सकता है, जहां नवाचार और प्रौद्योगिकी के संयोजन से चार प्रमुख क्षेत्रों में सहमति के साथ सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रम तक पहुंचा जा सकता है।[231] चीन में, सीट्रिप (चीनी यात्रा प्रदाता), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), चीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और तकनीकी आदान-प्रदान केंद्र (सीआईसीईटीई) और चीन पर्यटन अकादमी (सीटीए) ने संयुक्त रूप से "सुरक्षित और जिम्मेदार यात्रा पहल" शुरू की है, जो नहीं केवल यात्रियों को जिम्मेदार और सुरक्षित यात्रा के महत्व के बारे में शिक्षित करता है, लेकिन उनकी विदेश यात्रा के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो मानवीय सहायता भी प्रदान करता है।

दीर्घकालिक योजना

- **देशों के बीच संयुक्त वफादारी कार्यक्रम: भारत में एक संयुक्त योजना पहल हमारे एशियाई साथी के साथ मिलकर के शुरू की जा सकती है जो भारत[232]. के लिए स्रोत बाजार के रूप में कार्य कर सकती है।** उदाहरण के लिए, "आई गो चाइना - आई गो केन्या" संयुक्त लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसे चीन और केन्या दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद स्टैनबिक बैंक केन्या और इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) ने भी दोनों देशों में आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा खरीदारी और अवकाश के लिए प्रोत्साहन देकर पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल की है।

---

[231] https://globenewswire.com/news-release/2018/09/10/1568437/0/en/CTRIP-UNDP-CICETE-and-CTA-Launches-Safe-and-Responsible-Travel-Initiative.html
[232] http://africa.chinadaily.com.cn/a/201805/15/WS5afaea40a3103f6866ee8884.html

संकेतक 12.03: प्रमुख कार किराए पर देने वाली कंपनियों की उपस्थिति

परिभाषा: यह संकेतक देश की प्रमुख कार किराए पर देने वाली कंपनियों की संख्या को दर्शाता है, जो निम्नलिखित प्रमुख कार किराए पर देने वाली 7 कंपनियों की सूची से बाहर हैं:

1. ऐविस
2. बजट
3. युरोपकार
4. हर्ट्ज
5. नेशनल कार रेंटल
6. सिक्सट
7. थ्रिफ्टी

स्रोत: व्यक्तिगत किराये की कार वेबसाइटों के आधार पर लेखक की गणना

देश का मूल्य: देश में परिचालन करने वाली प्रमुख कार किराये पर देने वाली कंपनियों की संख्या।

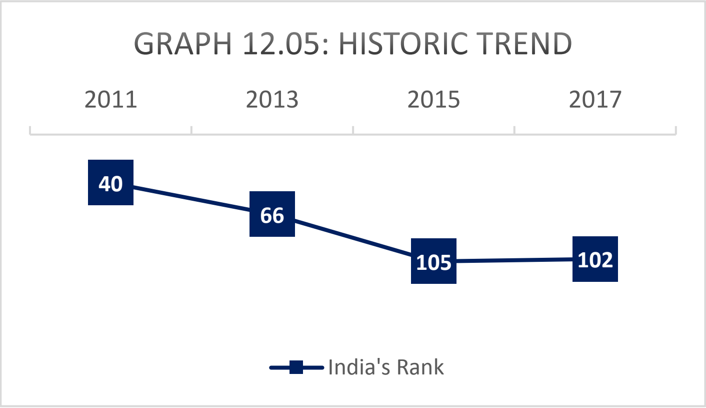

ग्राफ 12.05 संकेतक 12.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 3 पदों की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 2.08% का योगदान देता है।

तालिका 12.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
श्रीलंका	81	4	85	4	एशियाई साथी

पाकिस्तान	95	3	102	3	एशियाई साथी
चीन	105	2	102	3	एशियाई साथी
भारत	**105**	**2**	**102**	**3**	

संकेतक की पृष्ठभूमि: यह संकेतक एक देश में कार किराए पर देने वाली कंपनियों की संख्या को मापता है। (यानी ऊपर उल्लिखित 7 कार किराये पर देने वाली कंपनियों में से)। उदाहरण के लिए - भारत में 7 प्रमुख कार किराए पर देने वाली कंपनियों की सूची में वर्तमान में 3 कार किराए पर देने वाली कंपनियां यानी एविस, हर्ट्ज और नेशनल कार रेंटल परिचालन में हैं, इसलिए भारत का मूल्य 3. है। इसके अलावा, 50 देश हैं जो श्रेणी 1 पर आते हैं। श्रेणी में 7 परिचालन कर रही किराये पर कार देने वाली कंपनियां हैं। ऐसे 11 देश हैं जिनकी श्रेणी भारत (102) के समान है और 3 कार किराए पर देने वाली कंपनियां हैं उदहारण के लिए चीन और पाकिस्तान नीचे दिए गए अनुसार:

तालिका 12.05: एक देश में वर्तमान में कार किराए पर देने वाली कंपनियों की संख्या के आधार पर श्रेणी का स्वत्वार्पण

मूल्य / कार किराए पर देने वाली कंपनियों की संख्या	देश को स्वत्वार्पण की गयी श्रेणी	देशों की संख्या
7	1	50
6	51	21
5	72	13
4	85	17
3	102	11
2	113	16
1	129	8

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- यूरोपकार, कार किराए पर देने वाली कंपनियों में से एक, ने कारफ्लेक्सी[233] के नाम से भारत में एक सहायक कार किराए पर लेने की कंपनी की स्थापना की है, लेकिन वर्तमान में, यह इस संकेतक के तहत सूचीबद्ध नहीं है। इसलिए, पर्यटन मंत्रालय भारत को अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकता है ताकि जब डब्ल्यूईएफ़एफ अगली रिपोर्ट के लिए डाटा ले, तो वे देश के मूल्य में यूरोपकर की गिनती करें।
- **बजट और सिक्सट वर्तमान में क्रमशः हमारे पड़ोसी देशों, श्रीलंका और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं।** इसलिए, इन कंपनियों को भारत में कारोबार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को इन कंपनियों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें भारत में काम करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

दीर्घकालिक योजना

- थ्रिप्टी की एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सीमित उपस्थिति है। इस प्रकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भारत में अपना परिचालन शुरू करने के लिए इस कंपनी को आकर्षित करना चाहिए जो भारत की श्रेणी में और सुधार लाएगा।

[233] https://www.carflexi.com/en-us/bgl83q7fgwq0yp1g/budget-car-rental-in-india

संकेतक 12.04: प्रति एटीएम वयस्क जनसंख्या

परिभाषा: यह संकेतक प्रति 100,000 वयस्क आबादी पर स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) की संख्या को संदर्भित करता है

स्रोत: द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स / आईएमऍफ़ फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे

देश का मूल्य = $\frac{\text{एटीएम की संख्या x 100000}}{\text{वयस्क जनसंख्या}}$

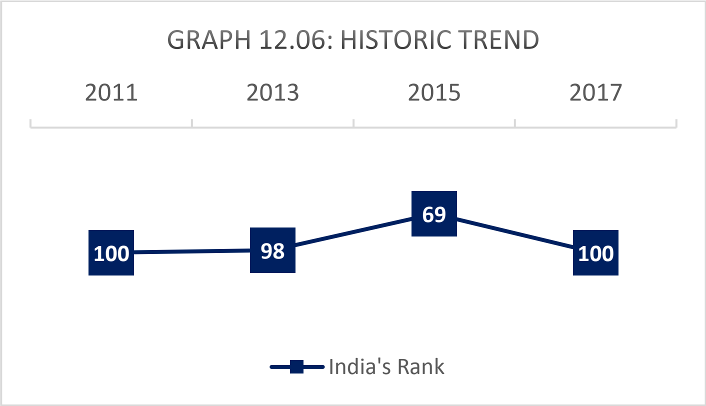

ग्राफ 12.06 संकेतक 12.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 31 पदों की कमी हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 2.08% का योगदान देता है।

तालिका 12.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
कोरिया, गणराज्य	36	777.892	1	290.660	एशियाई साथी
कनाडा	14	1163.762	2	222.274	शीर्ष प्रदर्शक
रूसी संघ	11	1372.97	3	184.697	शीर्ष प्रदर्शक
चीन	68	436.345	54	55.030	एशियाई साथी
भारत	**69**	**418.634**	**100**	**18.075**	

संकेतक का इतिहास: पहले "एटीएम प्रति 100000 वयस्क जनसंख्या " संकेतक के बजाय, "प्रति 1000000 जनसंख्या पर वीज़ा कार्ड स्वीकार करने वाले एटीएम" का उपयोग देशों की श्रेणी के लिए किया जाता था

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक

मध्यम अवधि की योजना

- **ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की स्थापना**

  भारत की 68.84% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में केवल 19% एटीएम ही हैं। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक एटीएम स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं ने एक बड़ा प्रभाव डाला क्योंकि 2011 में बैंक खातों में लोगों की संख्या 35% से बढ़कर 2017 में 80% हो गई। इस प्रकार, बढ़ती हुई खातों की संख्या ने बैंकिंग की

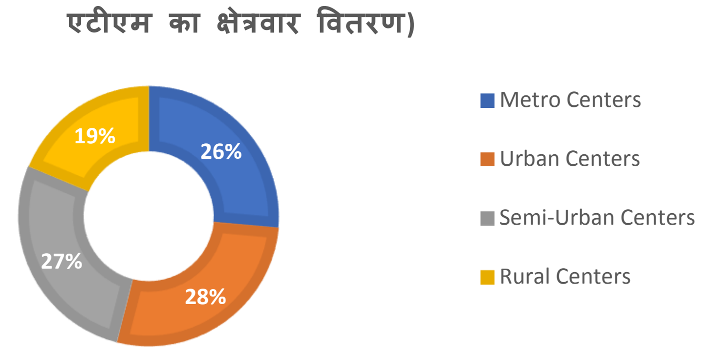

  अधिक मांग पैदा की। सेवाओं और इस मांग को बैंकों द्वारा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एटीएम की बढ़ती संख्या से पूरा करना होगा।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (जून 2018)

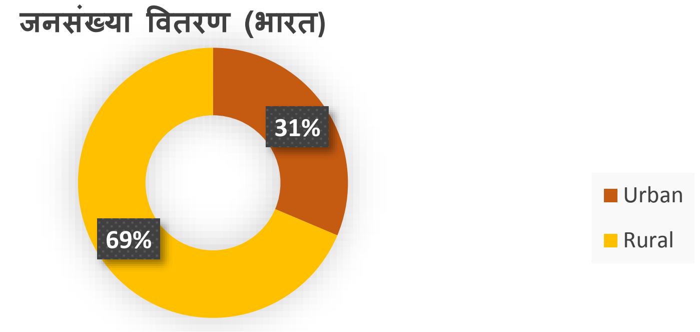

स्रोत: जनगणना भारत (2011)

दीर्घकालिक योजना

- **एटीएम को वर्चुअल टेलर मशीन (वीटीएम) से बदलना**

  चूंकि ग्रामीण आबादी ज्यादातर निरक्षर (लगभग 36%) हैं, इसलिए स्थापित किए गए एटीएम को वर्चुअल टेलर मशीन (वीटीएम) उपकरण में परिवर्तित किया जा सकता है, जो एटीएम कार्यक्षमता को बढ़ाकर (मूल्य वर्धित सेवाओं (वीएएस) के रूप में संदर्भित) करके चौतरफा वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।[234] इसलिए, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक वीटीएम स्थापित करने के लिए वित्त मंत्रालय भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ सहयोग कर सकता है, जिनकी निम्न मूल्य वर्धित सेवाएँ (वीएएस) हैं: -:-

तालिका 12.07: मूल्य वर्धित सेवाओं की सूची (वीएएस)

मूल्य वर्धित सेवाएँ (वीएएस) जिन्हें एटीएम में रोल आउट किया जा सकता है	
बैलेंस पूछताछ	लाइसेंस नवीनीकरण
मुद्रित रसीद	ई-वॉलेट टॉप अप
पिन सेवाएं	ई-वॉलेट टॉप अप
मिनी स्टेटमेंट	एंटरटेनमेंट इवेंट टिकट
बिल भुगतान	थर्ड पार्टी लॉयल्टी रिवार्ड्स
चैरिटी दान	लॉटरी टिकट
कार्डलेस निकासी	स्पोर्ट्स इवेंट टिकट
मोबाइल टॉप-अप	खाता स्थानांतरण (कार्डधारक के स्वामित्व वाले खाते)
व्यक्ति से व्यक्ति को घरेलू प्रेषण (आरंभिक)	यात्रा टिकट (शहरी उदा. बस)

[234] World Bank 2017 Dataset (as 2017 is the latest dataset)

व्यक्ति से व्यक्ति को घरेलू प्रेषण (एकत्र)	यात्रा टिकट (अतिरिक्त-शहरी उदा. ट्रेन)
कूपनिंग	यात्रा टिकट (अतिरिक्त-शहरी फ्लाइट)
पासबुक प्रिंटिंग	रोड टोल भुगतान / पूर्व भुगतान
करों का भुगतान / जुर्माना	व्यक्ति से व्यक्ति को सीमा पार प्रेषण (एकत्र)
व्यक्ति से व्यक्ति को सीमा पार प्रेषण (आरंभिक)	

<u>उप-सूचकांक डी</u>

<u>प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन</u>

प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन उप-सूचकांक, जो प्रमुख "यात्रा करने के लिए कारण" को कैप्चर करता है। व्यापार और व्यक्तिगत कारणों के अलावा, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत यकीनन एक देश की यात्रा करने के मुख्य कारण का गठन करते हैं। कुछ देशों में दूसरों की तुलना में कुछ समृद्ध विन्यासहै, लेकिन कुछ अन्य लोगों की तुलना में उन्हें बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में भी बेहतर हैं, एक ऐसा कारक जो विशिष्ट नीतिगत फोकस के लिए ऊंचा होना चाहता है।

इस उप-सूचकांक में 2 स्तंभ शामिल हैं:

1. प्राकृतिक संसाधन (5 संकेतक)

2. सांस्कृतिक संसाधन और व्यापार यात्रा (5 संकेतक)

<u>स्तंभ 13: प्राकृतिक संसाधन</u>

परिभाषा: यह स्तंभ उपलब्ध प्राकृतिक पूंजी के साथ-साथ बाहरी पर्यटन गतिविधियों के विकास को मापता है। प्राकृतिक राजधानी परिदृश्य, प्राकृतिक पार्कों और जीवों के अनुसंधान स्थल के रूप में परिभाषित की गई है। स्तंभ 13 के नीचे कुल 5 संकेतक हैं -

1. विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थलों की संख्या
2. कुल प्रजातियों
3. कुल संरक्षित क्षेत्र
4. प्राकृतिक पर्यटन डिजिटल मांग
5. प्राकृतिक संपत्ति का आकर्षण

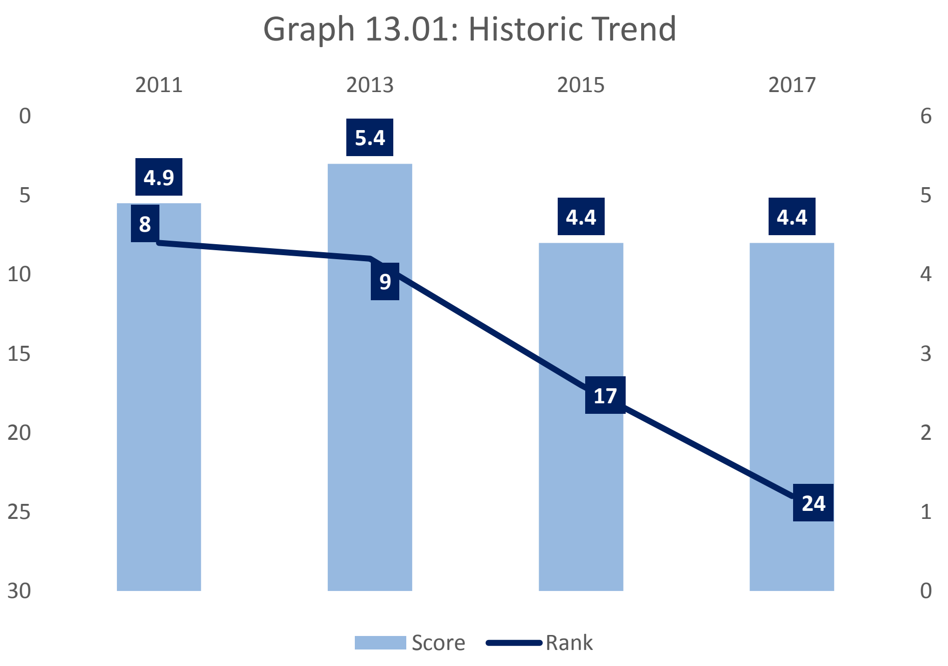

ग्राफ 13.01 भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है और स्तंभ में मूल्य 13. भारत की श्रेणी 2011 में 8 वें स्थान से घटकर 2017 में 24 वें स्थान पर आ गई है।

भार की स्थिति में बदलाव:

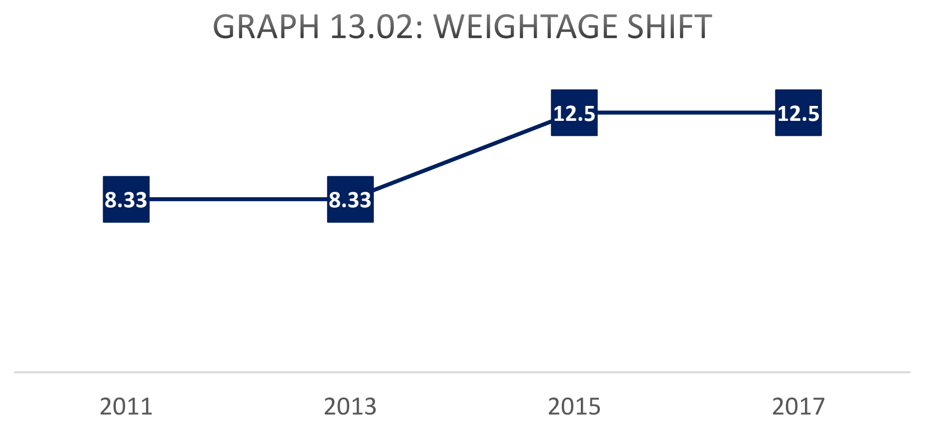

ग्राफ 13.02 भारत के स्कोर में स्तंभ 13 यानी प्राकृतिक संसाधनों के समग्र योगदान को इंगित करता है। वर्तमान में, इस स्तंभ को 12.5% भार दिया जाता है। इस स्तंभ का भार वर्ष 2015 में 50% तक बढ़ गया है।

तालिका 13.01: भार की स्थिति में संकेतक वार बदलाव

संकेतक	2011 (%)	2013 (%)	2015 (%)	2017 (%)	भार की स्थिति में बदलाव (%)
विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थलों की संख्या	2.08	2.08	2.5	2.5	20.19
कुल ज्ञात प्रजातियां प्रजातियों की संख्या	2.08	2.08	2.5	2.5	20.19
कुल संरक्षित क्षेत्र	NA	NA	2.5	2.5	NA
प्राकृतिक पर्यटन डिजिटल मांग	NA	NA	2.5	2.5	NA
प्राकृतिक संपत्तियों का आकर्षण	NA	NA	NA	2.5	NA

NA = लागू नहीं, उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

*** 2017 में प्राकृतिक संपत्ति के आकर्षण की शुरुआत की गई थी जबकि प्राकृतिक पर्यटन डिजिटल मांग और कुल संरक्षित क्षेत्रों को 2015 में पेश किया गया था**

तालिका 13.01 उस योगदान का प्रतिशत दर्शाती हैजो कि प्रत्येक संकेतक का भारत के समग्र स्कोर पर है।

संकेतक 13.01: विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थलों की संख्या

परिभाषा: यह संकेतक देश में विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थलों की संख्या को संदर्भित करता है। विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल वे गुण हैं जिन्हें विश्व धरोहर समिति उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य मानती है।

स्रोत: यूनेस्को, विश्व विरासत सूची (डब्ल्यूएचएल

देश का मूल्य = 1 * एक देश में प्राकृतिक साइटों की संख्या + 0.5 * एक देश में मिश्रित साइटों की संख्या

जहां मिश्रित साइटें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं

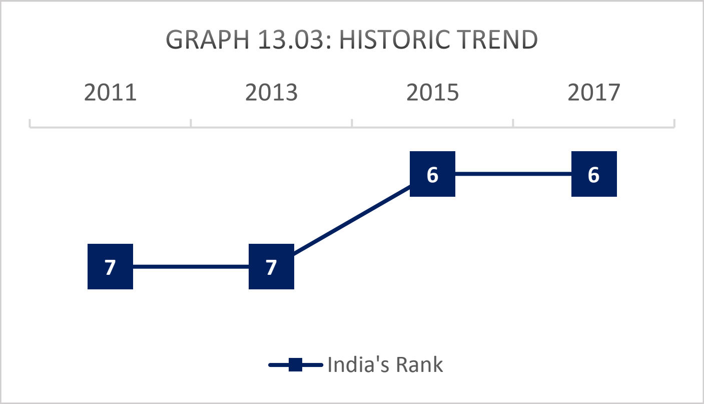

ग्राफ 13.03 सूचक 13.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2017 में, भारत की श्रेणी वर्ष 2015 की तुलना में लगातार बनी रही। इस सूचक का देश के स्कोर में 2.5% का योगदान है।

तालिका 13.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य(2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य(2017)	कारण
रूसी संघ	4	10	4	10	मुख्य प्रतियोगी
कनाडा	5	9	4	10	मुख्य प्रतियोगी

भारत	6	7	6	7.5	
ब्राजील	6	7	7	7	मुख्य प्रतियोगी
मेक्सिको	8	5.5	8	6.5	मुख्य प्रतियोगी

विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया [235]

- **चरण 1: संभावित सूची**
  - सभी देशों को अपनी सीमाओं के भीतर स्थित अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक विरासत स्थलों की एक 'सूची' बनाने की उम्मीद है। इस 'इन्वेंट्री' कोसंभावित सूची के रूप में जाना जाता है, और उन संपत्तियों का पूर्वानुमान प्रदान करता है, जो राज्य पार्टी अगले पांच से दस वर्षों में शिलालेख के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय ले सकती है और जिसे किसी भी समय अद्यतित किया जा सकता है।
- **चरण 2: नामांकन फ़ाइल**
  - राज्य पार्टी एक फाइल को नामांकित करती है जो पहले से ही विश्व विरासत केंद्र से सहायता के साथ अपनी संभावित साइटों की सूची में शामिल है क्योंकि विश्व विरासत समिति विश्व विरासत सूची में शिलालेख के लिए नामांकन पर विचार नहीं कर सकती है जब तक कि संपत्ति पहले से ही राज्य पार्टी की संभावित सूची में शामिल नहीं की गई है।
- **चरण 3: सलाहकार निकाय**
  - विश्व धरोहर कन्वेंशन द्वारा अनिवार्य दो सलाहकार निकायों द्वारा एक नामित संपत्ति का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जो नामित स्थलों के मूल्यांकन के साथ विश्व विरासत समिति प्रदान करता है। एक तीसरा सलाहकार निकाय प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के साथ-साथ प्रशिक्षण गतिविधियों पर विशेषज्ञ सलाह के साथ समिति प्रदान करता है।
- **चरण 4: विश्व धरोहर समिति**
  - हर साल में एक बार, विश्व धरोहर समिति यह तय करती है कि किन नामांकित स्थलों को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जाएगा।

- **चयन के लिए मानदंड**

विश्व धरोहर प्राकृतिक सूची में शामिल होने के लिए, साइटों को बकाया सार्वभौमिक मूल्य का होना चाहिए और उल्लेखित चयन मानदंडों में से कम से कम चार में से एक को पूरा करना होगा:

1. प्राकृतिक घटनाएं या सौंदर्य: इसमें अतिशय प्राकृतिक घटनाएं या असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और सौंदर्य महत्व के क्षेत्र शामिल हैं।

[235] UNESCO: World Heritage Centre

2. पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरण: ये पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिनमें जीवन का रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण है- भू-आकृतियों या महत्वपूर्ण भू-आकृति या भौतिक विशेषताओं के विकास में कार्यरत भू-वैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल हैं।

3. महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाएँ: ये उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो स्थलीय, ताजे पानी, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और पौधों और जानवरों के समुदायों के विकास और विकास में जीओआई एनजी पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं।

4. जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्राकृतिक निवास: इसमें जैविक विविधता के इन-सिटू संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण प्राकृतिक निवास स्थान शामिल हैं, जिनमें विज्ञान और संरक्षण के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय

तालिका 13.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	डब्ल्यूएचएल में Wजोड़ी गईं साइटें (2017-18 में)		डब्ल्यूएचएल में साइटें		संभावित सूची में साइटें	नए मूल्य (2019)
			प्राकृतिक साइटें	मिश्रित साइटें	प्राकृतिक साइटें	मिश्रित साइटें		
रूसी संघ	4	10	0	0	9	0	10	10
कनाडा	4	10	0	1	10	1	6	10.5
भारत	**6**	**7.5**	**0**	**0**	**7**	**1**	**9**	**7.5**
ब्राजील	7	7	0	0	7	0	12	7
मेक्सिको	8	6.5	0	1	6	2	10	7

वर्तमान रुझान

- भारत के लिए प्रमुख प्रतियोगिता ब्राजील और मैक्सिको है जो कि भारत से नीचे हैं और उसमें संभावित सूची में कई साइटें हैं।
    - रूस (श्रेणी 4th): 10
    - कनाडा (श्रेणी 4th): 10
    - भारत (श्रेणी 6th): 7.5
    - ब्राज़ील (श्रेणी 7th): 7
    - मेक्सिको (श्रेणी 8th): 6.5
- **रूस और कनाडा 2.5 अंकों से भारत से आगे हैं:** दोनों देशों का कुल स्कोर 10 है और दोनों नेकीअपनी संभावित सूची में क्रमशः 10 और 6 साइटें हैं।
- **भारत का अल्पकालिक ध्यान इस पैरामीटर के लिए अपनी श्रेणी बनाए रखने पर होना चाहिए - -**
    - **रूस:** 10 साइटें
    - **कनाडा**: 6 साइटें
    - **भारत:** 9 साइटें
    - **ब्राजील:** 12 साइटें
    - **मैक्सिको:** 10 साइटें

दीर्घकालिक योजना

- चूंकि ब्राज़ील की संभावित सूची में 12 साइटें हैं और मेक्सिको की सूची में 10 साइटें हैं, जो कि भारत की दस संभावित साइटों से अधिक है, समय के साथ यह निश्चित है कि भारत को अपनी श्रेणी बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा।
- भारत की दस संभावित सूची में मिश्रित साइटों की तुलना में अधिक प्राकृतिक साइटें हैं, और प्राकृतिक साइटें मिश्रित साइटों की तुलना में अधिक अंक लेती हैं। इसलिए, संस्कृति मंत्रालय का दीर्घकालिक ध्यान दस संभावित सूची के लिए एक प्राकृतिक साइट को सूचीबद्ध करने के साथ-साथ प्रस्तुत किए जाने वाले लेखन की गुणवत्ता में सुधार पर होना चाहिए और साथ ही नामांकन के लिए भेजने से पहले दस्तावेजों का गहन सत्यापन करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी अधिक प्राकृतिक स्थलों को नामांकित किया जा सकता है जिन्हें तब विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जा सकता है।

संकेतक 13.02: कुल ज्ञात प्रजातियां

परिभाषा: यह सूचक देश में स्तनधारियों, पक्षियों और उभयचरों की कुल ज्ञात प्रजातियों को संदर्भित करता है।

स्रोत: इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज (आईयू सी एन) रेड लिस्ट

देश का मूल्य = स्तनधारियों की कुल ज्ञात प्रजातियाँ + उभयचरों की कुल ज्ञात प्रजातियाँ + पक्षियों की कुल ज्ञात प्रजातियाँ

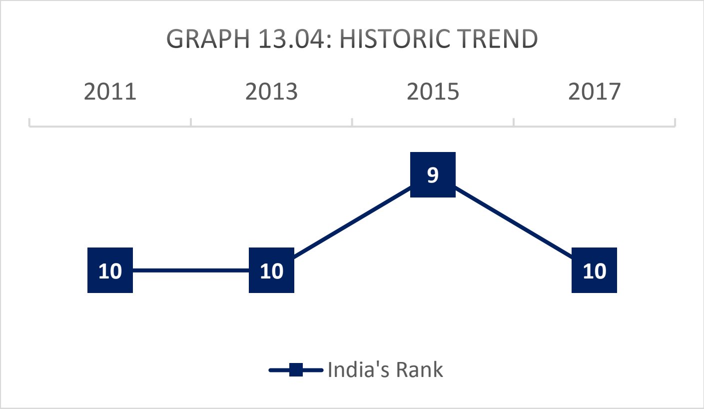

ग्राफ 13.04 सूचक 13.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी में 1 स्थान की कमी आई। यह सूचक देश के स्कोर में 2.5% का योगदान देता है।

तालिका 13.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारणs
ब्राजील	1	3237	1	3287	शीर्ष प्रदर्शक
कोलंबिया	2	2993	2	3037	शीर्ष प्रदर्शक
मेक्सिको	8	1977	9	1988	मुख्य प्रतियोगी
भारत	**9**	**1859**	**10**	**1889**	
कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य	N/A	N/A	11	1758	मुख्य प्रतियोगी

आईयूसीएन लाल सूची: यह जैविक संरक्षण की वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक प्रजातियों की एक सूची है। यह हजारों प्रजातियों और उप-प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए मापदंड का एक सेट का उपयोग करता है।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया की साइट और आईयूसीएन रेड लिस्ट में भारत में पक्षियों और स्तनधारियों की ज्ञात प्रजातियों की सूची की तुलना करने पर, यह पाया गया कि पक्षियों की 99 प्रजातियाँ और 82 प्रजातियाँ हैं जो स्तनधारियों की लाल सूची में शामिल नहीं हैं। इन प्रजातियों को नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

भारत में मौजूद पक्षी की प्रजातियां हैं, लेकिन आईयूसीएन लाल सूची में शामिल नहीं हैं		
अंडमान फ्लावरपेकर	डेजर्ट व्हाइट्ट्रोट	ओरिएंटल प्लोवर
आर्कटिक टर्न	ईस्टर्न ऑर्फियन वार्बलर	ऑर्टोलन बंटिंग
आर्कटिक वार्बलर	यूरेशियन क्रैग-मार्टिन	पेक्टोरल सैंडपाइपर
एशियाई डेजर्ट वार्बलर	यूरेशियन जैकडॉ	पिंक-रंप्ड रोज़फिंच
एज़्योर टाइट	यूरेशियन जे	रेड क्रॉसबिल
बाइकाल टील	यूरेशियन स्कोप्स-आउल	रेड काइट
बार्ड वार्बलर	यूरेशियन सिस्किन	रेड-बिल्ड ट्रोपिकबर्ड
ब्लैक नोड्डी	यूरोपीय गोल्डफिंच	रेड-ब्रेस्टेड गूज़
ब्लैक-बेलीड स्टॉर्म-पेट्रेल	यूरोपीय टर्टल-डव	रेड-ब्रेस्टेड मर्गेन्सर
ब्लैक हेडेड बंटिंग	गोल्डक्रेस्ट	रेड-थ्रोटेड थ्रश
ब्लैक हेडेड ग्रीनफिंच	ग्रेट स्निप	रॉक स्पैरो
ब्लैक हेडेड माउंटेन-फिंच	ग्रेटर रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो	रूक
ब्लैक लेग्ड कित्तीवके	ग्रेटर शॉर्ट-टूड लार्क	रूफस-टेल्ड रॉक-थ्रश
ब्लैक-थ्रोटेड थ्रश	हाउफिंच	शार्प-टेल्ड सैंडपाइपर
ब्लू-एंड-व्हाइट फ्लाईकैचर	हिल प्रिनिया	साइबेरियन स्टोनचैट
ब्ल्यू ब्रेस्टेड क्वेल	पहाड़ी निगल	सिल्वर-ब्रेस्टेड ब्रॉडबिल
ब्लू-विंग्ड लीफबर्ड	हुडेड क्रो	गायन बुशर्क
बोहेमियन वैक्सविंग	हॉर्न्ड ग्रीबे	सॉन्ग थ्रश
बोरल आउल	इंडियन ग्रासबर्ड	सूटी गल

ब्राउन स्कुआ	इंडियन यलो टिट	साउथ पोलर स्कुआ
बफ-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर	कश्मीर नटक्रैकर	स्पॉटेड फ्लाईकैचर
केप पेटरल	लेसर नॉडी	स्ट्रीक्ड शीयरवाटर
कैरियन क्रो	लेसर रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो	स्ट्रिएटेड स्वैलो
कैस्पियन प्लोवर	लेसर व्हाइट-फ्रंटेड गूस	टॉनी आउल
चेस्टनट-चीक्ड स्टारलिंग	लिटिल गल	ट्वीट
चाइनीज व्हाइट-ब्राउन रोसफिंच	लॉन्ग बिल्ड्डॉवचर	विविद नीलतावा
सिनेरौस टिट	लॉन्ग टेल्ड जैगर	व्हाइट-बेलीड ब्लू फ्लाईकैचर
क्लिकिंग श्राईक-बबलर	मैंडरिन बतख	वाइट-ब्राउन शार्टविंग
कॉमन चैफिंच	मेव गल	वाइट-आईड गल
कॉमन रेवेन	मयू थ्रश	व्हाइट-फेस स्टॉर्म-पेट्रेल
कॉमन रेडस्टार्ट	निकोबार इंपीरियल-पिजन	वायर टेल्ड स्वैलो
कॉर्न क्रेक	नीलगिरि थ्रश	वुडचैट श्राइक
क्रेस्टेड टिट-वंडरर	नॉर्दर्न व्हिटरर	येलो-रम्पड फ्लाईकैचर

भारत में मौजूद स्तनपायी प्रजातियां जिन्हें आईयूसीएनएन लाल सूची में शामिल नहीं किया हैं		
कैनिस लुपस चंको	सिनोप्टेरस स्फिंक्स	गजेला बेनेट्टी
लैटिडेंस सलाईमलि	मेगारोप्स निपहाण	निओफेलिस नेबुलोसी
सेमनोपीथेकस शिस्टेसियस	पटेरोपुस फाउनुलूस	फेलिस सिल्वेस्ट्रिस
सेमनोपीथेकस एंचीज़े	पेरोपोपस वैम्पाइरस	वुलस वुल्स पुसिल्ला
सेमनोपीथेकस थेरसाइटें	एनीकटेरिस स्पैलेआ	प्रायोनैलुरस विवरिनस
सेमनोपीथेकस एसीटेस	बांदीकोटा बेंगालेंसिस	कैटोपुमा टेंमिनमिनकी
क्यून अल्पाइनस अल्पाइनस	रैटस नोरवेगिकस	कैप्रा सिबिरिका
क्यून अल्पिनस लैनिगर	निविविटर निवाइवेंटर	आर्कटॉनिक्स कॉलरिस
पैराडॉक्सुरस जर्दोनी	गोलुंडा इलियोटी	पैंथेरा लियो फारिका
पगुमा लरवता	गेरिल्लस ग्लेडॉवी	इक्वास ओनगर
पेटौरिस्ता फिलिपेंसिस	वांडेलुरिया ओलेरासिया	कैनिस ल्यूपस पल्लिप्स

यूपेटोरस सिनेरियस	बांदीकोटा बेंगालेंसिस	सरवाइज एलाफस हैंग्लू
हाइलोपेटेस बबरी	रैटस रेवेगिकस नहीं	लोरिस लिडडेकेरियनस
हाइलोपेटेस फिम्ब्रिएटस	मेरिओनेस हर्रीनाई	हेलारैक्टोस चेरानुस
मुस्टेला पुटोरियस	गोलुंडा इलियोटी	मोशियोला मेमिना
वुल्फ्स वल्पीज़ ग्रिफ़िथी	सूस स्क्रॉफ़ एंडमैनेंसिस	मॉस्कस बेरज़ोवस्की
मुस्टेला सिबिरिका	स्यूडोस न्यौर	ओविस अमोन होदगोंसी
हर्पीस्टेस स्मिथि	बलाइनोप्टेरा एडेनि	सुशी साल्वनीस
हर्पेस्टेस जावानिकस	कोगिया सिमस	नेमोरहेडस सुमात्राएंसिस
हर्पीस्टेस विटिटोलिस	स्यूडॉर्का क्रैसिडेंस	एंबलॉनिक्स सिनेरियस
मुन्टिएकास मुंतजिक	बालाएनोप्रोटे फिजलस	मेलुरस ओर्सीनुस
एक्सिस एक्सिस	प्लैटनिस्टा गैंगेटिका	अनसिया एंशियल
नेमोरहेडस गोरल	बलायनोप्टेरा एक्यूटोरोस्ट्रेटा	प्रियनोडन पर्डिकोलर
नेमोरहेदस बेली	बालाएनोप्रट बोरेलिस	रकुर्वस डुवाकुली
एक्सिस पोर्सिनस	ग्लोबिसफला मैक्रोहाइन्चस	वुलप्स फेरिलैटस
लेपस नाइग्रिकॉलिस	फिजिटर कैटोडन	प्रोस्प्रा चित्रिकाउदता
कैनिस लुपस चैंको	बोस ग्रुन्निन्स	ओविस विग्नेई

- **इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित करने के लिए इन प्रजातियों को प्राप्त करने के लिए, उनकी लाल सूची में सूचीबद्ध करने के लिए आईयूसीएन परिषद के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह सूचीबद्ध प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करेगा और भारत को श्रेणी में टैली में एक बेहतर स्थिति सुरक्षित करने में मदद करेगा।**

दीर्घकालिक योजना

- आईयूसीएन लाल सूची में शामिल पक्षियों में 21 प्रजातियां लुप्तप्राय श्रेणी में और 16 भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में हैं। **इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दीर्घकालिक की योजना इन प्रजातियों की श्रेणी का संरक्षण होना चाहिए, लुप्त होने पर प्रजातियों की श्रेणी में कमी आएगी।**

- यह उस क्षेत्र के स्थानीय समुदाय को शामिल करके किया जा सकता है जैसा कि ओडिशा के जिले में किया जाता है जिसके कारण इस क्षेत्र में प्रवासी पक्षी प्रजातियों की आमद में वृद्धि हुई है और प्रभावी रूप से इकोटूरिज्म को बढ़ावा मिला है। ओडिशा को प्रवासी पक्षियों की आमद बढ़ाने में

<u>इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं</u>

<u>चिलिका झील: ईकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के प्रयास</u>

चिलिका झील भारत और एशिया में सबसे बड़ी तटीय लैगून है और ओडिशा में स्थित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। यह प्रवासी जलपक्षी का सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है, जो भारतीय उप-महाद्वीप पर कहीं भी पाया जाता है और देश में जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र में से एक है।

मंगलाजोडी इकोटूरिज्म ट्रस्ट सामुदायिक स्वामित्व और प्रबंधित उद्यम है। मंगलाजोडी के ग्रामीण कभी चिलिका झील के पास पक्षियों के अवैध शिकार से जुड़े हुए थे, लेकिन अब वे इस क्षेत्र में वन्यजीवों के सच्चे रक्षक के रूप में खड़े हैं। परिवर्तन मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रजातियों के संरक्षण और वन्यजीव पर्यटन से जुड़े लाभों के महत्व पर जागरूकता अभियान को लागू करने में समन्वित प्रयास के कारण हुआ था।

इस क्षेत्र में 2000 से अब तक पक्षियों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा, इस परिवर्तन के अन्य दिखाई देने वाले प्रभावों के कारण इकोटूरिज्म के माध्यम से राजस्व में वृद्धि हुई है, अवैध शिकार में कमी आई है और ग्रामीणों का समर्थन बढ़ रहा है।

ओडिशा में मंगलाजोडी इकोटूरिज्म ट्रस्ट ने सामुदायिक स्वामित्व और इको पर्यटन के सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य और

मदद करने वाली प्रैक्टिस को नीचे दी गई तालिका से पहचाना जा सकता है।

- देश में ऐसे समुदायों के अन्य उदाहरणों में अरुणाचल प्रदेश में सिंगचुन बागुन सामुदायिक ग्राम रिजर्व और राजस्थान में बिश्नोई समाज हैं ।
- **लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी वाले क्षेत्रों में संरक्षण जागरूकता कार्यक्रमों को शुरू किया जाना चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,** विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और पश्चिमी घाटों में।
- पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य के अधिकारियों और गैर सरकारी संगठन की मदद से बदलते हैं, जो वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक जैव विविधता हॉटस्पॉट के आसपास रहने वाले समुदायों को बनाकर उन क्षेत्रों में मौजूद वन्यजीव आबादी की सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए लोगों

के सामाजिक और पारिस्थितिक कमियों को संबोधित करने के लिए, संरक्षण कार्यक्रमों में प्रोत्साहन को शामिल किया जाना चाहिए।

संकेतक 13.03: कुल संरक्षित क्षेत्र

परिभाषा: यह संकेतक देश के कुल प्रादेशिक क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में संरक्षण के तहत स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों के कुल हेक्टेयर को संदर्भित करता है। एक स्थलीय क्षेत्र में कुल भूमि क्षेत्र और अंतर्देशीय जल शामिल हैं। संरक्षित क्षेत्र (समुद्री, स्थलीय या मीठे पानी), जैसा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) द्वारा परिभाषित किया गया है, को स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक स्थान, पहचाना गया, समर्पित और प्रबंधित, कानूनी या अन्य प्रभावी साधनों के माध्यम से दीर्घकालिक संरक्षण प्राप्त करना है। संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और सांस्कृतिक मूल्य के साथ प्रकृति। केवल संरक्षित क्षेत्र जो राष्ट्रीय रूप से नामित हैं, वे इस सूचक में शामिल किये गए हैं।

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र का सांख्यिकी विभाग

$$\textbf{देश का मूल्य} = \frac{\text{संरक्षण के तहत स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों का कुल हेक्टेयर}}{\text{देश का कुल क्षेत्रीय क्षेत्र}}$$

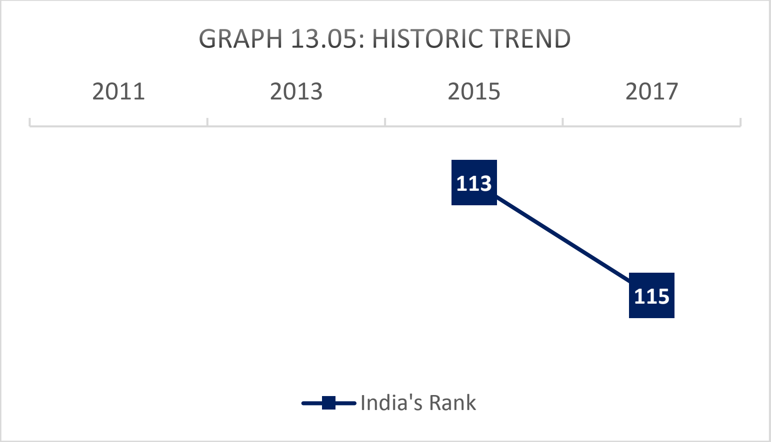

ग्राफ 13.05 संकेतक 13.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 2 पदों की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 2.5% का योगदान देता है।

तालिका 13.05: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
वेनेजुएला	2	49.54	1	53.86	शीर्ष प्रदर्शक
स्लोवेनिया	1	54.86	2	53.59	शीर्ष प्रदर्शक
भूटान	18	28.35	3	47.3	एशियाई साथी

ट्यूनीशिया	116	4.82	114	5.44	मुख्य प्रतियोगी
भारत	**113**	**5**	**115**	**5.35**	
मेडागास्कर	118	4.72	116	4.97	मुख्य प्रतियोगी

सरकारी पहल

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) पेरिस में 2015 में पार्टियों (सीओपी) के सम्मेलन में, भारत सरकार ने 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर नीच भूमि को पुनर्स्थापना में लाने के लिए एक बॉन चैलेंज प्रतिज्ञा की और 2030 तक एक अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया।भारत ने पहले ही 9.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्स्थापना के तहत ला दिया है, जिसका अर्थ है कि इन परिदृश्यों को बहाल करने का काम पहले से ही चल रहा है, और यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो यह चुनौती भारत को लंबे समय में 115 वें स्थान से अपनी श्रेणी में सुधार करने में मदद करेगी।[236].

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- संयुक्त राष्ट्र का सांख्यिकी विभाग प्रत्येक देश के कुल संरक्षित क्षेत्र के लिए डाटा का संकलन करता है, जो कि आईयूसीएन डाटा बेस से है। भारत के लिए आईयूसीएनएन डाटा बेस में 672 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में 771 संरक्षित क्षेत्र (104 राष्ट्रीय उद्यान, 544 वन्यजीव अभयारण्य, 77 संरक्षण रिजर्व और 46 सामुदायिक रिजर्व) का एक नेटवर्क है। इसलिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आईयूआईएसएन को लिखना चाहिए और उन्हें उपलब्ध संरक्षित क्षेत्रों की अपनी सूची को अद्यतित करने के लिए कह सकता है।[237].

दीर्घकालिक योजना

- पिछले दस वर्षों से, फिलीपीन पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन विभाग (डीईएनआर) ने जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मिलकर काम किया, जो वर्ष 2017 में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। इसने देश में 110 संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन का समर्थन किया। पीएएमई

[236] https://www.iucn.org/news/india/201808/india-first-all-bonn-challenge-countries-develop-progress-report

[237] https://protectedplanet.net/country/IN

प्रोजेक्ट, सभी स्तरों पर डीईएनआर कर्मचारियों के प्रबंधन कौशल और तकनीकी विशेषज्ञता को बेहतर बनाने के लिए निर्धारित किया गया है।

- इसमें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदारियों का पुनर्गठन शामिल है। इसके अलावा, यह सुधार और नए प्रबंधन मॉडल के प्रस्तावों को विकसित करने के लिए मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में प्रबंधन प्रभावशीलता में अध्ययन का समर्थन करता है। इस संदर्भ में, डीईएनआर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।
- स्थानीय प्रबंधन द्वारा प्रशासित होने के लिए नवीन प्रबंधन प्रणालियों के साथ नए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का समर्थन करने पर भी विशेष जोर दिया जाता है। यह परियोजना डीईएनआर (पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन विभाग) द्वारा संवर्धित ज्ञान प्रबंधन की शुरुआत को बढ़ावा देती है और जैव विविधता के मूल्य के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाती है। इसी प्रकार, विभिन्न राज्य वन विभागों की मदद से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करके स्थानीय समुदायों और क्षेत्र के कर्मचारियों को सशक्त बना सकते हैं क्योंकि यह जागरूकता बढ़ाने के लिए जीएसटी लोगों को बढ़ाता है जो संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापनामें मदद करेगा।

संकेतक 13.04: प्राकृतिक पर्यटन डिजिटल मांग

परिभाषा: यह सूचक ऑनलाइन खोज सूचकांक की संख्या को संदर्भित करता है। यह निम्न प्रकृति से संबंधित ब्रांड टैग से संबंधित कुल ऑनलाइन खोज मात्रा को मापता है: समुद्र तट, साहसिक और चरम, गोताखोरी, मछली पकड़ने, लंबी पैदल यात्रा, सर्फिंग, जल खेल, शीतकालीन खेल, पशु देखना, संरक्षित क्षेत्र और सतत और ग्रामीण पर्यटन।

स्रोत: ब्लूम परामर्श देशीय ब्रांड श्रेणी पर आधारित है, पर्यटन संस्करण

देश का मूल्य: 9 भाषाओं में उपरोक्त सांस्कृतिक ब्रांड टैग से संबंधित शब्दों के विश्लेषण के आधार पर 0-100 के पैमाने पर मापा जाता है

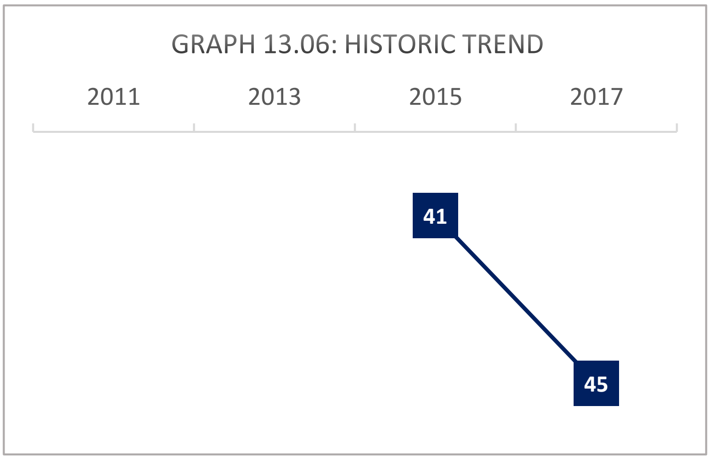

ग्राफ 13.06 संकेतक 13.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 4 पदों की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 2.5% का योगदान देता है।

तालिका 13.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
थाईलैंड	3	93.76	1	97.24	शीर्ष प्रदर्शक
कोस्टा रिका	6	88.41	2	93.17	शीर्ष प्रदर्शक
ऑस्ट्रिया	1	100	3	88.23	शीर्ष प्रदर्शक
अर्जेंटीना	39	30.76	44	23.16	मुख्य प्रतियोगी
भारत	**41**	**26.93**	**45**	**22.51**	

डी2 © टूल क्या है?

- डी2 © एक बिग डाटा कंपनी है जो देशों, क्षेत्रों और शहरों के बारे में विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। उनका मालिकाना सॉफ्टवेयर विभिन्न स्थानों के प्रति वैश्विक स्तर पर की गई सभी खोजों को इकट्ठा करता है और उसकी अपील को प्रकट करता है। हर साल, डिजिटल देश और डिजिटल सिटी इंडेक्स को मापा जाता है जो ब्याज और देशों के प्रदर्शन और पर्यटन, निवेश, निर्यात, प्रतिभा और राष्ट्रीय प्रमुखता के क्षेत्रों पर आधारित होते हैं।

- यह गणना मालिकाना डी 2 टूल पर आधारित है, जो प्रासंगिक ब्रांड टैग में ऑनलाइन पर्यटन-संबंधी खोज डाटा का विश्लेषण करके प्रत्येक देश के आकर्षण का आकलन करता है, जिसमें प्रत्येक गंतव्य-विशिष्ट कीवर्ड हैं जो पर्यटन गतिविधियों और आकर्षण से संबंधित हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **ब्रांड टैग का विज्ञापन और विपणन**
  - भारत के लिए ऑनलाइन खोज की मात्रा बढ़ाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक विज्ञापन रणनीति जिसमें प्रचार के डिजिटल, सामाजिक और पारंपरिक तरीकों का मिश्रण होता है; क्षेत्रों के भूगोल के आधार पर अपनाया जाना चाहिए।
  - पर्यटन से संबंधित ब्रांड टैग के प्रभावी विज्ञापन के लिए, खोज इंजन अनुकूलन (एसईओ) को लागू किया जाना चाहिए। फोकस को पारंपरिक विज्ञापन से सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर आदि पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
  - पर्यटन मंत्रालय के केवल 14 विदेशी कार्यालय हैं। इसलिए, सभी देशों में भारत के दूतावासों का उपयोग अपने संबंधित देशों में भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।
  - अतुल्य भारत सहित ऑनलाइन अभियानों की सामग्री अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह गैर-अंग्रेजी भाषी राज्यों और देशों से अधिक ऑनलाइन खोजों को आकर्षित करने में मदद करेगा।
  - अन्य देशों की मदद से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एक देश उन्मुख विपणन योजना तैयार की जानी चाहिए और हर 6 महीने में रूस (रूस, कज़ाख़िस्तान और यूक्रेन को कवर करते हुए), ब्राजील, दक्षिण कोरिया, स्पेन जैसे देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। (स्पेन और पुर्तगाल को कवर करते है), थाईलैंड (थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार को कवर करते है), अर्जेंटीना (पेरू, चिली, अन्य पड़ोसी स्पेनिश बोलने वाले देशों को कवर करते है) क्योंकि ये देश पर्यटकों के लिए नए स्रोत बाजार हैं।
  - **पर्यटन मंत्रालय ब्रांड टैग के विज्ञापन और विपणन के लिए एक जनसंपर्क रणनीति टीम या एक समर्पित विशेष सेल को भी नियुक्त कर सकता है।**

मध्यम अवधि की योजना

- **डी2 © उपकरण की सदस्यता**
    - पर्यटन विश्लेषण के लिए **डी**2-टूल को स्वीडन, पुर्तगाल, जर्मनी, वियतनाम, कोस्टा रिका, यूरोपीय पर्यटन आयोग आदि के पर्यटन संगठनों द्वारा सदस्यता ली गई है।
    - **पर्यटन मंत्रालय विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टि तक पहुँच प्राप्त करने के लिए इस टूल की सदस्यता भी ले सकता है और विभिन्न लक्षित बाजारों का अवलोकन भी कर सकता है।**

संकेतक 13.05: प्राकृतिक संपत्ति का आकर्षण

परिभाषा: "अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आपके देश में मुख्य रूप से अपनी प्राकृतिक संपत्ति (यानी पार्क, समुद्र तट, पहाड़, वन्यजीव, आदि) के लिए किस हद तक यात्रा करते हैं?"

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्यकारी राय सर्वेक्षण

मूल्य: 1 से 7 के पैमाने पर (1 = बिल्कुल नहीं; 7 = काफी हद तक)

तालिका 13.07: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारणs
न्यूजीलैंड	1	6.77	शीर्ष प्रदर्शक
कोस्टा रिका	2	6.63	शीर्ष प्रदर्शक
नॉर्वे	3	6.54	शीर्ष प्रदर्शक
निकारागुआ	112	3.97	मुख्य प्रतियोगी
भारत	**113**	**3.96**	
बोस्निया और हर्जेगोविना	114	3.95	मुख्य प्रतियोगी

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

अल्पकालीन योजना

- **प्रतिक्रिया तंत्र**
    - पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन मंत्रालय प्राकृतिक स्थलों की खोज के लिए देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या या उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था, के लिए डाटा प्रदान करने में सक्षम नहीं है, इसलिए, उपरोक्त डाटा को कैप्चर करने के लिए, **पर्यटन मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ गठबंधन विदेशी पर्यटकों के लिए वीज़ा नीतियों से जुड़ा एक प्रतिक्रिया तंत्र विकसित कर सकता है जो हमारे देश का दौरा कर रहे हैं क्योंकि यह उनकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में एक डाटा बेस को बनाए रखने में मदद करेगा।**

दीर्घकालिक योजना

- **जनसंपर्क रणनीति**

- भूगोल, प्रमुख प्रतिस्पर्धी स्थलों / देशों और उनके प्रसाद, प्रवृत्तियों और दृष्टिकोण, जनसांख्यिकी, आगंतुक गद्य / उपभोक्ता व्यवहार और बाजार के उत्पाद वरीयता के अनुसार एक कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता है।
- इसलिए, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) विश्वसनीय पर्यटन विपणन प्रतिनिधि / गंतव्य विपणन प्रतिनिधि / पीआर कंपनियों की नियुक्ति करके अपनी पीआर रणनीति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। प्रमुख स्रोत देश की प्राकृतिक संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए बाजार। एमओटी को भी अभियान की प्रभावशीलता को लगातार मापना चाहिए और उत्पन्न की गई अंतर्दृष्टि के अनुसार अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार करना और फिर से तैयार करना चाहिए।

स्तंभ 14: सांस्कृतिक संसाधन और व्यावसायिक यात्रा

परिभाषा: यह स्तंभ पुरातात्विक स्थलों, मनोरंजन सुविधाओं और सम्मेलनों जैसे सांस्कृतिक संसाधनों की उपलब्धता को मापता है। यह स्तंभ बड़े पैमाने पर किसी देश की पहले से मौजूद सांस्कृतिक विरासत के बजाय सांस्कृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। स्तंभ 14 के नीचे कुल 5 संकेतक हैं -

1. विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की संख्या
2. मौखिक और अमूर्त सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की संख्या
3. बड़े खेल स्टेडियमों की संख्या
4. अंतरराष्ट्रीय संघों की बैठकों की संख्या

5. सांस्कृतिक और मनोरंजन पर्यटन डिजिटल मांग

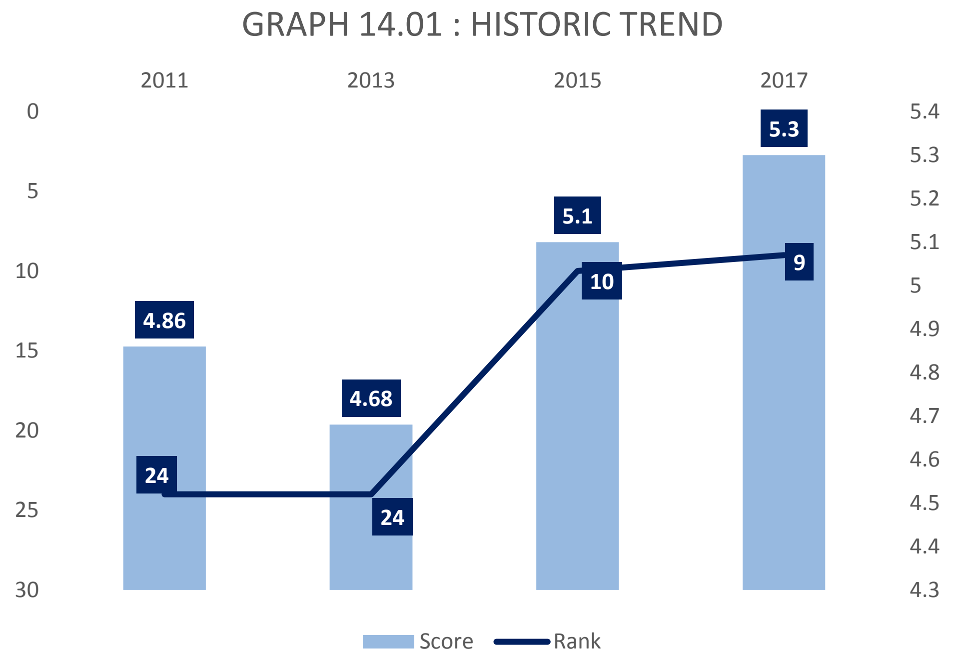

ग्राफ 14.01 भारत की श्रेणी और स्तंभ 14 में मूल्य के ऐतिहासिक रुझान को इंगित करता है। भारत की श्रेणी 2011 में 24 वें स्थान से बढ़कर 2017 में 9 वें स्थान पर पहुंच गई है।

भार की स्थिति में बदलाव:

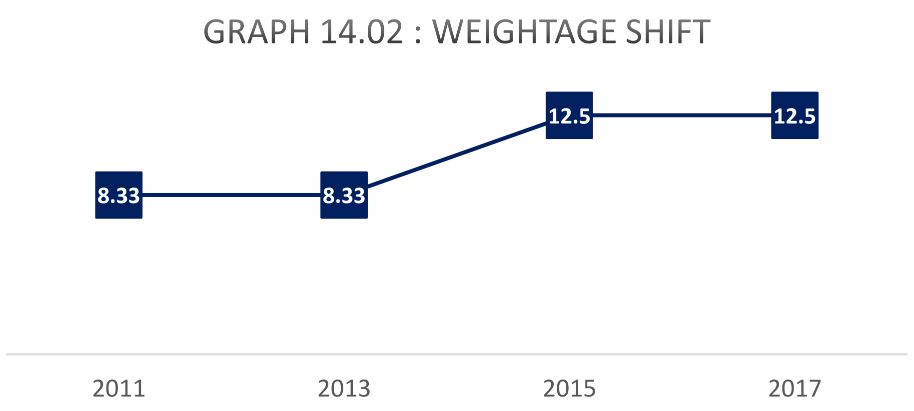

ग्राफ़ 14.02 भारत के स्कोर में स्तंभ 14 यानी सांस्कृतिक संसाधन और व्यवसाय यात्रा के समग्र योगदान को इंगित करता है। वर्तमान में, इस स्तंभ को 12.5% भार दिया जाता है। इस स्तंभ का भार वर्ष 2015 में 50% तक बढ़ गया है।

तालिका 14.01: भार की स्थिति में संकेतक वार बदलाव

संकेतक	2011-2013 (%)	2015-2017 (%)	भार की स्थिति में बदलाव (%)
विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की संख्या	2.1	1.6	-23.81
मौखिक और अमूर्त सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की संख्या	NA	1.6	NA
बड़े खेल स्टेडियमों की संख्या	2.1	3.1	47.62
अंतरराष्ट्रीय संघ की बैठकों की संख्या	2.1	3.1	47.62
सांस्कृतिक / मनोरंजन पर्यटन डिजिटल मांग	NA	3.1	NA

NA = लागू नहीं, उस वर्ष में संकेतक पेश नहीं किया गया था

मौखिक और अमूर्त सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की संख्या और सांस्कृतिक / मनोरंजन पर्यटन डिजिटल मांग, ये दो संकेतक 2015 से पेश किए गए थे।

तालिका 14.01 योगदान का प्रतिशत दर्शाती है जो कि प्रत्येक संकेतक का भारत के समग्र स्कोर पर है।

संकेतक 14.01: विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की संख्या

परिभाषा: यह सूचक देश में विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की संख्या को दर्शाता है। विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल वे गुण हैं जिन्हें विश्व धरोहर समिति उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य मानती है।

स्रोत: यूनेस्को, विश्व विरासत सूची (डब्ल्यूएचएल)

देश का मूल्य = 1 * एक देश में सांस्कृतिक स्थलों की संख्या + 0.5 * एक देश में मिश्रित स्थलों की संख्या

जहां मिश्रित स्थल सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं

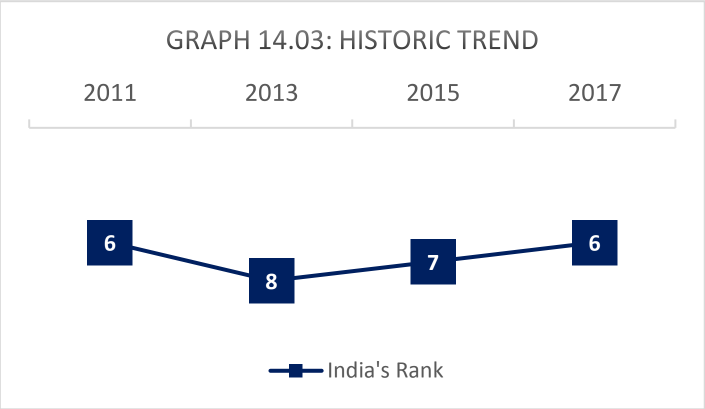

ग्राफ 14.03 संकेतक 14.01 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 1 स्थान की वृद्धि हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 1.6% का योगदान देता है।

तालिका 14.02: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
इटली	1	46	1	47	शीर्ष प्रदर्शक
स्पेन	2	40	2	41	शीर्ष प्रदर्शक
फ्रांस	4	35.5	3	38.5	शीर्ष प्रदर्शक
जर्मनी	3	36	4	38	मुख्य प्रतियोगी
चीन	5	35	5	37	एशियाई साथी

भारत	7	25	6	27.5	
मैक्सिको	6	26.5	6	27.5	मुख्य प्रतियोगी
यूनाइटेड किंगडम	8	23.5	8	25.5	मुख्य प्रतियोगी

विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया[238]

- **चरण 1: संभावित सूची**
  - सभी देशों को अपनी सीमाओं के भीतर स्थित अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत स्थलों की एक 'सूची' बनाने की अनुमति है। यह 'इन्वेंट्री' संभावित सूची के रूप में जानी जाती है, और उन संपत्तियों का पूर्वानुमान प्रदान करती है, जो राज्य पार्टी अगले पांच से दस वर्षों में शिलालेख के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय ले सकती है और जिसे किसी भी समय अद्यतित किया जा सकता है।
- **चरण 2: नामांकन फ़ाइल**
  - राज्य पार्टी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर से सहायता के साथ साइटों की नामांकन फ़ाइल पेश करने के लिए योजना बनाता है। विश्व धरोहर समिति, विश्व धरोहर सूची में शिलालेख के लिए नामांकन पर विचार नहीं कर सकती है जब तक कि संपत्ति को पहले से ही राज्य पार्टी की संभावित सूची में शामिल नहीं किया गया हो।
- **चरण 3: सलाहकार निकाय**
  - एक नामित संपत्ति का मूल्यांकन विश्व विरासत कन्वेंशन द्वारा अनिवार्य दो सलाहकार निकायों द्वारा किया जाता है, जो नामित स्थलों के मूल्यांकन के साथ विश्व विरासत समिति प्रदान करते हैं। एक तीसरा सलाहकार निकाय समिति को सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के साथ-साथ प्रशिक्षण गतिविधियों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है।
- **चरण 4: विश्व धरोहर समिति**
  - हर साल में एक बार, विश्व धरोहर समिति यह तय करती है कि किन नामांकित स्थलों को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जाएगा।
- **चयन के लिए मानदंड**
  - विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए, स्थलों के पास बकाया सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए और उल्लेखित चयन मानदंडों में से दस में से कम से कम एक को पूरा करना होगा जहां पहले 6 मापदंड सांस्कृतिक स्थलों के अंतर्गत आते हैं और अंतिम 4 प्राकृतिक स्थलों के अंतर्गत आते हैं:
    - **मानव रचनात्मक प्रतिभा:** यह मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करता है।

[238] UNESCO: World Heritage Centre

- **मूल्यों का एक दूसरे में बदलना: यह वास्तुकला या प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, टाउन-प्लानिंग या लैंडस्केप डिजाइन में विकास पर, समय के साथ या दुनिया के एक सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर मानव मूल्य एस का एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज प्रदर्शित करता है।**
- **सांस्कृतिक परंपरा की गवाही: यह सांस्कृतिक परंपरा, या एक सभ्यता जो जीवित है, या जो गायब हो गई है के लिए एक अद्वितीय या कम से कम असाधारण गवाही है।**
- **मानव इतिहास में इसकी उपयोगिता: यह एक प्रकार की इमारत, वास्तुशिल्प या तकनीकी कलाकारों की टुकड़ी या परिदृश्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो मानव इतिहास में महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है।**
- **पारंपरिक मानव बस्ती: यह एक पारंपरिक मानव बस्ती, भूमि-उपयोग, या समुद्र-उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो संस्कृति (या संस्कृतियों) का प्रतिनिधित्व करती है, या पर्यावरण के साथ मानव संपर्क विशेष रूप से जब यह प्रभाव अपरिवर्तनीय परिवर्तन में असुरक्षित हो गया हैं।**
- **सार्वभौमिक उपयोगिता की घटनाओं से जुड़ी विरासत: ये सीधे या मूर्त रूप से घटनाओं या जीवित परंपराओं से जुड़े होते हैं, विचारों के साथ, या मान्यताओं के साथ, उत्कृष्ट सार्वभौमिक उपयोगिता के कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के साथ। (समिति का मानना है कि इस मानदंड को अधिमानतः अन्य मानदंडों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए) ।**

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय

तालिका 14.03: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	डब्ल्यूएचएल में जोड़ें गए स्थल (में 2017-18)		डब्ल्यूएचएल में स्थल			संभावित सूची में स्थल	नए मूल्य (2019)
			सांस्कृतिक स्थल	मिश्रित स्थल	सांस्कृतिक	मिश्रित	कुल		
जर्मनी	4	38	3	0	41	0	41	15	41
चीन	5	37	1	0	36	4	40	43	38
भारत	**6**	**27.5**	**2**	**0**	**29**	**1**	**30**	**33**	**29.5**

मेक्सिको	6	27.5	0	1	27	2	29	17	28
यूनाइटेड किंगडम	8	25.5	1	0	26	1	27	8	26.5

वर्तमान रुझान

- भारत के लिए प्रमुख प्रतियोगिता मेक्सिको से है जिसका मूल्य भारत के समान है। यूनाइटेड किंगडम लंबे समय में एक समस्या हो सकती है। विभिन्न देशों की श्रेणी और मूल्य नीचे दिए गए हैं:
    - चीन (श्रेणी 5th): 37
    - भारत (श्रेणी 6th): 27.5
    - मेक्सिको (श्रेणी 6th): 27.5
    - यूनाइटेड किंगडम (श्रेणी 8th): 25.5
- **चीन भारत से 9.5 अंकों से आगे है: चीन का कुल स्कोर 37 है। चीन ने अपनी दस संभावितसूची में 43 साइटें हैं, जो कि भारत से अधिक है। भारत के लिए अल्पकालिक ध्यान इस संकेतक के लिए अपनी श्रेणी को बनाए रखने पर होना चाहिए दस संभावित सूची की स्थिति हमें नीचे दी गयी हैं:**
    - चीन 43 साइटें
    - भारत: 33 साइटें
    - मैक्सिको 17 साइटें
    - यूनाइटेड किंगडम 8 साइटें

दीर्घकालिक योजना

- चूंकि चीन की संभावित सूची में 43 साइटें हैं और जर्मनी (श्रेणी 4) में केवल 15 साइटें हैं, इसलिए यह संभावना है कि चीन लंबे समय में जर्मनी से आगे निकल जाएगा।
- यह मानते हुए कि चीन लंबे समय में जर्मनी से आगे निकल जाएगा, भारत को इस संकेतक में जर्मनी को पछाड़ने का लक्ष्य बनाना चाहिए।

- संस्कृति मंत्रालय का दीर्घकालिक ध्यान लेखन की गुणवत्ता में सुधार पर होना चाहिए जो दस संभावित सूची के लिए एक साइट को सूचीबद्ध करते समय प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही नामांकन सूची के लिए भेजने से पहले दस्तावेजों का पूरी तरह से सत्यापन करने की आवश्यकता होती है। इन सांस्कृतिक स्थलों को नामांकित किया जा सकता है जो फिर विश्व विरासत सूची में अंकित किए जा सकते हैं।

संकेतक 14.02: मौखिक और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

परिभाषा: यह संकेतक मौखिक और अमूर्त विरासत प्रथाओं और अभिव्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करता है। एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक अभ्यास है, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति, ज्ञान, या एक कौशल, साथ ही साथ उपकरण, वस्तुएं, कलाकृतियां, और सांस्कृतिक रिक्त स्थान जो यूनेस्को द्वारा जगह की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा माना जाता है।

स्रोत: यूनेस्को अमूर्त संस्कृति विरासत (आईसीएच) सूची

देश का मूल्य = किसी देश में मौखिक और अमूर्त संस्कृति के रूप में अद्वितीय तत्वों की संख्या (उदाहरण के लिए, भारत में कुंभ मेला, नोवरोज़ आदि)

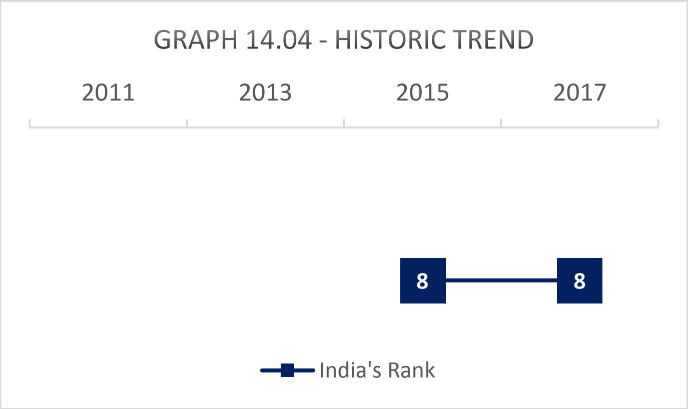

ग्राफ 14.04 संकेतक 14.02 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी वर्ष 2015 की तुलना में 8 वें स्थान पर बनी हुई थी। यह संकेतक देश के स्कोर में 1.6% का योगदान देता है।

तालिका 14.04: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
चीन	1	37	1	39	एशियाई साथी
जापान	2	22	2	21	एशियाई साथी
स्पेन	8	11	4	16	शीर्ष प्रदर्शक

क्रोएशिया	4	14	5	15	मुख्य प्रतियोगी
फ्रांस	5	13	5	15	मुख्य प्रतियोगी
तुर्की	6	12	5	15	मुख्य प्रतियोगी
बेल्जियम	10	10	8	13	मुख्य प्रतियोगी
मंगोलिया	6	12	8	13	मुख्य प्रतियोगी
ओमान	25	4	8	13	मुख्य प्रतियोगी
भारत	**8**	**11**	**8**	**13**	

यूनेस्को की समिति, जो संभावित सूची में से साइटों के चयन के लिए ज़िम्मेदार है, उन देशों को प्राथमिकता नहीं देती है जो सूचीबद्ध नहीं हैं और ऐसी साइटें हैं जो तत्काल सुरक्षा सूची में शामिल हैं। बैकलॉग में वे साइटें होती हैं, जिनकी समिति द्वारा सीमित क्षमता के कारण समीक्षा नहीं की जाती है। वे सभी साइटें जो भारत के बैकलॉग में हैं, प्रतिनिधित्व सूची से संबंधित हैं[239]।

तीन प्रकार की सूचियाँ हैं जिनके तहत तत्व पंजीकृत हैं:

- **तत्काल सुरक्षा सूची**
  - यह सूची एक देश में उन अमूर्त विरासत तत्वों से बनी है, जिन्हें जीवित रखने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है।
  - तत्काल सुरक्षा सूची पर अंकित किए गए तत्व उदाहरण के लिए अल अज़ी, पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र के एटलस (मोरक्को के) का मार्शल डांस (संयुक्त अरब अमीरात का), टास्कविन, मार्शल आर्ट, प्रदर्शन करने की कला आदि।
- **प्रतिनिधित्व सूची**
  - यह सूची उन अमूर्त विरासत तत्वों से बनी है जो इस विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
  - प्रतिनिधित्व सूची उदाहरण के लिए योग (भारत का), कुंभ मेला (भारत का), बेसल कार्निवल (का) आदि।
- **अच्छे सुरक्षा उपायों का रजिस्टर**

[239] https://ich.unesco.org/en/lists

- इस सूची में ऐसे कार्यक्रम, परियोजनाएं और गतिविधियां शामिल हैं जो एक अमूर्त विरासत तत्व को सुरक्षित रखने के लिए जनसंख्या को शिक्षित / प्रशिक्षित करती हैं।
- तत्वों को अच्छे सुरक्षा उपायों पर अंकित किया जाता है उदाहरण के लिए रोविंज / रोविग्नो की जीवित संस्कृति की सुरक्षा की सामुदायिक परियोजना: बटना ईकोम्यूज़ियम (क्रोएशिया)

तालिका 14.05: बैकलॉग में रहने वाले स्थलों की सूची

क्र.सं.	मौखिक और अमूर्त विरासत	से बैकलॉग
1	दशावतार: पारंपरिक लोक रंगमंच रूप, महाराष्ट्र और गोवा, भारत (00338)	2010
2	हिंगन: वोटिव टेराकोटा चित्रित पट्टिका मोलला, राजस्थान, भारत (00346)	2010
3	सिक्किम का लामा नृत्य: बौद्ध मठ नृत्य, सिक्किम, भारत (00352)	2010
4	नाचा: लोक रंगमंच, छत्तीसगढ़, भारत (00344)	2010
5	पटोला: पाटन के दोहरे इकत रेशम वस्त्र, गुजरात, भारत (00343)	2010
6	फड़: स्क्रॉल पेंटिंग और उनका कथन, राजस्थान, भारत (00342)	2010
7	राठवा नी घेर: रथवास, गुजरात, भारत का जनजातीय नृत्य (00348)	2010
8	संखेड़ा नं लाख काँम: लाख का लकड़ी में बना हुआ सांईखेड़ा का लकड़ी का फर्नीचर, गुजरात, भारत (00347)	2010
9	सतरिया संगीत, नृत्य और रंगमंच (00350)	2010
10	छाया कठपुतली थिएटर परंपराएं (00351)	2010
11	सालह का त्योहार, बिहार, भारत (00339)	2010
12	चार बेयट, गीतात्मक मौखिक कविता में एक मुस्लिम परंपरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, भारत (00841)	2012
13	चेट्टीकुलंगरा कुंभा भरणी केतुकजाझा (00708)	2012
14	पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा (00703)	2012
15	गद्दी जतरा (00705)	2012

16	जंगम ज्ञान (00702)	2012
17	कलमकारी पेंटिंग (00709)	2012
18	कोलम, अनुष्ठानिक सीमा रेखाचित्र और तमिलनाडु के डिजाइन, भारत (00842)	2012
19	संगीत और वीणा के वाद्य का ज्ञान (00844)	2012
20	नौटंकी (00699)	2012
21	राजस्थान में पगड़ी बांधने की प्रथा (00701)	2012
22	कव्वाली (00698)	2012
23	रणमल (00706)	2012

सम्मेलन सूची में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया:

उपलब्ध संसाधनों और उसकी क्षमता के अनुसार, यूनेस्को की समिति दो साल पहले से निर्धारित करती है, उन दो चक्रों के दौरान कितनी फ़ाइलों की संख्या का उपचार किया जा सकता है।

चरण 1: तैयारी और प्रस्तुत करना	
31 मार्च वर्ष 0	नामांकन के विस्तार के लिए प्रारंभिक सहायता अनुरोधों की समय सीमा
31 मार्च वर्ष 1	समय सीमा जिसके द्वारा सचिवालय द्वारा नामांकन प्राप्त किया जाना चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त फ़ाइलों की अगले चक्र में जांच की जाएगी।
30 जून वर्ष 1	समय सीमा जिसके द्वारा सचिवालय ने फाइलों को संसाधित किया होगा, जिसमें पंजीकरण और प्राप्ति की रसीद शामिल है। यदि कोई फ़ाइल अपूर्ण पाई जाती है, तो फ़ाइल को पूरा करने के लिए राज्य पार्टी को आमंत्रित किया जाता है।
30 सितंबर वर्ष 1	फाइलें, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए आवश्यक गुम सूचना जिसके द्वारा राज्य पार्टी सचिवालय को प्रस्तुत की जाएगी। अधूरी रह गई फाइलें स्टेट्स पार्टियों को वापस कर दी जाती हैं जो बाद के चक्र के लिए पूरी हो सकती हैं।
चरण 2: मूल्यांकन	
दिसंबर वर्ष 1 - मई वर्ष 2	मूल्यांकन निकाय द्वारा फाइलों का मूल्यांकन
अप्रैल - जून वर्ष 2	मूल्यांकन निकाय द्वारा अंतिम मूल्यांकन के लिए बैठक ।
समिति के सत्र से पहले हफ्तों के लिए	समिति के सत्र से पहले हफ्तों के लिए राज्यों की पार्टियों द्वारा परामर्श के लिए फाइलें और मूल्यांकन रिपोर्ट ऑन-लाइन उपलब्ध हैं।
चरण 3: परीक्षा	
नवंबर / दिसंबर वर्ष 2	समिति नामांकन की जांच करती है और अपने फैसले करती है।

संस्कृति मंत्रालय - कार्य और हस्तक्षेप

- **संस्कृति मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित प्रणाली की रूपरेखा तैयार की है:**

- **राष्ट्रीय स्तर पर:** अकादमियां (संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी), स्वायत्तशासी निकाय (जैसे आई.सी.सी.आर), अधीनस्थ निकाय (जैसे भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण) और विभिन्न स्वायत्त संस्थान, मिशन और सर्वेक्षण गठित किए जाते हैं।
    - **राज्य स्तर पर:** भारत क्षेत्र के राज्यों को कवर करने वाले विभिन्न आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र, पूर्व-पूर्वी क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र हैं।
- **संगीत नाटक अकादमी** को 2011 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) की सुरक्षा पर यूनेस्को कन्वेंशन के उद्देश्यों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था और यह यूएनएच पर यूनेस्को सम्मेलन के तहत **विभिन्न सूचियों और अन्य कार्यों के लिए भारत के नामांकनों** के **समन्वय और आईसीएच की राष्ट्रीय सूची के विकास और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है।**
    - **एक पैन- भारत (प्रगति में काम) 165 तत्वों की सूची** संगीत नाटक अकादमी की वेबसाइट पर मौजूद है।
- **इन अकादमियों की भूमिका:** समुदायों के बीच क्षेत्रीय, जिला आईसीटी और जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर अपनेपन और निरंतरता की भावना पैदा करता है।
- संस्कृति मंत्रालय ने विभिन्न संस्थानों, समूहों, व्यक्तियों, गैर-एमओसी संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से **"भारत की अमूर्त विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए योजना" नामक एक योजना बनाई है।** और विद्वान ताकि वे भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने, संरक्षण, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों / परियोजनाओं में संलग्न हो सकें।
- योजना के तहत सहायता गैर-आवर्ती अनुदान, सम्मान, आधारिक संरचना अनुदान आदि के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसमें संगठनों / व्यक्तियों को मजबूत करने के लिए आईसीएच के सभी रूपों के अस्तित्व और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित किया जाएगा आदि जो इन सांस्कृतिक परंपराओं / भावों को जीवित रखने में सम्मिलित हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय

तालिका 14.06: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	नवंबर / दिसंबर 2019 के लिए नामांकित तत्व	प्रक्रिया बैकलॉग के तहत फाइलें			प्रक्रिया बैकलॉग के तहत फाइलें
				प्रक्रिया बैकलॉग के तहत फाइलें	प्रक्रिया बैकलॉग के तहत फाइलें	कुल	
चीन	1	39	1	1	0	2	13
जापान	2	21	0	1	0	1	5
कोरिया, गणराज्य	2	21	0	2	0	2	1
स्पेन	4	16	0	2	1	3	1
क्रोएशिया	5	15	0	2	0	2	0
फ्रांस	5	15	0	2	1	3	1
तुर्की	5	15	1	1	1	2	4
बेल्जियम	8	13	0	0	1	1	1
भारत	8	13	0	0	1	1	23
मंगोलिया	8	13	1	1	0	1	0
ओमान	8	13	0	1	1	2	0

दीर्घकालिक योजना

- भारत का प्रदर्शन इस संकेतक में संतोषजनक है। भारत में अन्य देशों की तुलना में बैकलॉग में सबसे अधिक तत्व हैं, जो लंबे समय में अन्य देशों से आगे निकलने में मदद करेगा।
- यूनेस्को की समिति फाइलों को प्राथमिकता देती है:
    - **देशों में कोई तत्व नहीं है,**
    - **सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रथाएं**
    - **अंतर्राष्ट्रीय सहायता US $ 100,000 से अधिक है**
    - **तत्काल सुरक्षित सूची (एक देश में अमूर्त विरासत तत्व जो उन्हें जीवित रखने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता होती है)**
    - **बहु-राष्ट्रीय (ऐसे तत्व जो एक से अधिक देशों में पंजीकृत हैं। उदाहरण के लिए, जो अफगानिस्तान - अज़रबैजान - भारत - ईरान - इराक - कजाकिस्तान - किर्गिस्तान - उज़्बेकिस्तान - पाकिस्तान - ताजिकिस्तान - तुर्कमेनिस्तान - तुर्की) के लिए पंजीकृत है।**
- **इसलिए, नामांकन प्रक्रिया के दौरान, संस्कृति मंत्रालय को ऐसे तत्वों की फाइलों को महत्व देना चाहिए जो बहु-राष्ट्रीय हैं और ऐसे तत्वों को तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे प्रकार के तत्वों को यूनेस्को की आईसीएच समिति द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जाती है।**

संकेतक 14.03: बड़े खेल स्टेडियमों की संख्या

परिभाषा: यह सूचक 20,000 से अधिक सीटों की क्षमता वाले खेल स्टेडियमों की कुल संख्या को संदर्भित करता है।

स्रोत: WorldStadium.com के आधार पर रिपोर्ट की गणना

देश का मूल्य: खेल टीमों की संख्या + घटनाओं की वीज़ा संख्या + (स्पोर्ट्स स्टेडियम 20,000 से अधिक क्षमता वाले पंजीकृत)

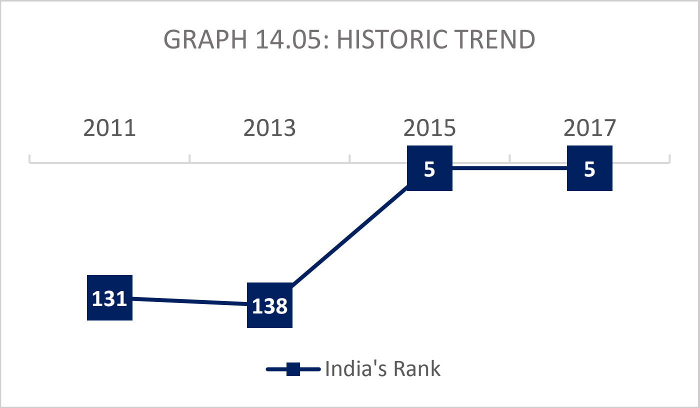

ग्राफ 14.05 संकेतक 14.03 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2017 की तुलना में 2017 में भारत की श्रेणी 5 वें स्थान पर बनी हुई है। यह संकेतक देश के स्कोर में 3.1% का योगदान देता है।

संकेतक का इतिहास: वर्ष 2015-2017: में, इस संकेतक की गणना को खेल की सीटों की प्रति मिलियन जनसंख्या से खेल स्टेडियमों की संख्या में बदल दिया गया है।

तालिका 14.07: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	टनाओं / खेल टीमों की संख्या (2017-2018 में)	नया मूल्य (2019)	कारण
चीन	2	124	2	141	4	145	एशियाई साथी
ब्राज़ील	3	95	3	95	-	-	शीर्ष प्रदर्शक

जापान	4	89	4	90	0	90	एशियाई साथी
भारत	5	86	5	87	6	93	
ऑस्ट्रेलिया	6	81	6	81	0	81	मुख्य प्रतियोगी
यूके	6	81	6	81	9	90	मुख्य प्रतियोगी

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: युवा कार्य और खेल मंत्रालय, खेल विभाग

अल्पकालीन योजना

- किसी देश के मूल्य की गणना इसके आधार पर की जाती है:
    - घटनाओं की संख्या; तथा
    - खेल स्टेडियमों के साथ पंजीकृत खेल टीमों की संख्या।

- इसलिए, देश के मूल्य को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं:
    - 20,000 से अधिक सीटों की क्षमता वाले स्टेडियमों में पंजीकृत घटनाओं की संख्या और खेल टीमों की संख्या बढ़ाएँ।
    - राज्यों को ऐसे क्लबों की पहचान करनी चाहिए जो अपंजीकृत हैं या 20,000 से कम क्षमता वाले स्टेडियम में पंजीकृत हैं
    - एक बार पहचाने जाने पर, क्लबों को 20,000 से अधिक सीटों वाले स्टेडियम में पंजीकृत किया जा सकता है।

- चीन, जापान, ब्रिटेन में पंजीकृत खेलों से तुलना करने के बाद भारत के लिए इस श्रेणी के मूल्य को बढ़ाने के लिए ध्यान दिए जाने वाले खेलों का सुझाव दिया जा सकता है:
    - रेस उपयोग
    - टेनिस
    - तैराकी
    - पोलो मैच / हॉर्स रेसिंग
    - इंडोर गेम्स

- कबड्डी
- टेबल टेनिस
- बैडमिंटन

- भारत में 32 स्टेडियम (नीचे तालिका में उल्लिखित) हैं जो 20000 से अधिक की क्षमता के होते हुए डब्ल्यूइऍफ़ के डाटा स्रोत में शामिल नहीं इन स्टेडियमों की सूची के लिए नीचे दी गई तालिका में देखें -

क्र.सं.	स्टेडियम	क्षमता	खेल / कार्यक्रम	शहर
1	डॉ। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम	26736	क्रिकेट	विशाखापत्तनम
2	डॉ। भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम	40000	क्रिकेट	गुवाहाटी
3	इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम	30737	एथलेटिक्स, फुटबॉल (सॉकर)	गुवाहाटी
4	मोइन-उल-हक स्टेडियम	25000	क्रिकेट	पटना
5	हीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम	50000	क्रिकेट	रायपुर
6	अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम	30000	Hockey	राजनांदगांव
7	सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम	50000	क्रिकेट	अहमदाबाद
8	सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम	33000	क्रिकेट	राजकोट
9	सीबी पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम	35000	क्रिकेट	सूरत
10	महाबीर स्टेडियम	25000	खेल परिसर	हिसार
11	एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम	25000	क्रिकेट	धर्मशाला
12	जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम	39133	क्रिकेट	रांची
13	बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम	35000	एथलेटिक्स	रांची
14	द स्पोर्ट्स हब	50000	खेल परिसर	तिरुवनंतपुरम
15	महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम	37406	क्रिकेट	गहुंजे, पुणे जिला
16	विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम	45000	क्रिकेट	नागपुर

17	खुमान दीपक मुख्य स्टेडियम	30000	फुटबॉल (सॉकर)	इम्फाल
18	केआईआईटी स्टेडियम	40000	क्रिकेट	भुवनेश्वर
19	अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम	30000	हॉकी	राजनांदगांव
20	पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम	26000	क्रिकेट	मोहाली
21	वार हीरोज स्टेडियम	30000	हॉकी	संगरूर
22	बाइचुंग स्टेडियम	30000	फुटबॉल (सॉकर)	नामची
23	चेन्नई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम	40000	एथलेटिक्स, फुटबॉल (सॉकर)	चेन्नई
24	M. A. Chidambaram Stadium	50000	क्रिकेट	चेन्नई
25	राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम	60000	क्रिकेट	हैदराबाद
26	G. M. C. बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम	30000	एथलेटिक्स, क्रिकेट	हैदराबाद
27	महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज स्टेडियम	30000	क्रिकेट	अगरतला
28	एकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम	50000	क्रिकेट	लखनऊ
29	केडी सिंह बाबू स्टेडियम	25000	क्रिकेट	लखनऊ
30	सैफई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम	43000	क्रिकेट	सैफई
31	राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम	25000	क्रिकेट	देहरादून
32	साल्ट लेक स्टेडियम	85000	एथलेटिक्स, फुटबॉल (सॉकर)	कोलकाता

- **इसलिए, पर्यटन मंत्रालय डब्ल्यूईएफ़एफ़ या worldstadium.com को लिख सकता है और सूची से इन स्टेडियमों के बहिष्कार के बारे में स्पष्टीकरण पूछ सकता है।**

दीर्घकालिक योजना

- इस चरण में 20,000 से कम या 20,000 के बराबर सीटों की स्टेडियमों की पहचान करना शामिल हैं। डब्ल्यूईएफ ऐसे स्टेडियमों की गिनती नहीं करता है जिनकी क्षमता 20,000 के बराबर है, जबकि स्टेडियम जिनकी क्षमता 20,005 है जैसे जापान के मामले में गिना जाता है।
- भारत में 20,000 के बराबर क्षमता वाले 42 स्टेडियम हैं, इसलिए इन स्टेडियमों में कुछ और सीटें जोड़ने से भारत की गिनती तुरंत 42 तक बढ़ जाएगी।
- पर्यटन मंत्रालय इन स्पोर्ट्स स्टेडियम की बैठने की क्षमता बढ़ाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय, खेल विभाग की सिफारिश कर सकता है ताकि उन्हें बड़े खेल स्टेडियम के रूप में भी गिना जा सके। बढ़ने से, इस सूचक के तहत 45 उल्लेखित स्टेडियम भारत की श्रेणी की क्षमता को और बेहतर बनाया जा सकता है।
- 45 स्टेडियमों की सूची जिनकी क्षमता केवल कुछ सीटों को जोड़कर बढ़ाई जा सकती है, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित हैं:

क्र.सं.	शहर	स्टेडियम	मौजूदा क्षमता	बढ़ाने के लिए न्यूनतम लक्ष्य
1	कंकरबाग	पाटलिपुत्र खेल परिसर	20 000	10
2	मुंबई	ब्रेबॉर्न स्टेडियम	20 000	10
3	तिरुवंतपुरम	यूनिवर्सिटी स्टेडियम	20 000	10
4	आइजोल	राजीव गांधी स्टेडियम	20 000	10
5	मंगलौर	मंगला स्टेडियम	20 000	10
6	मैसूर	चामुंडी विहार स्टेडियम	20 000	10
7	पुट्टपर्थी	हिल व्यू स्टेडियम	20 000	10
8	जलालाबाद	जलालाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम	20 000	10
9	लखनऊ	डॉ। अखिलेश दास स्टेडियम	20 000	10
10	अहमदाबाद	द एरिना बाय ट्रांसस्टैडिया	20 000	10
11	कोल्हापुर	राजर्षि शाहू स्टेडियम	20 000	10
12	इचलकरंजी	राजाराम स्टेडियम	20 000	10
13	रांची	सिल्ली स्टेडियम	20 000	10
14	भिलाई	जयंती स्टेडियम	20 000	10
15	विजयवाड़ा	इंदिरा गांधी स्टेडियम	20 000	10

16	विशाखापत्तनम	इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम	20 000	10
17	श्रीकाकुलम	कोडी राममूर्ति स्टेडियम	20 000	10
18	दुर्ग	रविशंकर शुक्ल स्टेडियम	20 000	10
19	दावानागेरे	कॉर्पोरेशन स्टेडियम	20 000	10
20	धारवाड़	आरएन शेट्टी स्टेडियम	20 000	10
21	गुलबर्गा	चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम	20 000	10
22	मंड्या	पीईटी क्रिकेट स्टेडियम	20 000	10
23	तुमकुर	तुमकुर नेहरू स्टेडियम	20 000	10
24	कोट्टायम	कोट्टायम नेहरू स्टेडियम	20 000	10
25	कराड	छत्रपति शिवाजी स्टेडियम	20 000	10
26	सतारा	शाहू स्टेडियम	20 000	10
27	सकीपारा	वीएसएस स्टेडियम	20 000	10
28	बीकानेर	डॉ. कर्णी सिंह स्टेडियम	20 000	10
29	तिरुचिरापल्ली	अन्ना स्टेडियम	20 000	10
30	भोपाल	तांत्या टोपे नगर स्टेडियम	20 000	10
31	एर्नाकुलम	महाराजा कॉलेज स्टेडियम	20 000	10
32	कोल्हापुर	श्री छत्रपति शिवाजी	20 000	10
33	मेरठ	कैलाश प्रकाश स्टेडियम	20 000	10
34	पावरपेट	एएसआर स्टेडियम	20 000	10
35	कोहिमा	इंदिरा गांधी स्टेडियम	20 000	10
36	गोंदिया	इंदिरा गांधी स्टेडियम	20 000	10
37	पूर्णिया	इंदिरा गांधी स्टेडियम	20 000	10
38	ब्रह्मपुर	ब्रह्मपुर स्टेडियम	20 000	10
39	कराड	छत्रपति शिवाजी स्टेडियम	20 000	10
40	होशियारपुर	लाजवंती स्टेडियम	20 000	10
41	मंड्या	विश्वेश्वरैया स्टेडियम	20 000	10
42	वैधन	राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम	20 000	10
43	धर्मशाला	एचपीसीए स्टेडियम	19 979	39

44	मार्गो	फतोर्दा स्टेडियम	19 800	210
45	जमशेदपुर	कीनन स्टेडियम	19 000	1010

संकेतक 14.04: **अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन की बैठकों की संख्या**

परिभाषा: यह सूचक देश में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय संघ की संख्या को दर्शाता है। यह तीन साल (2013 से 2015 के बीच टीटीसीआई 2017 की रिपोर्ट के लिए) के बीच किसी देश में सालाना आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संघों की बैठकों की औसत संख्या को मापता है। ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और कन्वेंशन एसोसिएशन (आईसीसीए) डाटा बेस पर आधारित हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संघों द्वारा आयोजित बैठकें शामिल हैं, जो निम्न मानदंडों को पूरा करती हैं:

- नियमित आधार पर होता हैं
- न्यूनतम तीन देशों के बीच घूमता हैं
- कम से कम 50 प्रतिभागी है

शामिल बैठकों में आईसीसीए के सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों द्वारा आयोजित की जाती हैं

स्रोत: द इंटरनेशनल कांग्रेस एंड कन्वेंशन एसोसिएशन (आईसीसीए)

देश का मूल्य = रिपोर्टिंग से पहले 3 साल के बीच किसी देश में आयोजित बैठकों की औसत संख्या (उदहारण के लिए 2017 की रिपोर्ट के लिए 2013 और 2015 के बीच)

किसी देश (आईसीसीए के सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों द्वारा आयोजित) की संख्या के लिए डाटा बेस तक पहुँचने के लिए, किसी को आईसीसीए का सदस्य होना चाहिए।

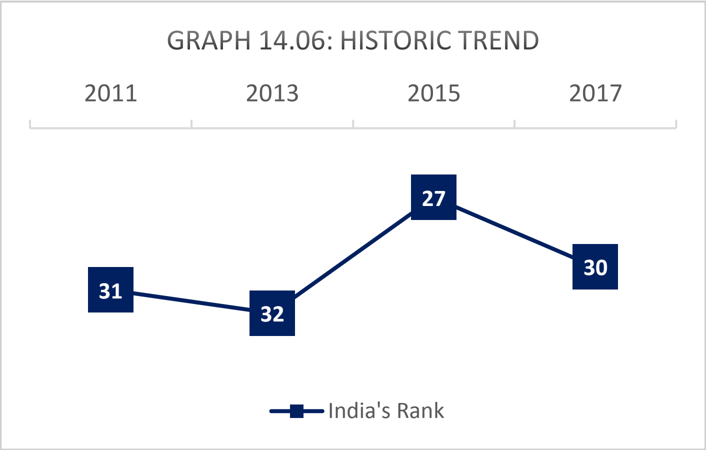

ग्राफ 14.06 सूचक 14.04 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2017 की तुलना में 2017 में, भारत की श्रेणी में 3 पदों की कमी हुई। यह सूचक देश के स्कोर में 3.1% का योगदान देता है।

तालिका 14.08: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
यूनाइटेड स्टेट्स	1	900	1	926	शीर्ष प्रदर्शक
जर्मनी	2	702	2	714	शीर्ष प्रदर्शक
यूनाइटेड किंगडम	4	524	3	599	शीर्ष प्रदर्शक
चीन	7	361.3	7	387	एशियाई साथी
ऑस्ट्रेलिया	16	236	15	256	मुख्य प्रतियोगी
ग्रीस	35	125.3	28	149	मुख्य प्रतियोगी
भारत	**27**	**149.3**	**30**	**140**	

संकेतक का इतिहास: वर्ष 2015-2017 में, इस संकेतक की गणना को अंतरराष्ट्रीय मेलों की संख्या से अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों की संख्या में बदल दिया गया था।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

दीर्घकालिक योजना

तालिका 14.09: देशों का प्रदर्शन

क्षेत्र-वार आईसीसीए सदस्य									
देश	**श्रेणी (2015)**	**श्रेणी (2017)**	**डेस्टिनेशन मार्केटिंग**	**मीटिंग मैनेजमेंट**	**मीटिंग समर्थन**	**स्थान**	**परिवहन**	**मानद सदस्य**	**कुल सदस्य**
चीन	7	7	20	17	6	14	1	0	58
ऑस्ट्रेलिया	16	15	10	2	8	11	0	2	33
ग्रीस	35	28	3	9	0	4	0	0	16
भारत	**27**	**30**	**1**	**11**	**0**	**8**	**0**	**0**	**20**

*** आईसीसीए के सदस्यों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे, गंतव्य विपणन, बैठक प्रबंधन, बैठक समर्थन, स्थान, परिवहन और मानद सदस्य प्रकार। यह तालिका विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार आईसीसीए में प्रत्येक देश के सदस्यों की संख्या दर्शाती है।**

- **आईसीसीए में डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन (डीएमओ) को बढ़ाना** [240]
    - 2015 में भारत की श्रेणी 27 थी जो 2017 में 30 हो गई। साथ ही, 2017 में भारत थाईलैंड और ग्रीस से आगे निकल गया।
    - चीन और ऑस्ट्रेलिया भारत के समान क्षेत्र में स्थित हैं, और इस संकेतक में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत के पास आईसीसीए के साथ पंजीकृत अन्य देशों की तुलना में कम से कम डेस्टिनेशन मार्केटिंग सेक्टर के सदस्य हैं।
    - डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन (डीएमओ) मियासीई (मीटिंग, इनिशिएटिव, कन्वोकेशन एंड इवेंट्स) टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये देश के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस इवेंट्स डेस्टिनेशन के रूप में और देश के लिए बिजनेस इवेंट्स को हासिल करने के लिए जिम्मेदार हैं।
    - डीएमओ ने रणनीतिक योजना की पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज किया और देश के लिए बिजनेस इवेंट जीतने के लिए सम्मोहक बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए।

[240] https://www.iccaworld.org/abouticca/

- ऐसे संगठन जो गंतव्य विपणन क्षेत्र में आईसीसीए के सदस्य बन सकते हैं उनमें राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रालय या आर्थिक विकास, राष्ट्रीय पर्यटन कार्यालय, राष्ट्रीय सम्मेलन ब्यूरो, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, क्षेत्रीय सम्मेलन ब्यूरो, शहर पर्यटन कार्यालय, शहर सम्मेलन ब्यूरो, या अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य प्रतिनिधित्व कंपनी शामिल हैं।
- **भारत के लिए, पर्यटन मंत्रालय और भारत कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी) आईसीसीए के तहत डेस्टिनेशन मार्केटिंग संगठन बनने के योग्य हैं। या तो, पर्यटन मंत्रालय आईसीसीए का सदस्य बनना चाहिए या डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन (डीएमओ) बनने के लिए आईसीपीबी की सहायता कर सकता है या दोनों को आईसीसीए सदस्यता के तहत डीएमओ के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।**

- **क्षेत्रीय स्तर के ब्यूरो की स्थापना और पंजीकरण**
  - क्षेत्रीय स्तर के ब्यूरो की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के लिए उपयुक्त गंतव्य के रूप में इस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रत्येक महानगरीय शहर जैसे ब्रिस्बेन कन्वेंशन ब्यूरो, मेलबर्न कन्वेंशन ब्यूरो आदि के लिए एक क्षेत्रीय स्तर का ब्यूरो है, जबकि भारत में केवल 1 क्षेत्रीय ब्यूरो यानी हैदराबाद कन्वेंशन विज़िटर ब्यूरो है।
  - वर्ष 2015-17 के लिए आईसीसीए सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इन वर्षों में आयोजित सभी बैठकों में से 31% नई दिल्ली में आयोजित की गईं। दिल्ली के लिए एक क्षेत्रीय ब्यूरो स्थापित किया जाना चाहिए और मिसीआई उद्योग के आउटरीच को बढ़ाने के लिए आईसीसीए के साथ पंजीकृत होना चाहिए, इस प्रकार, इस सूचक के लिए भारत के समग्र स्कोर में सुधार होगा।
  - इसके अलावा, भविष्य में स्थापित होने वाले किसी भी क्षेत्रीय स्तर के ब्यूरो को भी आईसीसीए के साथ डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

* आईसीसीए के सदस्य के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

- **चरण 1:** आवेदन पत्र को पूरा करें जिसे आईसीसीए के प्रधान कार्यालय से अनुरोध किया जा सकता है।
- **चरण 2:** एक बार आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद, इसे वापस कर दिया जाना चाहिए और प्रवेश शुल्क और प्रथम वर्ष की सदस्यता शुल्क के साथ चालान के साथ आवेदक को एक पुष्टिकरण भेजा जाएगा।

- **चरण 3:** आवेदन को एक बार आईसीसीएनिदेशक मंडल से अनुमोदन और प्रवेश शुल्क और प्रथम वर्ष की सदस्यता शुल्क के भुगतान से आईसीसीए निदेशक मंडल को भेजा जाएगा। तब आवेदक आईसीसीए का आधिकारिक सदस्य बन सकता है।

संकेतक 14.05: सांस्कृतिक और मनोरंजन पर्यटन डिजिटल मांग

परिभाषा: यह संकेतक ऑनलाइन खोज सूचकांक की संख्या को संदर्भित करता है। यह निम्नलिखित सांस्कृतिक ब्रांड टैग से संबंधित कुल ऑनलाइन खोज मात्रा को मापता है: ऐतिहासिक स्थल, स्थानीय लोग, स्थानीय परंपराएं, संग्रहालय, प्रदर्शन कला, यूनेस्को, शहर पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, स्थानीय दिव्य भोजन, मनोरंजन पार्क, अवकाश गतिविधियाँ, नाइटलाइफ़ और विशेष कार्यक्रम।

स्रोत: ब्लूम परामर्श देश ब्रांड श्रेणी पर आधारित, पर्यटन संस्करण

देश का मूल्य: 9 भाषाओं में उपरोक्त सांस्कृतिक ब्रांड टैग से संबंधित शब्दों के विश्लेषण के आधार पर 0-100 के पैमाने पर मापा जाता है

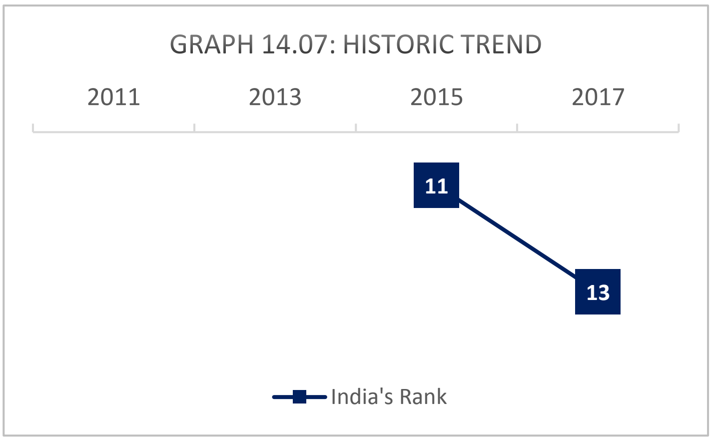

ग्राफ 14.07, संकेतक 14.05 में भारत की श्रेणी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह संकेतक वर्ष 2015 में पेश किया गया था। 2017 में, भारत की श्रेणी में वर्ष 2015 की तुलना में 2 पदों की कमी आई। यह संकेतक देश के स्कोर में 3.1% का योगदान देता है।

तालिका 14.10: देशों का प्रदर्शन

देश	श्रेणी (2015)	मूल्य (2015)	श्रेणी (2017)	मूल्य (2017)	कारण
फ्रांस	2	85.3	1	91.9	शीर्ष प्रदर्शक
स्पेन	4	80.5	2	83.3	शीर्ष प्रदर्शक

चीन	8	55	3	81.7	एशियाई साथी
अर्जेंटीना	12	41.6	12	50.9	मुख्य प्रतियोगी
भारत	**11**	**46.6**	**13**	**50.7**	

डी2 © उपकरण क्या है?

- विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। उनका मालिकाना सॉफ्टवेयर विभिन्न स्थानों के प्रति वैश्विक स्तर पर की गई सभी खोजों को इकट्ठा करता है और उसकी अपील को प्रकट करता है। हर साल, डिजिटल देश और डिजिटल सिटी सूचकांक को मापा जाता है जो ब्याज और देशों के प्रदर्शन और पर्यटन, निवेश, निर्यात, प्रतिभा और राष्ट्रीय प्रमुखता के क्षेत्रों पर आधारित होते हैं।
- यह गणना मालिकाना डी 2 टूल पर आधारित है, जो प्रासंगिक ब्रांड टैग में ऑनलाइन पर्यटन-संबंधी खोज डाटा का विश्लेषण करके प्रत्येक देश के आकर्षण का आकलन करता है, जिसमें प्रत्येक गंतव्य-विशिष्ट कीवर्ड हैं जो पर्यटन गतिविधियों और आकर्षण से संबंधित हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना

मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय

भारत के लिए ऑनलाइन खोज मात्रा बढ़ाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत एन पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक विज्ञापन रणनीति जिसमें प्रचार के डिजिटल, सामाजिक और पारंपरिक तरीकों का मिश्रण होता है; क्षेत्रों के भूगोल के आधार पर भी अपनाया जा सकता है।

अल्पकालीन योजना

- **डी 2 © उपकरण की सदस्यता**
  - पर्यटन विश्लेषण के लिए D2-उपकरण को स्वीडन, पुर्तगाल, जर्मनी, वियतनाम, कोस्टा रिका, यूरोपीय पर्यटन आयोग आदि के पर्यटन संगठनों द्वारा सदस्यता ली गई है।
  - **पर्यटन मंत्रालय विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टि तक पहुँच प्राप्त करने के लिए इस उपकरण की सदस्यता भी ले सकता है और विभिन्न लक्षित बाजारों का अवलोकन भी कर दीर्घकालिक योजना**

- **ब्रांड टैग का विज्ञापन और विपणन**
  - भारत के लिए ऑनलाइन खोज मात्रा बढ़ाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक विज्ञापन रणनीति जिसमें प्रचार के डिजिटल, सामाजिक और पारंपरिक तरीकों का मिश्रण होता है; क्षेत्रों के भूगोल के आधार पर अपनाया जाना चाहिए।
  - पर्यटन से संबंधित ब्रांड टैग के प्रभावी विज्ञापन के लिए, खोज इंजन अनुकूलन (एसईओ) को लागू किया जाना चाहिए। फोकस को पारंपरिक विज्ञापन से सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर आदि पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
  - पर्यटन मंत्रालय के केवल 14 विदेशी कार्यालय हैं। इसलिए, सभी देशों में भारत के दूतावासों का उपयोग अपने संबंधित देशों में भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।
  - अतुल्य भारत सहित ऑनलाइन अभियानों की सामग्री अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह गैर-अंग्रेजी भाषी राज्यों और देशों से अधिक ऑनलाइन खोजों को आकर्षित करने में मदद करेगा।
  - अन्य देशों की मदद से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एक देश उन्मुख विपणन योजना तैयार की जानी चाहिए और हर 6 महीने में रूस (रूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन को कवर), ब्राजील, दक्षिण कोरिया, स्पेन (जैसे देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ लागू किया जाएगा) स्पेन और पुर्तगाल को कवर करना, थाईलैंड (थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार को कवर करना), अर्जेंटीना (पेरू, चिली, अन्य पड़ोसी स्पेनिश बोलने वाले देशों को कवर करना) क्योंकि ये देश पर्यटकों के लिए नए स्रोत बाजार हैं।
  - **पर्यटन मंत्रालय ब्रांड टैग के विज्ञापन और विपणन के लिए एक जनसंपर्क रणनीति टीम या एक समर्पित विशेष सेल को भी नियुक्त कर सकता है।**

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए सिफारिशें

टीटीसीआई रिपोर्ट में डब्ल्यूईएफ द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली की पूरी तरह से जांच की जाती है और कुछ प्रासंगिक संकेतक जो कि पक्षपाती (भारत के खिलाफ) प्रतीत होते हैं या कुछ खामियों की पहचान की जाती है।

सभी 90 संकेतकों का विश्लेषण करने के बाद, 3 संकेतकों की पहचान की गई है और इन संकेतकों में मौजूद खामियां इस प्रकार हैं:

संकेतक 12.04 - प्रति वयस्क जनसंख्या के लिए स्वचालित टेलर मशीनें

यह संकेतक प्रति 100,000 वयस्क आबादी पर स्वचालित टेलर मशीनों की संख्या को मापता है

2015 तक इस संकेतक की गणना 1 मिलियन आबादी वाले वीज़ा कार्ड स्वीकार करने वाली स्वचालित टेलर मशीनों की संख्या के रूप में की गई थी। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही हैं, इसलिए डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए एटीएम स्थापित करने की आवश्यकता हर दिन कम हो रही है।

इसलिए, इस संकेतक को स्थापित किए गए एटीएम की संख्या के रूप में गणना करने के बजाय, इस सूचक को अधिक वैश्विक और हाल ही हालत को बताने के लिए भुगतान करने के तरीके के रूप में डिजिटल नकदी का उपयोग करने वाले वयस्कों की संख्या पर ध्यान देना चाहिए।

संकेतक 12.03 - प्रमुख कार किराए पर देने वाली कंपनियों की उपस्थिति

In प्रमुख कार किराए पर लेने वाली कंपनियों की उपस्थिति का सूचकांक (1 = कोई कंपनी मौजूद नहीं है, 7 = सभी सात विचारशील कंपनियां मौजूद हैं)

यह संकेतक सात प्रमुख कार किराए पर देने वाली कंपनियों की उपस्थिति को मापता है: एविस, बजट, यूरोपकार, हर्ट्ज, नेशनल कार रेंटल, सिक्सट और थ्रिप्टी। प्रत्येक देश के लिए आइएफ़एफ़ ने गिना कि इनमें से कितनी कंपनियां ऑनलाइन शोध के माध्यम से काम करती हैं।

इस संकेतक में जिन कार किराए पर देने वाली कंपनियों को लिया जाता है, वे एशियाई देशों में एक नवजात अवस्था में हैं। ये कंपनियां या तो यूरोप या उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं और इसलिए इन महाद्वीपों में इनके प्रमुख बाजार हैं। इन कंपनियों के संचालन में इस तरह की असमानता एशियाई देशों के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा करती है।

भारत और अन्य एशियाई देशों में लोगों के लिए घरेलू कार किराए पर देने की सेवाएं हैं। घरेलू कार किराए पर देने वाली कंपनियों का ऐसा ही एक उदाहरण है ज़ूमकार जो भारत के ग्राहक आधार को पूरा करता है। इन घरेलू कार किराए पर देने वाली कंपनियों को इस सूचक के हिस्से के रूप में डब्ल्यूईएफ द्वारा नहीं माना जाता है।

सभी देशों को एक समान अवसर देने के लिए, घरेलू कार किराए पर देने वाली कंपनियों को भी इस संकेतक को स्कोर करते समय विचार किया जाना चाहिए।

संकेतक 1.06 - निर्माण परमिट से निपटने के लिए लागत

यह संकेतक किसी व्यवसाय को गोदाम बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं से संबंधित लागत को मापता है (इसके मूल्य के संबंध में) ।

$$\text{मूल्य of a देश} = \frac{\text{निर्माण परमिट की लागत (गोदाम)} x\ 100}{\text{(वेयरहाउस मूल्य (प्रति व्यक्ति आय का } 50 \text{ गुना)}}$$

इस संकेतकके लिए एक देश के मूल्य की गणना देश के प्रति व्यक्ति आय के 50 गुना के साथ गुणा किए गए गोदाम के मूल्य के साथ की जाती है। इस सूचक के लिए उच्च मूल्य का मतलब निम्न श्रेणी है।

प्रति व्यक्ति आय कम होने वाले देशों में इन देशों के बराबर या उससे भी कम निर्माण लागत वाले देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद सूचक में निम्न श्रेणी / स्कोर होता है। इस संकेतक के डाटा सेट में देखी गई प्रवृत्ति यह है कि विकास के पहले चरण में देश निर्माण लागत की कम लागत के बावजूद स्कोर के पहुंच के निचले हिस्से पर होते हैं। इस प्रकार, प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति में एक कारक के रूप में निर्माण परमिट की लागत का सही मूल्य अस्पष्ट करता है। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि या तो परमिट की सही लागत का विश्लेषण किया जाए या प्रति व्यक्ति आय को स्लैब में सामान्य किया जाए।

<u>**वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आवश्यक स्पष्टीकरण**</u>

अध्ययन के दौरान, यह देखा गया कि 3 संकेतकों में, मूल्य की गणना के लिए व्युत्पन्न सूत्र, संकेतक के लिए प्रदान की गई परिभाषाओं से मेल नहीं खा रहा था। निम्नलिखित संकेतक हैं:

1. संकेतक 6.05: टीएंडटी डाटा प्रदान करने में समयबद्धता
2. संकेतक 7.02: द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों (एएसए) का खुलापन
3. संकेतक 9.05: पर्यावरणीय संधि अनुसमर्थन

संकेतक 6.05: टीएंडटी डाटा प्रदान करने में समयबद्धता

मूल्य संकेतक का मूल्य - उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों की संख्या (0 = कोई डाटा नहीं, 22.5 = सभी अवधियों के लिए डाटा माना गया हैं) 2015-2016

यह संकेतक मासिक या त्रैमासिक आधार पर दो प्रमुख टीएंडटी संकेतक (अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन और पर्यटन प्राप्तियां) की उपलब्धता को दर्शाता है।

टीटीसीआई रिपोर्ट 2015 में, माना गया अवधि अक्टूबर 2013 से नवंबर 2014 (14 महीने) तक है। 50% भार दो अंकों के निचले भाग को दिया गया है, इसलिए स्कोर न्यूनतम 0 से अधिकतम 21 तक है। ऐसे देश के लिए जो दोनों उपायों में पूर्ण स्कोर करता है, मूल्य की गणना 14 के रूप में की जाएगी। एक उपाय और दूसरे के लिए 7, कुल 21 बना रहा है।

टीटीसीआई रिपोर्ट 2017 में, माना गया अवधि अक्टूबर 2014 से नवंबर 2016 तक (यानी) 26 महीने है। गणना पद्धति समान रहती है। इसलिए, इस संकेतक में एक देश जो अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकता है, वह एक माप के लिए 26 हो जाता है और दूसरे के लिए 13, कुल 39 हो सकता है। टीटीसीआई रिपोर्ट 2017 में उल्लिखित पैमाने को 0 के रूप में दिया गया है, जिसमें कोई डाटा नहीं है और 22.5 डाटा सभी अवधियों के लिए रिपोर्ट किया गया है। ।

इस सूचक के पैमाने के बारे में एक स्पष्टीकरण आवश्यक है।

संकेतक 7.02: द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों (एएसए) का खुलापन

संकेतक के मूल्य - वायु सेवा समझौतों के औसत खुलेपन को मापने वाला सूचकांक (0 = सबसे अधिक प्रतिबंधित, 38 = सबसे उदार) | 2011

इस संकेतक की सरलीकृत परिभाषा प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि उसी के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू किया जा सके।

संकेतक 9.05: पर्यावरणीय संधि अनुसमर्थन

संकेतक का मूल्य - कुल पर्यावरणीय संधियों की संख्या (0-32 पैमाने, जहां 32 सबसे अच्छा है) | 2016

टीटीसीआई रिपोर्ट 2017 में उल्लेखित संधि की कुल संख्या 33 हैं, जबकि इस संकेतक में एक देश जो अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकता है वह 32 है (जैसा कि परिभाषा में दिया गया है)। इस संकेतक के पैमाने के बारे में एक स्पष्टीकरण आवश्यक है।